



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1993/आषाढ़ 5, 1915

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1993/ASADHA 5, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संचिधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
Ministry of the Defence)

गृह मंत्रालय
(आसूचना ब्यूरो)

नई दिल्ली, 8 जून, 1993

का. आ. 1366 :—आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
नई दिल्ली के बाह्य स्थित सहायक आसूचना ब्यूरो, अगरतला के 80% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी का
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः, केन्द्रीय सरकार,
राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)
नियम, 1976 के नियम 10 के उस नियम (4) के
अनुसरण में सहायक आसूचना ब्यूरो, अगरतला को एतद्-
द्वारा अधिसूचित करती है।

[सं. 3/6/92—हिन्दी-1171]

टी. गुहटे, उप निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Intelligence Bureau)
New Delhi, the 8th June, 1993

S.O. 1366.—80 per cent Officers/Employees working in
the Subsidiary Intelligence Bureau, Agartala of the Intelli-
gence Bureau (Ministry of Home Affairs), New Delhi, have
since acquired working knowledge of Hindi. As such, in
pursuance of sub-rule (4) of Rule (10) of the Official Lan-
guage (Use for Official Purposes of the Union), Rule, 1976,
the Central Government hereby notifies the above mention-
ed office of the Bureau located in Agartala.

[No. 3/6/92-Hindi-1171]

T. GWITE, Dy. Director

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 1993

का. आ. 1367 :—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष
पुलिस स्थान अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम
सं. 25) की धारा 6 के माध्य पठित धारा 5 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह (एम. सी. ए.) विभाग जी. ओर. आर. टी. सं. 34, तारीख 3 जनवरी, 1991 द्वारा दी गई आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद द्वारा रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिकथित हैं, संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है :—

आर. सी. सं. और अधि की धाराएं	अभियुक्त का नाम
भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120B और अष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के साथ पठित धारा 5(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन आर.सी.सं. 10(ए) 90-हैदराबाद, तारीख 27 जुलाई, 1990	1. श्री सी. हरिमोहन, प्रबंधक, इंडियन बैंक, एम. पाडु शाखा, विजयवाड़ा। 2. श्री ई.वी. सुब्बा रेड्डी, व्यापारी, मार्फत 25, कैनेडी नगर, तिरुपति (प्राइवेट व्यक्ति) 3. श्री दुर्गा प्रसाद रेड्डी सुपुत्र श्री ई. मल्ला रेड्डी, निवासी 31-3-13/2, मारुति नगर, विजयवाड़ा।

[संख्या 228/45/92-(1)—ए. बी. डी. —II]

पराग प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 7th June, 1993

S.O. 1367:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh vide

Home (SCA) Dept. G.O. Rt. No. 34 dated 3-1-1991 and G.O.Rt. No. 312 dated 10-2-1992 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of offences punishable under the relevant sections of Prevention of Corruption Act, 1988 and various sections of India Penal Code alleged to have been committed by the Central Government employees and private persons in the following cases by the Central Bureau of Investigation, Hyderabad :

RC No. & Secs. of Law	Name of the accused
RC. No. 10 (A)/90-Hyd. dt. 27-7-1990 under section 120-B r/w 420 Indian Penal Code & 5 (2) r/w 5 (1) (d) of Prevention of Corruption Act & Section 420 Indian Penal Code.	1. Sri C. Harimohan, Manager, Indian Bank, M.M. Padu Br. Vijayawada. 2. Sri E.V. Subba Reddy, Businessman, C/o. 25 Kennedy Nagar, Tiruchanur Road, Tirupati (Pvt. person). 3. Shri Durga Prasad Reddy, S/o. E. Mala Reddy, R/o. 31-3-13/2, Maruthinagar, Vijayawada.

[No. 228/45/92-(I)-AVD-II]

PAAG PRAKASH, Officer on the Special Duty (V-2)

आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 1993

का. आ. 1368 :—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह (एस सी-ए) विभाग—जी. ओ. आर. टी. सं. 2614 तारीख 11-9-1991 द्वारा दी गई आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध बेगमपेट पुलिस थाना द्वारा रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 135 93 की बाबत भारतीय पामपोर्ट अधिनियम की धारा 3, 10(3)(क)(ख), 12(1)(ख)(घ), 12(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471 और 109 के अधीन दंडनीय अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है :—

(1) सोणली रामा राव जो नरसिंह राव का पुत्र है, व्यवसाय : कारोबार ति. 22-6-597 मंडी मीर आलम, हैदराबाद 14-4-87 को हैदराबाद

- से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. वाई 487904, विमान टिकट सं. 098 4409 059976 : (वास्तविक नाम हरजीत हंस सुपुत्र सुधाकर हंस, आयु 35 वर्ष, नि. ग्राम बरदेक, तहसील जगरांव, जिला लुधियाना ।)
- (2) मोगली सुजाता राव, जो एम. रामा राव की पत्नी है आयु 37 वर्ष व्यवसाय : गृहणी, नि. 22-6-608, मंडी मीर आलम, हैदराबाद, 16-7-87 को हैदराबाद से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. वाई-48832 विमान टिकट सं. 098 4409 059978 : (वास्तविक नाम सर्वजीत कौर, पुत्री प्रीतपाल सिंह, आयु 28 वर्ष, नि. 49-ए, गोविंद नगर अम्बाला कैट)
- (3) जेतन राव, जो एम. रामा राव का पुत्र है, आयु 15 वर्ष, अपनी माता मोगली सुजाता राव के साथ संयुक्त पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए विमान टिकट सं. 098 4409 059972 (वास्तविक नाम अहमद अकबर अली पुत्र अकबर अली पुंजानी, आयु 18 वर्ष, नि. नेताजी नगर, हैदराबाद ।)
- (4) दिलशाद नुसदीन ललानी जो नुसदीन दिल ललानी की पत्नी है आयु 31 वर्ष, नि. हरी भंडार आर. सं. 22, शिवाजी पुलिस चौक, सामने : जोहेश्वरी, मुम्बई, 15-3-89 को मुम्बई से जारी पासपोर्ट सं. एफ-309731 : विमान टिकट सं. 098 4409 0559974 (वास्तविक नाम पतनीत कौर पत्नी लखवेन्द्र सिंह, आयु 25 वर्ष, नि. बरवा ग्राम, जिला जालंधर)
- (5) इम्माईल भाई जो जीवाभाई पुंजानी का पुत्र है आयु वर्ष, व्यवसाय : कारोबार, नि. 5-4-585, कट्टल मंडी हैदराबाद, 2-7-83 को हैदराबाद से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. यू. 600023, विमान टिकट सं. 098 - 4409 059975 (वास्तविक नाम नरेश कुमार जो बीड़ी चन्व का पुत्र है, आयु 31 वर्ष, नि. ग्राम सहाइबा, तहसील बालाचूर, जि. होशियारपुर)
- (6) सादिक सलीम बीड़ी बाला जो सलीम रजब अली बीड़ी बाला का पुत्र है, आयु : 31 वर्ष, नि. बस्तावल बिल्डिंग, तीमरा तल, फ्लैट सं. 2526, मुम्बई, 28-11-85 को मुम्बई से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. ए. 823911 विमान टिकट सं. 098 4409 059977 (वास्तविक नाम सुन्दरपाल सिंह जो अजीत सिंह का पुत्र है, आयु : 24 वर्ष, नि. ग्राम और डाकखाना : बादला जदियाला गुरु, अमृतसर ।)
- (7) यातीराजम चक्रवर्ती, जो याती राजम का पुत्र है, आयु : 25 वर्ष, नि. 208, अरुण अपार्टमेंट्स नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद : 5.5.88 को हैदराबाद से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. सी 635782, विमान टिकट सं. 098 - 4409 059973 (वास्तविक नाम हरजिन्दर सिंह, जो जागीर सिंह का पुत्र है, आयु : 23 वर्ष नि. ग्राम मलकपुर डाकखाना नारर, तहसील, फगवाड़ा, जि. कपूरथला) ।
- (8) बहादुर अतवल, जो करनैल सिंह का पुत्र है, आयु 33 वर्ष, नि. ग्राम बड़वा, डाकखाना भगोरम, जि. जालंधर (पंजाब) 11-10-89 को न्यूयार्क से जारी किए गए पासपोर्ट की सं. एफ 662623, विमान टिकट सं. 098 4207 47-1433 : (वास्तविक नाम लखवेन्द्र सिंह जो करनैल सिंह का पुत्र है, आयु : 30 वर्ष, नि. ग्राम बड़वा, तहसील नवन शहर, जि. जालंधर ।)

[सं. 228/9/92—ए. बी. डी. (ii)]

पराग प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी

ORDER

New Delhi, 10th June, 1993

S.O. 1368.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh accorded vide Home (SC-A) Deptt. G.O. Rt. No. 2614 dated 11-9-1991, and G.O.Rt. No. 311 dated 10-2-1992 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences punishable under section 3, 10 (3) (a) (b) Section 12(1) (b) (d) ; Section 12 (2) of the Passports Act, 1967, and Sections 468, 471 and 109 of Indian Penal Code (1860) in regard to crime No. 135/91 registered by Begumpet Police Station against the following persons.

RC No. & Secs. of Law	Name of the accused.
1	2
RC. 5(S)/92-Hyd. u/s 13, 10 (3) (a) (b) Section 12(1) (b) (d) and Sec. 12 (2) of the Passport Act, 1967, and Section 468, 471 and 109 of Indian Penal Code (186)	1. Mougli Rama Rao S/o Narsing Rao age 32 years OCC : Business, R/D 22-6-597, Mandi Mir Alam, Hyderabad Passport No. Y-487904 issued at Hyderabad on 14-4-87 Air ticket No.) 8 4409 059976 (Real.

1

2

- Name : Hatjeet Hans s/o.
Sudhakar Hans Age 35
years r/o. Villa Village
Bardeke, Tehasil Jagraon,
District Ludhiana.
2. Mougli Sujatha Rao w/o
M. Rama Rao, age 37
years OCC : House wife
r/o 22-6-608, Mandi Mir
Alam, Hyderabad, Passport
No. Y-48832 issued at
Hyderabad on 16-7-87 ;
Air ticket No. 0984409
059978 : (Real Name
Sarabjit Kaur D/o. Pritpal
Singh, age 28 years 8/049-
A, Govind Nagar, Ambala
Cantonment.
3. Chaitan Rao s/o M. Rama
Rao, age 15 years travelling
on Joint Passport with his
mother, Mougli Sujatha
Rao, Air ticket No. 098
4409 059972 : (Real Name
Ahmed Akbar Ali s/o.
Akbar Ali Punjuani,
age 18 years, r/o. Netha
Jee Nagar, Hyderabad.
4. Dilshad Nooruddin Lalany
w/o. Nooruddin Dil
Lalany, age 31 years r/o
Hari Bhandar R.No.
22, Shivaji Polic
Chowk Opp : Jogeswari,
Bombay Passport No. F-
309731 issued at Bombay on
15-3-89 ; Air ticket No.
098 4409 0 59974 (real
name : Partneet Kaur r/o
Barwa Village, Dist.
Jalandar.
5. Ismail Bai, s/o. Jiwabhai
Punjani age 28 years, OCC :
Businees r/o 5-4-585 Kattal
Mandi, Hyderabad, Pass-
port No. U. 600023 issued
at Hyderabad on 2-7-83
Air ticket No. 098 4409
0599 75 (real name : Naresh
Kumar s/o. Bidichand age
31 years r/o. village Sahaiba,
Tehsil Balachoor, Dist.
Hoshiyapur.

1

2

6. Sadiq Salim Bidiwala, s/o.
Salim Rajab Ali Bidiwala,
age 31 years R/o. Bartawal
Building 3rd floor, Flat No.
No. 2526, Bombay : Pass
port No. : A-823911 issued
at Bombay on 28-11-85 ;
Air Ticket No. 098 4409
059977 : (Real Name
Sunderpal Singh s/o. Ajit
Singh, age 24 years R/o
R/o. Vollage and Post
Bandla Jandiyala Guru
Amritsar).
7. Yathirajam Chakaravarthi,
s/o. Yathi Rajan, age 25
years R/o. 208 Arun Apart-
ments, Niloufer Hospi-
tal, Hyderabad, Passport
No. C-635782 issued at
Hyderabad on 5-5-88 : Air
ticket No : 0984409059973
(Real Name : Hari Jinder
Singh s/o. Jagir Singh, age
23 years R/o. Malakpur
Vi llage, P.O. Narur : Teh-
sil Phogwara, Dist.
Kapurthala).
8. Bahadur Atwal S/o.
Karnail Singh, age 33 years
R/o. Village Barwa, PO
Bhagoram, Dist. Jalandar
(Punjab.) Passport
No. F-4207 471433
(Real Name : Lakhvender
Singh s/o. Karnail Singh
age 30 years R/o. Barwa
Village : Tehsil Navan
Shaher, Dist. Jalandar)

[No. 228/9/92-AVD-II]

PARAG PRAKASH, Officer ON Special Duty (V)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जून, 1993

का. आ. 1369:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष
पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम
25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह (एम सी-
ए) विभाग जी. ओ. आर. टी. सं. 313 दिनांक 10-2-92
द्वारा प्राप्त आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से

विल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो हैदराबाद शाखा द्वारा 30-9-91 को निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध वर्ज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामला सं. आरसी 25 और 26 (एस)/91-हैदराबाद से संबंधित निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है, अर्थात् :—

आर. सी. संख्या एवं
विनांक

अभियुक्तों के नाम

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आरसी. सं. 25 (एस) 91-हैदराबाद दि. 30-9-91 तथा उससे संबंधित मारभूत अपराध
 1. बी. ए. सत्यनारायणा, सब-स्टाफ, आन्ध्रा बैंक सर्विस सैल, सैफाबाद, हैदराबाद।
 2. बी. रामचन्द्र मूर्ति, सब-स्टाफ, आन्ध्रा बैंक सर्विस सैल, सैफाबाद, हैदराबाद।
 3. अनूप मिश्रा, मकान नं. 3-6-21 1, शहीद यार जंग लेन, बशीरबाग, हैदराबाद।
 4. टी. नागा राज, मकान नं. 52-ए, सबमटेन रोड, सिकन्दराबाद।
 5. अशोक भवानी और अशोक बंगेय, 1-81, भवानी नगर, मलकाजगिरी सिकन्दराबाद।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 तथा 420 के साथ पठित 511 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरसी सं. 26 (एस) 91-एच, दिनांक 30-9-1991
 1. वाई. एस. रेड्डी आफिसर, एम. एम.-II, मैनेजमेंट आडिट डिपार्टमेंट, आन्ध्रा बैंक, सेंट्रल आफिस -II, सोमाजी-गुड्डा, हैदराबाद।
 2. बी. ए. सत्यनारायणा, सब-स्टाफ, आन्ध्रा बैंक सर्विस सैल, सैफाबाद, हैदराबाद।
 3. पी. रामचन्द्र मूर्ति, सब-स्टाफ आन्ध्रा बैंक सर्विस सैल, सैफाबाद, हैदराबाद।
 4. मोहन कुमार और मोहन रिजवानो, प्लॉट नं. 11, बी. एच. ई. एल. कालोनी रामूलपुरा, सिकन्दराबाद।
 5. अमरनाथ
(पता मालूम नहीं)

ORDER

New Delhi, the 11th June, 1993

S.O.1369.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act (XXV of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of Andhra Pradesh accorded vide Home (SC-A) Department GO. Rt. No. 313 dated 10-2-92 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the following offences in regard to CBI Case Nos. RC. 25 & 26(s) 91-HYD registered by CBI/Hyderabad Branch on 30-9-91 against the following persons :—

RC. No. & Date	Names of the Accused
1. RC No. 25(S)/91-Hyd., dt. 30-9-1991 u/s-120-B IPC r/w 420, 467, 468 & Andhra Bank Service Cell Saifabad, Offences thereof.	1. B.A. Satyanarayana, Sub-Staff, Andhra Bank Service Cell Saifabad, Hyderabad.
	2. B. Ramachandra Murthy, Sub-Staff, Andhra Bank Service Cell Saifabad, Hyderabad.
	3. Anup Misra, H.No. 3-6-21/Shahid Yar Jung Lane, Basheerbagh Hyderabad.
	4. T. Naga Raj, H.No. 52-A, Sebastian Road Secunderabad.
	5. Ashok Bhavani & Ashok Bhangay, 1-81, Bhavaninagar, Malkajgiri, Secunderabad.
2. RC. No. 26(S)/91-H, dt. 30-9-91 u/s 120-4 r/w 420, 467, 468, 471 IPC & 420 r/w 511 IPC	1. Y.S. Reddy, Officer, M.M.II, Management Audit Department, Andhra Bank, Central Office-II, Somajiguda, Hyderabad.
	2. B.A. Satyanarayana, Sub-Staff, Andhra Bank Service Cell, Saifabad, Hyderabad.
	3. P. Ramachandra Murthy, Sub-Staff, Andhra Bank Service Cell Saifabad, Hyderabad.

[सं. 228 56 92-ए. बी. डी. II]

पराग प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी

1	2
	4. Mohan Kumar & Mohan Rizwani, Plot No. 11, BHEL Colony, Resulpura, Secunderabad. 5. Amarnath (Address not known)
	[No. 228/56/92-AVD.II]
	PARAG PRAKASH, Officer on Spl. Duty (V)

नई दिल्ली, 11 जून, 1993

का. आ. 1370 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में एतद्वारा इस मंत्रालय के प्रशासनाधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित शाखा कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

- (1) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय, विशेष एकक, नई दिल्ली।
- (2) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय, धनबाद।
- (3) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय, नागपुर।

[संख्या 11011/3/93-हिन्दी-II]

ए. के. भट्टराई, उप सचिव

New Delhi, the 11th June, 1993

S.O. 1370.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following branch offices of the Central Bureau of Investigation, under the administrative control of this Ministry, where more than 80 percent Staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Supdt. of Police, C.B.I., Special Unit, New Delhi.
2. Supdt. of Police, C.B.I., Dhanbad.
3. Supdt. of Police, C.B.I., Nagpur.

[F. No. 11011/3/93-Hindi II]

A. K. BHATTARAI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1993

(आयकर)

का. आ. 1371 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “पंजिम जिमखाना, गोवा” को 1993-94 से 1995-96 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित

णतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जैवर जबाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तीसरे भरणतुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों की किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा, और
- (4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हैं जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त-कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हैं तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9274/फा. सं. 196/13/92-आयकर
(नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Deptt. of Revenue)

New Delhi, the 28th April, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1371.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies the “Panjim Gymkhana, Goa” for the purpose of the said clause for assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contribution received and

maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9274/F. No. 196/13/92-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1993

(आयकर)

का. आ. 1372.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "डूरंड फुटबाल टूर्नामेंट सोसाइटी, नई दिल्ली" को 1991-92 से 1993-94 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उप-धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जवहर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तिसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त-कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9277/फा. सं. 196/17/92-आयकर

(नि.—1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1372.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Durand Football Tournament Society, New Delhi" for the purpose of the said clause for assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23)] for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9277/F. No. 196/17/92-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1993

स्टाम्प

का.आ. 1373.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड नई दिल्ली को केवल ग्यारह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रुपए के समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो कि उक्त कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाले केवल तेरह करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार रुपए के कुल मूल्य के प्रत्येक 85/- 85/- रुपए के अंकित मूल्य के

ऋण-पत्रों के रूप में 30,00,001 से 45,75,000 तक की विशिष्ट संख्या वाले प्रत्येक 85/- रुपए के 15,75,000, 14 प्रतिशत सुरक्षित विभाज्य अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभावी है।

[सं. 16/93-स्टाम्प/फा. सं. 33/7/93-वि. क.]

ठाकुर दत्त, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1993

STAMPS

S.O. 1373.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Triveni Engineering Works Ltd., New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees eleven lacs, eighty one thousand, two hundred and fifty only, chargeable on account of the stamp duty on 15,75,000—14% Secured Redeemable Non-Convertible Debenture of Rs. 85 each bearing distinctive numbers 30,00,001 to 45,75,000 in the form of debentures of the face value of rupees 85 each of the aggregate value of rupees thirteen crores, thirty eight lakhs and seventy five thousands only to be issued by the said Company.

[No. 16/93-Stamps/F. No. 33/7/93-ST]

THAKUR DATT, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1993

स्टाम्प

का. आ. 1374.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस स्टाम्प शुल्क को माफ करती है, जो म. पारावीप फासफेट्स लि. के केवल अठ्ठावन करोड़ और अस्सी लाख रुपये के अंकित मूल्य के पांच लाख अठासी हजार शेयरों को नौरु सरकार द्वारा भारत की सरकार को अन्तर्गत किए जाने पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभावी है।

[सं. 18/93-स्टाम्प/फा. सं. 33/30/93-वि. क.]

ठाकुर दत्त, उप-सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1993

STAMPS

S.O. 1374.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the stamp duty with which the transfer of five lakhs eighty eight thousands shares of the aggregate face value of rupees fifty eight crores and eighty lakhs only of M/s. Paradeep Phosphates Limited by the Government of Nauru to the Government of India is chargeable under the said Act.

[No. 18/93-Stamps/F. No. 33/30/93-ET]

THAKUR DATT, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 मई, 1993

आयकर

का. आ. 1375.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (ए) के उप खंड (ii) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हग्न औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुन संरचना बोर्ड को उक्त उप खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 9299/फा. सं. 225/127/93-आयकरनि. -II]

अजय कुमार, अवर सचिव

CENTRAL BOARD DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th May, 1993

INCOME TAX

S.O. 1375.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Board for Industrial and Financial Reconstruction, established under section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) for the purpose of said sub-clause.

[Notification No. 9299/F. No. 225/127/93-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1993

आयकर संस्थापन

का. आ. 1376.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का मुकदमा) अधिनियम, 1992, के अंतर्गत अभिरक्षक ककरा संख्या 24, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आयकर अधिनियम, 1961, के उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 9298/फा. सं. 225/110/93-आयकर नि. -ii]

अजय कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1993

INCOME TAX ESTABLISHMENTS

S.O. 1376.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby Specifies Custodian, appointed under Special Court (Trial of offences relating to transaction in securities) Act, 1992, Room No. 24, Jeevan Deep, Parliament Street, New Delhi for the purpose of said sub-clause of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9298/F. No. 225/110/93-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

भाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली 7 जून, 1993

का.आ. 1377—मैसर्स रूबी एडवर्टाइजर्स, नई दिल्ली को फाल्माक पावडर ऑपरेटिव सर्कुलर नीटिंग मशीन के आयात के लिए 58,09,692/- रुपये (अठ्ठावन लाख नौ हजार छ सौ बानवे रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं. पी. सी. जी. 2130381 दिनांक 30-3-93 मंजूर किया गया था।

फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनूलिपि इस आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क और विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई है। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है।

2. अपने तर्कों के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक बम्बई के समक्ष विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार ये सन्तुष्ट हैं कि आयात लाइसेंस सं. पी. सी. जी. 2130381 दिनांक 30-3-93 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रति फर्म से खो गई है या गुम हो गई है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 के उप खण्ड 9 (गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रूबी एडवर्टाइजर्स को जारी की गई उक्त मूल सीमाशुल्क और विनियम नियंत्रण प्रति एतद्वारा निरस्त की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की दूसरी सीमाशुल्क और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फा. सं. 18/एम. 93/1763/ई. पी. सी. जी.-3/133]

एम. डी. केम, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Director General of Foreign Trade)

ORDER

New Delhi, the 7th June, 1993

S.O. 1377.—M/s. Ruby Advertisers, New Delhi were granted an import licence No. P/G/2130381 dated 30-3-93 for Rs. 58,09,692 Rupees Fiftyeight lakhs Nine Thousand Six Hundred and Ninetytwo only, for import of Falmac Powder Operated Circular Knitting Machine.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs and Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original customs and Exchange Control copy of the licence has been lost or

misplaced. I has further been stated that the Customs and Exchange Control purposes copy of the licence was not registered with any customs authority and as such the value of customs purposes copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes and Exchange Control purpose copy of import licence No. P/G/2130381 dated 30-3-93 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 195 dated 7-12-55 as amended the said original customs and Exchange control copy to M/s. Ruby Advertisers is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs and Exchange Control purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/AM93/1763/EPCG-II[133]

M. D. KEM, Dy. Director of Foreign Trade

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1993

का. आ. 1378.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयु-विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुविज्ञान परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में—

(1) "बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान) एम. एम. (सा. शा. वि.)"

(2) "गुलबर्गा विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान) एम. एम. (नेत्र विज्ञान)"

(3) "गुरुनानक देव विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन यक्ष्मा और श्वसन रोग एम. डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)"

(4) "महात्मा गांधी विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान) एम. एम. (नेत्र विज्ञान) डिप्लोमा इन आफथैल्मालोजी एम. डी. ओ."

- (5) "मंगलौर विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (चिकित्सा विज्ञान) ..
एम. डी. चिकित्सा विज्ञान डिप्लोमा इन
मेडिकल रेडियोग्राफिक्स
डी. एम. आर. डी."

- (6) "दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान) ..
एम. डी. (विकृति विज्ञान)
डिप्लोमा इन निरन्तरण पैथावाजी .. डी. सी. पी.
डाक्टर ऑफ मेडिसिन (स्त्रीरोग विज्ञान ..
एम. डी.) स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान
(विज्ञान और प्रसूति विज्ञान)
डिप्लोमा इन गायनाकोलाजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स
... डी. जी. ओ."

- (7) "पूना विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डिप्लोमा इन गायनाकोलाजी एण्ड
आब्स्टेट्रिक्स .. डी. जी. ओ."

[सं. वी.-11015/1/93 एम.ई. (यू.जी.)]

आर. विजयकुमारी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th May, 1993

S.O. 1378.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the said Schedule,—

- (1) under the heading "BUNDELKHAND UNIVERSITY", after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"Master of Surgery (General Surgery)...M.S.
(Gen. Surg.)"

- (2) under the heading "GULBARGA UNIVERSITY", after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"Master of Surgery (Ophthalmology)...M.S. (Ophth.)"

- (3) under the heading "GURUNANAK DEV UNIVERSITY", after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Tuberculosis & Respiratory Diseases)...M.D. (Tuberculosis and Respiratory Diseases)"

- (4) under the heading "MAHATMA GANDHI UNIVERSITY", after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"Master of Surgery (Ophthalmology)...M.S. (Ophth.)"
Diploma in Ophthalmology...D.O."

- (5) under the heading "MANGALORE UNIVERSITY", after the entries, the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis)...M.D. (Radio-Diagnosis)"

Diploma in Medical Radio Diagnosis...D.M.R.D."

- (6) under the heading "SOUTH GUJARAT UNIVERSITY", after the entries, the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Pathology)...M.D. (Pathology)"
Diploma in Clinical Pathology...D.C.P.

Doctor of Medicine (Gynaecology & Obstetrics).....
Obst. & Gynae.)

Diploma in Gynaecology & Obstetrics...D.G.O."

- (7) under the heading "UNIVERSITY OF POONA", after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"Diploma in Gynaecology / obstetrics...D.G.O."

[No. V. 11015/1/93-ME(UG)]

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

नागर विमानन और पर्यटन संत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 1993

का. आ. 1379.—अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 (1971 का 43वां) की धारा 3 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के. एन. अर्धनारीश्वरन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को तत्काल से भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अंशकारीत सदस्य के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या उनके वर्तमान पद को छोड़ने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[संख्या एवी-24022/1/91-वी. ई.]

एच. एस. संधु, सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 8th June, 1993

S.O. 1379.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri K. N. Ardhanareswaran, Chairman, National Airports Authority, New Delhi as a part-time Member on the Board of the International Airports Authority of India with immediate effect for a period of three years or till he relinquishes his present post, whichever is earlier.

[No AV-24022/1/91-ME]

H S. SANDHU, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 मई, 1993

का. आ. 1380.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल के पाथरडोह स्थित रेल पथ कार्यालय को, जहां कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[सं. हिंदी-93/रा. भा. 1/12/6]

मसीहुज्जमां, सचिव, रेलवे बोर्ड
भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th May, 1993

S.O. 1380.—In pursuance of sub-Rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the Office of PW1, Pathardih under Dhanbad Division, of Eastern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-93/OL-I/12/6]

NASIHUZZAMAN, Secy. Railway Board
Ex Officio Addl Secy. to the Govt of India

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1993

का. आ. 1381.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजौर कोलियरी आफ डब्ल्यू सी एन के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25/5/93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/195/92-आई आर (सी-ii)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th May, 1993

S.O. 1381.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajur Colliery WC Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-93.

[No. L-22012/195/92-IRC-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

PRESENT:

Shri P. D. Apshankar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/59 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Rajur Colliery, W.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the management—Shri G. S. Kapur, Advocate.

For the workman—No appearance.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 18th May, 1993

AWARD

The Central Government by their Order No. L-22012/195/92-IRC-II dated 21-10-1992 have referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

“Whether the action of the Sub Area Manager, Rajur Colliery, W.C. Ltd., Distt. Yeotmal, in terminating the services of Shri Dattu Savle Wasekar, Loader from 6-10-90 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2. The notices of the present reference were issued to both the parties. Accordingly the Advocate for the management, and workman in person remained present before this Tribunal on 18-1-1993 and the matter was adjourned on the request of the workman for filing the statement of claim by him.

3. The workman consistently remained absent since the next date, and remained absent on 21-1-1993, 22-1-1993, 23-2-1993, 13-4-1993 and 18-5-1993.

4. The workman had challenged the said action of the management, and as such it was for the workman to prove the alleged illegality and unjustification of the action of the management. As noted above, the workman remained absent, and failed to file the necessary statement of claim in support of the claim, and further to prove his claim. Therefore, the present reference stands disposed of.

The parties to bear their own costs of this reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
18th May, 1993.

नई दिल्ली, 31 मई, 1993

का. आ. 1382.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, एरनाकुलम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-5-43 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/11/89-डी-2 (ए)]

हरीश गोड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1993

S.O. 1382.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Labour Court, Ernakulam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 28-5-1993.

[No. L-12012/11/89-D.II (A)]
HARISH GOUR, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT,
ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

(Monday, the 10th day of May, 1993)

PRESENT :

Shri M. V. Vjswanathan, B.Sc., LL.B., Presiding Officer.
Industrial Dispute No. 13 of 1989 (C)

BETWEEN

The Regional Manager, Canara Bank, Regional Office.
Trivandrum-695001.

AND

The General Secretary, Canara Bank Staff Union, P.O.
Box No. 10051, 268/70, Ferore Road, Fort, Bombay-400001.

Representations :

Sri M. C. Sen, Advocate, Cochin-16—For Management
M/s. Cochin Law Chambers, Advocates, Paramara Buildings, Cochin-18—For Union.

AWARD

This industrial dispute was referred to this Court by the Central Government as per the Order No. L-12012/11/89-D.II (A) dated 18-7-1989. The dispute is between the management of Canara Bank and their workmen represented by the General Secretary, Canara Bank Staff Union. The issue referred for consideration is "Keeping in view, the exclusion of the names of Sri Radhakrishnan from the charge framed by the police and also considering the deposition of the complainant during the Enquiry Proceedings and his letter dated 22-4-1986, whether the action of the management of Canara Bank, in issuing a warning letter to Sri Radhakrishnan, sub-staff of Canara Bank, Tripunithura Branch, confirming the suspension period from 2-5-1984 to 11-6-1985 and not paying full wages for the period is justified. If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

II. The management has taken disciplinary proceedings against the employee Sri. Radhakrishnan for the misconduct alleged in the charge sheet dated 25-4-1984. In the domestic enquiry the workman was found guilty of the charges. The management accepted the findings in the domestic enquiry and imposed the punishment of warning. The period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 was treated as the period not spent on duty. The workman preferred an appeal to the Appellate Authority viz. the Chairman and Managing Director, Canara Bank. The said appeal was dismissed by the Appellate Authority. So the union took up the matter and challenged the validity of the domestic enquiry and punishment imposed on the workman. Before this court the union challenged the validity of the domestic enquiry and the findings thereon. So the said issue regarding the validity of the domestic enquiry and the findings thereon was considered by this Court as a Preliminary point. This court was pleased to uphold the domestic enquiry and the findings thereon, by virtue of the Preliminary Order dated 30-1-1993. The above said Preliminary Order of this Court is extracted below for convenience.

"PRELIMINARY ORDER

The workman is an employee of the management bank. He was charge sheeted alleging misconduct. The management

ordered domestic enquiry to enquire into the charges levelled against the workman. The Enquiry Officer found the workman guilty of the charges and proposed the punishment of issuing the warning letter to the workman. The management accepted the findings of the Enquiry Officer and imposed a punishment of warning and thereby a warning letter was issued. The period of suspension was confirmed and no salary was paid for the said period. The union took up the matter and raised an industrial dispute which resulted in the present reference.

2. The union filed a claim statement contending mainly as follows :—

The workman was charge sheeted by the charge sheet dated 25-4-1984. He was working as a Peon in the Tripunithura Branch of the Bank. It was alleged that at about 4.30 p.m. on 17-4-1984 the workman assaulted one Reghunandan, a customer of the Bank. The alleged incident took place at a place far away from the Bank and the incident by itself had nothing to do with the official duties assigned to the workman. The workman was suspended by an order dated 25-4-1984. On 19-4-1984 the workman was arrested on the same charges and he was released on bail. The said criminal case was compromised on 1-10-1985. The Judicial Ist Class Magistrate, Ernakulam by the order dated 1-10-1985 acquitted the accused under Section 320(8) of the Code of Criminal Procedure. An enquiry was conducted against the workman. The Enquiry Officer found the workman guilty of the charges levelled against him. The Enquiry Officer recommended the punishment of warning as envisaged under Chapter II Regulation 4 Clause (a) of the Canara Bank Service Code. The Management by their letter dated 10-3-1987 imposed the punishment of warning. The period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 is not treated as spent on duty, the said period will not be reckoned for any purpose whatsoever. The workman submitted an appeal to the Chairman and Managing Director of the Bank. That appeal was rejected. The workman is not guilty of the allegations made against him, the findings of the Enquiry Officer are illegal and perverse. The said findings are liable to be set aside. The punishment imposed on the workman is illegal. The management has not succeeded to substantiate the charges. The charges alleged against the workman will not amount to misconduct. The allegation that the conduct of the workman is prejudicial to the interest of the Bank is not correct. The allegations different from the charge sheet was brought out and evidence has been tendered during the enquiry. So the findings of such enquiry cannot be accepted. The management by a letter dated 2-4-1985 assured the workman that the disciplinary action initiated against the workman would be reconsidered on the production of the Court Order indicating that the workman is no way involved in the criminal case No. 70/84. The workman submitted the certified copies of the order clearly indicating that the workman is excluded from the list of accused and that he is not an accused at all in the Criminal Case No. 70/84. But the management proceeded with the enquiry. The enquiry was an empty formality. The disciplinary action was initiated on the basis of report submitted to Divisional Manager by the Senior Manager of the Branch. The said report was on the basis of information received from the police station. The complainant himself wrote to the Bank's authorities that his first complaint to the bank was not intended as complaint against the workman and that he has no complaint against the workman. But the disciplinary authorities continued the proceedings against the workman. The said action of the management amounts to victimisation. The enquiry was conducted by a legally qualified person who is fully conversant with the proceedings of domestic enquiries. The workman and the defence representative lack legal knowledge and experience. The request of the workman to engage a lawyer was disallowed. The said denial amounts to denial of natural justice. The findings in the enquiry are not based on the evidence on record. There was no material available on record to find the workman guilty of the charges. Hence, the union requested for setting aside the enquiry and the punishment imposed on the workman.

3. The management filed a written statement containing mainly as follows :—

The workman Sri K. Reghunandan was working as a peon in Tripunithura Branch of the Canara Bank from 19-8-1981 to 1-7-1985. The Bank received a complaint from Sri Reghunandan a customer of the Tripunithura Branch

and hold of S.B. account No. 16774 of the Tripunithura Branch. It was alleged in that letter that on 17-4-1984 while he was returning from his office, the workman herein along with some others assaulted him at about 4.30 p.m. near the Eroor-Puthiya Road bus stop. Sri Raghunandan has also informed the bank that as a result of the physical assault on him, He lost his S.B. pass book, a sum of Rs. 400 and some keys of Cash chest. The Police had registered case against the workman and others. The workman was arrested by the Police on 19-4-1984 and registered the case No. 70/84. The allegation against the workman was serious and so enquiry was initiated against him as per the Canara Bank Service Code and in terms of the Bipartite Settlements/Awards. The granting of bail and the compromise of the criminal case would not preclude the management from taking any departmental action against the workman. The domestic enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice and the prevailing rules of the service code. The workman was found guilty of the charges levelled against him. The management accepted the findings of the Enquiry Officer and imposed the penalty of warning and treated the period of suspension as not spent on duty. The misconduct committed by the workman was grave warranting severe punishment. But the management took a lenient view and awarded a lesser punishment. The findings of the Enquiry Officer are not perverse. But the findings are based on the evidence on record. The charge levelled against the workman amounts to misconduct within the meaning of Chapter XI, Regulation 3, Clause (m) of the Canara Bank Service Code. The conduct of the workman is an act prejudicial to the interest of the bank. The mere fact that the incident took place outside the Bank premises will not change the character of misconduct. The charge sheet was issued on 25-4-1984. The management has not taken any contradictory stand. The allegation different from the charge sheet was not brought out in evidence. The compromise of the case is not relevant in the departmental enquiry. The enquiry was conducted to enquire into the charges framed against the workman. The action of the management is only bona fide. The complainant Raghunandan did not deny the letter alleging the misconduct against the workman. But the complainant by his subsequent letter dated 22-4-1986 stated that he had no complaint against the workman. The evidence given by the complainant would prove the charge against the workman. The Enquiry Officer assessed the entire evidence on record and came to a proper conclusion. The enquiry officer is not a practising lawyer. There was no presenting officer in the enquiry. Under the Canara Bank Service Code the employee can engage a member of his union or colleague to defend his case. The employee has no right to appoint a stranger to defend his case in the enquiry. The employee Sri K. Radhakrishnan appointed Sri K. V. George as defence representative. No prejudice whatsoever was caused to the workman. He has no right to defend by a lawyer in the domestic enquiry. The charge sheet contained specific allegations which amount to misconduct. There was no denial of the opportunity to defend the charge framed against the workman. Hence, the management prayed for upholding the action taken by them.

4. The union challenged the very validity of the domestic enquiry and the findings thereon. So, this court was pleased to consider the validity of the domestic enquiry and the findings thereon as a preliminary point.

5. Before this court the enquiry officer was examined as MW1 and the workman was examined as WW1. The Entire enquiry file containing the enquiry report and the connected papers was marked as Ext. M1. A letter dated 3-12-1984 sent by the workman to the Enquiry Officer was marked as Ext. M1(a).

6. The Point: The workman was charge sheeted by the charge sheet dated 25-4-1984. The workman accepted the said charge sheet dated 25-4-1984. The charge levelled against the workman is as follows:

"You are working as Peon at our Tripunithura branch since 19-10-1981."

On 17-4-1984, you along with some others assaulted Shri C. Raghunandan, holder of S.B. Account No. 16774 of Canara Bank, Tripunithura branch at about 4.30 p.m. near the Eroor-Puthiya Road Bus Stop. The said Sri Raghunandan has informed the Bank that as a result of the physical assault

on him, he lost the S.B. pass book of the above account No. 16774 and Rs. 400, some important keys of Sri Raghunandan and also reported lost during the above incident.

Your above action being prejudicial to the interest of the bank, you have committed gross misconduct within the meaning of Chapter XI, Regulation 3, Clause (m) of the Canara Bank Service Code."

A reading of the said charge would show that the allegations made against the workman are specific. The union and the workman would contend that the said allegations contained in the charge would not constitute misconduct. But it is come out in evidence that the customer of the bank viz, Sri Raghunandan preferred a complaint to the bank alleging that the workman herein along with some other assaulted him on 17-4-1984 and as a result of that physical assault the said customer lost his S.B. pass Book and Rs. 400 and some important keys. It is true that the alleged incident took place outside the bank premises. But it is to be noted that the complaint was made by one of the customers of the bank. There is no dispute that the complainant Sri Raghunandan was having account with the Tripunithura Branch of the Bank wherein workman was working as a peon at the relevant time. The alleged assault on a customer of the Bank, by an employee of the bank and the complaint preferred by the said customer are sufficient enough for the management Bank to take disciplinary action. There is nothing wrong in treating the said action of the workman as prejudicial to the interest of the bank. It is further to be noted that it is clearly stated that the misconduct committed by the workman would come under Chapter XI Regulation 3, Clause (m) of the Canara Bank Service Code. So the charge alleged against the workman can be treated as misconduct as provided in the Canara Bank Service Code.

7. The management ordered domestic enquiry by appointing an officer of the bank as Enquiry Officer. The Enquiry Officer as MW1 has deposed before this Court that before joining in the service of the bank, he was a practising Lawyer and he had five years standing as an Advocate. But the fact that the Enquiry Officer is having legal knowledge or he is a legally trained person will not preclude him from acting as an Enquiry Officer. No prejudice will be caused to the workman on the mere fact that the Enquiry Officer is a legally trained person. It is further to be noted that there was no presenting officer to prosecute the charges levelled against the workman. So the request of the workman for permitting him to engage a lawyer of his choice to defend his case in the enquiry cannot be granted. So the said action of the Enquiry Officer in refusing to engage a defence lawyer cannot be treated as an act prejudicial to the interest of the workman. That cannot be taken as a ground to hold that it amounts to denial of opportunities. Moreover, there is no provision in the Canara Bank Service Code to permit an employee to engage a lawyer to defend his case in a domestic enquiry. It is further to be noted that the workman herein was defended by an office bearer of his union. The workman as WW1 has categorically admitted the fact that he was defended by a defence representative who was the then Assistant Secretary of his union. It is also deposed by the workman that his defence representative K. V. George had much experience in participating as a defence representative in domestic enquiries. So the workman was fully and effectively represented in the domestic enquiry. The enquiry proceedings and the deposition of the workman as WW1 before this court would clearly establish the fact that the workman actively participated in the enquiry by cross-examining all the management witnesses. The mere fact that the workman was not present at the time of the chief examination of the management witnesses cannot be taken as a ground to hold that prejudice has been caused to the workman. On the other hand, the Enquiry Officer was very much practical in giving the workman full opportunity to cross-examine all the management witnesses. The workman was served with list of witnesses and documents and the copy of the enquiry proceedings. He was also served with the copy of the depositions of the witnesses who were examined in chief. It is only after receiving all these documents the workman with the assistance of his defence representative cross-examined all the management witnesses. It is further to be noted that the management witnesses were examined in chief only because of the failure of the workman to participate in the enquiry. The Enquiry Officer cannot be found fault with. On the other hand, the workman was at fault, he neglected to participate in the enquiry. It is further to be noted that the Enquiry Offi-

cer had issued notice of the enquiry in advance and the workman was fully aware of the posting of the enquiry. So, there is nothing on record to hold that the Enquiry Officer failed to comply with the principles of natural justice. On the other hand, the Enquiry Officer has conducted the enquiry in accordance with the principles of natural justice. It is further to be noted at this juncture that the workman had requested for the postponement of the enquiry for one year in view of the criminal case pending before the Criminal Court. Lst. M1(a) is the letter sent by the workman to the Enquiry Officer requesting for the postponement of the enquiry for one year. The Enquiry Officer granted one year's time by granting in the said request made by the workman. The enquiry proceedings and the other available evidence would show that the Enquiry Officer had given so many adjournments as requested by the workman and his representative. So, there is nothing on record to hold that there was any violation of the principles of natural justice.

8. The union would contend that the findings in the enquiry are perverse and the said findings are not based on the evidence on record. But a reading of the enquiry report would show that the findings given by the Enquiry Officer are based on the evidence on record. The Enquiry Officer has given the reasons for his findings. The report submitted by the Enquiry Officer would clearly show that he has assessed and appreciated the evidence on record.

9. It is an admitted fact that a police case was registered against the workman, along with others on the allegation that the workman along with some others assaulted one Reghunandanan. It is also an admitted fact that the workman was arrested by the Police and subsequently released on bail. It is true that subsequently the name of the workman herein was deleted and his name was not included in the charge framed by the Criminal Court. It is also true that the said criminal case was compounded subsequently. It is also true that the complainant Reghunandanan sent another letter and in that letter it was stated that he had no complaint against the workman. But it is to be noted that the subsequent letter was sent in the year 1986. But the complainant Reghunandanan was examined before the Enquiry Officer and the complaint preferred by him to the Bank was marked in the enquiry. The complainant never denied the correctness or genuineness of the complaint preferred by him. On the other hand, he categorically deposed before the Enquiry Officer about the alleged assault by the workman and others on 17-4-1984. It is come out in evidence that as a result of the said assault said to have been taken place on 17-4-1984, the complainant Reghunandanan lost his S.B. pass book. He requested for the issuance of a duplicate pass book. The evidence of the complainant Reghunandanan was sufficient enough to infer that the workman herein was involved in that incident. There is no contra-evidence on the side of the workman. The workman has not adduced any independent evidence to establish his innocence of the charges. The evidence of the other witnesses examined in the enquiry in support of the charge would strengthen the testimony of the complainant Reghunandanan. So the appreciation of the evidence done by the Enquiry Officer can only be treated as just and proper. It is to be noted at this juncture that the degree and standard of proof and the nature of evidence required in a domestic enquiry are entirely different from that of a criminal proceedings. The subsequent compromise entered into by the parties cannot be taken as a ground to stop the departmental enquiry initiated against the workman. So, I have no hesitation to accept the findings in the enquiry. There is no sufficient ground to interfere with the findings of the Enquiry Officer.

10. In the result, the domestic enquiry and the findings are upheld as legal and valid."

III. The union representing the concerned workman has categorically challenged the sustainability of the punishment imposed on the workman Shri. Radhakrishnan according to the Union, the punishment of treating the period of suspension as not spent on duty is against the provisions contained in the Canara Bank Service Code. On the other hand the management would contend that the punishment imposed on the workman Shri Radhakrishnan is only in accordance with the provisions of the Canara Bank Service Code.

IV. The punishment imposed on the workman is only a minor punishment of warning and treating the period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 as not spent on duty. So the punishment imposed on the workman Shri Radhakrishnan is only a minor punishment and so this Court has no jurisdiction or Authority to interfere with the order of punishment passed by the management. The section 11A of the I.D. Act only provides jurisdiction for this Court to interfere with the punishment in case of discharge or dismissal of workman. Thus under Section 11A of the I.D. Act this Court has no jurisdiction to interfere with the order of punishment passed by the management herein. But the definite case of the management is that the punishment is imposed on the basis of the provisions contained in the Canara Bank Service Code. If the punishment imposed on the workman is against the provisions of the Canara Bank Service Code, then this Court is empowered to consider the very sustainability and propriety of the punishment imposed on the workman herein.

V. Chapter XI of the Canara Bank Service Code deals with the disciplinary actions. Chapter XI, Regulation 4 of the Service Code prescribes the punishments which can be imposed on the workman for proved gross misconduct. The workman was charge sheeted for the misconduct under Chapter XI, Regulation 3, Clause (m) of the service Code i.e. "doing any act which prejudicial to the interest of the Bank". The said misconduct is a prejudicial to the interest of the Bank". The said misconduct is a gross misconduct. The workman was found guilty of the said misconduct. So the management will be at liberty to impose any of the punishments prescribed in Chapter XI, Regulation 4 of the Service Code. It is an admitted fact that the management imposed the punishment on the workman under Chapter XI Regulation 4 clause (a) of the Service Code. Then the management can only imposed the punishment of warning. It is true that the management has imposed the punishment of warning. In addition to that the period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 was treated as period not spent on duty. Thereby the workman was not given full wages. This would give another indication that there will be a break of service. But, there is no provision under Chapter XI, Regulation 4 of the Service Code to impose the punishment of imposing break of service or treating the period of suspension as period not spent on duty and withholding of full wages for the said period cannot be treated as a punishment imposed under the provisions of the Service Code.

VI. Chapter XI Regulation 21, Clause 6 of the Service Code reads as follows :—

"If after steps have been taken to prosecute the employee under clause (2) of this Regulation he is not put on trial within a year of the commission of the offence, the employee may be dealt with as if he has committed an act of misconduct as defined in this Chapter provided that if the authority which was to start prosecution proceedings refuses to do so or comes to the conclusion that there is no case for prosecution, the employee may be proceeded against under the provisions of sub-clause (b) of clause (3) of this Regulation but he shall be deemed to have been on duty during the period of suspension, if any, and shall be entitled to full salary and allowances minus such subsistence allowance as he has drawn and to all other privileges for such period. If after enquiry it is decided not to continue the employee in service, he shall be liable only to termination with 3 months pay and allowances in lieu of notice.

Provided that if during the pendency of the enquiry the employee is put on trial the enquiry shall be stayed after which the provisions of clause (3) of this Regulation shall apply. Provided further that if the employee is put on trial after the conclusion of the enquiry but before the passing of the order thereon, the passing of the order shall be stayed after which the provisions of clause (3) of this Regulation shall apply.

Provided further that if the employee is put on trial the conclusion of the enquiry and order thereon an appeal under Regulation 20, if one is pending shall be stayed after which the provisions of clause (3) of this Regulation shall apply.'

So, the provisions of this Clause would show that the workman herein is entitled for his full wages during the period of suspension. It would also reveal the fact that the period of suspension has to be treated as the period spent on duty. This is further clarified by the provisions contained in Chapter XI Regulation 21 Clause 3(b) of the Service Code. In this sub clause also it is made clear that the period of suspension has to be treated as the period spent on duty. The proviso to Chapter XI Regulation 21 Clause 3(b) cannot be made applicable in the case of Sri. Radhakrishnan. Because in this case there was no charge sheet framed by the Criminal Court against the workman Sri. Radhakrishnan. Thus in this case the question of acquittal by giving the benefit of doubt does not arise at all. In the present case on my hand, the workman was never charge sheeted by the Criminal Court. He was not arrayed as an Accused in the Criminal Case. Only the Police registered a crime against the workman and subsequently the name of the workman herein was deleted from F.I.R. Thus, it is crystal clear that the provisions of Chapter XI Regulation 21 Clause 6 of the service Code can be made applicable in the case of the workman. Under this Clause 6 the workman is entitled for his full salary for the period of suspension. Moreover, the period of suspension must be treated as the period spent on duty. So, I have no hesitation to invoke the provisions contained in Chapter XI Regulation 21 Clause 6 of the Canara Bank Service Code. If that be so, the action of the management in treating the period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 as period not spent on duty can only be held as unjustified. The action of the management in not giving the full salary to the workman during the said period of suspension is also unjustified. But the management is well justified in issuing a warning letter to the workman Shri. Radhakrishnan.

VII. In the result, the punishment of warning imposed on the workman is upheld. The punishment of treating the period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 as not spent on duty is set aside. The management is directed to treat the period of suspension from 2-5-1984 to 11-6-1985 as the period spent on duty. The management is further directed to pay the full wages to the workman Sri. Radhakrishnan for the said period of suspension. An award is passed accordingly.

10-5-1993.
Ernakulam.

M. V. VISHWANATHAN, Presiding Officer.
APPENDIX

Witness examined on the side of Management :

MW1. Sri. Simon Ded Singh.

Witness examined on the side of workman:

WW1. Sri. Radhakrishnan.

Exhibits marked on the side of Management :

Ext. M1.—File containing proceedings and findings of domestic enquiry held against the workman.

Ext. M1(a)—Letter dated 3-12-1984 from the workman to the Enquiry Officer.

Presiding Officer

दिल्ली, 31 मई, 1993

का.आ. 1383.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के

निष्पत्ति को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-5-1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या फ़द-12012/52/91-आई आर (वा-II)]

हरिश गाूर, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1993

S.O. 1383.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, HYDERABAD as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 28-5-93.

[No. L-12012/52/91 IR(B-II)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

Present :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal,
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 74 OF 1991

BETWEEN

The General Secretary, Union Bank Employees Union,
A.P., R. No. 3 Unity House, 1st Floor, Abid Road,
Hyderabad. Petitioner.

AND

The General Manager, Union Bank of India, Regional
Office, Lata Complex, Hud Floor, Nampalli, Hydera-
bad. Respondent.

Appearances :

Sri P. Kishan Babu, Petitioner in person.

Sri G. Ramachandra Rao, Advocate for the Respondent-
Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-12012/52/91-IR B.II dt. 31-7-1991 and 11-10-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of the Deputy General Manager, Union Bank of India, Zonal Office, Bangalore to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of the Deputy General Manager, Union Bank of India, Zonal Office, Bangalore was justified in stopping the payment of Telex Operator special allowance of Rs. 145.00 per month to Sri P. Kishan Babu ? If not what relief the workman is entitled to ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 74 of 1991 and notices were sent to both the parties.

2. The claim statement filed by the General Secretary, Union Bank Employees' Union, Hyderabad runs thus : Sri P. Kishan Babu, who was working as Typist/Clerk at the Regional Office, Union Bank of India, Hyderabad had been assigned with the duties of Telex Operator at its Hyderabad Main Branch by the Management of Union Bank of India as per provisions of the promotion policy agreement. The post of Telex Operator carries a special allowance of Rs. 145.00 for performing additional duties of operating Telex Machine besides the normal duties of a Typist or Typist/Clerk. This post has to be offered to Senior most employee among Typist/Typist-Clerk/Clerk-Typist available at the station where vacancy exists. The Management has been assigning the post to the senior most employee among the Typist/Typist-Clerk/Clerk-Typist available at the station till the date of filing this

dispute. The relevant portion of promotion Policy agreement reads as under :

Clause—'C' Annexure III Page : 2.

"Agreement of duties of Telex Operators on regular basis will be made to the senior most Typist/Typist-Clerk/ Clerk-Typist (simple seniority) at the station".

In turns with the above provision, Sri P. Kishan Babu, Typist/ Clerk was assigned with the duties of Telex Operator as he happened to be senior most employee Typist/Typist-Clerk/ Clerk-Typist at the station of Hyderabad on 4-6-1990. But the Management had withdrawn the post of Telex Operator from Sri P. Kishan Babu, on the grounds that it was issued erroneously and offered the same to Sri V. S. K. J. Raju of Bowenpally Branch, who is junior to him. Sri P. Kishan Babu performed the duties of Telex Operator at Hyderabad Main Branch for over two months. Action of the Management in withdrawing the post is violative of Promotion Policy Agreement and it is utterly illegal. Even after this incident Management has filled up a vacancy which arose at Regional Office, Hyderabad subsequently, by one Mr. J. Nageswar Rao of Hyderabad Main Branch who is junior to many other Typist/Clerks or Clerk/Typists at the station. At present Sri P. Kishan Babu is transferred to outside the State on promotion to Officer cadre. Though the aggrieved employee is not available, in the interest justice and fairplay Hon'ble Tribunal to give correct interpretation of the Clause 'C'—Annexure III page 2 of Promotion Policy agreement and direct the Management to act accordingly.

3. The counter filed by the Management runs thus : It is stated that the post of Telex Operator has to be offered to the seniormost employee among each category of staff referred to therein in the order of priority. It is only when the employee is available in the category of Typist, it will be offered to the Typist-cum-Clerk and in the absence of any employee in the said category, it will be offered to the Clerk-Typist. It is true that Sri P. Kishan Babu Typist-Clerk was assigned the higher duties of Telex Operator as he happened to be senior-most among the three categories of employees who are eligible for higher assignment as Telex Operator. But this was by mistake in as much as an employee working in the typist-category was available for offering higher assignment as Telex Operator. In view of the same, the Respondent Bank had withdrawn the post of Telex Operator from Sri P. Kishan Babu and the said assignment as given to Sri V.S.K.J. Raju who was working as a Typist. The contention that the said Sri V.S.K.J. Raju is junior to Sri P. Kishan Babu is untenable. Sri V.S.K.J. Raju is a Typist whereas Sri P. Kishan Babu is a Typist-cum-Clerk and the question of one being senior to another in different categories does not arise. The contention that action of the management in withdrawing Sri P. Kishan Babu from the post is violative of Promotion Policy agreement and it is utterly illegal is incorrect and it is denied. The contention in para 1 of the claim statement that one Sri J. Nageswar Rao of Hyderabad Branch is junior among other Typist-cum-Clerks or Clerk-cum-Typists at the Station is incorrect and it is denied. He is only Typist and as such he comes in the 1st category of eligible employees out of the three categories referred to in the claim statement. The contention raised in para 2 of the claim statement is untenable. In as much as Sri P. Kishan Babu is already promoted to Officer cadre, the dispute between the parties if any regarding withdrawal of Sri P. Kishan Babu from the post of Telex Operator ceases to exist and he is not entitled to any relief. In view of the same, it is not necessary or incumbent upon this Hon'ble Tribunal to adjudicate upon a dispute only for academic purpose though the dispute does not exist now. The provisions regarding assignment of duties of Telex Operator on regular basis are contained in the revised promotion agreement for Award Staff and the same was circulated by the Bank under Staff Circular No. 2806 dt. 15-5-1985. Clause (e) of the aforesaid Circular reads follows :

"Assignment of duties of Telex Operators on regular basis will be made to the seniormost Typist/Typist-cum-Clerk/Typist (Simple seniority) at the Station."

As per the practice followed in the Bank, the correct interpretation of the above mentioned provision is that as and when a vacancy of Telex Operator arises first preference will be given to the Typist (i.e.) if at a particular station, typists are available, then the post of Telex Operator will be assigned

to the seniormost among Typists. If there are no Typists at the concerned Station then the senior-most amongst the Typist-cum-Clerks will be given the higher assignment of Telex Operator. In the absence of persons in any of the aforesaid two categories, the senior-most among the category of Clerk-cum-Typist will be given the higher assignment as Telex Operator. In or about June, 1990 a post of Telex Operator has arisen at Hyderabad main branch of the Bank. Sri V.S.K.J. Raju was the seniormost Typist available at the Hyderabad Station and in view of the same, he should have been given the higher assignment of the post of Telex Operator. But erroneously the post of the Telex Operator was given to Sri P. Kishan Babu who was working as 'Clerk-cum-Typist'. Soon after this mistake was realised, the post of Telex Operator was withdrawn from Sri P. Kishan Babu on 10-7-1990 and subsequently, the said post of a Telex Operator was filled up Sri V.S.K.J. Raju. The said action of the Respondent Bank is in accordance with the provisions contained in the above mentioned promotion policy and the action taken by the management is valid and just. It is further stated that interpretation sought to be placed by the petitioner is contrary to the letter and spirit of the promotion policy referred to above. Further stated that the reference made by the Government of India to this Tribunal for adjudication is not valid as it does not constitute an industrial dispute within the meaning of the Industrial Disputes Act 1947. Sri P. Kishan Babu was earlier posted as Telex Operator and later withdrawn was promoted to the Officer cadre and the dispute if any between the parties ceases to exist as on the date of reference. Therefore, it is prayed that the reference made to this Tribunal be rejected by upholding the action of the Management as valid and justified.

4. No oral or documentary evidence was adduced on either side. Arguments on both sides heard.

5. The contention of the Petitioner is that he was working as Typist/Clerk at the Regional Office, of the Respondent Bank and he was assigned with the duties of Telex Operator as he happened to be the seniormost employee Typist/Typist-Clerk/Clerk-Typist at the station of Hyderabad on 4-6-1990 and after two months the Management had withdrawn the post of Telex Operator from the Petitioner on the grounds that it was issued erroneously and offered the same to Sri V. S. K. J. Raju who is junior to the Petitioner. The action of the Management in withdrawing the post is violative of Promotion Policy Agreement and it is illegal. On the other hand the Respondent-Management stated in its counter that it is true that Sri P. Kishan Babu Typist-Clerk was assigned the higher duties of Telex-Operator as he happened to be seniormost among the three categories of employees who are eligible for higher assignment as Telex Operator. But this was by mistake in as much as an employee working in the Typist-category was available for offering higher assignment as Telex Operator. On account of this the Respondent Bank had withdrawn the post of Telex Operator from Sri P. Kishan Babu and the said assignment was given to Sri V.S.K.J. Raju who was working as a Typist. Now the argument of the Petitioner-workman is that Sri V.S.K.J. Raju is junior to the Petitioner-workman. The argument of the Respondent-Management is that Sri V.S.K.J. Raju is a Typist whereas Sri P. Kishan Babu is a Typist-cum-Clerk. These two categories are different and hence there is no violation of Promotion Policy agreement in assigning the post of Telex Operator to Sri V.S.K.J. Raju. Similar is the case of Sri J. Nageswar Rao of Hyderabad Branch is junior among other Typists-cum-Clerks or Clerk-cum-Typists at the Station. Sri J. Nageswar Rao is only Typist and as such he comes in the 1st category of eligible employees out of the three categories. It is not possible to accept the contention of the Petitioner-workman that the Respondent-Management has violated the Promotion Policy Agreement by withdrawing the post from Telex Operator. Since the Petitioner-Workman has been promoted to Officer Cadre, the question of offering the post of Telex Operator does not arise now. The next aspect of interpretation of Clause 'C' Annexure III page 2 of Promotion Policy Agreement. The Respondent-Management has interpreted the above mentioned Promotion Policy agreement. It reads as follows : "As and when a vacancy of Telex Operator arises first preference will be given to the Typist, i.e. if at a particular station, Typists are available then the post of Telex Operator will be assigned to the seniormost among Typists. If there are no Typists at the concerned station then the senior most amongst the Typist-cum-Clerks will be given the higher assignment of Telex Operator. In the absence of persons in any

of the aforesaid two categories, the senior-most among the category of Clerk-cum-Typist will be given the higher assignment as 'Telex Operator'. Here in this dispute by mistake Sri P. Kishan Babu was given the post of Telex Operator, after realisation, the post of Telex Operator was withdrawn from P. Kishan Rao on 10-7-1990 and subsequently the said post of Telex Operator was filled up by Sri V.S.K.J. Raju. Hence the action of the Respondent Management was valid and just. Hence I find that the Respondent-Management has rightly withdrawn the post of a Telex Operator from the Petitioner-workman, after realising the mistake committed by the Management and followed the Clause 'C' Annexure III page 2 of Promotion Policy agreement.

6. In the result, the Management of the Deputy General Manager, Union Bank of India, Zonal Office, Bangalore was justified in stopping the payment of Telex Operator Special Allowance of Rs. 145.00 per month to Sri P. Kishan Babu and he is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 5th day of May, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal
Appendix of Evidence.

NIL

नई दिल्ली, 31, मई, 1993

का.आ.-1384 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/305/90-आई आर (वि-2)]

हरिष गौर, ई-क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1993

S.O. 1384.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, HYDERABAD as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UNION BANK OF INDIA and their workmen, which was received by the Central Government on 28-5-93.

[No. L-12012/305/90-IR(B-II)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

Present :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal,
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 1 OF 1991

BETWEEN

The General Secretary, Union Bank Employees' Union,
Room No. 3 1st Floor, Unity House, Abids, Hyderabad-500 001.
.. Petitioner.

AND

1. The Regional Manager, Union Bank of India, Lata Complex Nampally, Hyderabad Respondents
2. The Dy. General Manager, Union Bank of India, Zonal Office, 10-A Kasturba Road, Bangalore-560 001.

1317 G1/93—3

Appearances :

Sri B. Sudhakar, General Secretary, Union Bank Employees' Union, for Petitioner.

Sarvasri G. Ramachandra Rao & T. Paduranga Chary, Advocates for the Respondents.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. 12012/305/90-IR(B-II) dt. 25-1-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Union Bank of India and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management in denying promotion to Shri G. Buchaiah, Peon/Hamal, Union Bank of India Jadcherla as in the para 1.5 of the Agreement of 28-10-75 is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 1 of 1991 and notices were given to both the parties.

2. The claim statement filed by the General Secretary, Union Bank Employees' Union, Hyderabad runs thus : The Petitioner Sri G. Buchaiah was appointed as peon/Hamal in the Bank and posted at Mallial Branch on 16-2-1984. He was designated as Daftary at Mallial Branch. He was transferred to Jadcherla branch on 27-1-1989. Prior to G. Buchaiah's transfer, one Mr. Anjaiah Goud, Peon/Hamal was also transferred to Jadcherla at his request from Chittoor Branch. After Sri Buchaiah has reported on 27-1-89, a vacancy of Daftary arose at the Branch due to transfer of Sri B. Gopal, the present Daftary-Jadcherla branch to Thimmaipei. The post of Daftary should have been given to Sri G. Buchaiah as per promotion policy which states that senior most sub-staff available at the station should be given higher assignments such as Head Peons/Daftary/Bill Collector/Cash Peon etc. But Sri Anjaiah Goud has been given higher assignment of Daftary who is junior to Sri G. Buchaiah which is violative of promotion policy. (a) As per promotion policy agreement dated 28-10-75, if any employee is transferred from one area of selection to another area of selection at his request, he will be put under bar for two years for any higher assignment in the same cadre. (b) If any post carrying special allowance is to be filled up and no eligible employee is available to fill up the vacancy at the concerned area of selection, the bar imposed on the employee/employees on account of request transfer is to be waived and the senior most employee be offered with higher assignment in the same cadre as per promotion policy agreement dated 28-10-75. In the present case M/s. Buchaiah and Anjaiah Goud have been transferred to Jadcherla at their request from Mallial and Chittoor branches respectively and both of them are under bar for any higher assignment at Jadcherla and a vacancy of Daftary at Jadcherla Branch has to be filled up. Then Clause 1.5 of promotion policy agreement dated 28-10-75 should have been utilised to solve this tangle. As per Clause 1.5 of promotion policy agreement, bar imposed on those employees has to be waived and senior most among them should be offered with the post of Daftary. Accordingly Sri G. Buchaiah should have been designated as Daftary. But the Management has acted otherwise which is utterly illegal and violative of promotion agreement. It is therefore just and necessary for the Tribunal to direct the Management to designate Sri G. Buchaiah as Daftary and pay the special allowances of Daftary retrospectively from 1-2-1989.

3. The counter statement filed by the 1st Respondent runs thus : It is true that Sri K. Buchaiah and Sri Anjaiah Goud were transferred to Jadcherla Branch of the Bank from Mallial and Chittoor Branches of the Bank. Both of them were transferred at their request. The contention raised that the post of Daftary should have been given to Sri Buchaiah as per promotion policy is incorrect and untenable. It is true that the Senior sub-staff available at the station should be given higher assignment such as Head Peon, Daftary etc., but the same is not applicable in the case of Sri G. Buchaiah. It is true that Sri Anjaiah Goud was given higher assignment. But the contention that it is violative of the promotion policy is incorrect. It is true that as per the Promotion Policy issued under Circular dated 28-10-1975 if any employee is transfer-

Ex. M2 is the photostat copy of the proceedings of another Enquiry Officer's report and they are marked by consent.

5. The contention of the workman is that Sri Lakshminarayana was working as Cashier-cum-Clerk in Dena Bank, Dharmavaram Branch and he was awarded punishment of stoppage of special allowance (cash allowance) and also stoppage of one annual grace increment with cumulative effect and that the action of the Respondent in imposing two punishments on Lakshminarayana is illegal, unjust and contrary to law and against the principles of natural justice. The allegation by the Respondent is that the workman concerned was working at Nizamabad Branch, refused to take cash from the customer for issuing demand draft and violated the instruction of the Branch Manager dt. 3-10-1981, that he further alleged that the workman refused to accept cash after 2.30 P.M. and he insisted for the initial of the accountant for accepting the cash from the customer. The petitioner further submits that Lakshminarayana submitted a detailed explanation on 19-2-1982 to the charge sheet dt. 22-1-1982 denying the allegation, that the Respondent without objectively considering the explanation submitted, ordered for an enquiry, and that the Petitioner Lakshminarayana in his explanation denied the charges, that no witnesses were examined in the enquiry nor the alleged party was produced in the enquiry for cross-examination, that as per Annexure-I Clause (3) of the Bipartite Settlement dt. 17-7-1984 if any transaction is entertained after working hours, it should be duly authorised by the competent officials and that the demand of the workman for the initials of the Accountant to receive the cash after business hours is just and reasonable and that the workman deposited amount on 8-12-1981 and the same was received by the workman and that the allegation that when Lakshminarayana refused to receive cash from M/s. Ganesh Photo Emporium is false and that the charge of shouting in the office that he will claim over time wages. It is further contended that the workman is the Branch Secretary of the Union of the Petitioner, Nizamabad Bank and it is nothing but victimisation by the Management, that the punishment imposed on the workman is not proportionate to the proved charges and that the punishment imposed by the Respondent against the workman is illegal and void.

6. The contention of the Management is that the workman was Accountant of Nampally Branch, Hyderabad and he was awarded punishment for the proved act of insubordination while discharging his duties in Cash Department and the same was based on the enquiry report. There are two charges for misconduct of the workman of different nature during different periods, the punishment awarded for each charge sheet after it was duly proved in the domestic enquiry is as per the provisions of the Bipartite Settlement. Therefore, there is no legality or violation of principles of natural justice because the enquiry of the charge sheeted employee has been conducted separately for each charge, that the disciplinary authority has gone through the reply submitted by the workman and ordered an enquiry as the explanation submitted by the workman is unsatisfactory. That the enquiry was held after giving full opportunity to the workman and Enquiry Officer followed the principles of natural justice and that there is no victimisation or unfair labour practice.

7. The Respondent Management has filed only two documents i.e. Exs. M1 and M2 the copies of the proceedings of the Enquiry against the workman. Having gone through the enquiry proceedings, I find that there is nothing grave misconduct committed by the Petitioner-workman. The case of the petitioner-workman is that the charge is ambiguous in so far as there is no mention of name of the party whose cash was refused and whether there was any complaint from the said party and that no witnesses were examined in the enquiry nor the alleged party was produced in the enquiry for cross-examination, that M/s. Ganesh Photo Emporium has deposited amount on 8-12-1981 and the same was received by the Petitioner-workman and that since the petitioner-workman is an active Member of the Union he has been victimised. I see there is no reason why the petitioner-workman is inflicted with the punishment of stoppage of annual increment with cumulative effect. Considering all the facts of the case I feel that this is a fit case in which the stoppage of annual increment with cumulative effect to Sri N. Lakshminarayana, Cashier-cum-Clerk, is set aside and the lesser punishment i.e. inflicting the punishment of stoppage of special allowance (Cash Allowance) is justified.

8. In the result, the action of the Management of Dena Bank is justified in inflicting the punishment of stoppage of Special Allowance (Cash Allowance) and stoppage of annual increment with cumulative effect to Sri N. Lakshminarayana Cashier-cum-Clerk, Dharmavaram Branch is not justified. The Respondent-Management is directed to release the annual increments which were stopped to the petitioner-workman.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 7th day of April, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Presiding Officer

Appendix of Evidence.

Witnesses examined for the Workmen :

Witnesses Examined for the Management: NIL

NIL

Documents marked for the Workmen :

NIL

Documents marked for the Management :

Ex. M1 by consent—Photostat copy of the proceedings of enquiry against N. Lakshminarayana, Head Cashier as per charge sheet No. RP/PEH/533/82, dt. 22-1-82.

Ex. M2 by consent—Photostat copy of the proceedings of enquiry against N. Lakshminarayana, Head Cashier, Dharmavaram vice charge sheet No. RP/PER/5273/83 dt. 9-6-1982.

नई दिल्ली, 1 जून 1993

का.ग्रा. 1386.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नम्बर (1) बम्बई के प्रबन्धतन्त्र के संबन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मैसर्स ए बी सी एण्ड सन्स प्रा० लि० के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31 मई, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31012/24/90-आर्.आर. (विविध)]

बी एन डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1993

S.O. 1386—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay No. 1 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. ABC and Sons Pvt. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 31st May, 1993.

[No. L-31012/24/90 IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT BOMBAY

Present :

Justice Shri R. G. Sindhakar, Presiding Officer.
REFERENCE NO. CGIT-1/84 OF 1990

Parties :

The Employers in relation to the Management of M/s. ABC and Sons Pvt. Ltd., Bombay.

AND

Their Workmen.

of them were transferred at their request. A vacancy of

[No. L-12012/1988/86-D II-A]
HARISH GOUR, Desk Officer

Appearances :

For the Management.—Shri Talsania Advocate.
For the workmen.—Shri M. B. Anchan Advocate

Dated this 19th day of May 1993

Industry : Port & Dock STATE : Maharashtra
Bombay, dated the 19th May 1993

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Labour Department/Shram Mantralay on 24th October 1990. The reference is to the effect :

"Whether the action of the management of Messrs ABC and Sons Pvt. Ltd., Bombay, a Stevedore Employer operating in the major port of Bombay in dismissing the services of Shri Chandrahas D. Juwarkar, Barge Khalasi, with effect from 24-01-1987 is justified. If not what relief the workman concerned is entitled to?"

The workman's widow has filed her statement of claim, since the workman had expired after the reference was made. The widow has also filed her affidavit to this effect on 22-03-1991.

The employers in relation to the management of Messrs ABC & Sons Pvt. Ltd. have filed their written statement.

During the pendency of this proceeding, the parties namely, the widow of the workman and the management have arrived at a settlement. The settlement is at Exhibit No. 2. The Parties have signed this settlement and their learned advocates have also affixed their signatures and confirmed their signatures and the settlement terms. The widow is to receive Rs. 12,500/- (Rupees : Twelve Thousand five hundred only.) in full and final settlement of the claims of the workman. In view of the settlement arrived at, the reference is to be disposed off and the award in terms of the settlement. No order as to costs.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1 BOMBAY

REFERENCE NO. CGIT-84 OF 1990

Employer in relation to the management of Ardeshir
B. Cursetjee and Sons (P) Ltd.

AND

Their workman (Chandrabhas D. Juwarkar).

- (1) The Management agree to pay to the widow of the workman Mrs. Smita C. Juwarkar and the said Mrs. Smita C. Juwarkar agree to receive sum of Rs. 12,500/- (Rupees Twelve thousand five hundred only) in full and final settlement of all the claims of the workman viz. late Chandrabhas D. Juwarkar in respect of his employment in the Management.
- (2) Upon payment of the said amount of Rs. 12,500/- neither the widow of the workman nor any other legal heir of the late Mr. Chandrabhas D. Juwarkar shall have any claim of any nature against the management.
- (3) The payment of the said amount of Rs. 12,500/- will be made by the Management to Smt. Smita C. Juwarkar on or before 7th June 1993.
- (4) The Management will also pay amount if any, lying in the account of the Provident Fund of late Mr. Chandrabhas D. Juwarkar.
- (5) Reference to stand disposed off in terms of these consent terms with no order as to costs.

(M. B. Anchan)
Advocate for the Workman
(S. K. Talsania)
Advocate for the Management.
(Smita C. Juwarkar)
(Capt. N. B. Jamnerkar)
for Ardeshir B. Cursetjee and
Sons (P) Ltd.

नई दिल्ली, 1 जून, 1993

का.शा. 1387—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नम्बर (1) हैदराबाद के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रथिहरण, एयर इण्डिया, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27 मई, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-11012/27/87-डी II(बी) डी-III(बी)]

बी एम डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1993

S.O. 1387.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad No. 1 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on 27th May, 1993.

[No. L-11012/27/87-DII(B)/D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (C) AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal,
Industrial Dispute No. 76 of 1988

BETWEEN :

The Workmen of Air India, Hyderabad represented by
its Regional Secretary Sri Elisha, Air Corporation
Employees' Union. ...Petitioner.

AND

The Management of Air India, Hyderabad. ...Respondent

APPEARANCES :

M/s. A. K. Jayaprakash Rao, P. Damodar Reddy,
V. N. Goud and Ch. Laxminarayan, Advocates—for
the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy and G. Sudha, Advocates—for
the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. 1-11012/27/87-D.II(B)/D.III(B) dt. 29-7-1988 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Air India, Hyderabad and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action on the part of the management of M/s. Air India in terminating the services of Smt. N. Kalavathi as a casual sweeper on 8-6-1984 and engaging her as a contract labour with effect from 9-6-1984 is legal and justified. If not, to what relief she is entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 76 of 1988 and notice were sent to both the parties.

2. The averments of the claim statement read as follows :

The petitioner submits Smt. N. Kalavathi was appointed as Sweeper in the year 1978 and the continuously worked without any interruption or break in service. The Respondent abruptly terminated her services w.e.f. 8-6-1984 without giving any notice or without paying any notice pay and retrenchment compensation and informed her that the sweeping work has been entrusted to a Contractor. The Petitioner submits the action of the Respondent in terminating her services as Casual Sweeper with effect from 8-6-1984 and engaging her as Contract Labour under a Contractor w.e.f. 9-6-1984 attracts the enumerated unfair labour practices under Section 2(f)(a) of the I.D. Act. The Petitioner submits that Smt. Kalavathi worked as Casual Sweeper for more than the stipulated period for regular absorption into the Corporation service, the Respondent without absorbing her services on regular basis, entrusted the sweeping work to a Contractor. The petitioner submits that the nature of work done by Smt. Kalavathi was of regular nature and she was working as Sweeper right from 1978 and her wages were being paid by Air India directly. The petitioner further submits that the services of all casual sweepers working at Madras and Bombay were regularised into Corporation service whereas the Respondent has denied this benefit to Smt. Kalavathi. The continuation of said Kalavathi as Casual Sweeper for years together was only the main objective of the Respondent to deprive her the status and privilege of becoming a regular workman of the Corporation. The petition submits the Respondent has not obtained any Licence as contemplated under the Contractor Labour Regulation and Abolition Act 1970 and as such the action of the Respondent in entrusting the work of Sweeping to a Contractor is illegal and invalid. The petitioner submits that the Respondent in order to create artificial break in service of Smt. Kalavathi has shown her sister's name Yamma for some period, though Smt. Kalavathi was working as casual sweeper under the Respondent without any interruption or break in service with a view to deprive her legitimate right of becoming a regular employee of the Corporation. Smt. Kalavathi made several representations and also preferred an Appeal to the Managing Director on 23-1-1986 and the said appeal has not seen the light of the day. The petitioner, prays that this Hon'ble Court may be pleased to hold that the action of the Respondent in abruptly terminating the services of Smt. N. Kalavathi as Casual Sweeper from 8-6-1984 and engaging her as Contractor, under a Contractor, w.e.f. 9-6-1984 as illegal, unjust, contrary to law and in violation of Section 25-F, 25-N of I.D. Act and that she is entitled for continuation in service as a Regular Sweeper from the date of her first appointment.

3. The averments of the counter filed by the Respondent read as follows :

It is submitted that the Petitioner Union has no right to espouse the cause of Smt. N. Kalavathi, and also not having the representative capacity to espouse any dispute. The Union which is recognised by the Respondent, is the 'Air India Employees' Guild'. That the allegation that Smt. Kalavathi was engaged as Sweeper in the year 1978 and she was continuously working without any interruption or break in service is not correct. In 1978, Respondent was having a booking office at Fateh Maidan Road, i.e. a small shop and for sweeping the said shop, Smt. N. Kalavathi was engaged. Everyday, hardly she had 20 minutes work and she was paid a consolidated amount of Rs. 50.00. The allegation that the Respondent abruptly terminated the services of Smt. N. Kalavathi w.e.f. 8-6-1984 is not correct. That in the year 1978-79 whenever there was work, the Respondent used to pay Rs. 6.25 per day for sweeping and cleaning the office. The Respondent vacated the said establishment at Fateh Maidan Road, Hyderabad and shifted their office to Sumrat Complex, Saifabad, Hyderabad. In normal course of their business, the Respondent has given the cleaning and maintenance of the building to one Contractor by name M/s. Kayor Associates. The question of engaging the sweeper by the Respondent does not arise. It is submitted that there is no permanent vacancy of Sweeper's post at the Hyderabad Office of the Respondent. Initially the Hyderabad

Office was established only for the purpose of booking Smt. N. Kalavathi whenever there was work, she was given work and she worked. So the question of the Respondent abruptly terminating her service without giving any retrenchment benefits does not arise. The work done by Kalavathi is purely on casual basis. Smt. N. Kalavathi herself approached M/s. Kayor Associates for work and she was working for them, and the wages are also paid by the Contractor. The Respondent has nothing to do either with regard to her service conditions or with regard to her termination. It may be noticed that the Management has no knowledge as to what has transpired between N. Kalavathi and the Contractor M/s. Kayor Associates and what were the terms between them. The allegation that she was working as a Casual Sweeper for more than the stipulated period for regular absorption is not correct. Engaging the Contractor are the Policy decision of the Respondent. One cannot make a demand by looking to Bombay and Madras Office to create the post of Sweeper at Hyderabad establishment as they are different and the value of work is more. The allegation that Kalavathi was denied the benefit of regularisation is not correct, as no appointment order was given to Kalavathi. The allegation that Kalavathi was working without any interruption or break in service, with a view to deprive her legitimate right of becoming a regular employee of the Corporation, her sister's name was shown for some period is not correct. The Union cannot term that her working from 9-6-1984 is unjust and it is violative of Sec. 25(F) of the I.D. Act. The relief prayed by the Petitioner Union is nothing but violative of the statutory provisions. As such, the relief is bad in law, and the petition be dismissed and reject the reference.

4. W.W1 and W.W2 were examined on behalf of the Petitioner-Workman and marked Exs. W1 to W26. M.W1 to M.W3 were examined on behalf of the Respondent-Management and Exs. M1 to M10 were marked on its side.

5. The evidence of W.W1 who is the Petitioner-workman in this case, is that she is working as Sweeper in Air India, Hyderabad under the control of Contractors, that she joined as Sweeper in the year 1978 in Air India, Hyderabad, that she is full time Sweeper working from 8.00 hours to 16.00 hours every day, that Air India removed her on 8-6-1984, that she was not given any notice before the termination order and not paid any wages in lieu of notice. However she was informed that she has to work as a contract labour under a Contractor. Air India has been paying her wages every time before termination. That the Air India removed her to avoid making her services permanent. That after termination of her services as Sweeper, she made a representation to Air India to make her permanent in Air India. Ex. W1 is the appeal made to the Management on 23-1-1986 and also made representation to the Air Corporation Employees Union, Air India Region. Ex. W2 dt. 1-3-1986 the Union wrote a letter instructing the Regional Secretary to initiate action with Air India. The Regional Secretary raised an I.D. and she authorised the Regional Secretary in her letter dated 20-6-1986 marked as Ex. W3, to represent her in the dispute. In the year 1981 the Attender working in Air India wanted her to get some workman to do work in the office in the year 1981. Then she took her sister, by name, Yamma and she worked in the office for about one week in the year 1981 and took the wages.

6. The evidence of W.W2 in brief as follows he is the Secretary of the Air Corporation Employees Union. He is acquainted with the facts of this case. Kalavathi is a Member of their Union. Ex. W3 is the authorisation given to him by the worker for representing her case. The worker was working as a Sweeper on contractual basis in the Air India from the year 1978. In the year 1984 Air India transferred her services to M/s. Kayor Associates with whom Air India entered into a contract. Till then Air India was paying wages to the worker directly. Ex. W25 is a notification issued by Maharashtra Government under Section 10 of the Contract Labour Act of 1970. Ex. W26 is a letter addressed by Air India Manager, Hyderabad to Asstt. Personnel Officer, Madras on 5-4-1984 regarding the subject of contract labour. In the Madras Office of the Air India, Sweepers are appointed as regular employees.

7. The Respondent-Management examined three witnesses namely M.W1, M.W2 and M.W3. The evidence of M.W1

in brief are as follows: He has been working as District Sales Manager in the Respondent-Corporation since 1977. Initially the Respondent Corporation was situated in Fateh Maidan Road, Hyderabad and it was continued in that building till 1981 December. Thereafter the Respondent Corporation was shifted to Samrat Complex in Safabad opposite Accountant General Office. When the office was situated in Fateh Maidan Road, a part-time sweeper was appointed and the sweeper has to work for half-an-hour in a day. The petitioner was appointed as part-time Sweeper in the Respondent Corporation at Hyderabad and she was working in the Respondent Corporation at Hyderabad and she was working in the Respondent Corporation by the time he was transferred to Hyderabad Office of the Respondent Corporation in the year 1978. There is no permanent Sweeper post created in the Hyderabad Branch of the Respondent-Corporation. The petitioner was appointed as a part-time sweeper on casual basis. After the office was shifted to Samrat Complex, the sweeping and maintenance of office was given to a contractor by name Koyar Associates and they have been carrying out the jobs sweeping and cleaning of the office ever since 1984. The Koyar Associates supplies three personnel to the Respondent Corporation for cleaning and maintenance, as required by the Respondent Corporation as per the terms of the contract and the petitioner is one among the said three personnel being supplied by the Koyar Associates, the Contractor. The Respondent has no administrative or supervisory control over the petitioner. The contractor will pay the salary to the petitioner. The Corporation pays the amounts under contract to the Koyar Associates by way of issuing cheques.

8. The evidence of M.W.2 is as follows: He is the Contractor for upkeep and maintenance of the Respondent Air India since 6 years. The period of contract is 2 years. The present contract will be expired by 6-6-1991. The Respondent is paying Rs. 2,100.00 per month under the contract for maintenance and up keeping. He employs the workmen as per the need to comply with the terms of the contract. He is the appointing authority of the workmen whom he engage and he will be paying the wages to them. He is the authority to sanction leave and to comply with other statutory needs of the employees. So far as the work of his contract in the Respondent Air India is concerned, he himself will be supervising the work of the employees he engaged. If there are any commission omissions in the employees engaged by him it will be brought to his notice by the principal employer i.e. the Respondent and he rectify the same. Whenever he engages more than 20 employees he obtain the licence under the Contract Labour (Regulation and Abolitions) Act, 1970 from the concerned authorities. He engaged only three persons to work in the Respondent-Air India under his contract and so there is no need to obtain any licence under Contract Labour (Regulations and Abolitions) Act, 1970 in respect of three workmen engaged by him to work in the Respondent. So he did not obtain such licence for them. Now the principal employer is the Respondent advised him to take licence under Contract Labour Act, 1970 for three persons engaged by him to work in the Respondent, under contract and so he made an application for issue of the said licence after paying the necessary payments by way of challan and the licence is yet to be issued. The petitioner has been working under him since last 6 years and she is being engaged by him to work in the Respondent since 6 years and he is paying the wages to her. The petitioner is not the employee of the Respondent. At the time of appointing her he thought that her age should be aged of about 40 years and that she is physically fit to discharge the duties he entrusted to her and so he appointed her.

9. The evidence of M.W.3 in brief are as follows: He has been working as Personnel Officer in Air India, Bombay since 1965. He knows the facts of this case. For appointment of handi-man/woman safai the procedure is that they notify the number of vacancies to the Employment Exchange at the concerned place and request them to send the list of candidates at the ratio of 1:5. The requisite qualifications for the above posts are, literate in English so as to follow simple instructions, one year's experience in the line and not more than 25 years of age, which is relaxable by five years in the case of SC/ST candidates, they will be interviewed by the Selection Committee and the Selection Committee will prepare wait list for the eligible candidates in order of merit. The selected candidates will have to be declared medically fit before appointment. Normally where the offices are located in small buildings, in places like Hyderabad,

Ahmadabad, Pune, Nagpur etc. there are no regular posts of Sweepers and the Sweeping work will be done by appointing the casual labourers. They have got personal computers and CRT sets in Hyderabad Office which is very sophisticated equipment and therefore it requires dust proof area and for that purpose they entrusted the work to the contractors. The petitioner is now working with the contractor to whom the contract was given by the Air India. They have no regular posts of Sweeper appointed by the Air India anywhere in India.

10. Ex. W1 is the Appeal for permanent job as Sweeper with Air India, Hyderabad, it is dated 23-1-1986 submitted by the Petitioner to the Respondent-Air India. Ex. W2 dated 14-3-1986 letter from Air Corporations Union, Madras authorising the Regional Secretary, A.C.E.U.I.A. Region, Hyderabad to initiate industrial dispute in the case of Mrs. Kalavathi. Ex. W4 is the letter dated 26-6-1986 addressed by the Union to the Asstt. Labour Commissioner, Hyderabad. Exs. W5 to W24 are the cash vouchers from 30-3-1982 to 1-6-1984. Ex. W25 is the Contract Labour Notification. Ex. W26 is the xerox copy of letter issued by Sales Manager to Air India Manager, Hyderabad, regarding casual labour.

11. Ex. M1 is the book let 'Air India Employees' Service Regulations'. Ex. M2 is the copy of the Licence dated 6-8-90 granted to M/s. Kayor Associates, Hyderabad. Exs. M3 to M5 are the xerox copies of the documents pertaining to contract. Exs. M6 to M10 are the specimen copies regarding appointments in the Air India etc.

12. The crucial points is whether the action on the part of the Management of M/s. Air India in terminating the services of Smt. N. Kalavathi as a casual Sweeper on 8-6-1984 and engaging her as a contract labour w.e.f. 9-6-1984 is justified or not?

13. The Petitioner was appointed as Sweeper in the year 1978 and she continuously worked without any interruption or break in service and the Respondent abruptly terminated her services with effect from 8-6-1984 without giving any notice or without paying any notice pay and retrenchment compensation and that the sweeping work has been entrusted to a Contractor. The further allegation is that the nature of work done by the Petitioner was of a regular nature and she was working as Sweeper right from 1978 and her wages were being paid by Air India directly. The contention of the Respondent-Air India is that the Petitioner was engaged as Part-time Sweeper, that whenever there was work, the Respondent-Management used to pay Rs. 6.25 per day for Sweeping and cleaning the office.

14. The evidence of M.W.1 states that the Petitioner was appointed as Part-time Sweeper in the Respondent Corporation at Hyderabad. To contradict this, there are documentary evidence to show that the Petitioner worked as Casual Labour but not as Part-time Sweeper. Exs. W5 to W23 clearly indicates that the Petitioner worked as Casual Labour. These exhibits are vouchers showing salary paid towards charges for sweeping and cleaning the office. Ex. W5 is the cash voucher dated 30-9-1982 showing that Rs. Five hundred (twenty amount paid to Mrs. Kalavathi, Casual Sweeper for office for the 26 days in September, 1982 at Rs. 20.00 per day. The last voucher is Ex. W23 dated 2nd May, 1984 wherein the Petitioner was paid Rs. 460.00 towards charges for sweeping and cleaning the B.O. for the month of April, 1984. There is no mention of Part-time Sweeper in all the vouchers i.e. Exs. W5 to W23. Hence I find that the Petitioner was engaged as Sweeper i.e. Casual Labour but not as Part-time Sweeper. The learned counsel for the Petitioner cited a ruling in Indian Airlines v. A. Philips [1989 (1) ALT, page 607] wherein it shows that casual labourer is covered under the Industrial Disputes Act, 1947. He also cited another decision of Bombay High Court in Air India v. United Labour Unions and others [1992 (1) 11 N, page 898] regarding Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, S. 10-Notification under S. 10 prohibiting contract labour for sweeping, cleaning, dusting or washing in Air India—Such workman are entitled to be absorbed as permanent workers of Air India.

"A notification under S. 10 is not a simple event. It is a matter of great moment and of serious consequences. Much space work, in the form of collection

and collection of data and other materials, consideration of such materials and evidence, discussions, deliberations and debates, and processing at various levels of the Government—all precede issue of notification under S. 10. An employment postulates a vinculum juris. The factum of employment is not disputed. The employees are admittedly there at one end of the vinculum. Who is there at the other? The contractor or Air India? The notification under S. 10 settled the question finally things are in brighter light thereafter. There is no longer any ghost of the labour contractor. There is the direct nexus between the workers and Air India.

The Petitioners have been attending to their workers admittedly for over a decade. Their areas of work are not such as require expertise or sophistication of skills. The Petitioners will be entitled to be absorbed as permanent workers in Air India."

The above cited decision applies to the Petitioner in question, since she has been working under the Respondent-Corporation w.e.f. 1978 and later under Contractor w.e.f. 9th June, 1984. Ex. W26 dt. 5th April, 1984 of Sales Manager, Air India, Hyderabad addressed to Assistant Personnel Officer, Madras indicates that the Sales Manager has himself committed in writing that he has been utilising the services of a Casual Labour for Sweeping/Cleaning of the office for the past six and seven years and the said Sales Manager, has also confirmed that the Casual Labour has been hired continuously without break right through during the past six or seven years. It clearly proved that the Petitioner has been continuously working for a number of years. If a minimum of six years from the year 1984 is deducted, the Petitioner has been continuously engaged from 1978. Hence the demand of the Petitioner to be absorbed as a permanent Sweeper in Air India from 1978 is justified, basing on the documentary evidence. In view of the above material on record, I am of the opinion that it is a fit case that the Petitioner be absorbed on permanent basis in Air India from 1978 onwards. On the other hand the Respondent-Management cited number of judgements reported in K. Govardhan Reddy v. Asstt. Engineer (Civil) [1989(3)] ALT-page 418 A.P., Eranallor Service Co-op. Bank Ltd. v. Labour Court [1986(II)] I.L.J. page 492, M.R. Mazdoor Sangh v. Indian Oil Corporation Ltd. (1990) LLR, page 307(SC), K. K. Thilakan v. Fertilizers and Chemical Travancore Ltd. [1991(2)] FLR, page 772, R. C. Cooper v. Union of India [AIR 1970(SC)] page 564, D.D.P.W.D.L.D.W.E.A. v. State of Karnataka [1990(60)] FLR page 576(SC) etc. etc. A perusal of all the above judgements, it is not very much relevant to the present case. The Petitioner-workman was first engaged by the Respondent-Manager and later, was engaged by the Contractor.

15. In the result, the action on the part of the Management of M/s. Air India in terminating the services of Smt. N. Kalavathy as a Casual Sweeper on 8th June, 1984 is not justified and engaging her as a contract labour w.e.f. 9th June, 1984 does not arise. The Respondent-Management is directed to absorb the Petitioner-workman into service with full back wages and other attendant benefits within one month from the date of publication of this Award.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 24th day of April, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined on behalf of Petitioner :

- W.W.1—N. Kalavathy.
- W.W.2—A. J. Elisha.

Witnesses Examined on behalf of Respondent :

- M.W.1—P. Ashok Kumar.
- M.W.2—K. Manohar.
- M.W.3—R. B. S. Kunde.

Documents marked for the Workmen

- Ex. W1 Dt. 23-1-86—Appeal dated 23rd January, 1986 made by N. Kalavathy to the Managing Director, Air India, Nariman Point, Bombay with regard to permanent job as Sweeper in Air India, Hyderabad.
- Ex. W2 Dt. 14-3-86—Letter dated 14th March, 1986 of Regional Secretary, Air Corporation's Employees' Union, Air India Region—Madras to Elisha A. J. Regional Secretary A.C.E.U., I.A. Region, Hyderabad authorising him to initiate action inclusive of raising Industrial Dispute in the case of Mrs. Kalavathy.
- Ex. W3 Dt. 20-6-86—Authorisation dated 20th June, 1986 of A. J. Elisha before the Asstt. Regional Commissioner (Central) Hyderguda, Hyderabad (A.P.) with regard to represent the case of Smt. Kalavathy.
- Ex. W4 Dt. 26-6-86—Representation dated 26th June, 1986 made by Regional Secretary, Air Corporation's Employees Union, Hyderabad Region to the Asstt. Labour Commissioner (L), Hyderguda, Hyderabad with regard to absorption of Mrs. Kalavathy, Casual/Permanent basis.
- Ex. W5 Dt. 30-9-82—Photostat Copy of the voucher No. 629 dated 30th September, 1982 for Rs. 520 paid to Mrs. Kalavathy by Air India, Hyderabad for September, 1982.
- Ex. W6 Dt. 1-11-82—Photostat copy of the voucher No. 724 dated 1st November, 1982 for Rs. 560 paid to Mrs. Kalavathy by Air India, Hyderabad for October, 1982.
- Ex. W7 Dt. 2-12-82—Photostat copy the voucher No. 822 dated 2nd December, 1982 for Rs. 520 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India Hyderabad for November, 1982.
- Ex. W8 Dt. 3-1-83—Photostat copy of the Voucher No. 1013 dated 3rd January, 1983 for Rs. 500 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during January, 1983.
- Ex. W9 Dt. 23-2-83—Photostat copy of the Voucher No. 1070, dated 23rd February, 1983 for Rs. 400 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during February, 1983.
- Ex. W10 Dt. 4-4-83—Photostat copy of the Voucher No. 006 dated 4th April, 1983 for Rs. 540 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during March, 1983.
- Ex. W11 Dt. 2-5-82—Photostat copy of the Voucher No. 108, dated 2nd May, 1982 for Rs. 520 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during April, 1983.
- Ex. W12 Dt. 2-6-83—Photostat copy of the Voucher No. 192 dated 2nd June, 1983 for Rs. 540 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during the month of May, 1983.
- Ex. W13 Dt. 2-7-83—Photostat copy of the Voucher No. 280 dated 2nd July, 1983 for Rs. 540 paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad for the month of June, 1983.
- Ex. W14 dated 3-8-83—Photostat Copy of the Voucher No. 368, dated 3-8-1983 for Rs. 540/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during July, 1983.
- Ex. W15, dated 3-4-83—Photostat copy of the Voucher No. 496, dated 3-4-1983 for Rs. 540/- paid to Mrs. Kalavathy in the month of April, 1983 by Air India, Hyderabad for cleaning the toilet and Office premises.
- Ex. W16, dated 4-10-83—Photostat copy of the Voucher No. 572 dated 4-10-1983 for Rs. 560/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during the month of September, 1983.
- Ex. W17, dated 2-11-83—Photostat copy of the Voucher No. 630, dated 2-11-1983 for Rs. 490/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad during the month of October, 1983.

Ex. W-18, dated 2-12-83—Photostat copy of the Voucher No. 683, dated 2-12-1983 for Rs. 520/- paid to Mrs. Kalavathy by Air India, Hyderabad during the month of November, 1983.

Ex. W-19, dated 2-1-84—Photostat copy of the Voucher No. 755, dated 2-1-1984 for Rs. 560/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad for the month of December, 1983.

Ex. W-20, dated 1-2-84—Photostat copy of the Voucher No. 832, dated 1-2-1984 for Rs. 480/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad for the month of January, 1984.

Ex. W-21, dated 2-3-84—Photostat copy of the Voucher No. 893, dated 2-3-1984 for Rs. 480/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India for the month of February, 1984.

Ex. W-22, dated 3-4-84—Photostat copy of the Voucher No. 2, dated 3-4-1984 for Rs. 520/- paid to Mrs. Kalavathy, by the Air India Hyderabad for the month of March, 1984.

Ex. W-23, dated 2-5-84—Photostat copy of the Voucher No. 70, dated 2-5-1984 for Rs. 460/- paid to Mrs. Kalavathy by the Air India, Hyderabad for the month of April, 1984.

Ex. W-24, dated 1-6-84—Photostat copy of the Voucher No. 114, dated 1-6-1984 for Rs. 540/- paid to Mrs. N. Yamma by the Air India, Hyderabad for the month of May, 1984.

Ex. W-25, dated 29-3-85—Photostat copy of the Gazette of Maharashtra with regard to Contract Labour (Regulation and abolition) Act, 1970.

Ex. W-26, dated 5-4-84—Photostat copy of the Confidential letter dated 5-4-1984 addressed to Asst. personnel Officer, Madras by the Sales Manager, Hyderabad with regard to Casual Labour.

Documents marked for the Management :

Ex. M-1 dated 28-2-1982—Booklet of the Air India Employees' Service Regulations (As amended upto 28th February, 1982).

Ex. M-2 dated 6-8-90—Photostat copy of the Licence given by the Asst. Commissioner of Labour, Hyderabad-III to M/s. KAYORR Associates, Seethaphal-mondi, Hyderabad.

Ex. M-3, dated 4-6-1988—Photostat copy of the Contract entered into between KAYORR Associates and Air India.

Ex. M-4 dated 5-6-90—Copy of the letter in by the Manager, Air India, Hyderabad to M/s. KAYORR Associates with regard to Renewal of contract of Unkeep and maintenance of Air India Premises for a further period of one year commencing from June, 06, 1990.

Ex. M-5—Photostat copy of the proforma of office letter of Air India, Madras.

Ex. M-6—Photostat copy of the proforma of Appointment order of Air India, Hyderabad.

Ex. M-7—Photostat copy of the proforma of confirmation letter of Air India, Hyderabad.

Ex. M-8—Photostat copy of the Proforma of temporary appointment letter of Air India.

Ex. M-9—Photostat copy of the Proforma of letter with regard to requirements one essential for recruitment of Handyman (Safai).

Ex. M-10—Photostat copy of the Proforma of letter of application given by the employer after selection and appointment on permanent basis by the selected candidates.

Y. V. CHALAM, Industrial Tribunal.

नई दिल्ली, 4 जून, 1993

का.आ. 1388.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कैंट बोर्ड अहमदनगर के प्रवन्धन के संवद्ध निवृत्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अतिरिक्त नं. 1 बम्बई के पंचवट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-13012/6/90-प्राई ग्रार(डीयू) (पार्टे)]

वा. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1993

S.O. 1388.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board, Ahmednagar and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-93.

[No. 13012/6/90-IR(DU) (Pt)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT BOMBAY

PRESENT :

Justice Shri R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-1/50 OF 1991

PARTIES :

The Employers in relation to the Cantonment Board, Ahmednagar.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management—No appearance.

For the Workmen—No appearance.

INDUSTRY : Cantonment Board

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 13th May, 1993.

AWARD

This is a reference made by the Central Government on 3rd June 1991. The reference is into the following point.

"Whether the action of the Management of Cantonment Board, Ahmednagar in terminating the services of Shri P. S. Salvi X-Ray Assistant with effect from 10-10-1979 and not condoning the break in service from 11-10-1979 to 31-05-1982 when he was again appointed on regular basis and not paying him the salary of X-Ray Assistant and Laboratory Technician for the period from 01-07-1978 to 31-07-1982 alongwith all other allowances is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

On receipt of this reference, notices were issued on 14th June 1991 to the Contonment Board of Ahmednagar and to the workman. It was duly served. The management was represented by Mr. Kulkarni, advocate and time was sought for filing written statement. Notice was issued to the workman directing him to file the statement of claim. Inspite of several opportunities given to the workman it was never filed. When the workman remained absent, the matter was adjourned for ex-parte hearing and several dates were fixed for the same since the post of the Presiding Officer was vacant, and the matter could not be taken up. Eventually it came up before me on 28th April 1993 on which date Ms. Furtado appeared on behalf of the workman and none for the management. Time was sought on behalf of the workman for filing the statement of claim, and the same was granted. The matter was fixed on 11th May 1993, and the management was duly served with the notice. However, there was no appearance either on behalf of the workman or on behalf of the management, and no statement of claim was filed by the workman.

The Industrial Disputes Act (Central) Rules 1957—Rule II provides the powers and procedure to be followed by conciliation officers, Boards, Courts, Tribunals, Labour Courts, National Tribunals, Industrial Tribunals etc.

The relevant Rule is Rule 10(B). From reading the said rule, it is the responsibility of the workman to file the statement of claim together with relevant documents, list of reliance and evidence before the Tribunal and such direction is expected to be given by the Central Government while referring the Industrial Dispute, that does not appear to have been done in this case. This Tribunal gave him several opportunities but it was not only not done within the prescribed period but it was never done. It is therefore, not possible to know on what basis the workman made this application and what his grievance in fact was. From the order of reference, it appears that the dispute that is referred for adjudication is :

“Whether the action of the Contonment Board Ahmednagar in terminating the services of Shri P. S. Salvi, X-Ray Assistant with effect from 10-10-1979 and not condoning the break in service from 11-10-1979 to 31-05-1982 when he was again appointed on regular basis and not paying him the salary of X-Ray Assistant & Laboratory Technician for the period from 01-07-1978 to 31-07-1988 alongwith all other allowances is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?”

It is not at all possible for this Tribunal to conclude whether the termination was not justified, that the act of condoning the break was justified ?, the non payment of salary and allowances for the period specified was proper and justified. No assistance has been given by the workman in this behalf. In these circumstances, the answer is that it is not shown that the action of the Contonment Board, Ahmednagar in terminating the services of Shri P. S. Salvi, X-Ray Asstt. w.e.f. 10-10-1979, not condoning the break in service from 11-10-1979 to 31-05-1982 and the

non payment of salary and allowances of an X-Ray Assistant and Laboratory Technician for the period from 01-07-1978 to 31-07-1988 is justified.

The question whether he is entitled to any relief, will therefore not arise.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 1993

का आ. 1389.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केंद्र बोर्ड, दिल्ली कैंट के प्रबन्धजत्न के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-13012/2/87-डी-2(बी) (पार्ट)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1993

S.O. 1389.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board, Delhi Cantt. and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-1993.

[No. L-13012/2/87-D.II(B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 58/88

In the matter of dispute between :

Shri Kokal Ram, Plumber, 1/186/170, Sadar Bazar, Delhi Cantt.

Versus

The Cantt. Executive Officer, Cantt. Board, Delhi Cantt.

APPEARANCES :

Workman in person.

Shri R. Nanawati—for the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-13012/2/87-D.II(B) dated 17-3-88 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of management of Cantt. Executive Officer, Cantt. Board Delhi in terminating the services of Shri Kokal Ram, Plumber is justified ? If not, what relief the workman is entitled to ?”

Kokal Ram workman in his statement of claim alleged that he was employed as Safai Karamchari on 21-2-66 and was promoted as Plumber later on. Due to his trade union activities the management was on the look out to victimise the workman and for that purpose a memo dated 7-4-86 containing false, frivolous and fabricated charges was served on him. He was placed under suspension. He submitted a comprehensive reply dated 14-4-86 with the said memo which was considered unsatisfactory by the management and enquiry against the workman in respect of the charges levelled was ordered on the basis of the report of the enquiry officer. He was discharged from service w.e.f. 10-3-87. The enquiry conducted against the workman was illegal, arbitrary and against the principles of natural justice on the ground that he was not afforded opportunity to defend himself, he was not allowed to have the services of a person despite his request to defend him, he was not afforded opportunity to cross-examine the witness deposing against him, copies of day to day proceedings were not supplied to him and the enquiry proceedings were conducted in utter dis-regard and patent violation of the rules governing the conditions of service of the workman. He was not allowed to produce his defence. The conclusion arrived at by the enquiry officer were perverse and the penalty imposed was shockingly disproportionate to the alleged act of misconduct.

3. On all these grounds the enquiry was illegal and the action of the management was justified.

4. The Management in its written statement alleged that the workman was allowed opportunities to defend himself cross-examine the witnesses produce defence and the proceedings conducted were fair and impartial manner. He was, however, not allowed to be represented by a legal practitioner on which order was within the rights of the enquiry officer. The workman was called several times to cross-examine the witnesses but he never attended to cross-examination the witnesses or lead any evidence. The conclusions arrived at by the enquiry officer were to be justified and the workman availed off the right to appeal and also the second appeal. He was drawing his pension and had been paid gratuity according to rules at his request after the said termination and was not entitled to any other relief.

5. The management examined Shri N. P. Dubey Office Superintendent, Cantonment Board MW1 while the workman himself appeared as WW1 in support of his defence. The following issues were framed :

(1) Whether the enquiry held against the workman is fair and proper ?

(2) As in terms of reference ?

6. I have heard representative for the parties and have gone through the record.

7. Issue No. 1

It has been urged by the management that the enquiry was conducted in a fair and proper manner and no illegality was committed by the enquiry officer. Brig. M. Gautam was Enquiry Officer and he had given full opportunity to the workman to cross-examine the witnesses of the management. There was no infirmity in the entire proceedings which was conducted by the enquiry officer according to law and

natural justice. The workman was, however, was not allowed to get himself defended through a legal practitioner which was well within the power of the enquiry officer. The workman was examined at length by the enquiry officer and charges were proved against the workman and the punishment given to him keeping in view the seriousness of the charges against him.

8. The workman representative on the other hand has urged that the workman was not allowed to be represented by a person of his choice opportunity to cross-examine the witnesses was not given to him and charges against the workman were not proved and the findings of the enquiry officer were perverse on the basis of which no punishment could be imposed upon the workman.

9. On careful perusal of the points urged by the representative for the parties, I am of the opinion that the enquiry conducted by the enquiry officer on its very face does not seem to be suffering from any infirmity which could be termed as denial of justice to the workman. The workman was never denied the right to cross-examine and it was he himself who did not cross-examine the witnesses. The workman was himself examined at length.

10. The important feature of this case was that the workman himself vide letter dated 6-6-88 photo copy of which has been admitted by him to the court has sought pension and DGRG from the management. Pension and DCRG has been taken by the workman from the management as per photo copy of the statement Ex. M-10. In his statement in the court he has denied asking for any pension or drawing any pension though he had earlier written on photo copy M-10 admitting the same and gave a note that he had received this under protest. This fact he never stated while he appeared in the court as his own witness on oath. He has already taken pension and all other pensionary benefits. Nothing has been pointed out which could materially affect the enquiry conducted by the management or the punishment imposed on the workman. I, therefore, hold that the enquiry forwarded by the management was fair and proper.

ISSUE NO. 2.

11. In view of my findings on issue No. 1 above I am of the opinion that the workman was not entitled to any other relief as the enquiry conducted by the management and the punishment imposed was fully justified. Parties shall bear their own costs.

12th April 1993.

GANPAT SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 1993

का.आ. 1390.—प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डी अन्नाहम एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध

में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम नं. 1 वर्ष 1947 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-6-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31011/17/91-आई आर (विविध)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1993

S.O. 1390.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 at Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. D. Abraham & Sons Pvt. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 1-6-93.

[No. L-31011/17/91-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT BOMBAY

PRESENT :

Justice Shri R. G. Sindhakar, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-1/84 OF 1991

PARTIES :

The Employers in relation to the Management of M/s. D. Abraham & Sons Pvt. Ltd., Bombay

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer : No appearance.

For the workmen : Mr. Wagh Advocate.

INDUSTRY : Port & Dock STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 20th day of May, 1993

AWARD

The Central Government by their order dated 10th October 1991 made the following reference to this Tribunal.

"Whether the action of the management of M/s. D. Abraham and Sons Pvt. Ltd., Bombay is justified in treating the extension of leave to their employees without pay and also to deny prefixing or suffixing leave to holiday? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?"

On receipt of this reference, notice was issued to the representative of the Transport and Dock Workers' Union, P. D'Mello Bhavan, P. D'Mello Road, Carnac Bunder, Bombay-400038, and to the Managing Director of the employer M/s. D. Abraham & Sons

Pvt. Ltd., Bombay. Mr. Wagh appeared on behalf of the Union, and there was no appearance on behalf of the management on the returnable date. On 30th January 1992, Mr. Shah was present on behalf of the management and thereafter, on the adjourned dates, none of the parties appeared. Though notices were issued and duly served, on the parties, both of them remained absent on the date fixed. However, on 13-07-1992, Mr. Wagh appeared on behalf of the Union, and none on behalf of the Management. On 03-11-1992 again, both the parties remained absent on the following dates, i.e. 30-12-1992 and 24-02-1993. Again, on 28-04-1993, there was no appearance on behalf of the management and Mr. Wagh appeared on behalf of the Union. A fresh notice was issued on the management, in spite of the service of the notice, there is no appearance on behalf of the management today.

On 30-01-1992, the parties have filed the terms of settlement. By these terms of settlement, the parties stated that "No dispute exists between the parties in respect of the present industrial dispute raised by the Union in this reference.

It is therefore, evident that the parties have amicably resolved the dispute they had on the point of extension of leave without pay and denial to prefix or suffix leave to holidays, as stated in para 1. As stated earlier, there is no appearance on behalf of the management to controvert this statement. Under these circumstances, the Award is drawn in terms of the settlement.

No order as to costs.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Ref. No. : CGIT-1/84 of 1991

M/s. D. Abraham & Sons Pvt. Ltd. Bombay

AND

Their Workmen

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR:

In the above reference the Industrial Dispute referred for adjudication of this Hon'ble Tribunal regarding the extension of leave without pay and denial of prefixing or suffixing leave to the Holiday is resolved amicably by the Transport & Dock Workers' Union, Bombay, and M/s. D. Abraham & Sons Pvt. Ltd. Bombay.

That therefore, both the parties pray that the award may please be made accordingly as no dispute exist between the Parties in respect of the Industrial Dispute raised by the Union in this reference.

M/s. D. Abraham & Sons Transport & Dock Workers Union Bombay.
Pvt. Ltd., Bombay.

Place : Bombay.

Dated : 30-1-92.

नई दिल्ली, 4 जून, 1993

का.आ. 1391.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डालमिया अन्तर्राष्ट्रीय के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अतिक्रमण बंगलोर के पंचयट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 जून, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-2(13)/36-कल-II/डी.-III(बी)]
डी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1993

S.O. 1391.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia International and their workmen, which was received by the Central Government on 1st June, 1993.

[No. L-2(18)/86-Con. II/D. III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE

Dated this 24th day of May, 1993

PRESENT :

Shri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding
Officer

CENTRAL REFERENCE NO. 46/90

I Party

L. Muniswamy
s/o Gopal,
Payavalam Post,
Via., Vettavalam,
Thiruvannamalai Taluk,
North Arcot District,
Tamil Nadu
Now residing at
C/o Narayanappa,
Someswara Colony,
Old Madivala,
Bangalore-560068

V/s.

II Party

(a) The Management
of B. R. H. Iron
Ore Mines of
M/s. Dalmia
International,
Hospet,
Bellary Dist.

(b) M. Rajakumar
s/o M. Raman,
Major, Dumper
Operator, Rasi
Cements Works,
Vishnupuram
(Wadapally)
Niryalguda Taluk,
Nalgonda Dist.,
Andhra Pradesh-508355

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its order No. L. 2(18)/86-Con.II/D. III(B) Dt. 8-8-90 under Sec. 10(2A)(1)(d) of I.D. Act 1947, the point for adjudication as per schedule to reference is :

"Whether the action of the management of M/s. Dalmia International, Hospet in terminating the services of Sri L. Muniswamy, employed through their contractor Shri Raman in their BRH Iron Ore Mines is justified ? If not, what relief is the workman entitled to ?"

2. As per reference the I party is L. Muniswamy and the II party is the Management (The Branch Manager) of BRH Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Patel Nagar, Hospet, Bellary District. The II party M/s. Dalmia International filed I.A. 2 under Order 1 Rule 10 C.P.C. on 12-11-91 praying that M. Rajkumar s/o Late M. Raman (Raising Contractor) should be impleaded as additional II party. I.A. 2 has been allowed by this Tribunal since the I party had no objections and the Legal Heir of the deceased raising contractor has been impleaded as II party (b). The original II party is therefore numbered II party (a). Since the II party (b) refused to receive the notice issued by this Tribunal, service has been held sufficient. It is obvious that II party (b) has been placed ex-parte though it is not stated in so many words in the order sheet.

3. As per the claim statement, the case of the I party is :—

The I party was employed by the II party (a) in 1963 through the raising contractor Raman. The Principal employer was II party (a). The role of the raising contractor was only that of a broker. The work of the I party workman was guided, directed and controlled by the II party (a). Just to prevent the workman getting the statutory benefits, II party (a) adopted the mode of recruiting the workmen through contractors. The I party workman and other workmen were demanding higher wages. So the II party (a) dismissed some workmen. The I party workman was issued a charge sheet alleging that on 2-5-74 under model standing order No. 14(2)(b) alleging that on 27-4-74 he had taken about 10 Cft. of ore from the company's stock and mixed in his stock and when questioned he replied rudely and violently and this amounts to misconduct viz., "theft, fraud or dishonesty" in connection with employer's business or property. The I party denied the charge. An enquiry, which was a farce was conducted by Govindarajulu, Security Officer. The enquiry was in total violation of principles of natural justice. The I party was not allowed to defend him-

self. The report of the E.O. is perverse. The I party workman was dismissed in pursuance of this illegal enquiry. The order of dismissal is invalid. The dismissal order has to be set aside and the I party workman deserves to be reinstated with full back wages and other benefits.

4. In the counter statement filed by the II party (a) the management of BRH Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International (as has already been stated the L.R. of raising contractor Rajkumar has remained Ex. parte) among other things have denied that the enquiry was fair. The II party (a) has contended that the enquiry was proper and it was conducted following principles of natural justice and the I party was given full opportunity to defend himself. The II party (a) has stated that it was the raising contractor who had employed I party workman and not the II party (a).

5. A preliminary issue was framed by this Tribunal on 3-6-91 to the effect whether the II party (a) had conducted the D.E. in accordance with law. This issue has been deleted since the D.E. was conducted by the raising contractor. This issue has been deleted as per order sheet dt. 14-8-91.

6. As could be seen from order sheet dt. 11-5-92 both counsel have submitted that the preliminary issue should be to the effect whether the D.E. conducted by the raising contractor was in accordance with law and principles of natural justice. They have also submitted that the evidence recorded earlier should be read as evidence on this preliminary point.

7. On this preliminary point on behalf of the II party (a) W.W. 1 Shah Saheb, Personal Officer of the II party (a) has been examined. On behalf of I party workman, he has got himself examined and closed his case.

8. This Tribunal by its considered order dt. 16-11-92 has set aside the D.E. This Tribunal has granted an opportunity to the II party (a) to justify its action against the I party workman by adducing further evidence.

9. This Tribunal has framed the following issues on 4-10-91 :—

1. Whether the reference is maintainable as against the II party ?
2. Whether the raising contractor/employer is a necessary and proper party and if so, is he required to be impleaded as II party in place of the existing II party ?
3. Whether the I party is workman as defined under the I.D. Act, under the II party ?
4. Whether the action of the management of M/s. Dalmia International, Hospet in terminating the services of Sri L. Muniswamy, employed through their contractor Sri Raman in their BRH iron ore mines is justified ? If not, what relief is the workman entitled to ?

10. Issue No. 2 does not survive for consideration since the Legal Representative of the deceased raising contractor has been impleaded as II party (b).

11. Ex. M. 19 is the award passed by the Industrial Tribunal in Karnataka on 20-2-82 in Complaint No. 1/80/C.R. 1/74. In this complaint 1/80 the present I party workman is the complainant and the raising contractor M. Raman is the opposite party. This order has been passed on the complaint of the I party. It is argued by the Learned counsel for the II party (a) that even as far back as 1980 the present I party workman chose to proceed only against the raising contractor and so the reference against II party (a) is bad. In the first place, this Tribunal cannot travel outside the reference. It is stated in the schedule to reference that the I party workman was employed through the raising contractor Raman. In the second place, it should be observed that the II party (a) has produced the D.E. papers Exs. M. 1 to M. 11. No doubt as could be seen from the office order Ex. M. 10 and other D.E. papers it is the raising contractor who has held the D.E. against the I party workman. If the II party (a) had nothing to do with the I party, I do not think, II party (a) could have produced the D. E. papers. It is also argued by the Learned counsel for the II party (a) that II party (a) is not the employer of the I party workman and that II party (a) had no control over I party workman. I will presently refer to the Supreme Court authority reported in AIR 1978 Supreme Court 1410 (Hussainbhai v/s. The Alath Factory Tezhilali Union and others) to show that the II party (a) had economic control over the I party workman and so II party (a) is the real employer of the I party workman and not the raising contractor. For these reasons I hold that the reference is maintainable and the I party is a workman as defined under Sec. 2(s) of the I.D. Act. This covers my finding on issue No. 1 and portion of issue No. 3. I say portion of issue No. 3 because it is argued that the I party workman is not a workman under the II party (a).

12. The Learned counsel for the II party (a) relied on Ex. M. 18 dt. 19-5-87, communication of the Ministry of Labour in which it is stated that there is no employer and employee relationship between II party (a) and the I party workman. This is not binding on this Tribunal since the law on the point has been laid down by the Hon'ble Supreme Court and the reference has been made on the directions of our Hon'ble High Court in W.P. No. 5353/87.

13. So far as issue No. 4 (schedule to reference) is concerned the argument advanced by the Learned counsel for the II party (a) is that the II party (a) has nothing to do with the I party workman and the I party workman, if he is entitled to any relief, is only against the raising contractor Raman represented by his son II party (b). It is not argued that the termination is justified. In fact no evidence is placed to show that the termination of the services of the I party workman by the II party (b) is justified. The only argument is that the II party (a) is not liable and II party (a) has nothing to do with the I party since II party (a) is not the employer of the I party workman. In this regard the Learned counsel for the II party (a) relied on the memorandum of settlement Ex. M. 17 between the raising contractors and II party (a). Ex. M. 17(b) is the signature of the raising contractor M. Raman who is described as a employer. Ex. M. 17(a) is the signa-

ture of Dasan Solemn representing the workmen. It is contended on the strength of Ex. M. 17 that the I party workman is estopped from contending that II party (a) as his employer. I reject this argument in view of the Supreme Court authority referred to infra. This Tribunal has to see whether the argument that the II party (a) has nothing to do with the I party workman can be accepted. I have already adverted to the fact that the D.E. papers Exs. M. 1 to M. 11 have been produced by the II party (a).

14. M.W. 1 Shah Saheb, Personal Officer of II party (a) has stated in his evidence that he knows Raising contractor M. Raman and that he worked in their company for 10 years. This is a clear admission that M. Raman the raising contractor represented by L.R. (II Party (b)) was working as a contractor under II party (a) and his activities were controlled by II party (a). The fact that Rajkumar (L.R.), s/o M. Raman has not been working with the II party (a) since 1982 does not make any difference and does not affect the rights of the I party workman. It is argued that there is no subsisting relationship between II party (a) and II party (b). This argument has no force in view of the Law laid down by the Supreme Court referred to infra.

15. The Personal Officer M.W. 1 had admitted in para 22 of his evidence that all machinery was supplied to the raising contractor by the II party (a) and if the II party (a) had stopped mining, there would have been no work for the I party workman. In para 23 he has clearly stated that the contractors do not bring any machinery. In para 24 of his evidence he has clearly admitted that the II party (a) made Raman the contractor. M. W. 2 Doddavadamutt, Geologist-cum-Asst. Mines Manager in II party (a) also has admitted that Raman was a contractor of II party (a).

16. From the evidence of the witnesses of II party (a), referred to above, it is abundantly clear that M. Raman was a raising contractor working under II party (a). It bears repetition. It is argued by the Learned counsel for the II party (a) that it is only II party (b) who is liable and II party (a) is not the employer of the I party workman. The Law on the point has been laid down by the Hon'ble Supreme Court in AIR 1978 Supreme Court 1410. The Hon'ble Supreme Court has been pleased to lay down that "Where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer" because he has economic control over the workers' subsistence, skill and continued employment. The Supreme Court has laid down :—

"The presence of intermediate contractors, with whom alone the workers have immediate or direct relationship ex contracts is of no consequences when, on lifting the veil or looking at the conspectus of factors governing employment, it is found, though draped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the Management, not the immediate contractor".

The Supreme Court has been pleased to warn the subordinate Courts "not be misled by the maya of legal appearances." This authority of the Supreme

Court settles the issue in favour of the I party workman. In view of the Law Laid down by the Supreme Court that Management, not the immediate contractor, is the real employer.

17. It is argued by the Learned counsel for the II party (a) that the Supreme Court, in the above authority has not considered the provisions of Contract Labour (Regulation and Appeal) Act, 1970.

18. The Learned counsel for II party (a) relied of 1992 Lab. I.C. 2582 (Association of Chemical Workers, Bombay v/s. Sh. A. L. Alaspurkar and others) of the Supreme Court, 1992 Lab. I.C. 75 (Supreme Court) (Dena Nath and others v/s. National Fertilisers Ltd. and others), 1969 (II) L.L.J. 554 (Supreme Court) (Bennett Coleman & Co. (Private), Ltd., v/s. Punya Priya Das Gupta), 1985 (II) L.L.J. 4 (Supreme Court) (The workmen of the Food Corporation of India v/s. M/s. Food Corporation of India), 1974 (I) L.L.J. 489 (Supreme Court) (M/s. Gammon India Ltd., etc. v/s. Union of India and others), and 1969 (II) L.L.J. 799 (Supreme Court) (Tata Engineering and Locomotive Company, Ltd., v/s. Prasad (S.C.) and another) and went to the extent of submitting to the Tribunal that AIR 1978 Supreme Court 1410 is not good Law. The Presiding Officer of this Tribunal, a humble fry, will be committing highest contempt of Court (which God forbid) if he comments on the authority of the Supreme Court.

19. The case of the I party is that he has been working since 1963. It has been suggested by the II party (a) to the I party workman W.W. 1 that I party workman started working under contractors only since 1969. This means that in 1969, atleast, the I party was working under contractor. The Contract Labour (Regulation and Appeal) Act 1970 has come into force on 7-9-70. So the Hon'ble Supreme Court could not have considered the provisions of this Act which came into force in 1970, while laying down the Law in 1978. 1992 Lab. I.C. 2582 and 1992 Lab. I.C. 75 deal with the law laid down by the Supreme Court in regard to the Provisions of the Contract Labour (Regulation and Appeal) Act. These two authorities are not applicable to the facts of the present case because as I have already stated the Act came into force on 7-9-70. The I party workman was an employee of the II party (a) even before this Act came into force.

20. I have absolutely no doubt that the Law laid down by the Hon'ble Supreme Court in AIR 1978 S.C. 1410 (Hussainbhai v/s. The Alath Factory Tezhilali Union and others) is applicable to the facts and circumstances of this case. Since II party (a) had economic control over the I party workman it is the II party (a) who is the employer of the I party workman. I have already stated that it is not argued that the termination of the services of I party is justified.

21. For the aforesaid reasons I hold on issue No. 4 that the termination of the services of the I party workman is not justified. Regarding the liability of II party (a) (later portion of issue No. 3), I hold that II Party (a) is liable.

22. The I party has prayed for declaration that the order of dismissal of his services as per Ex. M.10 Dt. 31-5-74 is bad and that he should be reinstated

with back wages. In view of my conclusion above it has to be ordered that the termination of the services of I party is bad. The I party, from his conduct in the Tribunal, looks a recalcitrant man and has given his age as 55 years and he has given some evidence in a temper and the Tribunal need not give weight to the portion of his absurd evidence. In para 7 of his evidence he says that he may be 55 years old or 40 years old. He may be more than 58 years old from his looks. In the circumstances of the case, I am of opinion, it is not proper to order reinstatement of I party workman. Award of reasonable compensation bearing in mind that the I party was getting Rs. 4.40 ps. per day then and his services were terminated in 1974, in my humble opinion will meet the ends of justice.

23. All other documents and evidence not referred to by me are not relevant. In any case they do not alter my conclusions reached above.

ORDER

It is hereby declared that the action of the management of M/s. Dalmia International, Hospet in terminating the services of I party workman employed through their contractor Raman in their B.R.H. Iron Ore Mines is not justified. The I party is awarded a compensation of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand). II party (a) is liable to pay this compensation to I party workman. Award passed accepting the reference as stated herein.

Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 24th day of May 1993)

M.B. VISHWANATH, Presiding Officer,

नई दिल्ली 4 जून, 1993

का.सा. 1392.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सुन्दरगढ़ माईनिंग लैबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबन्धतन्त्र के संबंध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, ओरिशा, भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 1 जून, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/31/88-डी-III(बी)]
बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1993

S.O. 1392.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society and their workmen, which was received by the Central Government on 1st June, 1993.

[No. L-29011/31/88-D. III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Sri R. K. Dash, LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 37 OF 1988 (CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 25th May, 1993.

BETWEEN :

- (1) The management of Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Purunapani.
- (2) Rourkela Steel Plant, Steel Authority of India Ltd., Rourkela—First party-management.

AND

Their workmen represented through Purunapani Mazdoor Union, At/P. O. Purunapani, Dist. Sundergarh.—Second party-workmen.

APPEARANCES :

- Sri D. Nayak, Advocate—For the Society.
Sri J. K. Tripathy, Advocate—For the Rourkela Steel Plant.
Sri L. K. Mohapatra, Advocate—For the second party-workmen.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon it by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short 'Act') have referred the following disputes for adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-29011/31/88-D. III(B) dated 29-9-88 :—

- (1) "Whether the action of the management of Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Contractor, Purunapani Limestone & Dolomite Quarry of SAIL, P. O. Purunapani, Dist. Sundergarh, Orissa in retrenching the following 8 workmen is justified. If not, what relief are the workmen entitled to?"
1. Aijib, 2. Sabina, 3. Mansuk, 4. Punia, 5. Budhni, 6. Anjulus, 7. Karmila, 8. Bharat.
- (2) "Whether the demand of the Purunapani Mazdoor Union, Purunapani on the management of Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Purunapani, Dist. Sundergarh (Orissa) for provision of employment to the dependants of the following 13 deceased employees is justified? If so, to what relief the dependants are entitled to?"
1. Telani, 2. Basanty, 3. Sonamati Badaik, 4. Palha, 5. Habil, 6. Bandhni, 7. Pusha, 8. Phanindar, 9. Jagnoo, 10. Pandiy, 11. S. N. Singh, 12. Jhirga & 13. Senjaro.

2. Originally parties to the fray are the Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Purunapani (for short 'Society') and their workmen represented by Purunapani Mazdoor Union (for short 'Union'). On the application of the union, the management of Rourkela Steel Plant being the principal employer has been added as a party.

3. Briefly stated the case of the workmen is that Purunapani Limestone & Dolomite Quarry is one of the Captive mines of Rourkela Steel Plant of the Steel Authority of India Ltd. The raw-materials raised from this quarry are being used by the Rourkela Steel Plant. Although raising of limestone and dolomite is a permanent and perennial nature of work, but the management of Rourkela Steel Plant has been entrusting the said work on contract basis since 1957. The society which is a registered one under the Co-operative Societies Act is a contractor under the Steel Plant which has been undertaking the raising of limestone and dolomite from the aforesaid quarry on contract basis and the society to execute the contract work has been engaging its own labour force. The predecessors of the eight workmen named in item No. 1 of the reference were the employees of the society who had been working in the mines being engaged by it. On their death these eight workmen had been given employment in 1982 and were allowed to work till 1987 when their services were terminated. According to the union there was no valid reason to terminate/retranche their services. About one year prior to their retrenchment, the society being in need of some more labourers engaged 78 persons to work in the mines. These 78 persons being juniors to them were allowed to continue to work whereas the management without any reason and rhyme did away with their job without complying with the requirements as envisaged under law.

4. As to the second item of reference, the case of the union is that it is the existing practice of the society that in the event of death of a workman his dependant is to be given employment but in the case of these 13 persons named in the reference they being the dependants/relatives of the 13 workmen who died in course of their employment, the management treated them differently and did not provide them employment. Against such unequal treatment the union issued a strike notice demanding immediate settlement. The State machinery intervened in the matter and took-up conciliation and directed the principal employer, namely, the Rourkela Steel Plant to attend the conciliation proceeding but it did not. Ultimately, as the conciliation failed, the present reference was made for adjudication of the disputes existing between the parties.

5. While challenging the maintainability of the reference in view of what has been provided in Section 68 of the Orissa Co-operative Societies Act, 1962, the society has pleaded inter-alia that it being a registered contractor under the Rourkela Steel Plant undertakes the raising of limestone and dolomite from its captive mines on contract basis and to carry out such work it engages its own labour force. The workers working in the mines has formed a society of their own and got the same registered under the Orissa Co-operative Societies Act. According to the bye-laws of the society, a labourer who is a share-

holder becomes a member of the society. The society does not have any permanent nature of work of its own to be performed. It being only a contractor under the Rourkela Steel Plant undertakes certain work on contract basis and executes the same within the time stipulated. So far the claim of those persons named in item No. 1 of the reference is concerned, it has specifically urged that three of them, namely, Mansur, Budhni and Bharat were casual workers appointed for 30 days for repair and maintenance of road and the rest had never worked under it at any point of time.

Coming to the second item of reference, the case of the society is that all the persons named therein are not dead. Two of them, namely, S. N. Singh and Jhinga are alive and are still working under the society. As to the claim of the remaining 11 persons, they are not entitled to employment with the aid of 'Dying in Harness' rules. In sum and substance the society has urged that the persons named in both the item of reference are not entitled to any relief as claimed.

6. The management of Rourkela Steel Plant on being added as a party to the proceeding has succinctly urged that it being the principal employer is no way concerned with the employment, non-employment or conditions of employment of the workers engaged by the society to execute the work undertaken on contract basis. The disputes as mentioned in the reference are in between the society in one hand and the union on the other and as a principal employer it is not responsible for any act done by the society which is admittedly a registered contractor under it.

7. In view of the pleadings of the parties, the following issues are settled :—

ISSUES

- (1) If the reference is maintainable in view of the provisions of Section 68 of the Orissa Co-operative Societies Act ?
- (2) Whether the subject matter under reference is an 'industrial dispute' within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 ?
- (3) Whether the Rourkela Steel Plant is a necessary party to the dispute referred for adjudication ?
- (4) If there is employer-employee relationship between the First party-Society and the second party-workmen ?
- (5) If the termination of employment of the eight workmen named in the reference amounts to retrenchment and if such retrenchment was legal and justified ?
- (6) If such retrenchment is neither legal nor justified, to what relief the said eight workmen are entitled ?
- (7) If the demand of the Purunapani Mazdoor Union Purunapani requiring the management of M/s. Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Purunapani, Sundergarh for providing employment to the dependants of the following 13 deceased employees is justified ?

- (1) Telani, (2) Basanty, (3) Sonamati Badaik, (4) Palha, (5) Habil, (6) Badni,

- (10) Pandey, (11) S. N. Singh,
(12) Thirga, (13) Soniaro.

- (8) If not, to what relief the said workmen are entitled ?

8. All the parties to the proceeding have choosen not to lead any oral evidence except bringing certain documents on record. The documents relied upon by the workmen are as follows :—

- (1) A letter addressed to the Asst. Labour Commissioner (Central), Rourkela, Ext. A.
- (2) Minutes of informal discussion between the society and the President of the Union in presence of the Asst. Labour Commissioner (C), Rourkela, Ext. B.
- (3) A letter addressed by the Rourkela Steel Plant to the President of the Society, Ext. C.
- (4) A show-cause filed by the society in I. D. Msc. case No. 2/86 in the Court of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar, Ext. D.
- (5) A letter of the General Secretary of the Union to the Secretary of the Society, Ext. E.
- (6) List of the workers of the society, a contractor under the Rourkela Steel Plant, Ext. F.
- (7) A letter of the union addressed to the Secretary of the society, Ext. G.
- (8) A letter of the Asst. Labour Commissioner (C), Rourkela to the Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour, Ext. H.
- (9) A letter of the General Secretary of the union to the Secretary of Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, Ext. J.
- (10) Order of this court passed in I.D. Case No. 4 of 1984, Ext. K.

The following documents of the Society are marked exhibits :—

- (1) A letter of the Rourkela Steel Plant to the Society, Ext. 1.
- (2) A resolution of the society Ext. 2.
- (3) Three letters of the society addressed to the Manager, Purunapani Limestone & Dolomite Quarry, Exts. 3, 4 and 5.
- (4) A letter of the Purunapani Limestone & Dolomite Quarry of the Rourkela Steel Plant to the President of the Society, Ext. 6.
- (5) A letter of the Purunapani Limestone & Dolomite Quarry of the Rourkela Steel Plant to the Secretary of the Society, Ext. 7.
- (6) An order of the society regarding appointment of 95 casual labour, Ext. 8.
- (7) An order of the society appointing 12 casual labour, Ext. 9.
- (8) Two letters of the Government of India, Ministry of Labour to the Secretary of the

society as well as the General Secretary of the North Orissa Workers Union, Exts. 10 and 11

- (9) Bye-laws of the society, Ext. 12.

No document has been filed on behalf of the principal employer, namely, the Rourkela Steel Plant, Rourkela

9. Out of the aforesaid seven issues, referred to above, the parties having advanced no argument with regard to issues Nos. 1 to 3, in other words, the said issues being not pressed by the parties it is not necessary to give any finding thereto. However, for academic purpose, I would like to say that Section 63 of the Orissa Co-operative Societies Act has absolutely no application to the facts of the present case and it does not stand as a bar to raise the present dispute.

10. Coming to the question whether the disputes as mentioned in the reference are 'industrial disputes' or not, a reference may be made to the definition of 'industrial dispute' as provided in Section 2(k) of the Act, which means, any dispute or difference between the employers and employees or between employers and workmen or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with conditions of labour of any person. In view of such definition, I am of the opinion that item No. 1 of the reference which relates to the legality and justifiability of retrenchment of eight workmen named therein squarely falls within the ambit of 'industrial dispute' and the same can be adjudicated upon by this Tribunal.

11. Next relates to the question as to whether the Rourkela Steel Plant is a necessary party to the dispute or not. Originally it was not a party to the proceeding but by virtue of an order passed by this Tribunal on 17-5-90 it was brought on record, being the principal employer. Against such order the society, if aggrieved did not move the higher court. So, on 17-5-90 it is held that the management of Rourkela Steel Plant is a necessary party to the proceeding no further probe is necessary in that regard and despite of that if anything is said contrary to what has been held earlier it would amount to sitting upon one's own order. It would not be wrong on my part to make a passing remark that once the question has been answered in affirmative that Rourkela Steel Plant is a necessary party and that after such decision it has been brought on record no further issue should have been framed to reopen the matter afresh.

12. Let me now take-up issue No. 4 in regard to the question as to if there exists relationship of employer and employee between the society and the persons named in the reference.

I may reiterate the case of the union that persons named in item No. 1 of the reference being the workmen had been terminated from service since 1987. So far the second item of reference is concerned, it has emphatically urged that thirteen persons named therein being the successor of the employees ought to have been given employment by the society on the principle of 'Dying in Harness' rules. This admission of the society takes me to find that these 13 persons had no employer and employee relation with the society. As

to the claim of the eight persons as named in item No. 1 of the reference, the case of the society is that Mansuk, Budhni and Bharat had been engaged as casual labourers for a period of thirty days and the remaining five were not given employment at any point of time. In view of such specific plea of the society, the union ought to have led evidence to prove that all the eight persons named in the item No. 1 of the reference were the workmen of the society as defined in the 'Act'. All the documents proved in this case as mentioned above although does not improve the case of the union in any manner but in view of the society's own admission in the written statement that Mansuk, Budhni and Bharat were the casual labourers and over and above name of Karmila finds place in the appointment order, Ext. 8, I am of the opinion that there existed employer and employee relationship between them and the society and not others.

In view of my findings as above, I shall now avert to the questions as set out in issues Nos. 5 and 6 simultaneously for the sake of convenience.

The consistent case of the society being that Mansuk and two others were the casual labourers appointed for thirty days, in all fairness the union ought to have led evidence that they had continuously worked from 1982 to 1987 and their period of employment was 240 days or more in any of the years. That having not been done, Section 25-F which provides for giving one month's notice or notice pay before retrenchment is not attracted at all. This apart, those three being the casual labourers can not claim employment as a matter of right and, therefore, they can not ask their employer to regularise their services.

The present trend of judicial opinion is unanimous that casual workers having worked for two to three years on daily wage basis are not entitled to claim regularisation of services as of right. In this connection, it would be profitable to refer to the Apex Court's view reported in 1992(1) J.T. page 394 (Delhi Development Horticulture Employees' Union Vrs. Delhi Administration) as under :—

"For regularisation, there must be regular and permanent post or it must be established that although the work is of regular and permanent nature, the device of appointing and keeping the workers on adhoc or temporary basis has been resorted to, to deny them the legitimate benefits of permanent employment."

Relying on the said decision the Allahabad High Court in the case of Jakir Hussain Vrs. Engineer in Chief, Irrigation Department and others reported in 1993 L.I.C. Page 836 has held thus :—

"The person who is appointed on daily wage on adhoc basis does not have any right to the post and his service can be terminated at any time. He can not claim regularisation of his service merely because he has completed 240 days in service."

13. The next is issue No. 7 with regard to the claim of the union for giving employment to 13 persons named in item No. 2 of the reference on the basis of 'Dying in Harness' rules as according to the union, their predecessors died during course of em-

ployment. Such claim by the union, in my opinion, does not fall within the ambit of 'industrial dispute' as defined in the Act and therefore, this Tribunal having limited jurisdiction can not exercise its power under the Constitution of India to redress such grievance even accepting the case of the remaining 11 that their predecessors died in course of employment. However, I may observe that good sense will prevail upon the society to consider the case of the remaining 11 named in item No. 2 of the reference for giving them employment only if it finds that their predecessors having worked for a year or more died in course of employment.

Before parting, I may observe that the management of Rourkela Steel Plant though in its written statement has taken the plea that it is in no way concerned with employment, non-employment, terms of employment or conditions of service between the society and its workmen but it appears to have exercised administrative control over it as borne out from Ext. 1, 6 and 7. As a principal employer it has exceeded its limit as enjoined upon it by law. It ought to have remembered that it has absolutely no business to ask the society as to whom it would employ to execute the work undertaken on contract basis. If such interference is made and the management of Rourkela Steel Plant is allowed to have overall supervision and control on the work of the contractor then certainly it will give a scope to the workers to contend in future that the contractor is only a name-lender and he has been brought into the picture with a view to deny the workers of their legitimate rights. With this observation the reference is disposed of.

Dictated and corrected by me.

R. K. DASH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 जून, 1993

का.आ. 1392.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धनत्व के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम नं० 1, बम्बई, के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-40012/179/91-आईआर (डीयू)]

बो.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th June, 1993

S.O. 1393.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (10 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the

management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-93.

[No. L-40012/179/91-IR(DU)]

B. M. DAVID, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT BOMBAY
PRESENT :

Justice Shri R. C. Sindhakar Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-1/35 OF 1992.

PARTIES :

The Employers in relation of the Management
of Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
Bombay

and

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer:—Shri S. R. Rajguru Advocate.

For the Workmen:—Shri G. S. Kulkarni
Union's Representative.

STATE : Maharashtra

INDUSTRY: Telecommunication

Bombay, dated the 25th May 1993

AWARD

This is a reference made by the Central Government vide its letter dated 07-05-1992. It is to the effect that;

"Whether the Management of Mahanagar Telephone Nigam Limited, Bombay is justified in terminating the services of Shri Nena Dhondiram Kharat, a Casual Mazdoor ?
If not, what relief he is entitled to ?"

The workman Shri Kharat has filed his statement and written statement has been filed on behalf of the Opposite Party, the employer.

The workman states that he was employed as a Casual Labourer in March 1985, in Bombay Telephones, now called the Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (Hereafter referred to as the MTNL.) He was removed from service in March 1988 without giving either a notice or notice pay though his juniors were retained by the MTNL. He states that the termination was on the pretext that there was no work. Whenever he was discharged he used to keep on enquiring for employment and he has not remained absent and left the job at any time. He has produced documents in support of his contention and which have been exhibited on the admission of MTNL.

MTNL in its written statement admits that the Workman Shri Kharat was employed by it since March 1985 as a Casual Labourer on daily wages of Rs. 12/-. It is further admitted that he worked for the full month of March 1985 and 15 days in April 1985. It is contended that he left the job

without giving any reason. It is further contended he has not worked in any other unit of MTNL after 15th April 1985. It is further stated that the workmen/Casual Labourers who were not reporting for duties in the midst of the month were free to join other departments of MTNL. However, the applicant workman was not deputed alongwith other Casual Labourers who were deputed to the maintenance wing for monsoon since he did not turn up

It is further admitted that he was employed whenever he reported for employment. In December he was engaged and he worked for 147 days, i.e. from 1st December 1985 to 30th March 1986. It is contended that thereafter again he absented himself from work.

Once again he was re-employed for the casual employment with effect from 1-3-1987 and he continued to work for 78 days on purely temporary basis upto 17th May 1987. Thereafter he was retrenched alongwith other temporary labourers. It is admitted that once again in September 1987 he was re-employed from 1st September 1987 to 16th December 1987 and again he was retrenched alongwith other labourers engaged from outside for the particular work for short term. He was again re-employed in January 1988, alongwith other labourers purely on temporary basis for 82 days with the approval of General Manager (C.C.) for short duration work and that also on purely temporary basis. After 23rd March 1988 he was retrenched alongwith other labourers."

It is stated that thereafter he did not turn up for work. On the contrary, he approached the Assistant Labour Commissioner in August 1989 contending falsely that he had worked continuously with the employer (MTNL) since 1985 to 1988. In short, the contention is that the workman applicant is not entitled to any relief from this Tribunal.

The workman applicant produced documents in support of his contention. The documents produced by the workman Shri Kharat were not admitted in the beginning by the learned advocate for the MTNL. However, later he admitted them. No oral evidence was led by either of the parties. However, they addressed oral arguments in support of their rival contentions. Written arguments were also submitted in addition to the oral arguments.

As stated at the outset, the question is as to whether the management of MTNL is justified in terminating the services of the casual labourer Shri Kharat who was employed by the MTNL intermittently since March 1985 to 1988. MTNL has produced in Exhibit M-8 a statement (Annexure I) showing the number of days the workman applicant was present between March 1987 and 1988. The period between April 1987 and March 1988 works out for 274 days, while the period between March 1987 and March 1988 works out of 205 days. The however, is the statement of the workman accompanying his application to the Asst. Labour Commissioner.

It is an admitted position that in March 1988 no notice was given to the workman by MTNL. What has stated in Para 7 of the written statement is that

he was retrenched after 23rd of March 1988. Therefore the termination of service was by way of retrenchment.

Retrenchment has been defined under section 2(oo) as :

"Termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, and it does not include voluntary retirement, or retirement on reaching superannuation if the contract of employment between the employer and the employee contains a stipulation in that behalf. OR termination of services as a result of non renewal of the contract of employment between the employer and the employee concerned, OR termination of services of a workman on the ground of continued illhealth."

I find that in the present case the termination was not by way of punishment inflicted by way of disciplinary action, it was not a voluntary retirement, it was not a retirement on reaching the age of superannuation, and it is not on the ground of continued ill-health or on the basis of expiry of the contract between the employer and the employee.

It is to be remembered that there is no letter of appointment issued by MTNL at the time of appointment of the workman not anything in writing issued at the time of termination. Therefore, this is a case of retrenchment within the meaning of section 2 (oo) and was so admitted in para 7 of the written statement and that was in 1988 March. Admittedly there was no notice of termination and therefore, there is a breach of the provisions of section 25 (F) of the Industrial Disputes Act, 1947. The provision contemplates that the workman has to be given one month's notice in writing and the workman has to be paid at the time of his retrenchment, compensation which shall be equal to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months, and notice in the prescribed format has to be served on the appropriate Government.

None of these three pre-requisites of a valid retrenchment has been fulfilled by MTNL.

It was urged on behalf of MTNL that the workman has not been in continuous service for one year and therefore, the provisions of section 25 (F) would not be attracted. As against this, the submission was that the workman has put in more than 240 days of service in a calendar year proceeding the date of termination of his service and therefore, he has to be deemed to be in continuous service for a period of one year. Reference has been made to Section 25 (B) which defines continuous service. Under subsection 2 of section 25-B, a workman is deemed to be in continuous service for a period of one year if the workman during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than 190 days, which is in the case of a workman employed below the ground in a mine, and 240 days which is

in any other case. The submission of the learned counsel for the workman is that he has met this requirement of 240 days in the 12 calendar months preceding the date termination of his service in March 1988.

The point is, whether the workman has actually worked for not less than 240 days in the 12 calendar months preceding the date of termination [retrenchment in March 1988]. The workman has addressed a letter to the Assistant Labour Commissioner on 29th January 1991 complaining about the improper manner in which his services were terminated and mentioning therein that from March 1987 till 1988 he was in continuous service, and completed more than 300 days. The annexure shows the break-up. On the basis of the calculations made of the number of working days between April 1987 and March 1988, the total number of working days comes to 274. It is true that this is a statement of the workman himself. In this connection, he has also produced at Exhibit W-1 and Exhibit W-2, two documents. Ex. W-1 shows the number of days he worked in a period of 12 calendar months preceding the date of termination, i.e. from April 1987 to March 1988. He relies upon the contents of Exhibit W-1, the statement in the written statement, the certificate given by the Assistant Engineer MTNL (Exh. W-2) and the Muster Roll Numbers.

At Exh. W-2 is the certificate issued by the Assistant Engineer MTNL. Exh. W-2 shows that he has worked for 104 days between March 1987 and August 1987. One can also turn to the written statement filed by MTNL. This shows therefrom that the workman worked for 78 days during the period from 1st March 1987 to 17th May 1987, (Para-5) Para 7 shows total number of 82 days for which he worked during the period of 1st January 1988 till 22nd March 1988, i.e. the day on which he was retrenched. (Para-7) In para 6, it has been admitted that he worked from 1st September 1985 to 15th December 1987. The total number of working days have however been not mentioned, and one doesn't know the reason therefor. It is clear from the recital made in para 5 and 7 of the written statement that the worker has worked for all the days without break. The total number working days of March are 31, April 30 and May 17, that works out to 78 days and that is the total number or days he has actually worked on. Between 1st January 1988 and 23rd March 1988, the total number of working days comes to 82 days and the workman has actually on all these days without break. It also appears from the recitals in the written statement, that he was actually working on all these days without a break. In para-3, it is mentioned that he worked for 30 days in March 1985 and 15 days in April 1985, i.e. upto 15-04-1985. He worked for 147 days between 1st December 1985 and 30th April 1986. The number of days covered by this period is 151 days. Therefore, he must have also worked on all the days between 1st September 1987 and 15th December 1987 and that works out to 112 days, and the total number of days for which the workman can be said to be working between March 1987 to March 1988 works out 274 days, it is from th-

ported in AIR 1993 (1) C.A.T. 336 was relied upon. There again in result, reinstatement was ordered with full back wages, for non-compliance of the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

The workman is entitled to the relief of reinstatement in service with full back wage, Award accordingly.

विषय संक्षेप

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैदिक प्रभाषा)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1992

का. मा. 1394 : - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को धारा 53 (2) के अनुवर्णन में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1992 को ममान्त रुप तर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर बर्धित रिपोर्ट भेजी है आ नीचे उक्त को जारी है :-

जुलाई 1991 से 30 जून 1992 तक के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-वाहति पर वार्षिक रिपोर्ट

भाग 1 — प्राथमिक समीक्षा

१. नैतिगत गतिविधियां एवं स्वरूप

1.1 वर्ष 1991-92 (अवधि-जुल) कार्यवर्ष की शीर्षका से स्थिर करने और मुद्रास्फीयता को कम करने का प्रयास को विवरण नीतिगत उपायों की प्राप्ति करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना—
कृपि (1)

1.2 पिछले दशक में व्यापक बुद्धि में तेजी देखी गी, लेकिन गलत उपाय-उपाय (जोड़-पट्ट) की वृद्धि की पराध्यायन उच्च दर के कारण व्यापक व्यापक प्रत्युत्तर और संरचनात्मक जटिलताएँ की जाती रही जिनमें से कुछ न विकास की प्रक्रिया की निश्चय करने में मदद करने में सक्षम नहीं हैं। विस्तृत नियमानुसार प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर और अन्य पर सुधार-त्मक कार्यवाही करने से बिलम्ब की वजह से 1990 के दशक में व्यापक व्यापक की तीव्र प्रभाव पड़ा।

[illegible]

महर्षियों में विदेशी कृषि की तकनीकों में होने वाले चुनौतीपूर्ण परिवर्तन का सामना देश को करना पड़ा। बाह्य और आंतरिक संकटों पर दबाव मौद्रिक स्थिरता के प्रति आशंकित और इसका परिणामस्वरूप सहायकता का अभाव ने निर्यात के लक्ष्यों को प्रतिबन्धित रूप में प्रभावित करना शुरू कर दिया। सहायकता के, जो स्वयं गरीबों का आर्थिक प्रादुर्भाव का हानि पहुँचाना है, का उद्देश्य एक और परिणाम रहा, अपने सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों में निवेश यात्राओं में उत्पादन और रोजगार मूल में अक्षयता लाकर इनमें भी बाधा पहुँचाना परम्परा कर दिया था। इन स्थितियों को मान्य था कि इसने निर्यात के लिए गुरुत्व स्थिरकरण के उपाय किए जायें, जैसे—राजकोषीय सुधार, मुद्रा प्रसार में तंगी, मुद्रा-स्थिरता पर नियंत्रण और भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना।

1.4 स्थिरकरण के उपायों के लाभों को प्रकाश आधार पर जारी ले जाने के लिए संरचनात्मक कठोरताओं और विफल में आने वाली अक्षयता जैसे प्रीपोषिक सामानों पर भी कार्यवाई करनी पड़ी। सर्व-प्रथम तो इनमें नियंत्रणों और विधियों को परिणामस्वरूप विकाशकारियों ने बढ़ते हुए हस्तक्षेप ने उद्यम और पड़ल की तेज गति को रोक दिया। दूसरा, देशों बाजारों के विशालीकरण के कारण समाज आमतौर पर अधिक राशम और लक्ष्य उत्पादों की मांग कर रहा था। तीसरे हमारे तब तक बाह्य विश्व की तुलना में विशेषकर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों की तकनीक की तुलना में समर्थ नहीं दिख रही थी। भारत में प्रौद्योगिकी विकास की प्रेरणा का आत्म आभारक रूप से अब तक सरकारी क्षेत्र की परम्पराओं एवं कुछ बड़े निजी क्षेत्र के निवेशों और सभी राज्य निर्देशित उद्योगों के माध्यम से हुआ। इस क्षेत्र में और आगे का विकास, प्रतिस्पर्धा और बाजार बंधन में उत्पन्न विस्मृत—रूप में की गयी पड़ल पर भी निर्भर हो सकता था। जैसा, सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त सहायता की वृत्त उस सीमा तक, जहाँ तक वह उन क्षमताओं में था जिनमें पर्याप्त प्रतिभा नहीं मिभा था, से निजी क्षेत्र में निवेश होने से रहा गया और अन्त में विश्व ध्वस्त में एक प्रमुख परिवर्तन आ गया। महायुद्ध की उपलब्धता कम हो गयी और सहायता की उपलब्धता में कमी तथा भ्रष्टाचार संयुक्त की स्थिति के लिए यह अपेक्षित था कि देश अपनी विदेशी मुद्रा का अर्थन करने के लक्ष्य के प्रति धर्मर हो, जिनका जम्बुओं और सेवाओं के आयात के लिए उसे भुगतान करना है। निर्यातों के लिए उच्चतर गुणवत्तावली चेतना और प्रतियोगी प्रौद्योगिकी अपेक्षित है। विदेशी बाजारों, जो मूल्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं सर्व के साथ साथ गुणवत्ता, सेवा और प्रौद्योगिकी के प्रति संवेदनशीलता दर्शाया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी प्रतिस्पर्धात्मक/सहायक प्रौद्योगिकी अंतरण के मुख्य साधन तथा बाजार के हिस्से के संबंध में निम्नलिखित बत रहे थे। जब तक देश विश्व बाजार में भाग नहीं लेता तब तक विशेषतः निर्यात का उद्यम सामान्यतः अव्यवस्था का आत्म आभारक विकास समर्थ नहीं है। देश के अनुसंधान के अभावों में पता चलता है कि उद्यमी, अपनी व्यवस्थाओं के निम्नलिखित उच्चतर वातावरण में आगे बढ़ें और दूरदर्शी बन गया है, जबकि वे अतिरिक्त आयात प्रतिस्पर्धा को निम्न में निर्भरता मनोवृत्ति का आभार बताने की कोशिश करते हैं और सक्रियता को बढ़ाते हैं। सबसे बड़े धर्म और व्यापार संबंधी सामान्य कारण के नियमों एवं धर्मों में अनिश्चित खुली बाजार प्रणाली में पूर्ण रूप में भाग लेने के लिए लगातार घटौत का मूल्य विकल्प कठिन बन गया था। इस प्रकार उदारीकरण और संरचनात्मक सुधार तथा देश के अर्थ और बाजार के बाजारों दोनों में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत के लक्ष्य अभिमत कर देने वाले थे।

1.5 यहाँ तक पृष्ठभूमि में जिसके आधार पर जुलाई 1991 में प्राथमिकता के स्थिरकरण और संरचनात्मक समायोजन दोनों के लिए नीय गति और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया है। राजकोषीय स्थिति को ठीक करने, वित्तिय दूर के समायोजन और सुधार, मौद्रिक स्थिरता तथा मुद्रा स्थिरता नियंत्रण आदि के तुरन्त उपायों का रूप धारण किया, जिस में व्यापक आर्थिक स्थिरता शामिल है। इन्हें के साथ-साथ औद्योगिक स्थिरता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का पूर्ण तरह से पुनर्गठन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के रूप में संरचनात्मक सुधार किए गए। तुरन्त लागू किए गए स्थिर-

करण के उपाय तुरन्त बाह्यवर्षिक संरचनात्मक सुधार का उपाय। राजकोषीय सुधार और संरचनात्मक समायोजन के उपाय आर्थिक व्यवस्था पर आने प्रभुत्व जमाये हुए थे, उस समय में भी बाह्य वित्तिय के संकट का निवारण में लाने के लिए दृढ़ उपाय किये गये। इसका परिणामस्वरूप, देश की विदेशी मुद्रा अस्थिरता जो जुलाई 1991 के बीच में 1.0 बिलियन अमरीकी डालर में से भी कम थी, मार्च 1992 के अन्त में 5.6 बिलियन अमरीकी डालर तथा जून 1992 की समाप्ति तक और बढ़कर 6.2 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गयी, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। एक ओर जहाँ आयात संयुक्त के प्रबल उपाय किये गये वहीं प्रतिभासी भारतीयों द्वारा देश में संसाधनों को लाने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयास किये गये। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से अधिक वित्तियोग द्वारा भी इसकी अनुपूर्ति की गई। भुगतान आधार पर व्यापारिक घाटा 1990-91 के 7.7 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 1991-92 में 3.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गया और तदनुसार चालू खाता घाटा क्रमशः 7.7 बिलियन अमरीकी डालर से तेजा से घटकर 2.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

1.7 राजकोषीय सुधार और संवेदन—द्वारा के व्यापक आर्थिक संकट का मूल राजकोषीय क्षेत्र के असंतुलनों के साथ निम्न से जुड़ा है। केन्द्र सरकार का कुल राजकोषीय घाटा वर्ष 1990-91 के मीमूदा बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के 8.4 प्रतिशत के बराबर था, जबकि यह घाटा 1980 के दशक के आरम्भ में 6 प्रतिशत और 1970 के दशक के मध्य में 3 से 4 प्रतिशत था। यह और भी उल्लेखनीय है कि 1980 के दशक के दौरान केन्द्र सरकार के राजस्व खाने में यह घाटा सन्त बना रहा और बढ़ता रहा (1990-91 में सकल देशी उत्पाद का लगभग 3.5 प्रतिशत) जो राजकोषीय दृष्टि में चिन्ता का विषय बन गया है। इस पर भी एक और पड़ल है—भारी मात्रा में मौद्रिक घाटा जिसने अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक अनिश्चितता का मूलन करने के अलावा मौद्रिक नीति के मूल्य-स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में अतिरिक्त पैदा कर दी है। राजकोषीय घाटे के कारण कृषि और औद्योगिक और बाह्य दोनों, बढ़ता जा रहा है जो अब सकल देशी उत्पाद का 57 प्रतिशत बढ़ता है। तब भुगतान के पारा बांध के कारण केन्द्र पर अर्थ-व्यवस्था का बोझ सकल देशी उत्पाद का 4.4 प्रतिशत और कुल व्यय के 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ता है। सरकारी खर्च में निरन्तर वृद्धि, वित्तिय संकट में मुद्राओं गयी अस्थिरता सहायता सहायता तथा कर प्रणाली में होने वाली तब में प्रवर्धित हुई और सार्वजनिक क्षेत्र में निरन्तर होने वाली हानि ने बजट के अंतरण को काफी बढ़ा दिया है। जहाँ एक ओर ये समस्याएँ प्रभावित राष्ट्र क्षेत्र में चालू खाने के घाटे के रूप में फीट गये हैं जो संसाधनों के लिए सीमा-मुक्त राजस्व (केन्द्र के निम्न कर राजस्व का लगभग 46 प्रतिशत) पर अनुचित रूप से निर्भर रहने की तरह से भारतीय उद्योगों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर बाजार बनाना पड़ा जिसमें दक्षता, प्रौद्योगिकी उत्पन्न तथा निर्यात स्पर्धात्मकता के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंत में, संसाधनों पर सरकार की बढ़ती हुई तथा वे अव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में और अधिक उत्पादक विशाक्तियों के लिए उचित उपलब्धता को प्रभावित किया है।

1.8 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सरकार ने अपने सामने यह सत्यावधि उद्देश्य रखा कि केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को काफी मात्रा तक (करीब सकल देशी उत्पाद के 3 से 4 प्रतिशत तक) कम कर दिया जाये। वर्ष 1991-92 के लिए राजकोषीय समायोजन कार्यक्रम ने केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे में सीधे गिरावट लाकर उसे 1990-91 के 8.4 प्रतिशत से घटकर 1991-92

में 6.5 प्रतिशत तक लाने की परिचल्पना की है। इस लक्ष्य को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया। वास्तव में, यह समायोजन प्राथमिक घाटे की दृष्टि से (राजकोषीय घाटा-निवल व्याज भुगतान) बहुत नीच था जो क्रमशः 6.0 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया। केन्द्र के राज-कोषीय घाटे में यह कमी सकल देशी उत्पाद के अनुपात में लगभग 1.4 प्रतिशत बिन्दु व्यय (निवल ऋण सहित) को कम करने सम्भव हो सकी। ये कटौतियाँ व्याज से इनक बालू खर्च से संबंधित थी जैसा नियमित मॉडिफ़ी, राज्यों और मध्य शासित क्षेत्रों के योजनाएँ अनुदान, रक्षा व्यय में थोड़ा नियंत्रण। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से प्रतिबंधित कमी लाने के लिए, 1991-92 में पूंजीगत व्यय को कम किया गया। अतिरिक्त राजस्व संग्रहण तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की ईक्यूटी धारिताओं में अप-निवेश के माध्यम से संसाधन क्षेत्र में भी कुछ समायोजन किये गये थे।

1.9 वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्र बजट में राजकोषीय समायोजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय घाटे को सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत तक लाने का निश्चय किया गया है। समायोजन का लगभग संपूर्ण भाग ही व्यय की वृद्धि को रोक कर प्राप्त किया जाना है। वास्तव में, इस वर्ष के केन्द्रीय सरकार के बजट के अनुसार, व्याज रहित व्यय तथा योजनाएँ व्यय दोनों को मिलाकर वर्ष 1991-92 से कम होगा और इस प्रकार फिर यदि बड़े हुए व्यय के भार को भी हिमाचल में लिया जाए, तो अनुमानित प्राथमिक घाटा वर्ष 1991-92 के सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत से घटकर 1992-93 में 2.3 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए, केन्द्र ही निवल बाजार उधार राशियों को 5,000 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया, जो 1991-92 के 7,500 करोड़ रुपये के स्तर से एक निहाई कम है। यद्यपि व्याज भार में कटौती कुछ वर्षों में तभी प्राप्त की जा सकती है, जब सरकारी उधार राशियों में कटौती और घाटे के मौद्रिकरण में कटौती साथ-साथ ऐसे मुद्दों किये जायें कि कर्ज को बाजार आधारित प्रतिभाष की दरों पर रखा जाये, सरकार द्वारा की गयी उधार राशियों की लागत में पारदर्शिता में वित्तीय क्षेत्र में मुद्दों किये जायें और मुद्रा-प्रदंड को महत्व दिया जाये।

1.10 सकल देशी उत्पाद की गुलता में व्यय (निवल उधार सहित) के अनुपात में 1.0 प्रतिशत बिन्दु की कटौती के अलावा 1992-93 के बजट में कर मुद्दों पर चेल्लय्या समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करके कर-संरचना में व्यापक परिवर्तन करने की पहल की गयी है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य कर-संरचना को सरल और व्यक्तिगत बनाने के साथ-साथ इसके आधार को व्यापक बनाना है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों का जोर इस बात पर है कि सीमा-शुल्क की दरों को प्रतिस्पर्धी देशों की प्रवृत्तियों के अनुकूल ढाल कर भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन दिया जाये, टैरिफ दरों के वितरण को कम किया जाये, उत्पादशुल्क की संरचना को व्यक्तिगत बनाया जाये और क्षतिपूर्ति प्रभावशाली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क की दरों को बढ़ाया जाये ताकि सीमा-शुल्क के संशोधन से हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकें। इस प्रकार वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गयी संरचनात्मक समायोजन और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया को 1992-93 में समेकित किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे से तीव्र कटौती के साथ-साथ बजट में प्रस्तावित मुद्दों से ऐसी धारा है कि वे एक उत्साह-वर्धक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करेंगे, विदेशी भुगतान को समस्याओं को कम करेंगे और समतान्तर रूप से मुद्रा-स्फीति से संभावनाओं को कम करेंगे। बजट ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें मध्यवर्ध में एक वृद्धतीय राजकोषीय संतुलन लाया जा सके।

1.11 मौद्रिक नीति उद्देश्य और साधन :- 1989-90 से मौद्रिक नीति को बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे तथा निरन्तर बनी रही अप्रत्यक्ष

निरन्तरता का सामना करना पड़ा। जिसमें मुद्रास्फीति एक बार पुनः उभर कर सामने आयी। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त, भुगतान संतुलन की निगडनी हुई स्थिति भी थी जो खाड़ी संकट के बाद विशेष रूप से बदतर हो गयी थी। अतः 1990-91 के उम्परावे तथा 1991-92 के पूर्वार्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत कार्यों में सकल मांग का आर विशेष ध्यान की मांग की सीमित रखना सर्वोपरि उद्देश्य बन गया। अन्तराष्ट्रिय प्रबंध पर प्रमुख बल देने के वावजूद वित्तीय प्रणाली की परिष्कारनगत कुशलता को बढ़ाने तथा मुद्रा बाजार को विकसित करने के दीर्घकालीन उद्देश्यों का भी अनुसरण किया गया। उसके साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा जुलाई 1991 में आरम्भ किये गये व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक मुद्दों के उपायों के समन्वित कार्यक्रम को समर्थन दिया जाए। इस संबंध में वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति (अध्यक्ष श्री एम. सरमिहम) द्वारा की गई सिफारिशों को मौद्रिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

1.12 आन्तरिक अवधि के दौरान विशिष्ट ऋण नीतिगत उपायों के चार प्रमुख तत्व थे। उपायों के प्रथम समूह का लक्ष्य आयात को सीमित करना था। आयात पर सावधान्य प्रसिद्ध लगाने के बजाय, नकदी मांजित लागू करके (जो एक समय 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के दायरे में रहा) तथा 25 प्रतिशत व्याज दर अधिभार लगाकर आयात वित्तपोषण की लागत में वृद्धि करने जैसे उपायों को आयात सीमित रखने का संभाव्य रहित तरीका माना गया। उपायों का दूसरा समूह, जो प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक नीति संबंधी दृष्टिकोण की उपज है, भुगतान संतुलन में खाल लेखा खाने को सीमित रखने के लिए उठाया गया है। याद के किसी विशेष स्तर के लिए, व्यय में कटौती अथवा समावेशन का निश्चय ही यह अर्थ है कि व्यवस्था की समय मौद्रिक मांग साथ ही मुद्रास्फीति को भी कम किया जाए। लेकिन समय मांग तथा मुद्रा स्फीति में कटौती से ही भुगतान संतुलन की स्थिति में तुरन्त सुधार नहीं हो जाता है। उन्हें व्यवस्था की विभिन्न कड़ियों के माध्यम से कार्य करना होता है तथा उसे घाय में से घायत के प्रति मामूली से लगाव जैसे मानदण्डों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजकोषीय घाटे को सीमित रखने के साथ-साथ मुद्रा और ऋण की तंगी का यह परिणाम भी होता है कि इससे मुद्रा स्फीति के नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के अलावा संसाधनों के उपयोग में अधिक मितव्ययिता आती है।

1.13 उपायों का तीसरा समूह विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कुछ गिरावट के फलस्वरूप आया। उन उपायों में आयातों पर नकदी मांजित संबंधी शर्तों का हटाया जाना तथा बड़े उधारकर्ताओं के मामले में उधार पर व्याज दरों को उदा प्रकार थोड़ा कम किया जाता शामिल है।

1.14 उपायों का अंतिम समूह सरकार द्वारा किये गये राजकोषीय समायोजन तथा व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक समायोजन के मेय से उत्पन्न हुआ जिसके संदर्भ में यह उद्देश्य समझा गया कि नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा मौखिक चर्चानिध अनुपात दोनों में मौखिक पूर्वव्यापिकाएँ के स्तर को कम किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र को मुद्दों के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में वित्तीय प्रणाली पर गठित नरसिंहम समिति ने बैंकों के संसाधनों के पूर्वव्यापिकाएँ में कटौती करने की संसुति की। इसके जवाब में सरकार अपनी उधार संबंधी जरूरतों को बैंकों के संसाधनों के पूर्वव्यापिके बजाय, उपायों से उपाय बाजार में पूरा करने पर सहमत हो गयी है। इन उद्देश्यों का उपाय में रखा जा रहा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार की विविधता करने के सरा राता है एक अंग के रूप में भारत सरकार ने दो नयी लिखने अर्थात् 364-द्वितीय खजाना विल और 5 और 10 वर्षीय दिनांकित प्रतिभूति दोनों न लामी आधार पर जारी की, ये लिखने भी मोद्रि नियंत्रण लागू करने के बेहतर साधन विकसित करने की दिशा में बढ़ने के लिए एक प्रमुख आधार प्रदान करेंगी। उधार की व्याज दरों को और अधिक व्यक्तिगत

बनाया जाना तथा जमा राशि की परिपक्वता अवधि और जमा राशि पर ब्याज दरें निर्धारित करने के संबंध में बैंकों को भी गई पर्याप्त स्वतंत्रता भी उक्त सुधार कार्यक्रम के अंग हैं।

1.15 1991-92 के मौद्रिक अवधियों को रेखांकित करने वाली व्यापक धर्म व्यवस्था की प्रमुख परिचरूपणाएँ थीं—सकल देशी उत्पाद की वृद्धि 3 से 3.5 प्रतिशत तक, मुद्रास्फीति की दर 9 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा एम3 के विस्तार में लगभग 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी। आयात-रिपोर्ट, वस्तुओं, (ऋण संबंधी तथा राजकोषीय समायोजन—उपायों का समग्र दृष्टि दूर पर प्रभाव तथा इस स्थिति में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि 2.0 प्रतिशत से थोड़ी कम रह गयी और विशेषकर औद्योगिक उत्पादन में पूर्णतः घटरोध बना रहा। ऐसी स्थिति में भी 1991-92 में एम3 का विस्तार 18.5 प्रतिशत तक पहुँच गया जिसके कारण ये—प्राथमिक खनिजों में देशी विस्तार और प्रायोजित स्तर की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा का प्रवेश। बैंकि विदेशी मुद्रा के आपन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी अतः इन संसाधनों के प्राप्ति को रोकने वाले उपाय नहीं किये गये ताकि कहीं ऐसा न हो कि इन उपायों से ऐसे भागों में कमी आ जाए।

1.16 औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन को पुनर्जीवित करने तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में मुद्रास्फीति नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1992-93 की प्रथम छमाही की मौद्रिक नीति बनायी गयी। सकल राजकोषीय घाटे को 1991-92 में सकल देशी उत्पाद के 6.5 प्रतिशत से घटाकर 1992-93 में सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत पर लाने के सरकार के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति तैयार की गयी थी। समग्र नीति का उद्देश्य है मुद्रास्फीति की दर को कम करके 8 प्रतिशत तक लाना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने बजट घाटे (और मुद्राकृत घाटे) को कम करके उसे 1992-93 में 5,389 करोड़ रुपये तक लाने की योजना बनायी है। मुद्राकृत घाटे में कटौती का पूरा असर—मुद्रास्फीतिके कम होने पर पड़े इसके लिए यह माना गया कि मुद्राकृत घाटे को न केवल वित्त वर्ष के अंत में बल्कि पूरे वर्ष भर में कम रखा जाना चाहिए। यदि मुद्राकृत घाटे को पूरे वर्ष भर में कम रखा गया तो मौद्रिक विस्तार (एम 3) को 1991-92 के 18.6 प्रतिशत से कम करके 1992-93 में उसे 11 प्रतिशत से भी कम के स्तर पर लाना संभव होगा।

1.17 आलोच्य अवधि के दौरान मौद्रिक और ऋण नीतिगत महत्वपूर्ण उपायों का तर्कान्तर नीचे दिया गया है :

1.18 (क) व्याज दरें—(i) बैंक दर— बैंक दर मौद्रिक नीति के एक साधन के रूप में बैंक दर निष्क्रिय रही थी तथा जुलाई 1981 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुद्रास्फीतिकारी दबावाँ तथा रिजर्व बैंक की आवश्यकताएँ बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए यह उपयुक्त समझा गया कि बैंक दर के (नियंत्रणकारी) साधन को सक्रिय किया जाये। तदनुसार 3 जुलाई, 1991 को कारोबार की सम्पत्ति से बैंक दर को 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत वार्षिक और 8 अक्टूबर 1991 को कारोबार की सम्पत्ति से इसे और अधिक बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।

1.19 (ii) उधार पर व्याज की दरें— आलोच्य अवधि में उधार पर व्याज की दरों में बार बार आणविक किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दरों से आवश्यकता में अन्तर्निहित मुद्रास्फीति को झलक भिजे और व्याज दरों को घटाकर बनाने की आवश्यकता न हो। पहले यह माना गया कि मौद्रिक अधिक मुद्रास्फीतिकारी दबाव के संकेत में फई उधार पर व्याज की दरें वास्तविक रूप में तकरा हा गया है,

*धर्मव्यवस्था में सकल मांग को घटाने की आवश्यकता के परिदृश्य में, साथ ही जमा राशि दरों में वृद्धि का ध्यान में रखते हुए, 2 लाख रुपये से अधिक का ऋण उधार दरों को 4 जुलाई 1991 से 1.5 प्रतिशत अंक और उठाकर 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया है।

1317 GI/93-6

अनुसूचित ऋणित्व बैंकों के उधार पर व्याज की दरों में 9 अक्टूबर 1991 से 1.5 प्रतिशत बिन्दुओं की एक समान वृद्धि कर दी गयी। तीसरे बैंकि 2 लाख रुपये से अधिक की ऋणसीमा के लिए न्यूनतम उधार पर व्याज की दर अप्रैल 1991 और अक्टूबर 1991 के बीच 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी थी, मुद्रास्फीति की दर में कुछ विरावट को देखते हुए, आवश्यकतापूर्वक 2 मार्च, 1992 से 2 लाख रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के लिए उधार पर व्याज की दर में एक प्रतिशत बिन्दु की कमी कर दी गयी। अंततः बैंकों की उधार की व्याज दर संरचना को क्रमिक ढंग से सुक्रियत बनाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में 22 अप्रैल 1992 से उधार पर व्याज की दरों की मौजूदा छः श्रेणियों को घटाकर चार कर दिया गया (परिणिष्ट सारणी I-1 में 22 अप्रैल 1992 तक संरचना में किये गये परिवर्तन दिये गये हैं)।

1.20 (iii) जमा राशियों पर व्याज—प्रतिवार्षिक बैंक जमा राशियों पर धनात्मक वास्तविक व्याज दर उपलब्ध कराने हेतु आलोच्य अवधि में बैंकों की जमा राशियों पर व्याज दर संरचना में कुछ संशोधन हुए। पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों ने अपने उधार कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था अपने नीजी संसाधनों से की है तथा बैंकलिनक बचत मात्रों प्रत्यक्ष रूप से बैंकों को तैयार करने के लिए अनुसूचित ऋणित्व बैंकों की मागधि जमा राशि दरों में सभी स्तरों पर 4 जुलाई 1991 से एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की गयी है। दूसरे अनुसूचित ऋणित्व बैंकों की 46 दिन से लेकर एक वर्ष के कम परिपक्वता वाली मौदादी जमा राशियों पर (विदेशी मुद्रा अनिवार्य तथा प्रतिभासी बाह्य जमा राशियों को छोड़कर) व्याज दरें 9 अक्टूबर 1991 से 9.0 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी, ताकि बैंक जमा राशियों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा अलगावधिर प्रतिरिक्त निधियों पर प्रतिभाष की बहुर दर सुनिश्चित की जा सके क्योंकि मुद्रास्फीति की ऊँची दर ने अल्पतमजित जमा राशियों की व्याज दरों को अलाभकारी बना दिया था। छवी के साथ, अलगावधिर जमा राशियों पर प्रतिफल को बेहतर रूप में अनुकूल बनाने के लिए एक वर्ष के लेकर 2 वर्षों से कम परिपक्वता राशि मौदादी जमा राशियों पर व्याज दर को 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत कर दिया गया जबकि दो वर्ष के लेकर तीन वर्ष से कम परिपक्वता अवधि की जमा राशियों पर व्याज दर को 11.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप एक वर्ष और अधिक परलु तीन वर्ष से कम की जमा राशियों के लिए व्याज दरें 12.0 प्रतिशत वार्षिक हो गयी। 3 वर्ष और अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशियों की व्याज दरें 13.0 प्रतिशत वार्षिक पर आरिर्वतित की रही। तीसरे अवस्था में, बैंकों को जमा राशियों पर व्याज दर को संरचना के विविधता में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में 22 अप्रैल 1992 से 46 दिन और अधिक की परिपक्वता वाला सभी निपदादी जमा राशियों (विदेशी मुद्रा अनिवार्य और प्रतिभासी बाह्य जमा राशियों को छोड़कर) पर व्याज की दरें “13.0 प्रतिशत वार्षिक से अवधिगत” की एकल निर्धारण सीमा के अस्तित्व से घायी गयी। अब बैंकों को यह छूट है कि वे परिपक्वता अवधि तथा जमा राशियों पर व्याज दरें 13 प्रतिशत वार्षिक की एकल निर्धारण सीमा के अस्तित्व निर्धारित कर लें। अन्ततः जमा राशि पर व्याज दरों को 24 अप्रैल 1992 में एक प्रतिशत अंक बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है (देखें परिणिष्ट सारणी I-2)।

1.21 (ख) आयातों पर नकद रकम और अन्य निविधियों में छूट— वर्ष 1991-92 के पूर्वार्ध तक, यह आवश्यकता थी, मुद्रा नीति संबंधी उपायों में क्रमिक रूप से सम्पत्ति की गई जो घटते हुए जाने तक पहुँच गया कि 22 अप्रैल

1991 से प्रभावी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किये गये पूंजीगत माल से इतने आयातों पर नकदी माजिन 200 प्रतिशत तक और ब्रिजिड लाइसेंसों के अन्तर्गत किये गये आयातों पर 150 प्रतिशत तक हो गया। इसके अतिरिक्त, 9 मई, 1991 से प्रभावी, सभी प्रकार के आयात वित्तपोषण पर बैंक ऋण के लिए 25 प्रतिशत ब्याज अधिभार भी लागू किया गया।

1.22 बाद में जैसे भी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ, सामान्य न्यूनतम नकदी माजिन आवश्यकता को कमिक रूप से घटाकर 8 अक्टूबर, 1991 से 200 प्रतिशत के स्थान पर 150 प्रतिशत, 9 दिसम्बर, 1991 से 50 प्रतिशत, 1 जनवरी, 1992 से 25 प्रतिशत करके अंततः 12 फरवरी, 1992 को इसे वापस ले लिया गया। बैंक ऋण अपने स्वयं के विवेक से माजिन का रूप और उसका आकार तय कर सकते हैं। हमी प्रकार, आयात वित्तपोषण पर 25 प्रतिशत ब्याज दर अधिभार भी 13 फरवरी, 1992 से निरस्त कर दिया गया।

1.23 (ग) निर्यातों के लिए प्रोत्साहन (i) निर्यात ऋण पुनर्वित्त:— निर्यातों को बढ़ाने की सहायी आवश्यकता और बैंकों को निर्यात ऋण देने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण पुनर्वित्त का मूला को उद्घाटित किया गया और इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों को निधियों की उपलब्धता भी बढ़ाई गई। 27 जुलाई 1991 से बैंकों को डि-स्तरॉय फार्मुले के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा था। 1988-89 में मासिक औसत स्तर के ऊपर निर्यात ऋण में जो वृद्धि हुई उस पर 50 प्रतिशत तथा वर्ष 1989-90 में निर्यात ऋण का मासिक औसत स्तर के ऊपर जो वृद्धि हुई उस पर 100 प्रतिशत निर्यात ऋण 4 सितम्बर, 1991 से प्रभावी प्रथम आधार पर पुनर्वित्त सीमाएं बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई जबकि दूसरे आधार के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निर्यात ऋण पुनर्वित्त जारी रखा गया। निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 नवम्बर, 1991 से प्रभावी दूसरे आधार में पुनर्वित्त बढ़ाकर 110 प्रतिशत और 28 दिसम्बर, 1991 से 125 प्रतिशत कर दिया गया। निर्यात क्षेत्र को अधिक सहायता जारी रखने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अप्रैल 1992, में निर्यात पुनर्वित्त निश्चित करने के लिए सामान्यतः आधार को आगे लाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के लिए निर्यात पुनर्वित्त की उपलब्धता में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

1.24 (ii) निर्यात ऋण पर ब्याज दरें:— निर्यात ऋणों पर ब्याज की कम दरों के कारण बैंक यह अनुभव करते रहे थे कि निर्यात क्षेत्र को उधार देना अनाधन्य है। साथ ही, निर्यात ऋण और अन्य ऋणों पर ब्याज दरों में भारी अंतर होने के कारण ऋण राशियों के घटते रहने की बड़ी संभावना थी। बैंकों को इसके लिए बेहतर प्रोत्साहन देने के लिए तथा उन्हें निर्यात प्रयासों को ऋण सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए पोतलवान पूर्व और पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को बढ़ाया गया। निर्यात ऋण पर ब्याज दर/के प्रति मासिक सहायता को वापस लेने के बाद अगस्त, 1991 में निर्यात ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि की गई और फिर अक्टूबर, 1991 में उधार दरों में सामान्य रूप से की गई वृद्धि के एक भाग के रूप में वृद्धि की गई (परिशिष्ट सारणी I.3) 2 मार्च, 1992 से 2 लाख रुपये से अधिक को ऋण सीमाओं के लिए न्यूनतम उधार दर में कमी किये जाने के कारण पोतलवान की मारीख से 90 दिन से अधिक अवधि के पोतलवान ऋण तथा अन्यथा अतिरिक्त निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज दरों को वर्तमान दरों से एक प्रतिशत अंक कम कर दिया गया है।

1.25 (iii) निर्यात संबंधी आयातों पर नकदी माजिन में छूट:— निर्यात प्रोत्साहन के उपायों के एक भाग के रूप में निर्यात संबंधी आयातों

(पूँजीगत माल से इतर) के संबंध में निर्धारित नकदी माजिनों में कमिक प्रियायते दी गई। वार्षिक निर्यात वस्तुओं को निर्धारित सीमा को जिस सीमा तक कुछ आयातों पर (पूँजीगत वस्तुओं के आयातों से इतर) विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों को बिना नकदी माजिन के माल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी, बढ़ाया गया।

1.26 (iv) अमरीकी डॉलरों के मूल्य वर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त योजना:— विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण योजना 1 जनवरी 1992 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य यह है कि निर्यातकों को विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण और संबंधित विदेशी मुद्रा के लिए लागू दरों पर ब्याज भुगतानों को सुविधा प्रदान की जा सके। 4 जनवरी 1992 से प्रभावी एक नयी पुनर्वित्त सुविधा "अमरीकी डॉलरों के मूल्य वर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त योजना" प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा निर्यातकों को प्रदान किये गये ऋण पर बैंकों को अमरीकी डॉलरों के मूल्य वर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण के 133-1/3 प्रतिशत के बराबर पुनर्वित्त दिया जाता है। डॉलर के मूल्यवर्ग वाले निर्यात ऋण योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए 22 अप्रैल, 1992 से इस योजना के अन्तर्गत पुनर्वित्त पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 5.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई, जबकि पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण (डॉलर के मूल्य वर्ग में) पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत वार्षिक हो बनी रही। अतः यह योजना बैंकों को निर्यातकों के लिए डॉलर मूल्यवर्ग में पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देती है।

1.27 (v) निर्यात ऋण (रुपया) पुनर्वित्त:— अगस्त और अक्टूबर 1991 में जब पोतलवान-पूर्व और पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण को ब्याज दरों को बढ़ाया गया था, तो निर्यात पुनर्वित्त की दर को नहीं बढ़ाया गया ताकि बैंकों को निर्यात ऋण पर नयी उधार दरों को लागू करने के लिए कुछ समय मिल सके। तदनुसार 22 अप्रैल 1992 से प्रभावी निर्यात ऋण (रुपया) पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।

1.28 180 दिन से अधिक अवधियों के लिए पोतलवान-पूर्व ऋण प्रदान करने हेतु प्राधिकृत बैंकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन:— निर्यात के प्रयासों को बढ़ावा देने और बैंकों को परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन मामलों में जहाँ निर्यातक अपने निर्यात से बाहर के कारणों से 180 दिन को अनुमति अवधि के अन्दर माल का पोतलवान नहीं कर पायें हों, 90 दिन तक पोतलवान-पूर्व ऋण के लिए अवधि बढ़ाने हेतु बैंकों को अधिकार प्रत्यायोजित किया है। बैंकों को 270 दिन तक पोतलवान-पूर्व ऋण ऐसे किसी भी पथ के संबंध में, जिसके लिए ऐसी लंबी अवधि तक ऋण की आवश्यकता हो, प्रारंभ से मंजूर करने के लिए भी अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

1.29 (घ) प्रारक्षित राशि की अपेक्षाओं में संबंधित उपाय: भारत में प्रारक्षित राशि की अपेक्षा, चलनिधि नियंत्रण के लिए एक प्रमुख साधन रही है। सांविधिक चलनिधि अनुपात, जिसे यद्यपि मूलतः विवेक सम्मत उपाय के रूप में स्वीकार किया गया था, मासिक रूप से सरकार को उधार की आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार आधारित दरों से कम दर पर करने का उद्देश्य पूरा करता रहा है। प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में लगातार वृद्धि के कारण यह साधन प्रति-उत्पादक के रूप में उभर

रहा था क्योंकि इससे बैंकों की लाभप्रवृत्ति भी प्रभावित होती है। श्री एम. सरसिंहम की अध्यक्षता में गठित वित्तीय प्रणाली पर समिति ने ग्रन्थ बातों के साथ-साथ सांविधिक चल निधि अनुपात को बरणबद्ध तरीके से कम किए जाने की सिफारिश की थी।

1.30 (i) सांविधिक चल निधि अनुपात :—सरकार द्वारा किये गए राजकोषीय समायोजन और व्यापक प्राथमिक स्थितिकरण के संदर्भ में यह व्यवहार्य समझा गया कि सांविधिक पूर्वक्रयाधिकार में वर्तमान स्तरों को तर्कसंगत बनाया जाये। वर्ष 1992-93 में केन्द्र के मुद्रांकृत घाटे में पूर्व अनुमानित कमी और केन्द्र के बाजार उधार कार्यक्रम में कमी की दृष्टि से सांविधिक चलनिधि अनुपात को वृद्धिशील आधार पर कम करने का निर्णय किया गया। तदनुसार, बकाया निवल मांग और मीयादी देयताओं (अनिवासी देयताओं को छोड़कर) के स्तर तक दिनांक 3 अप्रैल, 1992 को सांविधिक चलनिधि अनुपात 38.5 प्रतिशत पर अपरिचित रहेंगे और निवल मांग और मीयादी देयताओं में 3 अप्रैल 1992 के स्तर के ऊपर किसी भी प्रकार वृद्धि के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात 30 प्रतिशत होगा। अनिवासी देयताओं के संबंध में सांविधिक चल निधि अनुपात 30 प्रतिशत पर अपरिचित बना रहेगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उदारीकृत वित्तिय दूर प्रबंध प्रणाली के अन्तर्गत खोले गये अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना और विदेशी मुद्रा खाते, नकदी प्रारक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात दोनों को अनेकाओं से पूर्णतः मुक्त हैं।

1.31 (ii) वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात :—सरसिंहम समिति ने सिफारिश की थी कि मौद्रिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात का प्रयोग जारी रखा जाए यद्यपि यह अनुभव किया गया कि इसका वर्तमान स्तर काफी ऊंचा है और इसे कम करने की आवश्यकता है।

1.32 वर्ष 1991 के पूर्वार्ध की गंभीर अवधि के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को मई 1991 में लागू किया गया। यह अनुभव किया गया कि 15 प्रतिशत के औसत अनुपात के साथ-साथ 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को जारी रखा जाना ज्यादा अवधि तक उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में अवरोध होगा। साथ ही, यह विवेकपूर्ण भी नहीं होगा कि नकदी अवधि तक संरक्षकालीन प्रबंधन उपायों को जारी रखा जाए। तदनुसार बैंकों को 17 अप्रैल 1992 के स्तर के ऊपर निवल और मीयादी देयताओं में वृद्धि पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात रखने से छूट दे दी गई।

1.33 (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी बैंकों की नकदी शेष राशियों पर व्याज :—बैंकों की लाभप्रवृत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से नकदी प्रारक्षित अनुपात बढ़ाया गया है और साथ ही नकदी शेष राशियों पर व्याज भी बढ़ाया गया है। चूंकि नकदी शेष राशियों पर व्याज की अवधि से मौद्रिक नियंत्रण कम होता है, अतः नकदी प्रारक्षित निधि को और भी बढ़ाना पड़ा। यदि नकदी विशेष राशियों पर व्याज नहीं बढ़ा दिया जाता, तो उसी स्तर का मौद्रिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात को बहुत ही कम दर पर निर्धारित किया जा सकता था। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि को कम करने के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक समझा गया कि डिस्कोव पावर्टी के अन्तर्गत बैंकों को उनकी प्राप्त नकदी शेष राशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भरा किये गये कुल व्याज को वृत्तिनुसार बनाया जाए। ये संयोजन इस

वर्ष के दौरान दो वर्षों में किये गये। 19 अक्टूबर 1991 को प्रारम्भ होने वाले पञ्चाङ्ग से प्रस्तावों (i) 23 मार्च 1990 का निवल मांग और मीयादी देयताओं पर प्राप्त नकदी शेष पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज भरा दिया जाता रहा, (ii) 23 मार्च 1990 के बाद औसत 15.0 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात और 10.0 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अन्तर्गत प्राप्त नकदी शेष राशियों पर व्याज को घटी दर पर 5.0 प्रतिशत वार्षिक की दर से भरा दिया गया (जबकि इससे पहले यह 8.0 प्रतिशत वार्षिक था)। बाद में इस दर का 2 मई 1992 को प्रारम्भ होने वाले पञ्चाङ्ग से और घटाकर 3.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।

1.34 (iv) मातामृ ऋण उपाय :—(i) वृद्धिशील निवल खाते पर ऋण (निवल ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात वित्त वर्ष 1991-92 के पूर्वार्ध के लिए ऋण नाति के तौर पर बैंकों से वृद्धिशील निवल खाते पर ऋण के लिए 1991-92 में उनका वृद्धिशील निवल खाते पर ऋण (निवल ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। कार्टे से अनुपातल सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 1991 में निर्णय किया गया कि लगातार दो पञ्चाङ्गों में जिन बैंकों का अनुपात इस सीमा से अधिक हो, उनका अगले बार पञ्चाङ्गों के लिए पुनर्वित्त सामांय अपने स्तर पर कम कर दो जाएं और प्रत्येक उत्तरवर्ती पञ्चाङ्ग में सामांय ऋण देने वाले बैंकों का उत्तरवर्ती दो पञ्चाङ्गों में पुनर्वित्त सामांय कम कर दो जाएं। जिन बैंकों में लगातार नियंत्रित अनुपात का उल्लंघन हुआ है उन्हें पुनर्वित्त सुविधाएं पूर्णतः बंद कर दो जाएंगी।

1.35 सर्वस्त वैकिंग प्रणाली ने वर्ष 1991-92 में इस मातृदण्डों को अंतर्गत और पहले जैसा वृद्धिशील निवल खाते पर ऋण जमा अनुपात के नियंत्रण को जारी रखना 1992-93 के लिए आवश्यक नहीं माना गया। तदनुसार, अप्रैल 1992 में वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात का निर्धारण थात से लिया गया। बैंकों का यह सलाह दी गई कि वे अधिक और आर्थिक क्षेत्र का उत्पादक गतिविधियों को पुनः आलू कर, विशेषकर छोटे किसानों, लघु उद्योग और निवासी का आवश्यकताओं के लिए समर्थन देने, हेतु अपना ऋण सुविधाओं को सामांय करें। उन्हें यह वा सुनिश्चित करने का सलाह दी गई कि वे अपना उधार देने का गतिविधियों को अपने क्षेत्रों के अरूप में रखें और यह कि अपने क्षेत्रों या विधियों के उपायों के मध्य बड़े और जाका समय से बने आ रहे भारत सरकार का दूर करें।

1.36 (ii) अनुवृत्ति वित्तियक बैंकों का पुनर्वित्त सुविधाएं वापस लेना :—राजकोषीय के तंत्र दशाओं के संदर्भ में प्रारक्षित मुद्रा विस्तार को नियंत्रित करने का अनिवार्य आवश्यकता का ध्यान में रखते 19 अक्टूबर 1991 से निम्नलिखित पुनर्वित्त सुविधाएं वापस ले ली गई हैं : खाद्य वस्तुओं के लिए ऋण का पुनर्वित्त, वैकल्पिक पुनर्वित्त, 1:2 विस्तार्य खपति वित्त पुनर्वित्त और विदेशीय पुनर्वित्त। इस प्रकार वित्तिय ऋण पुनर्वित्त के प्रतिरक्षित कोई और पुनर्वित्त अब भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों का उपलब्ध नहीं है।

1.37 (iii) बैंक द्वारा बिलों का पुनर्गृहीत/पुनर्गृहीत :—रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में बैंकों के वित्त संवेधान के निराकरण/संकाया से ऐसा अनेक अन्तर्विषयक विशिष्टताएं सामने आई हैं जिनसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई बिल पुनर्गृहीत/पुनर्गृहीत सुविधा के व्यापक उद्देश्य का कथन और करने दोनों हैं। कर्तों में उल्लंघन करने का प्रवृत्ति का पता चलता है। जुलाई 1992 में बैंकों का इस आधार के तहत आदेश जारी किये गये हैं कि वे सहजता संबंध व्यवस्था के तहत के बने

उधारकर्तृकों के वित्तपोषण को टालने, निषेध दिनों को भुगतने और दिनों को भुगतने के लिए संविभागत्य प्रबंध निधिधी विनियोजित करने तथा ऋण मार्गदर्शकों और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करें। जैसा कि नवम्बर स्पष्ट किया गया है कि यह अनुशासन विनियम कंपनियों के साथ साथ बैंकों के वित्त संविभाग से भी संबंधित है। साथ ही रिजर्व बैंकों का सावधान किया है कि अपात्र मीमांसा दिनों के प्रति उनके द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी अतिरिक्त वित्त, उधार के रूप में माना जाएगा और तदनुसार उन्हें संबंधित अवधियों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात सांविधिक चलनिधि अनुपात का रख-रखाव करने के प्रयोजन हेतु अपनी बाहरी देयताओं की पुनर्गणना करनी होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की सृष्टि के लिए दंड भी दिया जा सकता है।

1.38 (IV) वित्तीय कंपनियों के लिए बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई सुविधाएं कियारा खरीद और उत्तर पट्टेदारी कंपनियों को बैंक अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों की तीन गुनी सीमा तक उधार दे सकते हैं। ऐसे कंपनियों का सुविधाएं प्रदान करते समय, बिलों का भुनाई/पुनर्भुनाई के माध्यम से प्रवर्तित किया गया ऋण या हिसाब में लिया जाता चाहिए। बैंकों को सलाह दी गई कि किराया खरीद और उत्तर पट्टेदारी कंपनियों के अतिरिक्त वित्तीय कंपनियों के मामले में यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा बो गये कुल ऋण सुविधा में बिल भुनाई/पुनर्भुनाई सुविधाएं भी शामिल हैं और यह निवल स्वाधिकृत निधियों का तीन गुना से अधिक न हो। जहां उधारो इस मानक से अधिक हों वहां बैंकों को सलाह दी गई कि प्रथम चरण के रूप में बेधाओं काहरण का अनुमति न दें और बकाया राशि का चरणबद्ध तरीके से कम करें।

1.39 उपर्युक्त निषेधों को लागू करते हुए जुलाई 1992 में बैंकों को सूचित किया गया है कि (क) भारी औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित अग्रणी वित्तीय कंपनियों द्वारा दूसरे रूप के कंपनियों पर भारित बिलों का भुनाई में सावधान रहे, (ख) उन्हें बेकैतर वित्तीय कंपनियों द्वारा बढ़ाई बिलों का पुनर्भुनाई नहीं करना चाहिए और इस प्रकार बिल कंपनियों का पुनर्भुनाई सुविधा देने से बचना चाहिए, तथा (ग) उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय कंपनियों को उपलब्ध कराया गया वनप ऋण संस्था के बिलों का पुनर्भुनाई सवित ऐसे कंपनियों का निवल हैसियत का अनुपात से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए।

1.40 (V) बैंकों और उनके सहायक संस्थाओं द्वारा संविभागत्य प्रबंध से संबंधित मार्गदर्शी निषेध संविभागत्य प्रबंध योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी निषेधों के अनुपालन से बचने का दृष्टि से रिजर्व बैंक ने यह पाया है कि बैंक अपने प्राथमिक से निधियों स्वरूप करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, ऐसे निधियों का प्रवित्त का गारंटी-कृत करें प्रस्तुत कर रहे हैं, आदि। अतः रिजर्व बैंक ने जनवरी 1991 के अपने परिपत्र में निहित शर्तों का बोहराया है और ऐसी कार्रवाई करने से बैंकों को रोकने के अलावा इस बात पर बल दिया है कि इन शर्तों के उल्लंघन की गंभीरता से लिया जाएगा और उन बैंकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी जो प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का बढ़ाने, रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त काहरण, और मुद्रा बाजार में पड़ने का रोकेंगे। ये शर्त बैंकों का सहायक संस्थाओं पर भी लागू होंगी केवल उन का छोड़कर जहां रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष से के विशिष्ट मार्गदर्शी निषेधों के अनुसार चलाये जा रहे उनके क्रियाकलापों के प्रतिकूल हों।

1.41 कुछ क्षेत्रों के लिए ऋणों पर प्रतिबंध 9 अक्टूबर, 1991 से प्रभावी बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक का बकाया ऋणों में कोई वृद्धि नहीं हो: (i) उपभोक्ता विकाश वस्तुओं का खरीद के लिए ऋण, (ii) अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त

क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण, (iii) शेयरों और डिबेंचर्स/बांडों के एज में व्यक्तिगत ऋण और (iv) प्रदल सम्पत्ति पर ऋण।

1.42 बैंकों के खातों पर दबावों का कम करने एवं औद्योगिक उत्पादन का उगाही का सुविधाजनक बनाने के संदर्भ में वित्त 22 अप्रैल, 1992 से प्रथम दो क्षेत्रों के ऋणों पर से प्रतिबंध हटा लिए गए, जबकि अन्य दो पर प्रतिबंध लागू रहे। इसके अतिरिक्त, बैंकों का यह सलाह दी गई कि वे वित्त 22 अप्रैल, 92 से शेयर और डिबेंचर्स/बांडों पर व्यक्तिगत ऋण पर 75 प्रतिशत का न्यूनतम मासिक निधारित करें।

1.43 (च) मुद्रा बाजार से संबंधित उपाय (i) जमा प्रमाणपत्र: 2 मई, 1992 से प्रभावी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय समूह) बैंकों का छोड़कर) द्वारा जारी किए जाने वाले जमा प्रमाणपत्रों (संक्षेप) का संसाधनों को 1989-90 में पाक्षिक औसत बकाया सकल जमा राशियों के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया। परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली को जमा प्रमाणपत्र जारी करने का सकल 7,537 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,551 करोड़ रुपये हो गई। बैंको द्वारा पहले का 5 प्रतिशत का संसाधन से अधिक जारी किए गए निक्षेप प्रमाणपत्रों पर नकदी प्रारक्षित अनुपात लागू नहीं होगा।

1.44 (ii) वाणिज्यिक पत्र: वाणिज्यिक पत्रों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी गईं: जैसे वाणिज्यिक पत्र का जारी करने के लिए कंपनी को नौ वर्षों पूरा (निधि आधारित) संसाधन में कमी करके उसे न्यूनतम 10 करोड़ रुपये के स्थान पर न्यूनतम 5 करोड़ रुपये कर दी गई और भारतीय साख निधारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिपल) और भारतीय निवेश सूचना और साख निधारण एजेंसी (आईसीए) से न्यूनतम साख निधारण का अपेक्षा का क्रम: इसके पूर्व को पी 1 तथा ए 1 के स्थान पर पी 2 तथा ए 2 कर दिया गया।

1.45 (iii) मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड: मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड को एक नयी योजना प्रारम्भ की गई। मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के अन्तर्गत तथा परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। बैंकों द्वारा स्थापित मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड के मामले में इन निधियों की सीमा वर्ष 1991-92 के दौरान प्रवर्तक बैंकों की पाक्षिक औसत सकल जमा राशियों के 2 प्रतिशत के बराबर होगी। यदि मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर मुद्रा बाजारों में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक माध्यम के तौर पर कार्य करना है, केवल व्यक्ति प्रलग-प्रलग ही मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड में अभिधान कर सकते हैं। न्यूनतम निधि-रोध यद्यपि 46 दिन की होगी। निवेशकों को न्यूनतम प्रतिलाभ दर की गारंटी नहीं दी जा सकती। प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड पर लागू नहीं होगी।

1.46 (ख) सरकारी प्रतिभूति बाजार और खजाना बिल निर्माण के विकास से संबंधित उपाय: सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्रिय बाजार का विकास करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार को इस तरह पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों पर ऋण के लिए सरकार की निर्भरता कम हो। इस उद्देश्य को आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति को अपनाकर प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। यह मुद्रा नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें व्याज दरों में लचीलापन, नयी लिखतों को प्रारम्भ किया जाना, खुले बाजार

के क्रियाकलापों द्वारा खल-निधि विस्तार संकुचन किया जायेगा। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं।

1.47 (i) मीट्रिक सिखन के रूप में लचीली वरों के साथ खजाना बिल को विकसित करने के लिए और दिनांकित प्रतिभूतियों और वर्तमान 91 विवसीय खजाना बिलों के बीच मध्यवर्ती परिपक्वता के साथ एक वित्तीय सिखन प्रदान करने के लिए, 182 दिवसीय खजाना बिल सिखन नवम्बर 1986 में प्रारंभ को गयी जो अब एक प्राकृतिक मुद्रा बाजार सिखन बन गयी है। खजाना बिल बाजार का और विकास करने की दृष्टि से तथा विभिन्न प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न लघु-प्रवधि की परिपक्वता वाले वित्तीय सिखनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 364 दिवसों की प्रवधि वाले खजाना बिलों को जारी किया गया। इस नीति के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल 1992 से 364 दिवसीय परिपक्वता प्रवधि के खजाना बिलों की छठ बार नीलामी आयोजित की गयी। ये नीलामियाँ काफी उत्साहपूर्ण रही और 5 अगस्त, 1992 तक लगभग 6,349.63 करोड़ रुपये चार महीने की लघु प्रवधि के भीतर जमा किए जिसकी प्रारम्भ में अधिकतम भाग दर पहली पांच नीलामियों के लिए 11.42 प्रतिशत तक थी तथा बाद की तीन नीलामियों के लिए क्रमशः 11.36 प्रतिशत, 11.27 प्रतिशत और 11.20 प्रतिशत थी।

1.48 (ii) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों को लचीली ब्याज दर वाली मीट्रिक सिखन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जो निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके, भारत सरकार ने पहली बार नीलामी द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की सकल राशि पर 5 वर्षीय परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ तथा इनकी ही राशि को 10 वर्षीय प्रतिभूति क्रमशः 3 जून, 1992 तथा 9 अगस्त, 1992 को बेचने का प्रस्ताव किया। 5 वर्षीय प्रतिभूति की नीलामी में 12.0 प्रतिशत की अधिकतम भाग वाली 713 करोड़ रुपये की 21 बोलियों को स्वीकार कर लिया गया, और 287 करोड़ रुपये की शेष राशि रिजर्व बैंक द्वारा अभिधान की गयी। इसी प्रकार, 10 वर्षीय प्रतिभूति की नीलामी में 12.75 प्रतिशत की अधिकतम भाग वाली बोलियाँ 647 करोड़ रुपये के लिए स्वीकार की गयी तथा शेष 353 करोड़ रु० की राशि रिजर्व बैंक द्वारा अभिधान की गयी।

1.49 (iii) जुलाई 1973 से रिजर्व बैंक, बैंकों और बीमा निगमों की सरकारी प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक के पास खुले हुए अपने संविभाग (पोर्टफोलियो खातों में 'अंशित' करने के लिए बाधित कोटा आवंटित करता रहा है जिससे कि वे अपने निवेशों पर अपनी आय को बढ़ा सकें। बैंकों और बीमा निगमों को कोटा आवंटन की यह प्रणाली वर्तमान वित्त वर्ष से समाप्त कर दी गयी है, क्योंकि प्रति अंतरण कोटा प्रणाली बैंकों/संस्थाओं और रिजर्व बैंक के मध्य केवल सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देनों को बढ़ाती है और मीट्रिक समुच्चय पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता।

1.50 (iv) भारतीय मितोकटा और वित्त गृह लिमिटेड ने 2 अप्रैल, 1992 से सीमित स्तर पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन प्रारंभ कर दिया है। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार का विकास करने की दिशा में यह प्रथम चरण है।

1.51 (v) नयी अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना का प्रारम्भ :- अनिवासियों और उनके द्वारा स्थायिक विदेशी कंपनियों निकायों को और प्रोत्साहन तथा व्यापक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से एक नयी अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना की घोषणा की गई। इस योजना की प्रमुख बात निम्नलिखित है :

1.52 इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यापारियों को भारत से बाहर विदेशी मुद्रा निधि या वर्तमान अनिवासी बाण्ड खातों/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों से अंतरण द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी। इस नयी अप्रत्यावर्तनीय रुपया योजना में निधियों के अंतरण को जमा करने के समय लागू विनिमय दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाएगा और इन निधियों को बाद में फिर से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस नयी योजना के अन्तर्गत जमा राशियाँ छः महीने से तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं और उन्हें प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए नियत मांग और मीमादी वेधताओं के अंश के रूप में नहीं लिया जाएगा और इस प्रकार ये जमाराशियाँ किसी भी प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होंगी। इन जमाराशियों में से दिये जाने वाले ऋणों की राशि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उद्यार्यों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक ऋण के अंश के रूप में नहीं लिया जाएगा। इन जमाराशियों और इनमें से दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज दर विनिमय लागू नहीं होंगी और इस प्रकार बैंक इस योजना में जमा और उधार की व्याज दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैंक इस योजना में प्राकृतिक जमाराशि व्याज दर प्रस्तावित कर सकते हैं। जहाँ जमाकर्ता एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे वही यदि एक बार इन जमाराशियों का बैंकिंग प्रणाली से बाहरण कर लिया जाता है तो बैंकिंग प्रणाली में उनकी पुनः वापसी पर भी उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इन प्राकृतिक विशेषताओं की वजह से, प्राधिकृत व्यापारी इस योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में जमाराशियों का संग्रहण कर सकेंगे और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर बिना किसी विनिमय जोड़िम के विदेशी मुद्रा को प्राकृतिक कर सकेंगे।

1.53 विनिमय दर नीति : रुपय की विनिमय दर के संबंध में नीतिगत गतिविधियाँ विभिन्न मूलभूत मुद्दों जैसे बाजारगत अपेक्षाओं की तात्कालिक प्रतिक्रिया और दोषावधि सुधारों के परिणाम से प्रभावित हुई। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 1 और 3 जुलाई, 1991 को रुपये के विनिमय मूल्य को दो चरणों में घटाकर समायोजन किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया था कि भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धिता को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप उसे उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके। देश की विदेशी मुद्रा प्राप्ति में निरंतर ह्रास की स्थिति बाजार की अपेक्षाओं को प्रस्थिर बना रही है। ऐसे वातावरण में उचित विनिमय दर समायोजन तात्कालिक अवधि में बाजार अपेक्षाओं को रोकने में सहायता करता है जो प्रथमः पूंजी के विकास को रोकती है और साथ में उसके प्रगम को प्रोत्साहित करती है। साथ ही, शीघ्र ही और निश्चित रूप से मध्यवर्धि में अवामुखी समायोजन, देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिता को बढ़ाने और व्यापार में अतन्तुलनों और चालू खाते के घाटों को सुधारने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। यह व्यापारिक वस्तुओं (विदेशी मुद्रा या देशी मूल्य वस्तुएं) से गैर-व्यापारिक (या घरेलू) वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य बढ़ाता है। इस प्रकार, यह व्यापारिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और इनकी खपत को हतोत्साहित करता है।

1.54 भारत के मामले में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन और करों के मामले में रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के अनुरूप उचित समायोजन देश के निर्यात कारोबार में एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। भारत और प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच मुद्रा व्यापक स्कीमिगत विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप अक्टूबर 1990 और मार्च 1991 के बीच की अवधि के दौरान रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर लगभग 2 प्रतिशत बढ़ी। इस अवधि में रुपये की अंकित प्रभावी विनिमय दर में 5 मुद्राओं की तुलना में 2.4 प्रतिशत की लगातार गिरावट होती रहने पर भी रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि हुई। फरवरी 1991 और जून 1991 के बीच 5 महीनों

की रुपये अधि में रुपये की अधिक प्रमाणी विनिमय दर में केवल 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मुद्रास्फीतिगत विभिन्नताओं में लगातार विस्तार होता रहा। पिछले दशक में निस्संदेह भारत ने रुपये के मूल्य में महत्वपूर्ण कमी की, किन्तु प्रतिस्पर्धी देशों ने अपनी मुद्राओं के मूल्य में प्रभावी रूप से और अधिक कमी की। भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धाता को बहाल करने और व्यापार और चालू खाते संबंधी घाटों को कम करने के लिए, रुपये के मूल्य में प्रमुखी समायोजन करना आवश्यक हो गया। समायोजन की सीमा निर्धारित करने के लिए चार घटकों की ध्यान में रखा गया (1) भारत और प्रमुख, औद्योगिक देशों के बीच पायी जाने वाली स्फीतिगत विभिन्नताएं, (2) भारत से प्रतिस्पर्धी कर रहे देशों की मुद्राओं में वास्तविक मूल्यहास कर स्तर, (3) भुगतान संतुलन में अपेक्षित सुधार को मात्रा और (4) बाजार अविशेषों के व्यापक सूचकांक। इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए रुपये के मूल्य में 18-19 प्रतिशत तक की कमी करना उचित समझा गया।

1.55 हाल की गत अधि के दौरान चरणबद्ध रूप में छोटी-छोटी मात्रा में किये गये विनिमय दर समायोजनों के विपरीत यह आवश्यक समझा गया कि बचनी हुई परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में रुपये का समायोजन किया जाए। विशेषकर दो कारणों से: प्रथम पूंजी प्राप्तियों और प्रेषणों को प्रोत्साहन देने के लिए बाजार की पूर्वपेक्षाओं को निरस्तार्हित करना और दूसरा विनिमय दर समायोजन को बृहद् स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों में एक भाग के रूप में ही समझना। इसके अतिरिक्त विनिमय दर में इस बड़े समायोजन से सरकारी बजट में से दी जाने वाली विवेकाधीन नियतितव्य आर्थिक सहायता को रोका जाना भी संभव हो सका।

1.56 जुलाई 1991 को विनिमय दर समायोजन के बाद वर्ष के दौरान रुपया जालर दर में स्थिरता आने के साथ-साथ सामान्यतया प्रेषा-कृत उच्च व्याज दरों सहित और विशेषकर निर्यात ऋण पर व्याज दरों में वृद्धि और आयात वित्तपोषण पर व्याज दर अधिप्रभार को लगाने से विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की प्रवृत्ति को बचाने में अत्यधिक सहायक मिली।

1.57 जुलाई 1991 की नयी व्यापार नीति के परिणामस्वरूप एक्जिम स्क्रिप की प्रणाली आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत निर्यातकों को उनमें निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर (या कुछ मामलों में 40 प्रतिशत) स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य आयात करने की पात्रता प्राप्त हुई। एक्जिम स्क्रिप के बेचे जाने पर प्रीमियम ने निर्यातकों को अपनी निर्यात लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बढ़ाया। तथापि एक्जिम स्क्रिप प्रणाली के दौरान अनेक परिचालनात्मक और अन्य समस्याएं आईं। सर्वप्रथम तो निजी प्रेषणों और प्रयुक्त प्राप्तियों के प्रोत्साहन योजना से बाहर रह जाने के कारण इसकी सीमा सीमित थी। इसकी बड़ी संख्या के लेन-देनों में किसी भी प्रकार का विस्तार परिचालन को दृष्टि से कठिन और दुर्बल हो जाता। दूसरे एक्जिम स्क्रिप के एक दूसरे ही लाइसेंस का रूप ले लिया जिससे विशेषतः लाइसेंसों के निर्णय और सत्यापन में शामिल प्रशासनिक कार्यभार के कारण बचने की आवश्यकता थी। नवम्बर 1991 में भारत सरकार द्वारा भुगतान संतुलन पर नियुक्त उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन योजना आयोग के सदस्य) का विचार था कि आयातों को निर्यातों से जोड़ने के आवश्यक तत्वों को बनाए रखते हुए और निर्यातकों को प्रोत्साहन देते हुए जो नयी प्रणाली बनायी जाये उसमें लाइसेंस करने की आवश्यकता जारी नहीं होनी चाहिए उसमें सेवा और वस्तुप्रेषण अंतरण को शामिल किया जाना चाहिए और उसे अधिमानतः बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से परिचालित किया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक मार्च 1992 से उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को आरम्भ किया गया जिसके विवरण अण्ड VI में दिये गये हैं।

1.58 उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को चलाने से एक उपाय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसे भारत सरकार और

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए उदारीकरण के समग्र उपायों के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें अनिवार्य भारतीयों द्वारा स्वर्ण आयात की अनुमति भी शामिल है। निर्यात बढ़ावा को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य या यथासंभव कम से कम अफसरशाही और विवेकाधीन नियंत्रणों के साथ दक्ष आयात प्रतिस्थापन। इसमें बैंकिंग फिनलॉ के माध्यम से वनप्रेषणों को प्रोत्साहित करने और गुप्त रूप से किये जाने वाले लेन-देनों के लिए प्रोत्साहन कम करने की व्यवस्था है। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली मार्गस्थ (अल्पकालिक) व्यवस्था है। इसमें निकट भविष्य में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता लाने का स्वीकृत उद्देश्य सम्मिलित है। जैसा कि रंगराजन समिति ने जोर दिया है कि विश्व आर्थिक प्रणाली के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को समन्वित करने के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए चालू खाता लेन-देनों की पूर्ण परिवर्तनीयता की विधा में हमें कदम दर-कदम बढ़ने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यापक आर्थिक स्थिति और विश्व व्यापार वातावरण में होने वाली गतिविधियों को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि लोकहित के प्रयोजनों और अन्य मद्दों के लिए विदेशी मुद्रा का अधिकारिक आर्बटन का अनुपात नार्मल रूप से घटा दिया जाए और इस प्रकार आयातकों द्वारा बाजार से खरीदी जाने वाली विदेशी मुद्रा के धनरात में वृद्धि की जाए।

1.59 उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का अनुभव काफी उत्पादनक सिद्ध हुआ है। बाजार दर और अधिकारिक दर के मध्य अन्तर उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहा। वस्तुओं और सेवाओं जिनमें बाजार निर्धारित दरों पर पूंजीगत लेखा लेन-देन संबंधी कई प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन-देन को भली प्रकार से चलाया गया। इससे विदेशी मुद्रा में बाजार निर्धारित लेन-देनों को विकास का एक अवसर मिला है।

संरचनात्मक सुधार :

1.60 संरचनात्मक सुधार के क्षेत्र में औद्योगिक अवविनियमन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति का उदारीकरण, सार्वजनिक उद्यम सुधार, कर प्रणाली में सुधार, व्यापारी उदारीकरण तथा तृतीय क्षेत्रों में सुधार—ये सब आर्थिक प्रणाली के आमूल मूल पुनर्विग्यास के व्यापक घटक बनते हैं।

1.61 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में औद्योगिक अवविनियमन में कुछ उद्योगों को छोड़कर, शेष के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने, एकाधिकार की अवधारणा, जिसमें औद्योगिक निवेश को अनुमति देने के लिए बड़ी औद्योगिक घरानों की आस्तियों का सीमा निर्धारण शामिल है, को समाप्त करने, केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को कुछ उद्योगों तक सीमित करने तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने के साथ-साथ लघु, अल्पत लघु और आशेण उद्योगों को बढ़ावा देने के उपायों को प्रमुखता दी गयी थी।

1.62 इसी प्रकार 34 चुनिंदा क्षेत्रों में विदेशी ईक्विटी के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ ही विदेशी तकनीकी समकौतों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतः अनुमोदन प्रणाली जुलाई 1991 में आरंभ की गयी नीति का एक भाग थी। भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः उपलब्ध अनुमोदनों के अलावा अन्य प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय विचार करता है और इससे भी महत्वपूर्ण रूप में, एक विदेशी निवेश संवर्धन परिषद विचार करती है और उन्हें अनुमोदन करती है। इस परिषद का गठन ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले भारी निवेशों को प्राप्ति करने, उनका सौदा करने के लिए किया गया भी उच्च तकनीकी और विश्व बाजारों में हमारी पहुँच में सहायता प्रदान करेगी। 51 प्रतिशत ईक्विटी तक की स्वतः अनुमोदन प्रणाली की सुविधा, प्राथमिक ती पर

नियति कारोबार में सभी व्यापारिक कंपनियों, होटलों और पर्यटन से जुड़े उद्योगों, तथा हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम तथा गैस की खोज/विकास करने, उसे माफ करने तथा विपणन में संबंधित जैसे लाजुक क्षेत्रों के लिए भी प्रदान की गई है। पूर्ण स्वामित्व वाले ऐसे विदेशी उद्योगों को अब से विजयी की बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें अपनी नियति प्राय से शोध लामांश अदायगी की अपेक्षा नहीं होगी। अनिवासी भारतीयों और मुख्यतया उनके स्वामित्व वाले विदेशी निगमित निकायों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अनुमति के परिणामस्वरूप 'फेरा कंपनियां' (अर्थात् 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी धारितावाली कंपनियां) भारतीय कंपनियों के समकक्ष हो गई हैं और इस प्रकार दोनों को समान रूप से कारोबार करने की सुविधा दी गई है। वर्तमान "फेरा कंपनियों" को भी 51 प्रतिशत इक्विटी का सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही, देश में ही बिफो किये जाने वाले माल पर विदेशी ट्रेड के नाम और ट्रेड मार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। "फेरा" के अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रावधानों से छूट प्रदान करने के लिए उसमें महत्वपूर्ण संशोधन करने पर विचार किया गया है। हाल में (जून 1992 में) उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत 22 उद्योगों को छोड़कर लामांश संतुलन को शर्त की बाधना ले लिया गया।

1.63 आर्थिक अनुमोदन सविवालय (एन.डी.ए.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1991-92 (अगस्त के जून) के उद्घाटन के बाद का अवधि के दौरान अनुमोदित विदेश निवेश, रत वर्ष का उत्तम अवधि के अनुमोदनों से कई गुणा अधिक है। गत वर्ष के 474 अनुमोदनों का तुलना में गई 1992 तक 1430 अनुमोदन दिये गए (परिष्कृत सारणी 1.5)। इससे विदेशी सहयोग अनुमोदनों, फिरसे विदेशी इक्विटी लगी हुई है, को कुल संख्या के अलग-अलग ध्येरे इस प्रकार हैं—भारतीय रिजर्व बैंक (573.4 करोड़ रुपये का विदेशी इक्विटी के 168 अनुमोदन), आर्थिक अनुमोदन सविवालय (468.8 करोड़ रुपये का विदेशी इक्विटी के 332); और विदेशी 7 ट्रा निवेश संबंधित परिषद (846.5 करोड़ रुपये का विदेशी इक्विटी के 19)। तथापि, हाल की आर्थिक के तत्काल विदेशी निवेश प्रभाव संबंधी वास्तविक डेटा के अभाव उपलब्ध नहीं हैं।

1.64 उद्योगों को स्थापित करने और निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन देने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की श्रमिका को कम करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सुधार लाने का दृष्टि से जो सुधार के उपाय किये गये उनमें प्रमुख हैं—उत्पत्ति बजट में अंतरणों में कटौत और सुविधा उद्योगों के इक्विटी उपनिवेश जो 20 प्रतिशत से अंतरण किये गए गया श्रमिका शब्द 49 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उच्च आर्थिक कमजोर अधिनियम में संशोधन पास किये जाने के बाद, भारत सरकार ने 54 केन्द्रीय उद्योगों के भानले औद्योगिक और विदेशी पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे हैं ताकि उनके पुनर्विन्माल और/या बैंक करने के संबंध में शीघ्र कार्यका तैयार किये जा सकें।

1.65 वर्ष 1991-93 के केन्द्रीय बजट ने कर-सुधार समिति (एडमज डॉ. राजा जो. बैरैया) का अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कर को सुधार-सात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर को दरों का अपेक्षाकृत रूप से कम करने और छूटों में कम जाकर व्यक्तिगत आय पर कराधान को पुनर्निर्माण बनाने के अलावा, पूर्णतया लाभ कर और तंपत्ति कर को उल्लेखनीय रूप से वृद्धिजन्य प्रयोग तथा अनुमानित कर योजना को लागू करने, कर आधार को व्यापक बनाने का कार्य शारंभ हो गया है। कंपनियों कराधान के प्रमुख विन्माल के कार्य को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है कि तब तक कि बैलेंस समिति का विस्तृत निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो जायें। अंतरण कराधान के मामले में त्रिभाषिक में कुछ और कटौतियां लागू की गई हैं (जिनसे वारि आने श्रमिवाले अनुच्छेद में दिये गये हैं)।

1.66 व्यापार नीति के क्षेत्र में जुलाई 1991 से विन्माल संबंध प्रमुख सुधार किये गये हैं—स्वीकृत उद्देश्य के अनुमान जो उद्यारीकरण के अगले तत्काल वर्षों में लागू किये जायेंगे श्रमिक क्षेत्र हैं सामान्य से कुछ उच्च प्रमुख सहित उद्योग नियंत्रित और श्रमिक व्यापारिक प्रणाली, आयातों और निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध, शार्वजनिक क्षेत्र का शरनीकरण, अत्यंत प्रतिस्थापन के स्थिति प्राप्त करने के लिए परणवद्ध श्रमिक कार्यक्रम और देशी उत्पादकों के लिए सरकार खरच के अधिमाल। सर्वप्रथम, 1 और 3 जुलाई 1991 के विनिर्माण वर समायोजन के बाद श्रमिक प्रतिपूति योजना (सं. रा. एम.) का 3 जुलाई 1991 से समाप्त कर दिया गया। पुनः पूर्ति लाइनेतों के स्थान पर नया विन्माल, जिन्हे पहले "एक्जिस्ट सिन्म" कहा गया है, आरम्भ किये गये। एक्जिस्ट सिन्म का शुरुआत व्यापार क्षेत्र में एक विन्मालगत परिवर्तन का प्रभाव है, जिनके द्वारा प्रणाली को निर्यातों से संबंध करके अधिकतम आयात प्रतिबंध प्राप्त करना है। एक्जिस्ट सिन्म को जिन्हे बाजार में प्रतिपूति पर देना जा सकता है, अनुमति मासों के आयात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नया उद्योगों तथा विशिष्ट प्रकार का उत्पादों और उपकरणों के विनिर्माणितियों के लिए स्विकृत शारमेंसों का छोड़कर कच्चे माल वार उपकरणों के लिए नये अनुमोदक लाइनेतों, सुषीकृत न किये गये नये सामान्य लाइनेतों का श्रेणी तथा नियति गृहों को दिये गये श्रमिका शारमेंसों को समाप्त कर दिया गया और ऐसे सभी प्रयास एक्जिस्ट सिन्म के माध्यम से किये जाने थे। इसके अलावा अग्रिम शारमेंसिण प्रणाली का नियति संवर्धन के साधन के रूप में सुसुद्ध करना था। तब-तबसे वर्ष में लाना गया, वह पाया गया कि एक्जिस्ट सिन्म योजनागतिक तौर पर दोषिल हो गई और उद्यारीकृत विवेका मुद्रा विनिर्माण वर प्रबंधन प्रणाली (एन.डी.ए.एम.ए.) को लागू होने पर उसे समाप्त कर दिया गया।

1.67 दूसरे पांच वर्ष का अवधि जो सर्वप्रथम शार्वजनिक-वर्षीय योजना का, श. अवधि है (1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997) के लिए घोषित कायरी नियति-प्रणाली निति में व्यापार उद्यारीकरण को काफ बल दिया गया है। इस निति निति से लाइनेसिण, मात्रात्मक प्रतिबंध और श्रम्य विनि-मात्मक तथा विवेकपूर्ण नियंत्रण काफ मात्रा में समाप्त हो गए हैं। निर्यातों तथा आयातों का नकारात्मक सूच्य में उल्लिखित मदों का छोड़कर निर्यातों और आयातों का शुद्ध रूप से करने का अनुमति दी गई है। शार्वजनिक क्षेत्र का एक्जिस्टियों के माध्यम से किये गये आयातों या निर्यातों का सरण-बद्ध मदों का सूच्य में शारों कटौतों का गई है। आयातों का नकारात्मक सूच्य में केवल 3 निविष्ट मदें, प्रतिबंधात्मक सूच्य में 68 मदें और शारण-बद्ध सूच्य में 8 मदें शामिल हैं। आयातों का प्रतिबंधात्मक सूच्य में मुख्यतया उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जिनको शेरिल लाइनेतों पर ही शार्यात नहीं किया जा सकता। सरण-बद्ध मदें हैं—पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, औषधियां, वनस्पति तेल और शर्करा, वर्यय तालन और सेवा, और शरणी। नकारात्मक सूच्य द्वारा विनियमित आयातों के मामले में कुछप्रकार का तथा वास्तविक रूप से इस्तेमाल करने को शारों का नियति रूप में लेन का प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। पूंज राश माल के आयातों को और उदार कर दिया गया और पूर्वनत माल के आयातों का शर काई नकारात्मक सूच्य नहीं है।

1.68 तीसरे, वर्ष 1991-93 के केन्द्रीय बजट में लागू संसा-प्रमुख में और कटौत कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, कच्चे माल, शार्व प्रमुख का अधिकतम दरों को 150 प्रतिशत से कम करके 110 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पूर्णतया माल का प्रमुख दरों को लगभग 10 से 25 प्रतिशत तक कम करके उसे अधिकतम 55 प्रतिशत के लगभग लाया गया है।

वितीय क्षेत्र के सुधार

1.69 वितीय प्रणाली पर गठित उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष: जी. एम. नरसिम्हम) की रिपोर्ट नवम्बर 1991 में प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप, समिति की अनेक सिफारिशों पर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। समिति द्वारा व्यापक रूप से सिफारिशों

की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण 'अल्प परि-
भाषित' समुदायों को भी लाभकारी स्थापना के माध्यम से कार्य करे,
जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और लाभप्रदता में वृद्धि हो।

1.70 उच्च समिति को यह राय थी कि मासिक चलनिधि अनुदान के
साधन को इसके मूल उद्देश्य के अनुगमन लागू किया जाये जिसमें इसे
विवेकसंगत प्रयोजनों के रूप में माना गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के
वित्तपोषण के प्रमुख साधन के रूप में। व्यापक प्राथमिक स्थिरता के साथ-
साथ एक संगत स्तर तक राजकोषीय घाट को कम करने के सरकार के
निर्णय के अनुसार उच्च समिति ने यह सिफारिश की है कि मासिक
चलनिधि अनुदान को साप्ताहिक पांच वर्ष की अवधि में खर्चबंद रूप से
कम करके 25 प्रतिशत तक ले आया जाए। केन्द्र के मुद्रांकित घाटे में
प्रत्याशित रूप में प्राप्ति गिरावट केन्द्र के ऋण प्राप्त करने के कार्यक्रमों
में आयी कमी तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार का धीरे-धीरे संवर्धन करने
की आवश्यकता के अन्तर्गत मासिक चलनिधि अनुदान को वृद्धिशील
प्राधार पर घटाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया है। मासिक
चलनिधि अनुदान में और अधिक कमी के बारे में खर्चबंद रूप में विचार
किया जा सकता है।

1.71 नकदी प्रारक्षित अनुदान (सीआरआर) के संबंध में नरसिम्ह
समिति ने यह राय दी है कि इस साधन को लागू करने में रिजर्व बैंक
को लचीलापन प्रदान करना चाहिए था ताकि वह अपने मौद्रिक नीति
उद्देश्यों और राजकोषीय घाट में कमी लाने से संबंधित सरकार के संकल्प
को पूरा कर सके। ऋण के गीण विस्तार के नियंत्रण के लिए इसका
प्रयोग बहुत ही कम अवसरों पर किया जाता चाहिए, और इसलिए इस
समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि
वह नकदी प्रारक्षित अनुदान के अपने उच्च स्तर में क्रमिक रूप से कमी
लाने के रास्ते में विचार करे। चलनिधि की स्थिति का जायजा लेते हुए
तथा मौद्रिक नीति की ध्यान में रखते हुए, एवं बैंकों के संसाधनों के पूर्व
अवधि-अधिकारों में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने
10 प्रतिशत की वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुदान को खत्म कर दिया है।
नकदी प्रारक्षित अनुदान में और अधिक कमी सभी लायी जा सकती है
जब मुद्रांकित घाटे में विस्थापित, समावेशन कर लिया जाये और बाजार-
सापेक्ष व्याज दर मजिद सरकारी प्रतिभूतियों में जुले बाजार के परिणाम
मौद्रिक नियंत्रण के प्रभावी साधन बन जायें।

1.72 नरसिम्ह समिति का यह प्रस्ताव था कि बैंकों को उनके सार्वजनिक
चलनिधि अनुदान और नकदी प्रारक्षित अनुदान की मूल मूलतः राशियों से
घटिक रोकी गयी जमा राशियों पर जो व्याज दर दी जाती है उनमें वृद्धि की
जाए। सरकार ने यह स्वाकार किया है कि सरकार द्वारा लिये गये उपायों
पर बाजार आधारित व्याज दर को अपनाते की ओर बढ़ने की आवश्यकता
है। नकदी प्रारक्षित अनुदान चलनिधि को अवरोध करने का अतिरिक्त,
एक मौद्रिक साधन है। अतः अत्यधिक राशि को कम करके नकदी प्रारक्षित
निधि अनुदान पर उच्चतर व्याज देना नकदी प्रारक्षित निधि अनुदान
लागू करने के मूल प्रयोजन को हल्का कर देता है। मौद्रिक नियंत्रण
की दृष्टि से, यह अतिरिक्त होता कि अत्यधिक व्याज नकदी प्रारक्षित अनुदान
को व्यवस्था की जाए, और उन पर कम व बिबिध व्याज न दिया जाए,
न कि नकदी प्रारक्षित अनुदान की सीमा अधिक रखी जाए, और उस पर
उच्च दर से व्याज का भुगतान किया जाए।

1.73 वर्षों ने बैंक प्रणाली की गिरती हुई वित्तीय स्थिति के कारणों
का पता लगाने हुए, नरसिम्ह समिति ने विभिन्न सुधारात्मक उपायों की
सिफारिश की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता के मानदण्ड,
आय की स्थिति के लिए, विवेकपूर्ण मानदण्ड और अशोध ऋणों के लिए
प्रावधान करना शामिल है।

1.74 अतः, 1992 में, रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों के लिए (विदेशी
बैंकों सहित) पूंजी पर्याप्तता उपायों के रूप में जोखिम प्रारक्षित अनुदान
प्रणाली प्रारम्भ की। इस प्रस्तावित प्रणाली के अन्तर्गत तुलन-पत्र प्राप्ति, और

गैर-निधि मध्ये और तुलन-पत्र से उत्तर प्रत्य मध्ये की निर्धारित प्रतिशत के
अनुसार जोखिम भारों को ज्ञाते और बैंकों की, निरंतर आधार पर
जोखिम भारित प्राप्ति और अन्य आधारित प्राप्ति के कुल जोड़ पर
निर्धारित स्तर के बराबर न्यूनतम पूंजी निधिया अनुगमन रखनी होगी।
अंतराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले सभी बैंकों को प्रतीति जल्दी हो
मके परन्तु किसी भी स्थिति में 31 मार्च 1994 तक 8 प्रतिशत के
मानदण्ड को प्राप्त करना होगा। भारत में कारोबार करने वाले विदेशी
बैंकों को यह मानदण्ड 31 मार्च, 1993 तक प्राप्त करना होगा। अन्य
बैंकों को 4 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड 31 मार्च, 1993 तक
प्राप्त करना होगा (पहले स्तर या मूल पूंजी को नियत मोमा जो कुल
पूंजी के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो निर्धारित किया गया है) और 31
मार्च, 1996 तक, 8 प्रतिशत का मानदण्ड पूरा करना होगा। मानदण्डों
के अनुपालन के प्रयोजन के लिए दूसरे स्तर के पूंजी तत्वों का जोड़ स्तर
I के तत्वों के जोड़ के अधिकतम 100 प्रतिशत तक रहेगा। बैंकों को
यह सूचित किया गया है कि वे निर्धारित स्तर तथा योजना की तुलना
में पूंजी-निधियों के वर्तमान स्तर की समीक्षा करें ताकि नियत अवधि के
अन्त तक निर्धारित अनुदान प्राप्त करने के लिए पूंजी निधियों में
खर्चबंद रूप में वृद्धि की जा सके।

1.75 यदि किसी बैंक का तुलन-पत्र उम बैंक की वास्तविक वित्तीय
स्थिति को दर्शाता है, तो वहां स्वीकृति प्राप्ति-प्रणाली, प्राप्ति
का वर्गीकरण और विवेकपूर्ण आधार पर अशोध ऋण के लिए प्रावधान
करने की उचित व्यवस्था होगी। नरसिम्ह समिति ने सिफारिश की थी
कि प्राप्ति स्वीकृति दस्तुन और वस्तुओं के रिकार्ड पर प्रावधान
होनी चाहिए, न कि किसी दस्तुनक प्राप्तिमानों पर, और यह कि बैंकों
की प्राप्ति, न कि किसी दस्तुनक प्राप्तिमानों के आधार पर किया जाता
चाहिए जिससे मानदण्डों को लागू करने में एकस्यता तथा संगतता
सुनिश्चित की जा सके, और भिन्न-भिन्न श्रेणियों में प्राप्ति के वर्गीकरण
करने के आधार पर प्रावधान किए जाएं। अतः, 1992 में यह निर्णय
लिया गया कि 1 अप्रैल, 1992 में प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष के शुरू
(होने वाले) तीन वर्षों की अवधि के दौरान खर्चबंद रूप से फंडिंग
संशोधनों के साथ, समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। बैंकों
को अनुदेश दिए गए कि वे भिन्नाधीन ऋण, ओवरड्राफ्टों और नकदी ऋण
खातों, धारियों और भुताए गए बिलों तथा अन्य खातों से संबंधित ऐसी
राशि को, जिसका नियत तरीका को भुगतान हो 'विद्युत बिलों' (राशि)
समझे 'निष्क्रिय प्राप्ति' को एक ऋण पुविदा के रूप में परिभाषित
किया गया है जिसके संबंध में व्याज का भुगतान 31 मार्च, 1993 को
समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चार तिमाहियों के लिए 31 मार्च, 1994
को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के लिए और 31 मार्च,
1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान दो तिमाहियों के लिए और
उसके बाद की अवधि के लिए नहीं किया गया है। बैंकों को यह भी
अनुदेश दिए गए कि वे सभी निष्क्रिय प्राप्ति पर न तो व्याज लगाएं
और न ही उसे खाने में डालें वर्तमान घाट स्वास्थ्य कूटों की तुलना
में बैंकों को अपने अग्रिमों का मोटे तौर पर चार सप्ताहों में वर्गीकरण करने
की आवश्यकता है: (1) मानक प्राप्ति, (2) अशोध प्राप्ति,
(3) संदिग्ध प्राप्ति, और (4) गुरु हर्ष प्राप्ति। मोटे तौर पर
इन श्रेणियों में प्राप्ति का वर्गीकरण सुनिश्चित ऋण प्राप्ति के
स्तर और देयताओं की वस्तुओं के लिए समर्थ प्रमाणों की निर्वहन
की सीमा को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तथापि प्राप्ति के
वर्गीकरण की ऋण स्थिति कूट प्रणाली, अतः तुलना के उपाकरण के
रूप में जारी रहेगी।

1.76 खाने की वस्तु संविध हो तो तथा संविध वस्तु हो गयी है
ऐसी माध्य हो जाने तक के बीच के मध्य, अतः तुलना को वस्तुओं और बैंक
के पक्ष में प्रमाणित, अतः तुलना के तुरंत पक्ष में साथ-साथ तुलना हो
जाने को ध्यान में रखते हुए बैंकों को चाहिए कि वे अशोध प्राप्ति
संविध प्राप्ति और प्राप्ति की तुलना के मध्य के लिए प्रावधान करें

1.77 जहाँ तक निवेशों के लिए लेखा-गणकों का संबंध है, अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को दो भागों में बांटना होगा, अर्थात् "स्वायं" निवेश और "बाह्य" निवेश। स्वायं निवेश वे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता अवधि तक रखना चाहता है जब कि बाह्य निवेश वे निवेश हैं जिनमें बैंक कारोबार अर्थात् राजभरा के आधार पर उनकी खरीद और बिक्री करना चाहते हैं। गुरुत्वान करने के लिए लेखा वर्ष 1992-93 से बैंक "स्वायं" श्रेणी में अपने निवेशों का 70 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं रखेंगे लेकिन इस अनुपात को यथासमय बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक लाया जाएगा। जहाँ स्वायं निवेश में मूल्यह्रास से उनके बसूरी योग्य मूल्य के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है और इसलिए इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, 'बाह्य' निवेशों के मूल्यह्रास के लिए पूरे प्रावधान करने होंगे। 'स्वायं' निवेश जब तक अधिक मूल्य से अधिक न हों, तो लागत मूल्य पर ही माना जाए, ऐसे मामले में, प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि से अधिक की अवधि के लिए प्रीमियम का परिचालन करना होगा। बैंकों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे "स्वायं" श्रेणी में अपने बानी प्रतिभूतियों को मुक्त रूप से बिक्री करें, लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो इस श्रेणी के अंतर्गत अपने बानी प्रतिभूतियों के ऐसे लेनदेनों पर हुई हानि का बड़े खाते में डालना होगा। इसके अलावा, इस संबंध में होने वाले लाभ को पूंजीगत प्रारक्षित खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

1.78 विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देवताओं और अपरिपक्व हाजिर तथा वायदा विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों की मासिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। हाजिर और वायदा लेनदेनों का पुनर्मूल्यांकन उम मय प्रवर्तित क्रमः हाजिर और वायदा विदेशी मुद्रा की दरों पर किया जाएगा।

1.79 जहाँ तक विनियमित ब्याज दर संरचना का संबंध है, अनेक सुधारात्मक उपाय लागू किये गये हैं:

(1) बैंकों की ऋण दरों को कालो सरन तथा कारगर बना दिया गया है, जिसमें रिहायशी सौकों की संख्या को घटा दिया गया है और कुछ एक दरों में वृद्धि कर दी गई है जिससे कि वार्षिक-महायत्ता के तत्वों में भी कमी लायी है, (ख) विनियमित जमा दर संरचना के स्थान पर 46 वित्तों और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सभी जमा राशियों के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक से अधिक का एगन निर्धारण लागू किया गया है, और (ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर बाज दरों में वृद्धि दर दी गई है तथा 364-दिवसीय खताना वित्तों और 5 वर्षीय और 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की नीलामी की गयी है। जहाँ यह उल्लेख करना प्राप्ति होगा कि कुछ एक निश्चित अर्थात् जमा प्रवाणतों, मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियाँ और प्रतिवासी (अप्रवासी-निध) कया जमा योजना तथा वाणिज्य बैंकों के जमा संस्थापनों के एक महत्वपूर्ण अंग के लिए अब बाजार सापेक्ष बाज दर निर्धारित की गई है।

1.80 नरसिंहम समिति ने शाखा लाइसेंसिकरण नीति को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यह विचार करते हुए कि देश भर में, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की मूलभूत सुविधाएँ पर्याप्त रूप से प्रदान करने के लक्ष्य को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है जिससे 1985-90 की अवधि के दौरान शाखा विस्तार नीति के अन्तर्गत यह कार्य पूरा कर लिया गया, रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में और अधिक छूट देने का निर्णय लिया है कि वे अपनी वर्तमान शाखाओं का पुनः आकट करके विशिष्ट शाखाएँ खोल कर अन्य स्थानों पर अपना कारोबार फैलाकर नियंत्रक कार्यालयों/प्रशासनिक यूनिटों को स्थापित करके और विस्तार काउण्टरों को खोल कर, के रूप में अपने वर्तमान शाखा नेटवर्क को वास्तव में बना लें। बैंकों को इस बात की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है कि वे प्राथमिक क्षेत्रों से दूर शाखाओं को तथा घाटा वाली शाखाओं या दूरस्थ क्षेत्रों वाली शाखाओं को बन्द कर सकते हैं। उदाहरित शाखा लाइसेंसि-
1317 GI/93—7

करण नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल उन्हीं बैंकों को नये शाखा कार्यालय खोलने/विस्तार काउण्टरों को पूर्णतया नये शाखा में परिवर्तित करने की छूट दी गई है जिन्होंने परिणामित पूँजी पर्याप्तता के मानदंडों और विवेकपूर्ण लेखा मंगला का प्राप्त कर लिया है। जब तक बैंक परिणामित पूँजी पर्याप्तता के मानदंड प्राप्त नहीं कर लेते और इस आशय की विशिष्ट रूप से सूचना नहीं दे देते, तब तक उन्हें नयी शाखा खोलने या विस्तार काउण्टर की एक पूर्ण शाखा के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

1.81 विदेशी बैंकों की शाखाओं का विस्तार अब तक की तरह निर्धारित तथा विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा। इस सम्बंध में विवेकपूर्ण और अन्य मापदंडों अनुपालन के अलावा पक्षपातरहित आपसी व्यवहार तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों को पर्याप्त बल दिया जाएगा।

पूँजी बाजार

1.82 पिछले वक्क के दौरान भारतीय मुद्रा बाजार में नये निर्गम संबंधी कार्यकर्ताओं और द्वितीयक बाजार के लेन-देनों दोनों ही के संदर्भ में हुए विकास को मानते हुए नरसिंहम समिति ने इस बात पर बल दिया है कि मर्चेंट बैंकिंग तथा पारस्परिक निधियों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थाओं जो पूँजी बाजार के कार्यकर्ताओं में संलग्न हैं, के कारोबार तथा शेयर बाजार का ठोस आधार पर विकास हो, निवेशकों की सुरक्षा के उपाय के रूप में विनियमों की एक संहिता आवश्यक है। पूँजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय के विनियमक कार्यों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को अन्तरिक करने की सिफारिश करते हुए समिति ने सेबी की भूमिका के बारे में यह माना है कि सेबी को केवल पूँजी निर्गम नियंत्रक की प्रतिबंधात्मक भूमिका ही अथवा नहीं करनी है बल्कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार के नियामक की भूमिका अदा करनी है ताकि बाजार में लेन-देन का कार्य नियंत्रित किए गए सिद्धांतों और मापदंडों निदेशों के आधार पर लिए जाते हैं। समिति की यह राय थी कि सेबी को बाजार के रोजमर्रा के कार्यों से दूर रहना चाहिए अथवा पूँजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अत्यधिक पक्षपातपूर्ण नियंत्रण जैसे जो कार्य किये जाने थे वे बोर्ड को नहीं करने चाहिए। नये पूँजी निर्गमों के मामले में यह कार्य मर्चेंट बैंकरो और हामीदरों पर छोड़ देना चाहिए कि वे किसी विशेष निर्गम पर लिखत के प्रकार पर उसके सौतों और मूल्य तय करने पर व्यावसायिक सलाह और अपने अधिमान शेयर के बारे में निर्णय करने का कार्य निर्गमकर्ता कंपनी पर छोड़ दें।

1.83 बाजार का स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने और विवेकपूर्ण मापदंडों निदेशों के आधार पर निवेशक की सुरक्षा के लिए बाजार को विश्वसित करने के ह्रादे से जो पूँजी बाजार संबंधी सुधारात्मक उपाय किए गए थे, उन सभी को अधिकांशतया लागू कर दिया गया है। 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति का एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय के रूप में सांख्यिक दर्जा दिया गया। जिसका कार्य प्रतिभूतियों के मामले में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, पूँजी बाजार संबंधी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, शेयर बाजार सहित बाजार की गतिविधियों को विनियमित करना होगा। साथ में, संसद द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड-बिल पास कर दिया गया जिसके अनुसार संगठन को 31 मार्च 1992 से निर्गम रानी रखने वाले एक निकाय के रूप में अधिकारिक साम्यता प्रदान की गई।

1.84 निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की पारस्परिक के निधियों को प्रवेश संबंधी अनुमति दिए जाने के निर्णय के पश्चात् खातों के प्रस्तुतीकरण सहित पारस्परिक निधियों के संश्लेषण तथा परिचालनों की देख-रेख के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दूसरे पक्ष भर के सभी शेयर बाजारों का वार्षिक निरीक्षण का कार्यभार प्रति, और वि. बोर्ड के अंतर्गत लाया गया ताकि शेयर बाजार क नियमित विकास तथा निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके तीसरे मई, 1992 में पूँजी निर्गम नियंत्रक अधिनियम, 1947 को समाप्त

कर दिए जाने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को ही कंपनियों के नये निर्गम कार्यक्रमों के लिए विनियमित प्राधिकरण बना दिया गया है।

1.85 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों जैसे अनेक पहलुओं से संबंधित अनेक मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं जिससे कुल मिलाकर पूंजी बाजार की भारी गतिविधियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:—(1) भावी निर्गमों और संश्लिष्ट प्रबंधन सविदा की शर्तों सहित से संबंधित अग्रणी प्रबंधक/मैनेजिंग डायरेक्टर (2) पारस्परिक निधियों और उनके प्रत्येक के घटक अर्थात् प्रायोजक धारक/आस्थि प्रबंधन कंपनी और आस्थि प्रबंधन के गठन सहित अभिरक्षक (3) आंतरिक जानकारी के आधार पर व्यापार की प्रवृत्ति के रोकने के लिए कड़े विनियमों सहित शेयरबाजार और (4) पूंजी निर्गमकर्ताओं और मध्यस्थों द्वारा उचित प्रकटीकरण तथा निवेशकों की सुरक्षा से संबंधित मानदंडों के अनुपालन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमोटर्स का अंशदान निर्गमों के मूल्य ऋण निधियों का साख निर्धारण बड़े निर्गमों की निर्गम प्राप्तियों का संभालन तथा हामीदारी और न्यूनतम अधिदान से संबंधित शर्तें शामिल हैं।

1.86 भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार लिमिटेड, फैन बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, साधारण बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित भारतीय ओवर द काउंटर एक्सचेंज को 23 अगस्त 1989 से प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक रटाक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गयी है। यह एक्सचेंज भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 20 सितम्बर 1990 को एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। भारतीय ओवर द काउंटर एक्सचेंज को छोटी और मध्यमकार की कंपनियों को कम लागत में पूंजी बाजार से वित्त जुटाने तथा व्यापक रूप से निवेशकों के लिए पूंजी बाजार निधियों की एक सुविधाजनक और वक्ष प्रणाली उपलब्ध करने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। यह एक रिंग (ब्यू) रहित इलेक्ट्रॉनिक तथा एक राष्ट्रीय शेयर बाजार है जिसमें पूरी तरह से नयी कंपनियों के शेयरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि यह अपने व्यापारिक परिचालन अगस्त 1992 के प्रारंभ से शुरू कर देगा।

1.87 पूंजी बाजार से संबंधित अन्य कुछ उद्धारकरण के महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं: (1) कर्मजित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के बांडों को छोड़कर डिबेंचर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों पर ब्याज की दरों पर लगे सभी प्रतिबंधों को अगस्त 1991 में निरस्त कर दिया गया था। यह देखा गया कि वर्ष 1991-92 के दौरान निर्गम जारी करने वाली कंपनियों ने अपरिचालनीय डिबेंचरों पर लगभग 17 प्रतिशत आंशिक परिचालनीय डिबेंचरों पर लगभग 16 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया। (2) गैर-बैंकिंग और गैर-वित्तीय कंपनियों ने उनके द्वारा स्वीकार की गई जमा राशियों पर वेब अधिकतम 14 प्रतिशत की ब्याज दर को बढ़ाकर जनवरी 1992 में 15 प्रतिशत कर दिया। (3) मियादी ऋणदात्री संस्थाओं से संबंधित ब्याज दर संरचना में और अधिक लचीलापन लाने की दृष्टि से इन संस्थाओं द्वारा ऋणों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा के निर्धारण की जगह एक रेगुलर प्रणाली आरम्भ की जिसमें अगस्त 1991 से कम से 15 प्रतिशत ब्याज पर निश्चित की गई थी। संस्थाएं अब सामान्यतया उधारकर्ता की ऋणपात्रता के आधार पर ब्याज की दर निर्धारित करती हैं, (4) विद्युत अर्द्ध रिफाई रखने वाली कंपनियों को विशेषता से बसे निवेशकों के लिए परिचालनीय डिबेंचर अथवा ईजकटी जारी करने की अनुमति दी गई ताकि वे, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उपलब्ध लागू होंगे जो विदेशी म्यूचुअल निधियों के मामले उपलब्ध हैं। (5) 1992-93 के केन्द्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि अच्छी साख वाले कंपनी निवेशकों, जैसे "पेंशन फंड", को उचित व्यवस्था के अंतर्गत

यह सुनिश्चित करने हुए कि इससे प्रबंधन नियंत्रण को हासिल होने का स्वतंत्रता न हो जाए, भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी जाए। (6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत सरकारी, निजी या संयुक्त क्षेत्र की पारस्परिक निधियों को वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट के अनुसार कर से छूट दी जायेगी। (7) भारत सरकार ने पारस्परिक निधियों के विकास और विनियमन के लिए तथा निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1992 में विवेकसम्मत मार्गदर्शी निदेशों की एक व्यापक सूची जारी की है। ये मार्गदर्शी निदेश संयुक्त रूप से और निजी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली पारस्परिक निधियों सहित सभी प्रकार की पारस्परिक निधियों को प्रतिनिधियों पर लागू होंगे। तथापि मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट मार्गदर्शी निदेशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। इन सरकारी मार्गदर्शी निदेशों में यह व्यवस्था की गयी है कि सभी पारस्परिक निधियों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से (सैबी) अनुमति लेनी होगी। पारस्परिक निधियों की स्थापना भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 के अंतर्गत एक न्याय के रूप में की जाएगी और पारस्परिक निधियों द्वारा आस्थि प्रबंध कंपनियों के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन मार्गदर्शी निदेशों में यह भी शर्त दी गयी है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड योजनाओं के माध्यम से न्यूनतम पितनी राशि जुटायी जानी है तथा प्रतिभूतियों/कंपनियों में निवेश और धाय के विवरण का क्या आधार हो। सैबी को यह अधिकार होगा कि वह पारस्परिक निधियों के कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी सूचना की मांग कर सके तथा पारस्परिक निधियों, आस्थि प्रबंध कंपनी के अभिरक्षक, प्रायोजक अथवा पारस्परिक निधियों में जुड़े किसी अन्य सहयोगी संस्था में उसकी किसी भी योजना की मांग सके।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों के परिचालनों में अनियमितताएँ

1.88 यह आवश्यक है कि यहाँ बड़े सरकारी प्रगिष्ठान की हाल ही में एक ऐसी गतिविधि का उल्लेख किया जाये जिसने अत्यन्त दूरानी उन मुद्धारत्मक उपायों तथा विस्थापनात्मक परिवर्तनों को पीछ धकेल दिया है जिनको इस दृष्टि से लागू किया जा रहा है या जो लागू हैं कि वित्तीय प्रणाली को और अधिक प्रत्याशात्मक, कुशल और पारदर्शी बनाया जा सके। प्राप्त सूचना के आधार पर कि कुछ बैंक, दलालों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में बड़े पैमाने पर लेनदेन कर रहे हैं और इस लेनदेन के दौरान वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें जुलाई 1991 में जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शी निदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः 30 अगस्त, 1992 में उप गवर्नर श्री. आर. जानकीरामन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई ताकि ये समिति, बाणिज्य बैंकों और विशेष वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू. टी. आई.) की यूनिटों और इसी प्रकार के निधियों में उसके लेन-देन के परिप्रेष्य में निधि प्रबंधन में हुई अनियमितताओं की जांच कर सके। समिति ने 1 जून और 5 जुलाई 1992 को दो अंतरिम रिपोर्टें तथा तीसरी रिपोर्ट 5 अगस्त 1992 को प्रस्तुत की जिन्हें तुरंत जनता के लिए जारी कर दिया गया।

1.89 समिति के प्राथमिक निष्कर्षों से पता चलता है कि संबंधित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्य करने की प्रणाली में गम्भीर खामिया हैं तथा विभिन्न कार्यों में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण में कमी और सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों तथा यूनिटों, भावि का लेनदेन करने वाले संबंधित अधिकारियों और दलालों के बीच गहरी साठ-गांठ है। समिति ने बैंकिंग तंत्र से निधियों को कनिष्ठ दलालों के व्यक्तिगत खातों में डालने से संबंधित अपराधों की विधियों का उल्लेख भी किया है जिससे, सरकारी नजर में छोड़कर ही निधियों के दुर्धनियोजन का सबूत बनता है। निधियों के प्रबंधन संबंधी किए गए परिचालनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा मार्गदर्शी निदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है तथा उनकी धीरे-धीरे उल्लंघन की है। रिपोर्ट में उल्लेख किए गए बहुत से लेनदेन में बैंक रसीदों के जारी करने तथा रिकार्ड करने और लेनदेन को नियंत्रित हेतु किए गए

भुगतान से संबंधित शिकायतें पड़ाने के क्रमगत हो जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। समिति के सामने ऐसा उदाहरण भी आए हैं जिनमें ऐसे दिनों की शुरुआत द्वारा बैंकों ने दलानों के लिए वित्त व्यवस्था की है जो प्रामाणिक लेनदेन की पुष्टि नहीं करते। समिति ने कुछ बैंकों द्वारा वित्तियोग प्रबंधन रीढ़ों पर भा. रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के बड़े पैमाने पर उल्लंघनों का भी स्पष्टतया उल्लेख किया है। इन लेनदेनों में बैंकों और संस्थाओं द्वारा लघायी गयी कुलराशि 3,542.79 करोड़ रुपये बैठती है।

1.90 जानकारीगत समिति ने अनेक कबजों की सिफारिश की है ताकि उचित नियंत्रण प्रणाली आरम्भ की जा सके, मौनीटरींग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके और परंपरागत प्रणाली में पायी जाने वाली कमियों को धूर दिया जा सके और ऐसी प्रतिभ्याएं बनायी जाएं ताकि भविष्य में इसी प्रकार की पुनःपुनर्निर्माण होने से रोका जा सके।

1.91 पूरे प्रकरण को सामने लाने, वैधिय देनानों की चरुती करने प्रपराधी को घंड देने और निरोधात्तका उपायों को गति देने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।

1.92 किए गए उपायों में ये शामिल हैं—गत एक वर्ष के दौरान बैंकों तथा विन्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए समस्त प्रतिभूति लेनदेनो की जांच करना, बैंक और क्पाड का परिसमागत बैंक ऑफ मयुरा को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेक्षक के अंतर्गत रखना, मेट्रोपॉलिटन कोओपरेटिव बैंक के विकसित कारोबार समाप्त करने संबंधी कार्रवाई आरम्भ करना, चार द्वात्यों की अनुमोदित बैंक सूची से निकालना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का समस्त कार्य सौंपना, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की संपत्ति की धुरी करना, बैंकों तथा विन्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूति लेनदेनो से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विनिष्ट रूप से एक विशेष न्यायालय की स्थापना करना और सभी परिपक्वता वाली श्रयधि की खजानों बिलों तथा खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के वतका हाजिर बायदा सीधों पर रोका लगाने को छोड़कर दिनकित प्रतिभूतियों और अनुमोदित/भ्यासी प्रतिभूतियों के अन्तर बैंक हाजिर बायदा सीधों पर रोका लगाने सहित विशेष मार्गदर्शी निदेश जारी करना।

1.93 मार्गदर्शी निदेशों के अन्तर्गत पूर्ण पट्टा ये हैं: (1) अन्य प्रतिभूतियों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की इतेश्यों के बांडों और यूनितों में बैंकों के ब्रिच होने वाले पून। श्रय सौदों पर वर्तमान प्रतिबंध जारी रहेगा; (ii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के लेनदेन वाले सहायक सामान्य वर्हों (एसआईएल) अन्तर्गत प्रपन्न केवल उसी समय जारी किए जाएं जब भारतीय रिजर्व बैंक के लोक श्रण कायस्थि में रखे उनके सहायक सामान्य द्वाते में पर्यप्त शेष हो। पर्यप्त शेष न होने पर सहायक सामान्य अन्तर्गत प्रपन्न के सौटा दिए जाने पर बैंकों पर वण्ठात्मक कार्रवाई की जा सकेगी (iii) सरकारी ऐसी प्रतिभूतियों के लेन-देन के परिप्रेष्य में, किर्सी भी स्थिति में बैंक-रसंव आरी नहीं की जाए जिनके लिए सहायक सामान्य वर्ह-सुविधा उपलब्ध है। केवल तैयार लेनदेनो के लिए अन्य प्रतिभूतियों के मामले में हूं बैंक रसंव जारी की जाए और वह भी असाधारण परिस्थितियों में और (4) संविधानीय प्रबंधन योजना ग्राहकों या दलानों समेत अन्य घटकों से सम्बन्धित लेनदेनो वाले मामलों में बैंक रसंव आरी नहीं की जानी चाहिए।

1.94 रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों और पारस्परिक निधियों के यूनितों के कारोबार से संबंधित समिति (अध्यक्ष: एम.एम. साइकर्णी) ने जानकारीगत समिति के अनुवर्तन के रूप में 8 अगस्त 1992 का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बा है जो कि विचारार्थन है।

1.95 प्रतिभूतियों से संबंधित अनियमितताओं से जुड़े सभी प्रश्नों को समय रूप में जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनो के मार्गनय

सदस्यों की लेकर एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (सं सं स.) गठित की गई है।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था — कार्य-निष्पादन और समस्याएं

1. व्यापक आर्थिक दृश्य

2.1 कतिपय गम्भीर व्यापक-आर्थिक असंतुलनो सहित अर्थव्यवस्था के एक दशक के बाव, राशकॉय दप 1991-92 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित धीमापन आया। वास्तविक सकल देशी उत्पाद 2.0 प्रतिशत से बढ़ी कम होने की आशा है जो 1980-81 के बाव सब से कम है, तथा इसमें 1990-91 के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1980-81 से 1990-91 के दशक की 8.5 प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है (सारणी 2.1)। इस कम वृद्धि का प्रमुख कारण 1979-80 के बाव पहली बार अर्थव्यवस्था के विकास का आना है, कृषि उत्पादन में भी लगभग 1.0 प्रतिशत का गिरावट आने की सम्भावना है।

सारणी: 2.1 वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि

(प्रतिशत वार्षिक)

क्षेत्र	(1980-81 से 1990-91)	सालों के पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-88 से 1989-90)	1990-91	1991-92
1. कृषि	3.5	5.3	4.3	--
2. विनिर्माण	7.0	7.5	7.3	--
3. सेवाएं	6.4	6.9	5.8	--
कुल-राष्ट्रीय देशी उत्पाद	5.5	6.4	5.8	2.0*

*सा.रि.बैं. के अनुमान

2.2 देशी वस्तु और निर्यात संघर्ष व्यापक परिदृश्य में भी गंदी और कुछ अनिश्चितता रही। सकल देशी उत्पाद अनुपात के परिप्रेष्य में देशी वस्तु जो 1989-90 में 22.7 प्रतिशत से गिरकर 1990-91 में 22.2 प्रतिशत रह गई थी, 1991-92 के दौरान इसके अस्थायी रूप से 23.2 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने का अनुमान है। इसके साथ ही, बायात कम करने के लिए किए गए कड़े उपायों से भुगतान संतुलन संबंधी चालू खाता घाटे में अस्थायिक घर्माहू हुई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990-91 के 14,684 करोड़ रुपये घिदेशों सेतों का अनुमानित निवल आगम घटकर 1991-92 में 8,042 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है या सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 2.8 प्रतिशत (1.3 प्रतिशत)। परिणामस्वरूप, सकल देशी निर्यात का अनुपात वर्ष 1990-91 के अनुमानतः 24.8 प्रतिशत से घटकर 1991-92 के दौरान 24.1 प्रतिशत रह जाएगा। (सारणी 2.2) और परिशिष्ट सारणी (II.2)।

सारणी : 2.2 बाँत और निवेश अनुपात

(प्रतिशत में)

वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल/निवल देश उत्पाद का अनुपात	1989-90	1990-91	1991-92*
1. सकल देश बाँत	22.7	22.2	23.2
2. कुल-सकल निवेश	25.2	24.8	24.1
3. निवल देश बाँत	13.6	13.4	14.3
4. निवल सकल निवेश	16.4	16.3	15.3
कुल			

* अंतिम

2.3 सकल देशी घरेलू के अंतर्गत आने वाले सभी तीनों श्रेणियों, अर्थात् घरेलू, निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र में गुधार परिलक्षित हुआ। घरेलू क्षेत्र के मामले में नहीं सकल वित्तीय आस्थितियों के अनुपात में 1990-91 के 11.1 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में 11.4 प्रतिशत तक मामूली वृद्धि दर्ज की गई, वहीं घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देवताओं में बैंक उधारियों और संभवतः घटी हुई निवेश गतिविधियों के कारण बहुत अधिक गिरावट आयी। इसी के परिणामस्वरूप, घरेलू वित्तीय स्थिति (निवल) में असमानुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई अर्थात् 9.8 प्रतिशत की तुलना में 10.8 प्रतिशत।

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

कृषि :

2.4 पिछले तीन वर्षों में कृषि उत्पादन में जो लगातार वृद्धि परिलक्षित होती रही वह वर्ष 1991-92 के दौरान नहीं रही। इसका प्रमुख कारण मानसून का देरी से आना और सभी खानों पर समान रूप से न रहना था। कृषि पैदावार के प्राथमिक भाँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि समग्र दृष्टि से उसमें 1991-92 में लगभग 1.0 प्रतिशत की कमी हुई।

2.5 वर्ष 1991 में खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन पिछले खरीफ मौसम के 103.2 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य तथा 99.9 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 94.2 मिलियन टन पर कम रहने का अनुमान लगाया गया है। रबी उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के बावजूद 74.8-76.3 मिलियन टन उत्पाद होने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष के 76.3 मिलियन टन के उत्पादन से न्यूनतम समान स्तर पर है। विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के बावजूद भी खानों के उत्पादन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, क्योंकि पैदावार क्षेत्रों में जल की समस्या रही। अतः वर्ष 1991-92 में खाद्यान्न के उत्पादन स्तर पिछले वर्ष के 176.2 मिलियन टन की तुलना में 169.0-170.5 मिलियन टन रहा। (परिशिष्ट सारणी II.3)।

2.6 अन्य फसलों में, गन्ना और जूट/सेस्ता के उत्पादन में पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 98 लाख गांठों के स्तर पर रहा जबकि तिलहन के उत्पादन में 2.7 लाख टन की कमी हुई। (परिशिष्ट सारणी II.4) कृषि उत्पादन में आई अत्यधिक गिरावट से कृषि पण्यों के मूल्यों में वृद्धि हुई और इससे बाजारगत अपेक्षाओं को प्रभावित किया।

खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, निकासी और वण्जार

2.8 खाद्यान्नों की पैदावार में आयी गिरावट के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा की गई खाद्यान्नों की सरकारी खरीद में वर्ष 1991-92 में 23.4 प्रतिशत से 18.3 मिलियन टन तक की

गिरावट आयी। तथापि, खाद्यान्नों की निकासी पिछले वर्ष के 16.1 मिलियन टन की तुलना में बढ़कर 19.0 मिलियन टन हो गयी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के मूल्यों में काफी अंतर होने की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए की गई आपूर्ति को दर्शाता है।

2.9 मार्च 1992 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डार एक वर्ष पहले के 17.3 मिलियन टन और मार्च के अंत तक के लिए 14.5 मिलियन टन के निर्धारित सुरक्षित स्टॉक मानक की तुलना में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 12.1 मिलियन टन का था। गृह के स्टॉक में विशेष रूप में तेजी से गिरावट आयी। (परिशिष्ट सारणी II.5)। पिछले कम स्टॉक को देखते हुए उसमें आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी ताकि कृषि पण्यों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके।

औद्योगिक उत्पादन

2.10 वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में आंशिक गिरावट रही। ऐसी स्थिति ग्यारह वर्ष पूर्व वर्ष 1979-80 में देखी गई थी। अस्सी के दशक में आर्थिक औद्योगिक वृद्धि उच्च अर्थात् 7.8 प्रतिशत पर रही। मानवीय योजना अवधि के दौरान, यह 8.4 प्रतिशत तक बढ़कर और भी अधिक रही। तथापि, वर्ष 1990-91 के उभराव में उत्पादन कम होने लगा और अंततः वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (परिशिष्ट सारणी II.6)।

2.11 वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में निम्नतर कार्य निष्पादन का विशेष कारण विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में पिछले वर्ष की 9.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.4 प्रतिशत की कमी का होना था। खनन और उत्खनन में भी पिछले वर्ष की 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.8 की आंशिक निम्नतर वृद्धि दर्ज की गयी। उत्पादन में वर्ष 1990-91 की 7.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष की तुलनीय अवधि में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.12 औद्योगिक उत्पादन के गत्यावरोधों में कई एक घटकों का योगदान रहा। अर्थात् संकुचन उपायों और आयात लागतों में वृद्धि ने न केवल आयात-समन उद्योगों को बल्कि निर्यातमुख और अन्य उद्योगों को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया; निर्यातों में कम वृद्धि और विशेष रूप से, रपया भुगतान क्षेत्रों के निर्यात में, ऋण की लागत में वृद्धि, माय ही, ऋण उपलब्धता की सीमाएं; अन्य शक्ति का ह्रास और उच्च मूल्यों के लिए उपभोक्ता प्रतिरोध; और सबसे महत्वपूर्ण, सार्वजनिक निवेश में गिरावट के कारण पूंजीगत वस्तुएं, विशेषकर और सामान्य रूप से अर्ध-निर्मित वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की श्रृंखला का प्रभावित होना था। इन सभी व्यापक घटकों के बावजूद कुछ एक उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी रही। खास पदार्थों के विनिर्माण उद्योगों और कृषि कच्चे भाग पर आधारित उद्योगों में सामान्यतया सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई, भले ही यह वृद्धि तेज गति से नहीं हुई। दूसरे, आधारभूत उद्योगों में कच्चे तेल और तेल से बनी वस्तुओं की छोड़कर उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

विनिर्माण क्षेत्र

2.13 विनिर्माण के क्षेत्र में, सर्वप्रमुख औद्योगिक समूहों के उपलब्ध भाँकड़े यह संकेत करते हैं कि सात समूहों ने 47.75 प्रतिशत भारों के साथ सकारात्मक वृद्धि दर्शायी, जबकि पिछले वर्ष 14 समूहों में 71.39 प्रतिशत भारों सहित सकारात्मक वृद्धि हुई। इन 7 समूहों में से वर्ष 1991-92 में केवल दो समूहों (जैसे पेट्रोल पदार्थ, समरक और हथवाक से बनी वस्तुओं और गैर-धार्मिक वस्तुएं)

उत्पाद) में 4.57 प्रतिशत भारांक के साथ वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1990-91 से 8 समूहों में 45.75 भारांक सहित वृद्धि हुई थी। (परिशिष्ट सारणी II.7) भोग दस औद्योगिक समूहों में, जिनमें नकारात्मक वृद्धि दर देखने में आई, बिजली मशीनरी समूह में अत्यधिक गिरावट (-10.3 प्रतिशत) आयी। इसके बावजूद अन्य समूह थे—धातु उत्पाद (-7.6 प्रतिशत), खमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं (-7.0 प्रतिशत), लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं (-6.7 प्रतिशत), वस्त्र उत्पाद (-3.7 प्रतिशत), जूत, हेमप मशीनरी और मशीन-औजार (-2.5 प्रतिशत), और रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम पदार्थ (-1.2 प्रतिशत) काफी हद तक संकुचन आयात और आयातों में वृद्धि बिजली की वस्तुएं, परिष्कृत उपकरण आदि आयात-समन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट से परिलक्षित होता है। यह उपभोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर उत्पादन की प्रवृत्तियों से भी स्पष्ट होता है। (परिशिष्ट सारणी II.8)। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के बिकाऊ उपभोक्ता जो मूलतया 'गृह वस्तु' उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, ने अप्रैल-जनवरी 1991-92 के दौरान 12.5 प्रतिशत की गिरावट रिकार्ड की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इसमें 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। साथ ही, आयात संकुचन उपाय, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण पर प्रतिबंध ने भी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव डाला।

2.14 इसी प्रकार, 1992 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी तेजी से गिरावट आई जो कि 12.8 प्रतिशत रही (परिशिष्ट सारणी II.8)। राजकोषीय ऋणरोध और सार्वजनिक निवेश में गिरावट ने पूंजीगत वस्तुओं की मांग को विपरीत रूप से प्रभावित किया जिसके लिए प्रमुख क्रेता सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र है।

2.15. आधारभूत उद्योग —जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, आधारभूत उद्योगों का कार्य-निष्पादन वित्तीय वर्ष 1991-92 में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा, जो प्राप्ति घटकों की निहित शक्ति को दर्शाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान आधारभूत उद्योगों में

सम्मिश्रण सूचकांक में वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत रही जो कि पिछले वर्ष की (4.8 प्रतिशत) दर से अधिक रही। (परिशिष्ट सारणी II.9)। आधारभूत उद्योगों में, पेट्रोलियम क्षेत्र—कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद दोनों को छोड़कर—सभी उद्योग बिजली, कोयला, इस्पात और सीमेंट ने 1990-91 की तुलना में अधिक वृद्धि दिखाई। तथापि कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वर्ष 1991-92 के दौरान 8.1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आयी जबकि पिछले वर्ष में यह गिरावट 3.1 प्रतिशत थी। पेट्रोलियम (घन) शोधक उत्पाद के उत्पादन में भी मामूली सी गिरावट आई जो पिछले वर्ष की 0.3 प्रतिशत की तुलना में 0.7 प्रतिशत थी।

III सरकारी वित्त

3.1 राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया: — 1991-92 के दौरान शुरू किये गये स्थिरीकरण उपायों का प्रमुख पहलू राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया से जुड़ा है। 1991-92 के लिए केन्द्रीय बजट में इसकी प्राप्ति के लिए घनेक उपाय किये गये जिनमें कर और सूचके के हावों को सुविनसंगत बनाना तथा सकल राजकोषीय घाटे को कम करना शामिल था। इस प्रक्रिया को 1992-93 के केन्द्र सरकार के बजट में और बढ़ाया गया और राजकोषीय समेकन की दिशा में उल्लेखनीय बल दिया गया ताकि उठे मध्यावधि में प्राप्त कर लिया जाए।

3.2 केन्द्र का बजट घाटा—1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार की समग्र बजटीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ जो घाटे के विभिन्न उपायों में किये गये कर्मियों से प्रदर्शित होता है। (परिशिष्ट सारणी III.1)। सकल राजकोषीय घाटा 1990-91 के 44,650 करोड़ रुपये से कम करके 1991-92 में 37,792 करोड़ रुपये तक ले आया गया। सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 1991-92 में लगभग 6.5 प्रतिशत रहा था, जबकि इसके पहले वर्ष में यह 8.4 प्रतिशत था। प्राथमिक घाटा भी 1991-92 में 21,839 करोड़ रुपये (अथवा सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत) तक काफी कम किया गया जबकि इसके पहले वर्ष यह 31,909 करोड़ रुपये (6.0 प्रतिशत) था। (सारणी 3.1)।

सारणी 3.1 : घाटे के उपाय : केन्द्र सरकार का मीट्रीकरण, बजट, सकल और निवल राजकोषीय घाटा

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	मुद्राकृत घाटा	परंपरागत घाटा	राजस्व घाटा	(करोड़ रुपये)
							बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद
1989-90	35,632	23,722	26,349	13,813	10,592	11,914	4,60,801\$
1990-91	44,650	30,710	31,909	14,746	11,347	18,562	5,29,537\$
1991-92 (सं. प्र.)	37,792	26,126	21,839	5,508††	7,032†	17,081	6,19,000*
1992-93 (ब.प्र.)	34,408	23,940	15,872	5,389	5,389	13,882	7,00,000@
बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
1989-90	7.91	5.26	5.85	3.07	2.35	2.64	
1990-91	8.43	5.80	6.03	2.78	2.14	3.51	
1991-92	6.50**	4.22	3.53	0.89	1.14	2.76	
1992-93	5.00	3.42	2.27	0.77	0.77	1.98	

†† भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार वास्तविक
द्विवर्तित अनुमान

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान
@ कच्चे अनुमान

बजट वस्तावेज के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकारों खातों की बन्वी के बाद यह घाटा 6,492 करोड़ रुपये था।

** 0.66 तथा अन्य लेनदेनों सहित

टिप्पणी : परिभाषाओं के लिए परिशिष्ट सारणी III.1 देखें।

3.3 उहाँ सकल राजकोपीय घाटे में कमी राजकोपीय सुधार के समर्थित इच्छा से वास्तविक घाटा 13,854 करोड़ रुपये के बजटीय स्तर से बढ़कर 17,081 करोड़ रुपये तक पहुँच गया जैसा कि 1991-92 के संशोधित अनुमानों में उल्लेख किया गया। राजस्व खाते में कमी इस स्तर के काफी अधिक बढ़ गयी जिसका कि पूँजीगत खाते में अधिशेष में वृद्धि। यह अधिशेष 6,135 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,049 करोड़ रुपये हो गया था। इसके परिणामस्वरूप परंपरागत बजट घाटा 7,032 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) पर रहा अथवा भा.रि. बैंक के रिकार्ड के अनुसार 6,492 करोड़ रुपये (अंतिम लेखा) पर रहा, जबकि पहले 7,719 करोड़ रुपये का बजट में अनुमान लगाया गया था। इस स्तर पर यह घाटा 1990-91 के दौरान 11,347 करोड़ रुपये के वार्षिक घाटे की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। केन्द्रीय सरकार को निम्न भारतीय निर्यात बैंक अधिनियम जो कि बजटीय क्रियाकलापों का मौलिक प्रभाव धरता है (मुद्रांकन घाटा) भी 1990-91 के 14,746 करोड़ रुपये के भारी समर्थन के मुकाबले 1991-92 में 5,508 करोड़ रुपये के निम्न स्तर पर रहा। अर्थात् वर्ष के अंत के ये धाँकड़े वास्तविक नहीं हैं क्योंकि घाटे की प्रवृत्ति लगातार पूरे वर्ष अनुचित रूप में बढ़ती रही। हालाँकि इसके बाद वर्ष के अंत में उसमें कमी आयी। यह 1991-92 में और भी बढ़ती आयी, यह प्रवृत्ति पाश्चात्त्य आंकड़ों से झलकती है जो यह दर्शाते हैं कि 1991-92 के दौरान औसत मुद्रांकन घाटा 10,209 करोड़ रुपये का था जबकि 1990-91 में यह 10,336 करोड़ रुपये का था। चरमोक्ति की वृद्धि पर काफी प्रभाव रखने के कारण यह औसत मुद्रांकन घाटा रहा जिसे और भी कम किया जाता है। (परिशिष्ट सारणी III.2)।

3.4 1991-92 के दौरान सकल राजकोपीय घाटे के वित्तीय स्वरूप यह दर्शाते हैं कि विदेशी उधारों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है जो कि पिछले वर्षों के दौरान देखी गयी हमारी प्रवृत्ति से काफी हटकर है, बाह्य बिल का अंश जो 1980-81 के 15.4 प्रतिशत से गिरकर 1990-91 में 7.1 प्रतिशत पर आ गया था, 1991-92 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 13.4 प्रतिशत पर पहुँच गया। परिणामस्वरूप आंतरिक बिल का अंश इसी अवधि में 92.9 प्रतिशत से गिरकर 86.6 प्रतिशत रह गया। सकल राजकोपीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार से उधार का अंश 1980 के प्रारंभिक दशक के एक तिहाई से गिरकर 1991-92 में 1/5 वें भाग से कम रह गया। अन्य देयताएँ, जिनमें भ्रष्टाचार, अव्यय निधि, विशेष जमा आदि शामिल हैं, घाटे के घाटे से कम रहती हैं जबकि 1980-81 में ये 1/4 से कुछ कम थी। (परिशिष्ट सारणी III.3 और III.4)।

3.5 राजस्व खाते में निगम कर और घाय कर (निवल) तथा अन्तराष्ट्रीय कच्चे तेल से रायल्टी से प्राप्तियाँ बजट में अनुमानित प्राप्तिओं से उच्च थीं। खजाना बिलों की भुनाई से संबंध में व्याज के भुगतान में कमी आयी। ये अनुकूल परिणाम उससे कहीं ज्यादा रहे जो सीमा शुल्क की उपाही में आयी 3,005 करोड़ रुपये की भारी कमी, निवल उत्पाद शुल्क में आयी मामूली-सी गिरावट, आर्थिक सहायता (सम्पत्ति) में 1,895 करोड़ रुपये की वृद्धि, राज्यों की अनुदान राशियों में उच्चतर वृद्धि तथा रक्षा पर राजस्व खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप आई। राजस्व खाते में विगड़ती हुई स्थिति को सुधारने की वृद्धि से और इस प्रकार सकल राजकोपीय घाटे की भारी मात्रा को रोकने के लिए पूँजीगत संचितरणों को कम करके 2,567 करोड़ रुपये तक लाता पड़ा जो वास्तव में 96 करोड़ रुपये के सकल संचितरणों की कमी दर्शाते हैं। दूसरी ओर पूँजीगत प्राप्तिओं उच्चतर बाह्य उधारों (निवल) तथा ऋणों की वसूली एवं 182 दिवसीय खजाना बिलों की निवल बिक्री से जुटाये गये 2,000 करोड़ रुपये के फलस्वरूप बजटीय अनुमानों से अधिक बढ़ गयीं; परंतु यह काफी सीमा तक घल्प बचतों की उपाही में 1,600 करोड़ रुपये की गिरावट के कारण प्रति संतुलित हो गया। इस प्रकार पूँजीगत प्राप्तिओं में उल्लेखनीय वृद्धि बजट में अनुमानित कुल प्राप्तिओं से 591 करोड़ रुपये अधिक रही।

3.6 उहाँ तक भुगतानों का संबंध है, कठोर व्यय नियंत्रण लागू करने के फलस्वरूप योजनेतर व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 373 करोड़ रुपये मात्र की मामूली-सी वृद्धि हुई। दूसरी ओर योजना खर्च में गिरावट आयी और संशोधित अनुमानों में यह 2.1 प्रतिशत कम रहा। योजनेतर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि सविसिधियों के कारण हुई जो बजट अनुमान में दी गयी 10,395 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,290 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। उधारों की सविसिधियों 4,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,800 करोड़ रुपये पर पहुँच गयी जिसका कारण था वास्तविक मूल्यों में वृद्धि को 30 प्रतिशत तक रोकने रखना जबकि बजटीय अनुमानों में औसत 40 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इस वृद्धि का एक और भी कारण था कि उधारों के प्राप्ति की खपत लागत में वृद्धि हुई। छोटे और सीमांत किसानों की मूल्य वृद्धि से छूट देने के कारण संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रायधान करना पड़ा। खाद्य सविसिधियों में 250 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई हालाँकि दिसंबर 1991 में चावल और रोहू के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गयी थी। इसके अतिरिक्त नकदी प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अवशिष्टीय दावों को निपटाने के लिए नियत सविसिधियों के संबंध में 550 करोड़ रुपये का उच्चतर प्रायधान भी करना पड़ा था।

3.7 1992-93 के लिए बजट: राजकोपीय घाटे में और कमी के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में भी बल दिये जाने की आवश्यकता जारी रही। इस प्रकार बजट में 5,389 करोड़ रुपये का परंपरागत बजट घाटा रखा गया जबकि 1991-92 में 7,032 करोड़ रुपये का (संशोधित अनुमान) बजट घाटा रखा गया था। राजस्व घाटा निरंतर से अंतराल को दिखाता रहेगा हालाँकि यह 13,882 करोड़ रुपये की घल्प मात्रा में हुआ जो कि 1991-92 में 17,081 करोड़ रुपये का था। (देखें परिशिष्ट सारणी III.5)। सकल राजकोपीय घाटा 1992-93 में बढ़कर 34,408 करोड़ रुपये पर आ जाने की आशा है जो 1991-92 के लिए संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 3,384 करोड़ रुपये की कमी अथवा सकल देशी उत्पाद के 6.5 प्रतिशत से कम होकर 5.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

3.8 राजकोपीय घाट में देखी गयी यह कमी कुछ उपायों की संपर्कित करके प्राप्त किये जाने की कल्पना की गयी है जैसे योजनेतर खर्च के व्यापक घटकों में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ईकित्ती धारिताओं का और अनिवार्य, अतिरिक्त मंजूरी भत्ते के भुगतान के लिए जो 1992-93 में देय होगा, प्रायधान न किया जाता। योजनेतर खर्च को सीमित रखने के लिए किये जाने वाले कुछ विशिष्ट आर्थिक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रमुख सविसिधियों में 1,849 करोड़ रुपये की सीमा तक कमी लाना, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को योजनेतर अनुदानों में कटौती, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विदेशी सरकारों को दिये जाने वाले योजनेतर ऋणों में कटौती तथा रक्षा खर्च में 7 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि। इसके अलावा योजनेतर व्यापक खर्च में कटौती से योजना व्यय 1991-92 के 13.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 4.8 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि दर्शाया।

3.9 केन्द्र का योजना परियोजना: आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1992 से शुरू हो गयी है, में उल्लिखित उद्देश्यों और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का योजना परियोजना 1992-93 के लिए 48,407 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है जो 1991-92 के लिए 40,172 करोड़ रुपये के संशोधित परियोजना के ऊपर 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। योजना के लिए बजटीय समर्थन 1991-92 के 17,671 करोड़ रुपये के मुकाबले 1992-93 में 18,501 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर अनुमानित है। तथापि कुल विल में इसका भाग 1991-92 के 44 प्रतिशत से गिरकर 38.2 प्रतिशत होगा।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक और अनिश्चित बजट संबंधी संसाधनों का अंशदान 1991-92 के 22,501 करोड़ रुपये से बढ़कर 1992-93 में 29,908 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो 32.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इनके परिणामस्वरूप, कुल वित्त में आंतरिक और अनिश्चित बजट संबंधी संसाधनों का अंश 1991-92 के 56 प्रतिशत से बढ़ कर 1992-93 में 61.8 प्रतिशत होगा।

3.10 योजनागत और योजनांतर व्यय: 1992-93 के बजट ने वर्ष के दौरान योजनागत व्यय को 34,612 (4.8 प्रतिशत की वृद्धि) करोड़ रुपये पर निर्धारित किया था, जबकि यह 1991-92 में 33,032 करोड़ रुपये का था। 1992-93 के दौरान योजना व्यय के अंतर्गत राजस्व और पूंजीगत घटक कुल व्यय का क्रमशः 53 प्रतिशत और 47 प्रतिशत होगा, जबकि ये 1991-92 में क्रमशः 51.3 प्रतिशत और 48.7 प्रतिशत थे। राजस्व व्यय का बढ़ता हुआ अंश इसका संकेत करता है कि नई भास्त्रियों भुजन के लिए उपलब्ध परिमाण को कम करने हुए, योजनागत व्यय का प्रमुख भाग व्यय के चालू मदों के लिए किया जाएगा। कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश 1991-92 के 29.2 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित बने रहने की संभावना है।

3.11 राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने की नीति के एक भाग के रूप में 1992-93 के लिए बजट ने समग्र व्यय के नियंत्रण, विशेषकर योजनांतर व्यय के व्याज-रहित घटकों पर जोर दिया। 1992-93 में 84,475 करोड़ रुपये पर अनुमानित कुल योजनांतर व्यय 1991-92 के 80,070 करोड़ रुपये के ऊपर 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। योजनांतर व्यय के विभिन्न घटकों में, व्याज भुगतान व्यय में वृद्धि का एक बड़ा अंश होगा क्योंकि केंद्र सरकार की बढ़ती हुई आय का प्रमुख अंश इनके भुगतान में ही खर्च किया जा रहा है। 32,000 करोड़ रुपये के कुल व्याज भुगतान में 17.4 प्रतिशत (अथवा 4,750 करोड़ रुपये) की वृद्धि होगी जो 1991-92 के 26.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि से और अधिक होगी। वास्तव में, व्याज भुगतानों को छोड़कर योजनांतर व्यय की अन्य मदों में 345 करोड़ रुपये की गिरावट आयगी। निवृत्त व्याज भुगतानों को व्याज प्राप्तियों से समायोजित करने के बाद, वे 1991-93 के 25.2 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 में 16.2 प्रतिशत की अपर वृद्धि को दर्शाएंगे। रक्षा व्यय में 1991-92 के 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 17,500 करोड़ रुपये पर 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया ने सवित्तियों पर व्यय में आवश्यक रूप में अधिक कटौती की, जो 1991-92 के 12,290 करोड़ रुपये की तुलना में 1992-93 में कुछ कम अर्थात् 10,487 करोड़ रुपये ही रह जाएगी।

3.12 कर-सुधार और अन्य उपायों पर चेलेय्या समिति :--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली, दोनों में व्यापक सुधार की आवश्यकता को अनुभव करते हुए बजट में कर-सुधार पर चेलेय्या समिति को कुछ सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया। व्यक्तिगत आय-कर को पुनः रचना के प्रस्तावों में कर छूट की सीमा को 28,000/- रुपये तक बढ़ाना, आय-कर दर स्तरों की संख्या को कम करना और 20 प्रतिशत की प्रारंभिक दर तथा 40 प्रतिशत की अधिकतम कम दर से कर-दरों को कम करना आदि शामिल हैं। कर-दरों में छूट को ध्यान में रख कर, बजट ने धारा 80 सोसोए (राष्ट्रीय बचत योजना), 80 सोसोबी (ईनिशियल पंचवर्ष बचा योजना) और 80 एल (मानव्य प्रतिभूतियों, जमापारियों, भा.यू.ड्र. के युक्तियों आदि पर व्याज से प्राप्त आय) के अंतर्गत उपलब्ध कटौतियों का शेष लेने की घोषणा की। धारा 88, जिसमें विनिर्दिष्ट बचतों के संबंध में कर-छूट की व्यवस्था है, के बावरे को राष्ट्रीय आवास बैंक और म्युचुअल फंड द्वारा गठित पेंशन निधियों के अंशदान को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल करते हुए व्यापक बनाया

गया। छोटे सुदरा व्यापारियों, जिनकी कुल वित्ती 5 लाख रुपये या अधिक से कम है, को कर की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए सुकायदारी के संबंध में एक अनुमानित-कर आरंभ किया गया। बजट में पूंजीगत काम कर और संपत्ति कर से संबंधित वर्तमान प्रणाली को सुकायुक्त बनाने पुनः संरचना के लिए भी प्रस्ताव है। पूंजीगत लाभों के संबंध में बजट का प्रस्ताव है कि कर-योग्य पूंजीगत लाभों की गणना कुल वित्ती में से मुद्रा स्थिति के समायोजन हेतु भास्त्रियों की अधिग्रहण लागत को घटाने के बाद की जायगी। संपत्ति कर के संबंध में, उत्पादक और अनुसादक भास्त्रियों के बीच विभेदीकरण किया गया और यह प्रस्ताव किया गया कि उत्पादक भास्त्रियों (वैक जमापारियों, शेयर प्रतिभूतियों, बांड आदि) को कर की परिधि से मुक्त रखा जाए तथा आवास बचतों, शहरी भूमि, गहनों, बुनियादी जैसी अनुसादक भास्त्रियों पर 15 लाख रुपये की छूट-सीमा से अधिक मूल्य के लिए 1 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाए। कर मापलों से संबंधित मुकदमों का सीझना में निपटान सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय' गठित करने की सरकार के उद्देश्य की घोषणा की।

3.13 उत्पाद शुल्कों के क्षेत्र में कर-संग्रहण और निपटान की प्रणाली में बिंत्र को दूर करने के लिए क्रिया-विधियों, नियम और विनियमों को सुकियुक्त तथा सरल बनाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। बजट ने यथासंभव विनिर्दिष्ट दरों से मूल्यानुसार दर प्रणाली में अंतरित होने का प्रस्ताव रखा ताकि मूल्यां में वृद्धि के कारण राजस्व में अधिक उछाल को सुनिश्चित किया जा सके। सीमा शुल्कों के क्षेत्र में टैरिफ के अत्यधिक स्तर को वर्तमान 150 प्रतिशत से कुछ अपवादों के साथ घटा कर 110 प्रतिशत कर दिया गया। सहायक आयात शुल्क के संबंध में शुल्क स्तरों की संख्या को कम कर दिया गया। मुनिवा पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित टैरिफ दरों को 80 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत कर दिया। पेट्रो-रसायन उद्योग के लिए विभिन्न कच्चे माल के आयातों पर 25 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की सीमा के बीच शुल्क लगाया जाएगा।

3.14 अनिश्चित कराधान उपायों से प्राप्त निवृत्त राजस्व लाभ को सारणी 3.2 में दर्शाया गया है।

सारणी : 3.2 अनिश्चित कराधान से राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

कर शीर्ष	बजट प्रस्ताव	राज्यों की भागीदारी	केन्द्र को निवृत्त
I. मूल बजट			
क. प्रत्यक्ष कर (क) + (ख) + (ग)	795	435	360
(क) निगम कर	325	—	325
(ख) आय कर	570	435	135
(ग) व्यय कर	-100	—	-100
ख. अप्रत्यक्ष (क) + (ख)	188	1,065	-877
(क) सीमा शुल्क	-2,023	—	325
(ख) संघ उत्पाद शुल्क	2,211	1,065	1,146
ग. योग (क + ख)	983	1,500	-517
II. बजटोपरीत रियायतों के बाव			
घ. द्वितीय बजटोपरीत कर-रियायतें			
(क + ख)	-847	-271	-576
(क) 26 मार्च 1992 की स्थिति के अनुसार	-245	—	-245
(ख) 30 अप्रैल 1992 की स्थिति के अनुसार	-602	-271	-331
ड. कुल राजस्व प्राप्ति (ग + घ)	136	1,229	-1,093

3.15 बजट प्रस्तुतीकरण के बाद वित्त मंत्री ने बजटोपरांत दो चरणों में कर रियायतों की घोषणा की जिनमें ये शामिल हैं: (i) परियोजना आयों और सामान्य सजीनरी पर आयदात शुल्क में प्रतिरिक्त कमी, (ii) 13,000 रुपये की पूर्ववर्ती सीमा को कम करके 7,000 रुपये की सीमा सहित धारा 80 एन के अंतर्गत कटौती की प्रांशिक रूप से बहाली, (iii) इन्विस्टी प्राधारित बचत योजना के संबंध में 2000 रुपये की उप सीमा सहित धारा 88 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कर छूट में 12,000 रुपये की वृद्धि, (iv) अनुमानित करों के अंश (v) पूंजीगत आयों पर कर की दर में कमी, और (vi) स्वर्ण पर आयदात शुल्क में प्रति दस ग्राम पर 450 रुपये से कम करके 220 रुपये प्रति दस ग्राम कर देना। इन रियायतों के परिणामस्वरूप, कुल 847 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की संभावना है जिसमें से 576 करोड़ रुपये की भरपाई केन्द्र और शेष की राज्य करेगा।

3.16 अन्य उल्लेखनीय गतिविधि है जो विदेशी मुद्रा में प्रवृद्ध लेनदेन की संभावना को और कम करने के उद्देश्य से 1 जून, 1992 से प्रभावी विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर की समाप्ति से संबंधित है। 1992-93 के बजट अनुमानों के अनुसार इस कर से 88 करोड़ रुपये उगाहने की अपेक्षा की गयी है।

3.17 19 जून, 1992 को कुछ और कर रियायतों की घोषणा की गयी जिसके अनुसार मोटरकार, हल्के वाणिज्यिक वाहन, टेलीवीजन सेट, थोक बर्बाद और दवाओं के लिए प्रथम तैयार सदों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी की गयी। यद्यपि इन रियायतों से पूरे वित्त वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की और हानि होगी फिर भी इन हानि के अधिकांश भाग की प्रतिपूर्ति विन्नी और माल के आयों पर और अधिक राजस्व की बसूली करके की जाएगी।

राज्यों के बजट 1992-93

3.18 25 राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति, जिसमें से नौ राज्यों ने मार्च 1992 में लेखा-अनुदान बजट प्रस्तुत किए से यह संकेत मिलता है कि 1991-92 के काराधना की वरों पर वर्ष 1990-91 (लेखा) में 70.3 करोड़ रुपये का प्रविशेष 1991-92 (सं. अनु.) में 1,667.1 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में वर्ष 1992-93 में 2225.3 करोड़ रुपये का कुल घाटा होगा। 13 राज्यों द्वारा 627.6 करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गयी है, जबकि 1991-92 में 15 राज्यों द्वारा 967.8 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए गए थे। वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट में, केन्द्र के नये कर प्रस्तावों में राज्यों की भागीदारी 1,500 करोड़* रुपये मानी गयी। राज्यों द्वारा जुटाये गये प्रतिरिक्त संसाधनों से प्राप्त राजस्व को समायोजित करने के बाद और केन्द्रीय करों में उनकी भागीदारी जिसकी मूल राशि 2127.6 करोड़ रुपये होती है, के बाद सभी राज्यों की 1992-93 की समेकित बजटीय स्थिति 97.7 करोड़ रुपये के कम घाटे वशीएगी जबकि 1991-92 (सं. अनु.) में इसमें 1,667.1 करोड़ रुपये का घाटा था।

3.19 राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 1980-81 के 3,712 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 1986-87 में 9,269 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तत्पश्चात्, वृद्धि में काफी तेजी आयी और 1987-88 के घाटा 11,219 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 18,815 करोड़ रुपये का हो गया और 1991-92 के लिए संशोधित अनुमानों में और अधिक, अर्थात् 20,219 करोड़ रुपये का आंका गया। 1992-93 के बजट अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा और बढ़कर 20,968 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि 3.7 प्रतिशत थी। राज्यों के बढ़ते हुए समय संसाधनों के अन्तराल के परिणामस्वरूप, राजस्व लेखा की स्थिति विगड़ती गयी जो कि 1987-88 से ही उच्च रही थी। वर्ष 1992-93 के बजट में संयुक्त राजस्व घाटा 3,669 करोड़ रुपये था 1991-92 (संशोधित

अनुमान) में 5,344 करोड़ रुपये संयुक्त राजस्व घाटे से काफी कम रहा। वर्ष 1991-92 में सकल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा 26.4 प्रतिशत वृद्धि है जबकि 1992-93 में वजटीय राजस्व घाटा 17.5 प्रतिशत आंका गया। सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत अर्थात् 1990-91 के 3.6 प्रतिशत की तुलना में प्रांशिक रूप से कम रहा। ऐसी संभावना है कि 1992-93 में यह और गिरकर 3.0 प्रतिशत रह जायेगी (परिशिष्ट सारणी III.6)।

3.20 राज्यों के संसाधनागम अंतराल के वित्तपोषण के स्वरूप से पता चलता है कि अंतराल का औसतन आधा भाग केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करके और शेष को बाजार से उधार लेकर राज्य अधिध निधियों और अन्य प्रकार की निधियों से पूरा किया गया (परिशिष्ट सारणी III.7)।

भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्धोपाय अधिम और राज्यों के ओवरड्राफ्ट

3.21 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 राज्यों के लिए सामान्य अर्धोपाय अधिमों की निर्धारित 744.8 करोड़ रुपये की सीमा अपरिबर्तित रही। यह सीमा इन राज्यों द्वारा राजस्व संबंधी अस्थायी घाटे से निपटने के लिए रखी गयी थी। केन्द्रीय सरकार की प्रातिभूतियों की धिरो पर इन राज्यों को दो नयी विशेष अर्धोपाय अधिम मंजूरी की 266.0 करोड़ रुपये की सीमा भी अवरिबर्तित रही। 1991-92 के दौरान सभी राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट दिनियमन योजना, 1985 का पालन किया जिनके अन्तर्गत ओवरड्राफ्टों को निर्धारित सान लघानंतर कार्यदिशनों को अवधि के अन्दर चुका किया जाना होता है।

समेकित वजटीय स्थिति:

केन्द्र और राज्य

3.22 1991-92 के संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्र और राज्यों की कुल प्राप्तियां बजट अनुमानों 1,78,093 करोड़ रुपये की तुलना में 2,572 करोड़ रुपये अधिक अर्थात् 1,80,665 करोड़ रुपये थी। राजस्व प्राप्तियां (आय) 1,27,971 करोड़ रुपये के बजट आंकड़ों की तुलना में कम अर्थात् 1,27,078 करोड़ रुपये थी, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां (आय, वजटीय अनुमान) 50,122 करोड़ रुपये से कहीं अधिक अर्थात् 53,587 करोड़ रुपये रहीं। कुल संवितरण 1,87,006 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 1,89,364 करोड़ रुपये रहा जो 2,358 करोड़ रुपये अधिक थे। संयुक्त समग्र घाटा, वजटीय अनुमान के 8,913 करोड़ रुपये की तुलना में कम अर्थात् 8,699 करोड़ रुपये रहा।

3.23 वर्ष 1992-93 के लिए बजट अनुमानों में केन्द्र और राज्यों का कुल घाटा 5,487 करोड़ रहा जो कि पिछले वर्ष के 8,699 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में काफी कम (36.9 प्रतिशत) था (परिशिष्ट सारणी III.8)। संयुक्त घाटे में घटे स्तर का कारण केन्द्रीय घाटे में निर्धारित गिरावट था जो कि 1991-92 के 7,032 करोड़ रुपये की तुलना में 1992-93 में 5,389 करोड़ रुपये और राज्यों का 1,667 करोड़ रुपये में से 98 करोड़ रुपये रह गया। 1991-92 में केन्द्र और राज्यों का कुल प्राप्तियां 1,98,617 करोड़ रुपये का था जो 1991-92 के 16.1 प्रतिशत की तुलना में 9.9 प्रतिशत का घाटा-संशोधित वृद्धि दर्शाता है। 1992-93 में केन्द्र और राज्य के कुल संवितरण, 2,04,104 करोड़ रुपये का आंका गया जो पिछले वर्ष के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत का घाटा-दर से बढ़े (परिशिष्ट सारणी III.9 और III.10)

बाजार से उधार

3.24 केन्द्रीय सरकार के सकल बाजार उधार की राशि 1991-92 के दौरान बढ़कर 8,918.0 करोड़ रुपये का हो गयी। निवल बाजार

* तथापि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजटोत्तर कर रियायतों से 847 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होती है, जिनमें 27 करोड़ रुपये की भरपाई राज्य करेगे, अतः केन्द्रीय करों से राज्यों की भागीदारी 1,500 करोड़ रुपये से घटकर 1,229 करोड़ रह जाएगी।

उधार राशियाँ 1990-91 के 8,001 करोड़ रुपये की तुलना में 7,500 करोड़ रुपये थीं। यह सरकारों खर्चों के लिए बाजार उधारियों पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों में वृद्धिगत होती है। राज्य सरकारों के मामले में, चूंकि 1991-92 के दौरान कोई चुनौती संबंधी देयताएँ नहीं थीं, सकल और निवल बाजार उधार राशि 3,364 करोड़ रुपये की थी। केन्द्र और राज्य सरकारों को तथा केन्द्र और राज्य गारंटीकृत इस्थानों की निवल बाजार उधार राशि 1991-92 में 14,651 करोड़ रुपये रही, जो कि 1990-91 में 14,097 करोड़ रुपये थी (परिगणित सारणी III. 11)

केन्द्र और राज्य सरकार के ऋणों पर व्याज दर कूपन रेट

3.25 देश की आर्थिक परिस्थितियाँ और देश में लागू व्याज दर वित्तियम को ध्यान में रखते हुए निवेश हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों को ऋणों पर वर्ष 1991-92 के दौरान व्याज दरों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया। (परिगणित सारणी-III.12)। कुछ परिवर्तनों को खण्ड 1 में स्पष्ट किया गया है।

केन्द्र के ऋणों में भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

3.26 वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार के ऋणों में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रारम्भिक अभिदान 4,822 करोड़ रुपये (सकल बाजार उधारों का 54.1 प्रतिशत) था जो कि पिछले वर्ष 4,432 करोड़ रुपये (सकल बाजार उधारों का 49.3 प्रतिशत) से बहुत अधिक रहा। 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार की विनाशित प्रतिभूतियों में राजधन बैंक की धारिताओं में 1990-91 की 3,481 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 295 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने नवदर्थ खजाना बिलों के निधियन के लिए रिज़र्व बैंक की वर्ष 1990-91 के 30,000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1991-92 के

दौरान 5,000 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की।

3.27 वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार के सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः 6,151 करोड़ रुपये और 5,000 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। यह राशि वर्ष 1991-92 के दौरान जुटायी गई राशि से बहुत कम थी। इसका प्रमुख कारण वृद्धिशील देशी देयताओं को 3 अप्रैल 1992 के स्तर में बैंकों के मासिक जलनिधि अनुदान में कटौती करके उसे 38.5 प्रतिशत से 30.0 प्रतिशत तक घाटा था।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बाण्ड

3.28 वर्ष के दौरान बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देशी बाजार में बाण्डों/डिबेंचरों की जारी कर 5,722 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की राशि जुटानी थी और साथ ही 6 उन्होंने 1,854 करोड़ रुपये की राशि विदेशी वाणिज्यिक उधारों अपूर्णिकर्ता-ऋणों द्वारा प्राप्त करते थे। इन उपक्रमों की बाजार सापेक्ष दरों पर उधार के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में जुलाई 1991 में ऐसे बाण्डों की व्याज दर-सीमा समाप्त कर दी गई। वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट के अनुसार 11,980 करोड़ रुपये की कुल राशि (देशी बाजार में बाण्ड/डिबेंचरों जारी कर 6,058 करोड़ रुपये तथा वाणिज्यिक उधारों अपूर्णिकर्ता ऋण के माध्यम से 5,922 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी राशि जुटाने की आवश्यकता है।

3.29 अभी तक उपलब्ध अन्ततिम सूचना के आधार पर 1991-92 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्ड के माध्यम से 4,227.82 करोड़ रुपये जुटाए गए। वर्ष 1990-91 में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्डों के निर्माणों से कुल 5,463.15 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। इस प्रकार वर्ष 1985-86 और 1991-92 के बीच जुटायी गयी राशि 20,630 करोड़ रुपये हो गई। इस राशि का एक बड़ा भाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर मुक्त बाण्डों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। (सारणी 3.3)

सारणी 3.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1985-86 से 1990-91 के दौरान जारी किये गये बाण्ड

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कर-मुक्त बाण्ड	कर योग्य बाण्ड	जोड़ (2+3)
1	2	3	4
85-86	—	353.69	353.69
1986-87	898.04	776.13	1,674.17
1987-88	1,737.32	946.92	2,684.24
1988-89	2,080.00	417.72	2,497.72
1989-90	2,597.00	1,132.00	3,729.00
1990-91	2,345.00	3,118.15	5,463.15
1991-92	2,161.64	2,066.18	4,227.82

स्रोत : संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित।

4. मुद्रा और मूल्य की प्रवृत्तियाँ

बैंकिंग और मौद्रिक प्रवृत्तियाँ

4.1 वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान मौद्रिक गतिविधियों की विमिश्रितता यह थी कि प्राथमिक तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा प्रारस्थियों में व्यापक वृद्धि के कारण जलनिधि में असाधारण वृद्धि हुई, जबकि इसके ठीक विपरीत 1990-91 में ऐसी प्रारस्थियों में भारी कमी आयी थी जिसके फलस्वरूप उस वर्ष मौद्रिक वृद्धि मंद रही, इसके अतिरिक्त देशी प्राथमिक जलनिधि की वृद्धि से उत्पन्न विस्तारकारक

प्रभाव पड़ा। सरकार को निवल बैंक ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र की बैंक ऋण दोनों में 1991-92 के दौरान अधिक मंद गति से वृद्धि हुई। इसके कारण थे—राजकोषीय सुधार के प्रति सरकार द्वारा शुरू किये गये वृहद आर्थिक अस्थितरीकरण संबंधी विभिन्न उपाय तथा अधिक मुद्रास्फीति और विदेशी भुगतान की कठिन स्थिति की पृष्ठभूमि में कठोर मौद्रिक नीति संबंधी उपाय। 1991-92 के दौरान बैंक जमा राशि की वृद्धि में तेजी आयी तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण विस्तार में गिरावट आयी।

मौद्रिक गतिविधियां

4.2 व्यापक मुद्रा (एम 3) तथा संकीर्ण मुद्रा (एम 1) दोनों में 1991-92 में काफी अधिक मौद्रिक विस्तार हुआ। एम 3 में पिछले वर्ष के 34,878 करोड़ रु. (15.1 प्रतिशत) की तुलना में 49,256 करोड़ रु. (18.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 1991-92 में एम 3 में हुई वृद्धि वर्ष के बृहत् आर्थिक उद्देश्य तैयार करते समय निर्धारित 13

प्रतिशत की वांछित वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि जो पहले खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर जा चुकी थी, में पुनः वृद्धि करने के लिए अतिवासियों से उनके परेपणों को प्राकृष्ट करने की अत्यधिक आवश्यकता वह प्रमुख कारण था जिसने मुद्रा आरक्षित निधि के इस प्रकार के सृजन से हुए खसनिधि के विस्तार को नष्ट करने से प्राधिकारियों को रोका।

सारणी 4.1 : एम 3 में घटबढ़ : संघटक और स्रोत

(करोड़ रु.)

मदें	(अप्रैल—जून)			
	1991-92अ	1990-91	1992-93अ	1991-92अ
1	2	3	4	5
एम 1	+ 21,219 (+ 22.8)	+ 11,832 (+ 14.6)	+ 7,753 (+ 6.8)	+ 6,267 (+ 6.7)
एम 3	+ 49,256 (+ 18.5)	+ 34,878 (+ 15.1)	18,243 (+ 5.8)	+ 12,535 (+ 4.7)
चलमुद्रा	+ 8,184 (+ 15.4)	+ 6,748 (+ 14.5)	+ 2,719 (+ 4.4)	+ 3,737 (+ 7.0)
सकल जमाराशियां	+ 40,850 (+ 19.3)	+ 28,054 (+ 15.2)	10,535 (+ 4.2)	+ 8,064 (+ 3.8)
जिसमें से	+ 5,606	+ 4,777	+ 3,909	+ 203
विदेशी मुद्रा जमाराशियां *	(+ 24.7)	(+ 26.7)	(+ 13.8)	(+ 0.9)
1. विदेशी मुद्रा की सभी जमाराशियां	+ 4,812 (+ 30.8)	+ 4,088 (+ 35.4)	+ 3,427 (+ 16.8)	—35 (—0.2)
2. अतिवासी (बाह्य) जमाराशियां	+ 794 (+ 11.3)	+ 689 (+ 16.8)	+ 482 (+ 6.2)	+ 238 (+ 3.4)
मांग जमाराशियां	+ 12,813 (+ 32.7)	+ 5,008 (+ 14.7)	+ 44 (+ 0.1)	+ 1,796 (+ 4.6)
सावधि जमाराशियां	+ 28,037 (+ 16.2)	+ 23,046 (+ 15.4)	+ 10,490 (+ 5.2)	+ 6,268 (+ 3.6)
सरकार को निवल बैंक ऋण	+ 18,101 (+ 12.9)	+ 23,042 (+ 19.7)	+ 6,391 (+ 4.0)	+ 10,445 (+ 7.5)
सरकार को भा.रि. बैंक का निवल ऋण	5,168 (+ 5.8)	+ 15,165 (+ 20.6)	+ 2,320 (+ 2.5)	+ 7,081 (+ 8.0)
जिसमें से	+ 5,508	+ 14,745	+ 3,913	+ 9,170
केन्द्र को	(+ 6.3)	(+ 20.5)	(+ 4.2)	(+ 10.6)
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	+ 19,296 (+ 11.2)	+ 20,065 (+ 13.2)	+ 8,493 (+ 4.4)	+ 89 (+ 0.1)
निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	+ 10,855 (+ 125.2)	+ 1,854 (+ 27.2)	+ 849 (+ 4.3)	—1,225 (—14.1)
बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रांतर देयताएं	—929 (—1.6)	+ 10,149 (+ 21.9)	—2,510 (—4.5)	—3,204 (—5.7)
भा.रि. बैंक की निवल मुद्रांतर देयताएं	+ 381 (+ 1.4)	+ 9,486 (+ 54.1)	—2,195 (—8.0)	+ 257 (+ 1.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

अ—अंतिम

*केवल वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित

4.3 1991-92 में एम3 के सभी संघटकों में 1990-91 की तुलना में उच्चतर गति से वृद्धि हुई, जिनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय है मांग जमा राशियों का मामला (पिछले वर्ष के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 32.7 प्रतिशत की वृद्धि) जो सरगोबद्ध एमेंतियों द्वारा रखा गया भाजिन मुद्रा जमा राशियों दर्शाती है, तथा शेयर बाजार की सहसा वृद्धि से जुड़ी मुद्राप्रवाह का तीव्र आवेग (परिशिष्ट सारणी IV.1)। 15.4 प्रतिशत मुद्रा विस्तार की गति पिछले वर्ष के 14.6 प्रतिशत की वृद्धि से कुछ अधिक थी। 28,037 करोड़ रु. की सावधि जमा राशियों के अतिरिक्त उपभय में से भारत विकास बोर्डों सहित लगभग 9,500 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा जमा राशियों के थे।

4.4 स्रोतों में से, सरकार को दिये गये निवल बैंक ऋण ने 23,042 करोड़ रु. (19.7 प्रतिशत) की तुलना में 18,101 करोड़ रुपए (12.9 प्रतिशत) की न्यूनतर वृद्धि हुई। केन्द्र सरकार को दिये गये निवल रिजर्व बैंक ऋण में न्यूनतर वृद्धि की यह प्रवृत्ति (1990-91 के 14,745 करोड़ रु. या 20.5 प्रतिशत की तुलना में 5,508 करोड़ रु. या 6.3 प्रतिशत) अधिक दिखायी देती है। तथापि, केन्द्र सरकार को दिये गये निवल रिजर्व बैंक ऋण के आठवें वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में तेजी से गिरने के पहले वर्ष के अधिकांश भाग में इस स्तर से काफी ऊपर रहे और जैसा कि खंड III में पहले ही दर्शाया गया है, केन्द्र सरकार को 1991-92 में पाण्डित्य औसत निवल रिजर्व बैंक ऋण अधिक था। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये निवल रिजर्व बैंक ऋण में भी पिछले वर्ष के 20,065 करोड़ रु. (13.2 प्रतिशत) की तुलना में 19,296 करोड़ रु. (11.2 प्रतिशत) की न्यूनतर वृद्धि हुई। स्वर्ण के पूनर्गुल्यन के अनाया, बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1990-91 के 4,694 करोड़ रु. (-68.8 प्रतिशत) की तुलना में 9,141 करोड़ रुपये (105.4 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1991-92 में मौद्रिक वृद्धि में पर्याप्त विस्तारकारक आवेग से भी रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर वेयताओं में कम वृद्धि हुई। इसमें विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों के आह्वान/नवीकरण के कारण रिजर्व बैंक को हुई 5,233 करोड़ रु. की विविध हानि का भी उल्लेखनीय योगदान था।

प्रारक्षित मुद्रा तथा रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां

4.5 प्रारक्षित मुद्रा में 1990-91 के 10,188 करोड़ रु. या 13.1 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में 11,730 करोड़ रु. या 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.2)। भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों* में पिछले वर्ष के 8,273 करोड़ रु. या 11.6 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में 875 करोड़ रु. या 1.1 प्रतिशत की अत्यन्त कम वृद्धि हुई। 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार को एनबीए तथा निवल भा.रि. बैंक ऋण में वृद्धि करने के लक्ष्य पूर्णतः पूरे हो गये (सारणी 4.2)। जैसा कि पहले दखा जा चुका है इन संकेतकों में बने रहने वाले तीव्र आवेग का निहितार्थ यह है कि प्राथमिक चलनिधि की आधारभूत वृद्धि अवधि के अंत की संख्या द्वारा सूचित (वृद्धि) से काफी अधिक है।

1992-93 के लिए मौद्रिक कार्यक्रम

4.6 1992-93 के मौद्रिक कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों पर लैमासिक सीमा तथा केन्द्र को निवल रिजर्व बैंक ऋण पर उप-सीमा शामिल है। इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को कुछ निवल बैंक ऋण पर तिसाही सांकेतिक सीमा की भी व्यवस्था है। इन सब पर वर्ष में 10.4 प्रतिशत की समग्र मौद्रिक वृद्धि के लक्ष्य की सीमा रखा गया। निवल देशी आस्तियों

की लैमासिक सीमा में (i) आधिकारिक विविध दर में हुए परिवर्तन (ii) सोने के मूल्य में हुए परिवर्तन (iii) प्रारक्षित निधि, धनशास्त्रों में हुए परिवर्तन तथा (iv) निवल अन्तराष्ट्रीय प्रारक्षित निधि अर्थात् अ.गु.को. के उपभोग की निवेत विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि और भा.रि. बैंक की लघु-प्रवृद्धि देखाए, यदि कोई हो तो, में हुए परिवर्तन का समायोजन करना होता है। रिजर्व बैंक के परिवर्तन कारकों अर्थात् निवल देशी आस्तियों और केन्द्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण की सीमा का अनुपालन जून, सितम्बर और दिसम्बर तिमाहियों के अंतिम सूचित शुःवार और उसके ठीक पहले के तीन शुक्रवारों की स्थिति का सामान्य औसत निकालकर निर्धारित किया जाएगा मार्च 1993 की तिमाही के लिए चार शुक्रवार तथा सरकारी लेखाबंदी के बाद 31 मार्च की स्थितियों का औसत निकाला जाएगा। केन्द्र सरकार को निवल बैंक ऋण की सांकेतिक सीमा का अनुपालन, सभी तिमाहियों में अंतिम सूचित दो शुक्रवारों की स्थितियों के औसत द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.7 जैसा कि सारणी 4.3 में दर्शाया गया है, प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 1992) के दौरान निवल देशी आस्तियों केन्द्र को निवल रिजर्व बैंक ऋण तथा केन्द्र सरकार को निवल बैंक ऋण संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं। तथापि, व्यापक मुद्रा में वृद्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है।

1992-93 की प्रथम तिमाही के दौरान मोद्रिक प्रवृत्तियां

4.8 वित्त वर्ष 1992-93 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) की दौरान मुद्रा विस्तार की गति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज रही। व्यापक मुद्रा (एम3) 12,535 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत) की तुलना में 18,243 करोड़ रुपये (5.8 प्रतिशत) बढ़ा। घटकों में सकल जमा राशियों ने उच्च वृद्धि दर्शायी, जबकि जनता के पास मुद्रा में घीमी गति से विस्तार हुआ। संसाधनों के पक्ष में सरकार को निवल बैंक ऋण कम रहा, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण 1991-92 की तुलना में उच्चतर था। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दर्शायी (परिशिष्ट सारणी IV.1)। प्रारक्षित मुद्रा में भी इस अवधि में 6,027 करोड़ रुपये (6.1 प्रतिशत) की उच्चतर वृद्धि हुई, जबकि इसके पहले वर्ष में 4,725 करोड़ रुपये (5.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इस उच्चतर वृद्धि का मुख्य कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को रिजर्व बैंक के ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि तथा कुछ विशेष लेनदेनों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि हुई थी।

कुछ मौद्रिक संबंध

4.9 वर्ष 1991-92 में मौद्रिक संबंधों में कतिपय विशिष्टताएं देखी गयीं जो नोतिगत प्रवृत्तियों और वास्तविक तथा मौद्रिक क्षेत्र की गतिविधियों की प्रवृत्तियों के प्रति अल्कातिक प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं। पहले प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि को रोकने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक लिखतों का सक्रिय और पर उपयोग किया जाता था। दूसरे, अनिवासी पर्याप्त विदेशी मुद्रा आवाक और साथ ही देशी स्रोतों से देशी प्राथमिक चलनिधि की व्यापक औसत वृद्धि के कारण एम3 में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तीसरे, वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि, जिसका लक्ष्य 4.0 प्रतिशत था, वस्तुतः 2.0 प्रतिशत के स्तर से कुछ कम रहा तथा मुद्रा-स्फीतिकारी वभाव बढ़े। इन कारकों के फलस्वरूप मुद्रा की प्रापगत तीव्र उन्वार-वढ़ाव तथा एम3 में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.3)। मुद्रा जमा अनुपात और बैंक प्रारक्षित निधि जमा अनुपात दोनों में कटौती के फलस्वरूप वृद्धिशील मुद्रा गुणक (एम3/प्रारक्षित) में भी विन्दुवार आधार पर पर्याप्त वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.4)।

* यदि भा.रि. बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों को प्रारक्षित मुद्रा में से

घटाया तो निवल देशी आस्तियों के समतुल्य बैठती है।

सारणी--1.3 : 1992-93 के लिए मौद्रिक कार्यक्रम

(करोड़ रुपये)

मदें	31 मार्च 1992 को बकाया	31 मार्च 1992 से आगे निर्धारित विस्तार				31 मार्च 1993 को निर्धारित बकाया	31 मार्च 1992 में प्राग जुन 1992 के अंत में वास्तविक कार्य निष्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1. प्रारंभित मुद्रा							
प्रारंभित मुद्रा	99,509	7,100	5,900	10,900	13,700	1,13,200	6,027
निचल दशी आस्तियां	80,671	10,900	9,300	13,600	16,200	96,900	5,178
		(11,100) @					
सरकार को भा. रि. बैंक का ऋण	94,016	7,300	7,500	7,400	5,800	99,200	2,320
जिसमें से केन्द्र को ऋण	92,266	7,400	7,600	7,000	6,100	98,400	3,913
अन्यो पर भा. रि. बैंक का ऋण	12,362	3,700	2,100	6,500	10,700	23,100	663
जिसमें से							
(1) बैंको पर	5,102						579
(2) बाणिज्यिक क्षेत्र पर	7,260						93
अन्य मदें (निषण)	25,707					25,100	2,195
निचल विदेशी आस्तियां	18,838	3,800	3,400	2,700	2,500	16,300	849
2. संसूचक लक्ष्य							
केन्द्र सरकार को	1,58,294	9,400	10,600	11,400	10,400	16,870	6,391
निचल बैंक ऋण (सामा)							(4.0)
व्यापक मुद्रा (एम. 3)	3,15,084	9,600	11,700	25,200	32,700	3,47,800	18,243
		(3.0)	(3.7)	(8.0)	(10.4)		(5.8)

@ 31 मार्च 1992 को 8,011 रु. प्रति औंस के आधार मूल्य पर मूल्यित 8,894 करोड़ रु. की राशि पर जून 1992 तक स्वर्ण मूल्य में 200 करोड़ रु. के पुनर्मूल्यन को घटाकर

अ--अस्थायी

बैंकिंग प्रवृत्तियां

4.10 कुल जमा राशियों, विशेषकर मांग जमा राशियों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा समय बैंक ऋण में सुस्पष्ट अल्प वृद्धि वित्तीय वर्ष 1991-92 (22 मार्च 1991 से 20 मार्च 1992) के दौरान अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के परिचालनों की विशिष्टताएं थीं।

4.11 सकल जमा राशियों का विस्तार पिछले वर्ष के 25,583 करोड़ रु. (15.3 प्रतिशत) के स्तर से बढ़कर 38,216 करोड़ रु. (19.8 प्रतिशत) हो गया और वह 1991-92 की दूसरी छमाही की ऋण नीति में घोषित 28,500 करोड़ रुपय के संशोधित कार्यकारी अनुमान

को पर्याप्त रूप से पार कर गया (परिशिष्ट सारणी IV-5)। विदेशी मुद्रा के पर्याप्त उपखर्च के अलावा बैंकों की जमा व्याज दरों के समय समय पर वृद्धि करके जमा राशियां आकृष्ट करने में बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता की बढ़ती विशेष कारकों यथा धायातों के प्रति लगाये गये और उधारकर्ताओं द्वारा मजबूरन रखे गये अतिरिक्त नकदी मार्जिनों की बड़ी राशियों, सरणीबद्ध करने वाली एजेंसियों द्वारा रखी गयी मार्जिन मुद्रा जमा राशियों तथा पूंजी बाजार में देखे गये उछाल से जुड़ी प्रवाह मुद्रा ने 1991-92 में बैंक जमा राशियों में तीव्र वृद्धि में अंशदान किया। 1992-93 की पहली तिमाही में जमा राशियों में वृद्धि की गति बनी रही है।

सारणी 4.4: बैंकिंग परिवर्तनी—वृद्धि दरें

(प्रतिशत में)

परिवर्तनी	(अप्रैल-जून)						
	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल जमाराशियां	19.8	15.3	19.1	18.7	14.9	4.5	3.4
भांग जमाराशियां	35.8	15.0	23.6	15.3	5.3	0.3	3.7
सावधिक जमाराशियां	16.5	15.4	18.2	19.4	17.1	5.0	3.3
बैंक ऋण	8.0	14.6	19.8	20.1	11.4	6.5	0.8
खाद्य ऋण	3.6	124.6	160.9	64.9	—57.1	9.2	18.0
खाद्येतर ऋण	8.2	12.4	18.5	22.8	17.4	6.4	0.1
निवेश	20.2	16.6	17.8	17.5	20.5	4.5	4.2

टिप्पणी. धनात्मक बढत के मामले में कोई विहृत नहीं दिया गया है।

4.12 सकल जमाराशियों में तीव्र विस्तार के बावजूद कुल बैंक ऋण में विस्तार की गति उल्लेखनीय रूप से कम रही। वर्ष में खाद्यान्नों की बसुली में गिरावट तथा अधिक निकासी जिसकी वजह से उनके स्टॉक के स्तरों में तीव्र गिरावट आयी, के कारण खाद्य ऋण का विस्तार 1990-91 के 2,500 करोड़ रुपये की तुलना में 164 करोड़ रुपये पर साधारण रहा। प्रतिबंधात्मक ऋण नीतिगत उपाय और अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट तथा ऋण की बढ़ती हुई लागत से खाद्येतर ऋण में कम विस्तार हुआ और वह 1990-91 के 12,348 करोड़ रुपये (12.4 प्रतिशत) तथा 1989-90 के 15,497 करोड़ रुपये (18.5 प्रतिशत) की तुलना में 9,127 करोड़ रुपये (8.2 प्रतिशत) रहा। बैंक जमाराशियों में व्यापक विस्तार के अनुरूप सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि की वृद्धि हुई।

4.13 हाल के वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्य बैंक मार्च के अंतिम सप्ताह में भ्रमस्त जमाराशियों तथा बैंक ऋण में अस्वाभाविक रूप से अधिक वृद्धि सूचित कर रहे हैं। 1991-92 में यह प्रवृत्ति नहीं दिखायी दी थी (परिशिष्ट सारणी IV.6) 20 मार्च से 27 मार्च 1992 तक की सात-दिन की अवधि में बैंकों द्वारा यथासूचित समस्त जमाराशियों में 3.0 प्रतिशत की तथा बैंक ऋण में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्षों में सूचित की गयी अधिक वृद्धि की तुलना में सामान्य है। इस तथ्य से कि 30 प्रतिशत तक घटा कर लाया गया सावधिक चलनिधि अनुपात 3 अप्रैल, 1992 के स्तर से ऊपर की निवल भांग और सावधि देयताओं में हुई वृद्धि पर लागू था, बैंकों को वर्षांत में अधिक जमा वृद्धि का आश्रय लेने से हतोत्साहित किया होगा। इस तथ्य की पुष्टि मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार और 31 मार्च, 1992 के बीच (म्यारु विनों की अवधि) जमाराशि में हुई 11,310 करोड़ रु. (4.9 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना मार्च 1991 के अंतिम सूचित शुक्रवार और 31 मार्च 1991 के बीच की अवधि में बैंकों द्वारा जुटायी गयी 12,232 करोड़ रुपये (6.4 प्रतिशत) से करने पर भी होती है। अप्रैल के पहले कुछ दिनों के भीतर इन जमाराशियों में क्षरण विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष कहीं अधिक था जो कि ऊपर उल्लिखित वृद्धिशील सावधिक चलनिधि अनुपात निर्धारणों को दर्शाता है। 31 मार्च से 3 अप्रैल 1992 के बीच की 3 दिनों की अवधि के भीतर ही सकल जमाराशि में 7,824 करोड़ रुपये की कमी पायी जो मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार तथा 31 मार्च, 1992 के बीच जमा हुई राशि का 69 प्रतिशत अंश है (31 मार्च,

1991 से 5 अप्रैल, 1991-92 के बीच की अवधि के दौरान 6705 करोड़ रुपये की कमी की तुलना में)।

4.14 बैंकों के पास जमाराशि संसाधनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के साथ बैंकों द्वारा व गैर-जमा संसाधनों के उपयोग में 1991-92 में स्पष्ट गिरावट आयी (परिशिष्ट सारणी IV.7)। सकल आधार पर 1991-92 के दौरान अतिरिक्त गैर-जमा संसाधनों का उपयोग 1025 करोड़ रुपये घट गया (1990-91 में बैंकों ने 65 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त गैर-जमा संसाधनों का उपयोग किया)।

1992-93 की पहली तिमाही की प्रवृत्तियां

4.15 सकल जमाराशि में 10,438 करोड़ रुपये (4.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 1991-92 की तुलनीय तिमाही में हुई 6,566 करोड़ रुपये (3.4 प्रतिशत) से उच्चतर थी। बैंक ऋण में हुई 8,166 करोड़ रुपये (6.5 प्रतिशत) की वृद्धि और भी चौकन्ना करने वाली थी, जो पिछले वर्ष के 960 करोड़ रुपये (0.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक रही।

4.16 1992-93 के दौरान (जुलाई 1992 के अंत तक) खाद्येतर ऋण में वृद्धि:

अभी तक (24 जुलाई 1992 तक) चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये खाद्येतर ऋण में अनुपूर्व वृद्धि हुई। इस चार महोत्सवों की अवधि में यह वृद्धि 1991-92 और 1990-91 की तदनुकूली अवधियों में क्रमशः अंकित केवल 714 करोड़ रुपये (या 0.6 प्रतिशत) और 874 करोड़ रुपये (या 0.9 प्रतिशत) की वास्तविक वृद्धि की तुलना में 9,994 करोड़ रुपये (या 8.3 प्रतिशत) थी (सारणी 4.5)। उक्त चार महोत्सवों की अवधि के दौरान यह वृद्धि पूरे वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान 9,127 करोड़ रुपये (या 8.2 प्रतिशत) की वृद्धि से भी अधिक रही। कुछ क्षेत्रों में मात्र के निर्माण (इन्वेंटरी बिन्ड-अप) का कुछ संकेत है; जब अप्रैल 1992 का ऋण नाति घोषित की गयी थी, तब यह परिकल्पित निरा मरा था कि 1992-93 की पहली छमाही के लिए खाद्येतर ऋण में वृद्धि लगभग 4,000 करोड़ रुपये (या 3.3 प्रतिशत) होगी।

सारणी 4.5 : अनुसूचित बाणिज्य बैंकों को खाद्योत्पन्न ऋण में वृद्धि
(करोड़ रु.)

वित्तीय वर्ष	बकाया	षट्क	
		संपूर्ण वृद्धि	प्रतिशत
1	2	3	4
पूर्ण वर्ष			
1991-92	1,20,922	4,127	8.2
1990-91	1,11,795	12,343	12.4
1989-90	99,447	15,497	18.5
अर्ध तक की अवधि			
1992-93			
जुलाई, 24, 1992 तक.	1,30,916	9,994	8.3
1991-92			
जुलाई, 26, 1991 तक	1,12,509	714	0.6
1990-91			
जुलाई 27, 1990.	1,00,32	874	0.9

*अनंतिम

4.17 ऋण का क्षेत्रवार वित्तियोजन : वित्तवर्ष 1991-92 के सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वित्तियोजन के अंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस वर्ष खाद्योत्पन्न सकल बैंक ऋण में वृद्धि पर्याप्त रूप में कम थी (परिशिष्ट सारणी 4.8)। उद्योग को वृद्धिशील ऋण के उद्योगवार व्योरे (परिशिष्ट-सारणी 4.9) यह दर्शाते हैं कि मुख्यतः सभी इंजीनियरिंग, रसायन संपूर्ण, कोयला, लोहा और इस्पात, अन्य धातु तथा धातु उत्पाद सूती वस्त्र, अन्य वस्त्र, कागज तथा कागज उत्पाद और वित्तियोजन में ऋण की वृद्धि में कमी आयी।

4.18 भारतीय रिजर्व बैंक पुनर्वित्तः नियंत्रित बढ़ाने तथा मांग ही नियंत्रित की वित्तपोषित करने के लिए बैंकों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की परम आवश्यकता पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान ऋण पुनर्वित्त नीति को और अधिक उदार बना दिया गया। नियंत्रित ऋण व्याज दरों में वृद्धि तथा नियंत्रित ऋण पुनर्वित्त फार्मले में उदारीकरण से नियंत्रित क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने में बैंकों को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला (परिशिष्ट सारणी IV. 10)।

सारणी 4.6 : नियंत्रित ऋण पुनर्वित्त

निम्नलिखित तारीखों को	नियंत्रित ऋण (बकाया)	नियंत्रित ऋण पुनर्वित्त की सीमाएं	कॉलम (2) के मुकाबले कॉलम (3) का अनुपात (प्रतिशत)
(करोड़ रुपये)			
1	2	3	4
22 मार्च 1992	8,863	4,129	46.6
20 मार्च 1992	10,695	5,594	52.3
26 जून 1992	12,020	7,163	60.0
24 जुलाई 1992	12,365	7,656	61.9

4.19 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पोलिसीगतः नियंत्रित ऋण जो अमेरिकी डालरों में मूल्यवर्गीकृत है, उसके प्रति पुनर्वित्त की एक नयी योजना 4 जनवरी 1992 में शुरू की गयी थी जिसके अंतर्गत बैंक वित्त नियंत्रितों को उपलब्ध कराया गया। अमेरिकी डालरों में मूल्य वर्गीकृत पोलिसीगतः नियंत्रित ऋण के 133-1/3 प्रतिशत तक के समकक्ष पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसे फरवरी और अप्रैल 1992 में और उदार बनाया गया। इसके फलस्वरूप डालर मूल्य वर्गीकृत नियंत्रित ऋण 3 अप्रैल 1992 के 23 करोड़ रुपये से बढ़कर 24 जून 1992 को 390 करोड़ रुपये हो गया। नयी योजना के अंतर्गत उपर्युक्त अवधि में पुनर्वित्त की सीमाएं 31 करोड़ रुपये से बढ़कर 519 करोड़ रुपये हो गयी।

अल्पाधिक, मुद्रा बाजार की प्रवृत्तियाँ

4.20 भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड : भारतीय मित्री-काटा और वित्त गृह लिमिटेड, अल्पकालिक चल मुद्रा अनुमूलन को कम करने के लिए मुद्रा बाजार को लिखतों और बाजार के निम्न घटनाओं को समन्वित करने के लिए एक सक्रिय वित्तीय बाजार के विकास हेतु प्रयास करना रहा है। मांग मुद्रा बाजार में इसका कुल नेटवर्क 1990-91 के 2,02,792 करोड़ रुपये की तुलना में काफी बढ़कर 1991-92 में 2,96,862 करोड़ रुपये हो गया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड द्वारा मांग मुद्रा बाजार में उधार की दैनिक औसत 1990-91 के 546 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1991-92 में 813 करोड़ रुपये हो गयी। 1991-92 और 1992-93 के पहले कुछ महीनों के दौरान भी भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड के मुद्रा बाजार लिखतों में गति नेटवर्क काफी बढ़ा है। (देखें परिशिष्ट सारणी IV. 11, 12 और 13)।

4.21 मांग मुद्रा बाजार : अप्रैल-जून 1991 के दौरान मांग मुद्रा की दरों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने के पश्चात् मांग मुद्रा की दर जुलाई 1991 में एक निम्न स्तर पर स्थिर हो गयी। भारतीय मित्री-काटा और वित्त गृह लिमिटेड की दैनिक भारांकित औसत उधार दरें जुलाई 1991 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 1991 में 11.0 प्रतिशत पर आ गयी और मार्च 1992 के अंतिम सप्ताह तक इस स्तर के आसपास बनी रहीं। (देखें परिशिष्ट सारणी IV. 14)। मांग मुद्रा बाजार में यह नरम स्थिति अल्पाधिक अवधि की वित्तीय प्रणाली में अल्पाधिक मुद्रा में हो जाने के कारण है। यह निम्नलिखित कारणों से हुई—विदेशी आक प्रेषण, भारत विकास बांडों की स्वदेशी निधियों तथा खाद्योत्पन्न ऋण के लिए कम मांग। इसके परिणामस्वरूप 32 प्रमुख अनुसूचित बाणिज्य बैंकों की मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक उधार लेने की राशि जुलाई 1991 के 7,200 करोड़ रुपये से कम होकर जनवरी 1992 में 5,700 करोड़ रुपये रह गयी। मांग मुद्रा बाजार में बाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गयी औसत दैनिक उधार की राशि जुलाई 1991 के 1,870 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 1992 में 3,420 करोड़ रुपये पर पहुँच गयी। अप्रैल 1992 में इन 22 प्रमुख अनुसूचित बाणिज्य बैंकों की औसत दैनिक उधार राशियाँ लगभग 6,520 करोड़ रु. की थीं। बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की वृद्धि होने के कारण मांग मुद्रा बाजार में वित्तीय संस्थाओं से बैंकों की उधार की मांग कम हो गयी। वित्तीय संस्थाओं की दैनिक औसत उधार राशि मांग मुद्रा बाजार में जून 1991 की 5,630 करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल 1992 में 3,760 करोड़ रुपये रह गयी।

4.22 अप्रैल-मई 1992 के महीनों के दौरान व्याज की दरों में तेज वृद्धि हुई और 28 अप्रैल 1992 को ये 100 प्रतिशत तक की आश्चर्यजनक ऊँचाई तक पहुँच गयी। मांग दर में तीव्र वृद्धि कुछ बैंकों

द्वारा अपनी नकदी प्रारक्षित अनुपात की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई उधार आवश्यकताओं के कारण आयी जो अप्रैल और मई 1992 में कई अवकाश के दिनों के कारण छोटी अवधि के लिए उनकी जमागणियों में वर्ष की समाप्ति पर होनेवाली वृद्धि, मांग निधियों की अपर्याप्त आपूर्ति तथा वाणिज्यिक बैंकों और विनियम संस्थाओं के निधि प्रबंधन में पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में विशेषकर सरकारी प्रतिष्ठानियों में उनके परिचालनों के कारण, बाजार में आयी अनियमितता के कारण हुई थी। तथापि मई 1992 के अन्त तक मांग मुद्रा दरे घटकर 15-20 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गयी। जून माह के दौरान अन्तर बैंक मांग मुद्रा बाजार में तरमी की प्रवृत्ति रही जिसमें जून 1992 के मध्य तक थोड़ा सा बढ़ाव आया। इसके बाद कुछ समय तक ये दरे 20-25 प्रतिशत के असुल्य स्थिर रह्यो, परन्तु जून 1992 के अन्त तक गिरकर 2-3 प्रतिशत तक आ गयी और कुछ समय तक रही परन्तु जुलाई 1992 में ये 10-15 प्रतिशत से नीचे गयी।

4.23 182 दिवसीय खजाना बिल : बिल वर्ष 1991-92 में 182 दिवसीय खजाना बिलों के प्रति काफी उत्पादजनक प्रभाव रहा। मार्च 1992 के अन्त में 182 दिवसीय बिलों की बकाया राशि 3,985.52 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 1991 की समाप्ति पर यह 1,077.59 करोड़ रुपये थी। (परिशिष्ट सारणी IV.15) समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन बिलों पर अधिकतम आय 8.77 से लेकर 10.08 प्रतिशत वार्षिक के बीच रही। 11 अप्रैल 1992 की नीलाम की गई (अब तक के वर्तमान वर्ष में इस परिपक्वता की अन्तिम धारिता) जिसमें 8.77 प्रतिशत अधिकतम प्राप्ति पर 245 करोड़ रुपये की बोनियां स्वीकार की गई।

4.24 364 दिवसीय खजाना बिल सरकारी प्रतिष्ठानि आधार की समग्र गतिविधियों के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि अप्रैल 1992 में अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाले 364 दिवसीय खजाना बिलों को नीलामी आधार पर जारी किया जाए। अगस्त 1992 तक की अवधि के दौरान 364 दिवसीय खजाना बिलों की नौ नीलामियां की गयीं और 19 अगस्त 1992 को इनकी बकाया राशि 7,159.63 करोड़ रुपये थी; (परिशिष्ट सारणी IV.16)। पहली पांच नीलामियों में इन बिलों की 11.42 प्रतिशत थी जबकि अंतिम

चार नीलामियों की अधिकतम आय क्रमशः 11.36 प्रतिशत, 11.27 प्रतिशत, 11.20 प्रतिशत और 11.17 प्रतिशत वार्षिक थी।

4.25 जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिकपत्र : जमा प्रमाणपत्रों का परिमाण बढ़ता रहा है और 12 जून, 1992 की बकाया राशि 6,556 करोड़ रुपये थी (परिशिष्ट सारणी IV.17)। जहां प्राथमिक निर्गम बढ़ते रहे हैं, वहीं द्वितीय बाजार में लेनदेन विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि धारकों को इस जमा प्रमाण पत्रों की पूरी मीमांसा तक रखने की वृद्धि भावना रही। इससे इस संभावना का भी पता लगता है कि मांग के संदर्भ में बैंक जमा प्रमाण पत्रों पर ब्याज दरों को आवश्यकता ने अधिक ऊंची दरों पर रख रहे हैं। जहां प्राथमिक बाजार में वाणिज्यिक पत्रों ने पर्याप्त प्रगति की है और 30 जून, 1991 के 64.70 करोड़ रुपये की बकाया राशि 30 जुलाई, 1992 को बढ़कर 145.05 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी, वहीं द्वितीय बाजार का अभी विकास होना है।

4.26 मूल्यों की प्रवृत्तियां : 1991-92 के दौरान व्यापक आर्थिक परिदृश्य में एक विस्तारजनक पहलू यह था कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी जो पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से शुरू हुई थी (सारणी IV.7)। इसका कारण अंशतः कुछ व्यापक स्तर के असंतुलनों के कारण हो सकता है और कई कुछ क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण। वर्ष भर में भारी मात्रा में और निरन्तर बने रहे राजकोषीय घाटों से उत्पन्न हुई अत्यधिक मांग के दबाव के कारण चलनिधि में अत्यधिक फैलाव आया और उसके कारण अवैधव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में जोर पकड़ा। दबावों के अन्त्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे मानसून की प्रगति का अगस्त 1991 के अंत तक अनुमान रहना और इसके फलस्वरूप मूल्यों की अपेक्षाओं में वृद्धि संवेदनशील पद्यों जैसे धान, खाद्य तेल, कपास आदि की मांग और आपूर्ति में असंतुलन, क्योंकि इनके देशी उत्पाद और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाने में बाधाएं रहीं; जुलाई 1991 के प्रारंभ में विदेशी मुद्रा दर में समायोजन जिनके कारण आयातों की लागतों में वृद्धि हुई और आयात-नमुखी उद्योगों में लागत काफी बढ़ गयी; औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में; अनाजों के सरकारी खरीद मूल्यों में तेज वृद्धि और उसके फलस्वरूप उनके निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि; निर्धारित मकों जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद (डीजल और मिट्टी के तेल को छोड़कर) उर्वरक और बिजली के मूल्यों में वृद्धि, तथा 1991-92 और 1992-93 के केन्द्रीय बजटों में उत्पाद शुल्कों में वृद्धि।

(प्रतिशत में)

सारणी 4.7 : वार्षिक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
(बिन्दु-दर-बिन्दु 12-माह की अवधि की वृद्धि)

निम्नलिखित के अन्त में	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	+13.6	+11.4	+9.0	+5.9	+9.6
मई	+12.9	+12.3	+8.4	+7.2	+9.3
जून	+11.3अ	+12.3	+9.4	+6.5	+9.5
जुलाई	+9.3अ	+14.5	+9.3	+6.4	+8.3
अगस्त	+8.7अ	+16.4	+7.6	+8.9	+6.3
सितम्बर		+15.9	+7.9	+9.0	+6.9
अक्टूबर		+14.3	+10.1	+7.6	+7.3
नवम्बर		+14.6	+11.1	+7.5	+7.0
दिसम्बर		+14.3	+12.6	+7.7	+4.4
जनवरी		+12.9	+13.5	+8.1	+5.6
फरवरी		+13.2	+13.2	+8.7	+5.3
मार्च		+13.6	+12.1	+9.1	+5.7

अ : अन्तिम

*मार्च से 8 अगस्त 1992 तक।

4.27 सामान्य धोक मूल्य सूचकांक में (आधार 1981-82=100) बिन्दुवार आधार पर 1989-90 में 9.1 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 1990-91 में 12.2 प्रतिशत। 1991-92 में यह और बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गयी। औसत आधार पर भी वृद्धि पिछले वर्ष के 10.3 प्रतिशत से उच्च होकर 13.7 प्रतिशत हो गयी [परिशिष्ट सारणी IV.19]। 1990-91 और 1991-92 में सोमम के दौरान भी कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आयी [परिशिष्ट सारणी 4.18]।

4.28 "प्राथमिक वस्तुओं" के मूल्यों में सब से अधिक वृद्धि देखी गयी है (जो 17.1 प्रतिशत की तुलना में 15.3 प्रतिशत है) (परिशिष्ट सारणी IV.19)। इसके बाद "खाद्य वस्तुओं" के मूल्यों में भी वृद्धि हुई और इस प्रमुख समूह में यह वृद्धि 1990-91 में 18.9 प्रतिशत और उसके ऊपर बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गयी। खाद्य वस्तुओं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और चीनी में 12.3 प्रतिशत से लेकर 65.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि देखी गयी। कापास के मूल्य भी 24.7 प्रतिशत

बढ़ गए। "ईंधन" समूह में सूचकांक काफी बढ़ गया जिसका कार इसके उप-समूह अर्थात् कोयला (27.4 प्रतिशत), खनिज तेल (9.2 प्रतिशत) और बिजली (13.7 प्रतिशत) के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि थी। "प्राथमिक वस्तुओं" और "ईंधन" समूह के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा उर्वरकों के निर्धारित मूल्यों में (28.8 प्रतिशत) सोमेट (17.4 प्रतिशत) तथा एल्गुमीनियम को छोड़कर प्रतीह धातु (9.7 प्रतिशत) की वृद्धि ने "विनिर्मित उत्पाद" के समूह के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी। इसके परिणामस्वरूप, इस समूह ने सामान्य मूल्यों के स्तर से 1991-92 में अधिकांशतः वृद्धि की (1990-91 में 43.0 प्रतिशत की तुलना में 52.7 प्रतिशत) (परिशिष्ट सारणी IV.20)।

4.29 मूल्यों की यह वृद्धि सामान्य प्रवृत्ति बन जाने के अलावा सामान्य उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्यों में पिछले 2 वर्षों में तीव्रतम वृद्धि देखी गयी जो कि 'खाद्य मर्च' के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए समिश्र मूल्य सूचकांक में दर्शायी गयी उल्लेखनीय वृद्धि में देखा जा सकता था (सारणी IV.8)।

सारणी 4.8 : खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं का मिश्रित धोक मूल्य सूचकांक

सर्वे	भारत	प्रतिशत घट-बढ़			भारत अंशदान		
		1991-92	1990-91	1989-90	1991-92	1990-91	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.000	13.6	12.1	9.1	100.0	100.0	100.0
खाद्य वस्तुएं मिश्र	27.529	17.3	16.9	5.7	37.0	39.0	18.2
(क) खाद्य पदार्थ (प्राथमिक)	17.386	20.9	18.9	2.1	29.4	28.1	4.5
(ख) खाद्य उत्पाद (विनिर्मित)	10.143	10.2	13.2	12.9	7.6	10.9	13.7
खाद्येतर मर्च	72.471	12.1	12.2	10.4	63.0	61.0	81.8

4.30 'खाद्य मर्च' के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई) के स्वरूप में प्रतिबिंबित हुई जिनके संबंध में 'खाद्य मर्च' की भारिता धोक मूल्य सूचकांकों में उनकी भारिता से लगभग दुगुनी है (परिशिष्ट सारणी IV.21) इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वृद्धि औद्योगिक कामगारों के लिए 13.9 प्रतिशत, शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए 13.6 प्रतिशत और कृषि श्रमिकों के लिए अधिकतम 21.9 प्रतिशत, श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 'खाद्य मर्च' के लिए इनकी सबसे अधिक भारिता है, वही की गई।

4.31 प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 1992-93) की प्रवृत्तियाँ: वर्तमान वित्त वर्ष 1992-93 की प्रथम तिमाही के दौरान धोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक ने तुलनात्मक दृष्टि से 2.3 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि दर्शायी जबकि 1991-92 की इसी अवधि के दौरान इसमें 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। स्कीम वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही मुद्रा नीति की वार्षिक दर में माह-ब-माह क्रमिक गिरावट की प्रवृत्ति रही (सारणी 4.52 देखें)। सभी प्रमुख पण्य समूहों के सूचकांकों ने नरमी दर्शायी। मांग के दबाव के कारण पण्यों के मूल्यों में उच्च स्तर पर वृद्धि होने के अलावा विभिन्न व्यापक स्तर की नीति संबंधी पहलुने किये जाने के कारण मूल्यों की उपेक्षित स्तर तक नियंत्रित रखा गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि इसकी तुलना में 1991-92 की तदनु रूप अवधि में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1317 GI/93-9

4.32 सोने चांदी के भाव: 1991-92 के दौरान सोने और चांदी के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखा गया। बंबई बाजार में सोन का भाव सघनतः पिछले 3 वर्षों में नरम रहने के पश्चात् 25 प्रतिशत तक बढ़ा। चांदी का भाव भी काफी बढ़ा, विशेषकर 1991-92 की पिछली तिमाही में। तथापि, सोने और चांदी के भावों में देशी और अंतर-राष्ट्रीय बाजारों में जो अंतराल था वह इस वर्ष के दौरान काफी कम हुआ। जुलाई 1991 में रुपये के मूल्यों में निम्नमूल्यी समायोजन किए जाने के तुरंत बाद सोने और चांदी दोनों के मूल्यों के अंतर में कमी आई, परंतु कुछ समय के पश्चात् जनवरी 1992 तक वह काफी बढ़ गया। तथापि मार्च 1992 में इस अंतराल में तेजी से गिरावट आयी और श्रमिक नयी विविध दर नीति (उद्यारीकृत विविध दर प्रबंध प्रणाली) के प्रभाव अनुभव करने का यह पहला ही महीना था और साथ ही अति-बासी भारतीयों द्वारा सोने के वैध रूप से आयात करने की सुविधा दी गयी थी [परिशिष्ट सारणी IV.22 से IV.24 तक] अप्रैल 1992 के अंत तक सोने के मूल्यों का अंतराल 34 प्रतिशत के लगभग गिर गया और मई तक यह 27 प्रतिशत गिर गया, तथा जून 1992 में और 24 प्रतिशत तथा जुलाई 1992 में और 21 प्रतिशत गिर गया जबकि पिछले 12 महीनों के दौरान अधिकांश समय यह अंतर 60 प्रतिशत के आसपास रहा। चांदी में यह अंतराल अप्रैल के अंत तक 110 प्रतिशत तक बढ़ गया, परंतु मई के अंत के आसपास यह अंतराल घटकर 101 और जून 1992 की यह 84 प्रतिशत तक रह गया परंतु जुलाई 1992 में बढ़ कर 96 प्रतिशत हो गया।

5. पूंजी बाजार की गतिविधियाँ

5.1 जुलाई 1991 से लागू उवारीकरण के विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाजार ने 1991-92 के दौरान अपने द्वितीयक बाजार के घटकों में अभूतपूर्व उछाल और नये निर्गमों की गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार देखा। द्वितीयक बाजार में आया उछाल, विशेषकर 1992-93 के लिए केन्द्रीय बजट के पश्चात्, आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों को काफी सीमा तक अनदेखा कर दिया, सट्टेबाजी के दबावों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेनों की जाँच करने के लिए गठित समिति (अध्यक्ष श्री आर. जानकी-रामन) की रिपोर्ट में सट्टेबाजी के दबावों के प्रकाश में आने के पश्चात् सरकार द्वारा तेजी से कार्रवाई की गयी। ईक्विटी मूल्यों में जो अनुचित वृद्धि हुई थी उसे मई-जून 1992 में काफी सीमा तक ठीक कर दिया गया।

5.2 मीयादी वित्त-मोषण और निवेश संस्थाओं द्वारा सहायता: प्रखिल भारतीय विकास बैंकों द्वारा 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान संवितरित 11,693 करोड़ रुपये (अन्तःसंस्थागत प्रवाह की राशियों को घटाकर) ने पिछले वर्ष की 2,204 करोड़ रुपये अथवा 29.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1,915 करोड़ रुपये अथवा 19.6 प्रतिशत की वृद्धि वर्ग की (परिशिष्ट सारणी 5-1 देखें)। उनकी मंजूरीयों में वृद्धि 1990-91 के 24.0 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घटकर 1991-92 के दौरान 11.6 प्रतिशत रह गयी, जो मुख्य रूप से इन संस्थाओं द्वारा सामना की गयी मुख्यतः कठिन आर्थिक स्थिति और संसाधन की तंगी को दर्शाती है। दूसरी तरफ, निवेश संस्थाओं (यूटीआई, एलआईसी, तथा जीआईसी) की संसाधन स्थिति उत्साहवर्धक रही है और उन्होंने 1991-92 के दौरान सहायता/निवेशों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनी मंजूरीयों और संवितरणों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।

5.3 1991-92 में कंपनी निवेश: डॉ. सी. रंगराजन द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार कंपनी निवेश-पूर्वानुमान वर्ष जो अभी तक कैलेंडर वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किए जाते थे, वर्ष 1991-92 से उन्हें वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। यह अध्ययन, निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के निवेशों के वार्षिक पूर्वानुमान की शृंखला में चौथा है, जो सभी परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की संभावित चरणबद्धता पर आधारित है, जिसके लिए आईसीआईआई, आईसीआईसीआई और आईएफ-सीआई द्वारा सहायता की मंजूरी दी गयी। अध्ययन का अनुमान है कि 1991-92 के दौरान सामान्य रूप से 19,049 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत व्यय किया गया जो 1990-91 के दौरान के संभावित पूंजीगत व्यय की तुलना में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। संस्थाओं के बिलों की पुनर्मुनाई योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत अनुमानित कुल संवितरित की अनेकाली निधियों सहित 1991-92 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 19,357 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। उपयुक्त अपस्फीतिकारक द्वारा कम किए जाने पर 1980-81 के मूल्यों पर कुल निवेश (रुपयों में), 1990-91 में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और संबंधित पिछले वर्षों के तदनुषंगी व्यय की तुलना में 1991-92 में 1.4 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। उद्योगवार देखा जाए तो धातु और धातु से बनी वस्तुओं का अंश 39.0 प्रतिशत (127 परियोजना अथवा 9,349 करोड़ रु.) पर अत्यधिक था, उसके बाद रसायन और पेट्रोरसायन का अंश अर्थात् 10.0 प्रतिशत (179 परियोजना अथवा 2,396 करोड़ रु.) रहा। उसके बाद जट को छोड़कर

बत्त, उद्योग का स्थान था अर्थात् 9.6 प्रतिशत (228 परियोजना अथवा 2,296 करोड़ रु.)।

5.4 गैर बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमाराशियों की वृद्धि संबंधी प्रवृत्तियाँ: उपलब्ध घनंतिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 9,901 सूचना देने वाली गैर बैंकिंग कंपनियों के कुल उधार 10,532 करोड़ रुपये बढ़कर 44,063 करोड़ रुपये पर हो गये, जबकि मार्च, 1990 के अन्त में 10,140 कंपनियों के पास 33,531 करोड़ रुपये के थे। सूचना देने वाली कंपनियों की कुल नियमित जमा राशियों में 1,245 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई जो 8,003 करोड़ रुपये पर स्थिर रह गयी, जब कि छूट प्राप्त उधार की राशि 9,287 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,060 करोड़ रुपये हो गयी। उधार दी गई कुल राशि में गैर वित्तीय कंपनियों का हिस्सा 59.6 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय कंपनियों का 35.5 प्रतिशत, और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों एवं अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों में प्रत्येक का अंश 4.9 प्रतिशत रहा। गैर बैंकिंग क्षेत्र द्वारा रखी गयी नियमित जमाराशियों सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों के 3.9 प्रतिशत के समकक्ष थीं (परिशिष्ट सारणी 5-2)।

5.5 नया निर्गम बाजार: 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के लिए सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों की नियंत्रक पूंजी निर्गम द्वारा बिये गये अनु-मोदन (सहमति/स्वीकृति इसमें प्रिमियम निर्गम शामिल है परन्तु बोनाम शेयर शामिल नहीं है) पिछले वर्ष बिये गये अनुमोदनों से 56.1 प्रतिशत अधिक थे (परिशिष्ट सारणी 5-3)। विशेषकर गैर सरकारी कंपनियों को दिये गये अनुमोदनों में 95.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी।

5.6 नये पूंजी निर्गम (जिसमें प्रिमियम निर्गम शामिल हैं परन्तु बोनाम निर्गम शामिल नहीं हैं) कुल 5,751 करोड़ रुपये के थे जो 1991-92 के दौरान 35.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं जबकि 1990-91 के दौरान इनमें 34.6 प्रतिशत की गिरावट आयी थी (परिशिष्ट सारणी 5-4)। नये निर्गम बाजार में डिबेंचर निर्गमों की प्रधानता रही जो कुल नये पूंजी निर्गमों के लगभग 70 प्रतिशत बैठते हैं। परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम 48.1 प्रतिशत बढ़े। ईक्विटी निर्गम 1,730 करोड़ रुपये के रहे जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। 1991-92 के दौरान नये निर्गम बाजार में एक उल्लेखनीय पहलू राइट निर्गमों में काफी वृद्धि का रहा। राइट निर्गमों की कुल राशि 3,847 करोड़ रुपये की रही जो 76.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं और 1991-92 के दौरान जारी कुल पूंजी निर्गमों के 66.9 प्रतिशत बैठते हैं जबकि इसके विपरीत 1990-91 में ये 51.7 प्रतिशत के थे।

5.7 नए निर्गमों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण: बंबई शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार नये निर्गमों के प्रति जनता का समग्र प्रतिकार 1991-92 में उन्माहवर्धक बना रहा। ऐसे निर्गमों की संख्या जिनमें 10 गुने से अधिक अभिदान प्राप्त हुआ कुल निर्गमों के 50.5 प्रतिशत बैठते हैं, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, जबकि पिछले वर्ष ऐसे निर्गमों की संख्या 21.9 प्रतिशत थी। जनता के अभिदान के लिए प्रस्तुत राशि कुल निर्गम की 49.1 प्रतिशत बैठती है जबकि 1990-91 में यह 45.0 प्रतिशत बैठती थी। हाल ही के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि द्वितीयक बाजार के सामने आयी कठिनाइयों और विघटन के बावजूद प्राथमिक निर्गमों की संख्या और राशि काफी अधिक है तथा जनता की प्रतिक्रिया उत्साहजनक बनी हुई है।

5.8 ईक्विटी मूल्य : 1991-92 के दौरान शेयर बाजार ने उछाल की स्थितियाँ देखीं। इसकी गतिविधियों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई और शेयर मूल्यों में उच्च वृद्धि। यद्यपि वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ईक्विटी मूल्य धीरे-धीरे चढ़े, लेकिन 1991-92 के लिए जुलाई 1991 में केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत होने के बाद इनमें तेजी से वृद्धि हुई और सितम्बर 1991 के तीसरे सप्ताह तक ये चढ़ते रहे। इसके बाद ईक्विटी मूल्यों में थोड़ी बहुत घट-बढ़ होती रही तथापि, अस्थिर स्थिति प्राशा-वादी बनी रही। वर्ष 1992-93* के केन्द्रीय बजट से शेयर बाजार में तेजी आयी। परिणामस्वरूप, मार्च 1992 में शेयरों के मूल्यों में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सम्पूर्ण शेयर मूल्यों (प्राधार : 1980-81-100) में भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित भारतीय (मासाहिक) सूचकांक में हुई घट-बढ़ की परिशिष्ट सारणी V-5 में दिखाया गया है। 30 मार्च 1991 के सप्ताहांत का सूचकांक 527.9 से बढ़कर 21 सितम्बर 1991 को समाप्त सप्ताह में 792.3 हो गया और 28 जनवरी 1992 के सप्ताहांत में यह पुनः बढ़कर 868.8 हो गया। फरवरी और मार्च 1992 में शेयर बाजार में हुई अपूर्ण वृद्धि ने 28 मार्च 1992 को समाप्त सप्ताह तक सूचकांक की 1,485.4 तक पहुँचा दिया।

5.9 यद्यपि, 1991-92 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का औसत सूचकांक 776.2 पर 55.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, किन्तु बिन्दुवार आधार पर यह 30 मार्च 1991 के सप्ताहांत के 527.9 से बढ़कर 28 मार्च 1992 के सप्ताहांत में 1,485.4 हो गया जो 181.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5.10 उद्योगवार विवरण यह संकेत करते हैं कि 1991-92 के दौरान सभी औद्योगिक समूहों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई; तथापि, एल्यूमीनियम व मोटर वाहन और मोटर वाहन सहायक उद्योगों के शेयर मूल्यों में क्रमशः 97.3 और 99.3 प्रतिशत की कमी हुई। जहाजरानी समूह के शेयरों ने अन्य सभी समूहों को पीछे छोड़ दिया जिसमें 580.5 प्रतिशत की अनपेक्षित वृद्धि हुई; इसके बाद सीमेंट (344.2 प्रतिशत) और रबर तथा रबड़ से बनी वस्तुओं (268.9 प्रतिशत) के शेयरों में वृद्धि हुई।

5.11 वृद्धि के साथ-साथ शेयर मूल्यों में भी तीव्र उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। वर्ष 1991-92 के दौरान सामान्य शेयर मूल्यों के सूचकांक में निम्नलिखित का गुणांक 27.0 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के गुणांक (14.7 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक था। इस प्रकार, जो 948.5 था पिछले वर्ष (288.6) की तुलना में सूचकांक का फलाव कमी और अधिकता का अंतराल 3.7 गुना था।

5.12 शेयर बाजार की गतिविधियों के प्रमुख निवेशक : शेयर मूल्यों में अप्रमत्तपूर्व वृद्धि के अलावा, द्वितीयक बाजार की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि भी सभी प्रमुख निदेशकों में देखी गयी, जैसा कि बम्बई शेयर बाजार के आंकड़ों से उपलब्ध है, यथा कुल सेन-वेन, बाजार पूंजीकरण तथा मूल्य-अर्जन अनुपात। 1991-92 के दौरान औसत मासिक सेन-वेन 5,981 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष के (3,001 करोड़ रुपये) का लगभग दुगुना है। बम्बई शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 1992 के अन्त में 2,76,434 करोड़ रुपये (अन्तिम) का बाजार पूंजीकरण मार्च 1991 के अंत के (75,348 करोड़ रुपये) मुकाबले 3 1/2 गुना अधिक है। औसत मासिक मूल्य अर्जन अनुपात (30 प्रति-

शुक्तियों बम्बई शेयर बाजार के सूचकांक की गणना करने पर, आधार 1978-79-100) 1991-92 में 26.1 बढ़ा जबकि 1990-91 में यह 19.3 था। जनवरी 1992 से मूल्य अर्जन अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती रही है और मार्च 1992 के दौरान यह 44.3 के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचा।

5.13 सट्टा बाजार की तेज गतिविधियों में ठहराव : जनवरी-मार्च 1992 की पिछली तिमाही के दौरान शेयर मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि अप्रैल 1992 में भी जारी रही। इसकी प्रतिबिम्बित करते हुए, ईक्विटी मूल्यों का भा.रि.बैं. सूचकांक (प्राधार : 1980-81-100) 4 अप्रैल 1992 को समाप्त सप्ताह में 1,656.9 के अत्यधिक स्तर पर पहुँच गया चूंकि शेयर कारोबार और शेयर मोदे के वित्तपोषण में कतिपय अनियमितताओं के बारे में पता चलने से शेयर मूल्यों का यह उच्च स्तर नहीं बना रह सका। इसके परिणामस्वरूप, मई और जून 1992 में सट्टा बाजार में तेज प्रवृत्ति में एक सुधार किया गया और इसके कारण 27 जून 1992 को समाप्त सप्ताह में भा.रि.बैं. सूचकांक गिरकर 1,162.1 रह गया, जो 4 अप्रैल, 1992 के शीर्ष स्तर से 29.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, बम्बई शेयर बाजार 30 शेयर संवेदनशील सूचकांक (सेनसेक्स) (प्राधार 1978-79-100) 22 अप्रैल 1992 को 4,467.32 के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया परन्तु 26 जून 1992 को (महीने का अन्तिम कारो-बारी दिवस) गिरकर 3,080.54 पर आ गया, 21 अगस्त 1992 की पिछले सर्वोच्च स्तर से 32 प्रतिशत से ऊपर गिरकर यह 3,034.94 पर आ गया। 21 अगस्त 1992 को अंतिम 'सेनसेक्स' एक साल पहले के स्तर से 77.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार हाल ही के संशोधन बहुत मामूली से प्रतीत होते हैं यदि उन्हें 25 जनवरी 1992 को समाप्त सप्ताह तथा 4 अप्रैल 1992 को समाप्त सप्ताह के बीच हुई भा.रि.बैं. सूचकांक में 90.7 प्रतिशत की वृद्धि अथवा 24 जनवरी 1992 और 22 अप्रैल 1992 के बीच सेनसेक्स में हुई 108.8 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना की जाए। शेयर मूल्यों की प्रधोमुखी अपरिवर्तनीयता जिस प्रकार बाजार-प्रभूताओं और बाजार संरचना की भटोरताओं की प्रतिबिम्बित करती है, उसी प्रकार स्क्रिप्स की कमी को भी प्रतिबिम्बित करती है।

5.14 शेयर बाजार में सुधार : समीक्षाधीन वर्ष का अनुभव यह बताता है कि शेयर बाजार में सुधारों के लिए एक अच्छे समन्वित प्रयत्न की आवश्यकता है ताकि बाजार की अस्थिरता को कम किया जा सके। 'सेबी' को संवैधानिक बर्जा दिए जाने से, यह प्राशा की जाती है कि दलानों का रजिस्ट्रिकरण, सूचना प्रणाली, दलानों की पूंजीगत पर्याप्तता, संस्थागत सवस्थता, भुगतान प्रणाली और शेयरों के परोक्ष सेन-वेन का भीमता से और प्रभावी रूप से निपटान किया जाएगा।

5.15 राजकीय वर्ष 1992-93 की पहली तिमाही के दौरान पूंजीगत निर्गम उल्लेखनीय रूप से अधिक है, यह तथ्य इसका संकेत करता है कि निदेशकों का प्राथमिक बाजार में विश्वास कम रहा।

5.16 भारत में साख निर्धारण एजेंसियों—क्रिसिल : भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) ने 1991-92 के दौरान तेजी से प्रगति की है। क्रिसिल ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 5,866.5 करोड़ रुपये की मात्रा के ऋणों के 103 कंपनियों द्वारा जारी कों अनुमति देने पर विचार करना, प्रीमियम निर्धारित करने के साथ साथ, पूंजी निर्गमों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना और भारतीय कंपनियों के लिए, ईक्विटी/परिवर्तनीय धियेयरों को जारी करने की अनुमति देना, और इसके लिए कर संबंधी बड़ी रियायतें भी जाएं जो अपतटीय पारस्परिक निधियों के मामले में उपलब्ध है।

* इस तेजी की प्रवृत्ति में योगदान देने वाले बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं : वित्तीय आस्थिरता पर संपत्ति कर को समाप्त करना, निजी और संयुक्त क्षेत्रों की पारस्परिक निधियों सहित विशिष्ट पारस्परिक निधियों से प्राप्त आय को छूट से संबंधित प्रावधान के क्षेत्र में विस्तार करना, भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों

155 अणु लिखतों का साख निर्धारण किया, जबकि 1990-91 में इसमें 1,689.9 करोड़ रुपये की मात्रा के अणुओं के 46 कंपनियों द्वारा जारी 77 अणु लिखतों का साख निर्धारण किया था। सावधि जमा कार्यक्रमों पर, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिखतों के साख निर्धारण के अलावा क्रिसिल ने 56 वाणिज्यिक पत्र के कार्यक्रमों का भी साख निर्धारण किया जो 948 करोड़ रुपये की मात्रा के थे। क्रिसिल ने पहली बार 'ग्रॉटो लॉन्स' का भी निर्धारण किया तथा एक नयी लिखत (स्ट्रक्चर्ड ट्राबलीनेशन) का साख निर्धारण भी किया। 1988 में अपनी स्थापना के बाद क्रिसिल ने मार्च 1992 की समाप्ति तक 10,626 करोड़ रुपये के कुल अणुओं के 304 अणु लिखतों का साख निर्धारण किया। ये लिखत 228 कंपनियों द्वारा जारी किये गये थे जिनमें से 5 कंपनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। 1991-92 वर्ष के दौरान साख निर्धारण की संख्या में वृद्धि का कारण इस तथ्य को जाना है कि नियंत्रक पूंजी निर्गम/सेबी के मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार जनता को डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे साख निर्धारण करावें। क्रिसिल ने 58 कंपनियों के अणु मूल्यांकन को भी पूरा किया है। इन परिवर्तनों के अलावा क्रिसिल ने रेडिय एजेंसी मलेशिया बरहद को तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इसने मैलाट-इजराइली प्रतिभूतियों की साख निर्धारण कंपनी लिमिटेड को भी सहायता उपलब्ध करायी है तथा इसके स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए भी सहमति दी है।

5.17 भारतीय निवेश आसूचना तथा साख निर्धारण एजेंसी लिमिटेड : भारतीय निवेश आसूचना तथा साख निर्धारण एजेंसी लिमिटेड ने सितम्बर 1991 में अपने कार्यक्रमों पर शुरु किये और 31 मार्च, 1992 तक 24 कंपनियों (24 विनिर्माण तथा वित्तीय कंपनियाँ दोनों) द्वारा जारी 47 अणु लिखतों का साख निर्धारण किया जिनमें वित्तीय बाजार से जुटाये जाने वाले 1,161.8 करोड़ रुपये के अणु निहित हैं। ये साख निर्धारण 33 डिबेंचर निर्गमों (985.3 करोड़ रुपये), 11 सौदाही जमा कार्यक्रमों (104.5 करोड़ रुपये) तथा 3 वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रमों (72.0 करोड़ रुपये) के संबंध में थे। भारतीय निवेश आसूचना और साख निर्धारण एजेंसी लिमिटेड ने साख निर्धारण के अलावा साख मूल्यांकन तथा सामान्य मूल्यांकन सेवाएं उपलब्ध कराना भी शुरू कर दिया है।

6. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ

6.1 राजकोषीय वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय ग्रंथ व्यवस्था पर बाह्य भुगतान की वजह से आए अपूर्व संकट के गंभीर दबावों का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया जा चुका है। अगस्त 1990 का खाड़ी संकट, विश्व व्यापार में सार्वभौम गिरावट, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कुछ ऐसे विदेशी कारक थे

जिन्होंने भारत के भुगतान संतुलन पर अतिक्रमण किया। बाह्य स्थिति पर ये दबाव वर्ष 1991-92 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) के दौरान भी पड़े बने रहे, तथापि, इसके बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभित निधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, जहाँ 12 जुलाई 1991 को 975 मिलियन अमरीकी डालर (2,492 करोड़ रु.) की रह गयी थी मार्च 1992 के अंत में बढ़कर 5,631 मिलियन अमरीकी डालर (11,578 करोड़ रुपये) के स्तर तक पहुँच गयी। वर्ष के दौरान स्थिरीकरण और विन्यासात्मक समायोजन कार्यक्रमों के साथ-साथ किये गये अनेक संकटकालीन प्रबंधन उपायों के मिले-जुले प्रयासों से देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विशेषकर, आयातों के भारी संकुचन और पूँजी के प्रत्यावाही को प्रोत्साहित देने के लिए किये गये दृढ़ प्रयासों से इस प्रक्रिया को काफी सहायता मिली। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अणुवाताओं से भी भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी समर्थन मिला।

6.2 भुगतान संतुलन : वर्ष 1991-92 के लिए भुगतान संतुलन के अंतिम आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक और सूचना के अन्य स्रोतों के आधार पर "त्वरित अनुमान" लगाये गये हैं जो सारणी 6.1 और 6.2 में दिये गये हैं। इसमें पता लगता है कि दक्षिण व्यापार घाटे में 1990-91 के दौरान हुए 7,750 मिलियन अमरीकी डालर (13,906 करोड़ रु.) की तुलना में 3,078 मिलियन अमरीकी डालर (6,915 करोड़ रु.) की तीव्र कमी आयी। ऐसा विशेषकर आयातों पर कठोर नियंत्रण के कारण हुआ। जहाँ तक अवश्य आय, पाकिस्तानी और बंगला देशी नागरिकों सहित 1991-92 के दौरान पर्यटक आयमन पिछले वर्ष की 8.6 प्रतिशत की निरोध गिरावट की तुलना में 10.3 प्रतिशत अधिक रहा। अतः पर्यटक आय में अनुमानतः नामूली सी वृद्धि परिलक्षित होती है। विदेशी मुद्रा (उन्मुक्ति) योजना 1991 के अंतर्गत 863 मिलियन अमरीकी डालर के उच्चय के कारण 1991-92 के दौरान निजी अंतरण आय में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, विदेशों में कार्यरत अग्रवासी भारतीयों के ग्रन्थ प्रेषण जो कि निजी अंतरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है, पिछले वर्ष के प्रेषणों के बराबर ही रहने का अनुमान है। व्याज भुगतानों तथा रायन्टी, तकनीकी जानकारी आदि के लिए विदेश को धन प्रेषण में वृद्धि होनी रहेगी। कुल मिलाकर उपर्युक्त व्याज सहित अग्रुप्य प्राप्तियों से निवल आय और आधिकारिक अंतरणों सहित वर्ष 1990-91 से कुछ अधिक होने का अनुमान है। फिर भी, व्यापार घाटे में तीव्र कटौती के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अग्रवासी जमा राशियों पर उपर्युक्त व्याज सहित चालू लेखा घाटा पिछले वर्ष के 7,728 मिलियन अमरीकी डालर (13,865 करोड़ रु.) से घटकर 2,835 मिलियन अमरीकी डालर (6,251 करोड़ रु.) का रह गया। सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में, चालू लेखा घाटा 1.1 प्रतिशत है जो कि 1990-91 में 2.6 प्रतिशत था।

सारणी 6.1 : भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मार्ग	करोड़ रुपयों में			मिलियन अमरीकी डालर में		
	1991-92 (त्वरित अनुमान)	1990-91 (अनुमान)	1989-90	1991-92 (त्वरित अनुमान)	1990-91 (अनुमान)	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
अ. चालू लेखा						
1. निर्यात, पोतपर्यंत निर्यात	18,135	18,491	16,955	44,607	33,178	28,229
2. आयात, लागत बीमा भाड़ा	21,213	26,241	24,411	51,522	47,083	40,642
3. व्यापार शेष	-3,078	-7,750	-7,456	-6,915	-13,906	-12,413

1	2	3	4	5	6	7
4. चालू खाता शेष	--2,835	--8,424	--7,269	--6,251	--15,114	--12,102
भा. कुल पूंजीगत लेखा अ. मु. को. और वि. भा. अधि. अर्बंटन	6,409	7,146	6,529	16,092	12,821	10,870
ह. प्रारम्भित निधि और मौद्रिक स्वर्ण (घट +/बढ़-)	--3,574	1,278	740	--9,841	2,293	1,232

@मूल बूक सहित

परिशिष्ट सारणी 6.1 भी देखें।

सारणी 6.2: चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू लेखा लेनदेन

(प्रतिशत में)

सदें	1991-92 (स्वरित अनुमान)	1990-91 (अनस्तिम अनुमान)	1985-90 वार्षिक औसत	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87	1985-86	1980-85 वार्षिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. निर्यात	7.2	6.3	5.1	6.4	5.2	4.9	4.5	4.4	5.0
2. आयात	8.4	8.9	8.3	9.2	8.7	7.7	7.7	8.1	8.4
3. व्यापार घाटा	1.2	2.6	3.2	2.8	3.4	2.8	3.2	3.7	3.4
4. अदृश्य प्राप्तियां@	3.3	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	3.0	3.6
5. अदृश्य भुगतान	2.9	2.4	1.9	2.2	2.0	1.9	1.6	1.6	1.5
	(3.2)	(2.7)	---	(2.7)	(2.4)				
6. अदृश्य (निवल)	0.4	0.3	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	2.1
(4-5)@	(0.1)	(0.0)	---	(0.1)	(0.5)				
7. चालू लेखा घाटा	0.8	2.3	2.2	2.2	2.6	1.9	2.0	2.3	1.3
(3-6)@	(1.1)	(2.6)		(2.7)	(2.9)				

—उपलब्ध नहीं

@यहां आधिकारिक अनुमानों को जिन्हें चालू खाता प्राप्तियों के एक अंश के रूप में लिया गया है, सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े अनिवासी, भारतीय जमा राशियों पर उपरिष्ठ व्याज सहित प्रतिशत दर्शाते हैं। 1988-89 से पूर्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

6.3 अनिवासी भारतीयों से निधियों के संग्रहण और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वारंशताओं से उच्चतर सहायता लेकर पूंजीगत खाते को बनाया गया। वर्ष के दौरान अनिवासी खाता योजना के अन्तर्गत 1,627 मिलियन अमरीकी डालर (3,641 करोड़ रु.) का बहिर्गमन हुआ [जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 168 मिलियन अमरीकी डालर (255 करोड़ रु.) का आगमन हुआ था] जिसमें सर्वाधिक बहिर्गमन अप्रैल-जून 1991 के दौरान हुआ जो लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर का था। यह वह अवधि थी जिसमें पूर्णतः अनिश्चितता बनी हुई थी। जैसे ही स्थिरकरण के उपाय लागू किए गये 1991-92 के अन्तिम तिमाही में बहिर्गमन कम होकर 152 मिलियन अमरीकी डालर का रह गया। इस प्रकार यह अन्य योजनाओं के पक्ष में संविभागीय अंतरण को भी दर्शाता है। इसी प्रकार, भारत विकास बांड के लिए कुल अभिवान 1,627 मिलियन अमरीकी डालर का रहा। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता के अन्तर्गत होने वाले बड़ी मात्रा के बहिर्गमन की पूर्ति भारत विकास बांड द्वारा की गई जिसमें उनकी परिपक्वता अवधियों का बढ़ाने का प्रतिरिक्त लाभ भी था। विदेशी सहायता (जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान द्वारा दी गयी 1 बिलियन अमरीकी डालर की विशिष्ट सहायता शामिल नहीं है) का उपयोग 1990-91 के ही स्तर पर रहा। भारत विकास बांड के प्रतिरिक्त वाणिज्यिक उधार राशियां भी पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कम रही क्योंकि योग्यता

निर्धारण एजेंसियां ने भारत की योग्यता निर्धारण को निचले स्तर पर रखा। इस वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवल ऋण वर्ष 1990-91 के 1,214 मिलियन अमरीकी डालर (2,178 करोड़ रु.) (ट्रस्ट निधि अर्हण के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुकोतियों को छोड़कर) की तुलना में कम अर्थात् 781 मिलियन अमरीकी डालर (2,079 करोड़ रु.) पर रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये आहरणों में दूसरा आहरण जुलाई 1991 में हुआ जो 221 मिलियन अमरीकी डालर (570 करोड़ रु.) तथा तीसरा आहरण 637 मिलियन अमरीकी डालर (1,647 करोड़ रु.) सितम्बर 1991 को किया गया। ये आहरण क्षति-पूर्ति और आयात वित्त पोषण सुविधा के अन्तर्गत किये गये। साथ ही बैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नवम्बर 1991 में 117 मिलियन अमरीकी डालर (305 करोड़ रु.) और जनवरी 1992 में 263.59 मिलियन अमरीकी डालर (685 करोड़ रु.) के आहरण किये गये (सारणी 6.3)। परिशिष्ट सारणी 6.2 चालू लेखा घाटे के वित्तपोषण की पद्धति प्रस्तुत करता है, यह दर्शाता है कि 1991-92 में वित्तपोषण की पद्धति पिछले वर्षों की तुलना में किस प्रकार उल्लेखनीय रूप में पृथक् थी।

6.4 1991-92 के दौरान भारत सहायता संघ ने भारत के लिए 6.7 बिलियन अमरीकी डालर तक की सहायता का वचन दिया जिसमें से 2.3 बिलियन अमरीकी डालर सीधे-संवितरण वाले होंगे।

31 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1,656 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (2.2 बिलियन अमरीकी डालर) की ऊपरि ऋण श्रृंखला सहायक व्यवस्था को अनुमोदित किया जो अनुमोदन की तारीख के बाद 20 महीनों में किस्तों में उपलब्ध होगा। 85 मिलियन वि.भा.प्र. (117 मिलियन अमरीकी डालर) की पहली किस्त

आह्वरण नवम्बर 1991 में किया गया तथा 185 मिलियन वि.भा.प्र. (263.59 मिलियन अमरीकी डालर) की दूसरी किस्त जनवरी 1992 में आह्वित की गयी। जलाई 1992 में वि.भा.प्र. 462 मिलियन (663 मिलियन अमरीकी डालर) की तीसरी किस्त आह्वित की गई।

सारणी 6.3 विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के संकलन को प्रभावित करने वाले विशिष्ट घटक

वर्ष	(मिलियन अमरीकी डालर में)		(रुपयों में)	
	1991-92	1990-91	1992-93	1990-91
1	2	3	4	5
1. विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में परिवर्तन	3,395	-1,132	10,190	-1,399
2. विशिष्ट घटक	3,739	2,328	9,978	4,147
(क) विशिष्ट वित्त पोषण	935	—	2,257	
जर्मनी	60	—	151	
जापान	295	—	610	
एशियाई विकास बैंक	125	—	323	
विश्व बैंक	455	—	1,173	
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन*	498	1,636	1,339	2,927
विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को प्रभावित करने वाले निवल वि.भा.प्र. लेन देन				
(ग) अन्य योजनाएं	923	692	2,923	1,220
विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य)	304	262	742	485
जमा राशियां				
विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता	-1,627	168	-3,641	255
अनिवासी भारतीय बांड और अन्य जमा राशियां	9	262	21	480
भारत विकास बांड	1,374**	—	3,557	
उन्मुक्ति योजना	863	—	2,244	
(घ) स्वीप	1,383	—	3,459	
III. विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में परिवर्तन (I-II)	-344	-3,460	212	-5,546

*यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भिक्सायी तथा सरकारी लेखा में विशेष आह्वरण अधिकार की खरीद/बिक्री से विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में हुई परिवर्तन को दर्शाता है।

**भारत विकास बांड के अंतर्गत कुल एकत्रित राशि 1,627 मिलियन अमरीकी डालर में से 1,374 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में 1991-92 के दौरान जमा हुई।

टिप्पणी: वर्ष के दौरान मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण रुपये के मूल्य को प्रवृत्ति अमरीकी डालर के मूल्य के अनुरूप नहीं होगी।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि

6.5 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि: भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां (जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा प्राप्तियां भा.रि. बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा सरकार द्वारा धारित वि.भा.प्र. कोष राशियां शामिल हैं)। मार्च 1991 के अंत के 5,834 मिलियन अमरीकी डालर (11,416 करोड़ रु.) से बढ़कर मार्च 1992 के अंत में 9,220 मिलियन अमरीकी डालर (23,850 करोड़ रु.) हो गयीं जो 3,386 मिलियन अमरीकी डालर (12,434 करोड़ रु.) की वृद्धि दर्शाता है (देखें परिशिष्ट सारणी 6.3)। अगस्त 1991 के अंत की तुलना में, जब प्रारक्षित निधियों का स्तर गिरकर 4,624 मिलियन अमरीकी डालर (11,975 करोड़ रु.) हो गया था, मार्च 1992 के अंत का स्तर लगभग दुगुना था। मोने के पुनर्मूल्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन-देनों (व्यास निधि ऋणों के अलावा) को छोड़कर विदेशी

मुद्रा प्रारक्षित निधियों में 1990-91 में हुई 2,351 मिलियन अमरीकी डालर (3,560 करोड़ रु.) की गिरावट की तुलना में 1991-92 में 2,793 मिलियन अमरीकी डालर (8,637 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में 1990-91 में हुई 1,132 मिलियन अमरीकी डालर (1,399 करोड़ रु.) की गिरावट की तुलना में 1991-92 में 3,395 मिलियन अमरीकी डालर (10,190 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई। मार्च के अंत तथा जून 1992 के अंत के बीच, विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में 590 मिलियन अमरीकी डालर (या 1,547 करोड़ रु.) की वृद्धि आयी।

विशेष आह्वरण अधिकार

6.6 विशेष आह्वरण अधिकार: विशेष आह्वरण अधिकारों की धारिताओं में पिछले वर्ष के 6 मिलियन वि.भा.प्र. की गिरावट की तुलना में

1991-92 (अप्रैल-मार्च) में 10 मिलियन वि.घा.घ. की गिरावट आयी। 1991-92 में हुई गिरावट 225.0 मिलियन वि.घा.घ. के मूल के वि.घा.घ. के निवल भर्जन, 397.2 मिलियन वि.घा.घ. के अंतण, 337.5 मिलियन वि.घा.घ. की पुनः खरीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 218.7 मिलियन वि.घा.घ. (व्याज सम्बन्धी की छोड़कर) के प्रभार व्याज की भ्रष्टाचारी और 76.2 मिलियन वि. घा. घ. मूल्य के वि.घा.घ. की बिक्री का संयुक्त परिणाम थी। अप्रैल-जून 1992 के दौरान 14.4 मिलियन वि.घा.घ. की वृद्धि प्राथमिक तौर पर 120 मिलियन वि.घा.घ. के भर्जन के कारण 54.2 मिलियन वि.घा.घ. की पुनः खरीद द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी।

6.7 स्वर्ण : विसम्बर 1991 में भारत सरकार द्वारा भा.रि. बैंक को सोने की बिक्री (जिसका मूल्य 493.81 करोड़ रु. या 191 मिलियन डालर के बराबर था) के फलस्वरूप मार्च 1992 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं 9.039 करोड़ रु. (3,499 मिलियन डालर) हो गयीं जो सोने के स्टॉक में 18.36 टन (से 350.92 टन) तक की वृद्धि दर्शाता है।

6.8 अपनी प्रारक्षित निधि प्रबंधन नीति के अंत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक आफ इंग्लैंड और बैंक आफ जापान से 405 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए जुलाई 1991 में चार किस्तों में बैंक आफ इंग्लैंड को सोना (46.91 टन) गिरवी रखा गया था, जिससे सितम्बर से नवम्बर 1991 के बीच ऋणोत्पत्ति करके छुड़ा लिया गया। इससे पहले, मई 1991 में, सरकार ने जस्ट किया गया सोने में से 19.99 टन भारतीय स्टेट बैंक को पट्टे पर दे दिया जिसे बाद में पुनः खरीद के विकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त सोने को नवम्बर/दिसम्बर 1991 में पुनः क्रय कर लिया जिसमें से 18.36 टन जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बाद में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को बेच दिया। शेष 1.63 टन स्वर्ण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखा गया। दोनों लेन-देनों में शामिल भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं 65.27 टन हैं जो फिलहाल विदेश में रखी गयी हैं।

6.9 जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, विदेशी मुद्रा आस्तियां, जो 12 जुलाई 1991 को 975 मिलियन अमरीकी डालर (2,493 करोड़ रु.) के निम्न स्तर तक पहुँच गयी थीं, मार्च 1992 के अंत तक बढ़कर 5,631 मिलियन अमरीकी डालर (14,578 करोड़ रु.) हो गयीं। पूर्वोक्त दो विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आबक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त उधार तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजें-

सियों द्वारा प्रदान की गयी तीव्र संवितरण सहायता से प्रारक्षित निधि के सृजन में मदद की। उक्त लेन-देनों में शामिल राशि को घटाने के बाद भी 1 बिलियन डॉलर का आबक बांध बचता है। यह पण्य व्यापार और अदृश्य राशियों के खाते में प्राप्तियों और भुगतानों (प्रतिरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशियों को छोड़कर) की निवल स्थिति दर्शाता है। प्राधिकृत व्यापारियों के साथ हुए भा.रि. बैंक के लेन-देनों से भी इसकी संपुष्टि हो गयी है। 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि में भा.रि. बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों से 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (5,215 करोड़ रु.) की निवल खरीद की, जबकि पिछले 12 माह की अवधि में 5.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (10,358 करोड़ रु.) की निवल बिक्री हुई, इस प्रकार 7.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का पण्यवर्त हुआ। ये विनियम दर में कमी की आशा खंडित होने के पश्चात् निर्वात प्राप्तियों और आबक प्रवणों का तीव्रतर पुनः प्रत्यावर्तन दर्शाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है अमरीकी डॉलर रुपये दर की स्थिरता तथा निर्यातों एवं आयातों के बिलपोषण मद्तिन व्याज दरों में वृद्धि का विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को उसने व्यापक आगमन में परिवर्तित करने पर जोरदार अंतर पड़ा।

6.10 पण्य व्यापार : राजकोषीय वर्ष 1991-92 में व्यापारिक शेष में उल्लेखनीय सुधार आया जिसमें मुख्यतः आयातों के अत्यधिक संकुचन का योगदान है। वर्ष के दौरान डॉलर के रूप में आयातों में पिछले वर्ष के 13.2 प्रतिशत की वृद्धि के ठीक विपरीत 19.4 प्रतिशत की गिरावट आयी। यदि निर्यातों में गिरावट नहीं आयी हुई होती तो व्यापार घाटा और अधिक कम हो गया होता। विदेश व्यापार के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार घाटा शेष 1990-91 के 5,930 मिलियन डॉलर या 10,640 करोड़ रु. से काफी घटकर 1,556 मिलियन डॉलर या 3,835 करोड़ रुपये रह गया। कुल घाटे को "तेल" और "तेल से इतर" घाटों में विभक्त करने से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। "तेल से इतर घाटा" जो 1990-91 में 425 मिलियन डॉलर या 762 करोड़ रु. था, 1991-92 में 3,394 मिलियन डॉलर या 8,272 करोड़ रु. के अतिरिक्त में बढ़ल गया जो कठोर आयात संकुचन उपायों के प्रभाव को दर्शाता है। इसके विपरीत, "तेल घाटा" 1990-91 के 9,878 करोड़ रु. से 22.6 प्रतिशत बढ़कर 1991-92 में 12,107 करोड़ रु. हो गया जो फिलहाल, रुपये के बाह्य मूल्य में अधोमुखी समायोजन के कारण हुआ, डॉलर के रूप में "तेल घाटा" में 10.1 प्रतिशत की कमी आयी और वह 5,505 मिलियन अमरीकी डॉलर से 4,950 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। "तेल से इतर घाटा" में मौजूद अतिरिक्त ने तेलखान में मौजूद घाटे को आंशिक रूप से कम कर दिया ताकि कुल घाटे को निम्न स्तर पर रखा जा सके (सारणी 6.4)।

सारणी 6.4 : भारत का विदेश व्यापार

वर्ष	मिलियन अमरीकी डॉलर			करोड़ रुपये में		
	1991-92	1990-91	1989-90	1991-92	1990-91	1989-90
	(घ)	(घ)	(घ)	(घ)	(घ)	(घ)
1	2	3	4	5	6	7
1. निर्यात	17,840 (-1.7)	18,143 (9.1)	16,626 (19.0)	43,978 (35.1)	32,553 (17.6)	27,681 (36.8)
कच्चा तेल	—	—	—	—	—	—
पेट्रोलियम, तेल, चिकनाई के पदार्थ	415 (-20.7)	523 (24.9)	418 (20.0)	1,022 (9.0)	938 (34.6)	697 (38.0)
तेल से इतर	17,425 (-1.1)	17,620 (8.7)	16,208 (19.0)	42,956 (35.9)	31,615 (17.2)	26,985 (36.8)

1	2	3	4	5	6	7
2. आयात	19,36	24,073	21,272	47,813	43,193	35,416
	(-19.4)	(13.2)	(9.1)	(10.7)	(22.0)	(25.4)
तेल और पेट्रोलियम तेल तथा चिकनाई के पदार्थ	5,365@	6,028	3,768	13,129	10,816	6,274
	(-11.0)	(60.0)	(25.2)	(21.4)	(72.4)	(44.0)
तेल से इतर	14,031	18,045	17,504	34,684	32,377	29,142
	(22.2)	(3.1)	(6.2)	(7.1)	(11.1)	(22.0)
3. व्यापार शेष	-1,556	5,930	-4,646	-38,835	-10,640	-7,735
तेल शेष	-4950	-5,505	-3,350	-12,107	09,878	-5,577
तेल से इतर	+3,394	-425	-1,296	+8,272	-762	-2,157

+ (अ) अन्तिम

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी VI.4 की देखें।

2. डी.जी.सी.आई.एस. से वर्ष 1989-90 के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए।

3. कोष्ठकों में आंकड़े पिछले वर्ष पर प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

@आधिकारिक औसत विनिमय दर का प्रयोग करके अमरीकी डालर में परिवर्तित। अन्य पथों के लिए मार्च 1992 के समग्र औसत विनिमय दर का प्रयोग किया गया है।

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस.।

6.11 चार वर्ष तक लगातार निर्यात के आधार में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने के बाद, 1991-92 में निर्यात में मंदी रही। डालर के रूप में निर्यातों में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आयी, हालांकि रुपये के रूप में विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण उनमें 35.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देशी और बाह्य दोनों कारकों ने निर्यात को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित था। आंतरिक कारकों में अन्य बातों के साथ साथ आयात संकुचन उपाय और कठोर मौद्रिक नीति लागू करना शामिल है। वर्ष के आरंभिक चरण में आर्थिक क्षेत्र में मीजूस सामान्य अनिश्चितता तथा 1992-93 के केन्द्रीय बजट से पूर्व सीमाशुल्क की दरों में कटौती की आशा से विदेश व्यापार संबंधी कार्यकलापों की गति धीमी रही। बाह्य कारक प्रमुख विकसित देशों, विशेषतः अमरीकी और यू.के. में मंदी की स्थितियों, विश्व व्यापार की वृद्धि में 1989 के 7.3 प्रतिशत और 1990 के 4.2 प्रतिशत से 1991 में 0.9 प्रतिशत की गिरावट और पूर्व सोवियत संघ के विघटन से संबंधित थे जिन्होंने इस क्षेत्र में भारत के व्यापार को अत्यन्त विघटित किया।

6.12 परिशिष्ट सारणी 6.5 और 6.6 में प्रमुख वस्तुओं और पथों के तीन वर्षों के क्रमशः निर्यात और आयात प्रस्तुत किए गये हैं।

6.13 रुपया भुगतान क्षेत्र और सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार : जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है पहले से सोवियत संघ के साथ व्यापार के अत्यन्त विघटित होने के कारण 1991-92 में निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रुपया भुगतान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीन देशों अर्थात् सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया तथा भारत के बीच होने वाले कुल व्यापार पण्यवर्त का 95 प्रतिशत सोवियत संघ के साथ होता था। रुपया भुगतान क्षेत्र में 1991-92 में निर्यात में डालर के रूप में 42.5 प्रतिशत की तथा रुपये में 21.0 प्रतिशत की गिरावट आयी। साथ ही, 1991-92 में पिछले वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था की तुलना में, डालर के रूप में रुपया भुगतान क्षेत्र के साथ कुल व्यापार पण्यवर्त (निर्यात जमा आयात) में 45.2 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

6.14 रुपया भुगतान क्षेत्र में निर्यात की मात्रा में इतनी सुनिश्चित गिरावट आयी कि 1991-92 में कुल निर्यात में 1.7 प्रतिशत (डालर के रूप में) की गिरावट आयी हालांकि सामान्य मुद्रा क्षेत्र को किय गये निर्यात

(कुल निर्यात "घटा" रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात) में हमी अवधि में 6.6 प्रतिशत की घनात्मक वृद्धि हुई थी। (परिशिष्ट सारणी 6.7)।

6.15 भारत सोवियत संघ व्यापार समझौता : वर्ष 1991 में भारत सोवियत संघ व्यापार संधि (सोवियत संघ के विघटन के पूर्व) में कुल 9,411 करोड़ रु. के व्यापार पण्यवर्त की परिकल्पना की गयी थी जिसमें से सोवियत संघ को 5,081 करोड़ रु. का निर्यात और सोवियत संघ से 4,330 करोड़ रु. का आयात किया जाना था। इस लक्ष्य की तुलना में, 1991 में वास्तुतः कुल 6,413 करोड़ रु. का व्यापार पण्यवर्त हुआ—सोवियत संघ को 4,164 करोड़ रु. का निर्यात और वहां से 2,249 करोड़ रु. का आयात। भारत के आयातों (2,081 करोड़ रु. या 48.1 प्रतिशत) से निर्यातों (917 करोड़ रु. या 18.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक कमी आयी।

6.16 अन्तिम आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भूतपूर्व सोवियत संघ को निर्यात में 1991-92 के राजकोषीय वर्ष के दौरान, 1,287 करोड़ रुपये की कमी होकर यह 3,967 करोड़ रुपये का रह गया। निर्यात में इस कमी का कारण कृषि और संबद्ध उत्पादों में 838 करोड़ रुपये की तेज गिरावट थी। 1991-92 के दौरान कुल आयात 1,780 करोड़ रुपये के हुए, जबकि 1990-91 में यह 2,548 करोड़ रुपये के हुए थे जो 768 करोड़ रुपये की गिरावट दर्शाते हैं। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों सहित "अन्य" वस्तुओं के अंतर्गत आयातों में 708 करोड़ रुपये की कमी होकर 1991-92 में ये 1,000 करोड़ रुपये के रह गये, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम तथा चिकनाई के आयातों में तेज गिरावट को दर्शाते हैं। अलौह धातुओं के आयातों में भी 108 करोड़ रुपये की कमी होकर 1991-92 में ये केवल 5 करोड़ रुपये के रह गये।

6.17 विघटन के पश्चात्, पहले से सोवियत संघ के देशों में कामन-वेल्थ ऑफ इंडीपेंडेंट स्टेट्स द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अब तक, भारत तथा कामनवेल्थ ऑफ इंडीपेंडेंट स्टेट्स के छः गणतंत्रों (अर्थात् रूसी संघ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान) के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहायता संबंधी करार किये गये हैं। सभी गणतंत्रों ने स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मूद्राओं में भुगतान करने का विकल्प दिया है। जहाँ तक स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के अन्य सभी शेष

गणतंत्रों के साथ व्यापार का संबंध है, जिनके साथ व्यापार तथा इनके बीच पूरी की जानेवाली संबंधित देशों की विधियों और उनके विधियों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूरी की जाएगी। भारत तथा कामनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के गणतंत्रों के बीच करार के सामान्य फार्म में इस बात का प्रावधान है कि व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग के सभी मामलों में वे प्रत्येक को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र का स्थान देंगे।

6.18 भारत सरकार और रूसी संघ के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर नया करार 22 फरवरी 1992 को भारत और रूसी संघ के बीच व्यापार और भुगतान संधि हुई। इस करार में द्विपक्षीय आधार पर तथा भुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार का प्रावधान किया गया है और इसके आधार पर दो देशों के बीच वर्ष 1992 के दौरान माल की निर्धारित सूची के अनुसार संतुलित आधार पर व्यापार किया जाएगा। व्यापार संधि के अंतर्गत व्यापार करने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार किये जाने और करार में परिणामी संशोधन होने तक दोनों सरकारों के बीच 5 मई 1992 को एक समझौता आपन पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें भारत सरकार भारत से निम्नलिखित माल के निर्यात के लिए 85 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के तकनीकी ऋण के रूसी संघ द्वारा अधिम उपयोग पर सहमत हुई, अर्थात् चाय (32 मिलियन डॉलर), काफी (15 मिलियन डॉलर), तम्बाकू (25 मिलियन डॉलर), काली मिर्च मसाले सहित (2 मिलियन डॉलर), मिमरेट (4 मिलियन डॉलर), वसाएं (3 मिलियन डॉलर) तथा फलों के जॉम (4 मिलियन डॉलर) रूस से 15 मई के आयात किये गये। उक्त माल के आयात और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा अमरीकी डॉलर में पूरी की गयी संबंधों के आधार पर किये जाएंगे। तथापि, व्यापारिक संधि के अंतर्गत व्यापारिक लेनदेनों के लिए भारत से/को अमरीकी डॉलर की कोई निकासी/प्राप्त नहीं होगी।

6.19 कुल 2,200 मिलियन अमरीकी डॉलर के पण्यावर्त (अर्थात् दुर्लभ व्यापार में प्रत्येक (1100 मिलियन डॉलर) के अलावा, उक्त साध में दोनों पहले की प्रत्येक की ओर से अपने अंतर्गत प्रतिपक्षी व्यापार, पण्य विनिमय, वस्तुविनिमय, वापस-खरीद परिचालनों, या अन्य किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से साम्यताप्राप्त व्यावसायिक सहयोग के आधार पर माल और सेवाओं के आयात और निर्यात की स्वतंत्रता का प्रावधान है।

6.20 बाह्य सहायता: 1991-92 में बाह्य सहायता के प्रावक में वृद्धि हुई। 4,527 मिलियन अमरीकी डॉलर (11,078 करोड़ रुपये) की ऋण और अनुदानों का सकल उपयोग 1990-91 के 3,736 मिलियन अमरीकी डॉलर (6,704 करोड़ रु.) की तुलना में 791 मिलियन अमरीकी डॉलर (4,374 करोड़ रु.) अधिक था। परिणामतः भुगतानों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही तथा वह पिछले वर्ष के 1298 मिलियन अमरीकी डॉलर (2,329 करोड़ रु.) की तुलना में 1991-92 के दौरान 1455 मिलियन अमरीकी डॉलर (3,559 करोड़ रु.) हो गया। वर्ष के दौरान विदेशी सहायता का निवल प्रावक 634 मिलियन अमरीकी डॉलर (3,144 करोड़ रुपये) बढ़कर 3,072 मिलियन अमरीकी डॉलर (7,519 करोड़ रुपये) हो गया (परिशिष्ट सारणी 6.8)। यद्यपि इस वृद्धि में अववादात्मक वित्तपोषण के अंतर्गत किये गये संश्लेषण शामिल हैं, जिसकी भुगतान संतुलन के समर्थन के रूप में व्यवस्था की गयी थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, जापान ने 295 मिलियन डॉलर (610 करोड़ रु.), जर्मनी ने 60 मिलियन अमरीकी डॉलर (151 करोड़ रु.) एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर (323 करोड़ रु.) और संरचनात्मक समायोजन ऋण के अंतर्गत विश्व बैंक ने 455 मिलियन डॉलर (1,173 करोड़ रु.) की राशि प्रदान की।

1317 GI/93—10

6.21 अनिवार्य (विदेशी) रुपया और विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खातों में वृद्धि: अनिवार्य (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत, 1991-92 के अंतर्गत आंकड़े 1990-91 के 87 मिलियन अमरीकी डॉलर (156 करोड़ रुपये) के प्रावक की तुलना में 27 मिलियन अमरीकी डॉलर (44 करोड़ रुपये) (अनुमानित व्याज तथा की छोड़कर) कार्य आह्वान सूचित करने हैं। तथापि, गिरावट का अनिवार्यतः यह तात्पर्य नहीं है कि विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ। यह खाता काफी सीमा तक भारत में रह रहे अनिवार्यता भागीदारों के स्थानीय व्यय पूरे करने के लिए रखा जाता है। तथापि, विदेशी मुद्रा (अनिवार्य) खाता के अंतर्गत 1990-91 में 168 मिलियन डॉलर 255 करोड़ रुपये के प्रावक की तुलना में 1991-92 में 1,627 मिलियन डॉलर (3,641 करोड़ रुपये) की बढ़ी राशि का बहिर्गमन हुआ (परिशिष्ट सारणी 6.9)। हालांकि, पश्चिमी निमाही में (अप्रैल-जून 1992) काफी बहिर्गमन हुआ, कई नीतिगत मुद्दों के बाद जूलाई, 1991 से उनमें कमी आयी। जून, 1991 में शुरू की गयी विदेशी मुद्रा (माध्यम प्रत्यावर्तनीय) योजना के अंतर्गत 1991-92 में 5 मिलियन डॉलर का प्रावक हुआ।

6.22 परिशिष्ट सारणी 6.9 बताती है कि मार्च, 1992 के अंत में अनिवार्य जमा राशियां 7,847 मिलियन अमरीकी डॉलर या 21,679 करोड़ रुपये की रहीं जिनमें—निवासी (विदेशी) रुपया खाता के अंतर्गत 2,591 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा विदेशी मुद्रा—निवासी खाता के अंतर्गत 5,256 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी जो क्रमशः 8,071 करोड़ रुपये और 13,688 करोड़ रुपये के समतुल्य हैं।

6.23 1990-91 के दौरान देश ने जो विदेशी मुद्रा के संकट को झेला उस पर काबू पाने के दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 1990 में विदेशी मुद्रा (बैंक तथा अन्य) जमा योजना के नाम की एक नयी योजना शुरू की। इस योजना की शर्तें विदेशी मुद्रा अनिवार्यता योजना की शर्तों के समान ही हैं। केवल इसमें दो अंतर हैं अर्थात्: (1) विदेशी मुद्रा (बैंक तथा अन्य) जमा योजना भी विदेशी नागरिकों/बैंकों अथवा अन्य संस्थाओं के लिए खुली है जबकि पहली योजना अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खाता योजना केवल अनिवार्यता भागीदारों/विदेशी नियमित निकायों के लिए ही खुली है तथा (2) इस योजना की परिपक्वता अवधि के पहले आह्वान करना बिल्कुल मना है।

6.24 विदेशी मुद्रा (बैंक तथा अन्य) जमा योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान निवल आगम राशि 304 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गई, जबकि गत वर्ष के दौरान यह 262 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। चातुर्विध वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रैल-जून के दौरान इस योजना के अंतर्गत यह आगम 1,237 मिलियन अमरीकी डॉलर तक हो गया और यह गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 77 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि से काफी अधिक था। इस योजना को 31 जूलाई, 1992 से प्रत्यापी रूब से स्थगित कर दिये जाने के समय इसके अंतर्गत वसूली राशि 2,232 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।

6.25 व्याज दरें—निवासी जमा राशियां: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्याज दर के घटबढ़ की प्रवृत्तियों की ध्यान में रखते हुए 1991-92 में विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खाता योजना के अंतर्गत जमा राशियों पर व्याज दरों में तीन बार (अर्थात् पिछले दो बारों को तुलना में कम बार संशोधन किये गये। तथापि राजकोषीय वर्ष 1992-93 के प्रारंभ से, व्याज दरों में कुछ और परिवर्तन किये गये हैं। परिशिष्ट सारणी 6.10 में आलोच्य अवधि में विभिन्न मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खाता जमा राशियों पर व्याज दरें दी गयी हैं। अनिवार्यता (बाह्य) रुपया खाते में व्याज दरों की पिछली बार 13 अप्रैल, 1991 को संशोधित किया गया।

6.26 विदेशी ऋण: भुगतान संतुलन के चालू खाते में सामान्यतः बढ़ते हुए घाटे के कारण भारत की विदेशी ऋण देयताएं, जिनमें बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय सहायता, वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां शामिल हैं, वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ती रही हैं। भारत का माध्यमिक और दीर्घावधिक ऋण अर्थात् जिनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक रही है तथा इसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां शामिल नहीं हैं, मार्च, 1992 के अंत में 57.6 बिलियन अमरीकी डालर (1,71,305 करोड़ रुपये) बैठती हैं जबकि मार्च, 1991 के अंत में ये 51.7 बिलियन अमरीकी डालर (1,00,466 करोड़ रुपये) में (परिणिष्ट सारणी 6.11)। अनिवासी भारतीयों की सभी परिपक्वता अवधियों की जमा राशियां और व्यापार उधार के स्वरूप के अल्पकालिक ऋण, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण (एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले), बैंकों की स्वीकृति सुविधा के अंतर्गत ऋण, आदि को शामिल करते हुई भारतीय बाह्य ऋण देयताएं मार्च, 1992 के अंत में 68.8 बिलियन अमरीकी डालर (2,01,671 करोड़ रुपये) बैठती हैं जबकि पिछले वर्ष की समाप्ति पर ये 67.1 बिलियन अमरीकी डालर (1,30,638 करोड़ रुपये) थीं। रूपों की दृष्टि से ऋण में वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग प्रमुख मुद्राओं की तुलना में छोटे के निम्नमुखी समायोजन के कारण हुआ जिसे जुलाई, 1991 में और मार्च 1992 में उधार विनियम दर प्रबंधन योजना को प्रारम्भ करने के कारण किया गया।

6.27 चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संबंध में मध्यावधिक और दीर्घावधिक बाह्य ऋण और अ.प्र.भा. जमा राशियां मार्च, 1992 के अंत में बढ़कर 31.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि मार्च, 1991 के अंत में यह 33.4 प्रतिशत था। यह अनिवार्यतः ऊपर उल्लिखित रुपये के अवमूल्यन को दर्शाता है। निर्यात के मुकाबले ऋण (उपरोक्त पारिभाषिक) अनुपात मार्च, 1991 के अंत में 259 प्रतिशत के लगभग था और यह बढ़कर मार्च 1992 के अंत में 303 प्रतिशत के लगभग पहुँच गया। ऋण सेवा अनुपात (अर्थात् प्राधिकारिक अंतरणों को छोड़कर माल और सेवाओं के निर्यात से ऋण की चुकौतियों का अनुपात जिसमें अनिवासी जमा राशियों पर व्याज शामिल नहीं है) 1991-92 के दौरान 26.2 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है जबकि 1990-91 में यह 25.2 प्रतिशत था, यह 1991-92 के दौरान प्राणिक रूप से निर्यात आयों में गिरावट को दर्शाता है।

6.28 उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिज़र्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में भारत के मध्यावधिक और दीर्घावधिक विदेशी ऋण के संबंधी सांख्यिकी प्रकाशित करता आ रहा है। भारत सरकार और विदेशी एजेंसियां भी इसी प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती रही हैं। तथापि परिभाषाओं और व्याप्तियों में अन्तर होने के कारण आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों में ऋण के घटकों और उनके जोड़, दोनों में, अन्तर देखा गया है। आंकड़ों के विभिन्न समूहों का समाधान करने, ऋण सांख्यिकी की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने तथा एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत की विदेशी ऋण सांख्यिकी की व्याप्ति, परिभाषा और वर्गीकरण के अध्ययन के लिए एक नीति-निर्धारक समूह नियुक्त किया, जिसकी सहायता एक कार्यदल ने की। दोनों समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। इन समूहों द्वारा सुझाये गये परिभाषा और वर्गीकरण के अनुसार, मार्च, 1991 के अंत में अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों (एक वर्ष की परिपक्वता अवधि से अधिक) सहित भारत का दीर्घावधिक और मध्यावधिक विदेशी ऋण 57,295 मिलियन अमरीकी डालर (1,10,715 करोड़ रुपये) का था। अल्प कालिक ऋण 5,839 मिलियन अमरीकी डालर (11,283 करोड़ रुपये) का था। सुझाये गयी परिभाषा के अनुसार अल्पकालिक ऋण में अनिवासी भारतीयों की एक वर्ष तक की जमा राशियां शामिल हैं,

लेकिन 180 दिनों तक की अवधि के लिए दिए गए सभी व्यापारिक ऋण इस ऋण में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सामान्य व्यापार ऋण माना गया है। उपर्युक्त कुल ऋण में 1,669 मिलियन अमरीकी डालर (2,559 करोड़ रुपये) का रुपया/बल द्विपक्षीय ऋण तथा 34 मिलियन अमरीकी डालर (67 करोड़ रुपये) की रुपया आपूर्तिकर्ता ऋण शामिल नहीं है क्योंकि न ऋण के कारण प्रारंभित निधि से विकासो नहीं हो है। नयी परिभाषा के आधार पर इस दल ने दिसम्बर, 1991 के अंत के आंकड़े भी संकलित किये। मध्य और दीर्घ अवधि के ऋण दिसम्बर, 1991 के अंत में 61,050 मिलियन अमरीकी डालर (1,57,345 करोड़ रुपये) और अल्पावधि ऋण 5010 मिलियन अमरीकी डालर (12,912 करोड़ रुपये) थे। मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण में 1,227 मिलियन अमरीकी डालर (3,161 करोड़ रु.) और 22 मिलियन अमरीकी डालर (56 करोड़ रु.) का रुपया आपूर्तिकर्ता का ऋण शामिल नहीं है।

6.29 रुपये की विनिमय दर: समीक्षाधीन वर्ष में रुपये के विनिमय दर के संबंध में नीति में काफी परिवर्तन हुए। सर्व प्रथम रुपये की दर का 1 और 3 जुलाई, 1991 को दो बार निम्न सूची समायोजित किया गया। मध्यम्य मूद्रा अर्थात् पीड स्टैबिलि की दृष्टि से रुप के 2 निम्न-गुणी समायोजन 17.38 प्रतिशत बैठते हैं। उसके पश्चात् रुपये की विनिमय दर को रुपया अमरीकी डालर दर के रूप में 26 रुपये प्रति डालर पर निर्धारित किया गया।

6.30 दूसरे, 1992-93 के लिए वज्रत भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार 1 मार्च, 1992 से उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के रूप में रुपये की प्राणिक परिवर्तनीयता लाभ की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत चालू खाते के लेनदेनों में (निर्यात, प्रेषण आदि) प्राप्त सभी विदेशी मुद्राओं को प्राधिकृत व्यापारियों को अब तक की तरह पूर्ण रूप में सौंपना अपेक्षित है। इन लेनदेनों के लिए विनिमय दर आय के प्रतिशत विदेशी मुद्रा को छोड़कर जिस पर कि भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राधिकारिक दर लागू होगी, प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उद्धृत मूल्य बाजार की दर होगी। इसके बवले में प्राधिकृत व्यापारी चालू खाते की प्राणियों की अपनी सभी विदेशी मुद्राओं की खरीद के 40 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित प्राधिकारिक विनिमय दर पर सौंपने उन्हें जोष 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा रखने की छूट होगी जिसे वे स्वीकार्य लेनदेनों के लिए मुक्त बाजार में बेच सकेंगे।

6.31 वे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने की आवश्यकता समझते हैं अथवा विदेश जाना चाहते हैं उन्हें उदारीकृत व्यापार और विदेशी मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों से यात्रा निर्धारित दरों पर विदेशी मुद्रा खरीदनी होगी।

6.32 वृद्ध विणिष्ट प्राथमिकता प्राप्त आयातों और लेनदेनों के संबंध में उक्त योजना में ये प्रावधान किये गये हैं कि उन्हें प्राधिकारिक दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाए। इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकारिक दर पर प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की विक्री केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगा, (i) विणिष्ट वस्तुओं के आयात जिसमें सरकारी विभागीय आवश्यकताएं, खनिज तेल, हील, मिट्टी का तेल और उर्वरक शामिल हैं, जैसा कि प्राथिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, (ii) 29 फरवरी 1992 तक एजिसम स्क्रिप का उपयोग न किये जाने के कारण उसके अंतर्गत किये गये आयात तथा (iii) लाइसेंसों के अंतर्गत जीवन रक्षक औषधियों और उपकरणों के आयात।

6.33 ग्रिमि लाइसेंसों के अंतर्गत किये जानेवाले आयातों और विदेश अग्रदाय साइडिंगों के लिए तथा रस्त और आसुधों के निर्यात के लिए

कच्चे माल की प्रतिपूर्ति के लिए किये जाने वाले आयातों के लिए मूल्य के 10 प्रतिशत तक प्राधिकारिक दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। भेष-अपेक्षा के लिए, विदेशी मुद्रा की खरीद मुक्त बाजार दर पर करनी होगी।

6.34 वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों तथा परिवर्तनीय मुद्राओं में आयात प्रेषणों के अन्य प्राप्तिकर्ताओं को यह अनुमति है कि वे भारत स्थित वैश्व में अपने विदेशी मुद्रा खातों में प्राप्ति के 15 प्रतिशत तक की राशि उस राशि में से रख सकते हैं जो उन्हें बाजार दर पर प्राधिकृत व्यापारियों को सौंपी है।

6.35 1991-92 के प्रथम 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) के दौरान पीर स्टैलिंग और रुपये के परिवर्तन दर को 290 बार संशोधित किया गया जबकि इससे पहले पूरे वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान इसमें 282 बार संशोधित किये गये थे। उसके बाद जब अमरीकी डालर मध्यस्थ मुद्रा हो गयी तो अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की खरीद और बिक्री की दरें क्रमशः 100 रुपये-3,8720 अमरीकी डालर और 100 रुपये-3,8530 अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रखी गयी हैं।

6.36 रुपया-रुबल की दर की समस्या का विशेषकर रूसी संघ को बचाया जून के निपटान के संधि में समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। अभी तक चुकौतियों के लिए रुपया-रुबल की दर 1978 की

व्यापार संधि के अनुसार निश्चित की जानी थी। तथापि, रुपया-रुबल, रुपया-डालर और डालर-रुबल की बित्तिय दरें ऐसी थी कि उनकी प्रति दरों को उचित रूप से समन्वय नहीं किया गया था। रूसी संघ अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य बन गया है और उसे अपनी बित्तिय दर घोषित कर दी है जो अतः अब रूसी संघ को बचाया जून की चुकौती हेतु एक अधिक वास्तविक रुपया-रुबल दर निर्धारित कर देने की आवश्यकता है।

6.37 मुक्त बाजार में रुपये की बित्तिय दर को प्रवृत्ति को देखते हुए आंशिक गव्हर्नोयता लागू करने समय यह सोचा गया था कि रुपये के लिए बाजार बित्तिय दर प्राधिकारिक दर में 15 प्रतिशत के लगभग घट-बढ़ करेगी और ज्यादा में ज्यादा 20 प्रतिशत तक। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की सार्वजनिक दलों का विशेषण करने पर यह पाया गया कि रुपये अमरीकी डालर बित्तिय दर कर और बिक्री का औसत जो 3 मार्च 1992 को 29,1971 रुपये प्रति अमरीकी डालर पर खुली, 24 मार्च 1992 को निरंतर गिरकर 31,4713 रुपये पर पहुँच गया जो प्राधिकारिक दर में इस दर का अंतर 21.55 प्रतिशत के लगभग दर्शाता है। (सारणी 6.5)। इसके पश्चात् बाजार दर में मई के महीने में सुधार हुआ और जून 1992 के महीने में यह स्थिर बनी रही। इस अवधि के दौरान अधिकारिक दर और बाजार दर के बीच का अंतराल 17 से 18 प्रतिशत के सीमित दायरे में घटता-बढ़ता रहा।

सारणी 6.5 रुपये की बित्तिय दर, संबंधी गतिविधियाँ

(रुपये प्रति अमरीकी डालर)

तारीख	भारतीय रिजर्व बैंक दर	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की सार्वजनिक दर	कॉलम (3) और कॉलम (2) के बीच अंतर (प्रतिशत)	भारतिका दर ((ii))
1	2	3	4	5
28 फरवरी 1992	26,0382	—	लागू नहीं	
3 मार्च 1992	25,8906	29,1971 (-10.82)	12.77	27,8745 (-6.59)
24 मार्च 1992	25,8900	31,4713 (-17.26)	21.56	29,2389 (-10.95)
31 मार्च 1992	25,8900	31,2256 (-16.61)	20.61	29,0314 (-10.50)
30 अप्रैल 1992	25,8900	30,6138 (-15.95)	18.25	28,7243 (-9.35)
29 मई 1992	25,8900	30,5577 (-14.79)	18.03	28,6906 (-9.24)
30 जून 1992	25,8900	30,6607 (-15.08)	18.43	28,7524 (-9.11)

(ii) (भा. रि. बैं.) प्राधिकारिक की 10 प्रतिशत और भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (सार्वजनिक) की 60 प्रतिशत दरें।

नोट : - कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े 28 फरवरी 1992 की दर के ऊपर अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की मूल्य वृद्धि (+) / मूल्यह्रास (-) दर्शाते हैं।

6.38 वर्ष के दौरान रुपये की प्राधिकारिक दर ने औसत आधार पर सभी मुद्राओं के मुकाबले मूल्यह्रास दर्शाया है; येन के मुकाबले 30.7 प्रतिशत, अमरीकी डालर के मुकाबले 26.7 प्रतिशत, पीड स्टैलिंग के मुकाबले 21.9 प्रतिशत और ह्यूडन मार्क के मुकाबले 21.8 प्रतिशत (VI परिशिष्ट सारणी 0.12)।

6.39 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियाँ :- विश्व उत्पाद वृद्धि, जिसमें 1982 के बाद निरंतर वृद्धि दर्शायी, 1991 में उसमें 0.3

प्रतिशत की मामूली सी गिरावट आयी। प्रमुख औद्योगिक देशों में इस लगातार तीसरे वर्ष 1991 में 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शायी। विकासशील देशों में यह गिरावट 3.4 प्रतिशत आंकी गयी। परिमाण की दृष्टि से विश्व व्यापार 1991 में 3.3 प्रतिशत गिरा जबकि 1990 में यह 4.1 प्रतिशत गिरा। दो गतिविधियाँ अमेरिका और यूरोप में आईं निरंतर अधिक मंदी की पुष्टि में और केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप के देशों तथा पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक और सामाजिक पुनर्रचना की प्रक्रिया जारी रहने की स्थितियों में हुई।

6.40 कठिन बाह्य परिवेश विकासशील देशों को अपने प्रयासों को समन्वित करने के लिए प्रमुख कठिनाई रही है जिसमें वे व्यापार नीति संबंधी सुधार लागू करके प्रत्यक्ष, विदेशी निवेश, पर नियंत्रणों को कम करके तथा सीमा प्रणुत्कों को घटाकर तथा अन्य व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करके अपनी अर्थ व्यवस्था को विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ समेकित करना चाहते हैं। विकासशील देशों में बाजार आधारित सुधारों का सफल कार्यान्वयन यह अपेक्षित करता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर औद्योगिक देश, विश्व बाजारों में उनकी पहुंच में वृद्धि के रूप में उनका समर्थन करें। उल्लेख सम्मेलन का संतुलित परिणाम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

6.41 पूर्ववर्ती सोवियत संघ 15 स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित हो गया और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता इन राज्यों की अर्थ क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 40 से 45 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तपोषण संबंधी अपेक्षाओं का अनुमान लगाता है। ब्याज दरों पर दबावों को और बढ़ाये बिना इन निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वास्तविक चुनौती होगी। साथ ही परम्परागत निवेश प्राप्तकर्ताओं अर्थात् विकासशील देशों को निवेश के प्रवाहों की सुरक्षा करनी होगी।

6.42 कुछ प्रमुख देशों ने न तो नौवीं कोटा समीक्षा के लिए और न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार ज्ञापनों में तृतीय संशोधन के लिए अभी तक अपना अनुसंधान दिया है। विकासशील देशों के लिए विशेषकर निधि के संशोधनों का नये स्वीकृत सदस्यों द्वारा संभवतः उपयोग के संदर्भ में इसके गंभीर परिणाम होंगे।

VII. मूल्यांकन और संभावनाएं

7.1 पिछले दशकों में 1991-92 के दौरान प्रमुख नीतिगत गति-विधियां और आर्थिक कार्यान्वयन दर्शाये गये हैं। वर्ष 1991-92 की शुरुआत संकटपूर्ण थी, कई स्तरों पर की गयी गुरजत कार्रवाई से वर्ष के मध्य तक व्यापक आर्थिक सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल होने के स्पष्ट लक्षण दिखायी दिये। इसके बाद देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में नाटकीय सुधार हुआ। इसके विपरीत 1992-93 में चिन्ता का केन्द्र विस्तृत औद्योगिक पुनरुज्जीवन देने की आवश्यकता और अपेक्षाकृत खराब मानसून को देखते हुए कृषि क्षेत्र में अतिस्थिति। दो वर्षों तक दो अंक वाली मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में चरनिधि की निरंतर तीव्र वृद्धि ने मौद्रिक प्रबंधन में त्रिविधा की स्थिति पैदा कर दी। प्रतिभूतियों के लेनदेनों में अनियमितताओं से उत्पन्न हुई हाल की समस्या को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली संतोषजनक रीति से पूर्ण विश्वास सुरक्षित बहाल किया जाना आवश्यक है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार समय की मांग है; हाल की घटनाएं सुधार नीति की गति को तीव्र करने के महत्व पर बल देती हैं।

7.2 सामान्यतः आर्थिक सुधार, जिसमें व्यापार, उद्योग और राज-कोषीय सुधार शामिल हैं, यथा संभव शीघ्र पूरे होने चाहिए। निर्यात में कमी लाने वाले कारण, जिन्होंने भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन और प्रमुख विकसित बाजारों में मंदी की दशाओं जैसे बाह्य कारणों के वजह से 1991-92 में औद्योगिक उत्पाद में कमी लाने में योगदान दिया, अभी भी आर्थिक परिवेश में प्रधान तौर पर छाये हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में कमी की स्थिति ने राजकोषीय असंतुलन और मौद्रिक वृद्धि वृद्धि वाली निरंतर जारी मुद्रा स्वीतिकारी संभावना से व्यापक आर्थिक समायोजन को अधिक कठिन कार्य बना दिया है।

7.3 देश ने एक प्रमुख संरचनात्मक प्रणालीगत सुधार प्रारंभ किया है तथा एक निर्देशित अर्थव्यवस्था से बाजार संकेतों के प्रति एक अधिक प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पीछे निहित तर्काधार अग्रिम ही मेहतर आर्थिक वृद्धता प्राप्त करना रहा है। कुल मिलाकर

हाल की अवधि के व्यापक आर्थिक सुधार को संतोषजनक रूप में लागू किया गया है यद्यपि भूलभूल आवश्यक तत्वों के बारे में अभी भी गंभीर चिंतन बनी हुई है और इसके प्रतिरिक्त आधार स्तर पर नीति-निर्धारण और उसके कार्यान्वयन के बीच अभी भी एक खाई है। यदि सुधार की प्रक्रिया में गति लानी है तो इन प्रश्नों पर निम्नसंदेह अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.4 कृषि संभावनाएं:- चालू वर्ष के दौरान जिलंब से आए दक्षिण-पश्चिम मानसून, जिससे प्रारंभ में फसल की संभावनाओं के बारे में काफी आशाएं हुई थी; जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे वह काफी अनुकूल होता गया। मौसम विज्ञान के 35 उप मंडलों में से 12 अग्रस्त, 1992 तक संबंधी वर्षा 25 उप मंडलों में अधिक/सामान्य और 10 उप मंडलों में कम थी, जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वह 24 उप मंडलों में अधिक/सामान्य और 11 उप मंडलों में कम रही थी। कम वर्षा वाले 10 उप मंडलों में से कम से कम छः उप मंडलों में उक्त कमी साधारण रही है। साथ ही छः उप मंडल हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के हैं जहाँ पर्याप्त जलों की सिंचाई की सुविधा है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि आद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 169-171 मिलियन टनों के उत्पादन की तुलना में कुछ सुधार परिलक्षित होगा। तब भी, वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित किया गया 183 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

7.5 जबकि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र द्वारा उचित मात्रा में लचीलापन प्राप्त कर लिया गया है आद्यान्नों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन की उपलब्धता अभी भी उल्लेखनीय नहीं है; 1981 से 1985 तक की पंचवर्षीय अवधि के दौरान 455.1 ग्राम का आंकड़ा 1986 से 1990 तक की अगली पंचवर्षीय अवधि के दौरान 474.8 ग्राम अथवा 4.3 प्रतिशत तक बढ़ गया है। गरीब जनता के उपयोग स्तर को सुधारने और इस प्रकार अधिक की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक है। इस संबंध में उन चुनौती प्रश्नों में जिनमें गरीब जनता का बाहुल्य है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना सहायक होगा। इन्हें अधिक संपन्न क्षेत्र हो या सूखाग्रस्त लगभग सभी क्षेत्रों में वृद्धि वरं मीधे की ओर जाने से हाल के वर्षों में कृषि में विकास की गति कम हो गयी है। वालों जैसी कुछ महत्वपूर्ण फसलों में कमी बनी हुई है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि समर्थन मूल्य संबंधी प्रोत्साहनों पर अधिकाधिक निर्भरता न केवल कृषि में तीव्रतर विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपर्याप्त है अपितु यह अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति का एक कारण भी बन सकता है। कृषि के स्तर पर, कृषि की निविष्टियों की लागत में वृद्धि, कृषि प्रौद्योगिकी में अवरोधता कृषि उत्पादों के लिए व्यापार की प्रतिकूल शर्तें तथा क्रय की क्षमता में कमी ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं को सामने ला दिया है। 1980 के दशक में कृषि में सार्वजनिक निवेश कम हो गया है इसी तरह अनुपूरक प्रावणों निवेश था। ग्रामीण विकास के लिए योजना सूचके में काफी वृद्धि करने के सरकार के हाल के निर्णय से इस प्रवृत्ति को बदलने में सहायता मिलेगी। अधिक निवेश के अलावा बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी और मूलभूत संरचना संस्थागत सुधार और संगठनात्मक सुधार को मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल संसाधनों के क्षेत्रांतरित सामंजस्य के रूप में पहले से पता लगाये गये कृषि जनबाधक अवरोधों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए फसल और गैर फसल आधारित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के समेकित पैकेज प्रदान करने में महत्तर भूमिका निभानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उच्चतर मूल्यों के लाभ कृषक समुदाय तक पहुंचे। बाजार के कार्यकलापों के विस्तार, बाणवानी, उद्यान, विज्ञान, रेशम उत्पादन, पशुपालन और डेरी उद्योग, मूर्तिपालन और मछलीपालन के जरिये कृषि आय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुणाइश है। इनमें से कई सहायक कार्यकलाप और सहायक कृषि व्यवसाय और छाछ अभिसंस्करण उद्योगों में निर्यात संभावनाएं सिद्ध हो गयी हैं। उनकी निर्यात संभावनाओं

के क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विस्तार सेवा को व्यापार बनाने में नयी गतिशीलता लाने के लिए बेहतर भौतिक निविष्टियों और संस्थागत ऋण के अलावा समन्वित प्रयासों की जरूरत होगी।

7.6 औद्योगिक विकास की संभावनाएं:- पिछले दशक में लगभग 8.0 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन में आयी अचानक स्थिरकरण की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में की गयी अपेक्षा से कहीं अधिक उन्नत थी। विशेष रूप से आयात संकुचन उपाय, ऋण प्रतिबंध, राजकोषीय समायोजन से माल और सेवाओं की सरकारी क्षेत्र की भांग में आयी कमी, विनिमय दर परिवर्तन और सीमानुत्क में कटौती संबंधी अपेक्षाएं इन सब कारणों से उत्पादन और निवेश संबंधी गतिविधियों में गिरावट आयी। अर्थव्यवस्था की आयात निर्भरता, यद्यपि सामान्यतः कम है तथापि वही जतनी समझी गयी थी, उससे कहीं अधिक है और इसलिए आयात संकुचन उपायों से विविध प्रकार के उद्योगों की, उत्पादन गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई प्रतीत होती है। अब, जबकि सुधारात्मक उपाय स्पष्ट रूप से आरम्भ हो गये हैं तथा आयात और बैंक ऋण पुनः उपलब्ध होने लगे हैं, यह आशा की जा सकती है कि राजकोषीय वर्ष 1992-93 के दौरान औद्योगिक निवेश और उत्पादन में सुधार होगा। प्रमुख अखिल भारतीय मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा जिन परियोजनाओं को आर्थिक सहायता संचर की गयी है, उनके पूंजीगत व्यय की अपेक्षित चरणबद्धता के आधार पर कंपनी निवेश के संबंध में की गयी भविष्यवाणी यह बताती है, कि 1992-93 के दौरान ऐसे पूंजीगत व्यय में काफी मात्रा में वृद्धि होगी, जबकि 1991-92 के दौरान इसमें मामूली सी गिरावट आयी थी। निर्यात में प्रत्याशित सुधार से भी औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। अनेक उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी मांग में मंदी और समय उत्पादन में क्षीण सुधार को देखते हुए, ऐसी आशा करना तर्कसंगत होगा कि 1992-93 के दौरान औद्योगिक विकास सामान्यतः लगभग 4-5 प्रतिशत पर रहेगा। औद्योगिक निवेश के पूरी तरह पुनः सक्रिय हो जाने के बाद 1993-94 में ही एक बार फिर 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है।

7.7 समय सकल देशी उत्पाद में वृद्धि:- समय रूप से 1992-93 के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर लगभग 3.5 प्रतिशत होने की संभावना है जो 1991-92 के 2.0 प्रतिशत से थोड़े कम के स्तर की तुलना में सुधरी हुई स्थिति दर्शाती है।

7.8 मुद्रास्फीति:- अर्थव्यवस्था में अत्यंत सबल अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिकारी संभावना का बना रहना रिजर्व बैंक के लिए चिन्ता का विषय है। सकल मांग को सीमित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को समन्वित करने का दुर्घट प्रयास किया गया है तथा इन नीतियों को विनिमय दर, व्यापार और औद्योगिक नीति की पुनर्संरचना के साथ परिचालित करने की कोशिश की गयी है। केवल मांग प्रवृत्तियों से, खासकर कम अवधि में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। जहां तक देश में सामान्य मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति का प्रश्न है यह आवश्यक है कि पण्य बाजार को स्पष्ट संकेत दिया जाये कि परिस्थिति की मांग पर सरकार आवश्यक उपलब्धता मामूली विशेषकर अनाज और दालों के मामले में, देशी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के एक अंश को खर्च करेगी। इस संबंध में गेहूं के आयात का निर्णय एक उचित कदम है। तीन लगातार वर्षों से मुद्रास्फीति की सामान्य से अधिक दर अर्थव्यवस्था में एक गम्भीर खतरे की सूचक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को सहने की क्षमता का अभाव रहा है। 1992-93 में वो अंकों की मुद्रास्फीति दर का बना रहना उच्च मुद्रास्फीति दर के प्रति

अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता के अभाव का सूचक है। अतः यह आवश्यक है कि 1992-93 के दौरान मुद्रास्फीति दर को 8 प्रतिशत तक लाना समय आर्थिक नीति का केन्द्रीय लक्ष्य होना चाहिए।

7.9 रोजगार लक्ष्य:- वर्तमान व्यापक आर्थिक परिदृश्य का एक चिन्ताजनक पहलू है समय रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि। मनायोजन का सामाजिक परिणाम विभिन्न वर्गों द्वारा बहन किये जाने वाले भार का साम्यमूलक स्वरूप - इस तथ्य से ही निर्धारित किया जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि से कितनी गतिविधियां और कितना अधिक रोजगार बढ़ेगा। जैसा कि योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अपने विशानिर्देशक प्रपत्र में बताया है, सकल देशी उत्पाद में वृद्धि की तुलना में रोजगार वृद्धि में रामोन्मुखी प्रवृत्ति तथा अर्थिकों की संख्या में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि के बीच के अंतराल ने बेरोजगारों में विशाल वृद्धि कर दी है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यदि प्रत्याशित 3.0 प्रतिशत वार्षिक की जगह समय रोजगार में 2.0 प्रतिशत वार्षिक की वर्तमान वृद्धि दर बनी रही तो बेरोजगारों की अनुमानित संख्या आठवीं योजना के आरम्भ में 23 मिलियन से बढ़कर योजना के अन्त में 28 मिलियन हो जायेगी। जब तक ऊंची और तेज आर्थिक विकास दर रोजगार वृद्धि की स्थिति में सुधार न करें, तब तक बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा आंशिक बेरोजगारों के लिए पूरक रोजगार की व्यवस्था जारी रखनी होगी। इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रस्तावित सहयोग एक उपयोगी उपाय होगा।

7.10 आठवीं योजना के अन्य लक्ष्य:- रोजगार लक्ष्य के अनावा आठवीं योजना के अन्य परिमाणारमक आयामों की पूर्ति के लिए भी अत्यंत सुनिश्चित प्रयासों की आवश्यकता होगी। सर्व प्रथम, 1992-93, जो योजना का प्रथम वर्ष है, के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद 3.6 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य से कम है, पावरटी वर्षों में वास्तविक विकास 6 प्रतिशत या उससे अधिक वार्षिक के हिसाब से बढ़ना चाहिए। परिकल्पित कृषि विकास दर (मूल्य बर्धित के हिसाब से 3.1 प्रतिशत में इसके पहले निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हुई कमी और भी अधिक होगी। दूसरे देशी बजल-दर आठवीं योजना के लिए 21.6 प्रतिशत के औसत स्तर पर अपरिवर्तित रहने पर भी, सरकारी क्षेत्र के अधिव्यय में तीव्र कटौती किये जाने की आवश्यकता है। घटक उत्पादन और सामान्य अमता में पर्याप्त विकास के बिना यदि अधिव्यय में कटौती प्राप्त की जाए तो सन्निधियों को कम करने और सरकारी क्षेत्र के मूल्यों टैरिफ और माल भाड़े को बढ़ाने की अपेक्षा के कारण स्कीमिकारक प्रभाव होंगे। साथ ही, सरकारी क्षेत्र की वृद्धि से तात्पर्य होगा घरेलू प्रयोग्य-प्राय में तदनुसार कमी और इस प्रकार जब तक खपत में रोक नहीं लगायी जायेगी, वृद्धि में वृद्धि नहीं होगी। अन्त में, योजना के लक्ष्यों की तुलना में बाह्य स्तर पर यह कार्यनिष्पादन ही है जिससे समायोजन कार्यक्रमों की सफलता या विफलता का पता चलेगा। आठवीं योजना अवधि के दौरान चालू लेखा घाटे में योजनाबद्ध तरीके से 2.4 प्रतिशत औसत से आठवीं योजना के दौरान 1.6 प्रतिशत तक की कमी करने के परिणामस्वरूप 13.6 प्रतिशत की निर्यात में वृद्धि करनी होगी और आयात वृद्धि को रोक कर 8.4 प्रतिशत तक लाना पड़ेगा। इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ऋण चुकौती भार के संबंध में मध्यावधि परिवर्तन चिन्ता का विषय है तथा इस भार में योजना के गत दो वर्षों में लगभग 11.0 बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि आरम्भ के वर्षों में यह भार लगभग 7.5 बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक (अनिवासी भारतीयों की जमा राशियाँ सहित) की दर से बढ़ा था।

7.11 तात्कालिक बाह्य क्षेत्र परिदृश्य:- यद्यपि बाह्य चलनिधि संकट की स्थिति में तेजी से कानू पा लिया गया था, फिर भी भुगतान

संतुलन के मामले में मूल भूत असंतुलन अभी भी वैसे का वैसे बढा हुआ है। वर्ष 1991-92 में चालू लेखा घाटे के सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 प्रतिशत तक की कमी आयी जो पूर्णरूप से आयातों में भारी कमी करने की वजह से हुई, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि में भी गिरावट आयी हालांकि आयातों की कमी के कारण बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन संभव हो सका, परन्तु इससे उद्योगों के गड़बड़ा जाने तथा बेरोजगारी बढ़ने से, भुगतान संतुलन के असंतुलन को समाप्त करने हेतु एक उपाय के रूप में आयातों में कमी करने की उपयोगिता के बारे में एक गम्भीर प्रश्न विन्हा लग गया है। इस वृद्धि को फिर से बहाल करने के उद्देश्य से एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर आयात पर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अतः वर्ष 1992-93 में आयातों के तेजी से बढ़ जाने की संभावना है तथा आशा की जाती है कि इससे निर्यातों को लाभ होगा और ऐसी आशा है कि इससे आर्थिक वृद्धि की दर में भी बड़ोत्तरी होगी।

7.12 व्यापार और औद्योगिक नीतियों में किए गए अनिवार्य मुधारों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि निर्यातों में भारी वृद्धि होगी। स्वतंत्र राष्ट्यों के राष्ट्र कुल के कुछ देशों के साथ की गई नयी व्यापारिक व्यवस्थाओं के बाद यह आवश्यक है कि भारत की निर्यात नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। नए बाजारों का पता लगाने तथा मौजूदा बाजारों में गेयर में विस्तार करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतिम विश्लेषण के रूप में; व्यापारिक उन्नतिकरण के लाभ केवल तभी प्राप्त किये जा सकते हैं यदि पतन मुविधार्ण, परिवहन और संचार जैसे देशी मूलभूत संरचनाओं तथा बिजली की अनधिक आपूर्ति में सुधार अत्यधिक गति और शीघ्रता के साथ किया जाये।

7.13 आयात जहाँ आर्थिक वृद्धि और निर्यातों के लिए अनिवार्य हैं वहीं हाल ही में आयातों में हुई वृद्धि की वजह काफी हद तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम वस्तुओं के आयात हैं। भुगतान संतुलन के क्षेत्र को ठीक रखने के लिए दोनों रूपों में अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थों का अवेधाकृत बेहतर उपयोग करने और ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करने के साथ-साथ उनका विविधीकरण अपनाने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण उपायों से संबंधित पक्ष में उपयोग को रोकने के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना भी शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में, आयोजित पेट्रोलियम पारगमन (पास-थ्रो) मूल्य तथा विनिमय दर की उचित प्रणाली अनिवार्य रूप से एक दूसरे की पूरक हों।

7.14 एक और क्षेत्र जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है वह है आधिकारिक माध्यमों के द्वारा भारतीय विशेषज्ञों से प्राप्त होने वाले निजी प्रेषणों में वृद्धि करना। ऐसे समान्तर बाजारों का मौजूद होना जिनके द्वारा पूर्ण में अर्थात् उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के लागू होने से पूर्ण इन प्रेषणों के एक बहुत बड़े भाग को दूसरी ओर भेज दिया जाता था। क्योंकि आधिकारिक दर की तुलना में इन बाजारों में प्रचलित रुपये की गैर-आधिकारिक विनिमय दरें कहीं अच्छी थीं। मार्च 1992 के बाद उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली को लागू करने और नीति से संबंधित अनेक अन्य गुंथारामक उपायों को करने से आधिकारिक बैंकिंग माध्यमों के द्वारा प्राप्त प्रेषणों को आकर्षित किया गया है। सोना आयात करने की सुविधा एक अनुकूल घटक है, चूंकि सोने की चोरी छुपी लाने से सम्बद्ध विदेशी मुद्रा में लेन देनों का एक समान्तर बाजार भी काफी हद तक कार्य कर रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप आधिकारिक माध्यमों के द्वारा प्राप्त होने वाले भारी प्रेषणों के मामले में बैंकिंग माध्यमों की परिचालनात्मक कुशलता में भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वे सुधार प्रेषण भेजने वाले तथा प्रेषण प्राप्त करने वाले ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप हो सकें।

7.15 अनिवार्य जमा योजना ने वर्षों में महत्व प्राप्त किया है और इन योजनाओं के अनुरूप प्राप्त आगमनों ने मातृ योजना के दौरान समग्र वित्तीय आवश्यकताओं के लगभग एक चौथाई भाग को पूर्ण की है। 1991-92 के भुगतान संतुलन संकट के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा (अनिवार्य) खातों से भारी मात्रा में निधियों के आह्वान ने इसे एक प्रतिस्वित स्रोत बना दिया है। इसके प्रतिस्वित इसकी लागत की वित्त का विषय बन गई है। बिम्बक ग्याज दर के अलावा लागत विदेशी

मुद्रा अनिवार्य खातों और अन्य विशेष प्रयोजन मूलक जमाराशियों को प्रदान विनिमय दर संरक्षण को परिलक्षित करती है। तर्क दिया जा सकता है कि कोई भी विदेशी अथवा अनिवार्य तब तक राशियां जमा नहीं करेंगी जब तक उसे विनिमय दर संरक्षण द्वारा उच्च प्रतिफल वाली प्रोत्साहन राशि अथवा व्याज दर अन्तर अथवा दोनों ही न मिले। हाल ही में अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियों के लिए विशेष आकर्षक विशेषताओं के साथ एक नयी योजना चालू की गई, इस वर्ष में होने वाली प्रतिक्रिया को अभी देखा जाना बाकी है। नीतिगत प्रयोजन ऐसे होने चाहिए जिससे विविध अनिवार्य योजनाओं को इनके आकर्षक को बनाये रखने को ध्यान में रखकर पुनर्गठित किया जा सके जबकि (1) स्थिरता के लिए प्रोत्साहन राशि, (2) देश के केन्द्रीय बैंक पर विनिमय भार, और (3) विदेशी मुद्रा में ऐसे उधारों के लिए देश पर समग्र रूप से प्रभावी लागत को कम किया जा।

7.16 देश का विदेशी ऋण, जिसमें अनिवार्य भारतीयों की जमाराशियां भी शामिल हैं, 31 मार्च 1992 को लगभग 70.0 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 2,05,000 करोड़ रुपये था और ऋण का एक वृद्धिशील अनुपात वाणिज्यिक रूप में है। प्राप्त होने वाली सहायता की मात्रा में भारी वृद्धि की सीमित संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए काफी मात्रा में सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है जो भुगतान संतुलन समर्थन, निवेश के लिए वित्त, टेक्नोलॉजी अन्तरण, भारतीय उद्योग में प्रतियोगिता और कुशलता को बढ़ाने और एक विस्तारित निर्यात आधार के रूप में बहुविध लाभ प्रदान करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक उदार आर्थिक वातावरण में प्रोत्साहन देने का काम निस्सन्देह शुरू हो चुका है। कम से कम एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्तर, मान लीजिए 2.0 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष प्राप्त करने के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण, पर्याप्त प्रवर्तन प्रयास और इन सबसे अधिक पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अस्वाप्तन की आवश्यकता पड़ेगी।

7.17 भुगतान संतुलनों का समग्र निष्पादन :—मौजूदा विभिन्न प्रतिस्वितताओं को मद्देनजर रखते हुए कुल मिलाकर 1992-93 में भुगतान संतुलन के समग्र निष्पादन के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण करना कठिन है। पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार ने अभी तक जोर नहीं पकड़ा है, जबकि इनमें से अनेक देशों के साथ करार किये जा चुके हैं। वर्ष की अप्रैल-जून की तीमाही के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों ने 8.4 प्रतिशत की वृद्धि नहीं दर्शायी है। ग्रेष सहीनों में उनका निष्पादन विश्व व्यापार के वातावरण पर उतता ही निर्भर करेगा जिनका कि देश में औद्योगिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने पर। तथापि, आयातों में खुली छूट दिए जाने और लागू किये गए विभिन्न मुधारों से निर्यात क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 1992-93 में बेहतर निष्पादन की अपेक्षा की गई है। मौजूदा प्रवृत्तियों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि 6 से 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के चालू लेखा घाटे के साथ देश के भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहेगा। विभिन्न स्रोतों से पुंजीगत आगमन की संभावना की देखते हुए यह परि-कल्पना की गई है कि 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर विशिष्ट वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

7.18 रुपये की विनिमय दर के घटोमुखी पुनः समायोजन (अमरीकी डॉलरों के रूप में लगभग 18.7 प्रतिशत तक) और इसके बाद अन्य पूरक उपायों के साथ उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली लागू किए जाने से कई लाभ हुए हैं यथा-निर्यातों के लिए बजट उपदानों का हटाया जाना निर्यात प्राप्ति का तात्पर्य से बसूनी समान्तर बाजार में रुपया दर में कुछ कमी करना, आधिकारिक बैंकिंग स्रोतों से अवेधाकृत अधिक प्रेषणों के संकेत त्वर आना। उल्लेखनीय है कि आर्थिक परिवर्तनीयता का यह प्रणाली सफल रही है और आधिकारिक दर पर खुला बाजार प्रीमियम समान्यतया 16 से 18 प्रतिशत के मामूली स्तर पर बना रहा है। इस अनुभव की समीक्षा उन कई कारकों के परिप्रेक्ष्य में की जानी है जिनमें विदेशी मुद्रा क्षेत्रों पर मांग के दबाव, बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में बायदा विक्री बाजार में अपेक्षा से अधिक मात्रा में एक्जिम स्क्रिप के स्तरों की उपलब्धता और आयात उदारीकरण उपायों के प्रति विलम्बित अनुकिया सामिल हैं। एक बार आयात मांग बढ़ जाने से प्रारंभित निधियों पर दबाव पड़ेगा और इस तरह मुक्त बाजार विनिमय दर पर इसको दबाव को महसूस किया जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही घरेलू मुद्रास्फीति दर का प्रश्न भी जुड़ा है जो कि मौजूदा व्यापक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में चिन्ता का विषय बनो हुई है। हालांकि इसमें निम्न दो वर्षों की तुलना में गिरावट परिलक्षित हुई है। चालू लेखा लेन-देनों के लिए रुपये की सम्पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने संबंधी समय सारणी व्यापक आर्थिक व बजटीय परिणामों और निर्यात और प्रेषणों के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार करनी होगी।

राजकोषीय सुधार

7.19 प्रारम्भ में यह बात जानने की जरूरत है कि ऋण की उचित स्तरों के भीतर रखे जाने का मामला केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय सुधार काफी समय से विनिर्दिष्ट है। राजकोषीय सुधार से अधिप्राप्त यह है कि सरकारों को अनिवार्य रूप से अपने खर्चों को पूरा करने के लिये राजस्व हो। यदि ऐसा न हो तो ऋण परिणामित साधनों को निवेशों की भाँति खर्च को पूरा करना चाहिए। जब तक केन्द्र के स्तर पर राजस्व घाटा जारी रहेगा और उसका उधारियों से बिना पोषण होता रहेगा तब तक अधिक उधारियों का दुष्प्रभाव और बैंकों को बाजार से कम दर पर उधार देने के लिए निवेश करने के प्रयास जारी रहेंगे। ऋण नियंत्रण और उत्पादनकारी व्यापारिक गतिविधियों से बाहर हो जाना सरकार की अपने राजस्व से उपभोक्ता परिव्ययों के संतुलन न कर पाने की आधारभूत कमजोरी से उत्पन्न होता है। राजकोषीय संतुलन संबंधी सुधार अनुसूचन के इस मूल कारण पर केन्द्रित होना चाहिए। केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा कम से कम करने में का सरकार का मध्यम अवधि उद्देश्य बेसी उधार का स्तर बहुतीय सीमा के भीतर रखने को सुनिश्चित करने की दिशा में होना चाहिए। इस मध्य को ध्यान में रखते हुए यह और भी आवश्यक है कि सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों पर बाजार संप्रेषण ब्याज दरों की ओर बढ़ने का आवश्यकता, वित्तीय प्रणाली में सफलतापूर्वक सुधार के लिए और प्रभावी मौद्रिक नीति के लक्ष्य के लिए एक पूर्व शर्त है। केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा 1990-91 के सकल देशी उत्पादन का 8.4 प्रतिशत में घटकर 1991-92 में लगभग 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है और अनुमान है कि 1992-93 में यह और घटकर 5.0 प्रतिशत रह जाएगा। ब्याज के बढ़ते हुए बोझ के परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे (सकल राजकोषीय घाटा में से निवल ब्याज भुगतान निकास कर) में समायोजन अपेक्षाकृत अधिक रहा अर्थात् 1990-91 में सकल देशी उत्पाद के लगभग 6.0 प्रतिशत से 1991-92 में 3.5 प्रतिशत और 1992-93 में घटकर सकल देशी उत्पाद का 2.3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इसे प्राप्त करने के लिए केन्द्र के निवल बाजार उधार 1992-93 के लिए घटकर 500 करोड़ रुपये रह गए जो 1991-92 के 7,500 करोड़ रुपये के स्तर से तीव्र गति से कम है। जबकि सरकार की बाजार उधारियों पर निर्भरता को कम करने की अपेक्षा उचित है "बन्नी" बाजार उधारियों में कमी की गति के लिए चेतावनी है कि यह सकल राजकोषीय घाटे के प्रथमोष्ठी समायोजन से भेल रखे। बाजार उधारियों को कम करने में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अन्य खातों से उधारियों की उच्च लागत से मौद्रिक घाटे में वृद्धि नहीं होनी है अन्यथा स्वरित राजकोषीय सुधार में यह प्रति उत्पादन होगा। साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सरकारी बजट घाटे की वित्तपोषण प्रणाली में यथोचित फेर बदल हो।

7.20 रिजर्व बैंक कुछ वर्षों में इस बात पर जोर देता रहा है कि एक सहमत स्तर तक केन्द्रीय सरकार को अर्थात् प्राथमिक रूप में ही महायत्ना देगा जिसे प्रत्येक वर्ष की समायोजन पर चुकाया जाना चाहिए। केन्द्र का भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण पर अत्यधिक निर्भरता से मौद्रिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक घाटे के विपरीत प्रभाव न होने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा दिखाये जाने वाले घाटे की सीमा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून की आवश्यकता है और साथ ही सभी खातों से एक निश्चित सीमा तक और भारतीय रिजर्व बैंक से उधारियों की उप सीमा में अधिक सरकारी उधारियों पर कानूनी रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। 1980 के दशक में केन्द्रीय सरकार की उधारियों में असाधारण वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों की कूपन दरों में वृद्धि और परिपक्वता अवधि में संकुचन से चुनौतियों में कठिनाइयों प्रतीते हैं; और जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था नये ऋणों का जारी करके भी निकट भविष्य में चुनौतियों के लिए आवश्यक धन जमा नहीं हो पाता। इस संदर्भ में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि लोक ऋण से मुक्त होने के लिए समेकित निवेश निधि को पुनः जानू किया जाए। यह दुर्भाग्य है कि सरकारी ऋण से मुक्ति की इस एकमात्र प्रणाली को

समाप्त कर दिया गया है। इस प्रणाली को नवतान लागू करने से धाने वाले समय में सरकारी उधारियों की दीर्घ अवधि व्यवहार्यता को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

7.21 केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों में, केन्द्र से राज्यों को खातों के अंतरण पर कुछ अपरिहार्य परिणाम हुए तथा ऐसा केन्द्रीय कराधान की प्रणाली की तर्क संगत करने के कारण हुआ। ब्याज दरों में परिवर्तन से लघु खर्चों में आकर्षण भी अप्रत्यक्ष रूप से कम हुआ। राज्यों के वित्तीय पर अधिक दबाव के कारण बार बार ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा। केन्द्र के खातों पर दबाव के कारण राज्यों को जारी किये ऋणों को रोक दिया गया जिनसे कई राज्यों के वित्त को संकटित कर दिया। राज्य ओवरड्राफ्ट वित्तियमन योजना के लागू होने के कारण, राज्यों के वित्तीयन में कटाव की दूर करने के लिए, जिनमें रिजर्व बैंक द्वारा लगातार 8 कार्य दिवसों के लिए ओवरड्राफ्ट रखने वाले राज्यों को भुगतान रोक देने की व्यवस्था है राज्यों वित्तीयन में आधारभूत सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य के वित्तीय-सात्मक घाटों का न होना सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकारों के मामले में यह सुविधा है कि वे कृषि और ग्रामीण खर्चों का पूरा बोझ उठाते हैं और साथ ही समाजिक और आर्थिक सरवनात्मक खर्च भी। ऐसे खर्चों में गंभीर या सघाट तर पर कटौती से विकास की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव हो सकता है। उनके मामले में खातों के उपाय की दृष्टि से हुई वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए साथ ही व्यय के प्रकार में कमी पर भी। साथ ही बिजली-कर और अन्य छूटों की मंजूरी देने तथा करों को बढ़े खाते डालने की कार्य प्रणाली सहित राज्यों की कराधान प्रणाली को सुनियोजित बनाकर राज्य सरकारों के खात आधार को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। बड़ी अप्रत्यक्ष आर्थिक-सहायता में कमी करने संबंधी कार्रवाई करने में पहले ही विनिर्बंध हो गया है। यह स्पष्ट है कि लागू करने और कर की दरों में वृद्धि करने या नये कर लागू करने के विपरीत कर अनुपातन में सुधार करने की दिशा में प्राथमिकता की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करनर राजस्वों के मध्यम से खातों को जुटाने की काफी संभावनाएं हैं विशेषकर, राज्य विभागीय और गैर-विभागीय उद्यमों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाकर। वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की अनुमानित हानि 17,000 करोड़ रुपये और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की 5,600 करोड़ रुपये रही। इस संबंध में, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का ह्रास ही का महत्वपूर्ण उपाय, सही दिशा में है। कृषि उपभोक्ताओं पर अत्यन्त बिजली शुल्क लगाने का करार, जो कि इससे पूर्व इस संबंध से सविनयी के एक बहुत बड़े भाग का लाभ उठा रहे थे। एक प्रगती गुरुवात है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जहाँ इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर राज्य परिवहन निगम और विभागों द्वारा चलाये जा रहे कृषि परियोजनाएं जो भारी हानि में चल रही हैं, कुछ तो परिचालन की उनकी अपनी क्षमता और कुछ खर्चों की मूल्य नीतियां। स्थिरकरण के कार्यक्रम के संदर्भ में राज्य सरकारों से ये और अन्य राजकोषीय मुद्दों पर विचार-विमर्श आवश्यक है। राज्यों के वजटीय परिचालनों पर निमाही समीक्षा से इस प्रकार के विचार-विमर्श संभव है।

7.22 सांविधिक जलनिधि अनुपात में कटौती के कारण 1992-93 में समय उधार पर दबाव से समायोजन का भार केन्द्र और केन्द्र द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं के उधार ने पिछले वर्ष के स्तर को कायम रखा। यहाँ एक दुविधा है : सरकारी प्रतिभूतियों की कूपन दर में वृद्धि, जो मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष परिणाम है तथा वास्तविक ब्याज दर को कायम रखने की जरूरत है, उधार देनेवाली सभी संस्थाओं के लिए समस्या है। विशेषकर ऐसे राज्यों के लिए, जिनकी समस्याएं अपेक्षाकृत अल्प अवस्था में हैं, यह एक समस्या है। इसके अतिरिक्त इन दरों पर, ऋण सेवा को परियोजनाओं की अधिक सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है, इन

उच्च लागत निम्नोपित परियोजनाओं को कभी भी प्रतिनाश कर के उस स्तर की प्रवेशा नहीं करनी चाहिए जो ऋण सेवा के योग्य बनाता है। प्रथम दृष्टि में, राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने राजस्व घाटों, सार्वजनिक उद्यमों की क्षतियों के निम्नोपण के लिए अपने वसूली अधिकार को उच्च लागत वाले उधारों तक सीमित रखें।

7.23 समस्याओं की जड़ राज्यों के बढ़ते हुए घाटे हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें उच्च लागत पर उधार लेकर इनका निम्नोपण करना पड़ा है। बदले में वे जानते राजस्व घाटे में जुड़ गयीं जिससे ऋण में जोरदार वृद्धि हुई। यह निवारण है कि केन्द्र सरकार के प्रस्तुत राजकोपीय दबावों को देखते हुए राज्यों को अपने राजस्व बजटों को केन्द्र के थोड़े से अंतरणों के साथ संतुलित करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्यों की राजस्व स्थिति निम्नोपित बनाना पड़ेगा। केन्द्र से अंतरणों में वृद्धि द्वारा समस्या को सुलझाने की कार्य प्रणाली से समायोजन का भार राज्य से हटकर केन्द्र पर ही आ पड़ेगा—जिससे समस्या ही बड़ेगी।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

7.24 हाल के वर्षों में, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के पर्याप्त उपाय किये गए हैं। वित्तीय प्रणाली की समीक्षा करने वाली समिति (अध्वनः श्री एम. नरसिंहम) ने वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन में और तेजी लाने की आवश्यकता पर काफी जोर दिया है। रिपोर्ट के खंड 1 में समिति की दूरगामी सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया है; जिसमें से कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

7.25 जबकि और अधिक सक्रिय खुले बाजार की परिस्थितियों संबंधी नीति के मौद्रिक नियंत्रण के साधन के रूप में प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं से मूल नीति में बदलाव की आवश्यकता को सन्तुष्ट स्वीकार किया गया है, लेकिन वास्तव में मुख्य मुद्दा इस सुधार में तेजी लाने का है। यह माना जाता है कि बैंकों की सांविधिक अपेक्षाएं इस ऊंचाई तक पहुँच गयी हैं कि वे अनुत्पादक होती जा रही हैं तथा इन्होंने सधस्यहीनता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। बैंक समायोजन की अत्यधिक तेज गति, अव्यवस्था में अत्यधिक प्राथमिक चलनिधि की समस्या को काफी बदतर बना सकती है, प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में कटौती की गति का निर्धारण सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में और अधिक यथार्थवादी स्तर तभी संभव है जब अव्यवस्था में स्फोटिकारक दबाव के स्थायी रूप के टिके रहने के स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने हों। जैसा कि नरसिंहम समिति ने जोर दिया है कि रिजर्व बैंक में इसका लचीलापन होना चाहिए कि यह अपनी मौद्रिक नीतिगत प्रयोजनों के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के साधन का उपयोग कर सके। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बाधकदी शेष पर व्याज का भुगतान है। ऊँचे व्याज के साथ ऊँचे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करने की अपेक्षा व्याज रहित कम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करना बेहतर है। दुविधा यह है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात समायोजन बैंकों की प्रारम्भियों को बढाने देता है जबकि व्याज में कटौती बैंकों की आय को प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के और नकदी शेष पर व्याज दर के स्तर को अंततः अनुकूल बनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र बैंक लाभप्रदता प्रभावित न हो। इसके अलावा, पुनर्निर्माण और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के बीच अंतर बड़ी है। शायद उच्च प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा उच्च पुनर्निर्माण को अपेक्षा निम्न प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और निम्न पुनर्निर्माण की प्रणाली को अपनाया बेहतर है। अदार्शतः प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का सामान्य स्तर ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी प्रकार के व्याज की अदायगी नहीं होती है तब भी बैंकिंग प्रणाली व्यवहार्य हो तथा ज्यों ही मौद्रिक विस्तार अत्यधिक होता है प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को बढ़ाया जाये जब मौद्रिक वृद्धि अपेक्षित स्तर पर वापस आ जाती है, निम्नगामी गतिविधियों को तेज किया जाना चाहिए।

7.26 नरसिंहम समिति ने यह सिफारिश की है कि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात को कम कर के 25 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए। कार्य की दिशा में यह उपयुक्त मध्य है। तथापि, सांविधिक चलनिधि अनुपात समायोजन की चरणबद्धता को दोषार उधार कार्यक्रम से समन्वय रखना चाहिए। सांविधिक चलनिधि अनुपात में भारी कटौती अप्रैल 1992 से लागू की गयी। अवश्य से, सांविधिक चलनिधि अनुपात में समायोजन की गति राजकोपीय समायोजन, मौद्रिक विस्तार तथा मुद्रास्फूर्ति दर की गति पर निर्भर करेगी। केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं ने पाँच वर्षों में उधार कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कटौती की है, किन्तु राज्य और राज्य द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं ने उधार के संबंध में पिछले वर्ष के स्तर को बनाये रखा है। सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिष्ठितियों के संबंध में बाजार-नापेक्ष दरों की दशा में कार्रवाई करने यह जरूरी होगा कि संपूर्ण उधार (केन्द्र और राज्य) की बाजार नापेक्ष दरों की दिशा में भी कार्रवाई की जाए और इसीलिए चरणबद्ध करने में बहुत आवश्यकता है।

7.27 नरसिंहम समिति का मूल आधार यह है कि वित्तीय व्याज दरें लाभप्रद होती चाहिए, और कि वित्तीय व्याज दर अर्थिक समायोजन का साधन नहीं होना चाहिए, जो सन्तुष्ट स्वीकार कर लिया गया है। मुद्रा बाजार पर, उधार और जमागति दर तथा सरकारी प्रतिष्ठितियों पर व्याज दरों के रूप में व्याज दर सुधार की प्रक्रिया काफी हद तक पहली प्रारम्भ हो गई। एक ओर इन उपायों को बनाए रखने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर प्रणाली में सभी दरों के प्रति तेजी अविविधिमय की अपेक्षा के धीरे-धीरे सतर्कतापूर्वक उस और बढ़ने की आवश्यकता है। अनेक देशों का यह अनुभव रहा है कि व्याजदरों और प्रशिक्षित निधि की अपेक्षाओं में अत्यधिक तेजी से किया गया अविविधिमय का परिणाम मौद्रिक नियंत्रण में पिछड़ जाना होता है—यह एक ऐसी बात है जिसे भारतीय अव्यवस्था इस स्थिति में सह नहीं सकती है।

7.28 नरसिंहम समिति की कई अन्य सिफारिशें हैं—जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार में कमी, ऋण वसूली की प्रक्रिया में गति लाने के लिए विशेष व्यायाधिकरणों की नियुक्ति, आस्ति पुनर्निर्माण निधि (एप्रारएफ) की स्थापना और सामीप्य ऋण संरचना का पुनर्गठन, जिनके विस्तृत परोक्षा की आवश्यकता है तथा वित्तीय प्रणाली की संरचना एवं इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित वित्तीयव्यवस्था—दोनों ही दृष्टियों से इन सिफारिशों के दूरगामी परिणाम होंगे।

7.29 जहाँ तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यनिर्धारित ऋण का संबंध है, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ऋण आवश्यकताओं का साधनपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। उत्पादन और रोजगार से संबंधित इन वर्गों के अंश में किसी भी परिवर्तन के परिणामों का साधनपूर्वक अध्ययन करना होगा क्योंकि भारत को आर्थिक संरचना अत्यन्त भिन्न-भिन्न है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण के दो पहलू हैं जिनकी स्वरूपा स्पष्टतः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पहला यह कि बैंकिंग प्रणाली से कम व्याज दरों के रूप में आर्थिक सहायता बढाने की आशा नहीं की जा सकती और रियायत देने की बात को ऋण के प्रकार के साथ संबद्ध करके बड़ी सोमा तक इस विषय का समाधान करने का विचार किया गया है। दूसरे, यह तर्क दिया जा सकता है कि वित्तीय व्यवस्था में विकास के हम चरण पर, जहाँ कि आज भारत है, कमजोर वर्गों को ऋण का व्यायसंगत वितरण न केवल उत्पादन को बढ़ाने में योगदान करेगा बल्कि इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। पर यह कि क्या सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली सर्वश्रेष्ठ साधन है, कुछ बाद-विवाद का विषय है। फिर भी हम बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि विकास की प्रक्रिया में ऋण के लिए कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं।

7.30 जब कि नरसिंहम समिति ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्रों से अनावश्यक और संदिग्ध ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए

एक आर्थिक पुनर्निर्माण निधि (एआरएफ) की स्थापना करने की सिफारिश की है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा ऐसी योजना का कार्यान्वयन करने से पूर्व, निधिकरण के स्तरों के बारे में स्पष्ट धारणा का होना आवश्यक होगा। वसूली के माहौल में ऐसी योजना के प्रभाव के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। वसूली की प्रक्रिया के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। विशेष वसूली व्यापार-धिकरणों की स्थापना के संबंध में नरसिंह समिति की सिफारिशों को जब लागू किया जाएगा, तब बैंकों के दावों को भी लागू किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने पहले ही, पूंजी-पर्याप्तता, आय की मांग्यता और प्रावधान-व्यवस्था के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारण कर दिये हैं। यह स्वीकार किया गया है कि परिणामतः उक्त प्रावधान की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी सहायता की आवश्यकता होगी। यदि बड़ी मात्रा में पूंजी की इन आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है तो उसका अर्थ केवल अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट हानिकारक प्रभावों सहित बड़े पैमाने पर मोद्रोकरण ही होगा। इस प्रकार बैंकों द्वारा नयी पूंजी जुटाने के लिए अग्रसरता साधना पूर्वक करने की जरूरत है।

कृषि ऋण

7.31 कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला संस्थापित ऋण अनिवार्य के लक्षणों से प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ समय के लिए निधियों के निरंतर उपयोग की प्रक्रिया कमजोर पड़ गयी है। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 ने वसूली समस्या को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋणों के लिए निर्धारित अपेक्षाकृत निम्न व्याज-दरों ने केवल अलाभकारी हैं, बल्कि सहकारी और अन्य ऋण संस्थाओं की निधियों को लागत एवं उनके द्वारा किये गये अन्य व्यय भी उनसे पूरे नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप, उदाहरण के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा संग्रह की गई और उधार की गई जमादारियों के प्रत्येक रुपये का अर्थ है नकारात्मक कीमत-लागत अंतर और परिणामी हानि। जब तक सहकारी/ग्रामीण ऋण एजसियों को निम्न व्याज पर उधार देना और प्रतियोगी दरों पर जमादारियां जुटानी होंगी, तब तक उनके लिए अपने जमा-संग्रहण और उधार के कार्यक्रमों का विस्तार करने में अंशरुकी निरुत्साह रहेगा। ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त जमादारियां जुटाने में सहकारी ऋण समितियों के असमर्थ होने के फलस्वरूप नाबाई/भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त का अधिकतर आश्रय लेना आवश्यक हुआ है।

7.32 सकल वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए एक मूलभूत प्रथम आवश्यकता यह है कि ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली, जिससे हाल की अवधि में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं, को पुनः ठीक कर दिया जाए और एक सक्षम संस्थागत संरचना अस्तित्व में लायी जाए। जबकि ग्रामीण ऋण संरचना को सुधरी अव्यवस्था में प्रदान करने के प्रश्न ने विभिन्न समितियों का ध्यान आकषित किया है, एक सक्षम संरचना विकसित करना अभी भी अपेक्षित है। सरकार एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रश्न पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है कि क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक ही राष्ट्रीय स्तर के बैंक के रूप में विलयित किया जाए अथवा चार या पांच प्रांतीय बैंकों के रूप में बैंकों की ग्रामीण सहायक संस्थाओं के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयित करने के लिए नरसिंह समिति द्वारा सुझाये गये विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। एक ऐसी ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली तैयार करना अनिवार्य जिसके लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता न हो। इस संबंध में, व्याज-दरों के बेहतर रूप में समन्वय बनाने एवं लक्षित और लक्ष्येतर उधार के मिश्रण पर ध्यान देना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएं गंभीर हैं और इनके लिए एक बहुविध दृष्टिकोण अपनाया अपेक्षित होगा। जिस सीमा तक किसी क्षेत्र में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली संतोषजनक है, वहां मौजूदा संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों की प्राचीन सहायक संस्थाओं जैसी नयी संस्थाओं का उनके अपने बल पर विकास करने को अनुमति देना उपयुक्त

होगा। तथापि, ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां ग्रामीण वितरण प्रणाली बिल्कुल स्पष्टतः असंतोषजनक है और यह अनिवार्य है कि ऋण वितरण प्रणाली में सक्षमता सुदृढ़ सुधार लाने हेतु शीघ्र उपाय किये जाएं।

प्रतिभूतियों के परिचालनों में अनियमितताओं से संशय :

7.33 पहले के एक खंड में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति संबंधी परिचापनों से हाल ही में पाई गई अनियमितताओं का उत्पत्ति और शाखा-विस्तार को स्पष्ट किया गया है। रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस रिपोर्ट के भाग II में दिया गया है। बैंक अपने परिचालनों तथा संगठनात्मक संरचना और स्टॉकिंग पर नये सिरे से अवलोकन कर रहा है। विशेष रूप से, बैंक अपने परिचालनों का आधुनिकीकरण कर रहा है, अपनी परिचालनागत कार्य कुशलता को मजबूत कर रहा है, एक नियमित और सुव्यवस्थित आर्थिक आसूचना तंत्र स्थापित कर रहा है एवं अपने स्वयं के तत्वावधान में एक सुदृढ़ पर्यवेक्षण प्राधिकरण नियुक्त कर रहा है जिसके पास बैंकों वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर व्यापक पर्यवेक्षण के अधिकार होंगे।

7.34 रिजर्व बैंक और भारत सरकार का स्वीकृत लक्ष्य भारत में और विदेशों में देश की वित्तीय प्रणाली में पुनः विश्राम कायम करना है। हाल की घटना को देखते हुए उचित अनुवर्ती उपाय करने से वित्तीय प्रणाली दृढ़तर और अधिक कार्यक्षम बनेगी।

7.35 एक महत्वपूर्ण विषय, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया पर इन अनियमितताओं के प्रभाव से संबंधित है। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए ये अनियमितताएं कारण नहीं हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ तथ्यों के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। पहले, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन की नीतियां जून 1991 के अंत में प्रारंभ हुईं। दूसरे, उदारीकरण की प्रक्रिया का संबंध अभी तक वस्तुतः राज-कोषीय सुधारों, औद्योगिक लाइसेंसकरण, व्यापारिक सुधारों, विनियम दर समायोजन एवं भूगर्भ-संयोजन को ठीक करने से रहा है। तीसरे, बैंक उधारों पर अब तक की उच्चतम व्याज-दरों और बैंक ऋण पर कठोर प्रतिबंधों के साथ 1990-91 में और 1991-92 की पहली छमाही में मौद्रिक नीति के अनुदेश पहले से कहीं अधिक कठोर कर दिये गए थे जिससे कि सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को, और विश्व रूप से आयात की मांग को नियंत्रित किया जा सके, इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान, आरंभित निधि की अपेक्षाओं के पारंपरिक अनुदेशों की नीति के, प्रमुख उपकरणों के रूप में प्रयुक्त किया गया था। यहां यह ध्यान में रखना मंज होना कि वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य बेहतर वित्तीय अनुशासन को लागू करना है। इस प्रकार वित्तीय उदारीकरण और प्रतिभूति लेनदेनों के बीच संबंध जोड़ना मान्य नहीं होगा। अंत में, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाएं--सार्वजनिक, निजी, विदेशी और सहकारी--हाल की घटना में सम्मिलित रहें हैं। वित्तीय प्रणाली, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान की बड़ी नीतिगत पहलों की श्रंखला ने मुसाध्य हुई है, कि व्यापक नृद्धि और विधिकरण के कारण उक्त प्रणाली अब विकास के एक ऐसे चरण पर पहुंच चुकी है जहां प्राप्ति की प्रगति केवल सभी संभव है जब उसकी कार्यक्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्याप्त रूप में और शीघ्रता से सुधार किया जाए। मध्यवर्तिक लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र में सुधार की एक विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कायम करना है अतः यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हाल की घटना कुर्भावपूर्ण है तथापि उसके कारण सुधारों की प्रगति पीछ न जैली जाये। जैसा कि नरसिंह समिति ने बल दिया है, वित्तीय प्रणाली में विद्यमान कमियों संरचनात्मक हैं तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था ने संरचनात्मक अड़चने दूर करने हेतु सुधार प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखने के लिए एक स्पष्टनीय और प्रतिबद्ध वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए एक सुनिश्चित और व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार के पैकेज की सशक्त रूप में कार्यक्षम

करता होगा ताकि हमारे उच्च क्षेत्र के लिए परिवर्तनशील लचीलापन और कार्यक्षमता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड

7.36 नरसिंहम समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक पर्यवेक्षी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है। सरकार ने रिजर्व बैंक के तत्वावधान में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष गवर्नर होंगे। उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर होंगे जिनको केवल पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य सौंपा जाएगा। उक्त बोर्ड में चार से पांच तक पूर्णकालिक सदस्य होंगे। वित्तीय पर्यवेक्षण के उक्त बोर्ड की एक परामर्शदात्री परिषद होगी जिसमें बैंकिंग, धनशास्त्र, लेखापरीक्षा, प्रबंधन संबंधी निधि और लोक नीति को पृष्ठभूमि वाले प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। उक्त बोर्ड पर्यवेक्षण कार्य करेगा और अनुपालन की भी देखेगा।

मुद्रा बाजार परिचालन और प्रारक्षित निधि अपेक्षाएं

7.37 मई 1989 में जब मुद्रा बाजार में मांग दरों का मुक्त छोड़ दिया गया था तो यह आशा की गई थी कि एक स्थायी और स्वस्थ मुद्रा बाजार की प्रवृत्ति उत्पन्न कर आएगी। तथापि, पिछले तीन वर्षों के अनुभव यह बताते हैं कि प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं संबंधी किसी भी एकल पाक्षिक अवधि के दौरान मांग मुद्रा दरों में तेजी से उतार-चढ़ाव आता है। यदि एक खंड में व्याज बरे मुक्त छोड़ दी जाती हैं और दूसरे खंडों में बरे सामान्यतया विनियमित रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में अस्थिरता के आवेग का प्रभाव पहले खण्ड पर ही पड़ता है। मांग मुद्रा दरों में अस्थिरता की प्रवृत्तियाँ मुख्यतः स्थिर और विनियामक दोनों ही प्रकार के ऐसे घटकों में देखी जा सकती हैं जो प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के स्थापना के संघालित करती हैं। इस संबंध में एक मुद्दा यह है कि क्या एक पाक्षिक अवधि के लिए दैनिक औसत के आधार पर बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकदी अनुपात रखने की मौजूबा प्रणाली इस अस्थिरता के तीव्र आवेग का कारण है? हालांकि, प्रारक्षित नकदी अनुपात रखने की मौजूबा प्रणाली, बैंकों को उधार देने तथा उधार लेने, दोनों ही प्रकार से लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन बैंकों में अत्यधिक लचीलापन हीना मांग मुद्रा दर में अस्थिरता का कारण बनता है। इसके विपरीत, सांख्यिक चल निधि अनुपात दैनिक आधार पर रखा जाना अपेक्षित होता है क्योंकि यह प्रारक्षित नकदी अनुपात वेयता की तुलना में एक पखवाड़े के अंतराल की वेयता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में, अनेक विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। प्रारक्षित नकदी अनुपात और सांख्यिक चल निधि अनुपात दोनों की वेयता तारीख एक ही हो सकती है, वेग में मौजूबा संभार प्रणाली को देखते हुए संबंधित तारीख तारी होगी जो सांख्यिक चल निधि अनुपात के लिए है और इस प्रकार प्रारक्षित नकदी अनुपात के वर्तमान समय के अन्तराल को समाप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि इस विकल्प को अपना लिया जाता है तो तर्क के रूप में यह कहा जा सकता है कि सांख्यिक चल निधि अनुपात की तरह ही प्रारक्षित नकदी अनुपात को भी दैनिक आधार पर रखना पड़ेगा। एक अन्य प्रारक्षित निधि अपेक्षा मुद्रा नीति को दुर्बल करती है और इसलिए प्रारक्षित निधियों को अपेक्षा-कृत काफी उच्च स्तर पर निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं की अवधि साध-साध चल सकती है। तथापि, इस मौजूबा संभार प्रणाली की स्थिति को देखते हुए इससे भी समस्या बड़ी हो जाएगी। अतः यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं की प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में मूल परिवर्तन करने के संबंध में विचार करते समय, यह बेहतर होगा कि पहले प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में समयबद्ध आधार पर कमी की जाए और उसके बाद, विधायी ढांचे में मूल परिवर्तन करने पर विचार किया जाए। कनिष्ठ बैंक जो विन्यासात्मक रूप से मुद्रा बाजार, मांग मुद्रा दरों पर निर्भर हैं, एक सीमा तक अस्थिर स्थिति हो

जाएंगे और मांग मुद्रा दरों में उच्च गति से उतार-चढ़ाव कुछ बैंकों द्वारा अपने कारोबार की एक सीमा से अधिक बढ़ा लिए जाने के कारण उनकी स्थिति की अपेक्षा प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं संबंधी प्रणाली पर कम निर्भर करता है।

7.38 हाल की अवधि में भारी मात्रा में राशि दिनांकित प्रतिभूति बाजार में व्यापक तौर पर तैयार बायदा लेन-देनों में खपाने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह कार्यकलाप दिखावे के लिए तो प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के समायोजन के लिए थे परन्तु उनसे अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार की हाल की प्रतियोगिताओं में मदद मिली। इसी कारण रिजर्व बैंक ने दिनांकित प्रतिभूतियों में तैयार बायदा लेन-देनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की। एक स्थायसंगत प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या चल निधि के अन्तर्गत समायोजनों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं तथापि खजाना बिलों में तैयार बायदा लेन-देनों की अनुमति है और पाक्षिक समायोजनों के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बाजार पर्याप्त होना चाहिए। दिनांकित प्रतिभूतियों में तैयार बायदा लेन-देन तत्काल शुरु नहीं किये जाने के कई कारण हैं। पहला कारण वर्तमान प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं और व्यापक विनियमों में विनियामक ढांचे को प्रबंधित करने के लिए ठीक जैसे कार्यकलापों की गुंजाइश रह सकती है। दूसरे, प्रणाली के सामने आ रही गंभीर समस्याओं की देखते हुए पाबंदी से पहले के लेन-देन से पाबंदी हटाने का कार्य पूरा किये जाने की जरूरत है। तीसरे, बाजार उधार कार्यक्रम तथा लम्बी अवधि वाले खजाना बिलों की मोलामी कार्य द्वितीयक बाजार के विघटन के बावजूद अत्यंत सुगमता पूर्वक चल रहा है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते कम-से-कम कुछ समय के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार बायदा लेन-देन पर पाबंदी लगाये रखना विवेकपूर्ण होगा।

7.39 अच्छी तरह से विकसित वित्तीय प्रणाली की यह पूर्वपेक्षा है कि मुद्रा बाजार के विभिन्न खण्डों का निकट सम्बन्ध हो, ताकि तापेक्षिक व्याज दरों को बीच विधियों को कम किया जा सके तथा उनमें अधिक स्थिरता आ सके। जब तक वित्तीय बाजारों के अर्थ खंडों में बरे मुक्त नहीं हो जाती तब तक विभिन्न मुद्रा बाजार की लिखतों पर व्याज दरों में परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसे प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि सरकारी ऋण ने व्यापक मोदीकरण की घटना को काफी हद तक कम करना होगा।

मौद्रिक नीति की स्थिति

7.40 व्यापक आर्थिक परिवर्तन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि वित्तिय क्षेत्र में कमी के कारण आपूर्ति में कमी होने की संभावनाएं और उनकी मुद्रास्फीति की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, मौद्रिक क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रियता अपनाये जाने की आवश्यकता है। 1992-93 के लिए एम3 के लक्ष्य में 11 प्रतिशत से कम तेजी से गिरावट हुई जबकि 1991-92 में यह 18.5 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान स्थिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी जा रही है, किन्तु यह सकल राजकोषीय घाटे और साथ ही मौद्रिक घाटे में महत्वपूर्ण समायोजन पर अनुमानित है। किन्तु इस संबंध में, राजकोषीय और मौद्रिक गतिविधियों का एक पहलू, जो कि रिजर्व बैंक की धिता का विषय भी रहा है, वह है, केन्द्र और बजटीय घाटे में भारतीय रिजर्व बैंक के निम्न ऋण का लक्षित स्तरों से काफी अधिक स्तर पर बने रहना। वर्ष 1992-93 के प्रथम साढ़े चार महीनों के दौरान अब तक बजट घाटा पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में बहुत अधिक रहा है और पिछले वर्ष की वृद्धि की गति की तुलना में भी इसकी वृद्धि की गति अधिक रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े स्तरों के ऋण के लिए जाने से प्रणाली के माध्यम से बहुआयामी प्रभाव हुए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक बाजार का अत्यधिक विस्तार हुआ है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत में, मौद्रिक नीति में चल निधि को नियंत्रण में रखने के उपायों को अत्यन्त कमी है।

प्रारंभित निधि की अपेक्षाएँ इतने ऊँचे स्तर पर पहुँच गयी हैं कि जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है कि उनकी क्षमता में काफी कमी आयी है, और इनमें किसी भी प्रकार की और बृद्धि करना प्रति-उत्पादन होना और यह मध्यस्थों का बीच से हटाने की प्रक्रिया में योगदान करेगी। मुद्रा स्कीम की वर्तमान प्रकृति की पृष्ठभूमि में व्याज दर सम्बन्धी उपाय का प्रयोग लचीलेपन के साथ करना होगा। वास्तविक व्याज दरें सकारात्मक रही हैं और मुद्रास्कीम से निपटने के लिए वही सूझबूझ से इनकी निर्धारित किया गया है। जब तक मुद्रा स्कीम में स्थिरता की प्रकृति नहीं दिखाई पड़ती, तब तक वर्तमान दरों को जारी रखने की आवश्यकता है। लागू की जाने वाली व्याज दर नीति के लिए यह आवश्यक है कि राजकोषीय घाटों को कम किया जाए। उद्योग में घा रही मंदी की स्थिति को देखते हुए, हमें ऋण देने में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के साथ-साथ भारी उद्योग भी समान रूप से अपने निवेश और उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ा सकें। दरों की संरचना निर्धारित करने का वर्तमान प्रणाली में किसी भी सुधार के लिए (मुद्रा बाजार में बाजार द्वारा निर्धारित संवर्धन वरों) (अल्पावधि लिखतों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पुनर्निर्माण वर और सरकारों विनियमित प्रतिभूतियों पर वार्षिकालीन प्राप्ति का वरों के परिप्रेक्ष्य में) के स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। सरकारी ऋण लिखतों की बाजार आधारित व्याज दरों से जाँचने के लिए एक मृदु आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति की उचित तौर पर अपनाए जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। तथापि, जब तक कि कुल बाजार की गतिविधियाँ मौद्रिक नीति का एक प्रभावी साधन नहीं बन जाती तब तक इस बारे में कोई भी कार्यवाई करना जल्दबाजी होगी। तब तक हमें ऐसा ही चलने दिया जाये। यह अर्थव्यवस्था सहस्रपूर्ण है कि वर्षभर मौद्रिक घाटे के परिमाण को यथार्थवादी स्तरों तक नियंत्रित रखा जाय। वास्तव में मध्यम अवधि के संदर्भ में, देखा जाय तो यह आवश्यक है जैसा कि रिजर्व बैंक ने पहले भी जोर देकर कहा है, कि रिजर्व बैंक से आपसी सहमति के परिणाम-स्वरूप निर्धारित हुए अर्थोपाय विभागों से अधिक के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपनी अल्पावधिक आवश्यकताओं सहित पूर्ण ऋण बाजार से उचित व्याज दरों पर जुटाये और इसके साथ ही रिजर्व बैंक से धन लेने पर सरकार की निर्भरता की एक सीमा हो। इस तथ्य के अतिरिक्त कि इससे प्रणाली अधिक प्रभावी मौद्रिक प्रबंधन में सहायता मिलेगी जिसमें कि मुद्रा स्कीमगत संभावनाओं को तेजी से रोकने में सफलता मिलेगी, इससे कई अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय गुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन जैसे व्याज दर संरचना का उप नियंत्रण तथा प्रारंभित निधि सम्बन्धी अपेक्षाओं को कम करना और विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में उधार दरों को समान स्तर पर लाने का कार्य आरम्भ करना, आदि में सुविधा होगी।

7.41 आरंभित निधियों सम्बन्धी अपेक्षाओं से अलग मौद्रिक नीतिगत उपायों पर जोर दिये जाने के कारण, यह आवश्यक है कि मौद्रिक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए व्याज दर नीति का प्रभावी तौर पर उपयोग किया जाए, जिसमें मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। स्थिर वित्तियम दर नीति के साथ-साथ व्याज दर नीति ने सर्वोच्च वृद्धि और सर्वोच्च कमी को निर्बंधित करने में योगदान किया और यह देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में तजी से सुधार का रूप महत्वपूर्ण कारक रहा है। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान उधार पर व्याज दरें तब तक जारी रखी जायें जब तक प्रसार की गति में कमी न आ जाय और मुद्रा स्कीम की दर में बहुनीय स्तर तक कमी न हो जाये। 1992-93 के दौरान मौद्रिक नीति को अधिक गतिविधियों में सुधार लाने के स्रोतों में कटौती किए बिना पूर्ण चलनिधि में तेजी से कमी लाने की अवांछनीय जिम्मेदारी भी थी। जहाँ रिजर्व बैंक के संवेद्य अनेक उद्देश्य होते हैं, वहीं उसका अंतिम लक्ष्य मुद्रा स्थिति के नियंत्रण पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करते हुए मौद्रिक नीति को चलाना है।

भाग दो—भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-पद्धति और परिचायन

VIII परिचय

8.1 भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ के इतिहास में 'यह लेखा' अस्थायी घटनापूर्ण वर्षों में से एक रहा है जब विदेशी चलनिधि खतरनाक

तौर पर निम्न स्तर तक पहुँच गयी थी, उम समय उसके दिन-प्रति-दिन के प्रबंधन में विदेशी प्रारंभित निधियों के संकट का निवारण करने तथा उसे उल्लेखनीय स्तर तक उभारने में एवं स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन उपायों में सम्यक् विचार-विमर्श की पहल करने और/अथवा उसमें भाग लेने में रिजर्व बैंक द्वारा अदा की गयी निर्णायक भूमिका इन सभी का निष्ठाने खंडों में व्यापक रूप से उल्लेख किया जा चुका है। सुधारात्मक उपायों के संदर्भ में इसके परिचालन संबंधी जिन दो प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है वे विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों तथा बैंकिंग विनियमों और पर्यवेक्षण संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं। औद्योगिक कृणता और पुनर्वास, ग्रामीण ऋण और लघु उद्योगों के लिए ऋण, ग्रामीण सहकारी बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमा स्वीकरण संबंधी कार्यकलापों के विनियमन, और मुद्रा प्रबंधन के विषय से संबंधित सभी मुद्दों पर बढ़ते हुए संदर्भ में नये तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

8.2 वर्तमान और भावी आर्थिक परिवर्तन में बैंक के विभिन्न विभागों की भूमिकाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाने हुए, बैंक ने फरवरी 1991 में हो अने परिचालनों और अपनी संगठनात्मक संरचना और स्टाफिंग के विभिन्न पहलुओं का पुनरावलोकन करना और उपयुक्त छोटी-छोटी अचभियों में विभक्त करते हुए एक वंशक पहले ही समग्र परिप्रेक्ष्य में अनुकूल कार्य-नीतिगत योजना तैयार करना शुरू कर दिया था। अगस्त 1991 में, कार्य-नीतिगत योजना तैयार करने में बैंक की सहायता करने हेतु दो प्राइवेट परामर्शदात्री संगठनों को सूचीबद्ध किया गया था। सितम्बर 1991 में श्री आर. जानकोरामन, उप गवर्नर, की अध्यक्षता में एक आंतरिक दल गठित किया गया था। दिसम्बर 1991 में प्रस्तुत उक्त दल की रिपोर्ट के आधार पर, बैंक के लिए निगमित योजना तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कार्य दल का गठन किया। जनवरी, 1992 में आंतरिक कार्य दल के साथ विस्तृत चर्चा के बाद दोनों परामर्शदात्री संगठनों ने रिजर्व बैंक को प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अंततः, उनमें से एक परामर्शदात्री संगठन, "मैसर्स ए.ए.एफ. फर्गुसन एंड कं". की कार्य दल और अन्य अधिकारियों, बैंक के स्टाफ तथा कर्मचारियों की सहायता करने के लिए मार्च 1992 में सूना गया। इससे पूर्व नवंबर 1991 में बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य श्री एम.एस. मराठे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन बैंक में मानव संसाधन विकास संबंधी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए किया गया था।

8.3 रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य को प्रखर लाने की जरूरत पर विचार करते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. पद्मनाभन की अध्यक्षता में मई 1991 में एक कार्य दल की नियुक्ति की गई तथा इसकी रिपोर्ट बैंक के विचाराधीन रही है। वित्तीय प्रणाली पर नरसिंह समिति की विचारियों के परभाव बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयुक्त पर्यवेक्षण प्रणाली के व्यापक प्रश्न पर अल्पाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा अब भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में वित्तीय पर्यवेक्षण के उन्नाधिकार प्राप्त बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। इसकी संगठनात्मक संरचना और स्टाफिंग के संबंध में सुनिश्चित व्योरे तैयार किये जा रहे हैं। बैंक के पेगेवर स्टाफ और शैक्षिक समुदाय के बीच सहयोगपूर्ण प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से बैंक में एक विकास अनुसंधान दल गठित किया गया है।

8.4 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूति ने नदों में अनियमितताओं की मात्रा और उसके विस्तार की जनवरी 1992 में प्रारंभिक जांच शुरू किए जाने पर जो परिकल्पना की गयी थी, वह उसकी तुलना में अधिक व्यापक और ज्यादा गहरी निकली है। जैसा कि परवती अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है, ऐसी सम्पत्ति जाणसाजियाँ किसी भी प्रणाली में हो सकती हैं। इसके अलावा अब रिजर्व बैंक तथा सरकार के सामने देश की वित्तीय प्रणाली में जनता का और अन्तराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करने का निर्धारित उद्देश्य है। इस उद्देश्य

के लिए उस घटना द्वारा मिली सीखों और जागरूकता समिति द्वारा प्रशिक्षण कमियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि भविष्य में उनकी पुनर्गति न होने देने के लिए सुझाव दिए और निदान के निपटारे उपाय लागू किये जा सकें। इन बातों, संगठन के दोनों सदस्यों के सार्वजनिक सदस्यों की लेकर अगस्त 1992 में प्रतिभूति प्रतिनिधित्वों को विचार-पूर्वक जांच करने के लिए 30 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गयी है (व्योरे बाय के पैराग्राफों में दिए गए हैं)।

8.5 इन प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में तथा साथ ही बदलती हुई आर्थिक गति-सूचना तकनीक सुझाव व्यावसायिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक की भूमिका उसके कार्य और परिचालन का महत्व बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट के भाग II में इनमें से कुछ मुद्दों और 1991-92 के दौरान बैंक के परिचालनात्मक पहलुओं का उल्लेख किया गया है और तत्पश्चात् जहाँ-कहाँ आवश्यक समझा गया प्राप्ति की अनुमति पूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए पूर्वज्ञात नीतिगत पहल की भी चर्चा की गयी है।

IX. वाणिज्य बैंकों से संबंधित गतिविधियाँ

वाणिज्य बैंकों का शाखा विस्तार

9.1 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार काउंटर खोलने और कुछ अलाभप्रद शाखाओं की अवला-बदली करने के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दिये जाने का उल्लेख किया गया था। 1985-1990 की अवधि के लिए शाखा विस्तार नीति पूरी होने के साथ, पूरे देश में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी पर्याप्त मूलभूत संरचना प्रदान करने का उद्देश्य मोटे तौर पर प्राप्त हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की अनुमति महसूस की गयी आवश्यकता और अर्थ सक्षमता के आधार पर दी जा रही है। अपविनिमन के प्रति हाल में उठाये गये कदमों और नरसिंहम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में परिचालनात्मक मामलों में अधिक आजादी चाहने वाले बैंकों से प्राप्त सुझावों के उत्तर में एक उदासीकृत लाइसेंसिंग नीति लागू की गई है जिसके ब्योरे खंड I में पहले ही दिये जा चुके हैं (पैराग्राफ 1.80)।

विवेकसम्मत मानदण्ड

9.2 इसी प्रकार, पूंजी पर्याप्तता के उपाय, आय संबंधी मान्यता के मानदण्ड, आस्तियों का वर्गीकरण विवेकसम्मत आधार पर अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान, और निवेश के लिए लेखापद्धति के मानक जैसी कई नीतिगत कार्रवाईयों निर्धारित की गई हैं। लेखा वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के प्रारम्भ से बैंकों के वार्षिक लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बैंकों से संशोधित फॉर्मेट में अपने वार्षिक लेख तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिससे कि परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में उनकी लेखा नीतियाँ स्पष्ट हो।

बैंकों का निरीक्षण

9.3 भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत दो प्रकार के निरीक्षण करता रहा है: (i) दो से चार वर्ष के अंतराल पर वित्तीय निरीक्षण

जिसमें मुख्यालय, नियंत्रक कार्यालय और विभिन्न शाखाओं का दौरा करना होता है और (ii) वार्षिक वित्तीय समीक्षा (वा.वि.स.) जो अभी तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित है जिसमें मुख्यालय और नियंत्रक कार्यालयों का केवल एक चौथाई कार्यालय ही शामिल हैं और यह निरीक्षण मुख्यतया बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली पर निर्भर होता है।

9.4 वार्षिक वित्तीय समीक्षा करने में आने वाली प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए 1 जनवरी 1991 से प्रयोग के तौर पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए "बैंक निरीक्षण की आणोदित योजना" प्रारम्भ की गई है। वार्षिक वित्तीय समीक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने और निष्कर्षों को अधिक मटीक बनाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत काफी मात्रा में विभिन्न शाखाओं को भी शामिल करने को उत्तम माना गया। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को जनवरी से जून की छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक से अधिक बड़ी शाखाओं का निरीक्षण करने की सलाह दी गई। इसका उद्देश्य है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक अग्रिम वाली सभी शाखाओं को शामिल किया जाए। शाखा निरीक्षणों की टिप्पणियाँ मुख्यालय की वार्षिक वित्तीय समीक्षा के लिए सहायक प्रणाली के एक भाग के रूप में काम आने की आशा है। प्रधान निरीक्षण, अधिकारी, मुख्यालय नियंत्रक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उन टिप्पणियों के निष्कर्षों पर अपने विचार देते हुए उन्हें अद्यतन बनाएंगे उन्हें पूरा करेंगे। तथापि, प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण पहले की भांति किए जा रहे हैं।

9.5 मई 1991 में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की वर्तमान पद्धति पर विचार करने और इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष श्री एम. पद्मनाभन) का गठन किया गया है। इस दल ने 8 जून 1991, को अपना कार्य करना प्रारम्भ किया और 10 सितंबर 1991 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर को प्रस्तुत की। ऋण स्थगन, सामेलन और परिसमापन

9.6 बैंक ऑफ़ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल लि. के मामलों की देखरेख के लिए केमैन आइलैंड में नियामकों द्वारा रिसेवर की नियुक्ति के परिणामस्वरूप बीसीसीआई (ओवर-सीज) लि. बम्बई ने 1 जुलाई, 1991 के सभी भुगतान और अन्य लेन देन बंद कर दिए हैं। अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं सहित सभी जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक कार्रवाई करने से बीसीसीआई (ओ) लि. बम्बई को रोकने के उद्देश्य से और मुख्यालय के लेन देनों से, बैंक की बम्बई शाखा की आस्तियों और देयताओं को पृथक् रखने और भारतीय जमाकर्ताओं के दावों के निपटाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को बीसीसीआई (ओ) लि., बम्बई के लेन देनों को समाप्त करने के लिए अंतिम परिसमापन नियुक्त करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई

1991 को भा.स्टे.बैंक को अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

9.7 बैंक ऑफ कराड़ द्वारा कुछ बलालों की ओर से किए गए प्रतिभूति लेनदेनों में बड़े पैमाने पर पाई गई अनियमितताओं, जिसमें बहुत बड़ी वित्तीय देयता शामिल है और जिसे बैंक अदा नहीं कर पाएगा, में उत्पन्न स्थिति में बैंक का छाप् रहना बैंक के जमाकर्ताओं और लोक हित के विरुद्ध हुआ होता। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी को बैंक ऑफ कराड़ लि. के लेनदेनों को समाप्त करने के लिए अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर, उच्च न्यायालय ने 27 मई 1992 को अंतरिम आदेश जारी किया।

9.8 इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त दो बैंकों का परिसमापन हो चुका है, जबकि अन्य 28 बैंक जो परिसमापन की प्रक्रिया में थे बंद मान लिए गए हैं। अब 96 बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में हैं।

9.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने 28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय मुख्यालयों की वार्षिक वित्तीय समीक्षा की। इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, चौदह निजी क्षेत्र के बैंकों, एवं दस विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण किये गये।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितताएं

9.10 इस रिपोर्ट के खण्ड I और VII में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेनों में हाल ही की गंभीर अनियमितताओं का विशेष उल्लेख किया गया है। जानकी-रामन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी और तीसरी अंतरिम रिपोर्टों में सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और अन्य ऐसी लिखतों के कपटपूर्ण लेनदेनों की शुरुआत उनके परिमाण, प्रकृति और कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है।

9.11 उक्त समिति की दोनों अंतरिम रिपोर्टों से ये मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं कि इनमें शामिल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्य-पद्धति में गंभीर खामियां हैं, इनके विभिन्न क्रिया-कलापों में अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण का अभाव है, प्रतिभूतियां जो नकली साबित हुई, की जमानत पर निधियां जुटायी गयीं, मांग मुद्रा बाजार में निधियों का आबंटन किया गया, निधियों के प्राप्त कर्ता बैंकों द्वारा इन राशियों को दलालों के खाते में डाला गया, केवल कुछ चुनिंदा दलालों के साथ प्रतिभूतियों के लेनदेनों का भारी केंद्रीकरण (समिति ने पाया कि 60 प्रतिशत लेन-देन दलालों के माध्यम से किये गये) और संबंधित अधिकारियों एवं सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी क्षेत्र के बांडों और यूनिटों आदि में सम्मिलित दलालों के बीच मीली-भगत का संकेत करते हैं। उक्त समिति ने बैंकिंग प्रणाली से कतिपय दलालों के व्यक्तिगत खाते में

निधियों के जमा कराये जाने के लिए अपनायी गयी मुक्तियों उपायों की सूची दी, जो प्रत्यक्षतः उनके कपटपूर्ण गलतबयानी का प्रमाण है। निधि-प्रबंधन के परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और मार्गदर्शी निदेशों का पूर्ण उल्लंघन और अवहेलना करते हुए किये गये हैं बैंक रसीदों को जारी करने और उनके रिकार्ड करने, प्रतिभूतियों की प्राप्ति और सुपुर्दगी और लेन-देनों के निपटान के लिए प्राप्तियां और भुगतान के संबंध में अपेक्षित आवश्यक अनुशासन भंग किये जाने के बारे में रिपोर्टों में उल्लिखित अनेक वाणिज्य लेन-देनों के बारे में बताया गया है। समिति के ध्यान में ऐसे भी उदाहरण आये हैं, जहां पर बैंकों द्वारा बिना यथार्थ वाणिज्यिक लेन-देनों के समर्थन के विलों की भुनाई के माध्यम से दलालों को वित्तीय सहायता दी गयी है। समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में कतिपय बैंकों द्वारा संविभागीय प्रबंध योजना संबंधी भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का बड़े पैमाने पर किए गए उल्लंघनों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है।

9.12 इन लेन-देनों में सम्मिलित बैंकों/संस्थाओं की कुल निवेश राशि 3,542.79 करोड़ रुपये हैं (जिसमें एक दलाल से एक बैंक द्वारा 350 करोड़ रुपये की जब्त की गयी प्रतिभूतियों के मूल्य शामिल करते हुए)।

9.13 समिति ने पाया कि पिछले वर्ष में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार की लिखतों, विशेषकर, तैयार वायदा सोदे (रेडीफावर्ड) के रूप में लेन-देनों की मात्रा में हुई वृद्धि के कारण बैंक रसीदों और यहां तक कि एसजीएल का अनुचित रूप से प्रयोग करना पड़ा और इसकी वजह से इन चुनिंदा दलालों के लिए निधियों का दूसरी और मोड़ना (विशाखन करना) संभव हो सका। इन निधियों का विशाखन इन अनियमित लेन-देनों में सम्मिलित दलाल और उनकी सहयोगी कंपनियों को अनेक लेन-देनों के माध्यम से विशेष कर राष्ट्रीय आवास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक कैंप द्वारा किया गया। अनेक लेन-देनों में संबंधित दलाल द्वारा उपलब्ध कराये गये करारों में उद्धृत दूसरी पार्टी नाम मात्र के लिए थी। इसके अलावा, दबाव को भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक कैंप द्वारा प्रदान संविदाओं के निर्धारण की सुविधा और भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में जारी बैंकर चेकों की बमूली और जमा को दलाल के खाते में डालना और उनके अनुदेशों पर भारतीय स्टेट बैंक के बैंकर चेकों को जारी करने अनियमित क्रिया-कलापों का कारण बनी। इस दलाल के साथ भारतीय स्टेट बैंक के लेन-देनों के संबंध में समिति द्वारा पायी गयी अनियमितताएं इसका संकेत देती हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय के पास रखी गयी भारतीय स्टेट बैंक की बहियों में निवेश खाता और भारतीय स्टेट बैंक के खाते के संबंध में दलाल के लेन-देनों को समाविष्ट करने के लिए चालबाजी की गयी।

9.14 समिति ने पाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में होने वाले कार्यों को काफी तेज गति से करने

की जरूरत है। साथ ही लेन देनों की भारी संख्या को प्रभावशाली ढंग से निपटाने तथा कपटपूर्ण/अनियमित लेन-देनों का पता लगाने के लिए बैंकों को नियमित समाधान हेतु संबंधित सूचनाएं देने के लिए कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है।

9.15 समिति ने अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशों की हैं:

(i) अन्य बैंकों के साथ तैयार-वायदा (रेडी फारवर्ड) और दुहरे तैयार-वायदा (डबल रेडी फारवर्ड) का कारोबार करने की बैंक की प्रथा को मात्र सरकारी प्रतिभूतियों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए तथा इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों, यूनिटों एवं शेयरों सहित अन्य प्रतिभूतियों के लिए वर्जित कर दिया जाना चाहिए।

(ii) तैयार वायदा तथा दुहरे तैयार वायदा के कारोबार को निवेश संविभागीय प्रबंध योजना के अंतर्गत वर्जित कर देना चाहिए।

(iii) बैंकेतर ग्राहकों के साथ वापस खरीद संबंधी लेनदेन न करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निषेध की सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(iv) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे लेन-देनों के लिए दलालों की ऋण सीमा सहित आंतरिक वित्त की सीमाएं भी बनायें।

(v) दलालों की संविदा टिप्पणी में प्रतिपक्षी पार्श्व और बलाली छर्च के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

(vi) जब बैंक दलालों अथवा अन्य पार्टियों की प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसे ग्राहकों के लिए किये गये सभी लेन देनों के प्रलेखन में बैंक की हैसियत के बारे में बताया जाना चाहिए।

(vii) बैंक द्वारा तीसरी पार्टी से लेन-देन के लिए रिजर्व बैंक के पास खोले गये अपने खातों पर आहरित चेक जारी करने पर लगाये गये वर्तमान निषेध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(viii) बैंकों द्वारा अपनी वाणिज्य बैंकिंग वाली सहयोगी संस्थाओं की ओर से किये जाने वाले लेन-देन सुस्पष्ट होने चाहिए जिनमें अपनी सहयोगी संस्थाओं के पूर्ण व्यौरे दिये गये हों।

(ix) बैंकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांड, यूनिट और इसी प्रकार की प्रतिभूतियों के सारे लेन-देन स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन जैसी पृथक संस्थाओं, जो बैंक रसीद जारी करने की आवश्यकता को ढालने के लिए स्थापित की जा सकती हैं, के माध्यम से करें।

(x) लोक ऋण कार्यालय के एसजीएल अनुभाग के कार्यों और बैंकों को सूचना भेजे जाने में तेजी लायी जानी चाहिए।

(xi) खजाना लेन देनों पर विशेष जोर देते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थल पर जाकर निरीक्षण करने, विवेकपूर्ण और अन्य मार्गदर्शी निर्देशों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित बैंक के अनुपालन की रिपोर्टिंग से भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के क्षेत्र को बढ़ाना।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की अपयुक्तता पर पुनर्विचार करना चाहिए।

(xiii) बैंकों के निवेश संविभागीय प्रबंध संबंधी कार्यों के लिए बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा पृथक लेखा परीक्षा।

(xiv) बाजार आसूचना के लिए जिम्मेदार भा.रि. बैंक के संगठन को मजबूत बनाना।

(xv) राष्ट्रीय आवास बैंक के निरीक्षण के लिए संस्थागत प्रबंध।

9.16 इन सिफारिशों को स्वीकार करने और इन पर अत्यंत तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा, भा.रि. बैंक ने आगे के खण्डों में उल्लिखित रूप में कदम उठाये हैं।

9.17 बैंकों और दलालों द्वारा आहरित विभिन्न चेकों की निधियों के प्रवाह का पता लगाने की दृष्टि से बैंकों/संस्थाओं की प्रतिभूतियों के लेन-देनों की जांच पड़ताल जारी है।

9.18 सरकार और रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक के मार्ग-दर्शी निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता के साथ ही आदाता के खाते में देय चेकों के संबंध में बैंकिंग के मानदंड की अवहेलना की गंभीरता से लिया है। चूकों, कपट और जालसाजी के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने की प्रक्रिया की गयी है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग प्रणाली की देय राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है, सरकार ने सभी प्रकार की कार्रवाई शुरू कर दी है।

9.19 जानकीरामन समिति की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए गवर्नर ने 9 जून 1992 को बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन-देनों में हुए हाल के रहस्योद्घाटन पर जनता की चिंता को नोट किया गया तथा बैंकों की कार्य-प्रणाली पर जनता के विषवास को यथाशीघ्र कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुख्य कार्यपालकों ने गवर्नर को सूचित किया कि उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली शुरू करने, निगरानी को मजबूत बनाने तथा वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं की कमियां को दूर करने के लिए सुधारात्मक

कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के चूकों से बचा जा सके। मुख्य कार्यपालकों ने जानकीरामन समिति की रिपोर्ट पर आधारित भा.रि. बैंक द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले मार्गदर्शी निदेशों को कार्यान्वित करने की अपनी वचनबद्धता अभिव्यक्त की है।

9.20 इस प्रकरण के संपूर्ण ओर-छोर को खोजनिकालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने निम्नलिखित अनेक कार्रवाईयां की हैं ताकि उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी सभी बैंकों और संस्थाओं द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान किये गये संपूर्ण प्रतिभूति लेन-देनों की जांच कर रहे हैं।

(2) समिति तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये जा रहे जांच को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की है, और सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करने को कहा है।

(3) बैंक ऑफ कराड़ लि., जो इस मामले में शामिल है, के अध्यक्ष तथा दो निदेशकों को रिजर्व बैंक ने पद छोड़ने को कहते हुए "कारण बताओ नोटिस" जारी किया। बाद में, जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंक ऑफ कराड़ लि. को परिसमापन के अधीन रखा गया तथा बैंक की आस्तियों की देखभाल के लिए एक परिसमापक की नियुक्ति की गयी है 80 करोड़ रुपये की आस्तियों वाले गैर-सरकारी बैंक—बैंक ऑफ कराड़ लि. ने बगैर किसी समर्थन के अथवा कल्पित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंक रसीद जारी करके लगभग 753 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान किया था। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिसमापन (अर्थात् समामेलन/विलयन अथवा अधिस्थगन) को छोड़कर दूसरा विकल्प अपरिहार्य नहीं समझा गया। बैंक के परिसमापन का निर्णय छोटे जमाकर्ताओं के हित में सबसे उत्तम था। किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन/विलयन का मतलब यह होगा कि अधिग्रहण करने वाले बैंक को लगभग 794.22 करोड़ रुपये की देयता के लिए राजी होना पड़ेगा। अधिस्थगन की स्थिति में संस्थागत जमाकर्ताओं के लिए यह संभव हो गया होता कि वे छोटे जमाकर्ताओं की भारी संख्या के हितों के विरुद्ध बैंक की आस्तियों पर अपने अधिमान दावों को प्रस्तुत करते और प्रत्येक छोटा जमाकर्ता जो अपनी जमा राशियों में 30,000 हजार रुपये तक की जमा बीमा राशि ले सकता था, वे उसे भी ले जाते। भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम ने उनकी बीमा देयताओं की जमानत पर आवश्यक निधि जारी करने के निदेश दिये हैं।

(4) बैंक ऑफ मदुरा लि. के कार्यों की जांच की जा रही है तथा रिजर्व बैंक से एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गयी है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार से सिफारिश की है कि वह सहकारी समितियों के राज्य के रजिस्ट्रार को

प्रतिभूतियों के भ्रष्टाचार में शामिल मेट्रोपोलिटन को-ऑपरेटिव बैंक के समापन की वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दें।

(6) बैंकों/संस्थाओं के हितों की सुरक्षा तथा उनको देय राशियों की वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत सरकार ने इस भ्रष्टाचार में शामिल उन सभी लोगों की संपत्ति को जब्त करने और भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अभिरक्षक के पास उन्हें रखने के लिए एक अध्यादेश जारी किया।

(7) रिजर्व बैंक ने बैंकों की अनुमोदित दलालों की सूची से चार दलालों के नाम हटा दिये गये हैं।

(8) रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और ए एन जेड ग्रिडलेज बैंक लिमि. को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में उनकी देयताओं को चुकाने के लिए प्रावधान करने का निदेश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अब राष्ट्रीय आवास बैंक की राशि भुगतान कर दी है, जबकि ए एन जेड भी दावे को भुगतान करने के वास्ते निधियों को देश में लाया है।

(9) बैंकों/संस्थाओं के प्रतिभूति लेन-देनों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए भारत सरकार ने "विशेष अदालत" की स्थापना की है।

(10) जानकीरामन समिति द्वारा प्रस्तुत पहली अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है तथा बैंक द्वारा उसको पहले लागू किया जा चुका है। इसने लोक ऋण कार्यालय एसजीएल अनुभाग को कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा लोक ऋण कार्यालय में एसजीएल लेन-देनों के संसाधन के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रारंभ की जा चुकी है तथा उक्त प्रणाली बंबई में केन्द्र सरकार के ऋणों के लिए लागू की गयी है जिसका शीघ्र ही राज्य सरकारों के ऋणों के लिए और अन्य प्रमुख लोक ऋण कार्यालयों में भी विस्तार किया जाएगा। उक्त प्रणाली में (क) एसजीएल अंतरण फार्मों के सत्परतापूर्वक और तुरंत संसाधन की और (ख) अलग-अलग एसजीएल खाताधारकों को कुछ अत्यावश्यक विवरण भेजने की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और संस्थाओं द्वारा यूनियों और सरकारी क्षेत्र के बाडों के कारोबार के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरह एक न्यास की स्थापना के लिए मांडल के सुझाव के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष श्री एस.एस. नाडकर्णी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है तथा 8 अगस्त 1992 को समिति से प्राप्त हुई रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(11) रिजर्व बैंक ने बैंकों की सहायक संस्थाएं, बैंक ग्रुपुअल फंड और चार विदेशी बैंकों सहित कई बैंकों/संस्थाओं के प्रतिभूति लेन-देनों की जांच के लिए सनदी लेखाकारों के अनुभवों फार्मों की नियुक्ति की है।

(12) बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की पर्यवेक्षी प्रणाली की तेजी से जांच करने और उसे मजबूत बनाने के लिए

कारवाई की जा रही है तथा इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में उच्च अधिकार प्राप्त बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया है।

(13) चालू वित्त वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक (बैपबिबि) की निरीक्षण प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा रहा है जिसमें वित्तीय मूल्यांकन को केन्द्र में रखकर सभी बैंकों के विस्तृत वार्षिक निरीक्षण का प्रावधान है। बैंकों के खजाना लेन देनों पर विशेष रूप से तथा अधिक नियमित अंतरालों पर ध्यान दिया जायेगा।

(14) चालू वित्त वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षण प्रक्रिया में लेखा परीक्षा की व्याप्ति का विस्तार किया जा रहा है।

(15) विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना जिनमें सभी परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिलों को छोड़कर, दिनांकित प्रतिभूतियों और अनुमोदित/न्यासी प्रतिभूतियों में अंतर-बैंक तैयार बायबा लेन-देन का निषेध तथा खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों में दुहरे तैयार बायबा लेन-देनों का निषेध किया गया है। इसके साथ ही लागू की जाने वाली आंतरिम नियंत्रण प्रणाली और अपनाये जाने वाले लेखा मानक्यों के लिए भी विस्तृत मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये।

9.21 जानकीरामन समिति का अब यह प्रस्ताव है कि समिति तथा उसमें सूचित निदेशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी पूर्व में की गई जांच के निष्कर्षों के परीक्षण संबंधी अपने भावी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित रहें।

9.22 संयुक्त संसदीय समिति अगस्त 1992 में संसद के दोनों सदनों से माननीय सदस्यों को लेकर 30 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गयी है जिसके विचारणीय विषय निम्नलिखित है:—

(1) प्रतिभूतियों, शेयरों, बांडों और अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित लेनदेनों में हुई अनियमितताओं और जालसाजी पूर्ण जोड़ तोड़ के सभी पहलुओं और विणाखीकरण के बारे में छानबीन तथा बैंकों, शेयर बाजारों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उनके लेनदेन के संबंध में भूमिका जो अदा की गयी है अथवा जो प्रकाश में आ सकती है।

(2) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा प्राधिकारियों की ऐसे लेनदेनों के संबंध में जावाबदेही निश्चित करना।

(3) उपर्युक्त के संदर्भ में नियंत्रणकारी प्रक्रिया और पर्यवेक्षी पद्धति के दुरुपयोग, यदि कोई हुआ हो तथा उसकी असफलता अपर्याप्तता की पहचान करना।

(4) ऐसी प्रणाली असफलता को दूर करने के लिए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, प्रणाली में सुरक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें करना।

(5) नीतियों और विनियमों के संबंध में ऐसी उचित सिफारिशें करना जिनका भविष्य में अनुपालन किया जाना हो।

9.23 औद्योगिक ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक की बदलती हुई भूमिका—बड़े उधारकर्ताओं के ऋण प्रस्तावों के लिए ऋण पूर्व अनुमोदन तथा कार्योत्तर स्वीकृति संवीक्षा की प्रणाली गत प्रतिशत आधार पर समाप्त कर दिये जाने के साथ औद्योगिक ऋण के प्रशासन के भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। ऋण के विनियमों की अपेक्षा विवेक-सम्मत अपेक्षाओं की दृष्टि से मानकों का अधिकाधिक पालन किया जाता है। बड़े उधारकर्ताओं ने गैर बैंकिंग स्रोतों से प्राप्त निधियों पर भी अधिकाधिक निर्भरता रखते हुए अपने वित्त के संसाधनों को विशाखीकृत करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ औद्योगिक रूग्णता, स्पष्ट और प्रारंभिक स्तर पर तथा बैंकों और वित्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण पर इसकी प्रतिक्रियाओं का विशेष महत्व हो गया है, विशेषकर हाल ही में किये गये विन्यासगत सुधारों के संदर्भ में। तेजी से बदलते हुए विन्यास में रिजर्व बैंक की न केवल औद्योगिक रूग्णता को रोकने के लिए और बैंकों की निष्क्रिय आस्तियों को कम से कम करने के लिए, बल्कि बैंकों द्वारा स्वस्थ आधार पर औद्योगिक ऋण के संवर्धन में प्रेरक के रूप में काम करने के लिए भी एक व्यापक भूमिका निभानी होगी। इन व्यापक उद्देश्यों को ठोस कार्यक्रमों में क्रियान्वित करने, नीतियों और संगठनात्मक तत्परता बैंकों में अधिकाधिक ध्यान आकृष्ट कर रही है।

9.24 रूग्ण औद्योगिक उपक्रम—रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रूग्णता के संबंध में अगस्त 1991 में नये मार्गदर्शी निदेश बैंकों को जारी किये हैं जिनमें बैंकों को संगठनात्मक मशीनरी को मजबूत करने के उपाय भी शामिल हैं ताकि प्रारंभिक रूग्णता का पता लगाया जा सके, संवर्धकों द्वारा पूंजी के बढ़ाने, जैसे सुधारात्मक उपाय किये जा सकें, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में बेहतर तालमेल किये जा सकें, पुनर्वास संबंधी एकमुश्त कार्यक्रमों में बैंकों द्वारा अधिदेशात्मक सहभागिता हो सके, अग्रणी निगरानी एजेंसी (अग्रणी बैंक/वित्तीय संस्था का निर्धारण किया जा सके, तथा पुनर्वास संबंधी एकमुश्त कार्यक्रमों के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जा सके। पुनर्वास संबंधी एकमुश्त कार्यक्रमों के अनुपालन को तेज करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने रूग्ण/कमजोर इकाइयों के लिए ऋण संवितरण के वास्ते (कार्यकारी पूंजी/पुनर्वास के लिए सीयादी ऋण) संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत “उधार के लिए एकल स्रोतीय संकल्पना” का विकास किया है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह भी विकल्प दिया

गया है कि वे अलग-अलग मामलों के आधार पर ब्याज/मीयादी ऋण को इक्विटी अथवा सहईक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। ताकि पुनर्वास योजना के अंतर्गत ईकाई का ऋण संबंधी बोझ कम हो जाए।

9.25 पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से पुन-रुद्धार के अंतर्गत रूग्ण/कमजोर ईकाईयों को निर्धारित सीमा से अधिक बैंकों द्वारा रियायत/राहत देने के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को रिजर्व बैंक ने समाप्त कर दिया है। इसके बदले बैंक ने तिमाही ग्लान्टों की एक प्रणाली शुरू की है जो रूग्ण/कमजोर औद्योगिक ईकाईयों के पुनर्वास के क्षेत्र में अपने कार्य-निष्पादन को चलाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1985 का दिसम्बर 1991 में संशोधन किया गया जिसमें इसका विषय क्षेत्र बढ़ा दिया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कंपनियों को भी इस अधिनियम की सीमा में लाया जा सके।

9.26 सितम्बर 1989 और सितम्बर 1990 के बीच रूग्ण लघु उद्योग ईकाईयों की संख्या (जिनमें ग्रामीण हस्त-शिल्पी कुटीर और ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं) 1,86,441 से बढ़कर 2,25,324 हो गयी, अन्य बड़ी रूग्ण/कमजोर ईकाईयों की संख्या 2,181 से बढ़कर, 2,284 हो गयी। बकाया बैंक ऋण बढ़कर 9,930.38 करोड़ रुपये का हो गया, जबकि पिछली अवधि में यह 6,501 करोड़ रुपये था और इस प्रकार यह कुल बैंक ऋण का 9.7 प्रतिशत तथा उद्योगों को कुल बैंक अधिमां का 17.7 प्रतिशत बनता है।

9.27. वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता :— सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक अपने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि) से असात मीयादी ऋण उपलब्ध कराना था परंतु वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय बजट के एक भाग के रूप में लिये गये निर्णय के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ में से दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियों को इस प्राणय से राशि आबंटन की परंपरा बंद कर दी गयी है कि वे उस राशि से औद्योगिक कृषि वित्तीय संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें। अतः वर्ष 1992-93 से दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियों से प्राप्त संस्थाओं को कोई राशि आबंटित नहीं की जाएगी।

9.28 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए रिजर्व बैंक में संपर्क ईकाई के रूप में काम करने के लिए स्थापित वित्तीय संस्था कक्ष ने इस संबंध में एक तिमाही सूचना प्रणाली प्रारम्भ कर दी है। इस प्रणाली के अंतर्गत। एकत्रित किये गये आकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और नीति तथा कार्यकलापों की निगरानी के प्रयोजन के लिए

सूचना की पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब तक 11 प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को इस कक्ष की निगरानी के अंतर्गत लाया गया है वित्तीय क्षेत्र में किये गये सुधारों के संदर्भ में, तथा वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण में और अधिक ध्यान देगा उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशों को, जो वित्तीय संस्थाओं पर लागू होने योग्य हैं, दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (क) वे संस्थाएं जो लेखा पद्धति की प्रक्रियाओं/मानकों (जैसे पूंजीगत पर्याप्तता आयुक्त मान्यता, अशोध्य ऋणों और अधिमां के लिए) प्रावधान करना और आस्त्रियों का वर्गीकरण, निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों में प्रगतिकरण और कराधान से जुड़ी हैं, तथा (ख) वे संस्थाएं जो वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य और संदिग्ध ऋण संविभागां की वसूली कार्यक्रमों से जुड़ी है। उक्त समिति की कुछ सिफारिशें जो पूंजीगत पर्याप्तता और विवेक सम्मत लेखा मानदंडों से जुड़ी है जो कि वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने योग्य है, उनके संबंध में जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, पहले ही आवश्यक कार्यवाई की जा चुकी है, भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करके उपयुक्त मानदंड सीधे ही लागू करेगा।

9.29 आवास वित्त :— प्रत्येक बैंक द्वारा आवास समिति के लिए अपनी वृद्धिशील, जमाराशियों के (अप्रैल 1991 से मार्च 1992 तक की अवधि के लिए जिसमें से ली गयी राशि) 1.5 प्रतिशत के लक्ष्य के आबंटन किये जाने के अलावा, वर्ष के दौरान यह अंतर्गत लगायी गयी थी कि (1) आबंटन का 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष उधार के रूप में दिया जाएगा जिसमें से कम से कम आधा भाग ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा (ii) 30 प्रतिशत मीयादी ऋण के रूप में आवास वित्त कंपनियों, आवास बोर्ड और अन्य सार्वजनिक आवास एजेंसियों को तथा (iii) शेष 40 प्रतिशत गारंटीकृत बांडों और राष्ट्रीय आवास बैंक के डिबेंचरों तथा आवास और शहरी विकास निगम को अधिधान के रूप में होगा बैंक अपने संसाधनों की स्थिति तथा अपनी सांविधिक प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने लक्ष्यों से अधिक भी आवास वित्त उपलब्ध करा सकते हैं।

9.30 मध्यवर्ती उधारदात्री एजेंसियों को वित्तपोषण के मामले में उधार की ब्याज दर 2 लाख रुपये से उपर की श्रेणी के मामले में लागू ऋण सीमाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम होगी। यह रियायत केवल तभी उपलब्ध होगी यदि कम से कम 75 प्रतिशत आवास ईकाईयां बूडकों द्वारा यथापरिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए तथा निम्न आय समूहों के लिए हों, तथा अंतिम उपभोगकर्ताओं से वसूल की जानेवाली ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित उधार की ब्याज दर संरचना के अनुरूप हों। अनु-

सूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को 5,000 रुपये तक के ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर दिये गये। 14 मई, 1991 में ऋणों का विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लाया जा सकेगा बशर्ते ऐसे हिताधिकारी उक्त योजना के अंतर्गत प्रायः के मानदंडों का पूरा करते हैं।

9.31 बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भूमि के मामले में मट्टेबाजी गतिविधियों को बैंकिंग प्रणाली द्वारा समर्थन न दिया जाए तथा यह कि “वास्तविक संपदा” (अचल संपत्ति) के प्रयोजनों के बकाया ऋणों में कोई वृद्धि न हो। तथापि बैंकों द्वारा अपने आवास वित्तपोषण के लक्ष्यों के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

9.32 भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई 1992 को राष्ट्रीय आवास बैंक की एक “सार्वजनिक वित्तीय संस्था” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संसाधनों के संग्रहण के वास्ते अपनी गतिविधियों को प्रभावी रूप से विशालीकृत कर पाया राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 अप्रैल 1992 को जारी की गयी अधिसूचना के अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंकों की श्रेयर पूंजी मार्च 1992 में 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गयी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से राष्ट्रीय आवास बैंक को 50 करोड़ रुपये का ऋण दिया जिसके साथ इस निधि से आवास बैंक को दिया गया कुल ऋण 175 करोड़ रुपये का हो गया।

9.33 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण :—तीन वर्ष पूर्व शुरू किये गये सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का कार्यक्रम स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित केन्द्रीय मूल्यांकन दल की सिफारिशों के अनुसार “सेवा क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली” के अंतर्गत आकड़ों के कंप्यूटरीकरण का कार्य विभिन्न राज्यों में विभिन्न बाह्य कंप्यूटर एजेंसियों को दिया गया था और बैंक की विवरणियों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य अब शुरू हो चुका है।

9.34 कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 :—जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990—30 जून 1991 को समाप्त हो गयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड द्वारा पहले सूचित किए गये आकड़ों से यह संकेत मिलता है कि बैंकों द्वारा 7,917 करोड़ रुपये का ऋणराहत प्रदान किया गया जिसमें से सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों

ने 2,962 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 808 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों ने 4,147 करोड़ रुपये प्रदान किये। इस पर बैंकों ने प्रदत्त ऋण राहत का बतवापन करने के उपरान्त कुल 7,800 करोड़ रुपये (अनन्तिम (-) वाणिज्य बैंकों ने 2,841 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 804 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों ने 4,155 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए बजट आबंटनों में से भारत सरकार द्वारा जून 1992 तक 2,925 करोड़ रुपये तीन एजेंसियों को प्रतिपूर्ति हेतु आबंटित किए गए (755.04 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को, 592 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 1,577.16 करोड़ रुपये सरकारी बैंकों को)। इसके साथ ही सरकारी समितियों के उधारकर्ताओं के लिए इसे योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के 50 प्रतिशत हिस्से को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम से कुल 1,604.16 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये।

9.35 बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी जिसमें उक्त समिति ने ग्राहक सेवा के अनन्त क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें सुधार की आवश्यकता है और बैंकों में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए अनेक सिफारिशों की हैं। रिजर्व बैंक ने उक्त समिति की विभिन्न सिफारिशों की भलीभांति जांच की है और यह निर्णय लिया है कि बैंकों को इसे तेजी से लागू करना चाहिए ताकि ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान की जा सके।

9.36 लघु उद्योगों पर गठित समिति :—दिसम्बर 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री पी. आर. नायक, तत्कालीन रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि वह लघु उद्योगों आदि की कार्यकारी पूंजी तथा सीमादी ऋण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा करे। यह रिपोर्ट अगस्त 1992 के अंत तक प्रस्तुत की जानी है।

10.1 नवे सहकारी सहकारी बैंकों को लाभमय देने के संबंध में गठित समिति :—जैसा कि पिछले वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है रिजर्व बैंक ने श्री एच. एल. मरठे, रिजर्व बैंक के बोर्ड के एक सदस्य, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जो नवे सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के संबंधित नीति तथा अन्य संबंधित मामलों पर परीक्षा करें। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई 1992 को प्रस्तुत कर दी है। उक्त समिति ने कुछ अधिक उदार प्रवेश नीति अपनाने का पक्ष लिया है और यह सिफारिश की है कि प्रस्तावित केन्द्र/क्षेत्र में सहकारी संस्था की आवश्यकता तथा विवेक समस्त मापदंड पर नवे सहकारी बैंकों के संगठन को अनुमति दी जा सकती है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां सहकारी आंदोलन की जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं, वहां सहकारी बैंकिंग गतिविधियों के विकास बैंकों बढ़ाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए। उसने यह सुझाव दिया है कि प्रारं-

अधिक श्रेष्ठ पूँजी के संबंध में की पंजीकरण पूर्व प्रविष्टि बिन्दु का आधार है उसे बढ़ाया जाए और 3 से 5 वर्ष के बीच में इसकी संभाव्यता के संबंधित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए बल दिया जाए। वर्तमान बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे भी इसी मानदंडों को प्राप्त करें। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रविष्टि बिन्दु और मानदंडों में कुछ ढील दी जाए तथा संभाव्यता का प्राप्त करने के लिए समय सीमा की सूची का गमना किया जाए। विशेषकर उन बैंकों के लिए जो पिछड़े हुए और कम विकसित राज्यों तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। साथ ही नये शहरी बैंकों के लिए संगठित मानदंडों के साथ साथ अन्य शहरी बैंकों के ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूची में संबंधित वर्तमान मानदंडों में और ऊर्ध्वमुखी सुधार किया जाये। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि महानगरीय क्षेत्रों के शहरी सहकारी बैंक उन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में भी कार्य करें। शहरी बैंकिंग संरचना एक सुदृढ़ और सक्षम रूप में कार्य करे इसके लिए, वर्तमान में एक ऐसी निगरानी प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की है जो बैंकों को अपेक्षाओं के संकेत दे सके और उसकी पूर्णता का समय रहते पता लगा सके, उसके पुनर्बांध की कार्य नीति निर्धारित कर सके और जो बैंक पुनर्बांध संबंधी कार्य नीतियों के अनुरूप कार्य न कर सके, उनके भावी विकास के बारे में निर्धारण कर सके। शहरी सहकारी बैंकों के प्रति परामर्षन की वर्तमान योजना को दूर करने के लिए यह सिफारिश की गई है कि राज्य सरकार/राज्य सहकारी बैंक/ग्रामीण मध्यवर्ती सहकारी बैंक शहरी सहकारी बैंकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/सेवाओं में संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगी।

10.2 मरटे समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिये जाना और उन्हें क्रियान्वित किया जाना शुरू हो जाने पर शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र में बैंकों की नीतिगत पहल का मुख्य बल नये बैंकों का लाइसेंस देने में विनियमों की छीरे छीरे छूट देने का रहेगा, कम विकसित राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन के लिए संबंधनात्मक पहल इसी क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण, आधारित है, लगभग 313 लाइसेंस रहित बैंकों के के संबंध में स्थिति की दुर्नि-क्षत बनाता, कमजोर बैंकों को समाप्त करना तथा सुदृढ़ और सक्षम आधार पर समेकित भावी विकसित करना जिसमें विनियामक तथा पर्यवेक्षी प्रक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

10.3 सहकारी बैंकों का पुनर्वास :- शहरी सहकारी बैंकिंग तंत्र के पर्यवेक्षण, निगरान और विकास के लिए अपने एक कार्यक्षेत्र के भाग के रूप में रिजर्व बैंक की यह प्रतिबद्धता करना होता है कि एक सुदृढ़ तथा सक्षम शहरी सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का अस्तित्व बना रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत बैंकों के पुनर्वास की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयास रहे हैं, तथा ऐसे बैंकों के कमजोर होने के कारण हैं - उनके द्वारा धारित निधियों में ह्रास होना, प्रतिदेयों का उच्च स्तर होना, न्यूनतम श्रेष्ठ पूँजी के संबंध में बैंकारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) का अनुपालन करना और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित मानदंडों के आधार पर उनको नियत समय पर निष्पादित न करना। वित्तीय स्थिति में भारी गिरावट दर्शाने वाली शिकायतों के निरीक्षण/जांच के विपरीत निष्कर्षों को देखते हुए बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (जो सहकारी समिति पर लागू है) के अन्तर्गत 3 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का निर्देश जारी किया गया थे जिनमें, अन्य बातों के साथ साथ जमाकर्ताओं को भुगतान करने व निविष्ट राशि से अधिक राशि न करने, पर रोक लगाने और श्रृंखला प्रथियों का सजुरी देने का नर्तककरण करने पर प्रतिषेध की व्यवस्था थी। इस प्रकार से, इन निर्देशों के अंतर्गत कुल 11 बैंक कार्य कर रहे थे।

10.4 मेट्रोपोलिटन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का समापन :- पूर्व में यह उल्लेख किया गया था कि एक मेट्रोपोलिटन कोऑपरेटिव

बैंक लिमिटेड द्वारा कुछ बैंकों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ाया राशि की "बैंक ग्यारेन्टी" जारी की गई, जबकि बैंक को कार्यशील पूँजी 8 करोड़ रुपये में भी कम थी। इस संबंध में अनियमितताओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने मई 1992 मशरूफ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 110ए (iii) के अनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उस सहकारी बैंक के बोर्ड के निदेशों को तुरन्त बदलने तथा इसके स्थापन पर एक प्रमाण का कार्यवाही जोड़ने तथा इस बैंक का कार्य संजालत करने के लिए कहा। संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने और विधिवत विचार करने बाद, रिजर्व बैंक ने 19 जून, 1992 को बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी प्रदान की। निरपेक्ष सीमा और प्रत्येक गारंटी निदान में धनुरोध किया गया है कि यह बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए तैयार रहे और जमाकर्ताओं के खाते में बढ़ाया राशि में से प्रत्येक जमाकर्ता की अधिकतम 30,000 रुपये तक की राशि का भुगतान करें।

10.5 सहकारी बैंकों के लेखा वर्ष में परिवर्तन :- लेखा अवधि 1991-92 के बाद के सहकारी बैंकों को लेखा अवधि वाणिज्य बैंकों को लेखा अवधि के अनुरूप हो कर दी गई है। बैंकारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 (i) में संशोधन कर दिया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक ऐसी तारीख निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है जिसके संबंध में सहकारी बैंक वार्षिक लेखा तैयार करेंगे। तदनुसार केन्द्र सरकार ने 29 जनवरी, 1992 को एक अधिवृत्ता जारी की जिस में प्रत्येक वर्ष को 31 मार्च वार्षिक लेखा के बंद करने की तारीख निर्धारित की गई तथा सहकारी बैंकों द्वारा लेखा बन्द करने की तारीख 31 मार्च 1992 रखी गई जिसमें जुलाई 1991 की पहली तारीख से मार्च 1992 की 31 तारीख तक का अवधि शामिल होगी।

XI बेकेतर वित्तीय और गैर-वित्तीय सम्पत्तियों द्वारा अमाराणिया स्वीकार किया जाना

11.1 बिट फंड अधिनियम, 1982 :- अधिनियम का अब तक 19 राज्यों/मंच प्राप्तित क्षेत्र में लागू किया जा चुका है - अर्थात् असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अंडोरा, दादरा व नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। शेष राज्यों/मंच प्राप्तित क्षेत्रों के मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

11.2 अनियमित निकायों द्वारा जमागतियों स्वीकार किया जाना :- परमिआधीन रूप के वीरान नोन और संघ प्राप्तित क्षेत्रों को अधिवृत्ताए जारी की गई हैं जिनमें अनियमित निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी और 58ई में परिकल्पना की गई है। इन कार्रवाई के करने से ऐसे राज्यों/मंच प्राप्तित क्षेत्रों को कुल संख्या 30 हो गई है। जैसा कि इन रिपोर्ट में सूचना दिया गया था, 19 अनियमित निकायों के विरुद्ध चलाये गये अधिवृत्ताओं में से 5 मामलों में जांच न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है। अन्य मामलों जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

11.3 वित्तीय कंपनियों पर कार्यकारी दण :- मई 1992 में रिजर्व बैंक ने बैंक अपाद बढ़ावा के अध्याय डा ए. सी. भाइ का अधिनियम में एक कार्यकारी दण गठित किया। दण का कार्य गैर-वैकिंग कंपनियों को भूमिका का गहराई में अध्ययन करना और वित्तीयमक तथा निराकरण उपाय का

सुझाव देना था ताकि इन कंपनियों के स्वरूप परिवर्तनों की सुविधित किया जा सके। यह द्वारा अपनी रिपोर्टें अगस्त 1992 के अंत तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

11.4 गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा राशियों के स्वीकरण के प्रति बैंक की नीति और विनियमन :- पूर्ववर्ती रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया था गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों अपनी जमा राशियों पर जो अधिकतम व्याज दर दे सकती है उसे 27 जुलाई, 1991 से 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत वार्षिक कर दिया था। सितम्बर 1991 में यह निश्चित किया गया कि व्याज का भुगतान या समायोजन तत्पश्चात् अंतरालों पर किया जाए। तथापि, 17 जून 1992 से इन कंपनियों को ऐसे अंतरालों पर व्याज का भुगतान या समायोजन किये जाने की अनुमति दे दी गई जो मासिक अवधियों में कम न हो। बैंक जमा राशियों के रूप में चल आस्तियों को रखने और किराया खरीद तथा उपस्कर पट्टेदारी कंपनियों द्वारा सरकारी तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों की प्रपेक्षाओं को जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 तिशत कर दिया गया है जो 1 नवम्बर 1991 से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही में से एक एक प्रतिशत करके प्राप्त किया जाएगा, और 1 नवम्बर 1992 को तथा इस तारीख से 15 तिशत तक हो जाएगा। 15 प्रतिशत चल आस्तियों में से, कम से कम 5 प्रतिशत केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और/अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकार के गारंटीकृत बांडों के रूप में रखा जाएगा। ऋण और निवेश कंपनियों द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली जमा राशियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम अवधि को क्रमशः 6 महीने और 36 महीनों की अवधि से बढ़ाकर क्रमशः 24 महीने तथा 60 महीने से अधिक कर दिया गया है जैसा कि किराया खरीद और उपस्कर पट्टेदारी कंपनियों के मामले में किया गया है। यह भी तय किया गया है कि यदि कोई कंपनी किराया खरीद वित्त और उपस्कर पट्टेदारी संबंधी दोनों ही प्रकार के कार्यकलापों में लगी है तो उसके इन दोनों कार्यकलापों के कारोबार को, उसके प्रमुख कारोबार और वर्गीकरण को निर्धारित करते समय एक ही माना जाएगा। औसतन 3 वर्ष के आधार पर कंपनी को अपनी आस्तियों का लगभग 50 प्रतिशत किराया खरीद और उपस्कर पट्टेदारी के रूप में रखना चाहिए और यह इन दो कार्यकलापों से होने वाली अपनी आय का कम से कम सौसरा हिस्सा रख सकती है ताकि उसे किराया खरीद या पट्टेदारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

XII. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

12.1 निगम की निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता बीमा सुरक्षा और बीमा प्रीमियम की दर क्रमशः 30,000 रुपये और 4 पैसे प्रति 100 रुपये वार्षिक के हिसाब से अपरिवर्तनीय रही। जून 1991 के अन्त में पूर्ण सुरक्षित खाते जमा खातों की कुल संख्या का 96.4 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान निगम ने एक वार्षिक बैंक और चार सहकारी बैंकों से संबंधित बांधों के निपटान के रूप में कुल 7.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा बांधा देयताओं के लिए 50.97 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है (बैंक आफ कराइ लिमिटेड के लिए 45.43 करोड़ रुपये की राशि सहित)। इस बात के लिए मांग बढ़ती जा रही है कि बीमा सुरक्षा की वर्तमान सीमाएं अपर्याप्त हैं। तथापि बीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की वृद्धि करने पर प्रीमियम दर के वर्तमान स्तर में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। यह मामला विचारणीय है।

12.2 प्रत्यय गारंटी योजनाओं में से निगम ने तीन योजनाओं को समाप्त कर दिया है अर्थात् लघु ऋण (वित्तीय निगम) गान्धी योजना, 1971 सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1971 और लघु ऋण (सहकारी ऋण समिति) गारंटी योजना 1982। इन योजनाओं को,

गारंटीकृत अधियों की राशि लघु या मामूली होने तथा सहभागिता वाली संस्थाओं द्वारा गारंटी शुल्क आदि का भुगतान बराबर न करने की वजह से 1 अप्रैल 1992 में समाप्त कर दिया गया। तथापि, छोटे उधारकर्ताओं के लिए दो योजनाएं, अर्थात् लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 और लघु औद्योगिक ऋण की एक योजना, अर्थात् लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 चालू है तथा कुल गारंटीकृत अधियों में इन दोनों योजनाओं का 99 प्रतिशत से भी अधिक का हिस्सा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत गारंटीकृत अधियों की राशि 31 मार्च 1991 से बढ़कर 46,543 करोड़ रुपये हो गई थी। 1 अप्रैल 1989 से गारंटी शुल्क दर को 50.75 पैसे से 1.50 रुपये प्रति 100 रुपये बढ़ा दिये जाने के बावजूद भी गारंटी शुल्क प्राप्ति में गारंटी दावा प्राप्ति से लगातार दो वर्ष तक कम रही। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वर्तमान गारंटी योजनाओं की परिवर्तनात्मक संभावना की पुनः समीक्षा की जाए।

XIII. विनियम प्रबंधन और विदेशी मुद्रा नियंत्रण

13.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विनियम प्रबंधन और नियंत्रण में पर्याप्त पुनर्विचार देखा गया। 1 मार्च 1992 से उदासीकृत विनियम पर प्रबंधन प्रणाली लागू करना जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, चालू खाते में बाह्य लेन देतों के लिए रुपये को खर्चबंद रूप में परिवर्तनीय बनाने का लक्ष्य मध्यावधि उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक प्रमुख प्रयास रहा। रिजर्व बैंक ने विनियम नियंत्रण का प्रत्येक पहलुओं को भी उधार बनाया है उनमें से कुछ को मरनीकृत किया है, उनकी जटिलता को कम किया है और विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए इसकी शक्तियों को कम करके प्राधिकृत विक्रेताओं को प्रवृत्त कर दिया गया है। तथापि बैंकों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से संबंधित प्रौद्योगिकी करार करते सहित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन देने और प्रत्यावधि की परिकल्पना वाले विदेशी मुद्रा-ऋण/साख संबंधी अनुमोदन करने की अनिवार्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

13.2 विदेशी निवेश :- निर्यात में वृद्धि करने और उत्पादन आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च तकनीक को प्राप्त करने के लिए भारी निवेशों और तकनीकी सहयोगी की प्रपेक्षा वाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में, औद्योगिक नीति के विवरणी के अनुबंध III में दिए गये उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब स्वतः अनुमोदन दिया जा रहा है। मूलतः निर्यात गतिविधियों में संलग्न व्यापारिक कंपनियों में भी ऐसे निवेशों की अनुमति दी जा रही है। तथापि जैसा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में अनिवार्य भारतीयों द्वारा 100 प्रतिशत इतिरिक्त निवेश को भी अनुमति दी जा रही है। अनिवार्य भारतीयों द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नये निर्णयों पर 100 प्रतिशत तक अपरिवर्तनीय आधार पर विशिष्ट वास्तविक प्रचल सम्पत्ति के विकास के क्षेत्र में संलग्न चालू या नयी कंपनियों को अनिवार्य भारतीयों को शेयर/परिवर्तनीय निवेश जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

13.3 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा - रक्षकता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उच्च तकनीक को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय कंपनियों और उनके विदेशी सहयोगियों के बीच तकनीकी करारों के लिए स्वतः अनुमति दे रहा है। इस प्रक्रिया में सहयोग हेतु विदेशी तकनीकियों को किराये पर लेना और भारत में विकसित तकनीकों के विदेशी परीक्षण को पहले की भांति सरकार/रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की शर्त से मुक्त किया गया है।

13.4 भारतीय फर्मों/कंपनियों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा अध्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रत्यक्ष निवेश :- रिजर्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी पूर्ण अनुमति के अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों को अध्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में निर्गमि किसी कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने या उनमें अधिदान करने के लिए चाहे वो सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से हों या निजी संस्धान द्वारा, मात्र ही भारत में किसी भी स्थामित्व या दावेदारी कंपनी में पूंजी सहयोग द्वारा निवेश कर सकते हैं।

13.5 भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासी भारतीयों द्वारा संविभागीय निवेश योजना के अन्तर्गत निवेश :- अनिवासी भारतीयों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विदेशाधीन सीमाओं तथा इस प्रभाव के ग्राम सभी के संकल्प के अन्तर्गत भारत के शेयर बाजार/(रों) में संविभागीय निवेश योजना के अन्तर्गत अध्रत्यावर्तनीय और अध्रत्यावर्तनीय दोनों आधारों पर संबंधित कंपनी की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 24 प्रतिशत और कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रेणी के कुल प्रदत्त 'मूल्य का 24 प्रतिशत, जबकि इसकी पिक्की सीमा 5 प्रतिशत हो, भारतीय कंपनियों के शेयर/डिबेंचर खरीदने के लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी निर्गमित निकायों को अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

13.6 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को, चाहे वे भारत में रहते हों या नहीं छ शर्तों के अन्तर्गत भारत में निवृत्त प्रचल सम्पत्ति अध्रत्यावर्तनीय उद्देश्य के लिए बि.पी.मुद्रा में मुगलान द्वारा खरीदने के लिए अब सामान्य अनुमति दे दी गई है।

13.7 गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और विदेशी कंपनियों द्वारा प्रचल संपत्ति का अधिग्रहण :- यह निर्णय किया गया है कि गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक चाहे वे भारत में रहते हों या नहीं और विदेश में निर्गमित विदेशी कंपनियों, ग्राम, सोसाइटी और एसोसिएटों को भारत में प्रचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारिता, अंतरण या विक्रय की अनुमति दी जाए, बसते इनके क्रय की राशि बि.पी.मुद्रा में विदेशों से धन प्रेषण के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी हों। सम्पत्ति के अधिग्रहण की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सम्पत्ति से प्राप्त किराये या विक्रय प्राप्ति को किसी भी रूप भाग से बाहर नहीं भेजा जाएगा।

13.8 अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वर्ण का आयात :- भारतीय राष्ट्रीयता मूल के लोगों को भारत में आने समय अपने सामान के एक भाग के रूप में 5,000 ग्राम तक (अर्थात् 5 कि. ग्राम) किसी भी रूप में स्वर्ण को लाने की सामान्य अनुमति दी गयी है बशर्ते सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत देय शुल्क की प्रदायगी किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में की जाती है। शुल्क की दर प्रारम्भ में 450 रुपये प्रति 10 ग्राम रखी गई थी बाद में उसे घटाकर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम कर दिया गया। अनिवासी भारतीयों के मामले में सामान्य अनुमति छह महीने में एक बार उपलब्ध होगी, जबकि अन्य लोगों के मामले में यह अनुमति उसी स्थिति में मिलेगी, जबकि उनका भारत के बाहर प्रवास भारत में आने के समय छह महीने कमन हो।

13.9 फेरा समीक्षा :- संस्धार ने अपने इस उद्देश्य की भी घोषणा की है कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 को संशोधन तथा विनियमों को हटाने के लिए फेरा अधिनियम की विस्तार से समीक्षा की जाएगी जिससे भारत में विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह और भारत

कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्योगों में निवेश में बाधा उत्पन्न होती हो।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने फेरा के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य अनुमति देने हुए कई अधिभूचनाएं जारी की हैं। इस प्रकार फेरा 1973 की धारा 26 (7), 28, 29 और 31 अन्तर्गत फेरा कंपनियों (अर्थात् भारत में निर्गमित कंपनियों जिनमें अनिवासी भारतीयों का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक हो) पर लागू सभी प्रतिबंध निम्नलिखितनुसार हटा दिए गये हैं और इस प्रकार उन्हें भारत में व्यापार के लिए अन्य भारतीय कंपनियों के समकक्ष रखा गया है। फेरा कंपनियों का अब अनुमति है कि वे :

- (क) भारत में निवास कर रहे कंपनियों से धन उधार ले सकती हैं या जमा राशि स्वीकार कर सकती हैं ;
- (ख) भारत के किसी व्यक्ति या कंपनी के एजेंट या तकनीकी या प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर सकती हैं ;
- (ग) किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने व्यापार चिन्ह का प्रयोग किए जाने की अनुमति ले सकते हैं ;
- (घ) भारत में कृषि और बागान को छोड़ कर व्यापार, वाणिज्य या औद्योगिक प्रकृति की किसी भी भविष्य की बना सकते हैं ;
- (ङ) भारत में कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के उत्क्रम का अधिग्रहण कर सकती हैं या ऐसी कंपनी के शेयर खरीद सकती हैं ;
- (च) भारत में किसी प्रचल सम्पत्ति को बेचने, बंधक रखने, भोज पर, उपहार, हस्तान्तरण द्वारा या उनका और किसी माध्यम से अधिग्रहण, धारण या विक्रय कर सकती हैं।

13.10 भारत विकास बांड और उत्पत्ति योजना :- 'विदेशी मुद्रा का प्रेषण तथा विदेशी मुद्रा बांडों में निवेश (उत्पत्ति और छूट) अधिनियम 1991' (जो 18 सितम्बर, 1991 को प्रस्तावित हुआ) के अन्तर्गत जो योजनाएं लागू की गयीं।

13.11 इस अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 'विदेशी मुद्रा में प्रेषण (उत्पत्ति) योजना, 1991' तैयार की जिसके अन्तर्गत अध्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत को निधियों का एक बार अंतरण करने की अनुमति दी गयी जिनके तारे में प्राधिकारताओं से निधियों का स्वतः या प्रेषण का प्रयोजन और स्वरूप नहीं पूछा जाएगा तथा उन्हें विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों और प्रत्यक्ष-कार निधियों से छूट प्राप्त होगी, जो योजना प्रारंभ में 30 नवम्बर 1991 तक खुली थी उसे जनवरी 1992 तक बढ़ा दिया गया।

13.12 अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को मूलतः 9.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर घमरीकी डालर में परन्तु बाद में भी 13.25 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर पौंड स्टर्लिंग में व्याज और मूलधन दोनों के पूर्ण प्रत्यावर्तन वापस सहित आबंटन की सारीख से पांच वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए, भारत विकास बांड जारी करने की अनुमति दी। मूलतः यह योजना 1 नवम्बर 1991 और 30 नवम्बर 1991 के बीच खुली रहती थी परन्तु इसे 31 जनवरी 1992 तक बढ़ा दिया गया। भारत विकास बांडों के पत्र अभिवादन के अनिवासी भारतीय, विदेशी निर्गमित निकाय और अतिरिक्त भारतीयों तथा विदेशी निर्गमित निकायों को आर.से.प्रत्यक्ष आधार पर कार्यकर रहे बक प्राधिकृत व्यापारियों को कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत विकास बांडों के अनिवासी धारकों को उनकी प्रतिभूति पर संपत्ति, ऋण

स्वीकृत करने के लिए अनुमति दी गयी है। यह रूपया ऋण प्रतिभूति के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक और व्याज दर बैंक दर के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

स्वैप

13.13 स्वैप बैंक ने 29 अप्रैल, 1991 में डालर/रुपया स्वैप लेन-देन प्रारम्भ किये। इन स्वैपों की प्रकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन और छह माह की परिपक्वताओं के लिए अमरीकी डालरों की हाज़िर खरीद और वायदा बिक्री के रूप में थी।

इन सौदों के पीछे विशेष प्रयोजन अन्त बैंक बाज़ार में उस अधिक चलविधि को समाप्त करना था जो उस समय बढ़ जाती है जब प्राधिकृत व्यापारी ग्राहकों को अपनी वायदा बिक्री को पूरा करने के लिए हाज़िर डालरों की खरीद करते हैं और यदि प्रीमियम उच्च हो तो इस अन्तर का फायदा उठाते हैं।

13.14 स्वैप काउन्टर को सितम्बर 1991 में 2.4 और 5. महानों के लिए चलाया गया और यह 19 फरवरी, 1992 तक जारी रखा गया, जबकि इसे अस्थायी रूप में बंद कर दिया गया था। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के प्रारम्भ होने के बाद बैंक ने 3 मार्च, 1992 से दो, तीन, चार, पांच और छह माह के लिए नियत तारीख वाली सुपुर्दगी के लिए कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डालर के वाट में स्वैप पुनः प्रारम्भ की। 30 जून 1992 को स्वैप सौदों में 2,051.25 मिलियन अमरीकी डालर बकाया था।

विदेशी मुद्रा/बाह्य खाते

13.15 कुछ नये विदेशी मुद्रा/बाह्य खातों को रखने की अनुमति दी गई है। पहला है "विदेशी मुद्रा अर्जकों की विदेशी मुद्रा खाता" जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के सभी निर्यातक और अन्य सभी प्राप्तकर्ता जिन्हें परिवर्तनीय मुद्रा में भाग्य विप्रेषण प्राप्त होते हैं उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत अपनी प्राप्ति का 15 प्रतिशत रख सकते हैं। खाते किसी भी रूप में रखे जा सकते हैं जैसे भारत के बैंकों में बालू बचत या मासिक जमा खातों के रूप में ऐसे खातों में रखी गयी निधियों का उपयोग व्यापार और विदेशी मुद्रा वियंक्षण विनिमयन के अन्तर्गत अनुमत बालू खाता अदायगी के लिए किया जा सकता है। इस अनुमति के कारण वर्तमान केफेक्स और बेक्रेन्त परमिट धारकों को 31 मार्च 1992 तक उक्त परमिटों के विरुद्ध उपलब्ध शेष में से सभी अनुमत उद्देश्यों के लिए विप्रेषण सुविधा प्राप्त करने रहने की अनुमति होगी।

13.16 दूसरा है, भारत की विदेशों में स्थित बैंकों के पास भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना। इसकी अनुमति अत्यन्तमक आधार पर ऐसे निर्यातकों को दी जाएगी जिनका पिछला रिकार्ड संतोषजनक रहा हो तथा प्राधिकृत व्यापारियों को नामित शाखाओं के पास विदेशी मुद्रा खाते रखने हेतु बाह्य समूह के देशों को किये जाने वाले निर्यातों और उन देशों में किये जाने वाले आयातों से पिछले वर्ष के दौरान जिनका निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 4 करोड़ रुपये से कम नहीं रहा हो। विदेश स्थित बैंक में विदेशी मुद्रा खाते रखने के संबंध में रिजर्व बैंक ऐसे मामलों पर विचार करेगा जहां निर्यातक निर्यात के प्रयोजनों के लिए आयात की अपनी आवश्यकताओं के विप्लोषण हेतु विदेश स्थित बैंकों से विदेशी मुद्रा में ओवरड्राफ्ट/नबीकरण से युक्त ऋण सुविधाएं पाने की व्यवस्था करने की स्थिति में है। निर्यातक द्वारा अमरीकी डालर या पौंड-स्टर्लिंग में सामान्यतः केवल एक ही खाता रखे जाने की अनुमति दी जायेगी। ऐसे निर्यातक का जिसे भारत या विदेश में स्थित बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी गई हो, उसके द्वारा किये गये सभी निर्यात पोतलवानों की प्राप्तिओं बाह्य समूह के देशों (उन देशों की छंड़कर जो एशियाई समा-प्रोधन संघ के सदस्य हैं) में ऐसे खातों में जमा करने की अनुमति होगी।

उक्त खाते में जमा निधियों का उपयोग विनिश्चित प्रयोजनों के लिए करने की अनुमति दी जाएगी।

13.17 तीसरा, भारत लीडने वाले भारतीयों द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास निवासी विदेशी मुद्रा (घार एक सी) खाते खोलने से संबंधित है। मौजूदा भारत लीडने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा पात्रता (घार आई एक ई ई) योजना का स्थापित करने वाली इस नयी योजना के अन्तर्गत, भारत लीडने वाले वे भारतीय जो बाह्य समूह के देशों के निवासी रहे हों, भारत में प्राधिकृत व्यापारियों की नामित शाखाओं में अमरीकी डालर में घार एक सी खाते खोल सकते हैं और रख सकते हैं जिनमें विदेश स्थित उनके विदेशी मुद्रा खातों में अनुमत मुद्राओं में उनके नाम जमा पूरी शेष राशियां जो भारत में उनके पहुंचने की तारीख से तीन महीनों के अन्तर अंतरित किये जाते हैं, जमा करने की अनुमति उन्हें होगी।

13.18 एकमोएनघार स्वैप योजना :— विदेशी मुद्रा (अनिव.सी) जमा योजना (एफगोएनघार) के अंतर्गत जमाराशियां घार मुद्राओं अर्थात् पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, ड्यूश मार्क और जापानी येन में स्वीकार की जा सकती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सी परिवर्तनीय मुद्रा रखने वाला कोई ग्राहक उक्त योजना के अन्तर्गत जमा राशि रखना चाहता है तो प्राधिकृत व्यापारियों को किसी अनिवार्य भारतीय (एन घार आई) के पास विद्यमान एक एक सी एन घार मुद्रा के आकार पर उस मुद्रा में पूर्णतः रहित स्वैप करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे घेर-एफ गो एन घार मुद्रा रखने वाला जमाकर्ता एक सी एन घार योजना में भाग ले सकेगा। इस प्रकार का स्वैप दो एक सी एन घार मुद्राओं के बीच करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वैप का अंतर ग्राहक को अदा किया किया जा सकता है या ग्राहक से प्राप्त किया जा सकता है तथा वह ग्राहक और उनके प्राधिकृत व्यापारी के बीच बांटा भी जा सकता है। तथापि प्राधिकृत व्यापारी और रिजर्व बैंक के बीच लेन-देन उक्त घार एक सी एन घार मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा में ही होगा तथा यह एक सी एन घार योजना के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत ही होगा।

13.19 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा में जमाराशियों का स्वीकार किया जाना :— प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि रिजर्व बैंक के पास अमरीकी डालर में रखी गई जमाराशियों पर एक माह के अधिक अवधि की समाप्ति पर देय ब्याज संचन इंटर बैंक द्वारा तदनुकूपी अवधि समाप्ति पर प्रदत्त करें (एल आई बी ओ घार) पर होगा। पूर्व में एक माह और उससे अधिक अवधियों के लिए अमरीकी डालर में जमाराशियों पर देय ब्याज लेन-देन की तारीख से पहले के दिन संचन इंटर बैंक द्वारा एक माह के लिए प्रदत्त दर (एल आई बी ओ घार) के समान दर पर था।

13.20 अंतर बैंक जमाराशियां :— प्राधिकृत व्यापारियों को अपनी विदेशी मुद्रा निधियों का प्रबंध अपने सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विदेशी/मूल्य मानदंडों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत तथा मौजूदा पर्याप्त और प्रभावी आन्तरिक नियंत्रणों के अधीन करने की अनुमति दी गई है। उनमें यह भी शामिल होगा कि वे अपनी परत का राशियों और अवधियों के लिए, निर्धारित बाजार दरों पर स्थानीय अंतर बैंक बाजार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकृत व्यापारियों के पास चार प्रमुख नामित मुद्राओं अर्थात् अमरीकी डालर पौंड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क और जापानी येन में जमा राशियां रखें। यह भी आवश्यक नहीं है कि ऐसे लेन-देन केवल लीडने खातों के निधिकरण व्यवस्था एन खातों में से ओवरड्राफ्ट कम करने के लिए ही हो।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों में उद्घाटन

13.21 नियंत्रण की कठोरताओं को कम करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों को शिथिल किया गया है :

- i) भारतीयों फार्म/कंपनियों को रिजर्व बैंक के पूर्वसुमोदन के बिना विदेशी तकनीक विदों की सेवाएं लेने की अनुमति दे दी गयी है, बशर्ते उन्हें नियुक्त करने की शर्तें दैनिक दर, नियुक्ति की प्रवधि आदि के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी दिशेशों के अनुरूप हों।
- ii) विदेश जाने वाले बाह्य बाह्यों द्वारा स्वर्ण आभूषण और कीमती पत्थर/स्वर्ण आभूषण देश के बाहर ले जाने के मूल्य की सीमाओं में उर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है।

iii) उद्घाटित विनियम दर प्रणाली (एल ई आर एम एम) लागू करने के परिणामस्वरूप निर्यात/इम्पोर्ट/कोफेक्म परमिट योजनाएं हटा दी गई हैं। फिर भी प्राधिकृत व्यापारियों को व्यापार, डाकटरी चिकित्सा, रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण, धनबल संबंधी होरे, सम्मेलनों में भाग लेने आदि के लिए निवासियों की विदेशी यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति दी गई है।

iv) व्यापारियों को प्रतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं कि वे निर्यात बाजारों के प्रेषण, निर्यातों पर कमीशन के प्रेषणों और बीजक मूल्य में कमी की अनुमति दें।

परिशिष्ट सारणियों की विषय सूची

सारणी सं.	शीर्षक	पृष्ठ
	I. नीतिगत गतिविधियां एवं स्वरूप	
1.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अधिभों के लिए ब्याज दर संरचना	2018
1.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों पर ब्याज दरें	2018
1.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निर्यात ऋण पर ब्याज दरें (ब्याज - कर के अभाव)	2019
1.4	न्यूनतम मार्जिन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर (22 अप्रैल, 1992 से)	2020
1.5	विदेशी सहयोग के अनुमोदन (पुलनात्मक आंकड़े)	2021
	II. वास्तविक प्रमुख्यवस्था : कार्य-निष्पादन और समस्याएं	
2.1	क्षेत्रवार संरचना तथा वास्तविक सकल जी उत्पाद (म. दे. उ.) की वृद्धि दरें	2022
2.2	देशी बचत तथा निवेश अनुपात के अनुमान	2022
2.3	कृषि उत्पादन	2023
2.4	पशुओं की सरकारी खराब निकासी और स्टॉक	2023
2.5	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां	2024
2.6	मिनिसॉल क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि	2024
2.7	औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर - उपयोग - आधारित वर्गीकरण	2025
2.8	आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियां	2026
	III. सरकारी वित्त	
3.1	घाटे के उपाय : केन्द्र सरकार का सुदृढ़ित बजट, सकल और निवल राजकोषीय घाटा	2026
3.2	केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के पाक्षिक स्तर	2027
3.3	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	2028
3.4	भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं	2029
3.5	बजट घाटा बाजार ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार को सहायता	2030
3.6	घाटे के मापदंड : राज्यों का सुदृढ़ित, बजट राजस्व, सकल और निवल राजकोषीय घाटा	2031
3.7	राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	2031
3.8	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और भविष्य	2032
3.9	केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी और विकासोन्मुख व्यय	2033
3.10	केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व	2034
3.11	केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा प्रायोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थाओं के बाजार उधार	2035
3.12	केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर कूपन दरें ब्याज दरें	2035

	4. मुद्रा और मूल्य से संबंधित प्रवृत्तियाँ	
4.1	मुद्रा स्टॉक (एम3) में घट-बढ़	2035
4.2	भारत में मुद्रा में घट-बढ़ घटक और स्रोत	2037
4.3	वर्तमान मुद्रा के अनुपात के रूप में बालू बाजार मूल्यों पर प्राय (सकल घरेलू उत्पाद) कुल जमा राशि, एम ₁ और एम ₃	2038
4.4	मौद्रिक अनुपात-वृद्धिशील	2038
4.5	सहस्रपूर्ण बैंकिंग संकेतक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2039
4.6	मार्च 1991 तथा मार्च 1992 के अन्तिम मन्त्रालय की अनुसूचित वाणिज्य बैंक की चुनिंदा मदों में घट-बढ़	2040
4.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर जमा संसाधन	2041
4.8	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण	2041
4.9	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण	2042
4.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता (नौवहन ऋणों, मुद्रा आपसी, आदि पर दिये गये विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर)	2043
4.11	भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह की रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त	2044
4.12	मुद्रा बाजार निश्चयों में भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह का संश्लेषी भाग	2045
4.13	भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह को प्रवर्तन रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त की व्याख्या करें	2046
4.14	भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह की माँग मुद्रा उधार करें	2047
4.15	भारत सरकार के 182 विधेयक खजाना बिल	2048
4.16	भारत सरकार के 364 विधेयक खजाना बिल	2048
4.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्माण	
4.18	थोक मूल्य सूचकांक में बिंदुवार आधार पर घट-बढ़ के तीन चरण	2049
4.19	थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़	2050
4.20	सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूहों/पथों का भारांकित योगदान	2051
4.21	थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रदर्शित मूल्यवृद्धि की वार्षिक और तिमाही दरें (बिंदुवार आधार पर)	2052
4.22	देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमतें	2053
4.23	ग्रामों के अनुसार सोना और चांदी का अनुपात	2054
4.24	सोने और चांदी के मूल्यों में अंतर	2054
	5. पूंजी बाजार की गतिविधियाँ	
5.1	सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता	2055
5.2	गैर बैंकिंग कम्पनी क्षेत्र के पास जमा राशियाँ	2057
5.3	सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए नियंत्रक, पूंजी निर्माण द्वारा प्रवर्तन सहायता/प्रभिकृतियाँ	2057
5.4	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नये पूंजी निर्माण	2058
5.5	भारतीय रिजर्व बैंक के साधारण शेयर मूल्य सूचकांक (साप्ताहिक)	2059
	6. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ	
6.1	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	2060
6.2	वित्तपोषण की आवश्यकता और वित्तपोषण के स्रोत	2061
6.3	भारत की भारत विदेशी मुद्रा निधियाँ	2061
6.4	भारत का विदेश व्यापार	2062
6.5	भारत के मुख्य पथों का निर्यात	2063
6.6	भारत में मुख्य पथों का आयात	2064
6.7	रुपया भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार	2066
6.8	बाह्य सहायता	2067
6.9	अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया खाता योजनाओं के प्रवर्तन जमा राशि की देयताएँ	2068
6.10	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमा राशियों पर व्याज दरें	2069
6.11	भारत के विदेशी ऋण	2070
6.12	रुपये की विनिमय दरें	2071

XIV. रिजर्व बैंक के संगठनात्मक मामले

14.1 मुद्रा तिजोरियाँ :- जून 1992 की समाप्ति पर देश में कुल 3,879 मुद्रा तिजोरियाँ कार्यरत थीं। इनमें से, 2,809 तिजोरियाँ भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास थीं। राष्ट्रीय बैंकों के पास 671 तिजोरियाँ थीं, जबकि खातों और उप खजानों के पास 418 तिजोरियाँ थीं। रिजर्व बैंक तथा जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि. के पास विद्यमान तिजोरियों की संख्या लगातार क्रमशः 17 से 5 पर अपरिवर्तनीय बनी रही। इन तिजोरियों के साथ ही, सांख्यिक क्षेत्र के पास बैंकों के पास रखे गये 492 निधान केन्द्र (रेपोजिटरीज) भी कार्यरत थे।

14.2 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित है, कुछ गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अब 'मुद्रा तिजोरी' खोलने की अनुमति दी गयी है। 15 गैर-सरकारी बैंकों ने मुद्रा तिजोरी की स्थापना के लिए आवेदन किये हैं जिनमें से 7 बैंकों को अपने-अपने कारोबार के क्षेत्र/अंचल में मुद्रा तिजोरी स्थापना की अनुमति दी गई है। एक ने तो उद्यम मुद्रा तिजोरी भी स्थापित कर ली है, जबकि दूसरे ने रिजर्व बैंक के साथ मुद्रा तिजोरी खोलने का करार किया था।

14.3 मुद्रा प्रबंध :- नये नोटों की उपलब्धता के संबंध में स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। काफी समय से नामिक और देवाम स्थित दो मौजूदा नोट मुद्रणालयों से आपूर्तियों की मात्रा कमीबेश बनी हुई है। नये नोटों की मांग में वृद्धि के कारण मांग और पूर्ति के बीच का अंतर विस्तृत होता जा रहा है तथा उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के संबंध में आपूर्ति की कमी अत्यधिक होने के कारण नये नोटों की अनुपलब्धता की शिकायतें बढ़ी हैं। इन परिस्थितियों में बैंक के लिए सभी मुद्रा तिजोरियों को यह सूचित करने की आवश्यकता हुई कि वे नोटों की छटाई करें और निरन्तर आधार पर पुनः जारी करने योग्य अधिकतम संख्या में छांट कर जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रधिक/कमी वाली तिजोरियों की पहचान की आये ताकि एक सक्रिय के अन्तर्गत दूसरे सक्रिय में पारस्परिक अन्तरण लागू किये जा सकें। इस प्रयास के परिणामस्वरूप एवं गंदे नोटों के निरंतर उपयोग के कारण जनसाधारण के पास और मुद्रा तिजोरियों में रखे गये मुद्रा नोटों की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। निरंतर बढ़ रही मांग की पूर्ति करने के लिए उच्चतर मूल्य वर्गों में नये नोटों की आपूर्ति को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता का सर्वोच्च महत्व बना हुआ है।

14.4 मुद्रा प्रबंध संबंधी समिति :- सरकार की दीर्घाविधि सिक्का द्वाला नीति संबंधी समिति के निर्णयानुसार मुद्रा प्रबंध संबंधी समिति के एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को 1995 तक चरणबद्ध रूप से सिक्के में बदलने पर बल दिये जाने से भारत सरकार के स्थायी ढल ने सिक्कों के स्वरूप/विशिष्टता को अंतिम रूप देकर इस 1317 GI/93--13

निर्णय को पहले ही कार्यान्वयन का रूप दे दिया है। इस ढल के अन्य निर्णय इस प्रकार हैं: (i) मैसूर और सालबनी में दो नये नोट प्रेसों की शुष्कता के साथ अपेक्षाकृत छोटे आकार के नये समूह के नोटों का प्रकाशन (ii) उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की बढ़ती हुई मांग को पूर्वानुमान के आधार पर नामिक प्रेस की वर्तमान उत्पादन क्षमता का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा उच्च मूल्य वर्ग नोटों की छपाई करना। इसके अतिरिक्त, मुद्रा प्रबंध संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार बैंक के साथ नकद व्यवहार की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने को दृष्टि से भी बैंक ने कार्रवाई शुरू कर ली है।

14.5 नये नोट प्रेस परियोजना: नये नोट प्रेसों के लिए मैसूर (कर्नाटक) और सालबनी (पश्चिम बंगाल) में परियोजना स्थलों पर अपेक्षित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सहित भवन निर्माण की गति में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आगे और प्रगति हुई। नये नोट की प्रेस परियोजना के निम्नतर मूल्यवर्गों के नोट छापने के लिए वेब टेक्नोलॉजी के संभावित प्रयोग हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की थी तथापि, तकनीकी आर्थिक पुनर्निर्धारण के आधार पर सभी मूल्यवर्गों के नोटों के लिए शीट टेक्नोलॉजी को ही अपनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य संयंत्र और उपकरणों के लिए निविदा-अभिलेखकरण के भाग के रूप में निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेजों का मूल्यांकन कर लिया गया है और सकल निविदाकर्ता के चयन के शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिये जाने की आशा है।

14.6 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण: जुलाई 1985 से जून 1988 तक की अवधि के लिए, पूर्ण में किये गये 'विदेशी मुद्रा (अनिवासी) और अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते का सर्वेक्षण' पुनः नवंबर 1991 में प्रारंभ किया गया है जिसमें जुलाई 1988 से जून 1991 तक की आगे की तीन वर्षीय अवधि सम्मिलित है तथा इसके परिणाम प्रतीक्षित हैं। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उनके 48वें दौर के विषय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दशवार्षिक अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (आईडीआईएस) 1991-92 शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन, अनुसूचियों, सारणीकरण, फॉर्मेट आदि के तकनीकी कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। क्षेत्र-कार्य जनवरी 1992 से प्रारंभ किया गया और दिसंबर 1992 तक उसके पूरे होने की आशा है।

14.7 कंप्यूटरीकरण की प्रगति: आंतरिक लेखाविधि और तिजोरी लेखाविधि के मानदंड ग्रहमवाबाद, भायखळा, नागपुर, मद्रास, हैदराबाद, बंगलूर, नयी दिल्ली और कानपुर के निर्णय विभागों में प्रपत्राये जा रहे हैं। उक्त प्रणालियाँ शीघ्र ही जयपुर और तिरुवनंतपुरम में लागू

की जाने वाली है। कंप्यूटीकरण वेतन सूची का मापदंड बंगलूर, अहमदाबाद, मद्रास, और कानपुर में पूर्णतः प्रचलन में है। वेतन सूची पैकेज को नागपुर और हैदराबाद निर्गम विभाग की प्रणालियों में भर दिया गया है और फिलहाल नागपुर में चालू कर दिये जाने की करीब है। वेतन सूची का सॉफ्टवेयर नयी दिल्ली और तिरुवनंतपुरम कार्यालयों के निर्गम विभाग की प्रणालियों में अगले माह तक भर दिया जायेगा। जहाँ तक अन्य कार्यालयों का संबंध है उसे चरणबद्ध रूप में किया जायेगा।

14.8 साप्ताहिक विवरण, लाभ और हानि लेखा, भा. रि. बैंक तुलनपत्र और भा. रि. बैंक सामान्य खातों को समाधान से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों/विवरणों को तैयार करने के लिए 'भूनिष्प' परिनालन प्रणाली से मुक्त पर्सनल कंप्यूटर सरकारी और बैंक लेखा विभाग में स्थापित किये गये हैं। अधिक विश्लेषण और नीति विभाग में पोच अतिरिक्त पीसीएटी विभाग के कार्यकर्ताओं का कंप्यूटीकरण करने के लिए लगाए गये हैं। नागपुर और बंगलूर में हस्ताक्षर भंडारण और पुनः प्राप्ति प्रणालियाँ स्थापित की गयी हैं। बंगलूर में स्थापित प्रणाली पूरी तरह कार्य कर रही है। हस्ताक्षर रखने संबंधी कार्य को पूरा कर दिया गया और इस प्रणाली का उपयोग हस्ताक्षरों की पुनः प्राप्ति और उनके सत्यापन के लिए किया जा रहा है। इसी तरह की प्रणाली कलकत्ता कार्यालय में भी लगायी गयी है। विधिक निर्णय संगृहीत करने और उनकी पुनः प्राप्ति के लिए विधि विभाग में एक मिनी-कंप्यूटर प्रणाली स्थापित की गयी है। साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। ('लेन' सहित) एएलपीएम मद्रास कार्यालय को सुपुर्दे किये और स्थापित किये गये। साफ्टवेयर मंगाया गया है और उसका परीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। एएलपीएम नयी दिल्ली को दिये गये हैं; 2 एएलपीएम स्थापित किये गये हैं परन्तु उन्हें अभी तक परिचालित नहीं किया जा सका है।

14.9 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट लाई मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में मौजूदा की-हनीबेल बुल मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रणाली के पुनःस्थापन की प्रक्रिया प्रगति पर है। नयी प्रणाली अगले वर्ष के प्रारंभ में स्थापित कर दिये जाने की आशा है। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष की आईबीएम कंप्यूटर प्रणाली पर एक समर्थक वेतनपत्रों अनुप्रयोग पैकेज विकसित किया गया है ताकि मौजूदा मेनफ्रेम प्रणाली, जो हाल में बार-बार खराब होने लगा है, के खराब हो जाने की स्थिति में संवेदनशील वेतनपत्रों के अनुप्रयोग की प्रक्रिया को अव्यवस्थित करने की स्थिति को टाला जा सके। सामान्य लेखांकन और पेंशन की प्रसिमिंग के लिए पीपी पर साफ्टवेयर पैकेज विकसित किये गये, जिसे बैंक के विभिन्न विभाग भी लाभप्रद रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कुछ प्रशासनिक अनुप्रयोगों तथा जवसोकना वस्तुओं के लिए अग्रिम, आवास ऋण, आदि के कार्यान्वयन के लिए साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ऋणों के संबंध में एसजीएल अंतरण (स्थानीय) वाला पहला चरण 2 जुलाई 1992 से शुरू कर दिया गया है और शेष सर्वों के संबंध में कार्य प्रगति पर है।

14.10 बैंक समाशोधन का कंप्यूटीकरण : त्रिवेन्द्रम और बड़ौदा को बंबई में तथा कोयम्बतूर, मनेम, त्रिची, मधुरै और त्रिवेंद्रम को मद्रास से संबद्ध करने के लिए एकतरफा अंतर्नगर समाशोधन की और अधिक विस्तृत कर दिया गया।

समाशोधन गृह की प्रक्रिया के जरिये भा. रि. बैं. के कर्मचारियों का वेतन जमा किये जाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा' की व्यवस्था लागू की गयी। यह योजना अभी मद्रास में और केन्द्रीय कार्यालय के एक वेतन संचितरण यूनिट में कार्यरत है। समाशोधन गृह की प्रक्रिया के जरिये मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में भी पेंशन जमा किया जाना शुरू कर दिया गया है। मद्रास आधारित वित्तीय कंपनियों के मासिक ध्यान भुगतान लेन-देनों सहित राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, मद्रास भी इलेक्ट्रॉनिक, समाशोधन कर रहा है।

14.11 कार्यालय का कंप्यूटीकरण : बैंक में उपकरणों और कार्यालय के सहायक माधनों के संबंध में और अधिक प्रगति की गयी है। बैंक में कार्यरत फ़ैक्स मशीनों की वर्तमान संख्या के अलावा केन्द्रीय कार्यालय के 8 विभागों, 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 21 कार्यालयों में 34 और फ़ैक्स मशीनें लगायी गयी हैं।

14.12 रिजर्व बैंक में कार्यनीतिगत आयोजना—रिजर्व बैंक अथवा कार्य नीतिगत आयोजना में सक्रिय रूप से व्यस्त है जिसकी अवधि 10 वर्ष की है, जो 2,3 और 5 वर्ष की लघुतर अवधियों में विभक्त है। उक्त प्रयोग का उद्देश्य उन प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को पहचानना है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवेश में घटित होने और जिनके परिणामों से रिजर्व बैंक का संबंध होने की संभावना है।

14.13 भारतीय रिजर्व बैंक में कंप्यूटीकरण के संबंध में भावी योजना का आयोजन वित्तीय क्षेत्र में हो रहे भारी सुधारों, नयी वित्तीय निधियों के प्रारंभ और वित्तीय बाजारों के विस्तार के संदर्भ में किया जाना चाहिये। यह आशा की जाती है कि व्यापक आर्थिक प्रशासन में लाइसेंसकरण हटाने, विनियम समाप्त करने तथा लेनदेनों और मूल्य निर्धारण हेतु बाजार द्वारा निर्धारित तंत्र के परिवेश में सरकार द्वारा शुरू किये गये अनेक उपायों के कारण पर्याप्त परिवर्तन होने वाले हैं। इस परिवेश में, मौजूदा क्षेत्रों में कार्य की मदों के कंप्यूटीकरण के अतिरिक्त, कार्य की नयी मदों के कंप्यूटीकरण के लिये अधिकतर गुंजाइश होगी। सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में नयी स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मैन फ्रेम कंप्यूटर प्रणाली के संस्थापन से साफ्टवेयर के विकास, बैंकों के साथ आंकड़ों के विनियम के लिये संचारण प्रयोगों एवं आंकड़ा-संसाधन और सुधार हेतु नयी और शीघ्रतर पद्धतियों के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। बैंक में प्रणालियों और साफ्टवेयर के क्षेत्रों में विशेषज्ञता का अनुकूल संगठनात्मक संरचना बनाने के द्वारा दृष्टतम प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। बैंक नेट और आईबीएम मैनफ्रेम जैसे मौजूदा कंप्यूटर (संचार

संसाधनों का इष्टतम रूप में उपयोग करता होगा। स्थानीय और अंतर-राज्य स्तरों के संसाधन के लिये माहकन और निर्बाध-आधारित कृष्युत्पत्ति समायोजन की सुविधा अधिकाधिक वाणिज्यिक तौर पर महत्वपूर्ण शहरों में उपलब्ध करानी होगी। समायोजन भूतान परिसरानों के लिये चारों महानगरों को परस्पर संबद्ध करने की भी आवश्यकता है ताकि प्रत्येक सव्य-बैंक बैंकनोट के माध्यम से प्रत्येक भूतान के बाहर अपनी निधियों की निवल स्थिति को सुरक्षित जान सके।

14.14 स्थिति अब कम से कम नेटवर्क वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है जिससे कि तत्काल सूचना आंकड़ों का अंशण सुसाध्य हो सके। मुद्रा बाजार संकेतकों (शेयर बाजार, मुद्रा बाजार), प्रतिभूति बाजार, आदि) में सही समय पर निरंतर अभिगम देश के अंदर प्रारंभ करने और संभव लघुतम समय में विश्वस्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सूचना का प्रवाह अत्यधिक गति सहित और कार्यक्षमता से युक्त हो। इंटरनेट के निर्माण एवं उपयोग के लिये विशेषज्ञता और सफ्टवेयर का प्रभावी प्रयोग होना चाहिये। बैंकनोट के पूरक रूप में एक ए.एन.ओ. और इलेक्ट्रॉनिक डाक सुविधाएं होनी चाहिये। भूमरीकी संयुक्त राज्य (यूएसए) के फंडबायर की पद्धतियों पर अभिनिर्धारित वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये 'समेकित निरंतर भूतान निपटान प्रणाली लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों और अन्य के एनजीएल खाते को निरंतर अद्यतन बनाने एवं ऐसे लेनदेनों के खरित भूतान निपटान की प्रणाली का होना अनिवार्य है। पर्याप्त मात्रा में अतिवासी भारतीयों (एनआरआई) के प्रेषण प्राप्त करने वाले अपेक्षाकृत छोटे शहरों को भी नेटवर्क में लाना होगा। रिजर्व बैंक के लिये सबसे बड़ा यह हमलिये आवश्यक है क्योंकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण का दायित्व इसे सौंपा गया है तथा केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

14.15 सी.डी. वेंगमुख स्मारक व्याख्यान—मानवां वित्तामणि वेंगमुख स्मारक व्याख्यान श्री जाक द लारोसीयेर गवर्नर बांक व फ्रांस द्वारा 24 मार्च 1992 को बम्बई में "1990 के दशक में विश्वव्यापी समायोजन प्रक्रिया" विषय पर दिया गया।

14.16 मियांजा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम—मियांजा गवर्नरों की परिषद की उत्तीर्ण बैठक टोकियो में 22 नवंबर 1992 को आयोजित की गई जिसकी मेजबानी बैंक आफ जापान ने की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अक्टूबर/दिसंबर 1992 में बम्बई में आयोजित अठारहवें मियांजा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम से संबंधित निदेशक स्टाफ की रिपोर्ट तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम के अर्थ और अर्थ में सहभागिता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मियांजा के अठारहवें केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम के व्याख्यान और नोट्स को एक साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।

14.17. रिजर्व बैंक का इतिहास—भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास लेखन पर कार्य चल रहा है और इस प्रयोजन के लिये स्थापित इतिहास कक्ष में निवेशन समिति के मार्गदर्शन में 1951 से 1967 तक की गतिविधियों को शामिल करते हुए प्राकृत्य सेवार करने का कार्य किया जा रहा है।

14.18. प्रशिक्षण—हाल में बैंक अपने कर्मचारियों की सामान्य कार्यक्षमता और व्यावसायिक कुशलता को सुधारने के लिये नये और नवप्रवर्तक क्षेत्रों में प्रशिक्षण शुरू करने की संभावनाओं की खोज कर रहा है। अब तक कई योजनाएं चल रही हैं और इस वर्ष

भी बैंक ने कतिपय नयी योजनाएं शुरू की तथा ये सुविधाएं और लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

14.19. विकास अनुसंधान समूह—आर्थिक सुधार संबंधी उपायों ने ऐसे जटिल और विभिन्न मुद्दों को उभारा है जिनके बारे में दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में अनेक अनुसंधान दलों की एक शृंखला द्वारा चर्चा किये जाने की आवश्यकता है और ये अध्ययन उच्च क्रम के बुद्धिजीवियों द्वारा किये जाने चाहिये। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग में नवंबर 1991 में एक विकास अनुसंधान समूह की स्थापना की गयी। विकास अनुसंधान समूह का उद्देश्य वर्तमान नीतिगत मुद्दों और बैंक के हित के क्षेत्रों में खरित और उत्तम श्रेणी के शोध पत्र प्रस्तुत करने का है। इस विकास अनुसंधान समूह के अध्ययनों का एक विशेष गुण यह है कि यह और बैंक के बाहर के विशेष अकादमीशियनों, सलाहकारों, तथा पेशेवरों और दूसरी ओर बैंक के अंदर के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम के बीच परस्पर सहयोग पूर्ण प्रयासों का परिणाम है। इन अध्ययनों को व्यावसायिक, अर्थ-शास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच और व्यापक अध्ययन के लिये प्रकाशित किया जाता है। इसके कार्य करने के पहले 6 महीनों के दौरान विकास अनुसंधान समूह में 3 अध्ययनों को प्रकाशित किया गया है और 6 अध्ययनों पर कार्य हो रहा है।

14.20. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान—इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ने अपनी अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को जारी रखा और वर्ष के दौरान उन्हें पूरा किया। इनमें निम्नलिखित अध्ययन शामिल हैं: आयाजना और नीति विश्लेषण की गति के क्षेत्र में अध्ययन, ऊर्जा नीति, कृषि और ग्रामीण विकास, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापक आर्थिक और मौद्रिक नीतिगत मुद्दे, बाह्य क्षेत्र और पर्यावरणगत अध्ययन, इस संस्थान ने अनेक विषयों पर विभिन्न सम्मेलन और कार्यशालाएं भी खलायी। ये विषय थे: व्यापार नीति संबंधी सुधार, परिवहन के लिये सीएनजी का कार्यान्वयन, विकास की चुनौतियां, आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा मांडलिंग तथा ऊर्जा के क्षेत्रों के लिये दीर्घकालीन आयाजना एवं विकास और पर्यावरण संबंधी स्थिरता। यह संस्थान अगस्त 1990 से विकास नीति के क्षेत्र में 1 वर्ष का एक पीएचडी कार्यक्रम भी खला रहा है। इसने अगस्त 1991 में दूसरे बैच को भी प्रवेश दिया है।

14.21. ईंदर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई—महाविद्यालय द्वारा इस वर्ष के दौरान पारस्परिक निधियां, ऋण निभारनी, चुनौती उद्योगों के प्रोफाईल (प्राइज) और उनके वित्तपोषण, मौद्रिक प्रबंध सुरक्षा, तथा सुरक्षा अधिकारियों के लिये जोखिम प्रबंध एवं अनुशासनिक कार्यवाई करने वाले प्राधिकारियों के लिये कार्यक्रम के क्षेत्रों में नये कार्यक्रम शुरू किये। इस महाविद्यालय ने वाणिज्यिक क्षेत्रों की वित्तीय प्रणाली और लाभप्रदता पर भी सेमिनार आयोजित किये।

14.22. इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 94 कार्यक्रम चलाये जिनमें (9 कार्यक्रम हिन्दी में चलाये हैं) 2,396 सहभागी थे। इनकी मिताकर 1954 में महाविद्यालय की स्थापना होने से लेकर अब तक 43,774 सहभागी प्रशिक्षण ले चुके हैं।

14.23. रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास—इस महाविद्यालय ने कुछ नये कार्यक्रम जैसे कार्यालय-प्रबंध, तथा अजून कीर्तिग,

राजभाषा अधिकारियों के लिये विकास कार्यक्रम, 'यूनिक्स' पर कार्यक्रम तथा 'सी' प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और निमित्त प्रणालियों के विनिर्देश और उनके विस्थापन पर कार्यक्रम।

14.24. इस वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने 76 कार्यक्रम चलाये जिनमें 1627 सहभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1963 में इसकी स्थापना से लेकर कुल प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या अब तक 28,490 हो गयी।

14.25. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे—वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने 4 नये कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर कार्यक्रम, ग्रामी कीड़े पालन के विनाशोपशान पर कार्यक्रम, कृषि ऋणों की वसूली की पद्धतियों पर कार्यक्रम, गहरी बैंक विभाग के अधिकारियों के लिये निरीक्षण पर परिचयात्मक कार्यक्रम तथा कृषि निर्यात पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त 'लघु परियोजनाओं के निरूपण का प्रबंध' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, एशियाई और पैसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण एमोसिगेशन की ओर से चलाया गया। अन्य कार्यक्रमों में श्रीलंका के राष्ट्रीय वसंत बैंक के अधिकारियों के लिये 4-4 सप्ताह के 4 विशेष कार्यक्रम तथा अफगानिस्तान के कृषि विकास बैंक के अधिकारियों के लिये "सीयावी ऋण देना" विषय पर एक कार्यक्रम शामिल है।

14.26. इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 104 कार्यक्रम चलाये जिनमें (11 कार्यक्रम हिन्दी में चलाये गये) 2,422 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार 1969 में अपनी स्थापना से लेकर महाविद्यालय ने अब तक कुल 40,478 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

14.27. प्रांचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों :— प्रांचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा इस वर्ष के दौरान चलाये गये कार्यक्रमों में श्रेणी III के कर्मचारियों के लिये कंप्यूटर परिचय पर चलाया गया एक सप्ताह का एक कार्यक्रम भी शामिल है। वर्ष के दौरान 1902 श्रेणी III के कर्मचारियों ने और 295 श्रेणी IV के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस प्रकार प्रांचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या बढ़कर क्रमशः 4,002 तथा 2,984 हो गयी।

14.28. वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण :— रिजर्व बैंक के ग्रेड 'D' 'डी' और 'सी' अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत 1986 में शुरू की गयी इस योजना के शुरू किये जाने से लेकर अब तक 116 अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। वर्ष के दौरान इस योजना को समीक्षा की गयी और उसे यथोचित रूप में संशोधित किया गया। संशोधित योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिये इस वर्ष 40 अधिकारियों की वाणिज्य बैंकों में प्रतिनियुक्त किया गया। इस वर्ष के दौरान 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने वाणिज्य बैंकों के प्रमुख विभागों में एक 6 महीनों का सहयोगित कार्यक्रम पूरा किया, जब कि एक और अधिकारी अभी इस प्रशिक्षण पर है।

14.29. इस वर्ष के दौरान बैंक ने 314 अधिकारियों को भारत स्थित प्रबंध नर्स/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया।

फिलहाल 2 अधिकारी विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में अनुप्रयुक्त (व्यावहारिक) अध्ययन में एम. फिल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

14.30. भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति :— वर्ष के दौरान 26 अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ईरान फिलीपीन और मलेशिया में स्थित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

14.31 इस योजना के अन्तर्गत जिसमें बैंक के अधिकारियों को अग्रिम से अधिक एक वर्ष तक विदेश में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) प्रदान की जाती है, यह योजना बैंक के स्वर्ण महोत्सव के एक भाग के रूप में 1985 में शुरू की गयी थी, 4 अधिकारियों को प्रति

वर्ष चुना जाता है और अब तक 24 अधिकारियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

14.32 विदेशी बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधा :— 1991-92 के दौरान विभिन्न देशों के कुल मिलाकर 174 विदेशी अधिकारियों ने बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाओं का लाभ उठाया। इनमें से 127 श्रीलंका से, 13 ईरान से, 8 अफगानिस्तान से और 7-7 कोरिया और मलेशिया, 4 यूगांडा से, 2-2 बोम्बेय और नेपाल से, तथा 1-1 इथोपिया, मालदीव द्वीपों, सिनेराली और जाम्बिया से थे। 1981 से लेकर अब तक प्रशिक्षित किये गये विदेशी बैंकों के अधिकारियों की कुल संख्या 813 थी।

14.33 कंप्यूटर तकनीक में प्रशिक्षण :— 1987 में रिजर्व बैंक कंप्यूटर के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता रहा है और कुल मिलाकर 117 अधिकारियों और 176 वित्तीय स्टाफ ने देश के विभिन्न संस्थाओं में इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

14.34 व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन :— भारतीय मतदी वित्तीय विशेषज्ञ संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ बार्टेड फाइनेंशियल एनलिस्ट्स ऑफ इंडिया—आई सी एफ ए आई) हैदराबाद, द्वारा संचालित मतदी वित्तीय विशेषज्ञ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना के अन्तर्गत 151 कर्मचारियों ने उक्त योजना का लाभ उठाया था।

14.35 पी.एच.डी. के लिए प्रायोजन की योजना :— एक वर्ष पूर्व, बैंक ने आर्थिक विनिर्देश और नीति विभाग से अधिकारियों का पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए प्रायोजित करने की एक अन्य योजना प्रारंभ की। वर्तमान में दो अधिकारी आई.आई.टी. मम्बई में अपना अध्ययन कर रहे हैं, जब कि एक अन्य अधिकारी द्वारा हैदराबादी विकास अनुसंधान संस्थान, मम्बई में अध्ययन किया जा रहा है।

14.36 उत्तर पूर्वी बैंक प्रबंध संस्थान :— उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से 1980 में गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी बैंक प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया था। उक्त संस्थान बैंकिंग और प्रबंध विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रशिक्षण और परामर्श कार्य में व्यस्त है। चूंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में बैंकिंग विकास की संभाव्यता की पूर्ति और अधिक प्रभावी रूप में करने के लिए इन सुविधाओं का विस्तृत करने की आवश्यकता है, अतः एन ई आई सी एम ने अपने प्रयोजन के आधार को व्यापक बनाने का प्रस्ताव करते हुए (जो कि तब तक केवल तीन बैंकों तक ही सीमित थी) रिजर्व बैंक से अपना एक प्रायोजक बनने का अनुरोध किया। तबनुसार रिजर्व बैंक ने अगस्त 1991 में नाबाई सहित तीन और बैंकों के प्रवेश के साथ ही उसका प्रथमी प्रायोजक बनना स्वीकार किया। एन ई आई सी एम के कार्यकलापों के निष्पत्ति में बैंक का अंश 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और प्रशिक्षण के प्रभावी उप गवर्नर उसके नियंत्रक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष है।

14.37 नियोजता कर्मचारी संबंध :—वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न केन्द्रों में नियोजता कर्मचारी संबंध कुल मिलाकर सद्भावपूर्ण रहे।

14.38 संगठनात्मक आवश्यकताओं और स्टाफ के विनियोजन में वृहत्तर लचीलेपन की प्राप्ति के अन्तर्गत श्रेणी III कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के प्रयत्न का अध्ययन करने लिए आन ईंडिया रिजर्व बैंक एम्पाईज एमोसिगेशन और बैंक आठ-आठ मन्त्रियों के साथ एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन अगस्त 1990 में किया गया था। बैंक ने उक्त दल की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा नकदी विभाग से संबंधित उसकी स्वीकृत की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। इन्हीं आधारों पर बैंक द्वारा ज्ञात ईंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के साथ एक अन्य संयुक्त अध्ययन दल, आधारभूत सशर्तों में भर्ती, अंगवलिप्त कर्मचारियों का पूर्णकालिक सेवा में नियमन, दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों को नियमित सेवा में परिवर्तन आदि के प्रश्न पर विचार करने हेतु गठित किया गया है और इसकी अभी प्राप्त होनी है।

14.39 बैंक के अधिकारियों के एमोसिगेशनों से उनके कैरियर को प्रभावित करने वाली विभिन्न नीतियों का पुनर्मुल्यांकन करने के लिए

प्राप्त अनुसूचियों के प्रत्यक्ष में मानव संसाधन विकास से संबंधित विशेष रूप से अधिकारियों के मंत्रियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के संबंध में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए श्री एस.एस. मराठे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन करने के लिए बैंक द्वारा उस पर कार्यवाई की जा रही है।

14.40 स्टाफ कल्याण: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने व्यापक स्तर पर स्टाफ के हित के लिए कल्याण के अनेक उपाय लागू किये हैं। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर की जन्म जन्ताष्टी के स्मारक के रूप में एक निधि की स्थापना के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। बैंक के केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कामगार कर्मचारियों के बच्चों के लिए इस निधि में से छात्रवृत्तियाँ देने हेतु 'भारतरत्न बाबासाहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर जन्मशती' वर्ष छात्रवृत्ति योजना के नाम से एक नयी योजना शुरू की गई थी।

14.41 बैंक ने "बैंक की स्वर्णजयन्ती वर्ष छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत कर्मचारियों के बच्चों की बी.ए. की बी.ए. की छात्रवृत्तियों के विस्तार और सीमा को उबार बनाया है। इस उद्देश्यपूर्णता में छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा समाप्त करते हुए सभी पात्र बच्चों को यह छात्रवृत्ति देने तथा कामगार कर्मचारियों के उन बच्चों को जिन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, पुस्तकों के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।

14.42 इकैथियों तथा बैंकों और उनके कर्मचारियों पर आतंकवादी हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा दी गई स्वरूपा के अनुसार ऐसी घटनाओं में पायलट/हारे गये अपने कर्मचारियों/उनके निकट संबंधियों के लिए अतिरिक्त/पुस्तक को एक मुश्त योजना बनाया है। एक मुश्त योजना के अनुसार भूत कर्मचारों का परिवार विभिन्न अन्य लाभों के साथ-साथ एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक के दायरे में अतिरिक्त प्राप्ति करने के लिए पात्र है। छुट्टी पर रहते समय दुर्घटना के कारण घायल होने पर मृत्यु का प्राप्ति होने पर अतिरिक्त की बैंक की अपनी योजना के साथ-साथ इस योजना से किसी अधिक घटना के होने को स्थिति में कर्मचारियों/उनके परिवारों के हित के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

14.43 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमाली में कुछ संशोधन लागू किये हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण संशोधन भी सम्मिलित है जिसके अनुसार स्वीकृत सेवानिवृत्ति मांगने वाले कर्मचारियों को 20 वर्ष की अधिक सेवा पूरी करने के बाद तथा ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक सेवा में अधिकतम 5 वर्ष तक जोड़ने हुए अधिपूर्य सेवानिवृत्ति पेंशन का प्रावधान किया गया है। जिन कर्मचारियों ने पूर्व में अंगदश्या भविष्य-निधि के लिए विकल्प दिया था, उन्हें पेंशन के लिए तय विकल्प का प्रयोग करने हेतु अनुमति दी गयी थी जिसकी प्रतिक्रिया में अब पेंशन के लिए विकल्प देने वालों का प्रतिशत 45.21 प्रतिशत तक आ गया है। एक निर्णय यह भी लिया गया है कि पेंशन के लिए अधिक सेवा के रूप में सार्वजनिक अंत के बैंकों भा.स्ते. बैंक/केन्द्रों राजस्व सरकारों/ केन्द्रिय स्वायत्त संस्थाओं में की गयी पिल्लो सेवा का नाम स्थान ने केन्द्रीय सरकार को पेंशन योजना में विश्वमान इसी प्रकार के नाम प्रावधानों के अनुसार दिया जाए।

आरक्षित श्रेणियों को रोजगार

अ.जा./अ.ज.जा.

14.44 कैलेन्डर वर्ष 1991 के दौरान बैंक में भर्ती की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की प्रतिनिधित्व सिम्बलानुसार था:

श्रेणी	भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	जिनमें से	प्रतिशत		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	59	16	9	27.1	15.3
श्रेणी III	186	33	26	17.7	14.0
श्रेणी IV	270	96	24	35.6	8.9
जिन में से	226	67	20	29.6	8.8
(क) स्वीपिंगों को छोड़कर					
(ख) स्वीपर	44	29	4	65.9	9.1

इन्हें मिलाकर 1 जनवरी, 1992 को स्थिति के अनुसार बैंक में अ.जा. और अ.ज.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या कमजोर श्रेणी IV में 2362 और 704 श्रेणी III में 2495 और 1190 तथा श्रेणी I में 525 और 109 तक बढ़ गई। वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के भर्ती अधिकारी ने बैंक के बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, कानपुर और पटना कार्यालयों में अनुरक्षित आरक्षण रोल्टरों का निरीक्षण किया। बैंक द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए एवं आल इंडिया रिजर्व बैंक एस.सी./एस.टी. एंड बुद्धिस्ट एम्पाईज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहे। वर्ष के दौरान इस प्रकार का तीन बैठकें बम्बई में आयोजित की गई थीं।

14.45 मृतत्व सैनिक: कैलेन्डर वर्ष 1991 के दौरान श्रेणी III और श्रेणी IV के भरे गए कमजोर 186 और 270 रिजर्व स्थानों में से तथा 66 पूर्व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखने पर श्रेणी III में निर्धारित आरक्षण दर 14.5 प्रतिशत तथा श्रेणी IV में 24.5 प्रतिशत था। इसके विपरीत, श्रेणी III में 26 और श्रेणी IV में 54 रिजर्व स्थान भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति कर के भरे गए जिससे 31 दिसम्बर, 1991 को बैंक में श्रेणी III में उनका कुल संख्या बढ़कर 787 और श्रेणी IV में 1,081 हो गई।

14.46 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति: कैलेन्डर वर्ष के दौरान, श्रेणी III और श्रेणी IV में आठ-आठ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती की गई जिससे बैंक में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 424 हो गई।

14.47 हिन्दी का संवर्धन: रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए बैंक लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पूर्णकालिक प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम और मसौने स्तर के अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिन में 208 अधिकारियों ने भाग लिया। इसी प्रकार से, वर्ष के दौरान 863 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। 38 अंग्रेजी टंककों का हिन्दी टंकण प्रशिक्षण भी दिया गया।

14.48 वर्ष के दौरान "बैंकिंग मन्त्रालय" का चौथा परिशोधित तथा परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया गया। बैंकिंग शब्दों और वाक्यों का एक व्याख्यात्मक कोश—'बैंकिंग परिभाषा कोश' पर कार्य पूरा हो गया है और यह प्रकाशन के लिए तैयार है।

14.49 बैंक के सभी कार्यालयों में 14 दिसम्बर, 1991 का हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। हिन्दी के उन्नयन में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों तथा अधिकारियों में प्रतियोगात्मक भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान अन्तर कार्यालय तथा अन्तर विभागीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और शील्ड वितरित की गईं।

14.50 'विदाउट रिजर्व' नामक गृह पत्रिका में हिन्दी के अंश में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी का तिमाही पत्रिका 'बैंकिंग चिन्तन अनुनितित', बैंकिंग साहित्य में मूल हिन्दी लेखन के रूप में बहुमूल्य योगदान देती आ रही है।

14.51 कार्यालय भवन और आवासीय स्थान: वर्ष 1991-92 के दौरान, कार्यालय भवन तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण/अधिग्रहण करने और मौजूदा परिसरों में सुदृढीकरण करने तथा तथा भूमि खरीदने पर कुल 14.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष के दौरान लखनऊ तथा भुवनेश्वर में अधिकारियों के 15 क्वार्टरों और 316 स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया गया। जम्मू में कार्यालय भवन और हवराबाद में बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय कम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अधिकारियों के 560 क्वार्टरों और 468 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य विभिन्न केन्द्रों में प्रगति पर है। नयी बम्बई में श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के क्वार्टरों के साथ-साथ एक कार्यालय भवन का निर्माण करने की योजना को भी अंतिम रूप दिया गया है।

14.52 बैंक ने अधिकारियों (स्थानान्तरणीय) के आवासीय क्वार्टरों के लिए 75 प्रतिशत पर समानान्तरक मानव संसाधन निर्वाचित किए हैं, जबकि प्रत्येक श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों (निर स्थानान्तरणीय), के मामले में ये मानदण्ड 50 प्रतिशत रखे गए हैं। बैंक ने अधिकारियों के

क्वार्टरों के मामले में, 11 केन्द्रों पर अपेक्षित समाधान परक स्तर का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के क्वार्टरों के मामले में भी 50 प्रतिशत से भी अधिक केन्द्रों पर अपेक्षित समाधान परक स्तर पूरा कर लिया गया और निर्माण-धीन आयोजनाधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर बैंक के कार्यालयों वाले लगभग 80 प्रतिशत केन्द्रों पर यह मानदण्ड पूरा हो जाएगा।

14.53 आवास ऋण: 1 जुलाई, 1991 से 30 जून, 1992 की अवधि के दौरान, कर्मचारियों (समितियों/व्यक्तियों) के लिए बैंक द्वारा आवास ऋण के रूप में कुल 14.26 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। विवरण नीचे दिए गए हैं।

श्रेणी	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	रूपों में ऋण की राशि
क. सहकारी आवास समितियाँ			
(i) नये ऋण			
(ii) अतिरिक्त ऋण			
ख. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण			
(i) नये ऋण			
(ii) अतिरिक्त ऋण			
ग. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण			
(i) नये ऋण			
(ii) अतिरिक्त ऋण			
जोड़ (क + ख + ग)			

*जम्मू, जयपुर, कानपुर और कलकत्ता (बैंकिंग) कार्यालयों के संबंध में आवास ऋण की स्वीकृत राशि की 31 मार्च 1992 तक है।

14.54 बैंक के उप गवर्नर डा. सी. रंगाराजन को योजना आयोग के पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20 अगस्त, 1991 से अपने कार्यालय का कार्य-भार छोड़ दिया। बोर्ड, डा. सी. रंगाराजन द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समादर करता है।

14.55 बैंक के उप गवर्नर श्री ए. घोष को, 20 जनवरी 1992 को कारोबार की समाप्ति पर उनकी सेवा अवधि पूरी हो जाने पर उनके कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया। बोर्ड, श्री ए. घोष द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समादर करता है।

14.56 बैंक के उप गवर्नर श्री पी. आर. नायक को, 31 मार्च, 1992 को कारोबार की समाप्ति पर उनकी सेवा अवधि पूरी हो जाने पर उनके कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया। बोर्ड, श्री पी. आर. नायक द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समादर करता है।

14.57 केन्द्रीय बोर्ड: बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस. एस. सारापोर को 30 जनवरी, 1992 से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।

14.58 श्री एस.पी. शुक्ला, 6 नवम्बर, 1991 से केन्द्रीय बोर्ड में सरकारी नामिती के रूप में कार्य करना बन्द कर देने और श्री मोनटेंक सिंह ग्रहणवालिया, सचिव, आर्थिक, कार्य भारत सरकार को उम्मीदारी से उनके स्थान पर नामित कर दिया गया। बोर्ड, श्री एस.पी. शुक्ला द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समादर करता है।

14.59 बोर्ड को यह जानकर हार्दिक दुःख हुआ कि पूर्व निदेशक कर्नल बी.एच. जैदी का 29 मार्च, 1992 को देहान्त हो गया। कर्नल जैदी 16 सितम्बर, 1958 से 12 दिसम्बर, 1963 तक बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में रहे। बोर्ड, उनके संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है।

14.60 5 जून 1992 को श्री डी.सी. कोठारी बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के भूतपूर्व निदेशक (15 जनवरी 1969 से 30 जून 1972 तक) के दुःखद निधन पर बोर्ड दुःख प्रकट करता है। बोर्ड उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःखद घड़ी में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करता है।

14.61 स्थानीय बोर्ड: 9 जून 1992 को श्री महबूब महमूद, बैंक के पूर्वी क्षेत्रीय स्थानीय बोर्ड के सदस्य (25 अगस्त 1984 से मृत्यु पर्यन्त) के दुःखद निधन पर बोर्ड दुःख प्रकट करता है। बोर्ड उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःखद घड़ी में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करता है।

14.62 वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्डों के किसी भी गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

14.63 कार्यपालकों की नियुक्ति: श्री डब्ल्यू.एस. सराफ को 1 फरवरी 1992 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया।

XV. वर्ष 1991-92 के लिए बैंक का लेखा (जुलाई-जून)

15.1 (1) आय: 30 जून, 1992 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रावधानों के लिए समायोजन करने के पश्चात् बैंक की आय पिछले वर्ष के 4,624.97 करोड़ रुपये से 1,074.59 करोड़ रुपये (या 23.2 प्रतिशत) बढ़कर 5,699.56 करोड़ रु. हो गयी। आय के साधन नीचे दिये गए हैं।

	(करोड़ रुपये)	
भदों	30 जून, 1992 को समाप्त वर्ष	30 जून 1991 को समाप्त वर्ष
(क) प्रतिभूतियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर व्याज (विदेशी प्रतिभूतियों, जमा राशियों आदि पर व्याज सहित)	4,527.84	3,415.36
(ख) रुपया तथा विदेशी खजाना वित्तों पर बट्टा	819.65	962.01
(ग) विप्रक्षणां, खरीदे गये वार वितरण आदि पर विनिमय प्रभार विदेशी (लेनदेनों सहित)	307.91	219.79
(घ) लोक ऋण कार्यालयों के प्रबंधन पर कमीशन तथा अन्य विविध आय	44.16	27.61
कुल आय :	5,699.56	4,624.97

15.2 वर्ष 1991-92 के दौरान व्याजगत आय से 1,112.28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस दौरान प्राप्त किये गये बट्टे में 142.36 करोड़ रुपये की कमी आयी और वह मुख्यतः रुपया खजाना वित्तों पर बट्टागत आय में हुई गिरावट के कारण रही।

15.3 (2) व्यय: 1990-91 के दौरान (जुलाई-जून) कुल व्यय 3,289.97 करोड़ रुपये का हुआ जो वर्ष 1991-92 में (जुलाई-जून) 919.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,199.56 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः विस्तारिक निधि सुविधा के अंतर्गत (जिगके अधीन 1981-1984 के दौरान ग्राहण किये गये थे) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये ग्राहणों के संबंध में सरकार को प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति राशि, स्थापना खर्च में वृद्धि, सिक्किम मुद्रण, सरकारी कारोबार करने के लिए मार्गजनिक सड़कों के बैंकों के अथवा किये गये कुल कारोबार पर कमीशन तथा नकदी प्राप्ति अनुपात के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा उनकी अतिरिक्त पात्र शेष राशि पर व्याज की अदायगी के कारण थी। 3,311.47 करोड़ रुपये के कुल व्याज भुगतान में इस वर्ष के दौरान उनकी पात्र अतिरिक्त शेष राशि (3 प्रतिशत के सांविधिक अनुपात से ऊपर) जो नकदी प्राप्ति अनुपात के प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक के पास रखी गयी थी उस पर अनुसूचित बैंकों की अदा किये गये व्याज की राशि ही 2,683.68 करोड़ रुपये हो गयी जो कुल व्यय की 63.9 प्रतिशत बनती है (सारणी 15.1)।

सारणी 15.1: भारतीय रिजर्व बैंक : आय और व्यय-1981-82 से 1991-92 तक

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	1981-92	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	कुल आय (सकल)	1185.42	1343.61	1645.13	1886.28	2209.67	2896.85	3541.23	4030.25	4426.73	4624.97	5699.56
2.	निम्नलिखित में विनियोजन											
(क)	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	290.00	315.00	315.00	350.00	400.00	430.00	450.00	450.00	525.00	525.00	—
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	180.00	225.00	275.00	300.00	350.00	300.00	330.00	330.00	375.00	400.00	—
(ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	75.00	75.00	80.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	—
(घ)	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	—	—	—	—	—	—	50.00	25.00	50.00	50.00	—
3.	जोड़ (क+ख+ग+घ)	545.00	615.00	670.00	675.00	760.00	740.00	840.00	815.05	960.00	995.00	—
4.	निवल आय (1-3)	640.42	728.61	975.13	1211.28	1449.67	2156.85	2701.23	3215.25	3466.73	3629.97	5699.56
5.	व्यय :											
(क)	अनुसूचित वारिज्य बैंकों को भत्ता दिया गया व्यय	228.66	303.19	503.28	625.00	810.00	1042.99	1521.59	1829.82	2137.33	2431.02	2683.89
(ख)	एजेंसी प्रसार	70.16	82.28	93.93	132.85	150.01	163.64	173.88	259.46	261.25	265.62	302.34
(ग)	प्रतिभूति मृदण	41.58	35.94	43.42	58.28	100.08	173.05	206.81	187.02	143.71	162.27	238.30
(घ)	विस्तारिक निधि सुविधा पर व्यय	—	—	—	—	—	368.00	357.03	445.18	388.89	62.00	540.42
(ग)	अन्य खर्च@	90.02	97.20	134.50	185.15	179.58	199.13	231.81	283.64	325.43	359.06	434.82
6.	कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ग)	430.42	518.61	765.13	1001.28	1239.67	1946.81	2491.12	3005.12	3256.61	3279.97	4199.56
7.	सरकार को अंतरित राशि (4-6)	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.04	210.11	210.13	210.12	350.00	1500.00

@ इसमें स्थापना पर व्यय, निधियों पर व्याज तथा अन्य व्यय शामिल है।

(-) का अर्थ है 'कुछ नहीं'

सारणी 15.1: भारतीय रिजर्व बैंक: प्राय और व्यय

1981-82 से 1991-92 तक (करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	कुल प्राय (मूल्य)	1185.42	1343.61	1645.13	1886.28	2209.67	2896.85	3541.23	4030.25	4426.73	4624.97	5699.57
2.	निम्नलिखित में विनियोजन											
(क)	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	290.00	315.00	315.00	350.00	400.00	430.00	450.00	450.00	525.00	525.00	—
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	180.00	225.00	275.00	300.00	350.00	300.00	330.00	330.00	375.00	400.00	—
(ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्वरोत्प्रेरण) निधि	75.00	75.00	80.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	—
(घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (वैयक्तिकीय प्रवर्तन) निधि	—	—	—	—	—	—	50.00	25.00	50.00	50.00	—
3.	जोड़ (क + ख + ग + घ)	545.00	615.00	670.00	675.00	760.00	740.00	840.00	815.00	960.00	995.00	—
4.	निवल प्राय (1-3)	640.42	728.61	975.13	1211.28	1449.67	2156.85	2701.23	3215.25	3466.73	3629.97	5699.57
5.	व्यय											
(क)	अनुसूचित जातीय बैंकों को प्रदा किया गया व्याज	228.66	303.19	503.28	625.00	810.00	1042.99	1521.59	1829.82	2137.33	2431.03	2833.84
(ख)	एजेंसी प्रसार	70.16	82.28	93.93	132.86	150.01	163.64	173.88	259.46	261.25	265.62	302.04
(ग)	प्रतिभूति मुद्रण	41.58	35.94	43.42	58.28	100.08	173.03	206.81	187.02	143.71	167.27	248.30
(घ)	वित्तीय निधि सृजना पर व्याज	—	—	—	—	—	368.00	357.03	445.18	388.59	62.00	549.32
(ङ)	अन्य खर्च	90.02	97.20	124.50	185.15	179.58	199.13	231.81	283.64	325.43	359.06	434.82
6.	कुल व्यय (क + ख + ग + घ + ङ)	430.42	518.61	765.13	1001.28	1239.67	1946.81	2491.12	3005.12	3256.61	3279.97	4195.56
7.	मरकाज की अंतरित राशि (4-6)	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.04	210.11	210.13	210.12	350.00	1500.00

*सूचक में स्थापना पर व्यय, निधियों पर व्याज तथा अन्य व्यय शामिल हैं। (—) का अर्थ है "कुछ नहीं"

15.4. स्थापना लागत 33.60 करोड़ रुपये बढ़कर 277.29 करोड़ रुपये हो गयी, जो कुल व्यय के 6.6 प्रतिशत बनती है। व्यय में यह वृद्धि मुख्यतः सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में प्राथमिक रूप से हुई वृद्धि के कारण तथा बिजनेस खर्चा, छुट्टी, किराया गिरावट आदि की प्रतिपूर्ति के लिये उद्धारित योजनाओं के कारण हुई।

15.5. प्रतिभूति मुद्रण और आकस्मिक लागत जो कुल व्यय की 5.7 प्रतिशत बनती है 238.30 करोड़ रुपये की हुई और यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 76.02 करोड़ रुपये अधिक थी। इस बढ़ोतरी का कारण नोट कामों और चंक कामों के मुद्रण प्रभार की दरों में वृद्धि थी।

15.6. एजेंसी बैंकों द्वारा किये गये सरकारी लेनदेनों में उच्चतर कुल कारोबार के कारण एजेंसी प्रभागों में वृद्धि हुई और यह प्रभार 36.72 करोड़ रुपये बढ़कर 302.31 करोड़ रुपये के हो गये जो कुल व्यय का 7.2 प्रतिशत बनता है।

15.7 वर्ष के दौरान लिया गया प्रमुख नीतिगत निर्णय रिजर्व बैंक के लाभ में से भागी सात्ता में राशि सरकार को अधिशेष अंतरित करने से पहले विभिन्न मासिक निधियों को ऋण देने-लेने औद्योगिक और कृषि वित्त संस्थाओं को ऋण देने के लिये विनियोजित किये जाने की परंपरा को छोड़ देने का रहा। सन्दर्भित केन्द्रीय बजट 1992-93 में की गयी घोषणा के अनुसार सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा अंतरित अधिशेष लाभ 1991-92 (जुलाई-जून) के लिये 1,500 करोड़ रुपये बंधे है जबकि 1990-91 में ये 350 करोड़ रुपये और 1980 के दशक में ये 210 करोड़ रुपये हुआ करते थे (देखें सारणी 15.1)।

3. कुल पत्र

15.8. बैंकों की जमा राशियाँ—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमा राशियाँ पिछले वर्ष की 30,789.62 करोड़ रुपये के स्तर से 12,658.49 करोड़ रुपये, बढ़कर 43,448.11 करोड़ रुपये हो गयी जबकि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित सहकारी बैंकों, गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों की सकल जमा राशियाँ पिछले वर्ष के 805.04 करोड़ रुपये से 356.67 करोड़ रुपये 1991-92 (जुलाई-जून) के दौरान घटकर 448.37 करोड़ रुपये रह गयी।

1317 GL/93--14

15.9. अन्य जमा राशियाँ—अन्य जमा राशियों में पिछले वर्ष के 5,868.62 करोड़ रुपये के स्तर से 1,821.45 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 7,690.07 करोड़ रुपये हो गयी जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खाते संख्या 1 की शेष राशियों में 1,573 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण थी।

15.10. विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ—विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में निर्गम विभाग में रखी विदेशी प्रतिभूतियाँ, विदेशों में रखी शेष राशियाँ तथा बैंकिंग विभाग में "निवेशों" का एक भाग शामिल है ये प्राप्तियाँ जो 30 जून 1991 को 2,382.69 करोड़ रुपये की थीं। 30 जून, 1992 को 13,742.24 करोड़ रुपये बढ़कर 16,124.93 करोड़ रुपये की हो गयी।

15.11. भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियाँ और निवेश—भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश तथा उसके सहायक संस्थाओं के धीयर जो 30 जून 1991 को 96,410.11 करोड़ रुपये के थे 2,381.35 करोड़ रुपये घटकर 94,028.76 करोड़ रुपये के रह गये। इसका कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों का इस वर्ष के दौरान किया गया अपनिवेश था।

15.12. ऋण और अग्रिम—अनुसूचित बैंकों और विपरीत संस्थाओं को दी गयी ऋण सुविधा जो जून 1991 के अंत के 9,506.43 करोड़ रुपये के स्तर से 3,077.11 करोड़ रुपये की तेज वृद्धि के साथ जून 1992 के अंत में 12,583.54 करोड़ रुपये की हो गयी जिसका मुख्य कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की और निर्गत पुनर्वित्त के अंतर्गत उच्चतर बकाया (7,395 करोड़ रुपये) का होना था।

15.13. अन्य आस्तियाँ—अन्य आस्तियाँ 30 जून 1991 के 2,513.35 करोड़ रुपये से 1,834.83 करोड़ रुपये बढ़कर 4,348.18 करोड़ रुपये हो गयी जो मुख्यतः बैंकिंग विभाग में स्वर्ण धारिता (1,188.65 करोड़ रुपये) तथा प्राप्त अग्रिम के कारण रहीं।

15.14. विदेशी मुद्रा जमा योजनाओं के लिये विधिमय सुरक्षा के अंतर्गत हुई हानियों के लिये प्रावधान—रिजर्व बैंक की लाभप्रदता पर हाल के वर्षों में तीव्र बनाव धाया क्योंकि बैंक से यह अपेक्षा है कि वह (i) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना तथा भारत स्थित विदेशी बैंकों द्वारा ऐसी ही योजना के अंतर्गत जमा की गयी विदेशी मुद्राओं, (ii) भारत विकास बांड के अंतर्गत जुटायी गयी

निधियों तथा (iii) विदेशी संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी मुद्रा ऋण जो उपयुक्त होने तक रिजर्व बैंक के पास जमा किये गये, इन उधार ली गयी विदेशी मुद्राओं के संबंध में विनियमन के अधिनियमों की सुरक्षा के लिये भारी मात्रा में प्रावधान करें। रुपये की विविध बरों में ऋण-बढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये भविष्य में और भी प्रावधान करने होंगे और ऐसे सभी प्रावधान बैंक के लाभों से किये जाने होंगे।

15.15 30 जून 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाता से निकासी/नवीकरण के कारण भारतीय रिजर्व बैंक पर विनियम अधिनियम की वजह से 5,531.91 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा जबकि 30 जून, 1991 में यह बोझ 2,513.83 करोड़ रुपये था। परिणाम स्वरूप बैंक की प्रारंभित निधियां भारी ढ़ाब में आ गयी हैं। इसी संवर्ष में विभिन्न विदेशी मुद्रा जमा योजनाओं

(पहले के पैराग्राफ 7.15 में उल्लिखित) का पुनर्विचार करने का प्रयास किया जा रहा है।

15.16. लेखा परीक्षक—बैंक का लेखा मैसर्स मोरार एस. इंजीनियर एंड कंपनी, बंबई; मैसर्स ब्रह्मय्या एंड कंपनी, मद्रास; मैसर्स एन. एम. रायजी एंड कंपनी, बंबई; मैसर्स गोयल गंग एंड कंपनी, नयी दिल्ली; मैसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी, कलकत्ता तथा मैसर्स जे.एन. शर्मा एंड कंपनी, कानपुर द्वारा लेखा परीक्षित किया गया। जहां पहले 2 लेखा परीक्षक वर्ष 1991-92 के लिये भारत सरकार द्वारा पुनः नियुक्त किये गये वहीं अन्य 4 लेखा परीक्षक नये-नये नियुक्त किये गये। रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों को 6 खंडों में बांटा गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट के लिये उनका आवंटन किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक

परिशिष्ट

लेखा संबंधी टिप्पणियां तथा उल्लेखनीय लेखा नदितियां

1. (क) स्वर्ण धारिताएं

निर्वास और बैंकिंग विभाग में रखे गये सोने का मूल्यांकन सोने के औसत लंबन मूल्य पर किया जाता है और इस प्रकार दायरों में प्राप्त राशि को भारतीय रिजर्व बैंक की उस वर्ष के अंतिम कारोबारी विवस को प्रचलित डालर की खरीद दर पर वयों में बदला जाता है; उम्मुक्त दर के 90 प्रतिशत को सोने के मूल्यांकन के लिए लागू किया जाता है।

(ख) विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

वर्ष के अंतिम कारोबारी विवस को प्रचलित बाजार दरों से अनधिक की दर पर विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निकाला जाता है और उसे उस तारीख को प्रचलित विनियम दर पर समकक्ष रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जहां मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभावित किया जाता है, वहीं प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए कोई राशि जमा नहीं की जाती।

(ग) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

प्रतिभूतियों का मूल्य जून माह के अंतिम कार्य विवस को प्रचलित बाजार दर से अनधिक पर निकाला जाता है। जहां इसमें मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभावित किया जाता है, वहीं प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए कोई राशि जमा नहीं दर्शायी जाती है। रुपया प्रतिभूतियों की विक्री से प्राप्त आय को रिजर्व बैंक के निवेश खाते में जमा किया जाता है। लाभ/हानि को प्रतिभूतियों के मोधन के समय ही वर्ष किया जाता है।

(घ) सरकारी खजाना विवस

खजाना विलों को लागत मूल्य पर आंका जाता है।

(ङ) रिजर्व बैंक के निवेश

भारतीय स्टेट बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय मनीकाटा और वित्त गृह सिमिटेड के शेयरों में रिजर्व बैंक के निवेशों को लागत मूल्य पर आंका जाता है।

(ख) विदेशी मुद्राओं में आस्तियों और देयताओं को केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ वगैरे को संविदा के आधार पर निर्धारित किया गया हो, तुल्य पत्र की तारीख को प्रचलित विनियम दरों पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है। आय और व्यय को उस महीने की धारिता दर पर जिसमें कि सेन-देन हुआ हो, रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि खाते

आय और व्यय को अंशित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अंशित आय के लिए लेखांकन और बकाया खर्च के लिए प्रावधान केवल एक मास रुपये और उससे ऊपर की असंग-असंग मदों के लिए ही किया जाता है।

(घ) सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान निधि (ग्रेजुटी फंड) में अभिदान प्रत्येक वर्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किये जाते हैं। कर्मचारियों के लिए हाल ही में नुब की गयी पेंशन योजना के लिए वास्तविक मूल्यांकन की पद्धति को अभी अपनाया जाना बाकी है।

(ङ) मूल्यह्रास

आस्तियाँ जैसे कि परिसर, फिक्स्ड, डिजली के उपकरणों पर मूल्यह्रास लिखे हुए मूल्यों में से घटाकर किया जाता है तथा कम्प्यूटर, मोटर वाहन इत्यादि के मामलों में सीधे प्रभारित माध्यम से किया जाता है।

2. प्रारक्षित निधि

इसमें भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में प्रारंभ में किया गया 5 करोड़ रुपये का अंशदान तथा स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन के कारण 6,495 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि शामिल है।

3. जमा राशियाँ—अन्य

इसमें विदेशी केन्द्रीय बैंकों, विदेशी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शेष राशियाँ स्टॉक-पेंशन/भविष्य निधि अंशदान में प्राप्त जमा राशियाँ शामिल हैं।

4. अन्य देयताएं

इसमें मुख्यतः विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ एशियाई समाशोधन संघ के खाने तथा अन्य आकस्मिकता खाने के लिए प्रारक्षित निधि शामिल है।

5. अन्य आस्तियाँ

इसमें मुख्य रूप से स्वर्ण (भारत से बाहर रखे गये सोने का मूल्य 1188.65 करोड़ रुपये आंका गया है) अथवा आस्तियाँ पूंजीगत विभाजन जो बाबू है प्राप्त राशियाँ अंतर कार्यालय के खातों में विशेष राशियाँ, स्टॉक को बिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं। अथवा आस्तियों का उल्लेख लागत मूल्य पर किया गया है परन्तु उसमें से संचित मूल्यह्रास को घटा दिया है।

वैकिंग विभाग के निवेशों में विदेशों में रखी विदेशी मुद्राओं के 1234.87 करोड़ रुपये की राशि शामिल है (पिछले वर्ष यह राशि 95.14 करोड़ रुपये की थी।)

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1992 की स्थिति का तुल्य पत्र

(हजार रुपये में)

निर्गम विभाग					
1990-91	देयताएं	1991-92	1990-91	आस्तियां	1991-92
र.		र.	र.		र.
<hr/>					
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट				सोने का सिक्का और बुलियन	
संचलन में नोट		13,45,21	11,87,86	(क) भारत में रखा हुआ	7275,91,94
जारी किये गये कुल नोट		64550,25,75	57858,45,88	(ख) भारत से बाहर रखा हुआ	467,50,24
					200,00,00
		64563,70,96	57870,33,74	विदेशी प्रतिभूतियां	7943,42,18
				रपया सिक्के	96,01,23
				भारत सरकार की रुपये प्रतिभूतियां	56524,27,55
				देशी विनियम बिल और दूसरे	50168,07,82
				वाणिज्यिक पत्र	
कुल देयताएं		64563,70,96	57870,33,74	कुल आस्तियां	64563,70,96
					57870,33,74

वैकिक विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	प्राप्तियां	रुपये	रुपये
प्रवर्तन पूंजी	5,00,00	5,00,00	नॉट	13,45,21	11,87,86
प्रारम्भित निधि	6500,00,00	6500,00,00	रुपया निक्के	7,57	10,89
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	5675,00,00	5675,00,00	छोटे निक्के	11,01	6,97
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	175,00,00	175,00,00	खरीदे तथा भुनाये गये बिल	—	—
जमा राशि			(क) आंतरिक	—	—
(क) सरकार	47,30,04	105,62,06	(ख) बाहरी	1827,77,18	399,20,21
(1) केन्द्र सरकार	39,16,17	15,75,60	(ग) सरकारी खजाना बिल	14690,06,84	2087,54,77
(2) राज्य सरकारें			विदेशों में रखे गये बकाया शेयर	34739,34,93	46337,16,59
(ख) बैंक	43448,10,84	30789,61,72	निवेश		
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	250,01,04	548,01,79	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम	170,73,00	16,99,00
(2) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	135,16,23	188,13,88	(1) केन्द्र सरकार		
(3) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	10,55,21	10,89,75	(2) राज्य सरकार		
(4) गैर-अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	52,65,07	57,98,58	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा		
(5) अन्य बैंक	7690,07,35	5868,61,65			
(ग) अन्य	126,06,92	185,22,75	अग्रिम :	7471,98,19	6104,28,23
देय बिल	13867,74,23	15853,01,52	(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12,68,58	18,83,64
अन्य देयताएं 2			(2) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	—	9,83
			(3) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	—	—
			(4) गैर-अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	3552,27,17	3322,36,70
			(5) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास	1516,59,75	60,84,16
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)		
			निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :		
			(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण		
			तथा अग्रिम	3576,55,41	3705,15,46
			(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	877,00,00	745,00,00
			(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	170,00,00	130,00,00
			(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	840,00,00	400,00,00
			(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बॉन्डों/डिबेंचरों में निवेश :		
			(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—
			(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—
			(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	—	—
			(4) अन्य	—	—
			राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :		
			(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण एवं अग्रिम	175,00,00	123,00,00
			(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बॉन्डों/डिबेंचरों में निवेश	—	—
			अन्य प्राप्ति	4348,18,26	251,3,35,01
कुल देयताएं	78011,83,10	65977,89,31	कुल प्राप्ति	78011,83,10	63977,89,31

(रुपय में)

30 जून 1992 की समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

1990-91	आय	1991-92
व्यय		1991-92
व्याज, बट्टा विनिमय शुल्क, कमीशन आदि		रु.
	जोड़	रु.
		1990-91
व्यय		रु.
व्याज		रु.
स्थापना व्यय		रु.
निदेशकों और स्थायी बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय		रु.
काजाना प्रेषण		रु.
एजेंसी प्रभार		रु.
प्रतिभूति छपाई (बैंक, पोट, फार्म आदि)		रु.
मुद्रण और लेखन सामग्री		रु.
आक और मार खर्च		रु.
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		रु.
लेखा परिशकों के शुल्क और व्यय		रु.
विविध प्रभार		रु.
बैंक सेवसि का मूल्यह्रास और उनकी सरभमत		रु.
विशेष व्यय		रु.
	जोड़	रु.
उपलब्ध शेष राशि		रु.
बट्टा हटाने निम्नलिखित में अंशदान		रु.
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		रु.
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि		रु.
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण		रु.
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि 2		रु.
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण,		रु.
(स्विकारीकरण) निधि 2		रु.
राष्ट्रीय प्रवास ऋण		रु.
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि,		रु.
		रु.
केन्द्रीय सरकार का देय अधिशेष		रु.

1 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती हैं।

(बी. जी. भाठवले)
मुख्य लेखाकार(एस. एस. मारुपोर)
उप गवर्नरप्रार. जामकीरामन
उप गवर्नर(एम. वेंकटरमणन)
गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोदस्तावेजित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1992 की स्थिति के तुलना पत्र और उक्त तारीख का समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेख पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून, 1992 की स्थिति के तुलन पत्र की प्रीर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेख की जांच की है और यह निहित करने हैं कि हमने बैंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी ऐसी जानकारी प्रीर स्पष्टीकरण हमें दिये गये प्रीर ये संतोषजनक हैं। हमारी प्रीर में प्रीर हमारी सर्वोत्तम जानकारी प्रीर हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक के बही/खातों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलन-पत्र पूर्णतया सही तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि हमसे बैंक के कार्यों की सच्ची प्रीर सही स्थिति का पता लग सके।

मेमर्स मोराव एस इण्डिय एंड कं.

लेखा-परीक्षक

16 अगस्त, 1991

मेमर्स बहम्या एंड कं.

लेखा-परीक्षक

मेमर्स गोपल गन एंड कंपनी

लेखा-परीक्षक

एल.एम. रायजी एंड कं.

लेखा-परीक्षक

मेमर्स गुहा नन्दी एंड कं.

लेखा-परीक्षक

मेमर्स जे. एन. शर्मा एंड कं., लेखा-परीक्षक

परिशिष्ट सारणी 1.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अधिमों के लिए ब्याज दर संरचना (ब्याजकर के अलावा)

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते का श्रेणी	लागू दरें		
	9 अक्टूबर, 1991 से पहले की दरें	9 अक्टूबर 1991	22 अप्रैल 1992
1	2	3	4
1. ऋण सीमा का प्रकार			
1.7,500 रुपये तक प्रीर उसके महि	10.0	11.5	11.5
2. 7,500 रुपये से अधिक प्रीर 15,000 रुपये तक	11.5	13.0	13.5
3. 15,000 रुपये से अधिक प्रीर 25,000 रुपये तक	12.0	13.5	
4. 25,000 रुपये से अधिक प्रीर 50,000 रुपये तक	14.0	15.5	16.5
5. 50,000 रुपये से अधिक प्रीर 2 लाख रुपये तक	15.0	18.5	
6. 2 लाख से अधिक*	18.5*	20.0	19.0
	(न्यूनतम)	(न्यूनतम)	(न्यूनतम)
II 1. विशेषक ब्याज दर अधिम	4.0	4.0	4.0
2. कृषि, लघु उद्योग प्रीर दो बाहुओं तक रखने वाले परिवहन वाहनों का सीमासी ऋण			
ऋण सीमा का प्रकार			
(i) 25,000 रुपये से अधिक प्रीर 50,000 रुपये तक	13.0	14.0	15.0
(ii) 50,000 रुपये से अधिक प्रीर 2 लाख रुपये तक	14.0	15.0	
(iii) 2 लाख रुपये से अधिक	14.0	15.0	15.0
		(न्यूनतम)	(न्यूनतम)
3. (i) उद्योगिता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण		बैंकों को दरे निर्धारित करने की छूट है	
(ii) शोहरों प्रीर डिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तियों को ऋण			
(iii) अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण			
3. अत्यन्तमक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले पण्यों के लिए उधार की दर			
अत्यन्तमक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत पण्यों पर ऋण/अधिम/नकदी ऋण,* ओवरड्राफ्ट	(न्यूनतम) 18.5*	(न्यूनतम) 20.0	(न्यूनतम) 19.0

टिप्पणी :

- उत्त पाटियों के लिए जिनकी नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट की सीमा दो लाख रुपये से अधिक है, उनके बिल धुनाई पर लागू ब्याज की दर उससे 1 प्रतिशत बिन्दु कम होनी चाहिए जितनी की नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा पर बसूल की जानी है।
- अंतिम हितवाधिकायियों को ऋण देने के लिए मध्यस्थ एजेंसियों (आवास ऋण देने वाली एजेंसियों सहित) तथा निविष्टियों का समर्थन देने वाली एजेंसियों के लिए ब्याज दरें उस न्यूनतम दर से 3.00 प्रतिशत बिन्दु तक कम होनी चाहिए जो 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा में आने वाली श्रेणी पर लागू होती है।

3. जहाँ अल्पकालिक ऋण प्रदानित की ऋण समितियों/बड़े प्रकार की बहु-उद्देश्यीय समितियों/कृषक सेवा समिति के माध्यम से अल्पकालिक ऋण विये जाते हैं, वहाँ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े प्रकार की बहु-उद्देश्यीय समितियों/कृषक सेवा समितियों से बैंकों द्वारा धन की जाने वाली ब्याज दर उससे 2.5 प्रतिशत बिन्दु कम होगी जो ऊपर I में वर्णित अंतिम उपभोगकर्ताओं के लिए निश्चित संबंधित ऋण मॉडल पर लागू होती है।

* इस दर में मितम्बर 1990 से किये गये परिवर्तन नीचे दिए गये हैं।

- 16.0 (न्यूनतम) 22 मितम्बर 1990 से लागू
 17.0 (न्यूनतम) 18 अप्रैल 1991 से लागू
 18.0 (न्यूनतम) 9 जुलाई 1991 से लागू
 20.0 (न्यूनतम) अक्टूबर 1991 से लागू
 19.0 (न्यूनतम) 2 मार्च 1992 से लागू

परिशिष्ट सारणी I . 2 : अनुसूचित बाणिज्य बैंकों की जमा राशियों पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते का प्रकार	लागू दरें		
	4 जुलाई 1991	9 अक्टूबर 1991	22 अप्रैल 1992
1	2	3	4
चालू	शून्य	शून्य	शून्य
बचत	5.0	5.0	6.0 ^a
सीमादी जमा राशियाँ			
(क) 46 दिनों से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम अवधि तक	9.0	11.0	13.0 से अधिक गारंटी
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम अवधि तक	10.0	12.0	
(ग) दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम अवधि तक	11.0	13.0	
(घ) तीन वर्ष और इससे अधिक	13.0	13.0	
* 24 अप्रैल 1992 से लागू	13.0	13.0	

परिशिष्ट सारणी I . 3 : अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

(ब्याज-दर की छोड़कर)

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	लागू दरें					
	1 अप्रैल 1991	23 अप्रैल 1991	6 अगस्त 1991	9 अक्टूबर 1991	1 जनवरी 1992	2 मार्च 1992
1	2	3	4	5	6	7
1. पोत-सदान से पूर्व ऋण						
(क) (1) 180 दिनों तक	7.50	7.50	12.50	15.00	15.00	15.00
(2) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	9.50	9.50	14.50	17.00	17.00	17.00
(ख) नकद प्रोत्साहन इत्यादि के लिए ई सी जी जी सी द्वारा शामिल 90 दिन तक की गारंटी	7.50	7.50	12.50	15.00	15.00	15.00
2. पोत-सदान के पश्चात् ऋण						
(1) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडरल द्वारा यथापिनिर्दिष्ट)	8.65	7.00	12.50	15.00	15.00	15.00

- (ii) मीयादी बिल (निर्यात बिलों, फेडाई द्वारा यथाविवक्षित मार्गस्थ अवधि की मीयादी अवधि को शामिल करते हुए कुल अवधि के लिए जहाँ भी लागू हो सतिस्विन अवधि को शामिल है।)

(क) 45 दिन तक		7.00	}	12.50	13.00	15.00	15.00
(ख) 45 दिन से अधिक और 90 दिन तक	8.65	8.65					

90 दिनों तक

(ग) 90 दिन से अधिक और पोत लदान का तारीख से छ माह तक (अग्रिम को तारीख से 2.00 के अग्रिमभार)	16.00	18.00	18.00	20.00	20.00	19.00
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(घ) पोत लदान की तारीख से छ. माह से अधिक	16.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00
(अग्रिम की तारीख से 2.00 के अग्रिमभार सहित)	(अग्रिम की तारीख से 2.00 के अग्रिमभार सहित)	(अग्रिम की तारीख से 2.00 के अग्रिमभार सहित)				

(iii) ई सी जी सी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त तकस प्रोत्साहन ड्यूटी ट्रा बैंक (90 दिन तक)	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
(iv) अनाहतिद शेष राशि (90 दिन तक)	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
(v) अभिवारण धन के लिए (केवल आपूर्ति भाग के लिए) पोत-लदान की तारीख (90 दिन तक) से एक वर्ष में ही देय	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
3. आस्थगित ऋण	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00

180 दिन से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण

4. ड्यूटी ट्रा बैंक बैंक में रिट स्कीम, 1976 मोबा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अव्यायी रूप से प्रमाणित ड्यूटी ट्रा बैंक के लिए (90 दिन तक)	व्याज मुक्त	व्याज मुक्त	व्याज मुक्त	व्याज मुक्त		
5. निर्यात ऋण, अन्य प्रकार से वित्तियित नहीं	16.00 (न्यूनतम)	18.00 (न्यूनतम)	18.50 (न्यूनतम)	20.00 (न्यूनतम)	20.00 (न्यूनतम)	19.00 (न्यूनतम)

6. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित पोत लदानोत्तर निर्यात ऋण

(i) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडाई द्वारा यथाविवक्षित)				8.5	6.5
(ii) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, मार्गस्थ अवधि फेडाई द्वारा यथाविवक्षित, छूट की अवधि, जहाँ भी अनुभव हो, कुछ अवधि में पोत लदान की तारीख से छ. माह तक शामिल है)				8.5	6.5

* 12 मार्च 1992 से भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं माना गया है।

परिशिष्ट सारणी 1.4 : न्यूनतम भाजित और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर

(22 अप्रैल 1992 से)

(प्रतिशत में)

पण्य	न्यूनतम भाजित			उच्चतम ऋण	
	मिले/प्रतिस्करण युनिट	गन्ता	गोदाम रमीने	सीमा का स्तर	(आधार वर्ष: 1990-91 को समाप्त तीन वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर))
1	2	3	4	5	
1. धान/बाजरा	60	75	60	75	
2. गेहूँ	60	75	60	70	
3. घाल	60	75	60	85	
4. अन्य खाद्यान्न	60	75	60	85	
5. तिलहन (जैसे सूतकरी, तंगिया/सरसों, चिनीला, सलसी, एरण्ड और सभी आयातित तेल)	60	75	60	85	

1	2	3	4	5
6 वनस्पति तेल (जैसे मूंगफली, तोरिया/ सरसों, अलसी, एरंड वनस्पति और सभी प्राप्यनि वनस्पति तेल)	60@	75	60	85
7 चीनी				
(क) प्राप्यनी स्टॉक	0	—	—	—
(ख) प्रतिगत स्टॉक	20*	—	—	—
(ग) निर्यात स्टॉक	75	75	60	—
8 गुड़ और खांडसारी	45	75	60	—
9. लहई और कपास	×	75	60	85

@पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति निर्यातकों के संबंध में लागू ।

—लागू नहीं × शर्तों से छूट प्राप्त

* 9 मई 1991 से 8 अगस्त 1991 तक की अवधि के दौरान 17.5 प्रतिशत की दर पर।

परिशिष्ट सारणी 1.5 : विदेशी सहयोग के अनुमोदन

सदें	1990	1991	1991-92 (अगस्त-मई) (तीन पश्चात अवधि)	1990-91 (अगस्त-मई)
1	2	3	4	5
1. निम्नलिखित द्वारा विदेशी सहयोग के दिये गये कुल अनुमोदन :				
(1) ओ. ए. स.	666	760	831	474
(2) भा. रि. बैं.	—	188	580	—
(3) वि. नि. सं. प.	—	2	19	—
जोड़	666	950	1,430	474
2. विदेशी ईक्यूटी के लिए विदेशी मुद्रा अनुमोदनों की सं. :				
(i) ओ. ए. स.	194	246	332	147
(ii) भा. रि. बैं.	—	41	168	—
(iii) वि. नि. सं. प.	—	2	19	—
जोड़	194	289	519	147
3. विदेशी ईक्यूटी की कुल राशि (रु. वस लाख)				
(i) ओ. ए. स.	1,283.2	3,577.6	4,688.4	1,632.6
(ii) भा. रि. बैं.	—	1,422.4	5,734.3	—
(iii) वि. नि. सं. प.	—	341.1	8,465.2	—
जोड़	1,283.2	5,341.1	18,887.9	1,632.6

टिप्पणी : 10 मिलियन = 1 करोड़ । ओ. ए. स. = औद्योगिक अनुमोदन परिषद

भा. रि. बैं. = भारतीय रिजर्व बैंक वि. नि. सं. प. = विदेशी निवेश संवर्धन परिषद

परिशिष्ट सारणी 2.1 : क्षेत्रांतर संरचना तथा वास्तविक सकल देशी उत्पाद (स.वे.उ.) की वृद्धि दरें

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	वास्तविक स.वे.उ. में अंश			वृद्धि दर				
	1990-91*	1980-81	1970-71	1990-91*	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और संबन्ध कार्य	31.6	38.2	44.5	+4.2	+2.7	+16.4	+0.4	-1.7
(क) कृषि	29.5	34.7	39.7	+4.3	+2.6	+17.6	+0.5	-1.7
2. उद्योग	24.6	20.8	18.6	+7.1	+7.4	+8.5	+6.8	+7.8
(क) विनिर्माण	20.6	17.6	16.1	+7.3	+7.2	+8.5	+7.0	+7.0
3. सेवाएं	43.8	41.0	36.9	+5.8	+7.8	+7.3	+5.8	+7.3
जोड़ (स.वे.उ.)	100.0	100.0	100.0	+5.6	+6.0	+10.5	+4.2	+4.3

* त्वरित अनुमान (करवर्ग 1992) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

@ निर्माण सहित

परिशिष्ट सारणी 2.2 : देशी बचत तथा निवेश अनुपात के अनुमान

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/राजकीय वर्ष	बालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बचत तथा निवेश			बालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत तथा निवेश		
	1991-92	1990-91	1989-90	1991-92	1990-91	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र की बचत जिस में से : वित्तीय	19.2	18.7	18.4	17.1	16.6	16.2
आस्तियों* में बचत	9.5	8.9	9.5	10.6	9.8	10.6
2. सार्वजनिक क्षेत्र	1.2	0.9	1.6	3.7	4.1	-3.4
3. देशी निजी कंपनी क्षेत्र	2.8	2.6	2.7	0.9	0.8	0.8
4. कुल : देशी बचत (1+2+3)	23.2	22.2	22.7	14.3	13.4	13.6
5. कुल विदेशी स्रोतों का शुद्ध आगमन	0.9	2.6	2.5	1.0	2.9	2.8
6. कुल निवेश (4+5)	24.1	24.8	25.2	15.3	16.3	16.4
बालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद/शुद्ध देशी उत्पाद (करोड़ रुपये)	6,19,000***	5,29,537**	4,50,601@	5,57,079***	4,77,460**	4,05,055@

* वित्तीय वास्तव्यों के लिए इनका समायोजन किया गया। चूंकि वित्तीय आस्तियों में बचत बचल आस्तियों के लिए पूंजी के उपयोग में शामिल नहीं होती। इससे शुद्ध आसत सकल आसतों से अधिक आते हैं। इसी प्रकार विदेशी स्रोतों के शुद्ध आगमन में होता है।

** त्वरित अनुमान,

*** सा. रि. बैंक के अनुमान

@ अंतिम अनुमान

टिप्पणियाँ : 1. नये आंकड़ों के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय तथा बचत और निवेश के अनुमानों में संशोधन होने के कारण बैंक के पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये तथा 1990-91 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के 'त्वरित अनुमानों' में प्रकाशित आसत 1989-90 तथा 1990-91 के आसतों से भिन्न हैं।

2. अंतरों की पूर्णांकित किये जाने के कारण आंकड़े कुल योग से मेल नहीं खा सकते।

परिशिष्ट सारणी 2 : 3 कृषि उत्पाद

(मिलियन टन में)

फसल	1988-89	1989-90	1990-91 (अंतिम)	1991-92 (संभावित उपलब्धि)
1	2	3	4	5
1 सभी फसलें	21.0	2.1	2.6	~1.0
2 खाद्यान्न	169.9	171.0	176.2	169.0-170.5
(क) खरीफ				
चावल	70.5	73.6	74.6	74.0-74.5
गेहूं	54.1	49.8	54.5	55.0
मोटे धानाज	31.5	34.8	33.0	27.0-27.5
दालें	13.8	12.8	14.1	13.0-13.5
(क) खरीफ	95.6	101.0	99.9	94.2
चावल	63.4	65.9	66.6	65.7
मोटे धानाज	26.6	29.6	27.9	23.5
दालें	5.6	5.5	5.4	5.0
(ख) रबी	74.3	70.0	76.3	74.8-76.3
चावल	7.1	7.7	8.0	8.3-8.8
गेहूं	54.1	49.8	54.5	55.0
मोटे धानाज	4.9	5.2	5.1	3.5-4.0
दालें	8.2	7.3	8.7	8.0-8.5
3 तिलहन	18.0	16.9	18.5	18.3
4 गन्ना	203.5	225.6	240.3	244.3
5 कपास*	8.7	11.4	9.8	9.8
6 जूट और मेस्ता@	7.9	8.3	9.1	10.1

* 170 कि. घा. की प्रत्येक गांठ @ 180 किघा. की प्रत्येक गांठ द्विगुण करें

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट सारणी 2.4 : पशुओं की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

(मिलियन टन)

राजकोषीय वर्ष	सरकारी खरीद			निकासी			स्टॉक*		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़@	चावल	गेहूं	जोड़@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1989-90	11.2	9.0	20.2	8.4	9.3	15.8	7.9	3.6	11.7
1990-91	12.8	11.1	23.9	7.8	8.3	16.1	11.2	5.8	17.3
1991-92\$ पहली तिमाही अप्रैल-जून	10.5	7.8	18.3	9.9	9.1	19.0	9.8	2.3	12.1
1991	1.3	7.7	9.0	2.5	2.1	4.6	9.9	11.0	21.1
1992 \$	1.1	6.4	7.5	2.3	1.9	4.2	8.4	6.7	15.1

*ये स्टॉक राजकोषीय वर्ष की अवधि के लिए माल के अंत के हैं तथा प्रथम तिमाही की अवधि के लिए जून के अंत के हैं।

@मोटे धानाज शामिल हैं। \$अनतिम

स्रोत : खाद्य और नगरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट सारणी 2.5 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ
(आधार : 1980-91=100)

वर्ष	क्षेत्र		खनन और उत्खनन		बिनिर्माण		बिजली		सामान्य सूचकांक	
	भारतीय		11.46		77.11		11.43		100.00	
	सूचकांक	वृद्धि दर	सूचकांक	वृद्धि दर	सूचकांक	वृद्धि दर	सूचकांक	वृद्धि दर	सूचकांक	वृद्धि दर
	(प्रतिशत)		(प्रतिशत)		(प्रतिशत)		(प्रतिशत)		(प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1987-88	184.6	3.7	161.5	7.9	181.0	7.6	166.4	7.3		
1988-89	199.1	7.9	175.6	8.7	198.2	9.5	180.9	8.7		
1989-90	211.6	6.3	190.7	8.6	219.7	10.9	196.4	8.6		
1990-91	221.2	4.5	208.0	9.1	236.8	7.8	212.8	8.3		
अप्रैल-जून	211.0	4.7	195.2	14.6	228.1	9.8	200.7	12.6		
जुलाई-सितम्बर	196.6	1.7	196.5	12.6	229.7	7.8	200.3	10.6		
अक्टूबर-दिसम्बर	215.1	0.4	203.4	5.9	237.6	3.7	208.6	4.9		
जनवरी-मार्च	262.0	10.5	237.1	5.0	251.9	10.1	241.6	6.2		
1991-92	2231.	0.9	204.4	-1.7	256.5	8.3	212.5	-0.1		
अप्रैल-जून	203.1	-3.7	188.2	-3.6	242.5	6.3	196.1	-2.3		
जुलाई-सितम्बर	193.1	-1.8	194.4	-1.1	252.5	9.9	200.9	0.3		
अक्टूबर-दिसम्बर	227.6	5.8	196.3	-3.5	261.8	10.2	207.4	-0.6		
जनवरी-मार्च	268.7	2.6	238.5	0.6	269.2	6.9	245.5	1.6		

परिशिष्ट सारणी 2.6 : बिनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि

उद्योगसमूह	भारतीय	राष्ट्रकोषीय वर्ष		
		1989-90	1990-91	1991-92
1 धातुसक				
तेज - वृद्धि (1991-92 के दौरान)				
1. पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	1.57	103.0	104.3	117.8
		(+11.8)	(+1.3)	(+12.9)
2. गैर धातुसक खनिज उत्पाद	3.00	189.9	193.2	204.9
		(+2.9)	(+1.7)	(+6.1)
कम वृद्धि (1991-92 के दौरान)				
3. मूल धातु व मिश्रधातु उद्योग	9.80	143.7	159.1	167.8
		(-0.8)	(+10.7)	(+5.5)
4. कागज और कागज उत्पाद	3.23	181.5	197.9	205.1
		(+6.0)	(+9.0)	(+3.6)
5. खाद्य और खाद्य उत्पाद	5.33	150.9	169.7	175.5
		(+1.6)	(+12.5)	(+3.4)
6. रसायन और रसायनिक उत्पाद	12.51	247.6	254.3	260.3
		(+6.1)	(+2.7)	(+2.4)

1	2	3	4	5
7. सूती वस्त्र	12.31	112.3	128.7	129.7
		(+4.2)	(+14.6)	(+0.8)
11. कृषात्मक (1991-92 के दौरान)				
8. विविध विनिर्माण उद्योग	0.90	333.2	323.7	270.6
		(+9.0)	(-2.9)	(-16.4)
9. बिजली की मशीनरी	5.78	459.2	562.0	503.9
		(+31.9)	(+22.4)	(-10.3)
10. खमड़ा तथा खमड़ा एवं फर उत्पाद	0.49	188.3	194.2	180.7
		(+6.1)	(+3.1)	(-7.0)
11. धातु उत्पाद	2.29	142.6	143.2	133.2
		(+6.8)	(+0.4)	(-7.0)
12. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	0.45	176.0	198.4	185.2
		(+2.5)	(+12.7)	(-6.7)
13. वस्त्र उत्पाद (जिसमें पहनने के कपड़े शामिल हैं)	6.82	151.7	103.2	97.3
		(+13.0)	(-32.0)	(-5.7)
14. जूट, हेम्प और मेस्ता वस्त्र	2.00	97.4	101.7	97.5
		(-4.4)	(+4.4)	(-4.1)
15. मशीनरी और मशीनी औजार	6.24	171.9	137.9	179.5
		(+6.7)	(+8.8)	(-4.0)
16. परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	6.39	181.1	192.5	187.6
		(+5.0)	(+6.3)	(-2.5)
17. रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	4.00	173.5	173.4	171.1
		(+3.1)	(-0.1)	(-1.2)
विनिर्माण क्षेत्र	77.11	190.7	208.0	205.0
		(+8.4)	(+9.1)	(-1.4)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तबनुकुर अवधि के वृद्धता में घट-बढ़ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 2.7: औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि दर उपयोग आधारित वर्गीकरण

उद्योग समूह	समस्त उद्योग				शुनिदा 155 उद्योग			
	प्रतिशत में घट-बढ़		उद्योगों की भारी संख्या		प्रतिशत में घट-बढ़			
	भारतीय वृद्धि दर				1989-90 1990-91@ 1991-92@			
	1985-86 1990-91@				मे			
	1	2	3	4	5	6	7	8
[क] आधारभूत वस्तु उद्योग	39.42	+7.4	+3.8	40	36.36	+5.2	+9.7	+6.2
[ख] उपभोक्ता वस्तुएं - जिनमें से	23.65	+7.3	+10.4	47	21.76	+5.2	+9.1	-1.1
[क] उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	2.55	+11.8	+14.8	12	2.20	+2.0	+9.1	-12.5
[ख] उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	21.10	+6.5	+9.4	35	19.56	+5.8	+9.1	+1.2
[ग] पूंजीगत वस्तुएं	16.42	+14.8	+17.4	32	11.32	+29.1	+5.4	-12.8
[घ] मध्यवर्ती वस्तुएं	20.51	+6.5	+6.1	36	16.10	+4.3	+9.5	-0.7
सामान्य सूचकांक	100.00	+8.5	+8.3	155	85.54	+9.2	+8.6	-0.5

@ अंतिम

*आंकड़े 155 शुनिदा उद्योगों पर आधारित हैं, सामान्य सूचकांक में जिनका भारी 85.5 प्रतिशत बैठता है।

स्रोत : औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी 2.8 : आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

उद्योग	आंक	यूनिट	राजकोषीय वर्ष		
			1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
विद्युत	11.43	बिलियन यूनिट	245.14	264.23 (+7.8)	286.70 (+8.5)
कोयला	6.61	मिलियन टन	200.90	211.70 (+5.4)	229.30 (+8.3)
बिक्री योग्य हस्तात	5.21	-बही-	9.03	9.31 (+3.1)	10.07 (+8.1)
सीमेंट	1.60	-बही-	45.80	48.69 (+6.3)	53.70 (+10.3)
कच्चा पेट्रोलियम	2.41	-बही-	34.09	33.03 (-3.1)	30.34 (+8.1)
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	1.52	-बही-	48.31	48.15 (-0.3)	47.82 (-0.7)
मूलभूत संरचना वाले उद्योगों का संमिश्र सूचकांक	28.77	संख्या	205.3	215.0 (+4.8)	228.0 (+6.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़-बढ़ को दर्शाते हैं।

स्रोत : योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट सारणी 3.1 घाटे के उपाय : केन्द्र सरकार का सुश्रीकृत बजट, सकल और निवल राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सकल राज कोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	सुश्रीकृत घाटा	परम्परागत घाटा	राजस्व घाटा	बाजार मूल्यों पर सकल उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	8,299	5,110	7,490	3,551	2,477	2,037	1,36,013
1981-82	8,666	4,591	7,686	3,207	1,400	392	1,59,760
1982-83	10,627*	5,973*	9,541*	3,368	1,656*	1,308	1,78,132
1983-84	13,030*	8,171*	10,903*	3,949	1,417*	2,540	2,07,589
1984-85	17,416	10,972	15,405	6,053	3,745	4,225	2,31,387
1985-86	21,857*	13,543*	18,940*	6,190	5,315*	5,889	2,61,920
1986-87	26,342	17,036	22,449	7,091	8,261	7,777	2,91,974
1987-88	27,044	18,431	21,548	6,559	5,816	9,137	3,32,616
1988-89	30,923	20,770	23,626	6,503	5,642	10,515	3,94,992
1989-90	35,632	23,722	26,349	13,813	10,592	11,914	4,50,601
1990-91	44,650	30,170	31,909	14,746	11,347	18,562	5,29,537
1991-92	37,792	26,126	21,839	5,508	7,032	17,081	6,19,000**
(संशोधित अनुमान)							
1992-93 (बजट अनुमान)	34,408	23,940	15,872	5,389	5,389	13,882	7,00,000

बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

1980-81	6.10	3.76	5.51	2.61	1.82	1.50
1981-82	5.42	2.87	4.81	2.01	0.88	0.25
1982-83	5.97	3.35	5.36	1.89	0.93	0.73
1983-84	6.28	3.94	5.25	1.90	0.68	1.22
1984-85	7.53	4.74	6.66	2.62	1.62	1.83
1985-86	8.34	5.17	7.23	2.36	2.03	2.25
1986-87	9.02	5.83	7.69	2.43	2.83	2.25
1987-88	8.13	5.54	6.48	1.97	1.75	2.75
1988-89	7.83	5.26	5.98	1.65	1.43	2.66
1989-90	7.91	5.26	5.85	3.07	2.35	2.64
1990-91	8.43	5.80	6.03	2.78	2.14	3.51
1991-92	6.50+	4.22	3.53	0.89	1.14	2.76
1992-93	5.00	3.42	2.27	0.77	0.77	1.98

@पूँजीगत लेखों में कतिपय प्रवृत्तियों के कुछ समायोजनों के कारण ये आंकड़े पहले प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं।

*इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982-83 में 1743 करोड़ रुपये, 1983-84 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 1628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण शामिल नहीं किये गये हैं।

†भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े

\$द्वारित अनुमान

**भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान

\$ \$ वर्ष के अनुमान

&बजट दस्तावेजों के अनुसार। 31 मार्च, 1992 की सरकारी लेखों को बन्द करने के बाद रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार 6,492 करोड़ रुपये का घाटा था।

‡ओ. सी. सी. तथा अन्य शामिल हैं।

टिप्पणी 1. ये आंकड़े मध्यम बजट प्रलेखों पर आधारित हैं तथा पहले प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न भी हो सकते हैं।

2. घाटा संबंधी संकल्पनाओं की परिभाषा के लिए वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 का पृष्ठ 84-85 देखें, उक्त रिपोर्ट का पृष्ठ 183 पैरा 7.18 भी देखें।

स्रोत : केन्द्रीय सरकार के बजट प्रलेख तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख एवं राष्ट्रीय लेखा मंडिकी।

परिशिष्ट सारणी 3.2 : केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के वार्षिक स्तर

(करोड़ रुपये)

वर्ष	दिनांक	केन्द्र का बजट घाटा				केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
बजट अनुमान		7,337	7,206	7,719	5,389	7,206	7,719	5,389	
(पाक्षिक तारीख)	दिनांक								
1	5-4-91	1,170	2,679	2,271	4,774	2,011	2,712	2,427	3,847
2	19-4-91	3,497	3,204	3,716	6,115	3,772	4,050	3,269	6,52
3	3-5-91	6,045	5,754	5,508	6,604	5,461	4,994	3,962	5,219
4	17-5-91	6,176	6,638	8,409	8,928	6,392	7,058	6,764	7,21
5	31-5-91	8,565	8,228	8,925	10,414	7,675	6,907	7,534	7,95
6	14-6-91	9,508	7,698	11,209	10,854	7,784	7,463	9,607	7,92
7	28-6-91	9,824	9,107	1,503	8,286	7,858	7,703	9,168	3,92
8	12-7-91	11,378	9,996	12,747		9,500	9,883	11,165	
9	26-7-91	11,382	10,128	11,873		9,140	8,185	10,580	
10	9-8-91	13,416	10,976	12,793		10,277	9,018	10,750	
11	23-8-91	12,596	8,729	11,571		9,938	6,543	10,303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	6-9-91	13,265	10,280	13,442	10,664	8,209	11,029	
13	20-9-91	11,535	10,289	10,393	9,111	7,269	11,029	
14	4-10-91	12,952	11,971	12,406	11,186	9,245	10,445	
15	18-10-91	10,375	10,755	13,097	9,869	10,241	11,863	
16	1-11-91	10,934	11,830	11,409	8,901	10,438	9,564	
17	15-11-91	13,044	13,636	14,245	12,403	12,476	12,419	
18	29-11-91	13,789	13,001	15,272	12,748	12,978	13,117	
19	13-12-91	13,317	15,330	17,419	13,634	15,159	15,930	
20	27-12-91	11,789	13,097	11,503	12,611	13,333	9,312	
21	10-1-92	14,206	15,093	16,177	15,277	14,621	13,961	
22	24-1-92	14,158	15,123	14,138	15,255	14,621	13,961	
23	7-2-92	13,675	15,442	15,726	15,395	15,447	15,305	
24	21-2-92	13,790	14,627	15,024	15,804	15,100	14,454	
25	6-3-92	14,266	15,072	13,011	16,383	16,064	12,435	
26	20-3-92	10,290	11,969	10,606	14,344	14,486	10,452	
	31 मार्च	10,624	11,430	6,492	13,813	14,746	5,508	
तिमाही औसत								
पहली तिमाही		6,398	6,187	7,337	5,843	5,841	6,104	
दूसरी तिमाही		12,262	10,068	12,137	9,772	8,185	6,104	
तीसरी तिमाही		12,314	12,803	13,822	11,622	11,938	11,865	
चौथी तिमाही		13,398	14,554	14,114	15,410	15,130	13,606	
वित्त वर्ष का औसत		10,947	10,818	11,508	10,635	10,336	10,209	

@ भारतीय रिजर्व बैंक के अधिलेखों पर आधारित

\$ वर्ष 1991-92 के लिए पञ्चवारों के संगत दिनांक विविष्ट किए गए हैं, अन्य वर्षों के संदर्भ में वित्तिक तदनुसंग पञ्चवारों से संबंधित हैं।

टिप्पणी : बजट संबंधी आंकड़ों के अनुसार केन्द्र का घाटा 1989-90 में 10,592 करोड़ रुपये और 1990-91 में 11,347 करोड़ रुपये का था।

परिशिष्ट सारणी 3.3 : सकल राजकोषीय घाटे का वितरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	विदेशी वित्त		देशी वित्त			कुल वित्त/ सकल राज-
	बाजार ऋण +	अन्य देयताएँ	परंपरागत घाटा \$	जोड़ (3+4+5)	कोषीय घाटा (2+6)	
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,281 (15.4)	2,679 (32.3)	1,862 (22.4)	2,477 (29.9)	7,018 (84.6)	8,299 (100.0)
1981-82	964 (11.1)	2,913 (33.6)	3,389 (39.1)	1,400 (16.2)	7,702 (88.9)	8,666 (100.0)
1982-83	1,258 (11.8)	3,771 (35.5)	3,942 (37.1)	1,656* (15.6)	9,369 (88.2)	10,627 (100.0)
1983-84	1,338 (10.3)	4,038 (31.0)	6,237 (47.8)	1,417* (10.9)	11,692 (89.7)	13,030 (100.0)
1984-85	1,452 (8.3)	4,095 (23.5)	8,124 (46.7)	3,745 (21.5)	15,954 (91.7)	17,416 (100.0)
1985-86	1,449 (6.6)	4,884 (22.4)	10,209 (46.7)	5,315* (21.5)	20,408 (91.7)	21,857 (100.0)

1	2	3	4	5	6	7
1986-87	2,024 (7.7)	5,532 (21.0)	10,525 (39.9)	8,261 (31.4)	24,318 (92.3)	25,342 (100.0)
1987-88	2,893 (10.7)	5,862 (21.7)	12,473 (46.1)	5,816 (21.5)	24,151 (89.3)	27,044 (100.0)
1988-89	2,460 (8.0)	8,418 (27.2)	14,403 (46.6)	5,642 (18.2)	28,463 (92.0)	30,923 (100.0)
1989-90	2,595 (7.3)	7,404 (20.8)	15,041 (42.2)	10,592 (29.7)	33,07 (92.7)	35,632 (100.0)
1990-91	3,181 (7.1)	8,001 (17.9)	22,121 (49.5)	11,347 (25.4)	41,469 (92.9)	44,650 (100.0)
1991-92 (संक्षिप्त अनुमान)	5,063 (13.4)	7,500 (19.8)	18,197 (48.2)	7,032 (18.6)	32,729 (86.6)	37,792 (100.0)
1992-93 (बजट अनुमान)	4,509 (13.1)	5,000 (14.5)	19,510 (56.7)	5,389 (15.7)	29,899 (86.9)	34,408 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वित्त/सकल राजकोषीय घाटे में प्रतिशत घंटा दर्शाते हैं।

+ कुछ वर्षों के संदर्भ में ये आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड पर आधारित हैं, लेखा संबंधी अज्ञान और पश्चात् के कारण परिशिष्ट III.11 में दिये आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

* ग्रन्थ देयताओं में चलन बजट, भविष्य निधियाँ, विशेष जमा राशियाँ, प्रारक्षित निधियाँ आदि शामिल हैं।

\$ भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष राशियों में परिवर्तनों को घटाने के बाद जारी किये गये 91 विवक्षित खजाना जिलों के घट-वृद्ध के रूप में परिभाषित।

* भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रॉवर ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982-83 के 1,743 करोड़ रुपये, 1983-84 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 के 1,628 करोड़ रुपये मध्यावधि ऋण इसमें शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट सारणी 3.4 : भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आंतरिक ऋण	ग्रन्थ बकाया	भविष्य निधि और ग्रन्थ लेखे	प्रारक्षित निधि और जमा राशियाँ	कुल आंतरिक देयताएं	विदेशी देयताएं	कुल देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30,864 (22.7)	7,976 (5.9)	5,977 (4.4)	3,634 (2.70)	48,451 (35.7)	11,298 (8.3)	59,749 (44.0)
1981-82	35,653 (22.4)	9,375 (5.9)	7,203 (4.5)	3,627 (2.3)	55,858 (35.0)	12,328 (7.7)	68,186 (42.7)
1982-83	46,939 (26.4)	11,098 (6.2)	8,789 (5.0)	4,364 (2.5)	71,190 (40.1)	13,682 (7.7)	84,872 (47.8)
1983-84	50,263 (24.3)	13,506 (6.5)	10,368 (5.0)	6,004 (2.9)	80,141 (38.7)	15,120 (7.3)	95,261 (46.0)
1984-85	58,537 (25.4)	17,157 (7.5)	12,547 (5.4)	8,563 (3.7)	96,804 (42.0)	16,637 (7.2)	1,13,441 (49.0)
1985-86	71,039 (27.0)	21,449 (8.2)	15,410 (5.9)	11,433 (4.4)	1,19,331 (45.8)	18,153 (6.9)	1,37,484 (52.4)
1986-87	86,312 (29.4)	24,725 (8.4)	20,204 (6.9)	15,006 (5.1)	1,46,247 (49.8)	20,299 (6.9)	1,66,546 (56.7)
1987-88	98,616 (29.7)	28,358 (8.5)	26,170 (7.9)	19,164 (5.7)	1,72,338 (51.8)	23,223 (7.0)	1,95,561 (58.8)
1988-89	1,14,498 (29.0)	33,933 (8.6)	34,702 (8.8)	20,992 (5.3)	2,04,025 (51.7)	25,746 (6.5)	2,29,771 (58.2)

1	2	3	4	5	6	7	8
1989-90	1,33,193 (29.6)	41,791 (9.3)	45,273 (10.0)	19,592 (4.3)	2,39,849 (53.2)	28,343 (6.3)	2,68,192 (59.5)
1990-91	1,54,004 (29.1)	50,100 (9.4)	56,940 (10.8)	22,150 (4.2)	2,83,194 (53.5)	31,525 (5.9)	3,14,719 (59.4)
1991-92 (संशोधित अनुमान)	1,70,104 (27.5)	55,620 (9.00)	67,105 (10.8)	24,850 (4.0)	3,17,679 (51.3)	35,501 (5.7)	3,53,180 (57.1)
1992-93 (बजट अनुमान)	1,88,019 (26.9)	61,790 (8.8)	78,663 (11.2)	27,301 (3.9)	3,55,773 (50.8)	39,565 (5.7)	3,95,338 (56.5)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट प्रलेख।

परिशिष्ट सारणी 3.5 : बजट घाटा, बाजार ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार को सहायता

(करोड़ रुपये)

मदें	1990-91 (लेखा)	1991-92 (व. अ.)	1991-92 (सं. अ.)	1992-93 (व. अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व लेखा				
i) प्राप्तियां (₹)	57,650	70,870	70,114	79,648
ii) व्यय (₹)	76,212	84,724	87,195	93,530
iii) अधिशेष (+)/घाटा (-)	-18,562	-13,854	-17,081	-13,882
2. पूंजीगत लेखा				
i) प्राप्तियां	39,915	38,174	39,521	38,016
ii) संवितरण	31,800	32,039	29,472	29,517
iii) अधिशेष (+)/घाटा (-)	+7,215	+6,135	+10,049	+8,493
3. कुल प्राप्तियां [1 (i) + 2 (i)]	96,665	1,09,044	1,09,635	1,17,663
4. कुल व्यय [1 (ii) + 2 (ii)]	1,08,012	1,16,763	1,16,667	1,23,047
5. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	-11,347	-7,719	-7,032	-5,384
6. (5) के प्रतिशत के रूप में (4)	-10.5	-6.6	-6.0	-4.4
7. निवल बाजार ऋण*	8,201 (8.988)	7,500 (3,918)	7,500 (8,919)	5,000 (5.151)
8. (3) के प्रतिशत के रूप में (7)	8.3	6.9	6.8	4.2
9. भारतीय रिजर्व बैंक को सजाना जिलों से भिन्न सरकारी रुपया प्रतिभूति संबंधी धारिताओं में वृद्धि (+)/गिरावट (-) (₹)	+3,481		-295	
10. केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वृद्धि (+)/गिरावट (-) (₹)	+14,745	+2,719	+8,000	+5,300

क- इसमें वाणिज्यिक विभाग शामिल हैं।

ख- भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार यहाँ भूयः आधार पर।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान तदर्थ सजाना जिलों के वित्तपोषण के लिए दो वर्षों कायदा 30,000 करोड़ रुपये और 5,000 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं।

ग- केन्द्र सरकार के बजट में दिये गये आगमन मद के अनुसार।

*कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सकल बाजार ऋणों को दर्शाते हैं।

व. अ. = बजट अनुमान सं. अ. = संशोधित अनुमान

परिशिष्ट सारणी 3.6 : छाटे के माध्यम से राज्यों का मुद्रांकृत, बजट, राष्ट्रपति, सकल और निवल राजकोषीय ऋण

(करोड़ रुपये)

	वर्ष राजकोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	मुद्रांकृत घाटा*	प्रत्यक्ष ऋण	राजस्व घाटा	सकल परिस्रुत अनुदान के रूप में वसूल राजस्व घाटा @
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3,712	1,714	487	897	+1,486	2.7
1981-82	4,062	2,209	789	1,020	+1,379	2.5
1982-83	4,986	2,830	+860	+820	+888	2.8
1983-84	6,359	4,067	38	561	+211	3.1
1984-85	8,199	5,834	1,436	1,438	924	3.5
1985-86	7,520	4,799	+1,862	+1,688	+654	2.9
1986-87	9,269	6,107	516	667	+169	3.2
1987-88	11,919	7,742	+157	66	1,038	3.4
1988-89	11,672	8,884	425	+330	1,897	3.0
1989-90	15,433	11,645	255	161	3,682	3.4
1990-91	18,815	14,559	+420	+70	5,335	3.6
1991-92 स.म.	20,219	15,427	340	1,667	5,344	3.3
1992-93 व.म.	20,968	14,997	ला.न.	98	3,669	3.0

* आकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले 23 राज्यों से संबंधित हैं।

+ अधिरोप दर्शाते हैं।

व.प्र. = वसूल अनुमान

(2) सकल देशी उत्पाद वस्तु बाजार मूल्यों पर

सं.प्र. = वित्तिय अनुमान

परिशिष्ट सारणी 3.7 : राज्यों के सकल राजकोषीय ऋणों का विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र सरकार से ऋण	बाजार से उधार	अन्य	सकल राजकोषीय	राज्यों की बाहरी देयताएं (वर्ष की समाप्ति पर)		
	(निवल)	(निवल)		घाटा (2+3+4)	कुल	केन्द्र सरकार से ऋण और अधिम@	बाजार से ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,564 (42.1)	184 (5.0)	1,964 (52.9)	3,712 (100.0)	23,977	17,071	2,973
1981-82	2,000 (49.2)	339 (8.3)	1,723 (42.5)	4,062 (100.0)	27,729	19,080	3,323
1982-83	2,735 (54.9)	390 (7.9)	1,858 (37.2)	4,986 (100.0)	29,457	20,425@	3,735
1983-84	3,031 (47.7)	563 (8.9)	2,765 (43.4)	6,359 (100.0)	38,493	27,539@	4,408
1984-85	3,589 (43.7)	693 (8.5)	3,926 (47.8)	8,199 (100.0)	44,334	31,226	5,100
1985-86	5,757 (76.0)	1,010 (13.4)	753 (10.0)	7,520 (100.0)	52,471	38,692@	6,104
1986-87	4,780 (51.6)	1,147 (12.4)	3,336 (36.0)	9,269 (100.0)	59,273	43,463	7,251

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1987-88	5,832 (52.0)	1,523 (13.6)	3,864 (34.4)	11,219 (100.0)	68,523	49,300	8,773
1988-89	6,888 (57.3)	1,973 (16.9)	3,011 (25.8)	11,672 (100.0)	79,496	55,985	10,706
1989-90	7,917 (51.2)	2,298 (14.9)	5,218 (33.8)	15,433 (100.0)	92,300	63,903	12,913
1990-91	9,950 (52.9)	2,184 (11.6)	6,681 (35.5)	18,815 (100.0)	1,08,236	73,852	13,097
1991-92 (सं. प्र.)	9,709 (48.0)	2,874 (14.2)	6,636 (37.8)	20,219 (100.0)	1,24,307	83,562	17,971
1992-93 (व. प्र.)	1,20,69 (57.6)	2,940 (14.0)	5,959 (28.4)	20,968 (100.0)	1,43,348	95,630	20,911

सं.प्र. = संशोधित अनुमान

व.प्र. = बजट अनुमान

(a) केन्द्र द्वारा राज्यों को उनके ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए 1982-83, 1983-84, 1985-86 में दिये गये क्रमशः 1,743 करोड़ रुपये 400 करोड़ रुपये और 1,628 करोड़ रुपये के मन्दावधि ऋण प्राप्ति हैं।

\$ इसमें अन्य प्रांतिक ऋण, ऋण बचत, भविष्य निधि आदि प्रायश्चित्त निधियाँ, जमा राशियाँ और प्राप्ति, आकस्मिकता निधि सहित उच्च और विविध लेखों में रखी गयी राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 3.9 : केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्राप्ति और संवितरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1990-91 (लेखा)	1991-92 (व.प्र.)	1991-92 (सं.प्र.)	1992-93* (व.प्र.)	निम्नलिखित में प्रतिशत वट-वट	
					स्तम्भ 2 की सुचना में स्तम्भ 4	स्तम्भ 4 के सुचना में स्तम्भ 5
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्ति	1,55,606	1,78,093	1,80,665	1,98,617	16.1	9.9
प्र. राजस्व प्राप्ति	1,05,752	1,27,971	1,27,078	1,44,720	20.2	13.9
कर प्राप्ति (क+ख)	87,561	1,03,882	1,01,939	1,16,264	16.4	14.1
(क) प्रत्यक्ष कर	14,268	18,114	18,589	21,325	30.3	14.7
(ख) अप्रत्यक्ष कर	73,293	85,768	83,350	94,939	13.7	13.9
प्र. पूँजीगत प्राप्ति	49,854	50,112	53,587	53,897	7.5	0.6
II. कुल संवितरण (स+प्र+इ)	1,66,883	1,87,006	1,80,364	2,04,104	13.5	7.6
व. विकास संबंधी व्यय (क+ख+ग)	98,151	1,05,747	1,08,488	1,11,027	10.5	2.8
(क) राजस्व	70,750	76,607	80,236	82,093	13.4	2.3
(ख) पूँजीगत परिधाय	16,366	17,647	16,355	17,975	0.1	9.9
(ग) ऋण और अधिम	11,035	11,493	11,895	10,959	7.8	7.9
प्र. विकासोत्तर व्यय (क+ख+ग)	63,973	74,440	74,025	83,541	15.7	15.6
(क) राजस्व	58,114	68,313	68,337	79,199	17.6	15.9
(ख) पूँजी	5,006	5,755	5,272	5,910	5.3	12.1
(ग) ऋण और अधिम	853	372	416	432	51.2	3.8
(इ) अन्य	4,759	6,819	6,853	7,537	44.0	10.0
III. समग्र अधिशेष (+)/वाटा (-)	-11,277	-8,913	-8,699	-5,487		

व.प्र. = बजट अनुमान

सं.प्र. = संशोधित अनुमान

टिप्पणी (1) जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, वे आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 9 देशी अनुदान बजट से हैं।

(2) अन्य वितरणों में प्रांतिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की मुआवजा और समानुपात, आकस्मिक निधियों में विनियोजन एवं निष्पक्ष प्रेषण शामिल हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजट में उल्लेखित राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की ऋणों के चुकौती संबंधी आंकड़ों में भिन्नता के लिए समायोजित किया गया है।

परिचित्त सारणी III-9 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासोन्मुख व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र सरकार				राज्य सरकारें				केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति			
	विकास संबंधी व्यय		कुल	विकास संबंधी व्यय	विकास संबंधी व्यय		कुल	विकास संबंधी व्यय		कुल	विकास संबंधी व्यय	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)	
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)	
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.3)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,931 (3.7)	52,057 (100.0)	
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)	
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,448 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.4)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)	
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)	
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.3)	61,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	1,01,602 (100.0)	
1987-88	36,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,614 (2.3)	1,11,161 (100.0)	
1988-89	41,536 (53.9)	35,579 (46.1)	77,055 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (23.4)	4,599 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (61.6)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,245 (100.0)	
1989-90	54,204 (56.9)	41,020 (43.1)	95,224 (100.0)	53,150 (69.2)	19,253 (25.1)	4,406 (5.7)	76,809 (100.0)	89,386 (60.5)	54,300 (36.8)	3,939 (2.7)	1,47,625 (100.0)	
1990-91	+ 59,645 (54.3)	49,367 (45.7)	1,08,012 (100.0)	62,831 (68.8)	23,162 (25.4)	5,295 (5.8)	91,288 (100.0)	98,151 (58.8)	63,973 (38.3)	4,759 (2.9)	1,66,883 (100.0)	
1991-92 (RE)	+ 61,795 (53.0)	54,872 (47.0)	1,16,667 (100.0)	72,745 (68.6)	28,133 (26.6)	5,107 (4.8)	1,05,985 (100.0)	1,08,486 (57.3)	74,025 (39.1)	6,853 (3.6)	1,89,364 (100.0)	
1992-93 (BE)	+ 61,138 (49.7)	61,909 (50.3)	1,23,047 (100.0)	76,706 (65.8)	33,912 (29.1)	5,944 (5.1)	1,16,562 (100.0)	1,11,027 (54.4)	85,541 (41.9)	7,536 (3.7)	2,04,104 (100.0)	

आंतरिक और विदेशी ऋणों की चुकौती शामिल नहीं है। @इसमें आंतरिक ऋणों की चुकौती, केन्द्र को ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुद्रावृद्धा और समनुवृद्धा, आर्कस्मिक निधि के लिए विनियोजित, राज्य सरकारों के निवन प्रेरण शामिल है।

58 इसमें आंतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार को ऋणों की चुकौती संबंधी आकड़ों में मिलाता के लिए समायोजित किया गया है।

+ जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, वे आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं, जिनमें से 9 लेखा समुदाय बजट से हैं।

टिप्पणी-1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित कुल व्यय में प्रतिशत व्यय दर्शाते हैं।

2. अंतर सरकार समायोजनों के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के आंकड़ों का जोड़ संयुक्त स्थिति से भेज नहीं जाता है।

3. 1989-90 से पूर्व केन्द्र सरकार के व्यय संबंधी आंकड़ों ने स्लेट पर किये गये पुनर्गठन व्यय तथा श्रद्धा व्यय समायोजनों पर राज्यों को दिये गये ऋणों को हिसाब में नहीं लिखा गया है।

प्रशिष्ट तालिका 310: केन्द्र और राज्य सरकारों के व्यय और परियोजना व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	(केन्द्र (सरकार))			राज्य +			केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,533	16,171	19,784
(क)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(ख)	2.1	7.6	9.7	0.5	1.4	4.9	2.7	11.9	14.6
1984-85	1,636	13,802	23,428	1,240	11,108	12,348	5,855	29,910	33,766
(क)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.1	83.6	100.0
(ख)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,982
(क)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
(ख)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,231	26,559	32,793	1,685	14,944	16,619	7,919	41,493	49,412
(क)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(ख)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	11.1	16.3
1987-88	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	43,299	57,010
(क)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(ख)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1
1988-89	8,824	35,596	44,420	2,413	19,983	22,401	11,237	56,534	66,821
(क)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(ख)	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	11.1	16.9
1989-90	10,003	41,588	51,581	3,006	22,983	23,995	13,099	64,567	77,576
(क)	19.4	80.6	100.0	11.0	88.4	100.0	16.8	83.2	100.0
(ख)	2.2	9.2	11.4	0.7	5.1	5.8	2.9	14.3	17.2
1990-91*	11,024	46,489	57,513	3,244	26,804	30,048	14,268	73,293	87,361
(क)	19.2	80.8	100.0	10.8	89.2	100.0	16.3	83.8	100.0
(ख)	2.2	8.8	10.9	0.6	5.1	5.7	2.7	13.8	16.6
1991-92 (संग्रह)*	15,000	52,205	67,205	3,589	31,145	34,734	15,589	83,359	101,939
(क)	22.3	77.7	100.0	12.3	89.7	100.0	18.2	81.8	100.0
(ख)	2.4	8.4	10.9	0.5	5.1	5.6	3.0	13.5	16.5
1992-93 (व्यय)**	17,153	59,295	76,448	4,172	35,614	39,816	21,325	91,939	116,264
(क)	22.4	77.6	100.0	10.5	89.5	100.0	18.3	81.7	100.0
(ख)	2.5	8.5	10.9	0.6	5.1	5.7	3.0	13.6	16.6

+ इसमें केन्द्रीय बजट प्रलेखों में सूचित करों में राज्यों के अंश को शामिल नहीं किया गया है।

* राज्य सरकारों के संबंध में आकर 25 राज्यों से संबंधित है जिनमें से 9 तेजा अनुदान बजट से हैं।

व्यय = बजट अनुमान

संग्रह = संगोहित अनुमान

(क) कुल और राज्यों में प्रतिशत अनुपात दर्शाता है।

(ख) राज्यों के प्रतिशत अनुपात को तुलना में प्रतिशत दर्शाता है।

परिशिष्ट 3.11 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लाने द्वारा प्रायोजित व्यापक लाभकरण एवं संस्थाओं से प्राप्त मुद्रा

(रुपये करोड़)

सरकार/प्राधिकरण	सकल बाजार उधार		कुसौधियां (कुल परिपक्वता)		निष्पन्न बाजार उधार	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
	1	2	3	4	5	6
1. केन्द्र सरकार	8,989	8,919	988	1,418	8,001	7,501
2. राज्य सरकार	2,569	3,364	—	—	2,569	3,364
3. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	2,442	2,702	14	14	2,429	2,688
4. राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं (इसमें स्थानीय प्राधिकरण तथा राज्य भूमि विकास बैंक शामिल हैं)	1,194	1,203	96	104	1,098	1,099
5. कुल बाजार उधार	15,194	16,188	1,098	1,536	14,097	14,652

*भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी 3.12: केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर कृप्य करें
साज करें

(प्रतिशत वार्षिक)

वर्ष	परिपक्वता	5	6	7	8	9 से	14 से	16	19 से	22 और	28	29 से	राज्य सरकार		
	अवधि वर्षों में					10	15		20	23		30	13	15	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1984-85	7.75	8.00			8.50			9.50		10.25	10.50		9.00		
1985-86	9.00		9.25		9.50			10.50	10.89		11.50	9.75			
1986-87	10.00		10.20		10.50		11.30	11.50					11.00		
1987-88					10.50	11.00		11.50					11.00		
1988-89	10.00			10.30	10.50	11.00		11.50							11.50
1989-90					10.50	11.00		11.50							11.50
1990-91	10.50				10.75	11.25		11.50							11.50
1991-92 (क)	10.50				10.75	11.25		11.50							11.50
(ख)	10.75				11.00	11.50		12.00							12.00
(ग)							12.50								
1992-93	12.00(घ)				12.75(ङ)								13.00		

(क) वित्तमंत्री द्वारा पर अधिकतम आय

+ 3 अवतार, 1991 को कृप्य कर को बढ़ा कर 12.00 प्रतिशत कर दिया गया।

(ख) I और II श्रेणियां

(घ) III, IV एवं V श्रेणियां

(ग) VI श्रेणियां

परिशिष्ट सारणी 4.1: मुद्रा स्टॉक (एम 3) में वृद्धि

(रुपये करोड़)

मई	31 मार्च, 1992 को अवधि*	1990-91	निम्नलिखित के दौरान वृद्धि**							
			1991-92*		1992-93*		1991-92*		1991-92*	
			समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. एम3 (क + ख + ग)	3,15,084	3,4,878	15.1	49,256	18.5	18,343	5.8	12,535	4.7	
(क) जनता के पास चल मुद्रा	61,232	6,718	11.6	8,184	15.4	2,719	4.4	3,737	7.0	
(ख) बैंकों के पास कुल जमा राशि (i + ii)	2,52,956	28,054	15.2	40,850	19.3	10,541	4.2	8,064	3.8	
जिसमें से बाह्य अभिराजिया (1 + 2) 88	28,273	4,777	26.7	5,606	21.7	3,909	13.8	20.1	6.9	
1. सभी विदेशी चल मुद्रा जमा राशियां	20,439	4,088	35.4	4,812	30.8	3,427	16.8	-35	-0.2	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. अनिवार्य विदेशी जमाराशियां	7,834	689	10.8	794	11.3	482	6.2	238	3.4	
(i) मांग जमा राशियां	51,983	5,008	14.7	12,813	32.7	44	0.1	1,796	4.6	
(ii) मीयादी जमा राशियां	2,00,973	23,046	15.4	28,037	16.2	10,400	5.2	6,268	3.6	
(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास "अन्य-जमाराशियां"	896	76	12.7	222	32.9	4,990	536.9	734	108.9	
II. एम 1 (क+ख (i)+ग)	1,14,111	11,832	14.6	21,219	22.8	7,753	6.8	6,267	6.7	
III. मुद्रा स्टॉक के स्त्रोत (एम 3) (1+2+3+4+5)										
1. सरकार को निवल ऋण (अ+आ)	1,58,294	23,042	19.7	18,101	12.9	6,391	4.0	10,445	7.5	
अ. सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण (i+ii) ≠	94,016	13,165	20.6	5,168	5.8	2,320	2.5	7,081	8.0	
(i) केन्द्रीय सरकार पर निवल ऋण (क-ख)	92,266	14,745	20.5	5,508	6.3	3,013	4.2	9,170	10.6	
(क) केन्द्रीय सरकार पर ऋण	94,348	15,086	20.6	5,904	6.7	1,906	2.0	7,589	8.6	
(ख) केन्द्रीय सरकार की जमाराशियां	2,082	341	25.4	396	23.5	-2,007	-96.4	-1,581	-93.8	
(ii) राज्य सरकारों पर निवल ऋण (क-ख)	1,750	420	25.1	-340	-16.3	-1,593	-90.1	-2,089	-100.0	
(क) राज्य सरकारों पर ऋण	1,750	420	25.1	-340	-16.3	-1,577	-90.1	-2,073	-99.2	
(ख) राज्य सरकारों की जमाराशियां	—	—	—	—	—	16	@@	16	@@	
(आ) सरकार को अन्य बैंकों के ऋण	64,278	7,877	18.1	12,933	25.2	4,071	6.3	3,364	6.6	
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (अ+आ)	1,91,065	20,065	13.2	19,296	11.2	8,493	4.4	89	0.1	
(अ) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण @	7,260	-7	-0.1	918	14.5	93	1.3	-850	-13.4	
(आ) वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्य बैंकों का ऋण	1,83,805	20,072	13.8	18,378	11.1	8,400	4.6	939	0.6	
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ+आ) \$	19,527	1,954	27.2	10,855	125.2	849	4.3	-1,225	-14.1	
(अ) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	19,838	1,915	31.6	10,855	130.0	819	4.5	-1,225	-15.3	
(आ) अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	689	-61	-8.1	
4. जनता के प्रति सरकार की चल-मुद्रा देयताएं	1,696	66	4.2	75	4.6	22	1.1	
मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्देतर देयताएं (अ+आ)	55,498	10,149	21.9	-929	-1.6	-2,510	-4.5	-3,204	-5.7	
(अ) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयताएं \$	27,403	9,486	51.1	381	1.4	-2,195	-8.0	257	1	
(आ) अन्य बैंकों की निवल मुद्देतर देयताएं (अवशिष्ट)	995	-663	2.3	-1,310	-4.5	-315	-1.1	3,461	-11.8	

**प्रारंभिक आंकड़े रिजर्व बैंक के संबंध में 31 मार्च तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।

विशेष टिप्पणी: अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के ऊपर हैं। @, 1, 2, 3 के स्थापना से बैंकों को उसका पुनर्निर्धारित नहीं।

\$ 17 अक्टूबर 1990 में प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग अनुपात पुनर्मूल्य के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है। ऐसे अधिमूल्य का रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयताओं पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ऐसे पुनर्मूल्य के निवल को दर्शाते हैं।

आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

टिप्पणी: पुनर्निर्धारित किये जाने के कारण घटक मदों को कुछ जोड़ से मेल खाता नहीं है।

परिशिष्ट सारणी 4.2 : प्रारक्षित मुद्रा में घट-बढ़-घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मदें	31 मार्च 1992 को बकाया*	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ \$			
		1990-91	1991-92*	1992-93* (अप्रैल- जून)	1991-92* (अप्रैल- जून)
1	2	3	4	5	6
प्रारक्षित मुद्रा (1 + 2 + 3 + 4)	99,509	10,188 (13.1)	11,730 (13.4)	6,027 (6.1)	4,725 (5.4)
1. जनता के पास चल मुद्रा	61,232	6,748 (14.6)	8,184 (15.4)	2,719 (4.4)	3,737 (7.0)
2. भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियाँ	896	76 (12.7)	222 (32.9)	4,990 (556.9)	734 (108.9)
3. बैंकों के पास नकदी	2,499	248 (12.5)	265 (11.9)	317 (12.7)	482 (21.6)
4. भा० रि० बैं० के पास बैंकों की जमा राशियाँ	34,882	3,116 (10.9)	3,059 (9.6)	-1,999 (-5.7)	-228 (-0.7)
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)					
1. सरकार की भा० रि० बैं० का निवल ऋण ≠	94,016	15,165 (20.6)	5,168 (5.8)	2,320 (2.5)	7,081 (8.0)
2. वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर भा० रि० बैं० के दावे @	5,102	2,535 (33.9)	-4,905 (-49.0)	570 (11.2)	-46 (-0.5)
3. वाणिज्यिक क्षेत्र को भा० रि० बैं० का ऋण	7260	-7 (-0.1)	918 (14.5)	44 93 (1.3)	-850 (-13.4)
4. भा० रि० बैं० की निवल विदेशी मुद्रा आप्तियाँ	18,838	1,915** (-4.633) @ @	10,855** (9,141) @ @	849** (1,049) @ @	1,225** (-1,807) @ @
		(31.6) (-76.4)	(136.0) (114.5)	(4.5) (5.6)	(15.3) (-22.6)
5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	1,696	66 (4.2)	75 (4.6)	-- (--)	22 (1.4)
6. भा० रि० बैं० की निवल मुद्रा देयताएं	27,403	9,4861** (54.1)	381** (1.4)	-2,195** (-8.0)	257** (1.0)
भा० रि० बैं० की निवल देशी आप्तियाँ	80,671	8,273	875	5,178	5,950

*अनंतिम

\$-31 मार्च से संबंधित आंकड़ों पर आधारित

@ नाबार्ड सहित

≠-विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं

** 17 अक्टूबर 1990 से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आसपास पुनर्मूल्यन के बाद स्थिति के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है। ऐसे अधिमूल्यन का रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताओं पर तदनुसंग प्रभाव पड़ता है।

@ @ स्वर्ण पुनर्मूल्यन की छोड़कर

टिप्पणी: कोष्ठकों में विवेक आंकड़े प्रतिगत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

1517 GI/93-17

परिशिष्ट सारणी IV.3 : चल मुद्रा के अनुपात के रूप में बालू बाजार मूल्यों पर भाय (सकल घरेलू उत्पाद) कुल जमाराशि, एम 1 और एम 3 की प्रवृत्तियाँ

	औसत* (करोड़ रुपये)				भाय बेग अनुपात			
	चल मुद्रा	कुल जमाराशियाँ	एम 1	एम 3	सकल घरेलू उत्पाद/चल मुद्रा	सकल घरेलू उत्पाद/सकल जमाराशि	सकल घरेलू उत्पाद/एम 1	सकल घरेलू उत्पाद/एम 3
	वर्ष 1	2	3	4	5	6	7	8
1986-77	27,062	1,03,620	47,009	1,30,938	10,789	2,818	6,211	2,230
1987-88	31,490	1,21,744	53,039	1,53,546	10,563	2,732	6,155	2,166
1988-89	35,934	1,43,556	61,877	1,79,884	10,992	2,751	6,384	2,196
1989-90	42,678	1,70,554	74,370	2,13,807	10,558	2,642	6,059	2,108
1990-91	50,046	1,98,066	87,375	2,49,282	10,581	2,674	6,061	2,124
1991-92-	57,661	2,32,092	1,04,121	2,91,130	10,735	2,667	5,945	2,126

*वर्ष के रिपोर्टिंग शुक्रवार के औसत

@अनंतिम

परिशिष्ट सारणी IV . 4 : मीट्रिक अनुपात

मर्दे	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92@
1	2	3	4	5	6	7
बिन्दुवार आधार पर						
(वृद्धिशील अनुपात)						
(क) चलमुद्रा/कुल जमाराशि (सी/एडी)	0.176	0.298	0.198	0.269	0.241	0.200
(ख) चलमुद्रा/एम 3 (सी/एम 3)	0.149	0.229	0.163	0.213	0.193	0.166
(ग) कुल जमाराशि/एम 3 (एडी/एम 3)	0.850	0.767	0.827	0.790	0.804	0.829
(घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम 3/घारएम)	3.348	2.608	3.086	2.560	3.423	4.199
(ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम 1/घारएम)	1.117	0.811	0.869	0.975	1.161	1.809
(च) बैंक की धारक्षित निधि/कुल जमाराशि (घार/एडी)	0.175	0.197	0.182	0.228	0.012	0.081
औसत आधार						
(वृद्धिशील अनुपात)						
(क) चलमुद्रा/कुल जमाराशियाँ (सी/एडी)	0.178	0.244	0.204	0.250	0.268	0.224
(ख) चलमुद्रा/एम 3 (सी/एम 3)	0.151	0.196	0.169	0.199	0.208	0.182
(ग) कुल जमाराशियाँ/एम 3 (एडी/एम 3)	0.848	0.802	0.828	0.796	0.776	0.813
(घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम 3/घारएम)	3.163	2.482	3.127	3.159	3.026	3.353
(ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम 1/घारएम)	0.978	0.772	0.930	1.163	1.109	1.342
(च) बैंक की धारक्षित निधि/कुल जमाराशि (घार/एडी)	0.194	0.255	0.179	0.138	0.116	0.175

@ अनंतिम

टिप्पणी :

- बिन्दुवार आधार पर, अनुपात 31 मार्च के आंकड़ों पर आधारित , जबकि औसत आधार पर, अनुपात, वर्ष के रिपोर्टिंग शुक्रवार के औसत के आधार पर निकाले गये हैं। इस सारणी में दिये गये सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात हैं।
- बिन्दुवार आधार पर यहाँ दर्शाये गये अनुपात पूर्व रिपोर्टों में दिये गये अनुपातों से भिन्न हैं, क्योंकि उनका आधार मार्च का अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार था।

परिशिष्ट सारणी IV. 5 महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेत अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(कराड़ रुपये में)

संदे	निम्नलिखित वित्त वर्ष में घट-बढ़					
	20 मार्च 1992 को बकाया	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93*	1991-92 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल मांग और सीमादा देयताएं (भारिबैं/भाजाबिबैं/गाबाबैं से उधार को छोड़कर)	2,51,795	29,208	26,241	39,709	14,791	6,591
2. कुल जमाराशियां (क + ख)	2,30,758	26,809 (19.1)	25,583 (15.3)	38,216 (19.8)	10,438 (4.5)	6,566 (3.4)
(क) मांग जमाराशियां	45,088	5,514 (13.6)	4,337 (15.0)	11,895 (35.8)	124 (0.5)	1,238 (3.7)
(ख) सीमादा जमाराशियां	1,85,670	21,295 (18.2)	21,246 (15.4)	26,321 (16.5)	10,314 (5.6)	5,328 (3.3)
3. भारिबैं से उधार	577	-1,128 (-32.0)	1,069 (44.6)	-2,891 (-83.4)	1,039 (180.1)	2,636 (78.0)
4. बैंक ऋण (क + ख)	1,25,592	16,734 (19.8)	14,848 (14.6)	9,291 (8.0)	8,166 (6.5)	960 (0.8)
(क) खाद्य ऋण	4,670	1,237 (169.9)	25,00 (124.6)	164 (3.6)	431 (9.2)	811 (18.0)
(ख) खाद्योत्तर ऋण	1,20,922	15,497 (18.5)	12,348 (12.4)	9,127 (8.2)	7,735 (6.4)	150 (0.1)
5. निवेश (क + ख)	90,196	9,707 (17.8)	10,696 (16.6)	15,131 (20.2)	4,025 (4.5)	3,188 (4.2)
(क) सरकारों प्रतिभूतियां	62,727	6,477 (18.1)	7,706 (18.2)	12,729 (25.5)	4,020 (6.4)	3,388 (6.8)
(ख) अन्य अनुसूचित, प्रि. सुविधाएं	27,469	3,230 (17.1)	2,990 (15.5)	2,402 (9.6)	5 (0.0)	-200 (-0.8)
6. ह्रास में नकदी	2,008	204 (14.1)	156 (9.5)	204 (11.3)	316 (15.7)	325 (18.0)
7. भारिबैं के पास शेष जमा	34,179	2,087 (9.8)	398 (1.7)	10,318 (43.2)	-2,227 (-6.5)	6,929 (29.0)
8. ऋण जमा अनुपात (%) @	54.4	60.8	60.4	54.4	55.5	58.9
9. खाद्योत्तर ऋण जमा अनुपात (%)	52.4	59.6	58.1	52.4	53.3	58.2

*अंतिम

टिप्पणी: 1. कंठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ का दर्शाते हैं।

2. आंकड़ों का पूर्णकृत किया जाने के कारण वृत्त मदों के योग कुल जोड़ से मेल नहीं खायेगे।

3. धनात्मक बढ़त के लिए कोई विवरण नहीं दिया गया है।

@ संबंधित अंतिम सूचित शुक्रवार को बकाया से संबंधित अनुसार।

परिशिष्ट सारणी IV. 6: मार्च 1991 और 1992 के अंतिम सप्ताह की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चुनिंदा मदों में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

मदें	मार्च, 1991 के अंतिम सप्ताह के दौरान घट-बढ़										मार्च, 1992 के अंतिम सप्ताह में घट-बढ़			
	23 मार्च 1990	22 मार्च 1991	29 मार्च 1991	22 मार्च 1991	31 मार्च 1991*	5 अप्रैल 1991*	22 मार्च 1991	20 मार्च 1992	27 मार्च 1992	20 मार्च 1992	31 मार्च 1992*	31 मार्च 1992	31 मार्च 1992*	31 मार्च 1992
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. कुल जमा राशियाँ (क + ख)	25,583 (15.3)	8,657 (4.5)	3,575 (1.8)	12,232 (6.4)	-6,705 (-3.3)	-2,090 (1.1)	38,216 (19.8)	6,808 (3.0)	45,021 (1.9)	1,310 (4.9)	-7,824 (-3.2)	985 (0.4)		
(क) मांग जमा राशियाँ	4,337 (15.0)	5,107 (15.4)	2,222 (5.8)	7,329 (22.1)	-5,268 (13.0)	-1,409 (-4.0)	11,895 (35.8)	3,805 (8.4)	2,847 (5.8)	6,652 (14.8)	-6,136 (-11.9)	983 (2.2)		
(ख) सावधि जमा राशियाँ	21,246 (15.4)	3,550 (2.2)	1,353 (0.8)	4,903 (3.1)	-1,437 (-0.9)	-681 (-0.4)	26,321 (16.5)	3,002 (1.6)	1,656 (0.9)	4,658 (2.5)	-1,688 (-0.9)	2 (0.0)		
2. बैंक ऋण (क + ख)	14,848 (14.6)	5,564 (4.8)	1,570 (1.3)	7,134 (6.1)	-5,059 (-4.1)	19 (0.0)	9,291 (8.0)	5,928 (4.7)	4,079 (3.1)	10,007 (8.0)	-6,171 (-4.6)	1,68 (1.3)		
(क) खाद्य ऋण	2,500 (124.6)	63 (1.4)	0 (0.0)	63 (1.4)	-128 (-2.8)	-50 (-1.1)	164 (3.6)	-62 (-1.3)	236 (5.1)	174 (3.7)	-266 (-5.5)	-71 (-1.6)		
(ख) खाद्येतर ऋण	12,348 (12.4)	5,501 (4.9)	1,570 (1.3)	7,071 (6.3)	-4,931 (-4.1)	69 (0.1)	9,127 (8.2)	5,990 (5.0)	3,843 (3.0)	6,833 (8.1)	-5,905 (-4.5)	1,758 (1.4)		

*अंतिम

टिप्पणी : 1. लघु कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. चौकोर कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वित्त वर्ष के घट-बढ़ के प्रतिशत के रूप में पूर्ण घट-बढ़ दर्शाते हैं।

3. घनात्मक बड़त के लिए कोई चिह्न नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.7 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-जमा-संसाधन

(करोड़ रुपये)

मार्च	निम्नलिखित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया			घट-बढ़	
	1990	1991	1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1. कुल जमा राशियाँ	166,959	192,542	230,758	25,383 (15.3)	38,216 (19.8)
2. सकल मांग और मीमांसा देयताएँ	185,845	212,086	251,795	26,241 (14.1)	39,709 (18.7)
3. बैंकिंग तंत्र के पास आस्तियाँ	5,444	5,582	7,927	138 (2.5)	2,345 (42.0)
4. अंतर बैंक आस्तियों से इतर सकल मांग और मीमांसा देयताएँ (2-3)	180,401	206,504	243,868	26,103 (14.5)	37,364 (18.1)
5. अंतर (4-1)	13,442	13,962	15,110	520 (3.9)	-852 (-6.1)
6. अन्य उधार	1,055	470	362	-585 (55.5)	-108 (-23.0)
7. वित्तीय संस्थाओं के साथ बिल पुनः मुनाई	3,934	3,479	3,306	-455 (-11.6)	-173 (-5.0)
8. गैर जमा संसाधन (5+7)	17,376	17,441	16,416	65 (0.4)	-1025 (-5.9)
स्थापन मद					
भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह से मांग मुद्रा उधार*	2,600	2,275	1,212	-325 (-12.5)	-1063 (-46.7)

*भारतीय आद्योगिक विकास बैंक, नाबाई और 'अन्य' से लिए गए उधार सहित मार्च 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह के उधार संबंधी प्रांकड़े शामिल हैं।

विषयणी कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े प्रतिशत में घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.8 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	23 मार्च 1990	22 मार्च 1991	20 मार्च 1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
(I) सकल बैंक ऋण (1+2)	1,02,671	1,18,019	1,26,006	15,348	7,987
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	2,006	4,506	4,670	2500	164
2. खाद्योत्तर सकल बैंक ऋण	1,00,665	1,13,513	1,21,336	12,848 (100.0)	7,823 (100.0)
(घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	40,383 [42.4]	42,915 [39.3]	45,469 [38.5]	2,532 (19.7)	2,554 (32.6)

(1) कृषि	16,526 [17.4]	16,750 [15.3]	18,187 [15.4]	224 (1.7)	1,437 (18.3)
(2) लघु उद्योग	15,543	17,181	18,158	1,638 (12.8)	977 (12.5)
(3) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8,314	8,984	9,124	670 (5.2)	140 (1.8)
(भा) उद्योग (मशीनें और बढ़)	38,262	44,508	47,330	6,246 (48.6)	2,822 (36.1)
(इ) थोक व्यापार (खाद्यान्न बसूली से इतर)	5,472	5,910	6,194	438 (3.4)	284 (3.6)
(i) भारतीय रुई निगम	140	91	208	-49 (-0.4)	117 (1.5)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्बरक वितरण के लिए)	230	212	21	-18 (-0.1)	-191 (-2.4)
(iii) भारतीय जूट निगम	54	62	70	8 (0.1)	8 (0.1)
(iv) अन्य व्यापार	5,048	5,545	5,895	497 (3.8)	350 (4.4)
(ई) अन्य क्षेत्र	16,548	20,180	22,343	3,632 (28.3)	2,163 (27.7)
(II) निर्यात ऋण (मद 1(2) के अन्तर्गत शामिल)	8,245	9,186	10,261	941	1,075
(II) निवल बैंक ऋण (अंतर बैंक सहभागिता सहित)	95,132	1,09,298	1,18,024	14,166	8,726

@अनन्तित

- टिप्पणी : 1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित बाणिज्य बैंकों (जिनके कारण मार्च 1990 से 49 और अगस्त 1990 से 48) से संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को वशति हैं। सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारि.बैं., भा.ओ.वि.बैं., एगिजम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा अन्तर बैंक सहभागिता के साथ पुनः धुनाये गये बिलों को भी शामिल किया गया है। निवल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारि.बैं., भा.ओ.वि.बैं., एगिजम बैंकिंग तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के साथ पुनः धुनाये गये बिलों को शामिल नहीं किया गया है।
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण के समानुपाती हैं।
3. चौकोर कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मद III में दिये गये अंतर-बैंक सहभागिता सहित निवल बैंक ऋण के समानुपाती हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.9: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण@

(करोड़ रुपये)

उद्योग	निम्नलिखित तारीखों को बताया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	23 मार्च 1990	22 मार्च 1991	20 मार्च 1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु, मशीनें और बढ़े उद्योगों का जोड़)	53,805	61,689	65,488	7,884	3,799
1. कोयला	178	229	247	51	18
2. लोहा और इस्पात	2,835	3,292	3,688	457	396
3. अन्य धातु और धातु उत्पाद	1,838	2,227	2,341	389	114
4. सभी इंजीनियरिंग जिसमें से इलेक्ट्रोनिक्स	12,509 (1,290)	13,931 (1,873)	14,915 (2,089)	1,244 (584)	984 (215)

1	2	3	4	5	6
5. बिजली	1,258	1,152	1,294	-106	142
5. सूती वस्त्र	3,659	4,073	4,251	414	178
7. जूट वस्त्र	340	339	332	-1	-7
8. अन्य वस्त्र	3,297	3,761	3,985	464	224
9. चीनी	647	639	900	-8	261
10. चाय	571	608	658	37	50
11. खाद्य-पदार्थों के अभिरांस्करण	1,056	1,216	1,252	160	36
32. बनस्पति तेल (बनस्पति सहित)	700	865	899	165	34
13. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	379	391	552	12	161
14. कागज और कागज उत्पाद	1,346	1,482	1,501	136	19
15. रबर और रबर की वस्तुएं	912	989	1,079	77	90
16. रसायन, रंजक, पेंट आदि उनमें से	6,785	7,743	8,279	958	536
(1) उर्बरक	(1,075)	(1,309)	(1,340)	(234)	(31)
(2) पेट्रो-रसायन	(681)	(680)	(609)	(-1)	(-71)
(3) दवाइयाँ और औषधियाँ	(1,103)	(987)	(1,120)	(-26)	(133)
17. मीमेंट	843	899	982	56	83
18. बमझा और बमझा उत्पाद	931	998	1,087	67	89
19. रत्न और जवाहरात	1,214	1,236	1,294	22	58
20- विनिर्माण	1,091	1,321	1,365	230	44
21. पेट्रोलियम	137	54	19	-83	-35
22. नदी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिए गये जहाज	149	87	68	-62	-19
23. अन्य उद्योग	11,130	14,157	14,500	3,027	343

@अनतिम

परिशिष्ट सारणी IV.10: अनुमूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय सहायता (मीषहम ऋणों, शुल्क वापसी, आदि पर दिये गये विशेष पुनः वित्त को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार	निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आवासी पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1991										
मार्च	4,129.08	2,812.25	--	--	3,225.97	533.97	210.93	--	7,565.98	3,346.22
अप्रैल	4,575.76	4,448.34	--	--	4,987.00	4,655.00	348.03	10.00	9,910.79	9,113.34
मई	5,111.06	3,167.57	--	--	3,065.76	120.00	291.38	37.50	8,468.20	3,325.07
जून	5,222.10	4,467.98	--	--	2,432.02	1,546.33	555.10	--	8,209.22	6,014.31
सितंबर	4,262.28	3,250.50	--	--	1,745.46	--	1,010.03	--	7,017.77	3,250.50
दिसंबर	4,747.33	292.13	--	--	--	--	--	--	4,747.33	292.13
1992										
मार्च	5,594.31	494.87	--	--	--	--	--	--	5,594.31	494.87
अप्रैल	5,746.88	3,694.07	--	--	--	--	--	--	5,746.88	3,694.07
मई	6,841.93	1,619.86	--	--	--	--	--	--	6,841.93	1,619.86
जून	7,163.34	1,531.83	--	--	--	--	--	--	7,163.34	1,531.83
जुलाई	7,655.61	1,562.36	--	--	--	--	--	--	7,655.61	1,562.36

परिशिष्ट सारणी IV . 11 : भारतीय सिटीकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

(करोड़ रुपए)

182 दिवसीय ख़ाता बिलों की जमानत पर पुनर्वित्त		अल्पवधिक वार्षिक गणितीय गिनों की जमानत पर पुनर्वित्त												केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की जमानत पर पुनर्वित्त*	
महीने के अंतिम दिन की	सीमा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तंभ 4 में दशमि बयी अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप सीमा	सीमा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तंभ 8 में दशमि बयी अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप सीमा	सीमा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तंभ 12 में दशमि बयी अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप सीमा	1	2	3
1991															
मार्च	200.00	12-6-81	23.026 (19-3-91)	300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
जून	100.00	भूत	212.17 20-6-91	300.00	700.00	भूत	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
सितंबर	100.00	95.52	98.77 (12-9-91)	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
दिसंबर	100.00	भूत	337.04 (2-12-91)	600.00	50.00	50.00	भूत	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1992															
मार्च	600.00	भूत	580.48 (28-2-92)	600.00	50.00	50.00	भूत	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
जून	100.00	26.55	87.75 (19-5-92)	100.00	200.00	151.20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
जुलाई	100.00	भूत	36.90 (3-7-92)	100.00	100.00	100.00	भूत	146.70	200.00	100.00	भूत	34.20	100.00	100.00	100.00

* 2 अप्रैल 1992 में लागू।

परिशिष्ट सारणी IV-12 : मुद्रा बाजार निचले में भारतीय मित्रीकाटा और बिल गृह का संबंधी प्रभाव

(करोड़ रुपये)

विषय	राष्ट्रकोषीय प्रवधि		1992-93 के दौरान	1991-92 के दौरान
	1990-91	1991-92	(7 अगस्त 1992 तक)	(9 अगस्त 1991 तक)
1	2	3	4	5
1. रॉग निधियां (नोटिस निधियों सहित)	2,02,792	2,96,864	1,67,715	1,13,703
2. खजाना बिल	32,329	23,166	9,834	11,009
3. बाणिज्यिक बिल	12,675	6,872	477	4,301
4. जमा प्रमाणपत्र	8	17	8	8
5. बाणिज्यिक पत्र	107	42	—	42
6. सावधि जमा राशियां	3,532	5,961	987	2,160
7. केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	—	—	3,582	—

परिशिष्ट सारणी IV-13 : भारतीय मित्रीकाटा और बिल गृह को प्रथम रिजर्व बैंक के पुनर्बिल की व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

182 दिवसीय खजाना बिलों के धारिताओं पर पुनर्बिल +		बाणिज्यिक बिलों पर पुनर्बिल		दिनांकित प्रतिभूतियों पर पुनर्बिल	
प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख	व्याज की दर
1	2	3	4	5	6
1991		1991		1992	
		जुलाई	15	अप्रैल	2
जुलाई	8 10.25		16.50		12.00
	9 10.00		16.25		
	13 10.50		18 16.00		
	15 10.75	अगस्त	29 15.75		
	17 10.50		5 15.00		
	18 10.25		7 14.00		
	22 10.00	सितंबर	25 14.00		
अक्टूबर	1 10.25				
	5 11.00	1992			
	7 10.25	अप्रैल	13 15.00		
	9 11.50		25 16.00		
	12 12.50		28 20.00		
	19 10.00	मई	5 17.00		
नवंबर	4 10.00	जुलाई	11 15.00		
	6 10.00				
	11 10.00				
	12 10.00				
	13 10.00				
	18 10.50				
	25 10.50				

दिसंबर	5	10.25
	7	10.00
1992		
मार्च	13	11.00
	21	10.00
	24	11.00
	25	12.50
	27	13.00
अप्रैल	7	12.00
	20	10.00
	30	11.00
मई	5	10.00

† 30 अप्रैल 1992 से ब्याज दर 182 दिवसीय खजाना बिलों सहित दीर्घावधिक परिपक्वता अवधि के खजाना बिलों से संबंधित है।

@ 30 मार्च 1992 से भारत सरकार की बिनाकित प्रतिभूतियों पर भा.मि.वि.गु. को 100 करोड़ रुपये की पुंयक पुनर्वित्त सीमा स्वीकृत की गयी थी।

परिशिष्ट सारणी IV. - 14 भारतीय मित्रीकाया और वित्त गृह को माल मद्रा उधार दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

1990-91					1991-92				
निम्नलिखित को समाप्त पक्षपाते के लिए	उधार दर			निम्नलिखित को समाप्त हुए पक्षपाते के लिए	उधार दर				
	न्यूनतम	अधिकतम	मध्य दर की औसत*		न्यूनतम	अधिकतम	मध्य दर की औसत*		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1990				1991					
जुलाई	13	8.50	13.75	11.45	जुलाई	12	10.25	38.50	23.40
	27	7.50	12.25	10.10		26	5.00	27.00	14.05
अगस्त	10	8.00	11.00	9.50	अगस्त	9	5.00	17.50	12.60
	24	6.00	11.00	9.40		23	9.00	15.00	13.40
सितंबर	7	6.50	15.75	12.25	सितंबर	6	3.50	15.00	10.95
	21	10.00	26.00	16.50		20	3.00	14.50	10.85
अक्तूबर	5	10.00	34.00	22.60	अक्तूबर	4	5.00	50.00	18.60
	19	16.00	60.50	37.20		18	4.00	35.25	19.75
नवंबर	2	9.00	31.00	21.00	नवंबर	1	10.00	24.50	14.90
	16	8.00	28.00	19.35		15	15.00	36.00	23.25
	30	7.50	28.00	16.60		29	3.00	36.00	20.55
दिसंबर	14	4.00	14.00	10.50	दिसंबर	13	2.00	21.00	9.35
	28	7.50	15.00	13.20		27	3.50	16.25	9.60
1991				1992					
जनवरी	11	7.00	15.25	13.40	जनवरी	10	3.25	16.25	9.95
	25	5.00	15.00	11.80		24	4.00	10.75	9.25
फरवरी	8	6.00	14.25	12.65	फरवरी	2.25	10.00	8.40	
	22	8.75	15.75	12.80		3.00	10.00	8.30	

	1	2	3	4		5	6	7 (प्रतिशत में)
मार्च	8	13.75	17.75	16.10	मार्च	4.50	9.75	8.75
	22	7.00	27.75	21.30		2.00	20.25	10.30
अप्रैल	5	5.00	25.00	16.05	अप्रैल	3	6.00	15.00
	19	14.25	46.00	23.75		17	34.00	36.50
मई	3	24.25	45.00	32.25	मई	1	20.00	86.00
	17	20.00	60.50	42.90		15	6.00	51.00
	31	4.50	45.00	29.10		29	3.50	36.00
जून	14	13.50	28.00	23.40	जून	12	4.50	16.50
	28	6.00	38.00	25.15		26	5.00	22.00
				जुलाई		10	3.00	18.50
						24	1.25	16.50
				अगस्त		7	3.50	12.50
						21	3.00	12.50

* यह दैनिक मध्य रात्रि का एक साधारण औसत है ।

परिशिष्ट सारणी IV. 15 : भारत सरकार के 182 विधायी बजाना बिल

मीलामी की तारीख	प्रस्तुत बोलियां		स्वीकृत बोलियां		100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए अधिकतम आय	अधिकतम आय (वार्षिक प्रतिशत)	बकाया बजाना बिलों की कुल राशि (करोड़ रुपये)
	संख्या	कुल	सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	कुल सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)		
	1	2	3	4	5	6	7
1991							
जुलाई	10	23	326.00	9	198.00	95.23	2,287.77
	24	22	444.50	14	275.50	95.23	2,500.57
अगस्त	7	25	1,001.25	10	576.25	95.24	2,801.77
	21	18	660.35	12	623.75	95.25	3,337.52
सितंबर	4	21	188.50	5	60.50	95.26	3,359.72
	18	15	534.80				3,289.47
अक्टूबर	1	13	109.65	11	99.65	95.25	3,192.12
	15	16	283.50	9	238.00	95.25	2,851.12
	30	16	937.83	15	622.70	95.23	3,375.92
नवंबर	13	8	196.67	4	189.67	95.24	3,336.32
	27	6	47.30	4	46.30	95.25	3,225.82
दिसंबर	11	12	57.65	11	56.65	95.23	3,194.97
	24	11	373.25	11	373.25	95.22	3,360.22
1992							
जनवरी	8	26	673.25	23	621.25	95.20	3,783.47
	22	29	1,109.25	7	582.25	95.24	4,090.22
फरवरी	5	44	1,055.35	2	100.00	95.30	3,613.97
	19	73	2,106.25	24	774.00	95.45	3,764.22
मार्च	4	59	1,184.50	2	125.00	95.80	3,828.72
	17	16	196.80	14	156.80	95.75	3,985.52
	31	8	43.70	7	42.70	95.57	3,985.52
अप्रैल	11	25	538.00	13	245.00	95.80	3,935.574
	28	---	---	---	---	---	3,812.87
	---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8
मई	13	--	--	--	--	--	--	3,123.20
	27	--	--	--	--	--	--	3,076.90
जून	9	--	--	--	--	--	--	3,020.25
	24	--	--	--	--	--	--	2,647.00
जुलाई	7	--	--	--	--	--	--	2,025.25
	22	--	--	--	--	--	--	1,443.50
अगस्त	5	--	--	--	--	--	--	1,343.50
	21	--	--	--	--	--	--	589.50

28 अप्रैल के पञ्चाङ्ग से 182 विधायी खजाना बिलों की सीमा सी नहीं हुई।

परिशिष्ट सारणी IV. 16: भारत सरकार के 364 विधायी खजाना बिल

सीमा की सारीख	प्रस्तुत बोलियां		स्वीकृत बोलियां		100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए अधिकतम धाय	अधिकतम धाय (वार्षिक प्रतिफल)	बकाया खजाना बिलों की कुल राशि (करोड़ रुपये)	
	संख्या कुल सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)	संख्या कुल सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1992								
अप्रैल	28	75	1,128.65	53	666.15	89.75	11.42	666.15
मई.	13	57	1,396.48	44	961.48	89.75	11.42	1,627.63
	27	60	1,087.23	41	797.75	89.75	11.42	2,425.36
जून	9	42	537.64	33	412.64	89.75	11.42	2,838.02
	24	85	1,756.16	66	1,474.16	89.75	11.42	4,312.18
जुलाई	7	26	589.00	10	387.00	89.80	11.36	4,699.18
	22	56	1,979.65	16	854.60	89.87	11.27	5,553.78
अगस्त	5	67	1,623.35	21	795.85	89.93	11.20	6,349.63
	19	55	997.80	35	810.00	89.95	11.17	7,159.63

परिशिष्ट सारणी IV. 17: अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम

निम्नलिखित को समाप्त पञ्चाङ्ग	जिन बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र* जारी किये उनकी संख्या	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये)	जमा प्रमाणपत्रों** की प्रभावी म्याद वर (वार्षिक प्रतिफल)	
1	2	3	4	
1991				
जुलाई	12	52	4,816	9.00-17.00
	26	52	4,683	10.50-17.00
अगस्त	9	53	4,805	11.00-17.00
	23	53	5,121	10.00-21.00
सितंबर	6	52	5,198	110.0-18.96
	20	51	5,010	11.50-16.00
अक्तूबर	4	51	4,901	12.00-21.00
	18	50	5,023	12.00-21.00

नवंबर	1	52	4,956	13.00-17.00
	15	51	4,957	11.00-21.00
	29	51	5,257	12.50-21.00
दिसंबर	13	51	5,406	12.50-17.66
	27	52	5,373	12.50-17.64
1992				
जनवरी	10	51	5,500	13.00-21.00
	24	51	5,655	12.00-22.00
फरवरी	7	51	5,633	13.50-16.01
	21	50	5,656	13.50-17.28
मार्च	6	50	5,693	12.50-17.62
	20	50	5,882	12.00-17.00
अप्रैल	3	49	5,810	13.00-17.50
	17	50	5,608	12.50-17.00
मई	1	49	5,735	12.50-18.40
	15	52	5,684	13.00-18.00
	29	50	5,928	13.00-17.20
जून	12	52	6,556	12.25-25.00

*पल्लवाङ्क के अंत में।

*पल्लवाङ्क के दौरान सभी परिवर्तता के प्रभावों के लिए जारी।

परिशिष्ट सारणी IV. 18 : बोक मूल्य सूचकांक में बिन्दुवार आकार पर
(आधार 1981-82—100) बट-बट के तीन चरण

(प्रतिशत में)

मई	चरण I			चरण II			चरण III		
	मार्च के अंत से अगस्त के अंत तक			अगस्त के अंत से दिसंबर के अंत तक			दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक		
	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सभी पण्य	6.5	5.6	9.6	-0.4	3.7	1.9	2.8	2.3	1.7
वस्तुएं II	6.8	10.4	13.9	-3.5	2.9	2.6	3.3	3.1	-1.3
ईंधन, पावर I	0.5	1.5	4.7	0.8	11.1	5.2	4.9	1.4	2.8
विशाली एवं भिन्नताई के बदल	0.6	1.5	4.7	0.8	11.1	5.2	4.9	1.4	2.8
विभिन्न उत्पाद	7.5	3.7	8.0	1.2	2.9	0.9	2.1	2.1	3.3

परिशिष्ट सारणी IV.15. धातु मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़

(आधार 1981-82=100)

(प्रतिशत में)

प्रमुख मूल्य/समूह/उप समूह पथ	सारांक	विस्तृत वर्ष के दौरान				प्रथम तिमाही के दौरान	
		बिन्दवार आधार		औसत आधार		बिन्दवार आधार	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पथ	100.000	12.1	13.6	10.3	13.7	4.3	2.3
I. प्राथमिक वस्तुएं	32.295	17.1	15.3	13.1	18.2	7.4	3.3
1. खाद्य वस्तुएं	17.386	18.9	20.9	12.0	20.2	10.0	5.8
(क) अन्न, ज	6.824	25.3	26.9	7.9	23.2	-2.6	0.9
(i) कान्ठ	3.685	13.4	30.7	5.7	21.7	4.4	2.2
(ii) गेहूं	2.248	48.9	12.3	16.2	18.3	-15.5	-3.8
(ख) दालें	1.093	10.8	9.4	10.7	9.3	5.7	1.9
(ग) फल व सब्जियां	4.089	22.7	19.0	19.8	24.1	28.2	14.2
(घ) दूध	1.961	8.9	13.7	4.2	12.9	6.0	0.8
(ङ) अण्डे, मछली, और मांस	1.783	10.5	16.3	9.1	14.6	11.4	3.4
(च) धान-मसाले, चटनी आदि	0.947	32.3	41.3	25.9	46.7	18.8	11.5
(छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.689	-2.0	-5.0	13.3	-8.9	14.4	17.2
(i) चाय	0.564	-12.6	0.4	6.1	-9.6	25.1	22.3
(ii) काफी	0.125	61.3	-22.2	60.6	-5.5	-19.9	-4.2
2. गैर-खाद्य वस्तुएं	10.081	19.3	8.1	17.2	17.6	3.8	-0.7
(क) रेशे	1.791	24.5	14.4	5.2	38.8	14.9	0.3
(i) कपास	1.335	44.3	24.7	-0.7	63.4	21.1	2.6
(ख) तिलहन	3.861	26.6	4.7	28.9	20.3	2.8	2.1
3. खनिज	4.828	-0.5	5.2	6.7	4.1	3.2	0.6
(i) पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	4.274	-0.4	1.9	8.5	1.4	1.9	0.0
II. ईंधन, पावर, विद्युत और चिकित्सा के पदार्थ	10.663	14.4	13.2	12.3	13.1	0.5	0.3
(क) कच्चा कोयला	0.353	0.09	26.1	0.0	7.0	0.0	0.0
(ख) खनिज तेल	6.666	20.6	9.2	19.3	10.1	0.0	0.1
(ग) बिजली	2.741	11.4	13.7	7.1	10.8	1.5	0.9
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	8.9	12.6	8.4	11.3	3.3	2.1
(क) धान, खांडमारी और गूड़	4.059	0.1	5.5	0.3	5.3	11.1	12.0
(i) चीनी	2.013	0.4	18.9	0.0	10.6	3.9	2.9
(ii) खांडमारी	0.300	-2.8	-6.9	-1.9	3.1	16.0	14.2
(iii) कढ़	1.746	0.1	-6.9	0.8	0.4	17.9	24.1
(ख) खाद्य तेल	2.445	32.7	1.9	26.0	19.1	2.0	5.2
(ग) सूती यस्त्र	6.093	6.5	16.0	8.0	14.4	4.9	0.0
(घ) रसायन और रसायन उत्पाद	7.355	7.3	15.5	5.6	13.9	2.9	1.3
(ङ) सोमेट	0.860	14.1	17.4	17.2	13.9	7.5	-1.8
(च) बोहा और इस्पात	2.441	6.0	4.5	6.7	5.5	0.7	2.0

परिशिष्ट सारणी IV 20: सामान्य योक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूहों/पण्यों का भारांकित योगदान
(आधार 1981-82=100)

(प्रतिशत में)

प्रमुख समूह / समूह उप समूह पण्य	भारतीय	वित्तीय वर्ष के दौरान				प्रथम तिमाही के दौरान	
		विन्दुवार आधार		औसत आधार		विन्दुवार आधार	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.000	100.0	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0
I. प्राथमिक वस्तुएं	22.295	44.6	37.1	40.4	43.2	56.7	48.4
1. खाद्य वस्तुएं	17.386	28.1	29.1	21.9	28.1	44.7	51.8
(क) अनाज	6.824	12.7	13.4	5.0	10.8	4.1	2.9
(i) ज्वार	3.685	3.9	8.2	2.1	5.7	3.7	4.1
(ii) गेहूँ	2.248	7.3	2.2	3.2	2.8	8.7	4.0
(ख) दालें	1.003	1.2	0.9	1.4	0.9	1.7	1.0
(ग) फल व सब्जियाँ	4.089	7.5	6.1	8.1	8.0	28.9	28.5
(घ) दूध	1.961	1.7	2.3	1.0	2.1	3.1	0.8
(ङ) अंडे, भट्ठी और मांस	1.783	1.6	2.2	1.7	2.0	5.0	2.9
(च) मिर्च-मसाले, जटनी आदि	0.947	3.6	4.8	3.2	5.0	6.9	9.8
(छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.698	0.2	0.3	1.4	0.7	3.2	6.0
(i) चाय	0.564	1.0	0.0	0.6	0.6	4.3	6.2
(ii) काफी	0.125	0.8	0.4	0.9	0.1	1.0	0.3
2. गैर-खाद्य वस्तुएं	10.081	16.6	6.6	16.8	13.9	9.8	3.0
(क) रेशे	1.791	3.4	2.0	0.9	4.8	6.6	0.2
कपास	1.335	3.7	2.4	0.1	4.9	6.4	1.7
(ख) तिलहन	3.861	8.3	1.5	9.9	6.1	2.8	3.6
3. खनिज	4.828	0.1	1.1	1.9	0.9	2.1	0.0
पेट्रोलियम कच्चा तेल	4.274	0.1	0.3	1.9	0.2	1.0	0.0
और प्राकृतिक गैस							
II. ईंधन, पावर, विद्युत और	10.863	12.2	10.2	12.0	9.8	1.2	1.3
जिकनार्ई के पदार्थ							
(क) कच्चा कोयला	0.352	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0
(ख) खनिज तेल	6.666	9.3	4.0	9.7	6.6	0.0	9.1
(ग) बिजली	2.741	2.9	3.1	2.1	2.4	1.1	1.2
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	43.0	52.7	47.4	47.0	43.1	50.2
(क) बीड़, खांडसारी और गुड़	4.059	0.0	1.3	0.1	1.3	8.1	15.2
(i) चीनी	2.013	0.1	2.1	0.0	1.2	1.4	2.0
(ii) खांडसारी	0.300	0.1	0.1	0.0	0.1	0.8	1.1
(iii) गुड़	1.746	0.0	0.7	0.1	0.0	5.9	12.0
(ख) खाद्य तेल	2.445	7.3	0.5	6.6	4.1	1.5	6.6
(ग) सूती वस्त्र	6.093	3.3	6.8	4.6	6.0	8.6	0.1
(घ) रसायन और रसायन उत्पाद	7.355	3.7	6.7	3.4	6.0	4.0	3.4
(ङ) सीमेंट	0.860	0.9	1.1	1.3	0.8	1.5	0.7
(च) लोहा और इस्पात	2.441	1.4	0.9	1.8	1.1	0.4	2.1

परिशिष्ट सारणी IV. 21 : बोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में
प्रदर्शित मूल्य वृद्धि की वार्षिक और तिमाही दरें
(बिल्ड-बार आधार पर)

		1990-91						1991-92						1990-91		(प्रतिशत में)		
		तिमाही			वार्षिक			तिमाही			वार्षिक			तिमाही			प्रतिशत-जन	
		अप्रैल-जून			अप्रैल-जून			अप्रैल-जून			अप्रैल-जून			अप्रैल-जून				
		अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्तूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च	घट-बढ़	अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्तूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च	घट-बढ़	अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्तूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
बोक मूल्य सूचकांक ^①	4.1	1.7	3.4	2.3	12.1	4.3	5.0	2.0	1.7	13.6	2.3							
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ^②	4.5	3.2	4.2	1.0	13.6	4.0	5.7	1.8	1.8	13.9	3.1							
झट्टी और श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ^③	4.0	2.6	3.8	2.4	13.4	3.0	5.7	1.6	2.7	13.6	1.6+							
छवि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.1	4.3	4.5	3.6	16.6	2.1	1.3	3.4	3.8	21.9	1.1+							

① आधार : 1981-82 = 100†, आधार : 1982 = 100, आधार : 1984-85 = 100, *आधार : 1968-69 = 100 †मई 1992 तक

परिशिष्ट सारणी 4—22 बेसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमतें

वर्ष	सोना		चांदी		बंबई और लंदन मूल्यों में अंतर	बंबई और न्यूयार्क के मूल्यों में अंतर
	बंबई बाजार (स्टैंडर्ड सोना प्रति 10 ग्राम स्वयं)		बंबई बाजार (0.999 तक प्रशुद्धित स्वयं प्रति कि. ग्रा.)		(प्रतिशत के रूप में औसत)	
	वर्ष के अंत में	औसत	वर्ष के अंत में	औसत	सोना*	चांदी**
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	2.5	—349
1981-82	1,645 (—3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (—1.5)	2,636 (0.7)	42.1	0.3
1982-83	1800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	37.8	—1.1
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	38.5	0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	53.3	27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,120 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	64.8	83.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	47.3	91.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	61.2	83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	62.6	114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (—4.3)	6,842 (7.5)	56.5	140.4
1990-91	3,466 (8.3)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (—1.2)	59.3	162.1
1991-92	4,334 (25.0)	4,298 (24.5)	6,040 (21.0)	7,332 (8.5)	51.3	124.2

*फरवरी 1992 तक यह अंतर इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले लंदन बाजार में प्रति ट्राय औंस डालरों के भाव को लंदन में अमरीकी डालरों के हाजिर खरीद और बिक्री पर आधारित दैनिक औसत की प्रति वस ग्राम स्वयं के भाव में बदला जाता था और फिर उसे रिजर्व बैंक की हाजिर स्टलिंग की बिक्री और खरीद के भाव में घटाया जाता था। मार्च 1992 से भावों की बंबई में अमरीकी डालरों की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी मंच के हाजिर बिक्री और खरीद के दैनिक औसत पर बदला जाता है।

**फरवरी 1992 तक, इस अंतर को इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले न्यूयार्क बाजार में सेंट प्रति ट्राय औंस के भावों में अमरीकी डालर के हाजिर खरीद और बिक्री के दैनिक औसत पर की स्वयं प्रति कि. ग्राम में बदला जाता था और फिर उसे स्टलिंग के भारतीय रिजर्व बैंक की हाजिर बिक्री और खरीद की औसत भाव से घटाया जाता था। मार्च 1992 से भावों की बंबई में अमरीकी डालरों की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी मंच के हाजिर बिक्री और खरीद के दैनिक औसत पर बदला जाता है।

टिप्पणी:—कोष्ठकों के अंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंक बढ़ दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 4.23 : ग्रामों के अनुसार सोना और चांदी का अनुपात*

वर्ष	बंबई बाजार में*		भारतीय बाजार में †	
	प्रतिशत मूल्य प्राधार पर (ग्राम)	वर्ष के अंत में मूल्य प्राधार पर (ग्राम)	प्रतिशत मूल्य प्राधार पर (ग्राम)	वर्ष के अंत में मूल्य प्राधार पर (ग्राम)
1	2	3	4	5
1980-81	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	68
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
1990-91	51	53	83	92
1991-92	59	54	87	83

† प्रति एक ग्राम सोने पर उल्लेख चांदी के ग्राम

* बंबई विलियम संध के भावों पर आधारित

‡ लंदन और न्यूयार्क बाजार के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त भावों पर आधारित

परिशिष्ट सारणी 4.24 : सोने और चांदी के मूल्यों में मासिक अंतर

माह/वर्ष	सोना		चांदी	
	बंबई लंदन		बंबई-न्यूयार्क	
	*समय	प्रतिशत	समय	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991				
अप्रैल	1,288.79	56.2	4,164.24	163.6
मई	1,371.21	58.0	4,233.39	158.2
जून	1,256.62	50.7	3,869.99	130.4
जुलाई	1,038.22	34.3	3,484.69	98.6
अगस्त	1,229.79	41.6	3,602.88	110.4
सितंबर	1,348.25	46.5	3,646.05	108.4
अक्तूबर	1,503.72	50.3	3,821.95	112.0
नवम्बर	1,716.32	57.3	3,898.29	115.4
दिसम्बर	1,872.46	62.2	4,440.45	136.6
1992				
जनवरी	1,977.70	67.0	4,927.09	143.6
फरवरी	1,789.50	60.7	4,691.24	136.1
मार्च	1,069.17	33.6	3,970.00	99.8
अप्रैल	1,131.48	33.6	4,396.74	110.5
मई	839.34	27.1	3,996.78	100.5
जून	794.89	24.1	3,313.47	84.0
जुलाई	708.55	20.7	3,694.59	96.2

* प्रति 10 ग्राम रुपये

@ प्रति कि. ग्राम रुपये

परिशिष्ट सारणी 5.1: सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता

(करोड़ रुपये)

संस्था	1989-90		1990-91		1991-92		स्वीकृतियों में घट-बढ़		संवितरण में घट-बढ़	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	1989-90 की तुलना में 1990-91	1989-90 की तुलना में 1991-92	1989-90 की तुलना में 1990-91	1989-90 की तुलना में 1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. अधिकृत भारतीय विकास बैंक										
(1 से 9)										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक										
	13,043.7	7,574.1	16,172.3	9,778.1	18,053.6	11,693.2	3,128.6 (24.0)	1,881.3 (11.6)	2,204.0 (29.1)	1,915.1 (19.6)
	11,272.1	6,468.4	14,165.9	8,550.1	15,879.6	10,384.1	2,893.8 (25.7)	1,713.7 (12.1)	2,081.7 (32.2)	1,834.0 (21.5)
	7,742.2	5,084.8	6,827.4	4,459.4	7,639.6	5,762.8	1,215.4* (21.6)*	612.2 (11.9)	945.6* (26.9)*	1,303.4 (29.2)
	7,354.7	4,701.0	6,381.2	4,017.4	7,155.8	5,279.0	1,156.7* (22.1)*	774.6 (12.1)	887.4* (28.4)*	1,261.6 (31.4)
	5,583.1	3,595.3	5,569.7	3,533.2	6,506.2	4,816.4	2,116.8* (61.3)*	936.5 (16.8)	1,508.9* (74.5)*	1,283.2 (36.3)
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2,294.9	1,121.8	2,965.1	1,574.8	2,869.2	1,605.2	670.2 (29.2)	-95.9 (-3.2)	453.0 (40.4)	30.4 (1.9)
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	2,850.6	1,357.1	3,744.0	1,967.6	4,305.9	2,351.3	893.4 (31.3)	561.9 (15.0)	610.5 (45.0)	383.7 (19.5)
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक			2,408.8	1,838.5	2,898.1	2,027.4		489.3 (20.3)		188.9* (10.3)
			1,213.9	1,094.7	1,373.7	1,180.9		159.8 (13.2)		86.2 (7.9)
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	146.6	141.2	234.7	153.9	277.7	185.2	88.1 (60.1)	43.0 (18.3)	12.7 (9.0)	31.3 (20.3)
6. बंदिन पूंजी और तकनीक निगम	8.8	5.0	10.5	7.3	14.5	7.4	1.7 (19.3)	4.0 (38.1)	2.3 (46.0)	0.1 (1.4)
7. भारतीय पॉपुलर वित्त निगम	14.1	9.5	11.4	12.4	19.9	18.5	-2.7 (-191)	8.5 (74.6)	2.9 (30.5)	6.1 (49.2)
8. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ऋण निवेश कंपनी	321.2	225.7	331.6	167.0	409.0	170.9	10.4 (3.2)	77.4 (23.3)	-58.7 (-26.0)	3.9 (2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. भारतीय तकनीकी विकास और सूचना निगम	52.8	12.8	85.0	39.2	103.5	48.3	32.2 (61.1)	18.5 (21.8)	26.4 (206.3)	(9.1) (23.2)
अनिवार्य संस्थाएं (10+12)	2,086.0	1,715.3	3,078.2	2,156.5	8,005.0	4,174.7	992.2 (47.6)	2,926.8 (95.1)	441.2 (25.7)	2,019.2 (93.6)
	1,956.0	1,500.3	2,568.2	1,631.5	4,955.0	3,624.7	612.2 (31.3)	2,386.8 (92.9)	131.2 (8.7)	1,933.2 (122.2)
10 भारतीय यूनिट ट्रस्ट @	1,296.6	1,080.5	2,077.2	1,582.7	3,832.5	2,910.4	780.6 (60.2)	1,755.3 (84.5)	502.2 (46.5)	1,327.7 (83.9)
@	1,166.6	865.5	1,567.2	1,057.7	3,182.5	2,410.4	400.6 (34.3)	1,615.3 (103.1)	192.2 (22.2)	1,352.7 (127.9)
11 भारतीय जीवन बीमा निगम	578.2	455.2	688.1	427.4	1,515.3	1,022.5	109.9 (19.0)	827.2 (120.2)	-27.8 (-6.1)	545.1 (139.2)
	578.2	455.2	688.1	427.4	1,115.3	972.5	109.9 (19.0)	427.2 (62.1)	-27.8 (-6.1)	545.1 (127.57)
12 भारतीय साधारण बीमा निगम @	211.2	179.8	312.9	146.4	657.2	241.8	101.7 (48.2)	314.5 (110.0)	-33.2 (-18.5)	95.4 (65.2)
द. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल वित्तीय सहायता (अ @ + अ @)	14,999.7	9,074.4	18,740.5	11,409.6	23,008.6	15,317.9	3,740.8 (24.9)	4,268.1 (22.8)	2,335.2 (25.7)	3,908.3 (34.3)
ई. राज्य स्तरीय संस्थाएं (13 और 14)	2,177.0	1,692.1	2,663.0	1,857.7	2,970.5	2,063.2	486.0 (22.3)	307.5 (11.5)	165.6 (9.8)	205.5 (11.1)
13. राज्य वित्तीय निगम	1,511.0	1,154.6	1,848.0	1,267.3	2,065.0	1,393.2	337.0 (22.3)	217.0 (11.7)	112.7 (9.8)	125.9 (9.9)
14. राज्य औद्योगिक वित्त निगम	666.0	537.5	815.0	590.4	905.5	670.0	149.0 (22.4)	90.5 (11.1)	52.9 (9.8)	79.6 (13.5)
15. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल वित्तीय सहायता (अ @ + अ @ + ई)	15,405.1	9,660.8	19,397.1	12,039.3	23,805.1	16,072.0	3,992.0 (25.9)	4,408.0 (22.07)	2,378.5 (24.6)	4,032.7 (32.5)

टिप्पणी: 1. 1991-92 के आंकड़े सभी संस्थाओं के लिए प्रतिवर्ष और राज्य वित्त निगम एवं राज्य औद्योगिक वित्त निगम के लिए अनुमानित हैं।

2. 1990-91 और 1991-92 के कुल को अंतर-संस्थानत निर्माणों के लिए समायोजित किया गया है जो 2-3 हजार करोड़ रुपये के रुपये में है।

3. काष्ठकों में विवेक के आंकड़े पिछले वर्ष के प्रतिवर्ष बट-बट दर्शाते हैं।

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2 अप्रैल 1990 से कार्य करना शुरू किया। यह समिति वर्ष 1990-91 के बट-बट 1989-90 के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लिए गये लघु उद्योग विकास निधि तथा राष्ट्रीय उद्योग विकास निधि योजना से संबंधित है।

स्रोत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी 5.2: गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र के पास जमाराशियां (मार्च अस्त के अनुसार)

(करोड़ रुपये)

संख्या	1989-90				1990-91 (अंतिम)			
	सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या	विनियमित जमाराशियां	छूट प्राप्त जमाराशियां	कुल	रिपोर्टिंग कंपनियों की संख्या	विनियमित जमाराशियां	छूट प्राप्त जमाराशियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल जमाराशियां जिसमें से:	10,140	6,758	26,773	33,531	9,901	8,003	36,060	44,063
1. गैर वित्तीय कंपनियां	2,438 (24.0)	4,044 (59.8)	16,759 (62.6)	20,803 (62.0)	2,365 (23.9)	4,610 (57.6)	21,671 (60.1)	26,281 (59.6)
2. वित्तीय कंपनियां	6,538 (64.5)	1,825 (27.0)	9,139 (34.1)	10,964 (32.7)	6,416 (64.8)	2,184 (27.3)	13,450 (37.3)	15,634 (35.5)
3. विभिन्न गैर बैंकिंग कंपनियां और प्रेषणित गैर बैंकिंग कंपनियां	1,164 (11.5)	889 (13.2)	875 (3.3)	1,764 (5.3)	1,120 (11.3)	1,209 (15.1)	939 (2.6)	2,148 (4.9)

टिप्पणियां: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सहास्यति, सूचना देने वाली कंपनियों/विनियमित छूट प्राप्त/सकल जमाराशियों की कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 5.3: सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए निर्यत्क, पूंजी निर्गम द्वारा प्रदत्त सहमतियां/अभिस्वीकृतियां

(करोड़ रुपये)

निर्यत्क का प्रकार	1990-91		1991-92	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
अ. गैर-सरकारी कंपनियां				
1. शेयर (क + ख)	498	2,552	794	3,939
क) प्रारंभिक निर्गम	231	1,252	361	2,025
ख) बाद के निर्गम*	268	1,300	438	1,914
2. डिबेंचर (क + ख)	233	3,570	375	8,050
क) परिचालनीय	137	2,588	231	5,858
ख) अपरिचालनीय	96	982	144	2,192
3. उप जोड़ (1 + 2)	732	6,122	1,174	11,989
4. बोनस शेयर	342	301	69	352
5. जोड़ (3 + 4)	1,074	6,423	1,243	12,341
आ. सरकारी कंपनियां				
1. शेयर (क + ख)	4	61	2	56
क) प्रारंभिक निर्गम	2	30	-	-
ख) बाद के निर्गम	2	31*	2	56
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड	17	6,007	17	6,985
3. उप जोड़ (1 + 2)	21	6,068	19	7,041
4. बोनस शेयर	10	140	1	20
5. जोड़ (3 + 4)	31	6,208	20	7,061

1	2	3	4	5
६. कुल जोड़ (अ३+अ३३) (अर्थात् बोनस निर्गम छोड़कर) जिसमें से :—	753	12,190	1,193	19,030
(1) शेयर	503	2,613	301	3,995
(2) डिबेंचर और बांड	250	9,577	392	15,035
७. कुल बोनस शेयर (अ४+अ४४)	352	411	70	372
८. कुल जोड़ (६+७) गैर सरकारी कंपनियों	1,105	12,631	1,263	19,402

*इसमें 1989-90 में प्रीमियम की 213 करोड़ रुपये की राशि 1990-91 में 274 करोड़ रुपये और 1991-92 में 402 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

** 0.19 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि।

स्रोत : नियंत्रक, पूँजी निर्गम

परिणाम मार्गी 5.1. गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के भये पूँजी निर्गम(८)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	निर्गम का प्रकार	1989- 90		1990- 91		1991- 92	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ईक्विटी शेयर (क+ख)*	268	1,218.8	246	1,285.7	367	1,729.5
		(57)	(272.0)	(41)	(128.1)	(56)	(227.5)
	(क) बिबरण पत्र	143	734.1	103	993.8	158	1,043.1
		(17)	(30.0)	(13)	(73.9)	(16)	(26.7)
	(ख) अधिकार पत्र	125	484.7	143	291.9	209	686.4
		(40)	(242.0)	(26)	(54.2)	(40)	(200.8)
2.	अधिमान शेयर (क+ख)	1	7.9	3	13.1	3	1.5
	(क) बिबरण पत्र	3	5.4	2	13.0	2	0.5
	(ख) अधिभाग पत्र	1	2.5	1	0.1	1	1.0
	जिनमें से						
3.	डिबेंचर (क+ख)	136	5,246.4	114	2,931.4	146	4,019.8
	(क) बिबरण पत्र	41	2,400.7	45	1,037.9	50	860.1
	(ख) अधिकार पत्र	92	2,845.7	69	1,893.5	96	3,159.7
	(i) परिवर्तनीय (क+ख)*	109	4,762.2	94	2,355.2	133	3,489.2
	(क) बिबरण पत्र	37	2,240.4	38	874.7	47	848.4
	(ख) अधिकार पत्र	72	2,521.8	56	1,480.5	86	2,640.8
	(ii) अपरिवर्तनीय (क+ख)	27	484.2	20	576.2	13	530.6
	(क) बिबरण पत्र	7	160.3	7	163.2	3	11.7
	(ख) अधिकार पत्र	20	323.9	13	413.0	10	518.9
4.	जोड़ (1+2+3)	408	6,473.1	363	4,230.2	516	6,760.8
	(क) बिबरण पत्र	190	3,140.2	152	2,044.7	210	1,903.7
	(ख) अधिकार पत्र	218	3,332.9	211	2,185.5	306	3,847.1

(८)अनतिम *बोनस निर्गम शामिल नहीं

**परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्राधिकृत रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल है।

टिप्पणियाँ :

1. कोष्ठकों में दिये आंकड़ों पूँजी निर्गमों पर प्रीमियम संबंधी आंकड़े हैं, जो कि संबंधित जोड़ में शामिल हैं।
 2. इन आंकड़ों में बित्तीय संस्थाओं आदि के पास निजी तौर पर रखे गये निर्गम शामिल नहीं हैं।
 3. आंकड़ों में अंगरान में अधिक राशि उन मामलों में दी गयी है जिनमें विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी। तथापि, जहाँ राशि अंगरान से कम रही है, उसे हिरास में नहीं लिया गया है क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- स्रोत : कंपनियों द्वारा जारी बिबरण पत्र/परिपत्र, वित्तायन, कंपनियों द्वारा रिजर्व बैंक की प्रस्ताववक्तियों के दिये गये उत्तर, वित्त मंत्रालय के स्टॉक एक्सचेंज प्रभाग में प्राप्त/पकड़ की गई जानकारी, वित्तिय स्टॉक एक्सचेंज, प्रेम रिपोर्ट, बैंड आउटों आदि।

लघुसिद्धि माहली 5.5 भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक लेखा मुख्य सूचकांक (साप्ताहिक)

(माघार 1990 - 81 or 100)

वर्ष/माह	औसत +	उच्च	निम्न	माह/वर्ष के अंतिम साप्ताहिक के अवधि में		
1	2	3	4	5		
1990-91	300.3	654.2	395.6	527.9		
(अप्रैल - मार्च)	(+30.2)			(+32.9)		
1991-92	776.2	1,485.4	536.9	1,485.4		
(अप्रैल - मार्च)	(+55.1)			(+181.4)		
अप्रैल 91	554.9	568.0	536.9	568.0		
मई	563.8	570.2	538.9	570.2		
जून	571.3	579.6	563.8	568.6		
जुलाई	607.8	644.3	569.3	644.3		
अगस्त	715.1	752.2	693.4	752.2		
सितम्बर	771.8	792.3	751.8	779.9		
अक्टूबर	761.2	781.3	750.9	750.7		
नवम्बर	801.3	821.4	781.8	813.4		
दिसम्बर	805.4	821.0	788.5	808.7		
जनवरी, 1992	840.7	868.8	822.1	868.8		
फरवरी	990.3	1,095.3	923.3	1,095.3		
मार्च	1,373.3	1,485.4	1,271.5	1,485.4		
अप्रैल	1,620.2	1,656.9	1,597.3	1,622.0		
मई	1,345.5	1,519.3	1,206.8	1,206.8		
जून	1,164.9	1,183.4	1,139.3	1,162.1		
शापन सर्वे	1987-88	1987-89	1989-90	1990-91	1991-92	पाँच वर्षों का औसत (1987-88 से 1991- 92 तक)
(अ) धन का गुणांक (प्रतिफल में)-	4.82	16.36	5.90	14.66	27.04	13.76
(आ) वियोजन (सोमा)	40.0	121.1	93.7	258.6	984.5	292.4

+ साप्ताहिक सूचकांकों पर आधारित

* अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 6.2 : विस्तीर्ण की आवश्यकता तथा विस्तीर्ण के स्त्रोत

	मिथिला प्रमरीकी डालर में				मिलियन विदेशी मुद्रा में			
	1989-90@ कुल सारणी		1990-91@ कुल सारणी		1991-92@ कुल सारणी		1990-91@ कुल सारणी	
	पंचवर्षीय योजना*		पंचवर्षीय योजना*		पंचवर्षीय योजना*		पंचवर्षीय योजना*	
	(अ. अ.)	(तु. अ.)	(अ. अ.)	(तु. अ.)	(अ. अ.)	(तु. अ.)	(अ. अ.)	(तु. अ.)
1. शुद्ध विदेशी धन का साटा साटा	19,514	39,235	15,114	6,933	7,269.1	27,998.9	8,423.6	2,835.0
2. संघर्षीय मुद्रा कोप को चुकौती	1,460	5,113	1,156	1,127	876.7	3,619.3	644.0	157.0
3. विस्तीर्णों की आवश्यकता (1+2)	12,004	11,138	16,270	8,065	8,145.8	31,609.2	9,067.6	3,291.0
4. विदेशी सहायता	3,099	12,728	4,070	6,860	1,855.9	9,115.5	2,268.4	2,80
	(25.7)	(28.6)	(25.0)	(85.1)	(22.8)	(28.8)	(25.0)	(85.1)
5. वाणिज्यिक उधार	2,958	10,647	1,309	4,417	1,776.9	7,547.5	729.3	1,805.0
	(24.7)	(24.0)	(8.0)	(54.8)	(21.8)	(23.9)	(8.0)	(51.8)
6. अनिवार्य जमा राशियाँ	2,442	10,164	2,260	-1,828	2,402.6	7,323.5	1,529.5	-747.0
	(20.3)	(22.9)	(13.9)	(-22.7)	(29.5)	(23.2)	(13.9)	(-22.7)
7. अ. मुद्रा कोप से आहरण		3,901	3,207				1,857.8	1,240.0
		(18.5)	(39.8)				(20.5)	(37.6)
8. अन्य पूंजी	2,281	5,823	3,234	4,156	1,370.2	2,995.3	2,186.4	1,737.4
	(19.0)	(13.1)	(20.5)	(51.5)	(16.8)	(12.6)	(18.5)	(536)
9. प्रारम्भिक विधियों का उपयोग	1,233	5,076	2,293	-8,747	740.2	3,627.4	1,278.0	-3,574
	(10.3)	(11.4)	(14.1)	(-108.5)	(9.1)	(11.5)	(14.1)	(-108.5)

टिप्पणी: 1) कोष्ठकों के अंक विस्तीर्ण संबंधी आवश्यकता (सद 3) के प्रमरीकी डालर में परिवर्तनों के अनुपात दर्शाते हैं तथा विदेशी आहरण अधिकार संबंधित वार्षिक औसत दरों पर हैं।

2) 1991-92 के वाणिज्यिक उधार के अंक में 1627 मिलियन प्रमरीकी डालर (1192 मिलियन वि. घा. अ.) के भारत विकास ऋण शामिल हैं।

तु. अ. = तुल्य अनुमान, @ अनिवार्य भारतीय जमा राशियों पर प्रोद्भूत भाग शामिल है।, * अनिवार्य जमा राशियों पर प्रोद्भूत व्याज शामिल नहीं है।

अ. अ. = अंशिक अनुमान

परिशिष्ट सारणी 6.3 : भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा विधियाँ

निम्नलिखित माह के अंत में	विदेशी मुद्रा प्रारम्भिक विधियाँ (करोड़ रुपये)				आरक्षित विदेशी मुद्रा विधियाँ (मिलियन प्रमरीकी डालर)				कुल आर-
	विदेशी आहरण अधिकार	स्पर्ण@	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	कुल (2+3+4)	विशेष आहरण अधिकार	स्पर्ण@	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	कुल (2+3+4)	मूद्रा विधियाँ@ (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मार्च 1990	183	281	5,787	6,251	107	487	3,363	3,962	3,045
जून 1990	200	281	5,356	5,843	118	495	3,072	3,685	2,784
मार्च 1991	200	6,823	4,388	11,411	102	3,496	2,236	5,834	4,329
									(2,111)
जून 1991	133	7,411	2,382	9,926	63	3,324	1,124	4,711	3,564
									(1,278)
नवम्बर 1991	476	8,558	4,412	13,576	134	3,353	1,722	5,259	3,838
									(1,766)
दिसम्बर 1991	120	9,489	9,287	18,896	46	3,675	3,580	7,301	5,095
									(2,930)
मार्च 1992	223	9,039	11,578	23,850	90	3,499	5,631	9,220	6,716
									(4,566)
जून 1992	297	8,932	16,125	25,354	115	3,459	6,221	9,795	6,838
									(4,822)

प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में घट-बढ़ (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)	कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेवदेन (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेवदेन (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेवदेन (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में घट-बढ़ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण और प्रारक्षित निधि शुद्धता के आह्वरण को घटाकर (मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार में)
11	12	13	14	15	16
-670	487	3,900	2,752	1,148	-661
-261	487	3,900	2,863	1,037	-111
1,284	..	5,169	3,221	1,948	800
(-934)					(2,221)-
-765	..	5,169	3,300	1,869	-79
(-833)					(-754)
-491	..	5,804	3,396	2,408	460
(-345)					(-805)
766	..	5,889	3,463	2,426	478
(819)					(341)
2,387	..	6,074	3,558	2,516	568
(2,455)					(1,887)
122	..	6,074	3,612	2,462	-54
(256)					(310)

*पिछले मार्च की तुलना में घट-बढ़

संबंधित महीनों के अन्त में रुपया—विशेष आह्वरण अधिकार की विनियम दर पर

स्तंभ 3 में 16 अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण का मूल्य प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपये तथा प्रति ट्रांश औंस 35 वि. प्रा. अ. पर किया गया जैसा कि स्तंभ 6 में अ. सु. कोष के आईएफएस के संबंध में है और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट इसे मूल्यन किया गया है।

कोष्ठकों के आंकड़े स्वर्ण पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित प्रारक्षित निधियां दर्शाते हैं।

टिप्पणी : सकल आह्वरण, पुनः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बकाया देयताएं @ उक्त निधि में प्रारक्षित निधि के आह्वरण की स्थिति सम्मिलित है। विस्तारित निधि सुविधा, सहायक ऋण व्यवस्था और आकस्मिक तथा क्षतिपूर्क वित्तपोषण सुविधा से संबंधित है तथा इसमें न्यास निधि ऋण शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट सारणी 6.4: भारत का विदेश व्यापार

	करोड़ रुपये		मिलियन अमरीकी डालर			मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार			
	1991-92 (अ)	1990-91	1989-90 (अ)	1991-92 (अ)	1990-91	1989-90 (अ)	1991-92 (अ)	1990-91	1979-90 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I निर्यात	43,978	32,553	27,681	17,840	18,143	16,626	13,154	13,100	12,954
	(35.1)	(17.6)	(36.8)	(-1.7)	(9.1)	(19.0)	(0.4)	(1.1)	(23.3)
अपरिष्कृत तेल	---	---	---	---	---	---	---	---	---
पेट्रोलियम, तेल और बिकनाई के पदार्थ	1,022	938	697	415	523	41	306	377	326
	(9.0)	(34.6)	(38.0)	(-20.7)	(24.9)	(20.0)	(-19.0)	(15.8)	(24.4)
तेल से इतर	42,956	31,615	26,985	17,425	17,620	16,208	12,848	12,723	12,628
	(35.9)	(17.2)	(36.8)	(-1.1)	(8.7)	(19.0)	(1.0)	(0.7)	(23.3)
II आयात	47,813	43,193	35,416	19,396	24,073	21,272	14,301	17,382	16,574
	(10.7)	(22.0)	(25.4)	(-19.4)	(13.2)	(9.1)	(-17.7)	(4.9)	(13.1)
तेल तथा पेट्रोलियम, तेल और बिकनाई के पदार्थ	13,129	10,186	6,274	5,365	6,028	3,768	3,927	4,353	2,936
	(21.4)	(72.4)	(44.0)	(-1.0)	(60.0)	(25.2)	(-9.8)	(48.2)	(29.8)
तेल से इतर	34,684	32,377	29,142	14,031	18,045	17,504	10,374	13,029	13,638
	(7.1)	(11.1)	(22.0)	(-22.0)	(3.1)	(6.2)	(-20.4)	(-4.5)	(10.0)
III व्यापार संतुलन	-3,835	-10,640	-7,735	-1,556	-5,930	-4,646	-1,147	-4,282	-3,620
तेल संबंधी शेष	-12,107	-9,878	-5,577	-4,950	-5,505	-3,350	-3,621	-3,975	-2,610
तेल से इतर शेष	+8,272	-762	-2,157	+3,394	-425	-1,296	+2,474	-307	-1,010-

टिप्पणी : 1. वर्ष 1989-90 के अंतिम आंकड़े वा. प्रा. अ. सं. महानिदेशालय से उपलब्ध नहीं हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

3. (अ) अंतिम

स्रोत : वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय

परिशिष्ट सारणी 6.5 : भारत के मुख्य पथों का निर्वात

पथ समूह	करोड़ रुपये		प्रतिशत वट-वट		मिलियन अमरीकी डालर		प्रतिशत		घट-बढ़	
	1989-90 (अ)	1990-91 (अ)	1991-92 (अ)	(3)/(2)	(4)/(3)	1989-90 (अ)	1990-91 (अ)	1991-92 (अ)	(8)/(7)	(9)/(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्राथमिक उत्पाद	5951 (21.5)	7759 (23.8)	9919 (22.6)	30.4 (22.6)	27.8 (23.8)	3,574 (21.5)	4,324 (23.8)	4,024 (22.6)	21.0 (22.6)	-7.0
उनमें से :										
कृषि और उससे सम्बद्ध उत्पाद	4,571 (16.5)	6,019 (18.5)	7,638 (17.4)	31.7 (17.4)	26.9 (18.5)	2,745 (16.5)	3,355 (18.5)	3,098 (17.4)	22.2 (17.4)	-7.6
अथर्व और खनिज	1,380 (5.0)	1,740 (5.3)	2,281 (5.2)	26.1 (5.2)	31.1 (5.3)	829 (5.0)	970 (5.3)	925 (5.2)	17.0 (7.2)	-4.6
वित्तियत वस्तुएं	20,310 (73.4)	23,319 (71.6)	32,384 (73.9)	14.8 (73.9)	38.9 (73.4)	12,199 (73.4)	12,996 (71.6)	13,137 (73.9)	6.5 (73.9)	1.1
उनमें से :										
चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं	1951 (7.0)	2,566 (7.9)	3,076 (7.0)	31.5 (7.0)	19.9 (7.9)	1,172 (7.0)	1,420 (7.9)	1,248 (7.0)	22.0 (7.0)	-12.7
रसायन और उससे संबद्ध उत्पाद	1,981 (7.2)	2,345 (7.2)	3,677 (8.4)	18.4 (8.4)	56.8 (7.2)	1,190 (7.2)	1,307 (7.2)	1,491 (8.4)	9.8 (8.4)	14.1
इंजीनियरी वस्तुएं	3321 (12.0)	3,809 (11.7)	5,107 (11.7)	14.7 (11.7)	34.1 (11.7)	1,995 (12.0)	2,12 (11.7)	2,072 (11.7)	6.4 (11.7)	-2.4
वस्त्र वित्तियत वस्तुएं	5,246 (19.0)	6,775 (20.8)	9,964 (22.7)	29.1 (22.7)	47.1 (20.8)	3,151 (19.0)	3,776 (20.8)	4,042 (22.7)	19.8 (22.7)	7.0
उनमें से :										
सूती धागा कपड़े, तैयार वस्त्र,	1,480 (5.3)	2,100 (6.5)	3,209 (7.3)	41.9 (7.3)	52.8 (6.5)	889 (5.3)	1,170 (6.5)	1,302 (7.3)	31.7 (7.3)	11.2
सित्तिलेनायें वस्त्र	3,224 (11.6)	4,102 (12.3)	5,411 (12.3)	24.4 (12.3)	34.9 (12.3)	1,936 (11.6)	2,236 (12.3)	2,195 (12.3)	15.5 (12.3)	-1.8
दस्तकारी की वस्तुएं	6,285 (22.7)	6,167 (18.9)	8,346 (19.0)	-1.9 (19.0)	35.3 (18.9)	3,775 (22.7)	3,437 (18.9)	3,386 (19.0)	-9.0 (19.0)	-1.5
उनमें से :										
रत्न और आभूषण	5,296 (19.1)	5,247 (16.1)	6,750 (15.4)	-0.9 (15.4)	28.6 (16.1)	3,181 (19.1)	2,924 (16.1)	2,738 (15.4)	-8.1 (15.4)	-6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खनिज और चिकनाई की वस्तुएं*										
आय	(2.5)	697 (2.9)	938 (2.3)	1,022	34.6	9.0 (2.5)	419 (2.9)	523 (2.2)	415	24.9
कुल निर्यात	723 (2.6)	537 (1.6)	653 (1.5)	-25.7	21.6	434 (2.6)	209 (1.6)	265 (1.5)	-31.1	-11.5
	27,681	32,553	43,978	17.6	35.1	16,626	18,143	17,840	9.1	-1.7

टिप्पणी : 1. वर्ष 1989-90 के अंतिम आंकड़े वांछा० अंश०म०नि० में उपलब्ध नहीं

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कूल निर्यात का प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. केवल कच्चे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित हैं।

अ-अनतिम

स्त्रोत : वार्षिक आकृति और अर्थ संकलन महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी VI.6 : भारत के मुख्य पथों का आयात

वर्ष सत्र	कराई रुपये		प्रतिशत घट-बढ़		सिद्धिमान अमरीकी डॉलर		प्रतिशत घट-बढ़		
	1989-90 (अ)	1990-91 (ब)	1991-92 (ज)	(3)/(2)	(4)/(3)	1989-90 (अ)	1991-92 (ब)	(8)/(7)	(9)/(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I शीत आयात									
उत्तम से :	14,440 (40.8)	18,454 (45.0)	21,002 (44.0)	34.7	8.0	8,873 (49.8)	10,842 (45.0)	8,559 (44.1)	25.0 -21.1
(अ) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से उत्पन्न तथा संबंधित सामग्री	5,274 (1.5)	10,816 (15.0)	13,129 (17.5)	72.4	21.4	3,768 (15.7)	6,023 (11.6)	5,365 (17.7)	60.0 -11.0
(आ) शीत उपभोग्य वस्तुएं	914 (2.6)	989 (2.3)	626 (1.3)	6.2	-35.7	549 (2.6)	751 (4.3)	258 (1.3)	6.4 -53.2
उत्तम से :	278	182	141	-51.9	-22.5	227	101	87	-55.3 -43.6
(क) अनाज और खाद्य से बनी चीजें	211	326	240	54.5	-26.4	127	182	97	-35.4 -46.4
(ख) खाद्य तेल	228	481	254	111.0	-47.2	137	288	103	95.8 -61.6
(ग) दालें	97	9	1	-90.7	-88.9	58	3	0	-91.4 -91.9
(घ) फली	7,252	7,649	7,267	5.3	-5.4	4,556	4,263	2,956	-2.1 -31.1
(ङ) अन्य शीत वस्तुएं	20.5	17.7	15.2			20.5	17.7	15.2	
उत्तम से :	1,776	1,766	2,259	-0.6	27.9	1,807	984	518	-7.7 -6.9
(क) उर्वरक उत्तम से :	253	347	450	37.2	16.8	182	189	178	27.3 -7.7
(ख) वस्त्र	269	278	299	-5.8	7.6	177	155	121	-12.6 -21.7
(ग) अन्य और बिना तयार किए गए पदार्थ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
iii) विनिमित्त										
ख) शरीर धातुएं	1,228	1,141	1,520	-7.1	33.2	738	636	617	-13.8	-3.0
ग) काल रक्त और उनसे बनी वस्तुएं (श्रवणारा कामरमहित)	1,253	1,102	820	-12.1	-23.8	753	614	351	-18.4	-44.5
घ) कच्चा खट्टा	358	456	488	27.2	7.0	215	54	198	18.2	-22.1
ङ) लुदी और चूड़ी कागज	172	226	182	31.4	-19.5	103	128	74	21.9	-41.4
च) धातुएं अथवा और धातु की छान	304	458	299	50.7	-34.7	183	255	121	39.8	-52.5
छ) तैला और इस्पात	1,084	1,328	1,015	41.0	-33.6	651	852	412	30.8	-51.7
कुल आयात (I+II)	2,305	2,113	2,154	-8.3	1.9	1,384	1,178	874	-14.9	-25.8
II आयात	20,972	20,739	26,611	13.2	12	12,036	15,030	16,837	5.0	-18.1
उनमें से	(59.2)	(55.0)	(56.1)			(59.2)	(55.0)	(55.0)		
अ) पूर्णतः वस्तुएं	8,831	10,465	10,324	18.5	-0.7	5,304	5,832	4,216	10.0	-27.7
आ) मुख्यतः निर्मित से सान्द्र मर्द	(24.9)	(24.2)	(21.7)			(24.9)	(21.2)	(21.7)		
उत्तम से	6,803	7,603	8,554	-2.9	25.0	4,056	5,001	3,652	-9.9	-1.3
क) सौती वस्त्रों और आभूषणों का	(19.2)	(15.3)	(18.7)			(19.2)	(15.3)	(18.7)		
ख) रसायन कार्बनिक और अकार्बनिक	4,242	2,739	4,322	-11.5	29.0	2,545	2,083	1,556	-18.2	-8.1
ग) वस्त्रोपयोगी धागा, वस्त्र आदि	2,135	2,289	3,523	7.2	53.9	1,282	1,276	1,429	-0.5	12.0
घ) काच की गिरी, कच्ची	349	443	343	26.9	-22.6	210	247	139	17.8	-43.6
ङ) अन्य	77	134	266	74.0	98.5	46	75	108	61.5	44.5
उनमें से	5,338	6,670	7,463	25.0	11.9	3,206	3,717	2,993	15.9	-19.3
क) कृत्रिम रेशम तथा प्लास्टिक के मासुत	(15.1)	(15.4)	(15.6)			(15.1)	(15.4)	(15.5)		
ख) व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा गैर पेशेवी सामान आदि	996	1,095	1,403	9.9	28.1	593	610	569	2.0	-6.7
ग) क्रोयला, कोक और ब्रिक्केट आदि	886	1,060	1,041	19.6	-1.8	532	591	422	11.0	-28.5
घ) औद्योगिक और पेशेवी उपकरण	562	789	1,036	40.4	31.3	338	440	420	30.3	-4.4
ङ) रसायन सामग्री और उसके उत्पाद	272	468	450	71.2	-2.6	163	261	185	59.7	-29.1
च) आयातित वस्तुएं विनिमित्त वस्तुएं	223	286	521	28.5	12.2	133	159	130	19.5	-18.3
कुल आयात (I+II)	168	203	223	20.8	12.3	101	113	92	12.1	-18.3
	35,416	43,193	47,813	22.0	10.7	21,272	24,073	19,395	13.2	-19.4

टिप्पणी: 1. वर्ष 1989-90 के आंकड़े वा. आ. अ. सं. प. नि. में उपलब्ध नहीं हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल निर्यात से प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. अ - अंतर्गत

4. + आर्थिक/वैज्ञानिक वस्तुएं निर्यात दर का उपयोग करके अमरीकी डालर के रूप में परिवर्तित आर्थिक वस्तुओं के लिए मार्च 1992 के लिए मॉडल, आयात विनिमित्त दर का उपयोग किया गया है।

स्वातंत्र्य: वाणिज्यिक आयातों और अंतर्गत आयातों के संकलन में परिवर्तन

परिशिष्ट सारणी 6.7 : रूपा भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	रू. भु. क्षेत्र			सा. म. क्षेत्र			जॉइ		
	निर्यात	आयात	व्यापार शेष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
करोड़ रुपये									
1985-86	2,310	2,071	+ 2.39	9,585	17,586	-9,002	10,895	19,658	-8,763
1986-87	2,231 (-3.4)	1,359 (-34.4)	+ 872	10,221 (19.1)	18,737 (6.5)	-8,516	12,452 (14.3)	20,096 (2.2)	-7,644
1987-88	2,444 (9.5)	1,883 (38.7)	+ 559	13,230 (29.4)	20,359 (8.7)	-7,129	15,674 (25.9)	22,244 (10.7)	-6,570
1988-89	3,162 (29.4)	1,655 (-12.2)	+ 1,507	17,070 (29.0)	26,580 (30.6)	-9,510	20,232 (29.1)	28,235 (26.9)	-8,003
1989-90 (अन्तर्निम्न)	5,173 (63.6)	2,679 (61.9)	+ 2,494	22,508 (31.9)	32,737 (23.2)	-10,229	27,681 (36.8)	25,416 (25.4)	-7,735
1990-91	5,507 (6.5)	2,869 (7.1)	+ 2,638	27,046 (20.2)	40,324 (23.2)	-13,278	32,553 (17.6)	43,193 (22.0)	-10,640
1991-92 (अन्तर्निम्न)	4,351 (-21.0)	1,955 (-31.9)	+ 2,396	39,627 (46.5)	45,858 (13.7)	-6,231	43,978 (35.1)	47,813 (10.7)	-3,835
मिलियन अमरीकी डालर									
1985-86	1,888	-711,693	+ 195	7,017	14,374	-7,358	8,905	8,905	16,067
1986-87	1,746 (-7.5)	1,064 (-37.2)	+ 682	7,999 (14.0)	14,663 (2.0)	9,745	15,727 (9.4)	-5,982 (-2.1)	
1987-88	1,885 (8.0)	1,454 (36.7)	+ 431	10,204 (27.6)	15,702 (7.1)	-5,498	12,089 (24.1)	17,156 (9.1)	-5,067
1988-89	2,183 (15.8)	5,15,243 (-21.4)	+ 1,041	11,787 (15.5)	18,354 (16.9)	-6,567	13,971 (15.6)	19,497 (13.6)	19,497
1989-90 (अ)	3,107 (42.3)	1,609 (40.8)	+ 1,498	13,519 (14.7)	19,663 (7.1)	-6,144	16,626 (19.0)	21,272 (9.1)	-4,646
1990-91	3,069	1,599	+ 1,470	15,073	22,474	-7,400	18,113	24,073	-5,930
1991-92 (अ)	1,765 (-42.5)	793 (-50.4)	+ 972	16,075 (6.6)	18,603 (-17.2)	-2,528	17,840 (-1.7)	19,396 (-19.4)	-1,556

टिप्पणी: 1 वर्ष 1989-90 के अन्तिम आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अक संकलन महानिदेशालय से उपलब्ध नहीं हुए।

2 कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

3. 1989-90 तक र. भु. क्षेत्र के देशों में पांच देश अर्थात् मोरिशस संघ, रुमानिया, चेकोस्लावाकिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और पोलैंड शामिल हैं। 1990-91 से उक्त में से पहले के तीन देश शामिल हैं।

3 अ-अन्तर्निम्न

परिमित सारणी 6.8: बाहरी सहायता

करोड़ रुपये															मिलियन अमरीकी डालर				
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1. ऋण	2,493	3,176	4,574	4,738	5,138	6,170	10,215	2,038	2,485	3,528	3,272	3,086	3,4399	4,174					
2. अनुदान	443	429	478	566	665	534	863	362	336	368	391	399	297	353					
3. सकल उपयोग	2,936	3,605	5,052	5,304	5,803	6,704	11,078	2,400	2,821	3,896	3,663	3,485	3,736	4,52					
4. चुकोती राशियाँ	776	1,176	1,581	1,646	1,987	2,329	3,559	634	920	1,219	1,137	1,193	1,298	1,455					
5. निवल	2,160	2,429	3,471	3,658	3,816	4,375	7,7519	1,766	1,901	2,677	2,526	2,292	2,438	3,072					
(3-4)																			

टिप्पणी: 1. ऋणों में गैर-सरकारी ऋण शामिल हैं, परन्तु आनिर्कती ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।

2. अनुदानों में पी. एन. 480-A अनुदान शामिल नहीं है।

3. सं-संगठित

4. अ-अनर्पित

5. आंकड़े अमरीकी डालर में वार्षिक दरों पर परिवर्तित किये गये हैं।

स्त्रोत: सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, भारत सरकार

प्रतिष्ठित मासिकी VI. 9 : प्रतिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा प्रतिवासी रुपया खाता योजनाओं के अन्तर्गत समाविष्ट की गयीं हैं।

(करोड़ रुपये)

मास के अंत में	प्रतिवासी विदेशी रुपया खाता										विदेशी मुद्रा प्रतिवासी खाता					कुल आवक		वर्षाया राशियों का कुल जोड़	
	वर्ष के दौरान आवक	कुल बकाया	वर्ष के दौरान आवक (2)	पॉड स्टनिंग	ड्यूय मार्क	यंत जोड़ (8 से 11 तक)	करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये	मिनिमम करोड़ रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1987	477	373	4,336	3,354	1,173	918	3,047	646	—	—	3,511	2,720	1,650	1,291	7,847	6,974	—	—	—
1988	477	368	5,107	3,942	1,363	1,051	4,406	541	—	—	4,947	3,827	1,840	1,419	10,540	7,769	—	—	—
1989	235	162	5,899	3,774	2,230	1,540	6,648	535	700	372	8,255	5,275	2,465	1,702	14,164	9,049	—	—	—
1990	277	176	6,507	3,777	2,165	1,309	9,304	337	1,208	655	11,324	6,536	2,442	1,475	17,831	10,363	—	—	—
1991	156	84	7,349	3,743	255	168	11,270	305	1,09	825	13,045	6,838	411	252	23,754	10,581	—	—	—
1992	44	27	8,071	2,591	3,641	1,627	10,300	2,002	447	859	13,608	5,256	3,256	—1,654	21,679	7,847	—	—	—

(1) अनुमानित प्रारंभिक बकाया को छोड़कर

* प्रारंभिक बकाया सहित

(2) (1) प्रारंभिक बकाया सहित न किया जाए

टिप्पणी :

1. कोष्ठकों में दिखे हुए अंकड़े संबंधित मुद्राओं में मिनिमम में बकाया तथा राशियां हैं।

2. अन्तर्गत नौ वर्गों में परिवर्तन प्राप्ति के मामले में वार्षिक औसत दर अष्ट तथा बकाया राशियों के मामले में वार्षिक दर पर किया गया है।

परमेशिष्ट मारुणः $\forall L, \cdot 0$: विदेशः सृष्टः अनिवार्यो खलु के जलराशिर्गो पर द्वाज दरे

		अनर्क, की डॉलर										पॉइलरिंग				ड्यूग मार्क				येत					
		6 महीने व उमसे अधिक तथा 1 वर्ष से कम				2 वर्ष व उमसे अधिक तथा 2 वर्ष से कम				3 वर्ष व उमसे अधिक तथा 3 वर्ष से कम				6 महीने व उमसे अधिक तथा 1 वर्ष से कम				2 वर्ष व उमसे अधिक तथा 2 वर्ष से कम				3 वर्ष व उमसे अधिक तथा 3 वर्ष से कम			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
प्रतीक्षा वर्षिक		9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00								
30 मई 1990		9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25								
19 जून 1990		9.00	9.25	9.75	10.00	1.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50								
13 अगस्त 1990		9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	9.00	9.25	9.25	9.25								
3 सितम्बर 1990		9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.25	9.50	9.75	9.75								
25 सितम्बर 1990		8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.50	9.75	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00								
4 दिसम्बर 1990		8.25	8.50	9.00	9.25	11.50	11.75	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50								
14 जनवरी 1991		7.50	8.00	8.50	9.00	13.25	13.25	13.25	13.25	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50								
8 फरवरी 1991		6.50	6.75	7.25	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	7.50	7.50	7.50	7.50								
11 दिसम्बर 1991		5.50	5.75	6.75	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	10.25	10.25	10.50	10.50	7.00	7.00	7.00	7.00								
29 जनवरी 1992		5.75	6.25	7.50	8.25	12.00	12.00	12.00	12.00	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	6.00	6.00	6.50								
27 मार्च 1992																									

परिशिष्ट सारणी VI, 11 : भारत के विदेशी ऋण

(करोड़ रुपये)

सर्वे	निम्नलिखित वर्षों के माब के अन्त में						
	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. मध्यवर्ती और दीर्घावधि							
1. विदेशी सहायता +	24,004 (19,311)	32,312 (24,711)	36,578 (29,182)	46,838 (29,872)	54,101 (32,145)	66,314 (34,281)	109,981 (38,101)
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	4,888 (3,932)	5,548 (4,791)	4,732 (3,356)	3,696 (1,364)	2,573 (1,494)	5,145 (2,623)	8,935 (3,451)
3. बाहरी वाणिज्यिक उधार*	6,908 (5,558)	11,243 (8,697)	13,543 (10,455)	19,147 (12,249)	23,661 (13,735)	29,007 (14,782)	57,389 (16,080)
4. जोड़ (1 + 2 + 3)	35,800 (28,801)	49,103 (37,699)	54,853 (42,993)	69,681 (44,485)	80,335 (47,374)	100,466 (51,686)	171,305 (57,632)
आ. अनिवार्य भारतीय जमा राशि	3,819 (3,075)	7,847 (6,073)	10,054 (7,770)	14,154 (9,049)	17,831 (10,363)	20,754 (10,584)	21,679 (7,847)
इ. कुल (अ + आ)	35,619 (31,876)	56,950 (43,772)	64,907 (50,763)	83,835 (53,534)	98,166 (57,737)	121,220 (62,270)	193,984 (65,479)
ई. अल्पावधि	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
उ. कुल जोड़ (इ + ई)						130,638 (67,070)	201,671 (68,670)
आपस मदें							
1. ऋण स्टॉक (दीर्घावधि-तथा मध्यावधि तथा अनिवार्य भारतीय जमा राशि) निर्यात अनुपात @ (प्रतिशत में)	201	270	258	272	247	259	303
2. ऋण भुगतान अनुपात** (संबद्ध राजकोषीय वर्ष के लिए) (प्रतिशत में)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

+ सर सरकारों शामिल नहीं है।

* इसमें बाहरी सहायता कार्यक्रम के अर्ध-नगर सरकारों ऋण और पूर्वी यूरोपीय देशों से रुपये में प्रतिव्यय आपूर्तिकर्ता के ऋण शामिल हैं।

** अनिवार्य भारतीय जमा राशियों पर प्रोद्भूत व्याज शामिल है।

@ नियति में व्यापारिक धनस्थों और सरकारी अंतरणों को छोड़कर अदृश्य प्राप्तियों के नि नि शामिल हैं।

टिप्पणी : अ = अनन्तिम

1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े अमरीकी डालर को मिलियन में दर्शाते हैं।

2. वर्ष 1992 के आंकड़ों के अन्तर्गत विदेशी सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधार, अनिवार्य (विदेशी) तथा खता जमा राशि तथा ई.ए.एफ. से इतर अल्पावधि ऋणों को बाजार दर पर बदला जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत विकास बांड तथा बी.ए.एफ. के अंतर्गत अल्पावधि ऋण को आधिकारिक दर पर बदला जाता है।

3. वर्ष 1992 के वाणिज्यिक उधार में 4214 करोड़ रुपये (1627 मिलियन अमरीकी डालर) के भारत विकास बांड को शामिल किया गया है।

4. अनिवार्य भारतीय जमा राशियों के अन्तर्गत अनिवार्य (विदेशी) रुपया खाता में उस पर प्रोद्भूत व्याज को शामिल नहीं किया जाता है।

5. उद्येक आंकड़ों में अनिवार्य भारतीय जमा राशि और अल्पावधि ऋण शामिल है। किन्तु वे विदेशी ऋण सांख्यिकी पर प्रस्तुत हान की रिपोर्ट में प्रस्तुत परिभाषा और वर्गीकरण के अनुसार नहीं है।

परिशिष्ट सारणी VI. 12. रुपये की बित्तिय दरें
(विशेष आहरण अधिकार/विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के बराबर रुपये)

अवधि	विशेष आहरण अधिकार	अवरोध डॉर	पौड स्ट्रिंग	भूख मार्च	जायता येन
1	2	3	4	5	6
घ. वार्षिक औसत दरें*	17.1208	12.9658	22.0872	7.4004	0.0941
(अप्रैल-मार्च)					
1987-88					
1988-89	19.2619	14.4817	25.5959	8.0494	0.113
	(-11.1)	(-10.5)	(-13.7)	(-8.10)	(-16.7)
1989-90	21.3684	16.6492	26.9179	9.0922	0.1166
	(-9.9)	(-13.0)	(-4.9)	(-11.5)	(-3.1)
1990-91	24.8491	17.9428	33.193	11.4351	0.127
	(-14.1)	(-7.2)	(-18.9)	(-20.5)	(-8.8)
1991-92	33.4325	24.4737	42.5152	14.6248	0.1845
	(-25.7)	(-26.7)	(21.9)	(-21.8)	(-30.7)
घा. मासिक औसत दरें					
मार्च 1991*	26.6358	19.2009	36.0742	11.9658	0.14
मार्च 1992*	35.3472	25.8901	44.6775	15.6033	0.1949
मार्च 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	--	29.4551	51.9588	18.1709	0.227
मार्च 1991 की तुलना में मार्च 1992 में प्रतिशत	(-24.64)	(-25.84)	(-21.49)	(232.3)	(-28.17)
मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-)					
जून 1991*	27.7772	21.0053	34.6572	11.7874	0.1394
जून 1992*	36.5507	25.8900	47.7889	16.4646	0.2043
जून 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	--	30.2361	55.9065	19.1931	0.2383
जून 1991 की तुलना में जून 1992	(-24.02)	(-18.87)	(-27.48)	(-28.41)	(26.38)
में % मूल्य वृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-)					
घ. निम्नलिखित की बित्तिय दरें					
29 मार्च 1991*	26.3457@	19.6429	34.1	11.4784	0.1391
31 मार्च 1991*	35.5143	25.8900	44.949	15.7294	0.1948
31 मार्च 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	--	31.2556	53.6913	18.8501	0.2328
28 जून 1991	27.855	21.0410	34.36	11.739	0.1523
30 जून 1992	37.053	25.8900	49.2789	17.0182	0.2061
30 जून 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	--	30.8607	58.4795	20.2429	0.246

* रिजर्व बैंक की अधिकारित दर दर्शाता है।

** भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की संकेतित दरें दर्शाता है।

@ विनांक 28-3-91 को

टिप्पणी. कोष्ठकों में दिये आंकड़े रुपये की प्रतिशत मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-) दर्शाते हैं।

[सं. एफ 19/19/92-बी. बी.-I]

एम. एल. सोलारामन, अवसर अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th September, 1992

S.O. 1394.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1992 :—

THE ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

for the Year July 1, 1991 to June 30, 1992

PART ONE—ECONOMIC REVIEW

I. Policy Developments and Perspectives

1.1 The year 1991-92 (July-June) was a landmark period in terms of undertaking strong policy measures to quickly stabilise the economy and also introducing a process of basic reforms.

1.2 The preceding decade had seen an acceleration in economic growth but the relatively high rate of growth of GDP was also associated with macro-economic imbalance and the persistence of structural rigidities, a certain degree of which constrained the sustainability of the growth process. Continuing macro-economic imbalance and a delay in taking corrective action in time accentuated the impact of global economic shock of 1990.

1.3 Large and growing fiscal deficit with a sizeable component of monetised deficit, inevitably resulted in rapid growth of monetary liquidity far out of alignment with the real economic growth, thereby generating severe demand pressure and accelerating the pace of inflation. These imbalances in turn spilt over onto the external sector in the form of a large and unsustainable current account deficit. The persistently high levels of fiscal deficit and current account deficit on the balance of payments (BOP) gave rise to a sizeable public debt, both domestic and external. The country was faced by a risk of default on external debt servicing during the early months of the fiscal year 1991-92. The strain on external and internal resources, the threat to monetary stability and the resultant inflationary process, had begun to affect adversely the goals of development. Inflation, which by itself hurts the real income of the poor, had another consequence in that it had also begun to hinder investment plans both in the public and private sectors giving rise to distortions in production and employment generation. The situation called for strong stabilisation measures : fiscal correction, monetary tightening, inflation control, and strengthening of the competitiveness of India's exports.

1.4 To carry forward the benefits of stabilisation measures on an enduring basis, longer-term issues of structural rigidities and impediments to growth have also had to be addressed. First, the myriad of controls and regulations with the consequent growth of bureaucratic intervention inhibited the spurt of enterprise and initiative. Secondly, with the diversification of the domestic market the community at large was seeking far more efficient and competitive products. Thirdly, technology was not catching up with that in the outside world especially in those countries which were competing with us. The impetus to technological development in India hitherto originated essentially through public sector projects and a few large private sector investments and all through State-directed planning. Any further development in this area could only be based on a broad-based initiative arising from competition and market efficiency. Fourthly, the absorption of substantial resources in the public sector, to the extent it was in areas which did not provide adequate returns, had begun to crowd out private sector investment. Finally, the world setting underwent a major change. Aid availability dwindled; the reduction of aid availability and the arithmetic of balance of payments required that the country had to move towards the goal of earning what it had to pay for its imports of goods and services. Exports demanded a higher quality consciousness

and competitive technology. Markets abroad, which became highly price sensitive, showed sensitivity to quality, service and technology, besides price. Foreign direct investment and foreign tie ups/collaborations were becoming a major instrument of technology transfer and networking in respect of market shares. Unless the country participated in the global market, further accelerated growth of exports, in particular and the economy in general were no longer possible. Studies on country experiences show that entrepreneurs become dynamic and forward-looking in environments of export-orientation, whereas in excessive import-substitution situations, they tend to acquire a dependent psychology and lose dynamism. Above all, the soft option of continuing exemptions from fully participating in the open multi-lateral trading system implied in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) rules and regulations became difficult. Thus, the logic for liberalisation and structural reforms, for introducing competition amongst business enterprises in both domestic and outside markets, was overwhelming.

1.5 It is against this background that since 1991 the authorities have addressed with utmost speed and determination, the issues of both stabilisation and structural reforms. Fiscal correction, exchange rate adjustment and reform, monetary targets and inflation control constituted the immediate measures for macro-economic stability which were simultaneously supported by structural reforms in the form of industrial deregulation, liberalisation of foreign direct investment, trade liberalisation, overhauling of public enterprises and financial sector reforms. The immediate stabilisation measures and the longer-term structural reforms can pose problems of prioritisation of measures such as, for example, between the goals of fiscal correction and fiscal consolidation, and between monetary control measures and financial sector reforms.

1.6 Even as the measures of stabilisation and structural adjustment were dominating the economic scene during 1991-92, determined efforts were made to bring the external liquidity crisis under control. As a result, there was a remarkable turnaround achieved in the country's foreign currency assets from less than US \$ 1.0 billion in the middle of July 1991 to US \$ 5.6 billion by the end of March 1992 and further to US \$ 6.2 billion by the end of June 1992. Drastic import compression measures were combined with efforts to encourage the inflow of resources into the country by non-resident Indians. This was also supplemented by exceptional financing by bilateral and multilateral agencies. The merchandise deficit, on a payment basis, declined from US \$ 7.7 billion in 1990-91 to US \$ 3.1 billion in 1991-92 and correspondingly, the current account deficit fell steeply from US \$ 7.7 billion to US \$ 2.8 billion.

FISCAL CORRECTION AND CONSOLIDATION

1.7 The origin of the recent macro-economic crisis is closely linked to the imbalances in the fiscal sector. The Central Government's gross fiscal deficit was equivalent to 8.4 per cent of GDP at current market prices in 1990-91 as against 6 per cent at the beginning of the 1980s and 3 to 4 per cent in the mid-1970s. More significantly, it is the emergence of a persistent and growing deficit on Revenue Account of the Central Government during the 1980s (around 3.5 per cent of GDP in 1990-91) that has been a cause of concern in the fiscal scene. Yet another aspect is the large size of the monetised deficit which, apart from generating excess liquidity in the economic system, has rendered difficult the attainment of the monetary policy objective of price stability. The fiscal deficit has resulted in growing indebtedness—both internal and external—which now constitutes about 57 per cent of GDP. With the onerous burden of debt servicing, interest burden of the Centre alone now forms 4.4 per cent of GDP and over 20 per cent of total expenditure. The continuous increase in Government expenditure, particularly on budgetary subsidies, together with an inadequately elastic response from the tax system and continuing losses of the public sector, has contributed to the budgetary gap. Apart from the spillover of these fiscal imbalances on to the external sector in the form of current account deficit, the disproportionate reliance on Customs revenue for resources (nearly 46 per cent of the Centre's net tax revenue) has tended to result in an ex-

cessively protected and sheltered market for Indian industry with its adverse implications for efficiency, technological upgradation and export competitiveness. Finally, the Government's draft on resources on an increasing scale has affected their availability for more productive activities in other sectors of the economy.

1.8 Against the above background, Government have in turn, set before themselves the medium-term objective of substantially reducing the Central Government fiscal deficit (to approximately 3 to 4 per cent of GDP) as well as the overall public sector deficit. The fiscal adjustment programme for 1991-92 visualised a sharp reduction in gross fiscal deficit of the Centre from 8.4 per cent in 1990-91 to 6.5 per cent in 1991-92, which was broadly attained. In fact, the adjustment was much sharper in terms of the primary deficit (fiscal deficit minus net interest payments) from about 6.0 per cent to 3.5 per cent. The reduction in the Centre's fiscal deficit was made possible by reducing expenditure (including net lending) to GDP ratio by about 1.4 percentage points, the reductions being related to non-interest current expenditures like export subsidies, non-Plan grants to States and Union Territories and some moderation in defence expenditure. In addition, capital expenditure was brought down in 1991-92 to achieve the desired reduction in fiscal deficit. Some adjustments were also effected on the resources side, through mobilisation of additions revenue and disinvestment in the equity holding of public sector enterprises.

1.9 The Centre's Budget for 1992-93 has carried forward the fiscal adjustment programme with the overall deficit slated to decline to 5 per cent of GDP. Almost the entire part of the adjustment is to be attained by arresting expenditure growth. In fact, according to the Central Budget for the year, the non-interest non-Plan expenditure taken together would be lower than that for 1991-92. Thus, again, if the increased burden were taken into account, the estimated primary deficit would recede from 3.5 per cent of GDP in 1991-92 to less than 2.3 per cent in 1992-93. In order to achieve this, the net market borrowing of the Centre has been pegged at Rs. 5,000 crore, a third lower than the level of Rs. 7,500 crore during 1991-92. Reduction in interest burden will, however, be achieved only over a period as the reduction in Government borrowings, as also in monetised deficit, has to be accompanied by reforms to place the debt at market-determined yield rates, transparency in the cost of borrowings by the Government, financial sector reforms, and the importance assigned to monetary management.

1.10 Apart from yet another 1.0 percentage point reduction in the expenditure (including net lending) to GDP ratio, the 1992-93 Budget has sought to initiate major changes in the tax structure by drawing upon the recommendations in the interim Report of the Chelliah Committee on tax reforms. The measures proposed in the area of direct taxes aim at simplification and rationalisation of the tax structure, as also widening its base. In the area of indirect taxes, the thrust of the Budget proposals is on encouraging competitiveness of Indian industry by bringing the Customs tariff rates in line with those in competitor countries, reducing the dispersion of tariff rates, rationalising the excise duty structure, and increasing the rates of excise duties selectively on certain non-essential commodities so as to raise additional resources to offset the revenue loss from restructuring of Customs tariffs. The process of structural adjustment and macro-economic stabilisation initiated in 1991-92 is thus being consolidated in 1992-93. The reforms proposed in the Budget, together with a sharp reduction in the fiscal deficit, are expected to lead to a buoyant industrial sector, create additional employment opportunities, reduce external payments problems and simultaneously bring down inflationary expectations. The Budget has initiated a process by which a sustainable fiscal balance could be brought about in the medium term.

MONETARY POLICY : OBJECTIVES AND INSTRUMENTS

1.11 Since 1989-90, monetary policy has had to contend with a growing fiscal deficit and persistent overhang of liquidity, leading to a resurgence of inflation. Superimposed on it was a deteriorating balance of payments situation, particularly

after the Gulf crisis. Thus, containing aggregate demand and, in particular, demand for imports, became an overriding consideration in the policy actions of the Reserve Bank of India during the latter half of 1990-91 and the first part of 1991-92. Despite the major preoccupation with short-term management, the longer-term objectives of promoting operational efficiency of the financial system and developing the money market were pursued. Simultaneously, the endeavour was to support the cohesive package of measures of macro-economic stabilisation and structural reforms initiated by the Government since July 1991. In this respect, the recommendations of the Committee on the Financial System (Chairman : Shri M. Narasimham) have had an important bearing on the formulation of monetary policy.

1.12 There were four major strands of specific credit policy measures during the period under review. The first set of measures aimed at import containment. As opposed to quantitative restrictions on imports, such measures as imposition of cash margins (which for a while ranged between 50 per cent and 200 per cent) and the increase in the cost of import finance through the imposition of a 25 per cent interest rate surcharge, were perceived as non-discretionary ways of containing imports. The second set of measures stemming from the restrictive monetary policy stance had also been undertaken to contain the current account deficit on the balance of payments. For a given level of income, reducing expenditures, or absorption, essentially means reducing the overall monetary demand and also inflation in the system. The reductions in the overall demand and inflation do not, however, translate themselves immediately into an improvement in the balance of payments. They have to work through several links in the system and depend upon such parameters as marginal propensity to import out of income. Combined with the containment of the fiscal deficit a regime of tight money and credit, apart from facilitating control of inflation, also results in greater economy in the use of resources.

1.13 The third set of measures were a response to an improvement in the foreign exchange situation and some slowing down of the annual rate of inflation. These measures included withdrawal of stipulations relating to cash margins on imports and some moderate lowering of lending rates in respect of large borrowers.

1.14 A final set of measures originated in the fiscal adjustment and a combination of macro-economic stabilisation and structural reforms undertaken by the Government in the context of which it was considered feasible to moderate the levels of statutory pre-emptions in terms of cash reserve ratio (CRR) and the statutory liquidity ratio (SLR). As part of the proposals for reforming the financial sector, the Narasimham Committee on the Financial System had recommended a reduction in pre-emptions of banks' resources. In response, the Government have agreed to meet their borrowing needs increasingly from the market instead of pre-emption of bank's resources. With this end in view and as part of the overall effort to develop the Government securities market which would also provide a major step towards evolving better tools of monetary control, the Government of India introduced three new instruments, viz., 364-day Treasury bills and 5-year and 10-year dated securities, all on an auction basis. The further rationalisation of lending rates and substantial freedom given to banks to determine deposit maturities and deposit rates also constitute a part of the above reform programme.

1.15 The key macro-economic assumptions underlying the monetary targets for 1991-92 were a real GDP growth of 3 to 3.5 per cent, an inflation rate of not more than 9 per cent, and a significant slowdown in M3 expansion to about 13 per cent. The import compression, credit restriction and fiscal adjustment measures, had an impact on the overall growth rate and in the event, the GDP growth turned out to be a little less than 2.0 per cent and in particular, there was a total stagnation in industrial output. Even so, the M3 expansion accelerated to as high as 18.5 per cent in 1991-92 which was attributable to the domestic expansion of primary liquidity and the larger-than-protected foreign exchange accruals. Since the inflows of foreign exchange were

of overriding priority, measures of sterilising the inflow of these resources were not undertaken lest the measures should dampen such inflows.

1.16 The monetary policy for the first half of 1992-93 was undertaken against the background of the need to revive industrial and agricultural production and encourage exports while keeping in mind the primacy of the objective of inflation control. Monetary policy was formulated against the Government's declared objective of reducing the gross fiscal deficit from 6.5 per cent of GDP in 1991-92 to 5 per cent of GDP in 1992-93. The objective of overall policy is to bring down the rate of inflation to 8 per cent. With this end in view, the Central Government has planned to reduce the budget deficit (and the monetised deficit) to Rs. 5,389 crore in 1992-93. To realise the full anti-inflationary impact of the reduction, it was recognised that the monetised deficit should be moderated throughout the year and not merely at the end of the financial year. If the monetised deficit is moderated over the year it would then be possible to bring monetary expansion (M3) from 18.5 per cent in 1991-92 to less than 11 per cent in 1992-93.

1.17 The rationale of the important monetary and credit policy measures during the period under review are set out below:

(a) Interest Rates

(i) Bank Rate

1.18 The Bank Rate as an instrument of monetary policy had been dormant and had remained unchanged since July 1981. In the context of the inflationary pressures, and the need to evolve a benchmark Reserve Bank rate it was considered opposite to activate the Bank Rate instrument. Accordingly, the Bank Rate was raised from 10.0 per cent to 11.0 per cent per annum with effect from the close of business on July 3, 1991, and further raised to 12.0 per cent per annum with effect from the close of business on October 8, 1991.

(ii) Lending Rates

1.19 During the period under review lending rates were modified four times with a view to ensuring that the rates reflected the underlying inflation in the economy and the need for charging positive real rates of interest. First, in the context of the need to reduce aggregate demand in the economy as also taking into account the increase in deposit rates, effective July 4, 1991 the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh was raised by 1.5 percentage points to 18.5 per cent (minimum). Second, perceiving that a number of lending rates had become negative in real terms in the context of the prevailing high inflationary pressures, lending rates of scheduled commercial banks were raised across the board by 1.5 percentage points, with effect from October 9, 1991. Third, since the minimum lending rate for limits over Rs. 2 lakh was raised from 16 per cent to 20 per cent between April 1991 and October 1991, effective March 2, 1992, the lending rate to borrowers with credit limits of over Rs. 2 lakh was reduced by one percentage point as a cautious response to some abatement of the inflation rate. Finally, as part of a process of progressive rationalisation of the banks' lending rate structure, effective from April 22, 1992 the existing six categories of lending rates were reduced to four (Appendix Table 1.1 presents the changes in the structure up to April 22, 1992).

(iii) Deposit Rates

1.20 There were a few revisions in the banks' deposit rate structure during the period under review essentially to provide for positive real rates of interest on bank deposits. First with a view to ensuring that banks finance their lending operations out of their own resources and to enable banks to compete with alternative savings instruments, the term deposit rates of scheduled commercial banks were raised cross-the-board by one percentage point effective July 4 1991. Secondly, to ensure competitiveness of bank deposits and to provide a better rate of return on short-term surplus funds as high inflation rates had rendered deposit rates at the short-end unremunerative, interest rate on term deposits (excluding

FCNR and NRE deposits) of scheduled commercial banks with a maturity of 46 days to less than one year was raised from 9.0 per cent per annum to 11.0 per cent per annum effective October 9, 1991. Simultaneously, for a better alignment of the return on short-term deposits, term deposit rate with maturity of one year to less than 2 years was raised from 10.0 per cent to 12.0 per cent, while that on deposits with maturity of two years to less than three years was increased from 11.0 per cent to the same 12.0 per cent. This resulted in setting the rate for deposits of one year and above but less than three years at 12.0 per cent per annum. Deposits with maturity of 3 years and over remained unchanged at 13.0 per cent per annum. At the third stage, as a step towards reform in the regulation of the banks' deposit rate structure, with effect from April 22, 1992, the rates on term deposits (excluding FCNR and NRE deposits) of all maturities of 46 days and over were made subject to a single prescription of 'not exceeding 13.0 per cent per annum'. Banks are now free to determine the maturities and deposit rates within the single ceiling rate of 13.0 per cent per annum (Appendix Table 1.2). Effective April 24, 1992, the interest rate on savings deposits was raised by one percentage point to 6.0 per cent per annum.

(b) Relaxation on Imports

1.21 Upto the first half of 1991-92, when there was the overriding necessity to contain imports the monetary policy measures were progressively tightened which culminated in the imposition of cash margins as high as 200 per cent on imports (other than capital goods) under OGL and 150 per cent on imports (other than capital goods) under specific licences, with effect from April 22, 1991. Furthermore, effective May 9, 1991, an interest surcharge of 25 per cent was levied on bank lendings for all types of import finance.

1.22 Subsequently, as the foreign exchange reserve position showed rapid improvement, gradual relaxations were effected in the general minimum cash margin requirement from 200 per cent to 150 per cent on October 8, 1991, to 50 per cent on December 9, 1991, to 25 per cent on January 1, 1992 and finally withdrawn effective from February 12 1992; banks can now decide the form and size of margin based on their own prudential considerations. Likewise, the 25 per cent interest rate surcharge on import financing was rescinded effective from February 13, 1992.

(c) Incentives for Exports

(i) Export Credit Refinance

1.23 In view of the paramount need to promote exports and also to provide greater incentive to banks to render export credit, the export credit refinance formula was liberalised and banks' access to funds under the facility was increased. Since July 27, 1991 banks were being provided export credit refinance under a two-tier formula amounting to 50 per cent of the increase in export credit over the monthly average level in 1988-89 plus 100 per cent of the increase over the monthly average level of export credit in 1989-90. With effect from September 4, 1991, refinance limit under the first tier was raised to 60 per cent while continuing export credit refinance of 100 per cent under the second tier. To provide additional incentive to banks for extending export credit, the refinance under the second tier was raised to 110 per cent effective November 2, 1991 and further to 125 per cent from December 28, 1991. With a view to encouraging banks to continue to provide greater support to the export sector the usual bringing forward of the base for determining export refinance was not undertaken in April 1992; this has resulted in a very sharp increase in the export refinance access for banks.

(ii) Interest Rates on Export Credit

1.24 In view of the low rates of interest on export credit banks have been finding it unremunerative to lend to the export sector. Moreover, with large interest rate differentials as between export credit and other credit, there was a strong possibility of seepage of credit. To provide greater incentive to banks and to enable them to provide credit support to the export effort, interest rates on pre-shipment and post-shipment export credit were raised. The export credit interest rates were raised in August 1991 after the interest rate subsidy on export credit was withdrawn and again in October 1991 as part of the general increase in lending rates

(Appendix Table 1.3). With the reduction in minimum lending rate for credit limits of over Rs. 2 lakh with effect from March 2, 1992 the rates of interest in respect of post-shipment credit beyond 90 days from the date of shipment as also export credit not otherwise specified have also been reduced by one percentage point from the existing rates.

(iii) Relaxation of Cash Margin on Export-related Imports

1.25 As part of export promotion measures, a series of relaxations were effected in the prescribed cash margins in respect of imports (other than capital goods) related to exports. The stipulated extent of actual export realisations up to which, on certain imports (other than capital goods), manufacturer-exporters were allowed to import goods without cash margins, was enhanced.

(iv) Refinance Scheme for Post Shipment Export Credit Denominated in US Dollars

1.26 A Scheme of Post-Shipment Export Credit Denominated in Foreign Currency was introduced effective January 1, 1992. The objective of the Scheme is to provide a facility to exporters to avail of post-shipment export credit denominated in foreign currency and pay interest at rates applicable for the foreign currency concerned. A new refinance facility called 'Refinance Scheme for Post-Shipment Export Credit Denominated in U. S. Dollars' was introduced effective January 4, 1992. Under this Scheme refinance is provided to banks equivalent to 133-1/3 per cent of the post-shipment export credit denominated in U.S. dollars, provided by banks to the exporters. In order to make dollar-denominated export credit scheme more attractive, the rate of interest on refinance under this Scheme was reduced from 7.5 per cent per annum to 5.5 per cent per annum with effect from April 22, 1992, while the rate of interest on post-shipment export credit (dollar-denominated) was retained at 6.5 per cent per annum. The Scheme provides banks with a strong incentive to provide dollar-denominated post-shipment export credit to exporters.

(v) Export Credit (Rupee) Refinance

1.27 When pre-shipment and post-shipment export credit interest rates were raised in August and October 1991, the export refinance rate was not raised so as to enable banks to have some time to phase in the new lending rates on export credit. Hence, effective April 22, 1992, the interest rate on export credit (rupee) refinance was raised from 9.5 per cent per annum to 11.0 per cent per annum.

(vi) Delegation of Powers to Banks to Grant Pre-shipment Credit for Periods Beyonds 180 Days

1.28 With a view to supporting export efforts and giving operational flexibility to banks, Reserve Bank has delegated powers to banks to allow extension of period for pre-shipment credit by 90 days in cases where the exporters have not been able to ship the goods within the permitted period of 180 days for reasons beyond their control. Powers have also been delegated to banks to sanction pre-shipment credit up to 270 days ab initio in respect of any commodity which would need credit for such a long duration.

(d) Measures Relating to Reserve Requirements

1.29 Reserve requirements have been a major instrument of control of liquidity in India. The SLR, though originally conceived as a prudential measure, has been partially serving the purpose of meeting the Government's borrowing requirements at less than market-related rates. With successive increases in reserve requirements, this instrument was increasingly becoming counter-productive as it affected the profitability of banks. The Narasimham Committee on the Financial System inter alia recommended that the SLR be brought down in a phased manner.

(i) Statutory Liquidity Ratio (SLR)

1.30 In the context of fiscal adjustment and macro-economic stabilisation undertaken by the Government, it was considered feasible to moderate the existing levels of statutory pre-emptions. Considering the anticipated decline in 1992-93 in the monetised deficit of the Centre and the reduction in the Centre's market borrowing programme, it was decided to reduce the statutory liquidity ratio on an incremental basis. Accordingly, up to the level of the outstanding net demand and time liabilities (excluding non-resident liabilities) as on April 3, 1992, the SLR will remain unchanged at 38.5 per cent and for any increase in net demand and time liabilities above the April 3, 1992 level, the SLR would be 30 per cent.

The SLR of 30 per cent in respect of non-resident liabilities would remain unchanged. It may be mentioned that the deposits mobilised under the Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme and Foreign Currency Accounts opened under Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) are fully exempted from both CRR and SLR requirements.

(ii) Incremental Cash Reserve Ratio

1.31 The Narasimham Committee had recommended that the cash reserve ratio should continue to be used as an instrument of monetary control though it was recognised that the existing levels were high and needed to be brought down.

1.32 During the critical period in the first half of 1991, a 10 per cent incremental cash reserve ratio was introduced in May 1991. It was recognised that the continuation of a 10 per cent incremental cash reserve ratio (CRR) in addition to the average ratio of 15 per cent would not be feasible for any extended period as it would greatly restrict the flow of credit to the productive sectors. Moreover, it would not be prudent to continue crisis management measures over a prolonged period. Accordingly, banks were exempted from maintenance of the 10 per cent incremental CRR for any increase in net demand and time liabilities (DTL) over the level as on April 17, 1992@.

(iii) 'Interest on Banks' Cash Balances held with the Reserve Bank of India

1.33 Over the years the CRR has been raised and at the same time the interest on cash balances has been raised to shore up bank profitability. Since payment of interest on cash balances attenuates monetary control the cash reserve had to be raised even further. Had interest not been paid on cash balances, the CRR could have been prescribed at a much lower rate to achieve the same level of monetary control. With a view to curtailing the increase in reserve money, it was considered necessary to moderate the total interest payments made by the Reserve Bank of India to banks on their eligible cash balances under the two-tier formula. The modifications were made in two stages during the year. With effect from the fortnight beginning October 19, 1991 (i) on the eligible cash balances based on the net DTL as of March 23, 1990 interest was continued to be paid at a rate of 10.5 per cent per annum, (ii) on the increase in eligible cash balances based on the net DTL maintained after March 23, 1990 under the average 15.0 per cent CRR as well as eligible cash balances under the 10.0 per cent incremental CRR, interest was paid at a reduced rate of 5.0 per cent per annum (as against 8.0 per cent per annum till then). The later rate was further reduced to 3.0 per cent per annum with effect from the fortnight beginning May 2, 1992.

(e) General Credit Measures

(i) Incremental Net Non-food Credit (Excluding Export Credit).—Deposit Ratio

1.34 As part of the credit policy for the first half of the financial year 1991-92, banks were required to ensure that their incremental net non-food credit (excluding export credit)-deposit ratio did not exceed 45 per cent in 1991-92. To ensure strict compliance, it was decided in October 1991 to automatically reduce refinance limits to banks which exceed this ratio for two successive fortnights for the next four fortnights and to reduce refinance limits for the subsequent two fortnights for banks with excess credit in each subsequent fortnight. Banks which persistently violated the stipulated ratio faced a total withdrawal of refinance facilities.

1.35 The banking system as a whole observed this guideline in 1991-92 and the continued prescription of an incremental net non-food credit-deposit ratio was not considered necessary for 1992-93. Accordingly, the stipulation of an incremental credit-deposit ratio was withdrawn in April 1992. Banks have been advised to normalise credit facilities to support the revival of productive activity in the agricultural and industries' sectors in particular the needs of the small farmers, small-scale industries and exports. They have also been advised to ensure that their lending operations are consistent with their own resources and that large and chronic mismatches between sources and uses of funds are avoided.

@The funds received under the India Development Bond were, however, already fully exempted from the incremental cash reserve ratio.

(ii) Withdrawal of Refinance Facilities to Scheduled Commercial Banks

1.36 In view of the imperative need to contain reserve money expansion in the context of severe inflationary pressures, the following refinance facilities were withdrawn effective October 9, 1991: food credit refinance; standby refinance; 182-day Treasury bill refinance; and discretionary refinance. Thus, except for export credit refinance no other refinance is now available to banks from the Reserve Bank.

(iii) Discounting/Rediscounting of Bills by Banks

1.37 The Reserve Bank's recent inspections/scrutiny of the bills portfolio of banks have revealed a number of disquieting features, tending to violate both in letter and spirit the broader objections of the bills discounting/rediscounting facility introduced by the RBI. Fresh instructions have, therefore, been issued in July 1992 to banks to ensure various norms and discipline in providing bill finance including avoidance of financing large borrowers outside the consortium arrangement, discounting accommodation bills, and deploying portfolio management funds for discounting bills, and generally restricting bill finance to the working capital needs based on credit norms. As explained below, the instructions also relate to bills portfolio of banks vis-a-vis the finance companies. Simultaneously, the Reserve Bank has cautioned the banks that any excess finance obtained by them against ineligible usance bills will be treated as borrowing and accordingly they will be required to recalculate their outside liabilities for the purpose of maintenance of CRR/SLR for the respective periods. Also, any defaults will invite the consequent penalties.

(iv) Bills Discounting/Rediscounting Facilities for Finance Companies

1.38 Bank's lending to hire-purchase and equipment leasing companies is subject to a ceiling of three times the net owned funds. While providing facilities to such companies, credit provided by way of bills discounting/rediscounting should be taken into account. Banks were advised in October 1991 that in the case of finance companies other than hire-purchase and equipment leasing companies also the former should ensure that the total credit accommodation provided by them, inclusive of bills discounting/rediscounting facilities, did not exceed three times the net owned funds of those companies. Where the lending was above this norm, banks were advised, as a first step, not to allow further drawals and to bring down the outstanding in a phased manner.

1.39 Reinforcing the above instructions, banks have been advised in July 1992 that (a) they should be circumspect in discounting bills drawn by finance companies set up by large industrial houses or other group companies, (b) they should not rediscount the bills discounted by non-bank financial companies thus desisting from providing any rediscount facility to finance companies, and (c) they should ensure that the overall credit limit provided to finance companies including bills discounting did not exceed three times the net worth of such companies.

(v) Guidelines on Portfolio Management by Banks and Subsidiaries

1.40 The Reserve Bank has observed that banks were adopting various devices for accepting funds from their clients for management, offering guaranteed rates of return on such funds, etc., with a view to avoiding compliance with the guidelines under the Portfolio Management Scheme (PMS). Therefore, the Bank has reiterated the stipulations contained in its circular of January 1991 and emphasised that violations of those stipulations would be viewed seriously and would invite deterrent action against the banks which would include raising of reserve requirements, withdrawal of refinance from the Reserve Bank, and denial of access to money markets apart from prohibiting the banks from undertaking such activity. The above stipulations will also apply to the subsidiaries of banks except where they are contrary to specific Reserve Bank or SEBI guidelines governing their operations.

(vi) Restriction on Credit to Certain Sectors :

1.41 Effective October 9, 1991, banks were required to ensure that there was no increase in the credit outstanding to each of the following sectors : (i) loans for purchases of consumer durables ; (ii) other non-priority sector personal loans; (iii) loans to individuals against shares and debentures/bonds; and (iv) real estate loans.

1.42 In the context of the easing of the pressures on banks' resources and to facilitate recovery of industrial output, the restrictions on the first two categories of loans were withdrawn with effect from April 22, 1992, while continuing the restrictions on the latter two. In addition, banks were advised to prescribe a minimum margin of 75 per cent on loans to individuals against shares and debentures/bonds effective April 22, 1992.

(f) Measures Relating to the Money Market

(i) Certificates of Deposit

1.43 Effective May 2, 1992, the limits for issue of Certificates of Deposit (CDs) by scheduled commercial banks (excluding regional rural banks) were enhanced from 5 per cent to 7 per cent of the fortnightly average outstanding aggregate deposits in 1989-90. Consequently, the aggregate limits for the banking system for issue of CDs increased from Rs. 7,537 crore to Rs. 10,431 crore. CDs issued by banks in excess of the earlier limit of 5 per cent will not be subject to CRR.

(ii) Commercial Paper

1.44 Some significant relaxations were made in the guidelines relating to Commercial Paper (CP), such as, the reduction in the working capital (fundbased) limit of a company for issue of CP to not less than Rs. 5 crore instead of Rs. 10 crore and the minimum credit rating requirement from the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) and Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) kept at P2 and A2 instead of P1 and A1 earlier, respectively.

(iii) Money Market Mutual Funds (MMMFs)

1.45 A new scheme of Money Market Funds (MMMFs) was introduced. The MMMFs can be set up by scheduled commercial banks and public financial institutions as defined under Section 4A of the Companies' Act, 1956. The limit for these funds in the case of MMMFs set up by limit would be equivalent to 2 per cent of the sponsoring bank's fortnightly average aggregate deposits during 1991-92. As MMMFs are primarily intended to be a vehicle for individual investors to participate in the money market, only individuals can subscribe to MMMFs. The minimum lock-up period would be 46 days. The investors cannot be guaranteed a minimum rate of return. Reserve requirements will not apply to MMMFs.

(g) Development of Government Securities Market & Treasury Bills

1.46 With a view to developing an active market for Government securities, the gilt-edged market is being reorganised in such a way that the Government reduces its dependence on credit from the Reserve Bank of India and the banks. This is sought to be achieved by adopting an internal debt management policy, which would serve as a tool of monetary control with flexibility of interest rates, introduction of new instruments and by liquidity expansion/contraction through open market operations. Towards achieving the above objectives, the following measures have been undertaken during the year :

1.47 (i) To develop the Treasury bill as a monetary instrument with flexible rates and to provide a financial instrument with an intermediate maturity between dated securities and the existing 91 day Treasury bill, the 182-day Treasury bill was introduced in November 1986, which has since become an attractive money market instrument. With a view to developing the Treasury bill market further and to provide financial instruments with varying short-term maturities to cater to the needs of different investors, Treasury bills of 364-day maturity were issued. In consonance with this policy, nine auctions of Treasury bills of 364-day maturity

have so far been held since April 1992 during the current financial year. The response to these auctions up to August 19, 1992 has been very encouraging inasmuch as Rs. 7,159.63 crore have been collected within a short span of about five months with a cut-off yield of 11.42 per cent each initially for five auctions and those of 11.36 per cent, 11.27 per cent, 11.20 per cent, and 11.17 per cent, respectively, for the subsequent four auctions.

1.48 (ii) In furtherance of the objective of developing dated securities of the Government of India as a monetary instrument with flexible yields to suit investor expectations, Government of India offered to sell dated securities of 5-year maturity for an aggregate amount of Rs. 1,000 crore, as also 10-year security for an equivalent amount, for the first time by auctions on June 3, 1992 and August 3, 1992, respectively. At the auction of 5-year security, 21 bids for Rs. 713 crore at a cut-off yield of 12.0 per cent were accepted and the balance amount of Rs. 287 crore was subscribed to by the Reserve Bank. Similarly, at the auction of 10-year security, bids for Rs. 647 crore at a cut-off yield of 12.75 per cent were accepted and the balance amount of Rs. 353 crore was subscribed to by the Reserve Bank.

1.49 (iii) Since July 1973, Reserve Bank has been allotting banks and insurance corporations an annual quota for 'switching' Government securities in their portfolios with the Reserve Bank mainly with a view to enabling them to improve the yields on their investments. The allotment of such quotas to banks and insurance corporations has since been dispensed with in the current financial year as the system of switch quotas merely generated transactions in Government securities between banks/institutions and the Reserve Bank without any effect on the monetary aggregates.

1.50 (iv) The Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) has started dealing in dated Government securities on a limited scale from April 2, 1992. This is a first step in the direction of developing a secondary market in Government securities.

(h) New Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme

1.51 With a view to providing further incentives and giving wider options to non-residents, including Overseas Corporate Bodies owned by them, a new Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Scheme was announced. The salient features of the Scheme are as follows :

1.52 Authorised dealers would be permitted to accept deposits under this Scheme by way of transfer of foreign exchange funds from outside India or from the existing NRE/FCNR accounts. The funds transferred to this new non-repatriable rupee Scheme would be converted into rupee at the prevailing exchange rate at the time of placing the deposit and these funds will no longer be repatriable. The deposits under the new Scheme, which can be accepted for maturities of six months to three years, would not be considered as part of net DTL for purposes of reserve requirements and as such these deposits would be free from any reserve requirements. Lendings out of these deposits would not be considered as part of net bank credit for purposes of determining priority sector lending. These deposits, and advances out of them, would not be subject to interest rate regulations and as such banks will be free to determine the deposit and lending rates under this Scheme. Banks would be able to offer attractive deposit rates under this Scheme. While depositors would be free to move from one bank to another once these deposits are withdrawn from the banking system they would no longer enjoy these facilities even if they return to the banking system. With these attractive features, authorised dealers will be able to mobilise substantial deposits under the Scheme and attract foreign exchange on a non-repatriable basis without any exchange risk.

EXCHANGE RATE POLICY

1.53 The policy developments in regard to exchange rate of the rupee were influenced by a variety of fundamental considerations : considerations of immediate countering of market expectations and also those of longer-term reforms. A reference was made in the last year's Report to the two-step downward adjustment in the exchange value of the rupee on July 1 and 3, 1991 with a view to placing it at an appropriate level consistent with the need to maintain the competitiveness of India's exports. A situation of persistent erosion in the country's foreign exchange assets generates

destabilising market expectations. In such a milieu, appropriate exchange rate adjustment helps in the immediate period to reverse market expectations and thereby stems capital outflow in the first instance and later encourages inflow. Simultaneously, very soon and positively in the medium term, the downward adjustment becomes an instrument to improve the country's international competitiveness and to correct the imbalances in trade and current account deficits. It raises the relative price of traded goods (by increasing the domestic price of foreign currency) to non-traded (or home) goods, thereby encouraging production of tradeables while discouraging their consumption.

1.54 In India's case, studies have shown that the real effective exchange rate of the rupee (REER) with appropriate adjustments made for import incentives and taxes has served as an important determinant of the country's export performance. Between October 1990 and March 1991 the REER appreciated by about 2 per cent as a result of widening inflation differentials between India and major industrialised countries. The REER increase took place despite continuing depreciation in the nominal effective exchange rate (NEER) of the rupee, by 2.4 per cent against 5 currencies over the same period. In the 5-month period between February 1991 and June 1991, the NEER fell by only 2.5 per cent while inflation differentials continued to widen. All this resulted in an erosion of India's international competitiveness. No doubt India has depreciated the rupee value to a significant extent during the past decade but the country's competitors have resorted to far more depreciation in the values of their currencies in effective terms. To restore the competitiveness of India's exports and to bring about a reduction in trade and current account deficits, it became imperative to make a downward adjustment in the value of the rupee. In determining the extent of adjustment four factors were kept in mind : (i) inflation differentials between India and major industrial countries ; (ii) the extent of real depreciation of the currencies of the countries competing with India ; (iii) the degree of correction required in balance of payments ; and (iv) the broad indicators of market expectations. Taking all these factors into account, the depreciation of the rupee value by 18-19 per cent seemed appropriate.

1.55 Unlike in the recent past when exchange rate adjustments were made gradually in small doses, it was thought necessary to effect a sizeable adjustment of the rupee value in the changed circumstances, essentially owing to two reasons: first, to dampen market anticipations so as to offer incentives for remittances and capital inflows; and secondly, to treat the exchange rate adjustment as part of the major stabilisation and structural reform programmes. Besides, such a large adjustment in the exchange rate also made it possible to avoid discretionary export subsidies from the Government budget.

1.56 The stability of the rupee-dollar rate during the year since the exchange rate adjustment of July 1991 together with the relatively high interest rates more generally and in particular, the raising of interest rates on export credit and the imposition of an interest rate surcharge on import finance, provided a strong impetus to reverse the outflow of foreign exchange.

1.57 The new trade policy of July 1991 introduced a system of EXIM scrip under which exporters earned freely tradeable import entitlements equivalent to 30 per cent (or 40 per cent in some cases) of the value of their exports. The premium on the EXIM scrip, when traded, gave an added attraction to exporters to boost their export profitability. The system of EXIM scrip, however, faced many operational and other problems. First, it was limited in scope with invisible receipts including private remittances being left out of the incentive scheme. Any extension of it to such large number of transactions would have been cumbersome and difficult to operate. Secondly, EXIM scrip partook the character of yet another licence which needed to be avoided particularly because of administrative work-load involved in the issue and verification of licences. The High-Level Committee on Balance of Payments (Chairman : Dr. C. Rangarajan) appointed by the Government of India in November 1991 was of the view that while retaining the essential elements of linking imports with exports and offering incentive to exporters any new system should avoid the need for issue of licences, cover service and remittance transfers, and should preferably operate through the banking system. On its recommendations,

effective March 1, 1992, the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) has been introduced, the details of which are explained in Section VI.

1.58 LERMS should not be viewed as a measure in isolation. It constitutes a part of the totality of liberalisation measures undertaken by the Government of India and the Reserve Bank, including permission to import gold to NRIs. Apart from providing a boost to exports, it aims at efficient import substitution with as little bureaucratic and discretionary controls as possible. It seeks to encourage remittances through banking channels and reduce incentives for clandestine transactions. LERMS is a system in transition. It subsumes the declared objective of movement into full convertibility on current account in the near future. As the Rangarajan Committee has emphasised, in order to achieve the full benefits of integrating the Indian economy with the world economic system, we need to move step by step towards full convertibility of current account transactions, keeping in view the developments in the macro-economic situation and the world trading environment. It is also envisaged that the proportion of official allocation of foreign exchange for the purposes of public good and other items should be gradually reduced, thus increasing the proportion of foreign exchange that the importers have to buy from the market.

1.59 The experience of LERMS has proved to be encouraging. The spread between the market rate and the official rate has been remarkably stable. Foreign exchange dealings relating to a wide variety of transactions in goods and services including capital account transactions at the market-determined rates, have been conducted smoothly. It has provided an opportunity for the development of market-determined transactions in foreign exchange as a preparatory arrangement for full convertibility on current account.

STRUCTURAL REFORMS

1.60 In the area of structural reforms, industrial deregulation, liberalisation of policies relating to foreign direct investment, public enterprise reform, reforms of the taxation system, trade liberalisation, and financial sector reforms, constitute a wide set of radical restructuring of the economic system.

1.61 In industrial deregulation, the virtual abolition of the requirement of industrial licensing except for a shortlist of industries, abolition of the concept of monopoly involving limits on the assets of large industrial houses for permitting industrial investment, restricting the number of industries reserved exclusively for the public sector to a short list of industries and permitting competition between the public and private sectors, and alongside, measures to promote small, tiny and village industries, were highlighted in the last year's Report.

1.62 Likewise, the system of automatic approval to be granted by the Reserve Bank for foreign direct investment up to 51 per cent for foreign equity in 34 select areas, as also for foreign technology agreements, was a part of the policy initiative taken in July 1991. Apart from the RBI's automatic approvals, other proposals are considered and approved on merits by the Secretariat for Industrial Approvals and, more significantly, by a Foreign Investment Promotion Board (FIPB) specially created to invite, negotiate and facilitate substantial investment by international companies that would provide access to high technology and world markets. The system of automatic approval up to 51 per cent equity has been extended to trading companies primarily engaged in export activities, to hotels and tourism-related industries and also to such critical sectors as hydrocarbons and exploration, development, refining and marketing of petroleum oil and gas. Fully-owned foreign enterprises will henceforth be allowed to set up giant power projects without the requirement to balance dividend payments with export earnings. NRI's and overseas corporate bodies predominantly owned by them are permitted up to 100 per cent foreign equity in high priority areas. The general permission granted by the Reserve Bank under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 has brought the FERA companies (i.e., those having more than 40 per cent foreign equity) on a par with the Indian companies and has thus provided a level playing field to all. The existing FERA companies have also been extended the facility of 51 per cent equity. Also, the use of foreign brand names and trademarks on goods for sale within the country has been permitted. Significant amendments to the FERA for relaxing several of its restrictive provisions

have been contemplated. Recently, in June 1992, the condition of dividend balancing has been withdrawn except for 22 industries under the consumer goods category.

1.63 According to the information available with the Secretariat for Industrial Approvals (SIA), foreign collaborations approved during the post-liberalisation period of 1991-92 (August to June) have been many times over that in the corresponding period of the previous year. As against a total of 474 approvals in the previous year, there have been 1,430 approvals up to June 1992 (Appendix Table 1.5). Of these, the break-up of the total number of foreign collaboration approvals involving foreign equity are : RBI (168 for foreign equity worth Rs. 573.4 crore); SIA (332 for foreign equity worth Rs. 468.8 crore); and FIPB (19 for foreign equity worth Rs. 846.5 crore). Details of actual inflow of direct foreign investment for the recent period are, however, not yet available.

1.64 In regard to the reform of public sector enterprises, apart from the narrowing of their role in setting up industries and inducing competition with the private sector, reductions in budgetary transfers to them and equity disinvestment of selected enterprises which began with 20 per cent and which has now been proposed up to 49 per cent, constitute major reform measures. Besides, after the passing of amendments to Sick Industrial Companies Act, 1985 (SICA), the Government of India have referred 54 Central enterprises to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for preparing detailed programmes of restructuring or closure.

1.65 The Central Budget for 1992-93 has initiated the process of reforming the taxation system based on the interim Report of the Tax Reforms Committee (Chairman : Dr. Raja J. Chelliah). Apart from streamlining the personal income taxation with lower tax rates and reduced exemptions, substantial rationalisation of the capital gains tax and wealth tax as also the widening of the tax base by introducing a presumptive tax scheme, has been effected. A major restructuring of corporate taxation has been deferred until after the detailed recommendations of the Chelliah Committee are received. In indirect taxation some further cuts in Customs tariffs have been implemented (as detailed in a subsequent paragraph).

1.66 In the trade policy area, major structural reforms have been introduced since July 1991, with the avowed objective of liberalising, within the next three to four years, the tightly-controlled and complex trade regime with high nominal tariffs, quantitative restrictions on imports and also on exports, public sector canalisation, phased manufacturing programme (PMP) for attaining import substitution, and Government purchase preferences for domestic producers. First, after the exchange rate adjustments of July 1 and 3, 1991, the Cash Compensatory Scheme (CCS) was abolished with effect from July 3, 1991. The Replenishment Licences were replaced by a new instrument called EXIM scrip described earlier. The introduction of EXIM scrip represented a structural change in trade policy which sought to achieve optimal import restraint by linking imports to exports. EXIM scrips which could be sold in the market at a premium could be utilised for the import of permitted goods. All Supplementary Licences for raw materials and components except for small-scale industries and for manufacturers of specified drugs and equipments, the category of unlisted OGL and additional licences granted to Export Houses, were abolished and all such imports were to be routed through the medium of EXIM scrips. Furthermore, Advance Licensing System as an instrument of export promotion was strengthened. As the year progressed, the EXIM scrip scheme was administratively found to be cumbersome and, with the introduction of LERMS, it was abolished.

1.67 Secondly, the export-import policy announced for the five-year period to coincide with the Eighth Plan, April 1, 1992 to March 31, 1997, has made a major thrust towards trade liberalisation. The new policy substantially eliminates licensing, quantitative restrictions, and other regulatory and discretionary controls. Exports and imports are allowed freely, subject only to a negative list of imports and a negative list of exports. The list of canalised items imported or exported through public sector agencies has been drastically curtailed. The negative list of imports consists of only 3 prohibited items, 68 restricted items and 8 canalised items.

The restricted items of imports include mainly consumer goods which can be imported only against licences. The canalised items are petroleum products, fertilisers, drugs, vegetable oils and seeds, fatty acids and oils, and cereals. The actual user conditions hitherto obtaining has been dispensed with except in the case of imports regulated by the negative list. Import of capital goods has been further liberalised and there is no longer a negative list of import of capital goods.

1.68 Thirdly, with further reduction in Customs tariffs implemented in the Central Government Budget for 1992-93, the maximum tariff rate for raw materials, etc., has been lowered from 150 per cent to 110 per cent, while for capital goods, tariff rates have been lowered by about 10 to 25 per cent to a maximum of about 55 per cent.

FINANCIAL SECTOR REFORM

1.69 Consequent to the submission in November 1991 of the report of the high-level Committee on the Financial System (Chairman: Shri M. Narasimham), follow-up action on a number of recommendations of the Committee was initiated by Government and the Reserve Bank. The Committee made wide-ranging recommendations with a view to ensuring that the financial sector operates on the basis of operational flexibility and functional autonomy thereby enhancing efficiency, productivity and profitability.

1.70 The Committee was of the view that the statutory liquidity ratio (SLR) instrument should be deployed in conformity with the original intention regarding it as a prudential requirement and should not be viewed as a major instrument for financing the public sector. In line with Government's decision to reduce the fiscal deficit to a level consistent with macro-economic stability, the Committee has recommended that the SLR be brought down in a phased manner to 25 per cent over a period of about five years. Consistent with the anticipated decline in the monetised deficit of the Centre, and the reduction in the Centre's borrowing programmes and the need for the gradual promotion of a Government securities market, the SLR on an incremental basis has been reduced to 30 per cent. Further reduction in SLR may be thought of in stages.

1.71 As regards the cash reserve ratio (CRR), the Narasimham Committee had observed that the Reserve Bank should have the flexibility to operate this instrument to serve its monetary policy objectives and that, given Government's resolve to reduce the fiscal deficit, the occasion for its use to control the secondary expansion of credit should be less; and the Committee had, therefore, recommended that the Reserve Bank should consider progressively reducing the cash reserve ratio from its high level. Weighing the liquidity situation and the monetary policy considerations, and the need to reduce pre-emptions of banks' resources, the Reserve Bank has discontinued the 10 per cent incremental CRR. Further reduction in CRR is possible once an enduring adjustment in the monetised deficit is attained and open market operations in Government securities with market-related rates of interest become an effective instrument of monetary control.

1.72 The Narasimham Committee had proposed that the interested rate paid to banks on their SLR investment and on CRR in respect of impounded deposits above the basic minimum should be increased. The Government has recognised the need to move towards market-related interest rates on Government borrowing. The cash reserve ratio is essentially a monetary instrument for impounding liquidity. The payment of higher interest on CRR by reducing the amount impounded dilutes the very purpose of imposing a CRR. From the viewpoint of monetary control it is preferable to have a lower CRR with less or no interest paid rather than to have high CRR and pay a high rate of interest.

1.73 Identifying the causes for the deterioration in the financial health of the banking system over time, the Narasimham Committee recommended various remedial measures which include inter alia capital adequacy norms, prudential norms for income recognition and provisioning for bad debts.

1.74 In April 1992, the Reserve Bank introduced a risk-assets ratio system for banks (including foreign banks)

in India as a capital adequacy measure. Under the proposed system, the balance sheet assets, non-funded items and other off-balance sheet exposures will be assigned risk weights according to the prescribed percentages and banks will be required to maintain unimpaired minimum capital funds equivalent to the prescribed level of the aggregate of the risk-weighted assets and other exposures, on an ongoing basis. All banks with international presence will have to achieve the norm of 8 per cent as early as possible and in any case by March 31, 1994. Foreign banks operating in India will have to achieve this norm by March 31, 1993. Other banks will have to achieve a capital adequacy norm of 4 per cent by March 31, 1993 (Tier I or core capital having been set at not less than 50 per cent of total capital) and the 8 per cent norm by March 31, 1996. The total of Tier II elements will be limited to a maximum of 100 per cent of total of Tier I elements for the purpose of compliance with the norms. Banks have been advised to review the existing level of capital funds vis-a-vis the prescribed level and plan to increase the capital funds in a phased manner to achieve the prescribed ratio by the end of the period stipulated.

1.75 If the balance sheet of a bank is to reflect actual financial health of that bank, there has to be a proper system of recognition of income, classification of assets and provisioning for bad debts on a prudential basis. The Narasimham Committee had recommended that a policy of income recognition should be objective and based on record of recovery rather than on any subjective considerations, that classification of assets of banks should be done on the basis of objective criteria which would ensure a uniform and consistent application of the norms, and that provisioning should be made on the basis of classification of assets into different categories. In April 1992 it was decided to implement the Committee's recommendations, with certain modifications, in a phased manner over a three-year period commencing from the accounting year beginning April 1, 1992. Banks have been instructed to treat an amount in respect of term loans, overdrafts and cash credit accounts, bills purchased and discounted and other accounts, as "past due" when it has not been paid on the due date. A "non-performing assets" has been defined as a credit facility in respect of which interest has remained unpaid for a period of four quarters during the year ending March 31, 1993, three quarters during the year ending March 31, 1994 and two quarters during the year ending March 31, 1995 and onwards. Banks have been instructed that they should not charge and take to income account interest on all non-performing assets. As compared with the existing eight health codes, banks are required to classify their advances into four broad groups: (i) standard assets, (ii) sub-standard assets, (iii) doubtful assets, and (iv) loss assets. Broadly, classification of assets into these categories has to be done taking into account the degree of well-defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation of dues. The health code system of classification of assets would, however, continue as a management information tool.

1.76 Taking into account the time-lag between an account becoming doubtful of recovery, its recognition as such, the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged to the banks, banks are required to make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets.

1.77 As regards accounting standards for investments, investments in approved securities have to be bifurcated into 'permanent' and 'current' investments. 'Permanent' investments are those which banks intend to hold till maturity and 'current' investments are those which banks intend to deal in, i.e., buy and sell on a day-to-day basis. To begin with, banks would have to keep not more than 70 per cent of their investments in the 'permanent' category from the accounting year 1992-93 but this ratio will have to be brought down to 50 per cent in due course. While the depreciation in respect of 'permanent' investment is not likely to affect their realisable value and therefore need not be provided for, depreciation in 'current' investments would have to be fully provided for. 'Permanent' investments could be valued at cost unless it is more than face value, in which case the premium has to be amortised over the period remaining for maturity of the security. Banks are not expected to sell securities in the 'permanent' category.

freely, but if they do so, any loss on such transactions in securities in this category has to be written off. Besides, any gain should be taken to capital reserve account.

1.78 Foreign currency assets and liabilities and unmatured spot and forward foreign exchange transactions are required to be revalued on a monthly basis. Spot and forward transactions are to be revalued at the then prevailing spot and forward foreign exchange rates, respectively.

1.79 In regard to the regulated interest rate structure, a series of reform measures have been put in place :

- (a) Considerable rationalisation has been effected in banks' lending rates with the number of concessive slabs reduced and some of the rates have been enhanced thereby reducing the element of subsidy ;
- (b) The regulated deposit rate structure has been replaced by a single prescription of not exceeding 13.0 per cent per annum for all deposit maturities of 46 days and above ; and
- (c) Rates of interest on Government securities have been raised and 364-day Treasury bills and 5-year and 10-year securities have been auctioned. It is also pertinent to note that for a few instruments such as Certificates of Deposit, Money Market Mutual Funds and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme, a significant proportion of deposit resources of commercial banks is now at market-related rates of interest.

1.80 The Narasimham Committee had suggested abolition of branch licensing policy. Considering that the objective of providing adequate banking infrastructure through out the country, particularly in rural areas, had been broadly achieved with the completion of the branch expansion policy for the period 1985—90, the Reserve Bank decided to give greater freedom to banks to rationalise their existing branch network by re-locating branches, opening of specialised branches, spinning-off of business at other locations, setting up of controlling officers/administrative units and establishing extension counters, etc. Banks have already been permitted to close down branches other than in rural areas, as well as swap unremunerative branches or those in remote areas. Under the liberalised branch licensing policy, only those banks which attain the revised capital adequacy norms and prudential accounting standards have been given freedom to set up new branch officers/upgrade the extension counters into full-fledged new branches without the prior approval of the Reserve Bank. Till such time banks attain the revised capital adequacy norms and until they are specifically advised in this regard, they should continue to obtain prior approval for opening new branches or converting extension counters into full-fledged branches.

1.81 Expansion of branches of foreign banks will be based, as thereto, on considerations of national advantage from the point of view of facilitating exports and foreign investment. Principles of non-discriminatory reciprocal treatment and mutual benefits, besides compliance with prudential and other norms, will be given due weightage.

CAPITAL MARKET

1.82 Recognising the growth during the last decade of the Indian capital market, in terms of both new issue activities and secondary market transactions, the Narasimham Committee emphasised that for the business of merchant banking and mutual funds and such other financial institutions involved in the capital market activities, as also that of the stock exchanges, to grow on sound lines, a framework of regulations is essential as a measure of investor protection. While recommending that the regulatory functions of the Office of the Controller of Capital Issues (CCI) be transferred to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) the Committee perceived the role of SEBI to be not merely one of replacing the restrictive role of CCI but that of undertaking the role of market regulator to ensure that the market is operated on the basis of well-laid down principles and guidelines. The Committee was of the view that SEBI should not get involved in the day-to-day functioning of the market or exercise excessive discretionary control of the type practiced by the

CCI. In the matter of new capital issues, it is for the merchant bankers and the under-writers to offer professional advice on a particular issue, on the nature of the instrument, its terms and pricing, and for the issuing company to decide its preference.

1.83 Almost all of these capital market reform measures intended to achieve a blending of market freedom and regulation of the market for investor protection based on prudential guidelines have been implemented. A Presidential Ordinance promulgated on January 31, 1992 accorded statutory status as an autonomous body to the SEBI to protect investors' interest in securities, to promote the development of the capital market and to regulate the working of the market including the stock exchanges. Subsequently, the SEBI Bill was passed by the Parliament giving official recognition, effective March 31, 1992, to the organisation as a surveillance body.

1.84 SEBI has been vested with wide-ranging powers to oversee constitution as well as the operations of mutual funds including presentation of accounts, following the decision to allow the entry of private sector and joint sector mutual funds. Secondly, all stock exchanges in the country have been brought under the annual inspection regime of SEBI for ensuring orderly growth of the stock market and investor protection. Thirdly, with the repealing of the Capital Issues Control Act, 1947 in May 1992, SEBI has been made the regulatory authority in regard to the new issue activities of companies.

1.85 SEBI has issued a series of guidelines covering different aspects of its jurisdiction and responsibility which would have, in their totality, a significant bearing on the future development of the capital market. SEBI's guidelines cover :

- (i) Lead managers/merchant bankers concerned with prospects issues and portfolio management (including the terms and conditions of the contract),
- (ii) Mutual funds and each of their constituents, namely, sponsors, trustees, asset management company (AMC) and custodian, including the formation of the AMC,
- (iii) Stock exchanges including stringent regulations to curb the practice of insider trading, and
- (iv) Compliance by issuers of capital and intermediaries with norms regarding proper disclosure and investors' protection which inter alia cover promoters' contribution, pricing of issues, credit rating of debt instrument monitoring of issue proceeds of large issues and stipulations regarding underwriting and minimum subscription.

1.86 The Over-the-Counter (OTC) Exchange of India (OTCEI) promoted jointly by ICICI, UTI, SBI Capital Markets Ltd., Canbank Financial Services Ltd., GIC and LIC, has been recognised as a stock exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 with effect from August 23, 1989. The Exchange was incorporated as a company under Section 25 of the Indian Companies' Act, 1956, on September 20, 1990. The OTCEI has been set up with a view to providing small and medium companies an access to capital market to raise finance in a cost-effective manner and provide a convenient and efficient avenue of capital market investment for investors at large. It is a ringless, electronic and national exchange, listing the shares of entirely new companies. It is expected to commence trading operations around the beginning of August, 1992.

1.87. A few other significant liberalisation measures concerning the capital market are :

- (i) All restrictions on interest rate on debenture and public bonds other than the tax-free PSU bonds were rescinded in August, 1991. It was observed that during 1991-92 the issuing companies offered around 17 per cent on non-convertible debentures and around 16 per cent on partly convertible debentures.
- (ii) The maximum rate of interest payable by non-banking and non-financial companies on deposits accept-

ed by them was raised from 14 per cent to 15 per cent in January 1992 (For details and other measures on these companies, see Part II of this Report).

- (iii) In order to impart greater flexibility in the interest rate structure relating to term-lending institutions, the prescription of ceiling rates of interest on lendings by these institutions was replaced by a system of minimum rate prescribed at 15 per cent, effective August 1991. The institutions now generally charge rates of interest in accordance with their perception of creditworthiness of the borrowers.
- (iv) Permission has been given to companies with a track record to issue convertible debentures or equity to investors abroad, in order to enable them to tap investible funds available in international capital markets. These issues would be subject to the same tax treatment as is available to the off-shore mutual funds.
- (v) It has been proposed in the Union Budget 1992-93 to allow reputable foreign investors such as Pension Funds to invest in the Indian stock market, with suitable mechanism to ensure that this did not threaten the loss of management control.
- (vi) All mutual funds registered with SEBI (public, private or joint sector) would be exempt from the payment of income-tax according to the Union Budget for 1992-93.
- (vii) The Government of India issued a comprehensive set of prudential guidelines in February 1992 for the development and regulation of mutual funds (MFs) and for ensuring investor protection. These guidelines cover activities of all the mutual funds including those to be set up in the joint and private sectors. Money Market Mutual Funds would be, however, regulated by the RBI on the basis of specified guidelines to be laid down by it. The Government guidelines provide for authorisation of all the MFs by the SEBI, establishment of MFs in the form of trusts under the Indian Trusts Act, 1882 and establishment of Asset Management Companies by the MFs. The guidelines also suitable the minimum amount to be raised through the open-ended and close-ended schemes, as well as the criteria for investment in securities/companies and income distribution. SEBI will have the right to call for any information regarding the operations of the MFs and any of its schemes from the MFs, Asset Management Company, custodian, sponsor or any others associated with MFs.

Irregularities in the securities operations of banks and Financial Institutions

1.88 It is necessary to refer to a recent development of great public concern that has tended to sideline the otherwise far-reaching reform measures and structural changes that are being implemented or underway so as to make the financial system much more competitive, efficient and transparent. On the basis of the information received that some banks were undertaking large-scale transaction in Government securities through the medium of brokers in the course of which they were violating the Reserve Bank of India's detailed guidelines issued to them in July 1991, a Committee, with Deputy Governor Shri R. Janakiraman as Chairman, was set up on April 30, 1992 to investigate the irregularities in funds-management by commercial banks and financial institutions, in particular, in relation to their dealings in Government securities, public sector bonds, UTI units and similar instruments. The Committee submitted two interim Reports on June 1, and July 5, respectively and a third Report on August 25, 1992 which were all released to the public immediately.

1.89 The preliminary findings of the Committee have indicated serious deficiencies in the functioning of the banks and financial institutions involved absence of necessary internal control in various functions, raising money without the backing of genuine securities, diversion of call money to the current accounts of chosen brokers, and massive collusion between

the concerned official and the brokers involved in dealings in Government securities, public sector bonds and units, etc. The Committee has listed the devices adopted for diversion of funds from the banking system to the individual accounts of certain brokers which prima facie constitute evidence of fraudulent misrepresentation. Funds-management operations have been conducted in gross violation and with utter disregard of instructions and guidelines issued by RBI from time to time. The break-down of essential discipline regarding the issue and recording of Bank Receipts (BRs), the receipt and delivery of securities and the receipt and payment for settlement of the transactions, have been exposed in many of the transaction detailed in the Report. The Committee has also come across instances wherein brokers have been financed by banks through the discounting of bills not supported by genuine transactions. Large-scale violations of RBI guidelines on Portfolio Management Services by certain banks have also been pointedly brought out by the Committee. The total amount of exposure of banks and institutions involved in these transactions aggregated Rs. 3,542.79 crore.

1.90 The Janakiraman Committee has recommended a series of steps so that remedial action is taken to introduce a proper control system, strengthen monitoring, remove lacunae in the existing system and establish procedures so as to prevent recurrence of similar lapses in future.

1.91 The Reserve Bank of India and the Government have taken a number of steps with a view to unearthing the entire ramifications of the episode, to recover the banking dues, to punish the guilty, and to set in motion enduring measures of a preventive nature.

1.92 The measures include examination of the entire securities transactions of banks and financial institutions for the past one year, placing Bank of Karad Ltd. under liquidation, placing Bank of Madura Ltd. under an RBI observer, starting winding-up proceedings against Metropolitan Co-operative Bank Ltd., the de-listing of four brokers from the Reserve Bank's list approved brokers, entrusting the entire investigation to the Central Bureau of Investigations (CBI), winding-up proceedings against Metropolitan Co-operative Bank Ltd. of all Special Court to exclusively attend to the cases relating to securities transactions of banks and financial institutions, appointment of reputed firms of Chartered Accounts to conduct special audit of the treasury operations of major players in the market under the provisions of section 30(1B) of the Banking Regulation Act, 1949 and issuance of special guidelines including the prohibition of inter-bank ready-forward deals in dated securities and approved/trustee securities except Treasury bills of all maturities and prohibition of double ready-forward deals in Government securities including Treasury bills.

1.93 The other important aspects of the guidelines are : (i) The existing prohibition on day-back deals between banks in other securities such as PSU bonds and units will continue ; (ii) Banks should ensure that Subsidiary General Ledger (SGL) transfer forms covering their sale transactions in Government/approved securities are issued only if they have sufficient balance in their respective SGL accounts in the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India. In the event of bouncing of SGL transfer forms, banks will render themselves liable to penal action ; (iii) BRs should not be issued under any circumstances in respect of transactions in Government securities, for which SGL facility is available. BRs may be issued in the case of other securities for ready transactions only, under exceptional circumstances ; and (iv) BRs should not be issued covering transactions relating to either portfolio management scheme clients or other constituents including brokers.

1.94 The Committee on Trading in Public Sector Bonds and Units of Mutual Funds (Chairman S.S. Nadkarni), appointed by the Reserve Bank as a follow-up of the Janakiraman Committee, has since submitted its Report, on August 8, 1992 which is under consideration.

1.95 A 30-member Joint Parliamentary Committee (IPC), comprising honourable members from both the Houses of Parliament has been constituted to probe into the entire

II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS

1. MACRO-ECONOMIC SCENE

2.1 After a decade of relatively high growth which never theless was accompanied by some serious macro-economic imbalances, the Indian economy faced a distinct slowdown during the fiscal year 1991-92. The real GDP growth is expected to be a little less than 2.0 per cent, the lowest since 1980-81; it contrasts with that of 5.6 per cent during 1990-91 and the trend growth of 5.5 per cent for the decade 1980-81 to 1990-91 (Table 2.1). A dominant factor in this low growth scenario has been the stagnation in industrial output for the first time since 1979-80; agricultural output is also expected to register a decline of about 1.0 per cent.

Table 2.1 : Growth in Rural Gross Domestic Product

(In Per cent Per Annum)				
Sector	Decade (1980-81 to 1990-91)	Seventh Five Year- Plan Period (1985-86 to 1989-90)	1990-91	1991-92
(Annual Average)				
1	2	3	4	5
1. Agriculture	3.5	5.3	4.3	..
2. Manufacturing	7.0	7.5	7.3	..
3. Services	6.4	6.9	5.8	..
Total GDP	5.5	6.4	5.6	2.0*

*RBI estimate.

See also Appendix Table II.1.

2.2 The macro scene concerning domestic saving and investment also remained subdued and somewhat uncertain. The gross domestic saving to GDP ratio, which fell from 22.7 per cent in 1989-90 to 22.2 per cent in 1990-91, is tentatively estimated to register a rise to 23.2 per cent during 1991-92. Simultaneously, with severe import compression measures, the current account deficit on the balance of payments was drastically cut down and, as a counterpart, the estimated net inflow of foreign resources is estimated to decline from Rs. 14,684 crore in 1990-91 to Rs. 8,042 crore in 1991-92 or, as percentage of GDP, from 2.8 per cent to 1.3 per cent, respectively. As a result, the ratio of gross domestic investment is estimated to have fallen from 25.0 per cent during 1990-91 to 24.5 per cent during 1991-92 (Table 2.2 and Appendix Table 11.2).

Table 2.2 : Saving and Investment Ratios

(In per cent)			
Ratios to GDP/NDP at current market prices	1991-92*	1990-91	1989-90
1	2	3	4
1. Gross Domestic Saving	23.2	22.2	22.7
2. Gross Aggregate Investment	24.5	25.0	25.2
3. Net Domestic Saving	14.3	13.4	13.6
4. Net Aggregate Investment	15.7	16.5	16.4

*Tentative.

2.3 In the composition of gross domestic saving, all the three sectors, namely, household, private corporate and public sectors, showed improvement. In the case of the household sector, while the gross financial assets ratio registered a marginal rise from 11.1 per cent in 1990-91 to 11.4 per cent in 1991-92, there occurred a significant decline in the household sector's financial liabilities following reduced bank borrowings and probably reduced investment activities. It is as a result of this that the ratio of household financial assets (net) showed a more than proportionate increase from 9.8 per cent to 10.6 per cent.

2. PRODUCTION TRENDS AGRICULTURE

2.4 The sustained progress in agricultural production, witnessed for the last three years in succession could not be maintained during the year 1991-92 mainly on account of delayed and spatially unfavourable distribution of monsoon. Preliminary data on agricultural production indicate reduction of about 1.0 per cent in 1991-92.

2.5 The 1991 Kharif foodgrains production has been estimated lower at 94.2 million tonnes against the target of 103.2 million tonnes and the production of 99.9 million tonnes in the previous Kharif season. Despite concerted efforts at enhancing the Rabi output, it is expected to be 74.8--76.3 million tonnes which is more or less at the same level as in last year at 76.3 million tonnes. Pulses output did not show any improvement despite special production programmes mostly due to water stress in producing areas. Thus, the total foodgrains output in 1991-92 may be placed at 169.0--170.5 million tonnes against the level of 176.2 million tonnes in the previous year (Appendix Table 11.3).

2.6 Among other crops, production of sugarcane and jute/mesta showed noticeable improvements over the previous year's level. Cotton production remained at the previous year's level of 98 lakh bales while there was a shortfall of 2 lakh tonnes in oilseeds (Appendix Table II.3).

2.7 The absolute fall in agricultural production has contributed to a significant extent, to increases in prices of agricultural commodities and influenced market expectations.

Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains

2.8 Reflecting in part the fall in foodgrains production, procurement of foodgrains by public sector agencies declined during 1991-92 by 23.4 per cent to 18.3 million tonnes. The off-take of foodgrains, however, increased to 19.0 million tonnes as against 16.1 million tonnes during the previous year, reflecting the supply response of the Public Distribution System (PDS) to increased demand in view of the increased differential between the PDS and open market prices.

2.9 The stocks of foodgrains with the public sector agencies as at the end of March 1992 were lower at 12.1 million tonnes against 17.3 million tonnes a year ago and the stipulated buffer stock norm of 14.5 million tonnes for the quarter ending March. The stocks of wheat in particular dwindled rather sharply (Appendix Table II.4). Given the low carry-over of stocks, the need for augmenting supplies to keep agricultural commodity prices in check has become imperative.

INDUSTRIAL PRODUCTION

2.10 During the financial year 1991-92, industrial production registered a fractional rise, the lowest since eleven years ago in 1979-80. During the eighties, annual industrial growth was as high as 7.8 per cent. It was still higher at 8.5 per cent during the Seventh Plan period. In the second half of 1990-91, however, output slowed down eventually culminating in a rise of only 0.1 per cent during 1991-92 (April--March) (Appendix Table II.5).

2.11 The poor performance in industrial growth during the financial year 1991-92 was particularly in evidence in the output of manufacturing sector which registered a fall of 1.4 per cent as compared with a rise of 9.1 per cent in the previous year. Mining and quarrying output registered a marginal increase of 0.8 per cent as against a rise of 4.5 per cent in the previous year. The output of the electricity sector accelerated to 8.4 per cent as against a rise of 7.8 per cent in 1990-91.

2.12 A vast set of factors contributed to the setback to industrial output : import compression measures and rise in import costs affecting not only import-intensive industries but also a wide spectrum of export-oriented and other industries; reduced growth of exports and in particular, exports to rupee payment areas; the increase in cost of credit, as also the limitations on credit availability; erosion in the purchasing power and consumer resistance at higher prices; and above all, the decline in public investment affecting the demand for capital goods, in particular, and for a series of intermediate and other goods in general. Despite these all-pervasive factors, some of the industries stood the ground rather well. Food processing and manufacturing industries and industries based on agricultural raw materials have generally shown at least positive growth if not acceleration. Secondly, infrastructure industries showed significant expansion in output except for crude petroleum and petroleum products.

Manufacturing Sector

2.13 In the manufacturing sector, data in respect of seventeen major industrial groups, indicate that during 1991-92, only seven groups with a weightage of 47.75 percentage points recorded positive growth rate as compared with that of 14 groups with a weightage of 71.39 percentage points recording a positive growth in the previous year. Out of these seven groups, only two groups (viz., beverages, tobacco and tobacco products and non-metallic mineral products) with 4.57 per cent weight recorded acceleration in 1991-92 as against 8 groups accounting for the weightage of 45.75 points in 1990-91 (Appendix Table II.6). Among the remaining ten industrial groups, which experienced negative growth rate, electrical machinery group registered the sharpest fall (-10.3 per cent), followed by metal products (-7.0 per cent), leather & leather products (-7.0 per cent), wood and wood products (-6.7 per cent), textile products (-5.7 per cent), jute, hemp, mesta textiles (-4.1 per cent), machinery and machine tools (-4.0 per cent), transport equipment (-2.5 per cent) and rubber, plastic & petroleum products (-1.2 per cent). The decline in industrial output is, to a large extent, a reflection of the import compression and rise in import costs as may be seen from the decline in the output of import-intensive industries, such as, electrical goods, transport equipment, etc. This is also evident from trends in production based on the use-based classification (Appendix Table II.7). The consumer durables segment of the consumer goods industry, which basically represents the 'white goods' industries, recorded a decline of 12.5 per cent during 1991-92 as compared with a rise of 9.1 per cent in the previous year. Besides import compression measures, the restriction on credit for the purchase of consumer goods also appears to have had a dampening impact on the demand for consumer goods.

2.14 Similarly, capital goods production also declined sharply during 1991-92, the order of decline being 12.8 per cent (Appendix Table II.7). The fiscal restraint and decline in public investment have adversely affected the demand for capital goods, for which the major buyers are Government or public sector.

Infrastructure Industries

2.15 As already mentioned, the performance of infrastructure industries during the financial year 1991-92 was better than in the previous year, indicating the underlying strength of the supply factors. The growth rate in the composite index of infrastructure industries at 6.0 per cent during 1991-92 has been higher than that in the previous year (4.8 per cent) (Appendix Table II.8). Among the infrastructure industries, barring petroleum sector, crude as well as petroleum products, all the industries—electricity, coal, steel and cement—registered higher rates of growth than 1990-91. Production of petroleum crude, however, experienced a larger decline of 8.1 per cent during 1991-92 as compared with the decline of 3.1 per cent in the previous year. Output of petroleum refinery products also declined, though marginally by 0.7 per cent as compared with a decline of 0.3 per cent in the previous year.

III. GOVERNMENT FINANCES

Process of Fiscal Adjustment

3.1 A dominant aspect of the stabilisation measures initiated during 1991-92 related to the process of fiscal adjustment. The Union Budget for 1991-92 sought to achieve this by a series of measures to rationalise the tax and expenditure structures and bring down the "gross fiscal deficit". This process has been further carried forward in the Union Budget for 1992-93 with a significant thrust towards fiscal consolidation to be achieved in the medium term.

Centre's Budget Deficit

3.2 During 1991-92, there was considerable improvement in the overall budgetary position of the Central Government which was reflected in the reduction in the various measures of deficit (Appendix Table III.1). Gross fiscal deficit (GFD) was brought down from Rs. 44,650 crore in 1990-91 to Rs. 37,792 crore in 1991-92. As a percentage to GDP, GFD was placed at around 6.5 per cent in 1991-92 as against 8.4 per cent during the previous year. Primary deficit was also substantially lower at Rs. 21,839 crore (or 3.5 per cent of GDP) in 1991-92 as against Rs. 31,909 crore (6.0 per cent) during the previous year (Table 3.1).

Table 3.1 : Measures of Deficit : Monetised, Budget, Gross and Net Fiscal Deficits of Central Government

(Rupees crore)							
Year	Gross Fiscal Deficit	Net Fiscal Deficit	Primary Deficit	Monetised Deficit	Conventional Deficit	Revenue Deficit	GDP at Market Prices
1	2	3	4	5	6	7	8
1989-90	35,632	23,722	26,349	13,813	10,592	11,914	4,50,601%
1990-91	44,650	30,710	31,909	14,746	11,347	18,562	5,29,537%
1991-92 (RE)	37,792	26,126	21,839	5,508*	7,032+	17,081	6,19,000*
1992-93 (BE)	34,408	23,940	15,872	5,389	5,389	13,882	7,00,000@
As a Percentage to GDP at Market Prices							
1989-90	7.91	5.26	5.85	3.07	2.35	2.64	
1990-91	8.43	5.80	6.03	2.78	2.14	3.51	
1991-92	6.50**	4.22	3.53	0.89	1.14	2.76	
1992-93	5.00	3.42	2.27	0.77	0.77	1.98	

* Actuals according to RBI records. *RBI Estimate.

\$ Quick Estimates.

@ Rough Estimate.

+ As per Budget Document. The deficit according to RBI records after closure of Government accounts as on March 31, 1992 was Rs. 6,492 crore. **Inclusive of OCC and other transactions.

See also Appendix Table III.1.

3.3 While reduction in gross fiscal deficit was indicative of the concerted efforts at fiscal correction, its burden, however, fell entirely on the capital account, as revenue deficit widened from the budgeted level of Rs. 13,854 crore to Rs. 17,081 crore in the revised estimates for 1991-92. The deterioration in the revenue account was more than offset by the increase in surplus on capital account from Rs. 6,135 crore to Rs. 10,049 crore. Consequently, the conventional budget deficit stood lower at Rs. 7,032 crore (revised estimates) or at Rs. 6,492 crore (as per RBI records) as against Rs. 7,719 crore budgeted earlier; at this level the deficit was considerably lower than the actual deficit of Rs. 11,347 crore during 1990-91. Net RBI credit to the Central Government which indicates the monetary impact of budgetary operations (monetised deficit) was also lower at Rs. 5,508 crore in 1991-92 as compared with a much larger support of Rs. 14,746 crore in 1990-91. These year-end figures are, however, deceptive as the phenomenon of the deficit remaining at unreasonably high levels almost throughout the year before the year-end reduction, persisted even more during 1991-92: this is reflected in the fortnightly data which show that the average monetised deficit during 1991-92 was Rs. 10,209 crore as against Rs. 10,336 crore in 1990-91. To have a salutary impact on the growth of liquidity, it is the average monetised deficit which has to be moderated (Appendix Table III.2).

3.4 The financing pattern of gross fiscal deficit in 1991-92 indicated increased reliance on external borrowings which marked a departure from the trend observed during the previous years. The share of external finance which had steadily declined from 15.4 per cent in 1980-81 to 7.1 per cent in 1990-91, increased significantly to 13.4 per cent in 1991-92. Consequently, the share of internal financial declined from 92.9 per cent to 86.6 per cent during the same period. The share of market borrowings in the financing of the gross fiscal deficit declined from one-third in the early 'eighties to less than one-fifth in 1991-92. Other liabilities comprising small savings, provident funds, special deposits, etc., financed a little less than one-half of the deficit as compared with a little less than one-fourth in 1980-81 (Appendix Tables III.3 and III.4).

3.5 In the revenue account, receipts from corporation tax and income-tax (net) and royalty on offshore crude were higher than those estimated in the budget. Interest payments on account of discount on treasury bills showed a decline. These favourable outcomes were more than neutralised by a huge shortfall of Rs. 3,005 crore in customs collections, a marginal decline in net excise revenue, an increase of Rs. 1,895 crore in subsidies, higher provision for grants to States and increased revenue expenditure on defence. In order to counteract the worsening in the revenue account and thereby to restrict the magnitude of the gross fiscal deficit, capital disbursements had to be scaled down by Rs. 2,567 crore which in effect reduced aggregate disbursements by Rs. 96 crore. Capital receipts, on the other hand, exceeded the budget estimates as a result of higher external borrowings (net), and recovery of loans coupled with a mopping up of Rs. 2,000 crore through net sales of 182-day Treasury bills which to a great extent offset the decline of Rs. 1,600 crore in small savings collections. Thus, the substantial increase in capital receipts resulted in aggregate receipts being in excess of the budgeted estimates by Rs. 591 crore.

3.6 As regards payments, the enforcement of strict expenditure control resulted in a modest increase of only Rs. 373 crore in non-Plan expenditure over the budget estimates. Plan expenditure, on the other hand, declined and was lower by 2.1 per cent in the revised estimates. A substantial increase in non-Plan expenditure was in respect of subsidies which went up from Rs. 10,395 crore indicated in the budget estimates to Rs. 12,290 crore. The fertiliser subsidy increased from Rs. 4,000 crore to Rs. 4,800 crore following the decision to restrict the actual price increase to 30 per cent as against the average increase of 40 per cent assumed in the budget estimates and also on account of the increase in rupee cost of imported fertilisers. Moreover, an additional provision of Rs. 405 crore had to be made in the revised estimates on account of the exemption provided to small and marginal farmers from the price rise. Food subsidy increased by Rs. 250 crore notwithstanding the increase in issue prices of rice and wheat in December 1991. In addition, a higher provision of Rs. 550 crore was made in res-

pect of export subsidies to meet the residual claims under the Cash Compensatory Scheme.

The Budget for 1992-93

3.7 The Budget for 1992-93 continued to emphasise the need for macro-economic stabilisation through a further reduction of the fiscal deficit. The Budget has thus projected the conventional budget deficit at Rs. 5,389 crore as against Rs. 7,032 crore during 1991-92 (revised estimates). The revenue account would continue to show a gap, though of a substantially lower magnitude at Rs. 13,842 crore as against Rs. 17,081 crore in 1991-92 (Appendix Table III.5). Gross fiscal deficit is expected to come down to Rs. 34,408 crore in 1992-93—a reduction of Rs. 3,384 crore as compared with the revised estimates for 1991-92 or a fall from around 6.5 per cent to 5.0 per cent of GDP.

3.8 The envisaged reduction in fiscal deficit is sought to be achieved through a combination of measures, viz., reduction in the non-interest components of non-Plan expenditure, further disinvestment of equity holdings in public sector enterprises, and non-provision for payment of additional dearness allowance that may fall due in 1992-93. Some of the specific economy measures to contain non-Plan expenditure include cutback in major subsidies to the tune of Rs. 1,849 crore, reduction in non-Plan grants to States and Union Territories, cuts in non-Plan loans to public enterprises and foreign governments and normal increase of 7 per cent in defence expenditure. Besides the reduction in non-Plan non-interest expenditure, Plan expenditure would register a small increase of 4.8 per cent as against 13.4 per cent in 1991-92.

Centre's Plan Outlay

3.9 Keeping in view the objectives and financial targets underlying the Eighth Five-Year Plan which has commenced from April 1, 1992, the Central Plan outlay for 1992-93 has been fixed at Rs. 48,407 crore which represents a step-up of 20.5 per cent over the revised outlay of Rs. 40,172 crore for 1991-92. Budget support for the Plan is expected to be higher at Rs. 18,501 crore in 1992-93 as against Rs. 17,671 crore in 1991-92; its share in total finance would, however, decline from 44 per cent in 1991-92 to 38.2 per cent. The contribution from Internal and Extra-Budgetary Resources (IEBR) of the public sector enterprises is expected to go up from Rs. 22,501 crore in 1991-92 to Rs. 29,906 crore in 1992-93 representing a substantial rise of 32.9 per cent. Consequently, the share of IEBR in total finance would increase from 56 per cent in 1991-92 to 61.8 per cent in 1992-93.

Plan and Non-Plan Expenditure

3.10 The 1992-93 Budget has placed the Plan expenditure during the year at Rs. 34,612 crore—an increase of 4.8 per cent as compared with Rs. 33,032 crore in 1991-92. Within the Plan expenditure, the revenue and the capital components would account for 53 per cent and 47 per cent, respectively, during 1992-93 as compared with 51.3 per cent and 48.7 per cent, respectively, in 1991-92. An increasing proportion of revenue expenditure would imply that a major share of Plan expenditure would be taken up by current items of expenditure, thus cutting into the quantum available for the creation of new assets. The proportion of Plan expenditure in the total expenditure is expected to remain unchanged at the 1991-92 level of 29.2 per cent.

3.11 The Budget for 1992-93 has envisaged containment of overall expenditure, particularly non-interest components of non-Plan expenditure as part of the strategy to correct the fiscal imbalance. Total non-Plan expenditure estimated at Rs. 84,475 crore in 1992-93 would show an increase of 5.5 per cent over that of Rs. 80,070 crore in 1991-92. Among the various components of non-Plan expenditure, interest payments would account for a major share of the increase, absorbing a rising portion of the Central Government income. Total interest payment at Rs. 32,000 crore would increase by 17.4 per cent (or Rs. 4,750 crore) which would be on top of a substantial increase of 26.9 per cent in 1991-92. In fact, excluding interest payments, the other items of non-Plan expenditure would decline by Rs. 345 crore. Adjusted for interest receipts, net interest payments would show a smaller increase of 16.2 per cent in 1992-93.

as against 25.2 per cent in 1991-92. Defence expenditure at Rs. 17,500 crore would be higher by 7 per cent as against an increase of 6 per cent in 1991-92. The process of fiscal adjustment has necessitated substantial pruning of the expenditure on subsidies which would be considerably lower at Rs. 10,487 crore in 1992-93 as against Rs. 12,290 crore in 1991-92.

Chelliah Committee on Tax Reforms and Other Measures

3.12 Recognising the need for a comprehensive reform of both the direct and indirect taxes system, the Budget has proposed to give effect to some of the recommendations of the Chelliah Committee on tax reform. The proposals for restructuring of personal income-tax involved the raising of the tax exemption limit to Rs. 28,000, reduction in the number of income-tax rate slabs and lowering of tax rates with an entry rate of 20 per cent and the maximum marginal rate of 40 per cent. In view of the reduction in tax rates, the Budget has also announced the withdrawal of deductions available under Section 80 CCA (National Savings Scheme), 80 CCB (Equity-Linked Savings Scheme) and 80L (Income from interest on certain securities, deposits, units of UTI, etc.) The scope of Section 88, which provides for tax rebate in respect of specified savings, has been widened by including within its purview contributions to pension funds set up by National Housing Bank and by mutual funds. A presumptive tax in respect of shopkeepers has been introduced to bring small retail traders with an annual turnover below Rs. 5 lakh into the tax net. The Budget also contained proposals to streamline/restructure the existing system in respect of capital gains tax and wealth tax. As regards capital gains, the Budget has proposed that taxable capital gains would be computed after allowing the cost of acquisition of asset to be adjusted for inflation before deducting it from the sale proceeds. In the sphere of wealth tax, a distinction has been made between productive and non-productive assets and it is proposed to exempt non-productive assets (bank deposits, shares, securities, bonds, etc.) from the purview of the tax while non-productive assets like residential houses, urban land, jewellery, bullion, etc., would be taxed at the rate of one per cent of the value in excess of the exemption limit of Rs. 15 lakh. The Budget has announced the Government's intention to set up a National Court of Direct Taxes in order to ensure that litigations in direct tax matters are settled expeditiously.

3.13 In the field of excise duties a number of measures have been proposed for rationalisation and simplification of procedures, rules and regulations with a view to eliminating delays in collection and settlement in the system. The Budget has proposed a switch over from specific rates to a system of ad valorem rates, wherever feasible, so as to ensure buoyancy in revenue on account of increase in prices. As regards customs duties, the peak level of tariff was reduced from the existing 150 per cent to 110 per cent with a few exceptions. The number of duty slabs in respect of the auxiliary import duty has been reduced to four. Tariff rates in respect of selected capital goods have been reduced from 80 per cent to 60 per cent. Import of various raw materials for the petro-chemical industry would attract a duty ranging between 25 per cent and 80 per cent.

3.14 The net revenue yield from the additional taxation measures is indicated in Table 3.2.

Table 3.2 : Revenue Yield from Additional Taxation

(Rupees Crore)			
Tax head	Budget proposals	States share	Net to centre
1	2	3	4
I. Original Budget			
A. Direct Taxes			
(a+b+c)	795	435	360
(a) Corporation Tax	325	—	325
(b) Income Tax	570	435	135
(c) Expenditure Tax	— 100	—	— 100

1	2	3	4
B. Indirect Taxes (a+b)	188	1,065	— 877
(a) Customs Duties	—2,023	..	—2,023
(b) Union Excise Duties	2,211	1,065	1,146
C. Total (A+B)	983	1,500	—517
II. Post-Budget Concessions*			
D. Post-Budget Tax Concessions (a+b)	—847	—271	—575
(a) On March 26, 1992	—245	..	—245
(b) On April 30, 1992	—602	—271	—331
III. After Post-Budget Concessions			
E. Total Revenue Yield (C+D)	136	1,229	—1,093

3.15 Subsequent to the presentation of the Budget, the Finance Minister announced post-Budget tax concessions in two stages which included : (i) further reduction in the import duty on project imports and general machinery, (ii) a partial restoration of the deduction under Section 80L with a reduced ceiling of Rs. 7,000 as against Rs. 13,000 earlier, (iii) increase in the maximum tax rebate available under Section 88 to Rs. 12,000 with a sub-ceiling of Rs. 2,000 in respect of Equity-Linked Savings Scheme, (iv) enlargement of the scope of the presumptive tax, (v) reduction in the rate of tax on capital gains, and (vi) reduction in the import duty on gold from Rs. 450 per 10 grammes to Rs. 220 per 10 grammes. These concessions were expected to result in a total revenue loss of Rs. 847 crore of which Rs. 576 crore would be borne by the Centre and the balance by the States.

3.16 Another significant development related to the abolition of the Foreign Exchange Conservation (Travel) Tax with effect from June 1, 1992 in line with the objective of further reducing the scope for illegal transactions in foreign exchange. According to the budget estimates for 1992-93, Rs. 88 crore was expected to be mobilised from this tax.

3.17 Some more tax concessions were announced on June 19, 1992 in terms of which Central excise and Customs duties in respect of motor cars, light commercial vehicles, television sets, bulk drugs and drug intermediates were reduced. Although these concessions would involve a further loss in revenue of over Rs. 100 crore during a full financial year, much of this loss would be compensated for by increased revenue following improved sales and imports of goods.

State Budgets—1992-93

3.18 The combined budgetary position of all the 25 States, of which nine presented Vote-on-Account budgets in February-March 1992, indicated, at 1991-92 rates of taxation, a higher overall deficit during 1992-93 at Rs. 2,225.3 crore as compared with the deficit of Rs. 1,667.1 crore in 1991-92 (RE) and a surplus of Rs. 70.3 crore in 1990-91 (Accounts). The revenue yield from Additional Resource Mobilisation (ARM) envisaged by 13 States would be lower at Rs. 627.6 crore as against Rs. 967.8 crore mobilised by 15 States in 1991-92. The States' share in the Centre's new tax proposals in the Union Budget for 1992-93 was placed at Rs. 1,500 crore*. After adjusting for the revenue yield from States' ARM and their share in Central taxes which together amount to Rs. 2,127.6 crore, the consolidated budgetary position of all States would show a much smaller deficit of Rs. 97.7 crore in 1992-93 as against the revised deficit of Rs. 1,667.1 crore in 1991-92.

3.19 The gross fiscal deficit of States has increased steadily from Rs. 3,712 crore in 1980-81 to Rs. 9,269 crore in 1986-87. Thereafter, the increase has been quite sharp and the deficit widened further from Rs. 11,219 crore in 1987-88 to Rs. 18,815 crore in 1990-91 and the revised estimates for 1991-92 have placed it still higher at Rs. 20,219 crore. According to the budget estimates for 1992-93, the fiscal deficit has gone up further to Rs. 20,968 crore—an increase of 3.7 per cent. The increasing size of the overall resources gap

*Post-budget tax concessions announced by the Union Finance Minister would, however, result in a total revenue loss of Rs. 847 crore of which Rs. 271 crore would be borne by the States. Hence the States' share in Central taxes would stand reduced from Rs. 1,500 crore to Rs. 1,229 crore.

of the States has been mainly the outcome of the worsening of the revenue account which has run high deficits since 1987-88. In 1992-93, the combined revenue deficit budgeted at Rs. 3,669 crore was considerably lower than Rs. 5,344 crore in 1991-92 (RE). Revenue deficit accounted for 26.4 per cent of the gross fiscal deficit in 1991-92 while the budgeted revenue deficit for 1992-93 accounted for 17.5 per cent. States' gross fiscal deficit as percentage of GDP was a fraction lower at 3.3 per cent in 1991-92 as against 3.6 per cent in 1990-91; it is expected to register a further decline to 3.0 per cent in 1992-93 (Appendix Table III.6).

3.20 The financing pattern of the States' resources gap revealed that on an average half of the gap was financed through loans from the Central Government while the balance was met through market borrowings, State Provident Funds and others (Appendix Table III.7).

Ways and Means Advances and Overdrafts of States

3.21 The limit for normal Ways and Means Advances (WMA) provided by the Reserve Bank to 23 States to enable them to tide over temporary shortfall in revenues remained unchanged at Rs. 744.8 crore. The limit for special WMAs granted to these States against the pledge of Central Government securities also remained unaltered at Rs. 266.0 crore. During 1991-92, all State Governments complied with the Overdraft Regulation Scheme, 1985, under which overdrafts have to be cleared within the stipulated period of seven consecutive working days.

Consolidated Budgetary Position : Centre and States

3.22 According to revised estimates for 1991-92, total receipts of Centre and States were higher at Rs. 1,80,665 crore (Rs. 2,572 crore) as compared with the budget estimates of Rs. 1,78,093 crore. Revenue receipts at Rs. 1,27,078 crore were lower than the budget figure of Rs. 1,27,971 crore while capital receipts at Rs. 53,587 crore were considerably in excess of the budget estimates of Rs. 50,122 crore. Aggregate disbursements stood at Rs. 1,89,364 crore as against Rs. 1,87,006 crore in the budget estimates—an increase of Rs. 2,358 crore. The combined overall deficit was lower at Rs. 8,699 crore as compared with Rs. 8,913 crore indicated in the budget estimates.

3.23 The budget estimates for 1992-93 have placed the overall deficit of the Centre and States at Rs. 5,487 crore which is substantially lower (36.9 per cent) than Rs. 8,699 crore in the previous year (Appendix Table III.8). The reduced level of the combined deficit is the result of the projected decline in Centre's deficit from Rs. 7,032 crore in 1991-92 to Rs. 5,389 crore in 1992-93 and that of the States from Rs. 1,667 crore to Rs. 98 crore, respectively. Aggregate receipts of the Centre and States at Rs. 1,98,617 crore in 1992-93 would show a smaller increase of 9.9 per cent as compared with 16.1 per cent in 1991-92. Aggregate disbursements of the Centre and States budgeted at Rs. 2,04,104 crore in 1992-93 would also increase at a slower rate of 7.8 per cent as against 13.5 per cent in the previous year (Appendix Tables III.9 and III.10).

Market Borrowings

3.24 Gross market borrowings by the Central Government amounted to Rs. 8,919.0 crore during 1991-92. Net market borrowings were placed at Rs. 7,501 crore as against Rs. 8,001 crore in 1990-91; this reflected the concerted effort to reduce the reliance on market borrowing for financing Government expenditure. In the case of State Governments, also there were no repayment obligations during 1991-92, gross and net market borrowings, amounted to Rs. 3,364 crore. The net market borrowings of the Central and State Governments, and of the Central and State-guaranteed institutions amounted to Rs. 14,652 crore in 1991-92 as against Rs. 14,097 crore in 1990-91 (Appendix Table III.11).

Coupon Rates on Central and State Government Loans

3.25 The coupon rates on Central and State Government loans were changed rather significantly during 1991-92 basically

to make Government securities more attractive for investment considering the economic conditions and the prevailing interest rate structure in the country (Appendix Table III.12) some of the changes have been explained in Section I. Apart from issuing 5-year and 10-year securities on an auction basis, the Government have raised the coupon rates on the Centre's, as also the State securities, of 15-year maturity to 13.0 per cent.

Reserve Bank's Support to Central Loans

3.26 The Reserve Bank's initial subscription to the Central Government loans during 1991-92 at Rs. 4,822 crore (54.1 per cent of the gross market borrowings) was substantially higher than Rs. 4,432 crore (49.3 per cent of the gross market borrowings) during the previous year. During 1991-92, Reserve Bank's holdings of Central Government dated securities decreased by Rs. 295 crore as compared with an increase of Rs. 3,481 crore during 1990-91. Apart from this, the Central Government issued special securities to the Reserve Bank of India towards funding of ad hoc Treasury bills to the tune of Rs. 5,000 crore during 1991-92 as against Rs. 30,000 crore in 1990-91.

3.27 The gross and net market borrowings by the Central Government budgeted at Rs. 6,151 crore and Rs. 5,000 crore, respectively, during 1992-93 are substantially lower than the amounts mobilised during 1991-92. This mainly reflects the reduction in the SLR for banks from 38.5 per cent to 30.0 per cent on incremental domestic liabilities over the April 3, 1992 level.

Bonds of Public Sector Undertakings (PSUs)

3.28 During the year, a large number of Central public sector undertakings, according to the budget documents, were to raise resources through the issue of bonds/debentures in the domestic market amounting to Rs. 5,722 crore (revised estimates) and they also resorted to external commercial borrowings/suppliers' credit to the tune of Rs. 1,854 crore. These undertakings are being increasingly encouraged to borrow at market-related rates and in this context the interest rate ceiling on such bonds was removed in July 1991. According to the Union Budget for 1992-93, a total amount of Rs. 11,980 crore (Rs. 6,058 crore through issue of bonds/debentures in the domestic market and a substantially higher amount of Rs. 5,922 crore by way of commercial borrowings/suppliers' credit) is sought to be mobilised.

3.29 On the basis of provisional information available so far, public sector bonds issued during 1991-92 helped raise Rs. 4,227.82 crore. In 1990-91, total realisation from the issue of PSU bonds was as much as Rs. 5,463.15 crore. Between 1985-86 and 1991-92, the total amount thus raised amounted to about Rs. 20,630 crore. A large proportion of this amount was on account of amounts raised through tax-free PSU bonds (Table 3.3).

Table 3.3 : Public Sector Undertakings—Issue of Bonds
During 1985-86 to 1991-92

Year	(Rupees crore)		
	Tax Free Bonds	Taxable Bonds	Total (2+3)
1	2	3	4
1985-86	..	353.69	353.69
1986-87	898.04	776.13	1,674.17
1987-88	1,737.32	946.92	2,684.24
1988-89	2,080.00	417.72	2,497.72
1989-90	2,597.00	1,132.00	3,729.00
1990-91	2,345.00	3,118.15	5,463.15
1991-92	2,161.64	2,066.18	4,227.82

Source : Returns received from the respective public sector undertakings.

IV. MONETARY AND PRICE TRENDS BANKING AND MONETARY TRENDS

4.1 Monetary developments during the financial year 1991-92 were characterised by a striking acceleration in liquidity growth primarily due to large accretion of foreign exchange assets of the banking sector in sharp contrast to a massive loss of such assets in 1990-91 that had resulted in subdued monetary growth in that year; there was in addition the expansionary impact arising from the growth of domestic primary liquidity. Both net bank credit to Government and bank credit to the commercial sector expanded at a much slower pace in 1991-92. This can be attributed to various measures of macro-economic stabilisation initiated by the Government towards fiscal correction and the tight monetary policy measures against the background of high inflation and difficult external payments position. There was an acceleration in bank deposits growth during 1991-92 and a slowdown in credit expansion of scheduled commercial banks.

MONETARY DEVELOPMENTS

4.2 Monetary expansion during 1991-92, in terms of both broad money (M3) and narrow money (M1), was consider-

ably higher. M3 registered an increase of Rs. 49,256 crore (18.5 per cent) as compared with Rs. 34,878 crore (15.1 per cent) in the previous year. The expansion of M3 in 1991-92 was markedly higher than the desired expansion of 13 per cent set out at the time of formulating the macro-economic objectives for the year. The overriding need to attract inflows from non-residents, to enable a build back of foreign exchange reserves, which had earlier dipped to dangerously low levels, weighed as a major factor which dissuaded the authorities from sterilising the growing liquidity associated with such foreign exchange reserve build-up.

4.3 All the components of M3 experienced higher pace of expansion in 1991-92 as compared with 1990-91, the most striking being the case of demand deposits (an increase of 32.7 per cent as against 14.7 per cent in the previous year) reflecting the margin money deposits kept by the canalising agencies, and the volatility in money flows associated with the stock market boom (Appendix Table IV.1). The pace of currency expansion at 15.4 per cent was somewhat higher than the increase of 14.6 per cent in the previous year. In the additional accruals of time deposits of Rs. 28,037 crore, about 9,500 crore represented foreign currency deposits including those under the India Development Bonds.

Table 4.1 : Variation in M3 : Components and Sources

Item	(Rupees crore)			
	1991-92P	1990-91	(April—June)	
			1992-93P	1991-92P
1	2	3	4	5
M1	+21,219 (+22.8)	+11,832 (+14.6)	+7,753 (+6.8)	+6,267 (+6.7)
M3	+49,256 (+18.5)	+34,878 (+15.1)	18,243 (+5.8)	+12,535 (+4.7)
Currency	+8,184 (+15.4)	+6,748 (+14.5)	+2,719 (+4.4)	+3,737 (+7.0)
Aggregate deposits	+40,850 (+19.3)	+28,054 (+15.2)	10,535 (+4.2)	+8,064 (+3.8)
of which				
External Deposits*	+5,606 (+24.7)	+4,777 (+26.7)	+3,909 (+13.8)	+203 (+0.9)
1. All foreign currency deposits	+4,812 (+30.8)	+4,088 (+35.4)	+3,427 (+16.8)	—35 (+0.2)
2. NRE deposits	+794 (+11.3)	+689 (+16.8)	+482 (+6.2)	+238 (+3.4)
Demand deposits	+12,813 (+32.7)	+5,008 (+14.7)	+44 (+0.4)	+1,796 (+4.6)
Time deposits	+28,037 (+16.2)	+23,046 (+15.4)	+10,490 (+5.2)	+6,268 (+3.6)
Net bank credit to Government	+18,101 (+12.9)	+23,042 (+19.7)	+6,391 (+4.0)	+10,445 (+7.5)
RBI's net credit to Government of which :	5,168 (+5.8)	+15,165 (+20.6)	+2,320 (+2.5)	+7,081 (+8.0)
to Centre	+5,508 (+6.3)	+14,745 (+20.5)	+3,913 (+4.2)	+9,170 (+10.6)
Bank credit to commercial sector	+19,296 (+11.2)	+20,065 (+13.2)	+8,493 (+4.4)	+89 (+0.1)
Net foreign exchange assets	+10,855 (+125.2)	+1,854 (+27.2)	+849 (+4.3)	+1,225 (+14.1)
Net non-monetary liabilities of the banking sector	—929 (—1.6)	+10,149 (+21.9)	—2,510 (—4.5)	+3,204 (+5.7)
RBI's net non-monetary liabilities	+381 (+1.4)	+9,486 (+54.1)	—2,195 (—8.0)	+257 (+1.0)

Note : Figures in brackets are percentage variations.

P : Provisional.

* Relate to scheduled commercial banks only.

4.4 Among the sources, net bank credit to Government registered a much lower expansion of Rs. 18,101 crore (12.9 per cent) as against Rs. 23,042 crore (19.7 per cent). This trend of a lower expansion is more noticeable in net Reserve Bank credit to Central Government (Rs. 5,508 crore or 6.3 per cent as compared with Rs. 14,745 crore or 20.5 per cent in 1990-91). However, the figures of net Reserve Bank credit to Central Government ruled for above this level for most part of the year before dropping sharply in the last week of the financial year and as already indicated in Section III, the fortnightly average net RBI credit to Central Government was high in 1991-92. Bank credit to commercial sector, too, recorded a lower increase of Rs. 19,296 crore (11.2 per cent) as against Rs. 20,065 crore (13.2 per cent) in the previous year. Net foreign exchange assets of the banking sector, excluding the revaluation in the value of gold, registered a sizeable expansion of Rs. 9,141 crore (105.4 per cent) as against a reduction of Rs. 4,694 crore (—68.8 per cent) during 1990-91. A substantial expansionary impulse in monetary growth in 1991-92 also originated in the reduced expansion in the net non-monetary liabilities of the Reserve Bank. An important factor contributing to this had been the exchange loss incurred by the Reserve Bank, placed at Rs. 5,233 crore, due to withdrawal/renewal of FCNR deposits.

Reserve Money and Net Domestic Assets of the Reserve Bank

4.5 The expansion of reserve money was Rs. 11,730 crore or 13.4 per cent in 1991-92 as against Rs. 10,188 crore or 13.1 per cent in 1990-91 (Appendix Table 4.2). The

Reserve Bank of India's net domestic assets (NDA)* showed a very small increase of Rs. 875 crore or 1.1 per cent in 1991-92 as against Rs. 8,273 crore or 11.6 per cent in the previous year. The targets on expansion of NDA and net RBI credit to the Central Government during 1991-92 were fully met (Table 4.2). As observed earlier, the continued volatility in these indicators has implied that the underlying growth of primary liquidity has been much larger than indicated by the end-of-period numbers.

Monetary Programme for 1992-93

4.6 The monetary programme for 1992-93 includes inter alia quarterly ceilings on net domestic assets (NDA) of the RBI and a sub-ceiling on net RBI credit to the Centre; there is also a quarterly indicative ceiling on total net bank credit to general Government (i.e. Central and State Governments). These are circumscribed by the overall monetary growth target of about 10.4 per cent over the year. The quarterly NDA ceilings are to be adjusted for (i) changes in official exchange rate, (ii) changes in the valuation of gold, (iii) changes in reserve requirements, and (iv) changes in net international reserves (i.e. foreign exchange reserves net of the use of IMF credit and RBI short-term liabilities, if any). Compliance with the ceilings on RBI variables, i.e. NDA and net RBI credit to Central Government, will be determined by taking a simple average of four Fridays leading up to and including the last reporting Friday of June, September and December quarters; for the March 1993 quarter it would be the average of the four Fridays and March 31 after the closure of Government accounts.

Table 4.2 : Ceiling on Net Domestic Assets and Actual Performance

Item	Outstand- ing March 31, 1991	Targeted Expansion over March 31, 1991				Targeted Outstand- ing as on March 31, 1992	Actual Performance : Expansion over March 31, 1991				Actual outstand- ing as on March 31 1992P
		End- Sep- tember 1991	End-Oct. (Novem- ber 1) 1991	End- Decem- ber 1991	End- March 1992		End- Sept. 20 1991	End-Oct. (Novem- ber 1) 1991	End- Dec. 27 1991	End March 31 1992P	
		3	4	5	6		8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reserve Money (RM)*	87,779	3,921	9,340	9,340	13,682	1,01,430	2,063	3,437	8,331	11,730	99,509
Net Domestic Assets (NDA)	79,796	5,094 (8,023)	10,140 (8,023)	10,140 (8,023)	14,584 (12,870)	94,350 (92,636)	2,176	1,583	1,924	87.5	80,671
RBI Credit to Govt of which :	88,848	10,012	10,040	10,110	7,712	96,560	7,062	7,880	8,146	5,168	94,016
Credit to Centre	86,758	12,002	12,002	12,000	8,802	95,560	8,891	9,565	9,812	5,508	92,266
RBI Claims on others of which :	16,349	—2,418	—590	3,030	10,372	26,720	—3,436	—5,918 HHHH	—6,218	—3,987	12,362
(i) Banks	10,007						2,527	—5,027	—5,408	—4,905	5,102
(ii) Commercial sector	6,342						909	—886	—810	918	7,260
Other items (net)	25,401	2,499	2,670	3,000	3,499	28,930	1,450	384	4	306	25,707
Net Foreign Assets	7,983	—1,173	—1,040	—800	—903	7,080	—113	1,854	6,407	10,855	18,838
*RM Components :											
Currency	—	—	—	—	—	—	775	3,274	6,347	8,449	63,731
Bankers' Deposits	—	—	—	—	—	—	948	—95	1,753	3,059	34,882

*Net domestic assets equal reserve money minus net foreign exchange assets of RBI.

Figures in brackets are net of the increase in gold value over the amount of Rs. 6,548 crore valued at the base price of Rs. 6,388 per ounce as on March 31, 1991.

P : Provisional.

4.7 As set out in Table 4.3, the performance criteria during the first quarter (April-June 1992) in respect of NDA and net RBI credit to the Centre, as also the net bank credit

to the general Government, have been met. The broad money growth, however, has been higher than the targeted trajectory.

Table : 4.3 Monetary Programme for 1992-93

(Rupees Crore)

Item	Outstand- ing as on March 31, 1992	Targeted Expansion over March 31, 1992				Targeted Outstand- ing as on March 31, 1993	Actual Perfor- mance : Expansion at End- June 1992 over March 31, 1992 P
		End- June 1992	End- September 1992	End- December 1992	End- March 1992		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Reserve Money							
Reserve Money	99,509	7,100	5,900	10,900	13,700	1,13,200	6,027
Net Domestic Assets (NDA)	80,671	10,900	9,300	13,600	16,200	96,900	5,178
		(11,100)@					
RBI Credit to Government	94,016	7,300	7,500	7,400	5,800	99,200	2,320
o/w Credit to Centre	92,266	7,400	7,600	7,000	6,100	98,400	3,913
RBI claims on others	12,367	3,700	2,100	6,500	10,700	23,100	663
of which :							
(i) banks	5,102						570
(ii) commercial sector	7,260						93
Other items (net)	25,707					25,100	2,195
Net Foreign Assets	18,838	—3,800	—3,400	—2,700	—2,500	16,300	849
2. Indicative Targets							
Net Bank credit to general	1,58,294	9,400	10,600	11,400	10,400	16,870	6,391
Government (Ceiling)							(4.0)
Broad Money (M3)	3,15,084	9,600	11,700	25,200	32,700	3,47,800	18,243
		(3.0)	(3.7)	(8.0)	(10.4)		(5.8)

@ Net of the revaluation of Rs. 200 crore in gold value up to June 1992 over the amount of Rs. 8,894 crore valued at the base price of Rs. 8,011 per ounce as on March 31, 1992. Other adjustments have not been made. Figures in brackets represent percentages. P : Provisional.

Monetary Trends during the First Quarter : 1992-93

4.8 The pace of monetary expansion during the first quarter (April-June) of the financial year 1992-93 was faster than that in the previous year. Broad money (M3) increased by Rs. 18,243 crore (5.8 per cent) as compared with Rs. 12,535 crore (4.7 per cent). Among the components, aggregate deposits registered higher increases while currency with the public recorded a lower pace of expansion. On the sources side, net bank credit to Government was lower, while bank credit to the commercial sector was higher as compared with the corresponding period of 1991-92. Net foreign exchange assets of the banking sector experienced a substantial accretion (Appendix Table IV.1). Reserve money also registered a higher expansion of Rs. 6,027 crore (6.1 per cent) in this period as against Rs. 4,725 crore (5.4 per cent) in the previous year. The higher expansion was mainly due to substantial rise in RBI credit to commercial sector and also larger accretion to net foreign exchange assets of the RBI due to some special transactions.

Some Monetary Relationships

4.9 The year 1991-92 experienced certain peculiarities in the monetary relationships reflecting short-term responses to policy impulses and impulses from real and monetary sector developments. First, the fiscal and monetary instruments were used actively to contain the reserve money growth. Secondly, M3 grew at a fast pace essentially due to the size-

able foreign exchange inflow and also the large average growth of primary liquidity from domestic sources. Thirdly, real GDP growth, targeted at 4.0 per cent, actually turned out to be lower at a little less than 2.0 per cent and the inflationary pressures strengthened. As a result of these factors, there occurred an increase in income velocity of currency as well as M3 (Appendix Table IV.3). The incremental money multiplier (M3/RM), on a point-to-point basis, also showed a substantial increase following reductions in both the currency-deposit ratio and the bank reserves-deposit ratio (Appendix Table IV.4).

BANKING TRENDS

4.10 A phenomenal increase in aggregate deposits, especially demand deposits, and a noticeably low growth of overall bank credit, characterised the scheduled commercial banks' operations during the financial year 1991-92 (March 22, 1991 to March 20, 1992).

4.11 Expansion in aggregate deposits, accelerated to Rs. 38,216 crore (19.8 per cent) from the previous year's level of Rs. 25,583 crore (15.3 per cent) and outstripped substantially the revised working estimate of Rs. 28,500 crore announced in the credit policy for the second half of 1991-92 (Appendix Table IV.5). Apart from the sizeable

foreign exchange accruals, the restoration of banks' competitiveness in attracting deposits by means of periodical enhancements in bank deposit rates, special factors such as large amounts of additional cash margins imposed against imports and kept by borrowers, the margin money deposits

kept by the canalising agencies, and the float money associated with the buoyancy observed in the capital market, contributed to the rapid increase in bank deposits during 1991-92. The tempo of deposit growth has continued during the first quarter of 1992-93.

Table 4.4 : Banking Variables—Growth Rates

Variables	(In per cent)						
	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	April-June	
						1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
Aggregate Deposits	19.8	15.3	19.1	18.7	14.9	4.5	3.4
Demand Deposits	35.8	15.0	23.6	15.3	5.3	0.3	3.7
Time Deposits	16.5	15.4	18.2	19.4	17.1	5.6	3.
Bank Credit	8.0	14.6	19.8	20.1	11.4	6.5	0.8
Food Credit	3.6	124.6	160.9	64.9	57.1	9.2	18.0
Non-food Credit	8.2	12.4	18.5	22.8	17.4	6.4	0.1
Investments	20.2	16.6	17.8	17.5	20.5	4.5	4.2

Note : No sign is indicated for positive variation.

4.12 Notwithstanding the accelerated expansion in aggregate deposits, total bank credit witnessed a markedly slower pace of expansion. Food credit expansion was modest at Rs. 164 crore as against Rs. 2500 crore during 1990-91 on account of a fall in procurement of foodgrains in the year alongside higher offtake leading to a steep fall in their stock levels. Restrictive credit policy measures and general slowdown of the economy together with the increasing cost of credit brought about a lower expansion in non-food credit placed at Rs. 9,217 crore (8.2 per cent) as compared with Rs. 12,348 crore (12.4 per cent) in 1990-91 and Rs. 15,497 crore (18.5 per cent) in 1989-90. In line with the large expansion in bank deposits, banks' investments in Government and other approved securities increased by a much higher amount than that in the previous year.

4.13 In recent years, scheduled commercial banks have been reporting an unusually large rise in aggregate deposits and bank credit in the last week of March. In 1991-92 this phenomenon was not visible (Appendix Table IV.6). The increase in aggregate deposits in the seven-day period March 20 to March 27, 1992 of 3.0 per cent and that in bank credit of 4.7 per cent, as reported by banks, is modest as compared with large increases reported in previous years. The fact that the reduced statutory liquidity ratio of 30 per cent was applicable on the increase in net demand and time liabilities over the level of April 3, 1992 could have discouraged banks from resorting to high year-end deposit growth. This fact is also borne out to an extent when the rise in deposits, as between the last reporting Friday of March and March 31, 1992, of Rs. 11,310 crore (4.9 per cent) as compared with a higher amount of Rs. 12,232 crore (6.4 per cent) mobilised by the banks between the last reporting Friday of March 1991 and March 31, 1991. The unwinding of these deposits in the first few days of April was more striking this year than in the past, reflecting the influence of incremental SLR prescription referred to above. Within 3 days between March 31 and April 3, 1992, there was an absolute decline of Rs. 7,824 crore in aggregate deposits constituting 69 per cent of the accrual between the last reporting Friday of March and March 31, 1992 (as against a decline of Rs. 6,705 crore during the 5-day period—March 31, 1991 to April 5, 1991).

4.14 With a substantial amount of deposit resources available to the banks, the use of non-deposit resources by banks showed a distinct decline during 1991-92 (Appendix Table IV.7). On an aggregate basis, the use of additional non-deposit resources during 1991-92 declined by Rs. 1,025 crore; during 1990-91 banks had used additional non-deposit resources to the tune of Rs. 65 crore.

TRENDS IN THE FIRST QUARTER : 1992-93

4.15 The accretion to aggregate deposits was higher at Rs. 10,438 crore (4.5 per cent) as compared with that of Rs. 6,566 crore (3.4 per cent) in the comparable quarter of 1991-92. The expansion in bank credit was even more striking at Rs. 8,166 crore (6.5 per cent) as compared to Rs. 960 crore (0.8 per cent) in the previous year.

NON-FOOD CREDIT EXPANSION DURING 1992-93 (UP TO JULY 1992)

4.16 There has occurred a phenomenal increase in non-food credit rendered by scheduled commercial banks during the current year so far (up to July 24, 1992). The increase during this four month period was Rs. 9,994 crore (or 8.3 per cent) as against the actual increase of only Rs. 714 crore (or 0.6 per cent) and Rs. 874 crore (or 0.9 per cent), respectively, during the corresponding periods of 1991-92 and 1990-91 (Table 4.5). The increase during the four-month period exceeded the increase during the entire financial year 1991-92 at Rs. 9,127 crore (or 8.2 per cent). There is some indication of an inventory build-up in some sectors. When the April 1992 credit policy was announced, it was visualised that non-food credit expansion would be around Rs. 4,000 crore (or 3.3 per cent) for the first half of 1992-93.

Table 4.5 : Non-Food credit expansion of scheduled Commercial Banks

Financial Year	Outstanding	(Rupees crore)	
		Variations	
		Absolute	Percentage
1	2	3	4
Full Year			
1991-92	1,20,922	9,127	8.2
1990-91	1,11,795	12,348	12.4
1989-90	99,447	15,497	18.5
Period so far			
1992-93			
up to July 24, 1992*	1,30,916	9,994	8.3
1991-92			
up to July 26, 1991	1,12,509	714	0.6
1990-91			
July 27, 1990	1,00,320	874	0.9

*Provisional.

SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT

4.17 Data on sectoral deployment of gross bank credit for the financial year, 1991-92 indicate that expansion in non-food gross bank credit was substantially lower this year (Appendix Table IV.8). The industry-wise break-up of incremental credit to industry (Appendix Table IV.3) shows that credit expansion to all engineering, chemicals group, coal, iron and steel, other metals and metal products, cotton textiles, other textiles, paper and paper products and constructions in the main decelerated.

RBI REFINANCE

4.18 Considering the paramount need to promote exports and also to provide greater incentive to banks to finance exports, export credit refinance policy was further liberalised during the year. The increase in export credit interest rates together with the liberalisation of the export credit refinance formula acted as major incentives to banks to increase the flow of credit to the export sector (Appendix Table IV.10).

Table 4.6 : Export Credit Refinance

As on	Export Credit (Outstand- ing)	Export Credit Refinance Limits Rupees crore	Ratio of Col. (3) to Col. (2) (Per cent)
1	2	3	4
March 22, 1991	8,863	4,129	46.6
March 20, 1992	10,695	5,594	52.3
June 26, 1992	12,020	7,163	60.0
July 24, 1992	12,365	7,656	61.9

4.19 As referred to earlier, a new scheme of refinance against post-shipment export credit denominated in US dollar was introduced with effect from January 4, 1992, under which banks are provided export credit refinance equivalent to 133 1/3 per cent of the post-shipment export credit denominated in U. S. dollars extended by them to the exporters. In order to make the scheme more attractive, it was further liberalised in February and April 1992. The dollar-denominated export credit increased from Rs. 23 crore as on April 3, 1992 to Rs. 390 crore as on June 24, 1992. The refinance limits under the new scheme during the above period increased from Rs. 31 crore to Rs. 519 crore.

TRENDS IN THE SHORT-TERM MONEY MARKET

4.20 Discount and Finance House of India (DFHI) has been seeking to develop an active secondary market for the money market instruments and integrate various segments of the market in order to facilitate the smoothening of short-term liquidity imbalances. Its turnover in call money market was significantly higher at Rs. 2,96,862 crore in 1991-92 as compared with Rs. 2,02,792 crore in 1990-91. As a result, the daily average lendings by DFHI in the call money market increased to Rs. 813 crore in 1991-92 as against Rs. 546 crore in 1990-91. There was an increase in the cumulative turnover of DFHI in money market instruments during 1991-92 as also in the first few months of 1992-93. Appendix Tables IV 11, 12 and 13).

Call Money Market

4.21 After witnessing sharp volatility during April-June 1991, the call money rates tended to stabilise at lower levels in July 1991. DFHI's weighted average lending rates came down from 23.4 per cent in July 1991 to 11.0 per cent in December 1991 and remained around that level till the last week of March 1992 (Appendix Table IV.14). The easy conditions in the call money market were due to the excess short-term liquidity in the financial system on account of foreign inward remittances, counterpart funds of India Development Bond and sluggish demand for non-food credit. As a result, the average daily borrowings of 32 major scheduled

commercial banks in the call money market came down from around Rs. 7,200 crore in July 1991 to around Rs. 5,700 crore in January 1992. The average daily lending by these commercial banks in the call money market increased from around Rs. 1,780 crore in July 1991 to around Rs. 3,420 crore in April 1992. The average daily borrowings of these 32 major scheduled commercial banks was around Rs. 6,520 crore in April 1992. With the increased resources of the banking system, bank's borrowings in the call money market from financial institutions were reduced. The daily average lending of financial institutions in the call money market declined from around Rs. 5,630 crore in June 1991 to around Rs. 3,760 crore in April 1992.

4.22 During the months of April and May 1992, there was a flare up in interest rates with rates reaching dizzy heights of 100 per cent on April 28, 1992. The volatility in the call rate was caused by increased borrowings by some banks to cover their enhanced CRR requirements on year-end increase in deposits, inadequate supply of call funds and uncertainty in the market in the context of irregularities in funds management by commercial banks and financial institutions, particularly in relation to their operations in Government securities. By the end of May 1992, however, call money rates subsided to lower levels of 15-20 per cent. During the month of June, inter-bank call money market ruled fairly easy with a marginal upward movement by the middle of June 1992. The rates firmed up to 20-25 per cent thereafter, for some time but by the end of June 1992 they declined to 2-3 per cent which were short-lived with the rates ruling in the range of 10 to 15 per cent in July 1992.

182—Day Treasury Bills

4.23 There was an overwhelming response to 182-day Treasury bills in the fiscal year 1991-92. The outstanding amount of 182-day Treasury bills as at the end of March 1992 was Rs. 3985.52 crore as compared with Rs. 1077.59 crore as at the end of March 1991 (Appendix Table IV.15). During the period under review, the cut-off yield on these bills moved between 8.77 per cent to 10.08 per cent per annum. There was an auction on April 11, 1992 (the last held in this maturity in the current year so far) at which bids worth Rs. 245 crore were accepted at a cut-off yield of 8.77 per cent.

364—Day Treasury Bills

4.24 As part of the overall development of the Government securities market, the Government of India decided in April 1992 to float Treasury bills of varying maturities up to 364 days on an auction basis. During the period up to August 1992, nine auctions were held for 364-day Treasury bills and the outstanding amount as on August 19, 1992 was Rs. 7,159.63 crore (Appendix Table IV.16). The cut-off yield on these bills in the first five auctions was 11.42 per cent, while the cut-off yields in the last four auctions were 11.36 per cent, 11.27 per cent, 11.20 per cent and 11.17 per cent per annum, respectively.

Certificates of Deposit and Commercial Paper

4.25 The volume of Certificates of Deposit (CDs) has been growing and as on June 12, 1992 the outstanding amounted to Rs. 6,556 crore (Appendix Table IV.17). While the primary issues have been increasing, the transactions in the secondary market have not developed as holders have a strong preference to hold the CDs to maturity. This points to the possibility that relative to demand, banks are pricing the interest rate on CDs at a somewhat higher level than necessary. While the primary market in Commercial Paper (CP) has made significant progress and outstanding has increased from Rs. 64.70 crore as on June 30, 1991 to Rs. 145.05 crore as on July 31, 1992, the secondary market is yet to develop.

PRICE TRENDS

4.26 A disquieting aspect of the macro-economic scene during 1991-92 was the further accentuation of inflationary trends which began towards the second half of the previous year (Table 4.7). This could be attributed partly to certain macro-level imbalances and partly to a number of sectoral developments. The pressure of excess demand, generating

Table 4.7 : Annual Rate of Inflation in Terms of WPI
(Point-to-Point 12-Month Period Increase)

(In Per cent)					
At the end of	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6
April	+13.6	+11.4	+9.0	+5.9	+9.6
May	+12.9	+12.3	+8.4	+7.2	+9.3
June	+11.3P	+12.3	+9.4	+6.5	+9.5
July	+9.3P	+14.5	+9.3	+6.4	+8.3
August	+8.7P*	+16.4	+7.6	+8.9	+6.3
September		+15.9	+7.9	+9.0	+6.9
October		+14.3	+10.1	+7.6	+7.3
November		+14.6	+11.1	+7.5	+7.0
December		+14.3	+12.6	+7.7	+4.4
January		+12.9	+13.5	+8.1	+5.6
February		+13.2	+13.2	+8.7	+5.3
March		+13.6	+12.1	+9.1	+5.7

P : Provisional.

* Up to August 8, 1992.

from the large and persistent fiscal deficits over the years, resulted in an excessive liquidity expansion, thereby fuelling inflationary pressures in the economy. The other sources of pressures have been very many : uneven progress of monsoon until the end of August 1991 and the consequent stimulus to price expectations; supply-demand imbalances in sensitive commodities like pulses, edible oils, raw cotton, etc., due to shortfall in domestic production and constraints in augmenting their domestic availability caused by foreign exchange shortage; exchange rate adjustments in early July 1991 leading to an increase in import costs contributing to some cost-push in import-intensive industries; decline in industrial production, especially in the manufacturing sector; a sharp increase in procurement prices of cereals and consequent rise in their issue prices; increase in prices of administered items such as, coal, petroleum products (other than diesel and kerosene), fertilisers and electricity; and increases in excise duties in the Union Budgets for 1991-92 and 1992-93.

4.27 The increase in the general index of wholesale prices (base : 1981-82=100), on a point-to-point basis, was 9.1 per cent in 1989-90 and 12.1 per cent in 1990-91; it further rose to 13.6 per cent in 1991-92. The increase on an average basis at 13.7 per cent was also higher than that of 10.3 per cent in the previous year (Appendix Table IV.19). There was no noticeable seasonal let-up both in 1990-91 and 1991-92 (Appendix Table IV.18).

4.28 The prices of primary articles' recorded the largest increase (15.3 per cent as against 17.1 per cent) (Appendix Table IV.19). Again, the increase in prices of 'food articles' in this major group was of the order of 20.9 per cent on top of an increase of 18.9 per cent in 1990-91. Among food items, rice, wheat, coarse cereals and sugar witnessed increases in the range of 12.3 per cent and 65.5 per cent. Raw cotton prices also went up by 24.7 per cent. The index of the 'fuel' group rose significantly owing to hikes in the administered prices of its sub-groups, viz., coal (27.4 per cent), mineral oils (9.2 per cent) and electricity (13.7 per cent). The substantial increases in the prices of the 'primary articles' and the 'fuel' group and the hike in the administered prices of fertilisers (28.8 per cent), cement (17.4 per cent) and non-ferrous metals excluding aluminium (9.7 per cent) imparted considerable upward push to prices of the 'manufactured products' group. As a result, this group contributed the most to the rise in the general price level in 1991-92 (52.7 per cent as against 43.0 per cent in 1990-91) (Appendix Table IV.20).

4.29 Apart from the price increase getting generalised, commodities of common consumption faced by far the sharpest increase in the past two years which was reflected in the sizeable increase in the specially constructed composite price index for 'food items' (Table 4.8).

Table 4.8 : Composite WPI of Food Items & Non-food Items

Item	Weight	Percentage Variation			Weighted Contribution		
		1991-92	1990-91	1989-90	1991-92	1990-91	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8
All Commodities	100.000	13.6	12.1	9.1	100.0	100.0	100.0
Food Items/Composite	27.529	17.2	16.9	5.7	37.0	39.0	18.2
(a) Food Articles (Primary)	17.386	20.9	18.9	2.1	29.4	28.1	4.5
(b) Food Products (Manfd.)	10.143	10.2	13.2	12.9	7.6	10.9	13.7
Non-food Items	72.471	12.1	10.2	10.4	63.0	61.0	81.8

4.30 The large rise in the prices of 'food items' was reflected in the behaviour of the three consumer price indices (CPIs) in respect of which the weight of 'food items' is about twice their weight in WPI (Appendix Table IV. 21). Thus, the CPI for Industrial Workers registered an increase of 13.9 per cent, that for Urban Non-manual Employees 13.6 per cent, and that for Agricultural Labourers the highest at 21.9 per cent as it has the largest weightage, amongst CPIs, for 'food items'.

First Quarter Trends : April-June 1992-93

4.31 During the first quarter of the current financial year 1992-93, the general index of wholesale prices registered a smaller rise of 2.3 per cent as compared with the increase of 4.3 per cent in the similar period in 1991-92. Since the beginning of the financial year, there has occurred a steady downward trend in the annual rate of inflation month by month (see Table 4.7 and graph 2). The indices of all major commodity groups showed easiness. Apart from the demand resistance to high levels of commodity prices, the price expectations have been, to an extent, kept under check due to various macro-level policy initiatives. During the first quarter of the current financial year, the CPI for Industrial Workers registered an increase of 3.1 per cent as compared with the increase of 4.0 per cent in the corresponding quarter of 1991-92.

Bullion Prices

4.32 Prices of gold and silver registered greater gyrations during 1991-92. Overall, the price of gold in the Bombay market rose by about 25 per cent on an average basis after remaining subdued in the preceding three years. Silver price, too, gained appreciably, more prominently in the last quarter of 1991-92. Even so, the average spread of gold and silver prices between domestic and international markets narrowed rather significantly during the year. Immediately following the downward adjustment in the value of the rupee in July 1991, the spread for both gold and silver prices narrowed sharply, but, after a while, they rose steadily until January 1992. There was, however, a sharp drop in the spread in March 1992 as it was the first month experiencing the impact of the new exchange rate policy (Liberalised Exchange Rate Management System) and also that of the legal import of gold by NRIs (Appendix Tables IV. 22 to IV. 24). By the end of April 1992, the spread in Gold price had dropped to about 34 per cent and to 27 per cent in May and further to 24 per cent in June 1992 and furthermore to 21 per cent in July 1992 as against approximately 60 per cent which had prevailed for most of the preceding 12-month period. In silver, the differential went upto 110 per cent by the end of April but it came down to 101 per cent towards the end of May and to 84 per cent in June 1992, but rose to 96 per cent in July 1992.

V. CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS

5.1 As a sequel to various liberalisation measures effected since July 1991, the Indian capital market witnessed during 1991-92 an unprecedented buoyancy in its secondary market segment and a significant improvement in new issue activities. The buoyancy in the secondary market, particularly after the Central Budget for 1992-93, defied economic fundamentals to a very large extent, pointing towards a more than usual build-up of speculative pressures. Once such speculative pressures were brought out in the Report of the Committee to enquire into securities transactions of banks and financial institutions (Chairman: Shri R. Janakiraman) and expeditious action was taken by the Government, there occurred in May-June 1992 a sizeable correction to the undue increase in equity prices.

Assistance by Term-financing and Investment Institutions

5.2 Disbursements by all-India development banks (net of inter-institutional flows) at Rs. 11,693 crore during 1991-92 (April-March) registered an increase of Rs. 1,915 crore or 19.6 per cent against an increase of Rs. 2,204 crore or 29.1 per cent in the previous year (Appendix Table V.1) Reflecting largely the difficult economic situation, as also the resource constraints faced by these institutions, the increase in their sanctions during 1991-92 decelerated rather significantly

from 24.0 per cent in 1990-91 to 11.6 per cent. On the other hand, the investment institutions (UTI, LIC and GIC) showed buoyant resource position and expanded phenomenally their sanctions and disbursements under various schemes of assistance/investments during 1991-92.

Corporate Investment Forecast

5.3 Estimates of corporate investment, hitherto presented on a calendar year basis, according to a methodology developed by Dr. C. Rangarajan, are generated on a financial year basis as from the year 1991-92. The study, the fourth in series on annual forecast of investment of private corporate business sector based on expected phasing of capital expenditures on all projects for which assistance has been sanctioned by IDBI, ICICI and IFCI, has estimated that capital expenditures aggregating Rs. 19,049 crore in nominal terms would have been incurred during 1991-92 denoting a rise of 3.0 per cent over the expected capital expenditure during 1990-91. Including the amounts expected to be disbursed under the institutions' Bills Rediscouting Scheme and the Technical Development Fund Scheme, the expected total capital expenditure during 1991-92 worked out to Rs. 19,357 crore. When deflated by an appropriate deflator, the total investment in real terms (i.e., at 1980-81 prices) shows a rise of 15.4 per cent in 1990-91 and a decline of 1.4 per cent in 1991-92 over the corresponding expenditures in respective previous years. Industry-wise, 'metals and metal products' accounted for the highest share of 39.0 per cent (127 projects or Rs. 9,349 crore) followed by 'chemicals and petrochemicals' at 10.0 per cent (179 projects or Rs. 2,396 crore). 'Textiles (other than jute)' followed next with a share of 9.6 per cent (228 projects or Rs. 2,296 crore).

Trends in Growth of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

5.4 According to the provisional data available, during the year ended March 31, 1991 the aggregate borrowings of 9,901 reporting non-banking companies rose by Rs. 10,532 crore and stood at Rs. 44,063 crore as against Rs. 33,531 crore held by 10,140 companies as at the end of March 1990. The total regulated deposits of the reporting companies recorded an increase of Rs. 1,245 crore and stood at Rs. 8,003 crore while exempted borrowings rose by Rs. 9,287 crore to Rs. 36,060 crore. Non-financial companies accounted for 59.6 per cent of aggregate borrowings while financial companies accounted for 35.5 per cent and miscellaneous non-banking companies and residuary non-banking companies for 4.9 per cent each. The regulated deposits held by the non-banking sector were equivalent to 3.9 per cent of the total deposits of all scheduled commercial banks (Appendix Table V. 2).

New Issue Market

5.5 Approvals (consents/acknowledgments including premium but excluding bonus shares) granted by the Controller of Capital Issues (CCI) to both Government and non-Government companies for 1991-92 (April-March) were higher by 56.1 per cent over the approvals granted in the previous year (Appendix Table V. 3). In particular, approvals to non-Government companies recorded a substantial rise of 95.8 per cent.

5.6 New capital issues (including premium but excluding bonus issues) aggregated Rs. 5,571 crore, registering during 1991-92 a significant rise of 35.9 per cent in contrast to a decline of 34.6 per cent recorded during 1990-91 (Appendix Table V. 4). Debenture issues dominated the new issue market accounting for about 70 per cent of the total new capital issues. Convertible debenture issues increased by 48.1 per cent. Equity issues amounting to Rs. 1,730 crore witnessed an increase of 34.5 per cent over those in the previous year. A marked feature of the new issue market during 1991-92 was the substantial rise in rights issues. The total amount of rights issues at Rs. 3,847 crore registered an increase of 76.0 per cent and accounted for 66.9 per cent of the total capital issues during 1991-92 in contrast to 51.7 per cent during 1990-91.

Performance Analysis of New Issues

5.7 According to the Bombay Stock Exchange (BSE) data, overall public response to the new issues continued to be

encouraging in 1991-92. The number of issues which were subscribed to more than ten times accounted for 50.5 per cent of the total issues for which data were available, as against 21.9 per cent in the previous year. The amount offered for public subscription accounted for 49.1 per cent of the total issue as compared with 45.0 per cent in 1990-91. More recent data suggest that despite the difficulties and disruption faced by the secondary market, the number and amount of primary issues have been sizeable and the public response has continued to be encouraging.

Equity Prices

5.8 During 1991-92, the stock market witnessed boom conditions—large-scale increase in activities and upsurge in share prices. Though equity prices moved up slowly during the first quarter of the year, they rallied sharply following the presentation in July 1991 of the Union Budget for 1991-92 and continued to rise till the third week of September 1991. The equity prices moved in narrow ranges thereafter, although the undercurrent remained optimistic. The Union Budget for 1992-93* had a buoyant effect on stock markets. As a result, share prices rose by 35.6 per cent in March 1992. Appendix Table V.5 provides the movements in the RBI All-India (Weekly) Index Numbers of Ordinary Share Prices (base : 1980=100). From 527.9 for the week ended March 30, 1991 the index spurted to 792.3 for the week ended September 21, 1991 and further to 868.8 during the week ended January 28, 1992. The phenomenal buoyancy in February and March 1992 had driven the index up to 1485.4 by the week ended March 28, 1992.

5.9 Though the average RBI index for 1991-92 at 776.2 showed an increase of 55.1 per cent on a point-to-point basis, the index recorded a gain of 181.4 per cent from 527.9 during the week ended March 30, 1991 to 1485.4 during the week ended March 28, 1992.

5.10 The industry-wise analysis indicated that all the industry groups made gains of more than 100 per cent during 1991-92 except for the share prices of aluminium and automobiles and auto-ancillaries which, however, gained 97.3 per cent and 99.3 per cent, respectively. The shipping group's shares outperformed all the others with a phenomenal gain of 580.5 per cent followed by cement (344.2 per cent) and rubber and rubber products (268.9 per cent).

5.11 Along with the increase, there was also volatility in share prices. The co-efficient of variation (CV) of the index of ordinary share prices during 1991-92 at 27.0 per cent was substantially higher than the CV in the previous year (14.7 per cent). The dispersion (the range between High and Low) in the index at 948.5 was 3.7 times the range for the previous year (258.6).

* Some of the important proposals in the Budget contributing to this buoyant fervour were : abolition of wealth tax on financial assets, enlarging the scope of provision relating to exemption of income from specified mutual funds, including those in the private and joint sectors, consideration to permit foreign investors (pension funds) to invest in Indian capital market, proposal to do away with Government control over capital issues including premium fixation and permission for Indian companies to issue equity convertible debentures to investors abroad with the same tax treatment as available for off-shore mutual funds.

Major Indicators of Stock Market Activities

5.12 The considerable increase in the activities of the secondary market has been also reflected in all the major indicators, as are available from the Bombay Stock Exchange (BSE) data, viz., turnover, market capitalisation and price-earning ratio. The average monthly turnover at Rs. 5,981 crore during 1991-92 was almost twice as the previous year (Rs. 3,001 crore). Market capitalisation based on BSE data as at the end of March 1992 at Rs. 2,76,434 crore (Provisional) was more than three-and-a-half times that at the end of March 1991 (Rs. 75,348 crore). The average monthly price earning P/E ratio (circulated from 30 scrip BSE sensitive index, base : 1978-79=100) rose to 26.1 in 1991-92 from 19.3 in 1990-91. There has been a continuous increase in P/E ratio since January 1992 with the peak reaching at 44.3 during March 1992.

Correction to the Speculative Fervour

5.13 The phenomenal upsurge in share prices during the last quarter January-March 1992 also continued during April 1992. Reflecting this, the RBI index of equity prices (base : 1980-81=100) peaked to an all-time high of 1,656.9 during the week ended April 4, 1992. However, this level of share prices could not be sustained as certain irregularities in securities dealings and financing of share transactions came to light. Consequently, a correction to the speculative fervour occurred in May and June, 1992, resulting in a fall in the RBI index to 1,162.1 for the week ended June 27, 1992 showing an erosion of 29.9 per cent from the peak level of April 4, 1992. The BSE 30 share Sensitive Index—SENSEX (base : 1978-79=100) reached the all-time peak of 4,467.32 on April 22, 1992 but fell to 3,080.54 on June 26, 1992 (the last trading day of the month); it remained at 3,034.94 on August 21, 1992 showing a fall of about 32 per cent over the peak level. The latest SENSEX as on August 21, 1992 still shows an increase of 77.7 per cent over the level a year ago. Thus, recent correction appears very moderate when considered against the increase of 90.7 per cent in the RBI index ended January 25, 1992 and the week ended April 4, 1992, or an increase of 108.8 per cent shown by the SENSEX between January 24, 1992 and April 22, 1992. The downward inflexibility of share prices is as much a reflection of scarcity of scrips as it is of market imperfections and the rigidities in the market structure.

Stock Market Reforms

5.14 The experience of the year under review shows that there is a need to undertake a well-coordinated package of stock market reforms so as to contain the instability of the market. With the statutory status accorded to SEBI, it is expected that issues, such as, registration of brokers, reporting system, capital adequacy of broker, institutional membership, settlement system and insider trading would be addressed quickly and effectively.

5.15 The fact that capital issues are phenomenally high during the first quarter of the fiscal 1992-93 indicates that investor confidence in the primary market remains unimpaired.

Credit Rating Agencies : CRISIL

5.16 The Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL), established by ICICI and UTI, made steady progress during 1991-92. CRISIL rated 155 debt instruments issued by 103 companies covering a debt volume of Rs. 5,866.5 crore during the review period as against 77 debt instruments issued by 46 companies covering a debt volume of Rs. 1,689.9 crore in 1990-91. Apart from rating instruments like fixed deposit programmes, convertible and non-convertible debentures, CRISIL also rated 56 commercial paper programmes covering a total volume of Rs. 948 crore. CRISIL, for the first time, rated an asset-backed security, viz., 'auto loans' originated by Citibank and also assigned rating to a new instrument, viz., 'Structured Obligation'. Since its inception in 1988, CRISIL had, by the end of March 1992, rated 304 debt instruments for a total debt value of Rs. 10,626 crore. These instruments were issued by 228 companies of which 5 companies are in the public sector. The increase in the number of credit rating during the year 1991-92 is attributed to the fact that according to the CCI/SEBI guidelines, credit rating is mandatory for companies issuing debentures to the public. CRISIL has also completed Credit Assessment of 58 companies. Apart from these operations, CRISIL entered into the area of providing technical assistance and training to Rating Agency Malaysia Berhad (RAM). It also rendered assistance to MALLOT—the Israel Securities Rating Company Limited and has agreed to provide training to its staff.

ICRA

5.17 Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) commenced its operations in September 1991 and up to March 31, 1992, it had rated 47 debt instruments issued by 24 companies (both manufacturing and financial companies) involving Rs. 1,161.8 crore of debt to be raised from the financial market. Credit ratings were in respect of 33 debenture issues (Rs. 985.3 crore), 11 fixed deposit programmes (Rs. 104.5 crore) and 3 commercial paper programmes (Rs. 72.0 crore). ICRA, in addition to providing rating, has also started providing credit assessment and general assessment services.

VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

6.1 The severe pressure of a crisis proportion suffered by the Indian economy in its external payments situation during the fiscal year 1990-91 and the first quarter of 1991-92 were highlighted in the previous year's Annual Report. The Gulf crisis of August 1990, the global slow-down in world trade, and the break-up of the erstwhile Soviet Union were some of the external factors impinging on India's balance of payments. The pressure on the external situation persisted through the second quarter (July-September) of 1991-92 after which, however, there occurred a marked turnaround in the country's international reserves. The foreign exchange assets, which dipped to a low of US \$ 975 million (Rs. 2,492 crore) as on July 12, 1991, made a remarkable recovery and attained the level of US \$ 5,631 million (Rs. 14,578 crore) by the end of March

1992. The series of crisis management measures as also the brisk action on stabilisation and structural adjustment programmes undertaken during the year, have combined to achieve a remarkable transformation in the country's international liquidity position. In particular, the drastic compression of imports and the determined efforts made to encourage repatriation of capital have helped the process. A measure of balance of payments support was also received from bilateral and multilateral donors.

Balance of Payments

6.2 Final balance of payments data for 1991-92 are not yet available. However, 'Quick Estimates' have been prepared based on data available with the Reserve Bank and other sources of information and are presented in Tables 6.1 and 6.2. These reveal a sharp contraction in merchandise

Table 6.1 : India's Overall Balance of Payments

Item	In US \$ million			In Rupees crore		
	1991-92 (Quick Estimates)	1990-91 (Provisional Estimates)	1989-90	1991-92 (Quick Estimates)	1990-91 (Provisional Estimates)	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
A. Current Account						
1. Exports, f.o.b.	18,135	18,491	16,955	44,607	33,178	28,229
2. Imports, c.i.f.	21,213	26,241	24,411	51,522	47,083	40,642
3. Trade Balance	-3,078	-7,750	-7,456	-6,915	-13,906	-12,413
4. Current Account Balance @	-2,835	-8,424	-7,269	-6,251	-15,114	-12,102
B. Total Capital Account, IMF and SDR Allocation	6,409	7,146	6,529	16,092	12,821	10,870
C. Reserves and Monetary Gold (Increase-/Decrease+)	-3,574	1,278	740	-9,841	2,293	1,232

@ After taking into account errors and omissions. See also Appendix Table VI: 1.

Table 6.2 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices

Item	(In per cent)								
	1991-92 (Quick Esti- mates)	1990-91 (Provisi- onal Esti- mates)	1985-90 Annual average	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87	1985-86	1980-85 Annual average
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Exports	7.2	6.3	5.1	6.4	5.2	4.9	4.5	4.4	5.0
2. Imports	8.4	8.9	8.3	9.2	8.7	7.7	7.7	8.1	8.4
3. Trade deficit	1.2	2.6	3.2	2.8	3.4	2.8	3.2	3.7	3.4
4. Invisible Receipts @	3.3	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	3.0	3.6
5. Invisible Payments	2.9	2.4	1.9	2.2	2.0	1.9	1.6	1.6	1.5
	(3.2)	(2.7)	..	(2.7)	(2.4)				
6. Invisibles (net) (4-5) @	0.4	0.3	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	2.1
	(0.1)	(0.0)	..	(0.1)	(0.5)				
7. Current Account Deficit (3-6) @	0.8	2.3	2.2	2.2	2.6	1.9	2.0	2.3	1.3
	(1.1)	(2.6)		(2.7)	(2.9)				

.. Not available.

@ Include official grants which are treated as part of current account receipts here.

Note : Figures in brackets indicate percentages including accrued interest on NRI deposits. Data for the period prior to 1988-89 are not available.

trade deficit to US \$ 3,078 million (Rs. 6,915 crore) as compared with US \$ 7,750 million (Rs. 13,906 crore) during 1990-91, largely as an outcome of the massive contraction of imports. As regards invisibles, tourist arrivals, including nationals of Pakistan and Bangladesh, during 1991-92 were higher by 10.3 per cent as compared with an absolute fall of 8.6 per cent during the preceding year. Hence tourist receipts are estimated to show a moderate rise. Due to accruals of US \$ 863 million under Foreign Exchange (Immunities) Scheme 1991, private transfer receipts during 1991-92 are likely to show an increase though other remittances from non-resident Indians working abroad, which are a major component of private transfers, are estimated to be at the same level as in the preceding year. Interest payments as well as outward remittances on account of royalty, technical knowhow, etc., would continue to show an increase. On balance, net receipts from invisibles including accrued interest as also official transfers are expected to be somewhat higher than in 1990-91. Nevertheless, essentially as a result of the drastic cut-back in trade deficit, the current account deficit (CAD) (including accrued interest on NRI deposits) stood slashed to US \$ 2,835 million (Rs. 6,251 crore) from US \$ 7,728 million (Rs. 13,865 crore) in the preceding year. As a proportion to GDP, CAD is estimated at 1.1 per cent as compared with 2.6 per cent in 1990-91.

6.3 The capital account was characterised by mobilisation of funds from non-resident Indians and larger assistance from bilateral and multilateral donors. During the year occurred an outflow of US \$ 1,627 million (Rs. 3,641 crore) under the ECNRA scheme (as against an inflow of US \$ 168 million (Rs. 255 crore) during 1990-91) but the bulk of these outflows amounting to nearly US \$ 1 billion occurred during April-June 1991—a period of overall uncertainty. As measures of stabilisation were put in place rapidly, the outflows tapered down to US \$ 152 million in the last quarter of the year 1991-92 which also seem to represent portfolio switches in favour of other schemes. Simulta-

neously, subscriptions to India Development Bond (IDBs) aggregated US \$ 1,627 million. As such the large outflow under the FCNRA was recouped through the IDBs with the added advantage of lengthening of maturities. Utilisation of external assistance, excluding exceptional financing of US \$ 1 billion by the World Bank, the ADB and Japan, was at the same level as in 1990-91. Commercial borrowings other than IDBs were significantly lower during the year due to the downgrading of India's rating by the Rating Agencies. Net purchases from the IMF during the year were lower at US \$ 781 million (Rs. 2,079 crore) as compared with US \$ 1,214 million (Rs. 2,178 crore) (excluding repayments to the IMF under Trust Fund Loan) during 1990-91. Drawings from the IMF took the form of a second drawal equivalent to US \$ 221 million (Rs. 570 crore) in July 1991 and a third drawal equivalent to US \$ 637 million (Rs. 1,647 crore) in September 1991 under the Compensatory and Contingency Financing Facility (CCFF) and US \$ 117 million (Rs. 305 crore) in November 1991 and US \$ 263.59 million (Rs. 685 crore) in January 1992 under the Stand-by Arrangement (Table 6.3). Appendix Table VI. 2 presents the modes of financing of the current account deficit; this shows how there was a significant departure in mode of financing during 1991-92 from that of the past years.

6.4 The Aid-India Consortium committed aid during 1991-92 up to US \$ 6.7 billion for India of which US \$ 2.3 billion would be fast-disbursing. The IMF approved on October 31, 1991 in Upper Credit Tranche Stand-by Arrangement amounting to SDR 1,556 million (US \$ 2.2 billion) which would be available in instalments over 20 months subsequent to the date of approval. The first instalment of SDR 85 million (US \$ 117 million) was drawn in November 1991 and the second instalment of SDR 185 million (US \$ 263.59 million) in January 1992. In July 1992 there was a drawal of third instalment of SDR 462 million (US \$ 663 million).

Table 6.3 : Special Factors Affecting Movement in Foreign Currency Assets

Item	In US \$ million		In Rupees crore	
	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
I. Change in Foreign Currency Assets	3,395	-1,132	10,190	-1,399
II. Special Factors	3,739	2,328	9,978	4,147
(a) Exceptional Financing	935	..	2,257	
Germany	60	—	151	
Japan	295	—	610	
ADB	125	—	323	
World Bank	455	—	1,173	
(b) Transactions with IMF*	498	1,636	1,339	2,927
(net SDR transactions affecting foreign currency assets)				
(c) Other Schemes	923	692	2,923	1,220
Foreign Currency (Banks & Others)	304	262	742	485
Deposits				
Foreign Currency Non-Resident Accounts	-1,627	168	-3,641	255
NRI Bonds and other deposits	9	262	21	480
India Development Bonds	1,374**	—	3,557	
Immunity Schemes	863	—	2,244	
(d) Swaps	1,383	—	3,459	
III. Change in Foreign Currency Assets, (I-II)	-344	-3,460	212	-5,546

* Represents changes in foreign currency assets arising from drawals from the IMF and from sale/purchase of SDRs on Government Account.

** Of total collection of US \$ 1,627 million under ID Bond, US \$ 1,374 million accrued to foreign exchange assets of the RBI during 1991-92.

Note : Due to valuation change during the year the trend in rupee terms would not correspond with US dollar value.

Foreign Exchange Reserves

6.5 India's foreign exchange reserves (comprising foreign currency assets of the Reserve Bank of India (RBI), gold held by the RBI and SDR balances held by the Government) rose from US \$ 5,834 million (Rs. 11,416 crore) at the end of March 1991 to US \$ 9,220 million (Rs. 23,850 crore) at the end of March 1992 showing an increase of US \$ 3,386 million (Rs. 12,434 crore) (see Appendix Table VI.3). As compared with end-August 1991 when the level of reserves had fallen to US \$ 4,624 million (Rs. 11,975 crore), the end-March 1992 level was almost twice that size. Exclusive of gold revaluation and also of transactions with the IMF (other than the Trust Fund Loans), the foreign exchange reserves increased by US \$ 2,793 million (Rs. 8,637 crore) during 1991-92 against a fall of US \$ 2,351 million (Rs. 3,560 crore) during 1990-91. Foreign currency assets rose by US \$ 3,395 million (Rs. 10,190 crore) during 1991-92 as compared with a fall of US \$ 1,132 million (Rs. 1,399 crore) during 1990-91. Between end-March and end-June 1992, foreign currency assets rose further by US \$ 590 million (Rs. 1,547 crore).

SDRs

6.6 Holdings of SDRs fell by SDR 10 million during 1991-92 (April-March) as compared with a fall of SDR 6 million during the preceding year. The decline during 1991-92 was the combined result of a net acquisition of SDRs worth SDR 225.0 million, IMF draws worth SDR 397.2 million, repurchases of SDR 357.5 million, payment of charges/interest amounting to SDR 218.7 million (net of interest subsidy) to IMF, and sale of SDRs worth SDR 76.2 million. During April-June 1992, there was an increase of SDR 14.4 million offset by repurchases amounting to SDR 54.2 million primarily due to acquisition of SDR 120 million.

Gold

6.7 The gold holdings of the Reserve Bank of India at US \$ 3,499 million (Rs. 9,039 crore) at the end of March 1992 reflected an addition to gold stocks to the extent of 18.36 tonnes (to 350.92 tonnes) consequent upon the sale of gold by the Government of India to the RBI in December 1991 (equivalent in value of Rs. 493.81 crore or US \$ 191 million).

6.8 The gold (46.91 tonnes) pledged by RBI in four instalments in July 1991, as part of its reserve management policy and as a means of raising resources temporarily to the Bank of England (BOE) to raise loans of US \$ 405 million from BOE and the Bank of Japan, was redeemed by repayments during September to November 1991. Earlier, in May 1991, Government had leased 19.99 tonnes out of confiscated gold to State Bank of India which, in turn, entered into a sale of 18.36 tonnes with a repurchase option in the international market. The gold was repurchased by the State Bank of India in November/December 1991; the quantity of 18.36 tonnes was subsequently sold by the Govern-

ment to the Reserve Bank of India. The balance of 1.63 tonnes of gold has since been returned by the State Bank of India to the Government. The gold holdings of the Reserve Bank of India involved in both the transactions, adding up to 65.27 tonnes, are kept abroad for the time being.

6.9 As stated earlier, foreign currency assets, which had touched a low of US \$ 975 million (Rs. 2,493 crore) on July 12, 1991, rose to US \$ 5,031 million (Rs. 14,578 crore) at the end of March 1992. Inflows under the two special schemes mentioned earlier, borrowings from the IMF and the fast-disbursing assistance extended by multilateral and bilateral agencies, facilitated the reserve build-up. After the amounts involved in the above transactions are netted out, there still remained an inflow of US \$ 1 billion. It represents the net position of receipts and payments on account of merchandise trade and invisibles (excluding the amount received under the Immunity Scheme). This is also corroborated by RBI transactions with Authorised Dealers (ADs). During the period from April 1, 1991 to March 31, 1992, net purchases by RBI from ADs amounted to US \$ 1.8 billion (Rs. 5,215 crore) in contrast to net sales of US \$ 5.8 billion (Rs. 10,358 crore) in the previous 12-month period, implying a turnaround of US \$ 7.6 billion. They indicate a faster repatriation of export proceeds and inward remittances following a break in expectations of a depreciation of the exchange rate. As mentioned earlier, the stability of the US dollar-rupee rate combined with increases in interest rates including those for financing exports and imports had a powerful effect on reversing the outflow of foreign exchange into a large inflow.

Merchandise Trade

6.10 The fiscal year 1991-92 witnessed a striking improvement in trade balance contributed mainly by a severe compression in imports. Imports declined by 19.4 per cent in dollar terms during the year in sharp contrast to a rise of 13.2 per cent in the previous year. The trade deficit would have shrunk still further but for the fall in exports. According to the provisional data on foreign trade, the trade deficit, which stood at US \$ 425 million (Rs. 762 crore) in 1990-91, from US \$ 5,930 million (Rs. 10,640 crore) in 1990-91. The break-up of the total deficit into oil and non-oil components suggests a revealing picture. 'Non-oil deficit', which stood at US \$ 425 million (Rs. 762 crore) during 1990-91, turned into a surplus of US \$ 3394 million (Rs. 8,272 crore) during 1991-92 reflecting the impact of severe import compression measures. In contrast, 'oil deficit' rose by 22.6 per cent from Rs. 9,878 crore in 1990-91 to Rs. 12,107 crore in 1991-92 which, however, arose from the downward adjustment in the external value of the rupee; in dollar terms, the 'oil deficit' declined by 10.1 per cent from US \$ 5,505 million to US \$ 4,950 million. The surplus in 'non-oil deficit' partially moderated the deficit in the oil account to keep the total deficit at a lower level (Table 6.4).

Table 6.4 : India's Foreign Trade

Item	US \$ Million			Rupees crore		
	1991-92 (P)	1990-91	1989-90 (P)	1991-92 (P)	1990-91	1989-90 (P)
1	2	3	4	5	6	7
I. Exports	17,840	18,143	16,626	43,978	32,553	27,681
	(-1.7)	(9.1)	(19.0)	(35.1)	(17.6)	(36.8)
Crude oil	—	—	—	—	—	—
POL	415	523	418	1,022	938	697
	(-20.7)	(24.9)	(20.0)	(9.0)	(34.6)	(38.0)
Non-oil	17,425	17,620	16,208	42,956	31,615	26,985
	(-1.1)	(8.7)	(19.0)	(35.9)	(17.2)	(36.8)
II. Imports	19,396	24,073	21,272	47,813	43,193	35,416
	(-19.4)	(13.2)	(9.1)	(10.7)	(22.0)	(25.4)

Table 6.4 (Contd.)

Oil & POL	5,365@ (—11.0)	6,028 (60.0)	3,768 (25.2)	13,129 (21.4)	10,816 (72.4)	6,274 (44.0)
Non-oil	14,031 (—22.2)	18,045 (3.1)	17,504 (6.2)	34,684 (7.1)	32,377 (11.1)	29,142 (22.0)
III. Trade Balance	—1,556	—5,930	—4,646	—3,835	—10,640	—7,735
Oil Balance	—4,950	—5,505	—3,350	—12,107	—9,878	—5,577
Non-oil Balance	+3,394	—425	—1,296	+8,272	—762	—2,157

(P) : Provisional.

@ Converted in US dollar terms by using official average exchange rate. For other commodities composite average exchange rate for March 1992 is used.

Notes : 1. See also Appendix Table VI. 4.

2. Final data for the year 1989-90 are not available from DGCI&S.

3. Figures in brackets represent percentage change over the previous year.

Source : D.G.C.I. & S.

6.11 After attaining significant increase in the export base continuously for four years, the export performance during 1991-92 was sluggish. Exports declined by 1.7 per cent in dollar terms, although in rupee terms they increased by 35.1 per cent due to exchange rate changes. Exports were adversely affected by both domestic and external factors. Internal factors included inter alia the imposition of import compression measures and tight monetary policy. The general uncertainty on the economic front prevailing in the initial part of the year and expectations of a reduction in Customs tariffs before the 1992-93 Central Budget contributed to an overall slowdown in foreign trade activity. External factors related to recessionary conditions in major developed countries, particularly the USA and the UK, a slowdown in the expansion of world trade to 0.9 per cent in 1991 from 4.2 per cent in 1990 and 7.3 per cent in 1989 and the break-up of the erstwhile Soviet Union, which severely disrupted India's trade with the region.

6.12 Appendix Tables VI.5 and VI.6 present exports and imports respectively, by major categories and commodities for three years.

India's Trade with Rupee Payment Area (RPA) and General Currency Area (GCA)

6.13 As mentioned earlier exports during 1991-92 were adversely affected by the severe disruption of trade with the erstwhile USSR. The USSR accounted for 95 per cent of the total trade turnover between India and the three countries under RPA, viz., the USSR, Czechoslovakia and Romania. There was a steep decline in exports to RPA by 42.5 per cent in dollar terms and by 21.0 per cent in Rupee terms during 1991-92. Furthermore, there was a shortfall of 45.2 per cent in the total trade turnover (exports plus imports) with RPA in dollar terms during 1991-92 as compared with the corresponding period of the previous year.

6.14 The extent of the decline in exports to RPA was so pronounced that total exports showed a decline of 1.7 per cent (in dollar terms) during 1991-92 even though exports to GCA (total exports minus exports to RPA) recorded a positive growth of 6.6 per cent during the same period (Appendix Table VI.7).

Indo-USSR Trade Protocol

6.15 For the calendar year 1991 the Indo-USSR Trade Protocol (prior to the break-up of the USSR) envisaged a total trade turnover of Rs. 9,411 crore consisting of Rs. 5,081 crore of exports to the USSR and Rs. 4,330 crore imports from the USSR. Against this target, a total trade turnover of Rs. 6,413 crore was actually realised during 1991—Rs. 4,164 crore of exports to the USSR and Rs. 2,249 crore of imports therefrom. The shortfall was larger in India's imports (Rs. 2,081 crore or 48.1 per cent) than in exports (Rs. 917 crore or 18.0 per cent).

6.16 The provisional data indicate that exports to the erstwhile USSR declined by Rs. 1,287 crore to Rs. 3,967 crore during the fiscal year 1991-92. The shortfall in exports is attributable to a steep decline in exports of agricultural and allied products by Rs. 838 crore. Total imports aggregated Rs. 1,780 crore during 1991-92 as compared with Rs. 2,548 crore in 1990-91, showing a fall of Rs. 768 crore. Imports under the item 'Others' (including crude oil and Petroleum products) declined by Rs. 708 crore to Rs. 1,000 crore in 1991-92, reflecting the sharp fall in imports of crude oil and Petroleum products. Non-ferrous metals also declined by Rs. 108 crore to Rs. 5 crore in 1991-92.

6.17 Consequent upon their separation, the countries of the erstwhile USSR have formed the Commonwealth of Independent State (CIS) and efforts are being made by the Government of India and the republics of CIS to reestablish trade and economic links with each other. So far, trade and economic co-operation agreements have been reached between India and six Republics of the CIS, viz., the Russian Federation, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Uzbekistan and Turkmenistan. All the Republics have opted for payments in freely convertible currencies. As regards trade with all other remaining Republics of CIS with which trade agreements remain to be concluded the trade between India and these Republics and the contracts to be concluded between them shall be carried out in freely convertible international currencies in conformity with the laws and regulations of respective countries. The general form of agreement between India and the Republic of the CIS is that they shall accord to each other the most-favoured-nation (MFN) treatment in all matters of trade and commercial co-operation.

New Agreement on Trade and Economic Co-operation between Government of India and Russian Federation

6.18 A trade and payments protocol was concluded between India and the Russian Federation on February 22, 1992. On the basis of the agreement, which provides for trade on a bilateral basis as also trade in freely convertible currencies, the trade between the two countries during the calendar year 1992 shall be effected on a balanced basis in accordance with the specified list of goods. Pending finalisation of the modalities for carrying out trade under the trade protocol and consequential amendments to the agreement, a memorandum of understanding was signed on May 5, 1992 between the two Governments whereby Government of India agreed to the advance utilisation by the Russian Federation of technical credit to the extent of US \$ 85 million for export of goods from India, viz., tea (US \$ 32 million), coffee (US \$ 15 million), tobacco (US \$ 25 million), spices including black pepper (US \$ 2 million), cigarettes (US \$ 4 million), medicines (US \$ 3 million) and fruit pulp concentrates (US \$ 4 million). Import of goods from Russia consists of 15 items. The import and export of goods as specified above shall be carried out on the basis of contracts concluded at internationally competitive prices and denominated in US

dollars. There shall, however, be no outflow/inflow of US dollars from/to India on account of trade transaction under the trade protocol.

6.19 Apart from the total turnover of US \$ 2,200 million (i.e., US \$ 1,100 million each in two-way trade), the protocol provides for freedom for both the sides to import and export goods and services from each other outside its ambit on the basis of countertrade, commodity exchange, barter, buy-back operations, or of any other internationally recognised form of business cooperation.

External Assistance

6.20 The inflow of external assistance rose during 1991-92. Gross utilization of loans and grants at US \$ 4,527 million (Rs. 11,078 crore) was higher by US \$ 791 million (Rs. 4,374 crore) than that of US \$ 3,736 million (Rs. 6,704 crore) during 1990-91. The amortisation payments continued to show a rising trend and amounted to US \$ 1,455 million (Rs. 3,559 crore) during 1991-92 as against US \$ 1,298 million (Rs. 2,329 crore) in the preceding year. Net inflow of external aid rose by US \$ 634 million (Rs. 3,144 crore) to US \$ 3,072 million (Rs. 7,519 crore) during 1991-92 (Appendix Table VI.8) though the increase includes the disbursements under exceptional financing that was arranged as balance of payments support. Under this arrangement, a sum of US \$ 295 million (Rs. 610 crore) was provided by Japan, US \$ 60 million (Rs. 151 crore) by Germany, US \$ 125 million (Rs. 323 crore) by ADB and US \$ 455 million (Rs. 1,173 crore) by the World Bank under a structural, adjustment loan.

Accretions to NR(E)R and FCNR Accounts

6.21 Under Non-Resident (External) Rupee Accounts [NR(E)RA] Scheme, provisional data for 1991-92 indicate a withdrawal of US \$ 27 million (Rs. 44 crore) (excluding estimated interest element) as compared with an inflow of US \$ 87 million (Rs. 156 crore) in 1990-91. However, the decline does not necessarily imply outflow of foreign exchange. The account is to a large extent maintained for meeting the local expenditure of NRIs in India. There was, however, a sizeable outflow of US \$ 1,627 million (Rs. 3,641 crore) under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNRA) in 1991-92 as against an inflow of US \$ 168 million (Rs. 255 crore) in 1990-91 (Appendix Table VI.9). Although the outflows were heavy in the first quarter (April-June 1992), they slowed down from July 1991 onwards after the institution of many policy reforms. Under Foreign Currency (Ordinary Non-Repatriable) Scheme, introduced in June 1991, there was an inflow of US \$ 5 million during 1991-92.

6.22 Appendix Table VI.9 shows that at the end of March 1992, non-resident deposit stood at US \$ 7,847 million or Rs. 21,679 crore (US \$ 2,591 million under NR(E)RA and US \$ 5,256 million under FCNRA equivalent to Rs. 8,071 crore and Rs. 13,608, respectively).

6.23 With a view to tidying over the foreign exchange crisis faced by the country during 1990-91, the Reserve Bank of India introduced in November 1990 a new scheme called the Foreign Currency (Bank and Others) Deposit Scheme [FC (B&O) D]. The terms and conditions of this scheme are similar to those in the case of Foreign Currency Non-Resident (FCNRA) Scheme except in two respects, viz., (i) the FC (B&O) D]. The terms and conditions of this scheme are or other institutions as against only NRIs/overseas corporate bodies (OCBs) in the case of FCNR accounts; and (ii) withdrawals before maturity are strictly not allowed.

6.24 Under the FC(B&O)D scheme, net inflow during 1991-92 amounted to US \$ 304 million as compared with US \$ 262 million during the preceding year. During the first quarter (April-June) of the current financial year, inflow under this scheme amounted to US \$ 1,237 million and were substantially higher than the amount of US \$ 77 million received during the same period of the preceding year. When the scheme was suspended temporarily with effect from July 31, 1992, the amount outstanding under it was US \$ 2,232 million.

Interest Rates—Non-Resident Deposits

6.25 In view of the trends in interest rate movements in the international markets, the interest rates on deposits under FCNRA Scheme were revised three times in 1991-92, that is, relatively less frequently as compared with the previous two years. Since the beginning of the fiscal year 1992-93, however, a further change in interest rates has been effected. Appendix Table VI.10 sets out the rates of interest on FCNRA deposits for different currencies during the period under review. Interest rate on NR(E)RA was revised last on April 13, 1991.

External Debt

6.26 With the generally growing deficit in the current account of balance of payments, India's external debt liabilities—comprising multilateral and bilateral assistance, commercial borrowings and non-resident Indian (NRI) deposits, have gradually risen over the years. India's medium and long-term debt, i.e., having an original maturity of more than one year and excluding NRI deposits, amounted to US \$ 567.6 billion (Rs. 1,71,305 crore) as at the end of March 1992 as compared with US \$ 51.7 billion (Rs. 1,00,466 crore) as at the end of March 1991 (Appendix Table VI.11). Including NRI deposits of all maturities and short-term debt in the nature of trade credit, suppliers' credit (with less than one year's maturity), credit under bankers' acceptance facility (BAF), etc., India's external debt liabilities at the end of March 1992 stood at US \$ 68.8 billion (Rs. 2,01,671 crore) as compared with US \$ 67.1 billion (Rs. 1,30,638 crore) at the end of the preceding year. A major part of the debt increase in rupee terms is attributable to the downward adjustment of the rupee vis-a-vis major currencies carried out in July 1991 and in view of introduction of LERMS in March 1992.

6.27 In relation to GDP at current market prices, medium and long-term external debt and NRI deposits are estimated to have risen to 31.2 per cent at the end of March 1992 as against 23.4 per cent at the end of March 1991 reflecting essentially the rupee depreciation referred to above. The debt (as defined above) to export ratio was round 259 per cent at the end of March 1991 and rose to about 303 per cent at the end of March 1992. The debt-service ratio (i.e. ratio of debt-service payments to exports of goods and services excluding official transfers) is estimated to have increased to 26.2 per cent during 1991-92 from 25.2 per cent in 1990-91, which is partly reflective of the decline in export earnings during 1991-92.

6.28 Based on the data available, the Reserve Bank has been publishing statistics of India's medium and long-term external debt in its Annual Reports. The Government of India and international agencies have also been publishing similar data. However, due to difference in definitions and coverage, both the total and components of debt have shown variations as between different sources of data. With a view to reconciling the different sets of figures, and streamlining the procedures and evolving a reliable system of debt statistics, the RBI appointed a Policy Group (to be assisted by a Task Force) to look into the coverage, definition and classification of external debt statistics of India. The Reports of the two Groups have been submitted. According to the definition and classification recommended by the Groups, India's medium and long-term external debt including NRI deposits (of more than one year maturity) amounted to US \$ 57,295 million (Rs. 1,10,715 crore) as at the end of March 1991. Short-term debt amounted to US \$ 5.89 million (Rs. 11,283 crore). Short-term debt according to the recommended definition includes NRI deposits up to one year and excludes all trade credits up to 180 days as they are treated as normal trade credits. The total debt mentioned above excludes Rupee/Rouble bilateral credit of US \$ 1,669 million (Rs. 2,559 crore) and Rupee Suppliers' Credit of US \$ 34 million (Rs. 67 crore). They do not involve any drawdown of reserves. The Groups also compiled the data for the end of December 1991 on the lines of the new definition. The medium and long-term debt stood at US \$ 61,050 million (Rs. 1,57,345 crore) and short-term debt at US \$ 5,010 million (Rs. 12,912 crore) as at the end of December 1991. Rupee/Rouble bilateral credit of US \$ 1,227 million (Rs. 3,164 crore) and Rupee Supplier's Credits of US \$ 22 million (Rs. 56 crore) are not included in the medium-term and long-term debt.

Exchange Rate of the Rupee

6.29 The year under review saw some radical changes in policy in regard to the exchange rate of the Rupee. First, the Rupee rate was adjusted downwards in two stages, on July 1 and July 3, 1991. The two-step downward adjustment of the Rupee in terms of the intervention currency, viz., the Pound sterling, worked out to 17.38 per cent. Thereafter, the Rupee exchange rate was anchored on a Rupee-US dollar rate close to Rs. 26 a dollar.

6.30 Secondly, as announced in the budget speech for 1992-93, effective March 1, 1992, the partial convertibility of the Rupee was introduced in the form of Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS). Under the system all foreign exchange receipts on current account transactions (exports, remittances, etc.) are required to be surrendered to the authorised dealers (ADs) in full as hitherto. The rate of exchange for these transactions is the free market rate quoted by the ADs except for 40 per cent of the proceeds which would be based on the RBI official rate. The ADs in turn will surrender to RBI 40 per cent of their purchase of foreign currencies representing current account receipts at the official rate of exchange announced by the RBI. They are free to retain the balance of 60 per cent of foreign exchange for being sold in the free market for permissible transactions.

6.31 Those who need to import goods and services or undertake travel abroad are expected to buy foreign exchange at market-determined rates from the ADs subject to the transactions being eligible under the liberalised trade and exchange control regime.

6.32 In respect of certain specified priority imports and transactions, provision has been made in the scheme for making available foreign exchange at the official rate. The RBI will thus sell foreign exchange at the official rate to ADs only for, (i) import of specified goods covering Government departmental needs, crude oil, diesel, kerosene and fertilisers, as authorised by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, (ii) imports under Exim Schemes unutilised as on February 29, 1992, and (iii) imports of life-saving drugs and equipment under licences.

6.33 For imports under Advance Licences and Special Import Licences and imports for replenishment of raw materials for gem and jewellery exports, foreign exchange is

available at official rates for 40 per cent of the value. The remaining requirement may be met through purchases in the free market.

6.34 Exporters of goods and services and other recipients of inward remittances in convertible currencies are allowed to retain up to 15 per cent of the receipts in foreign currency account with banks in India out of the amount to be surrendered to the ADs at market rates.

6.35 During the first eleven months of 1991-92 (April-February), the pound sterling-Rupee parity was revised 290 times as compared with 282 revisions in the preceding full year (April-March). Subsequently, when the US dollar has been the intervention currency, the Reserve Bank's buying and selling rates for US dollar have been kept unchanged at Rs. 100=US \$ 3,8720 and Rs. 100=US \$ 3,8530, respectively.

6.36 There is an urgent need to settle the question of the Rupee-Rouble rate, particularly in relation to the settlement of outstanding debt to the Russian Federation. So far the Rupee-Rouble rate used for debt repayments was fixed according to the 1978 Trade Protocol. However, the Rupee-Rouble, Rupee-Dollar and Dollar-Rouble exchange rates have been such that the cross-rates have not been properly aligned. The Russian Federation has become a Member of the International Monetary Fund and has declared its exchange rate. It is necessary to arrive at a more realistic Rupee-Rouble rate to settle the outstanding debt obligations of India owed to the Russian Federation.

6.37 As for the behaviour of the Rupee exchange rate in the free market, it was perceived at the time of introducing the partial convertibility that the market exchange rate for the rupee would deviate from the official rate by about 15 per cent and roughly by not more than 20 per cent. Analysing the indicative rates of Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) it is found that the Rupee-US dollar rate the average of selling and buying which opened at Rs. 29.1971 per US dollar on March 3, 1992, moved down steadily to Rs. 31.4713 on March 24, 1992, at which the deviation from the official rate worked out to about 21.55 per cent (Table 6.5). Thereafter, the market rate registered a recovery in the month of May and remained steady in the month of June 1992. During this period, the spread between the official and market rate remained in a narrow range of 17 to 18 per cent.

Table 6.5 : Rupee Exchange Rate Movements

Dates	RBI Rate	FEDAI Indicative Rate	(Rupees per US dollar)	
			Spread between Col. (3) and Col. (2) (in per cent)	Weighted Rate @
1	2	3	4	5
February 28, 1992	26.0382		N.A.	
March 3, 1992	25.8906	29.1971 (-10.82)	12.77	27.8745 (-6.59)
March 24, 1992	25.8900	31.4713 (-17.26)	21.56	29.2388 (-10.95)
March 31, 1992	25.8900	31.2256 (-16.61)	20.61	29.0914 (-10.50)
April 30, 1992	25.8900	30.6138 (-15.95)	18.25	28.7243 (-9.35)
May 29, 1992	25.8900	30.5577 (-14.79)	18.03	28.6906 (-9.24)
June 30, 1992	25.8900	30.6607 (-15.08)	18.43	28.7524 (-9.44)

@ 40 per cent of official (RBI) and 60 per cent of FEDAI (Indicative) rates.

Note : Figures in brackets indicate appreciation (-)/depreciation(+) of rupee against the US dollar over February 28, 1992 rate.

6.38 During the year, the official rate of the rupee showed a depreciation against all currencies on an average basis—by 30.7 per cent against Yen, by 26.7 per cent against US dollar, by 21.9 per cent against Pound sterling and by 21.8 per cent against the Deutsche Mark (Appendix Table VI.12). International Economic Developments

6.39 World output growth which had shown a sustained rise after 1982, turned out to be a small decline of 0.3 per cent in 1991. In the major industrial countries it slowed for the third consecutive year to 0.8 per cent in 1991. In developing countries, it is estimated to have declined by 3.4 per cent. The world trade in volume terms slowed to 3.3 per cent in 1991 from 4.1 per cent in 1990. These developments took place against the background of persistence of recessionary tendencies in the US and Europe and the continuation of economic and social restructuring process in the countries of central and eastern Europe and the former USSR.

6.40 The difficult external environment has been a major problem confronting developing countries in their efforts to integrate themselves into the world economy through introduction of trade policy reforms, reduction of controls on foreign direct investment and lowering of tariff and other trade barriers. The successful implementation of market oriented reforms in developing countries would require support by the international community, in particular industrial countries in the form of increased access to world markets. A balanced outcome of the Uruguay Round is of utmost importance to strengthen the multilateral trading system.

6.41 The former Soviet Union transformed itself into 15 independent States and international assistance is critical in ensuring the viability of these States. The IMF estimates financing requirement for these States at about \$ 40-45 billion. The real challenge would be to meet these investment needs without adding to pressures on interest rates while at the same time safeguarding flows to the traditional recipients, viz., developing countries.

6.42 A few major countries have not yet given their approval either for the Ninth Quota Review or for the Third Amendment to the Articles of Agreement of the IMF. It has serious implications for developing countries especially in the context of the likely use of Fund's resources by the newly admitted members.

VII. ASSESSMENT AND PROSPECTS

7.1 The previous Sections have set out the major policy developments, as also the economic performance during 1991-92. While the year 1991-92 began with a crisis, swift action taken on many fronts produced, by the middle of the year, clear signs of a restoration of international confidence in the Indian economy as a result of the wide-ranging economic reform measures. A dramatic improvement in the country's foreign exchange reserves followed. In contrast, the real concerns in 1992-93 centre on the need to bring about a revival in industrial and agricultural growth. Two years of double-digit inflation, and the persistently strong growth of liquidity in the economy pose a dilemma for monetary management. The recent problem arising from irregularities in dealings in securities has focused attention on the financial sector. A satisfactory and early restoration of fuller confidence in the functioning of banks and financial institutions is vital. Financial sector reforms is still the need of the hour; the recent events serve to emphasise the importance of hastening the pace of reforms.

7.2 Economic reforms in general, including trade, industry and fiscal reforms, should be completed as quickly as possible. The causes leading to export shortfall, which contributed to a stagnation in industrial output in 1991-92, due to external factors like the break-up of the erstwhile Soviet Union and the recessionary conditions in major developed markets continue to dominate the economic scene. Persistent inflationary potential reflecting fiscal imbalance and monetary growth in a situation of shortages in certain sectors, makes macro-economic adjustment a more difficult task.

7.3 The country has embarked on a major structural system reform and the underlying rationale of the move from

a command economy to an economy more responsive to market signals has essentially been to achieve greater economic efficiency. By and large, the macro-economic reform of the recent period has been managed satisfactorily though there are still serious concerns about the basic infrastructure and, moreover, there is still a hiatus between policy formulation and implementation at the ground level. These issues will undoubtedly need to be given greater attention if the reform process is to gather momentum.

Agricultural Prospects

7.4 The delayed South-West monsoon during the current year, which initially created considerable apprehensions about crop prospects, has turned out to be quite favourable as the season progressed. Out of 35 Meteorological sub-divisions, the cumulative rainfall up to August 12, 1992 was excess/normal in 25 sub-divisions and deficient in 10 sub-divisions as against excess/normal in 24 sub-divisions and deficient in 11 sub-divisions during the same period of the previous year. Amongst the 10 sub-divisions which received deficient rainfall, in at least six, the deficiency has been moderate. Also these six belong to States like Haryana and Uttar Pradesh with considerable area under irrigation. Foodgrains production is thus expected to show some improvement over the previous year's production of 149-171 million tonnes. Even so, the target for the year 1992-93, placed at 183 million tonnes, may be difficult to attain.

7.5 While a fair degree of resilience has been achieved by the agricultural sector over the years, the increase in per capita per day availability in foodgrains is still not too significant; the figure of 455.1 grammes during the five-year period 1981 to 1985 has risen to 474.3 grammes during the next five year period 1986 to 1990 or by 4.3 per cent. An efficient public distribution system (PDS) is necessary to improve the consumption level of the poor and thus help increase labour productivity. In this regard, the focus on revitalising the PDS in selected blocks, which have concentration of poor households, should be helpful. The pace of agricultural growth has decelerated in recent years, with the growth rates drifting downwards in almost all regions—in better-endowed as much as in drought-prone areas. Shortages have persisted in some important crops like pulses. Studies show that excessive reliance on price incentives is not only insufficient to trigger a faster growth process in agriculture but can also be a source of general inflation in the economy. At the farm level, rising costs of farm inputs, stagnation of farm technology, unfavourable terms of trade for farm products, and reduced labour absorption, have brought to the fore the problems of the agricultural sector. Public investment in agriculture has slowed down during the 1980s; so has complementary private investment. The Government's recent decision to substantially raise the Plan outlay for rural development should help to reverse this trend. Apart from larger investment, better farm technology and infrastructure, institutional reforms and organisational improvements should play a greater role in providing an integrated package of crop and non-crop-based rural development projects with focus on agro-climatic zones already identified in terms of area-based coherence of soil type, rainfall, temperature and water resources. It is necessary to ensure that benefits of higher prices reach the farm community. There is considerable scope for supplementing farm incomes, through expanded activities of market gardening, horticulture, sericulture, animal husbandry and dairying, poultry and fishing. Many of these allied activities and the associated agro-business and food-processing industries have proven export potential. Areas of export potential in them should be given a special thrust. These would require, apart from better physical inputs and institutional credit, concerted attempts at improving infrastructural facilities and a new dynamism in the extension service network in rural and semi-urban areas.

Prospects for Industrial Growth

7.6 The stagnation of industrial output in 1991-92—after a growth of about 8.0 per cent per annum in the past decade—was far worse than that was expected in the context of the stabilisation policies; in particular, the import compression measures, credit restraint, and fiscal adjustment leading to a reduction in public sector demand for goods and services, expectations regarding exchange rate changes and Customs duty reductions, all contributed to slippages in production and investment activities. The import-intensity of the

economy, though generally low, has been higher than perceived and the import compression measures seem to have adversely affected output activities over a wide spectrum of industries. Now that the reform measures have been clearly set out and the availability of imports, as also bank credit, has been fully restored, it could be expected that there would be a pick-up in industrial investment and output during the fiscal year 1992-93. Corporate investment forecast, based on expected phasing of capital expenditures on all projects for which assistance has been sanctioned by major all-India term-financing institutions, suggests a sizeable increase in such capital expenditures during 1992-93 as against a small decline in real terms in 1991-92. Industrial growth may also benefit from the expected improvement in exports. Considering the demand recession experienced by a number of industries, and the weak recovery in overall output, it would be reasonable to expect that in 1992-93 industrial growth would be moderate at around 4-5 per cent; a return to the trend rate of over 8 per cent could be expected to be attained only in 1993-94 after there is a full revival of industrial investment.

Overall GDP Growth Inflation

7.7 Overall, real GDP growth during 1992-93 is expected to be around 3.5 per cent which would be an improvement over the 1991-92 level of a little less than 2.0 per cent.

7.8 A matter of concern to the Reserve Bank has been the persistence of strong underlying inflationary potential in the economy. With a view to containing aggregate demand, determined efforts have been made to integrate fiscal and monetary policies which in turn have sought to operate in tandem with the restructuring of the exchange rate, trade and industrial policies. Demand management measures by themselves are insufficient to control inflation, especially in the short-term. In so far as the general inflationary tendencies in the country are concerned, it is necessary to give clear signals to the commodity markets that the authorities would deploy as the situation develops, a part of the foreign exchange assets for augmenting domestic supplies of key consumption goods, particularly cereals and pulses. The recent decision to import wheat is an appropriate response in this context. Three successive years of sharply above-trend inflation rates provide a serious danger signal for the economy. The Indian economy has been characterised by the virtue of lack of inflation tolerance. Continuing of a double-digit inflation rate in 1992-93 would signal a loss of sensitivity to high inflation rates. It is, therefore, necessary to consider the avowed objective of bringing down the inflation rate to 8 per cent in 1992-93 as the central objective of overall economic policy.

Employment Goal

7.9 A worrisome feature in the current macro-economic scene is the slow growth in overall employment opportunities. The social implications of adjustment, the equitable nature of the burden borne, will be determined by how soon and by how much employment will respond to increases in output. As the Planning Commission have brought out in their Eighth Five-Year Plan: 1992-97, a declining trend in employment elasticity with respect to GDP growth, combined with a gap between the addition to labour force and the increase in employment, has left behind a large backlog of unemployment. Estimates suggest that if the growth of overall employment remains only at around 2.0 per cent per annum as in the recent past instead of 3.0 per cent per annum as anticipated, the backlog of unemployment would grow from an estimated 23 million at the beginning of the Eighth Plan to 28 million at the end of the Plan. Until rapid and high economic growth takes care of the need for improving employment growth, special employment programmes for the unemployed and supplementary employment for the under-employed would need to be continued. In this context, the proposed linking of the PDS with the IRDP would be a useful measure.

Other Eighth Plan Goals

7.10 Apart from the employment goal, the fulfilment of the other quantitative dimensions of the Eighth Plan would also require very determined efforts. First, to the extent the

real GDP growth during 1992-93, the first year of the Plan, is below the 5.6 per cent per annum target, the actual growth in the subsequent years would have to be accelerated to 6 per cent per annum or beyond. The backlog in the projected agricultural growth rate (3.1 per cent in value added terms) would be still larger. Secondly, the domestic saving rate, even at an unchanged level of 21.6 per cent average for the Eighth Plan, would require a sharp reduction in the dissaving of the public sector which, if achieved without substantial improvement in factor productivity and general efficiency, would have inflationary implications because of the need to reduce subsidies and to enhance public sector prices, tariffs and freights. Also, the increase in public sector saving may mean some curtailment of household disposable income and hence of saving unless restraints are exercised in consumption. Finally, it is the performance on the external front vis-a-vis the Plan goals that would determine the success or otherwise of the adjustment programmes. The planned reduction in the current account deficit (CAD) from an average of 2.4 per cent during the Seventh Plan period to 1.6 per cent during the Eighth Plan would require an export growth of 13.6 per cent in Volume terms and a restraint on import growth to 8.4 per cent. Such an achievement is all the more imperative as the medium-term scenario regarding the debt-service burden is of concern with the burden rising from about \$ 7.5 billion a year (including NRI deposits) in the initial years to around \$ 11.0 billion a year in the last two years of the Plan.

The immediate External Sector Scenario

7.11 While the trauma of the external liquidity crisis has been swiftly over-come, the question of the fundamental disequilibrium on the balance of payments front still remains. The reduction in current account deficit to 1.1 per cent of GDP in 1991-92, was entirely due to the severe compression in imports, which took its toll in a reduced growth of the economy. While the management of the external sector was rendered possible as a result of the import compression, the resulting dislocation of industry and employments raises serious questions about the feasibility of the import compression route as a way out of the balance of payment disequilibrium. In order to revive growth, restrictions on imports have been virtually removed with the exception of a small negative list. A spurt in imports may therefore be expected in 1992-93 with beneficial effects on exports and hopefully, the rate of growth of the economy.

7.12 In the light of the radical reforms in trade and industrial policies, it is no doubt reasonable to expect a substantial rise in export growth. With the new trading arrangements with some of the countries constituting the Commonwealth of Independent States (CIS), there is a need for a appraisal of India's export strategy. Vigorous efforts are required to identify new markets and to expand the country's share in the existing markets. In the final analysis, the benefits of trade liberalisation may be reaped only if the domestic infrastructure like port facilities, transport and communications, and uninterrupted supply of power, are improved with utmost speed and urgency.

7.13 While imports are essential for the growth of the economy and for exports, the recent growth in imports has to a large extent been on account of crude oil and petroleum products. Attainment of viability on the balance of payments front requires concerted efforts at both more efficient use of petroleum products and augmenting as well as diversifying energy sources. The package of energy conservation measures should include appropriate pricing to restrain consumption. In this context, the pass-through of imported petroleum prices and an appropriate exchange rate system are inevitably intertwined.

7.14 An area which requires immediate attention is the augmentation of private remittances from Indian expatriates through official channels. The existence of the parallel markets through which a substantial proportion of such remittances was diverted earlier, that is to say, prior to the introduction of LERMS, was facilitated by the more favourable unofficial exchange rate for the rupee prevailing in these markets vis-a-vis official rate. The introduction of LERMS and a number of other related policy reform

measures since March 1992 have facilitated attraction of remittances through official banking channels. The facility to import gold is another favourable factor since parallel market transactions in foreign exchange have been to a large extent linked to the clandestine imports of gold. A large flow of remittances through official channels which will be induced through these measures will also require improvement in the operational efficiency of banking channels which have to become sufficiently responsive to the needs of customers who remit and those who receive.

7.15 The non-resident deposit schemes have gained importance over the years, and the inflows under these schemes have met nearly one-fourth of total financing needs during the Seventh Plan period. The large-scale withdrawal of funds from the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNRA), in the aftermath of the balance of payments crisis in 1991-92, has rendered it an uncertain source. Besides, its cost has become a matter of some concern. The cost, apart from interest rate differential, also reflects the exchange rate protection given to FCNRA and other special-purpose deposits. It may be argued that no foreigner or NRI will place deposits unless he gets the incentive of a high enough return either through exchange rate protection or interest rate spreads or both. Recently, a new scheme for non-repatriable deposits with very attractive features has been introduced; the response to this is still to be seen. The policy objective should be to restructure the various NRI schemes with a view to maintaining attractiveness while reducing (i) the incentive for volatility, (ii) the exchange burden on the central bank of the country, and (iii) the overall effective cost to the country in terms of foreign exchange for such borrowing.

7.16 The country's external debt, inclusive of non-resident Indians' deposits, is placed at about US \$ 70.0 billion or Rs. 2,05,000 crore as on March 31, 1992 and an increasing proportion of debt is on commercial terms. In view of the limited possibilities of a quantum jump in aid flows there is a need to attract foreign direct investment (FDI) on a sizeable scale which confers multiple benefits in the form of balance of payments support, finance for investment, technology transfer, enhancement of competition and efficiency in the Indian industry, and an enlarged export base. The encouragement to FDI in a liberal economic environment has no doubt begun. The attainment of at least an FDI level of say, US \$ 2.0 billion a year, would require the assurance of a stable economic environment, considerable promotional efforts and, above all, the availability of adequate infrastructural facilities.

Overall Performance of Balance of Payments

3.7 Given various uncertainties, it is somewhat difficult to forecast the overall performance of the balance of payments in 1992-93. The trade with East European countries is yet to pick up although agreements have been entered into with a number of these countries. Exports to the General Currency Area in the April-June quarter of the year, have shown an increase of 8.4 per cent; their performance in the remaining months will depend as much on the environment in world trade as on the revival of industrial activity in the country. With the freeing of imports and various reform measures put in place, a better performance on the export front is, however, expected in 1992-93 as compared with that in the previous year. On the basis of current trends, it appears that the country's balance of payments will continue to be under pressure with a current account deficit of US \$ 6 to 7 billion. Keeping in view of the possible inflow of capital from various sources, an exceptional financial need of the order of US \$ 3 billion is envisaged.

7.18 The downward adjustment in the exchange rate of the rupee (by about 18.7 per cent in US dollar terms) and the subsequent introduction of the LERMS combined with other complementary measures, have brought in a number of benefits : removed of budgetary subsidies for export; faster realisation of export proceeds; some correction to the rate for the rupee in the parallel market; and signs of larger remittances through official banking channels. Significantly, this system of partial convertibility has functioned well and

the open market premium over the official rate has generally remained in a narrow range of 16 to 18 per cent. This experience has to be viewed against a number of factors which have contained the demand pressures on foreign exchange resources; sizeable forward sales by banks; the more-than-anticipated level of EXIM scripts available in the market; and the delayed response to import liberalisation measures. Once import demand picks up, the pressure on reserves and hence on the free market exchange rate would begin to be felt. Also, there is the question of the domestic inflation rate which, in the context of the current macro-economic scene, continues to cause concern, although it has declined relative to the last two years' experience. The time-table for introducing full convertibility of the rupee for current account transactions will have to be carefully chalked out keeping in view the macro-economic, including the budgetary, implications of such a decision and the need to increase incentives for exports and remittances.

Fiscal Correction

7.19 At the outset, it has to be recognised that fiscal correction at the Centre and the States is long overdue if debt is to be kept within reasonable levels. Fiscal correction means essentially that Governments should have their revenues cover expenditures and where they do not, returns from investment should cover amortisation costs. So long as revenue deficits continue at the Centre and are financed by borrowing, the vicious cycle of increased borrowing and attempts to force the banks to lend at below-market rates will continue. Credit repression and crowding-out of productive business activity flow from the basic flow of Governments not balancing their consumption outlays with revenues. The correction of the fiscal imbalance has to focus on this root cause of the disequilibrium. The Government's medium-term objective of substantially reducing the Central Government's gross fiscal deficit has to be perceived in the context of ensuring that the level of domestic debt is kept within a sustainable limit. This is all the more necessary in view of the fact that the need to move towards market-related interest rates on Government dated securities and Treasury bills is prerequisite for successful reform of the financial systems also to enable the pursuit of an effective monetary policy. The Centre's gross fiscal deficit has been reduced from 8.4 per cent of GDP in 1990-91 to about 6.5 per cent in 1991-92 and is further expected to decline to 5.0 per cent in 1992-93. As a result of the growing interest burden, the adjustment has turned out to be much sharper in terms of the primary deficit (gross fiscal deficit minus net interest payments) from about 6.0 per cent of GDP. In 1990-91 to 3.5 per cent in 1991-92 and is further expected to decline to 2.3 per cent of GDP in 1992-93. In order to achieve this, the net market borrowing of the Centre has been reduced to Rs. 5,000 crore for 1992-93, a third lower than the level of Rs. 7,500 crore in 1991-92. While the Government's reliance on market borrowing has rightly been sought to be reduced, a word of caution is necessary in that the pace of reduction in market borrowing has to be consistent with the downward adjustment of the gross fiscal deficit. While reducing the market borrowing care needs to be taken to ensure that the monetised deficit does not increase because of higher cost of borrowing from other sources as this would be counterproductive to an early fiscal correction. At the same time, it is necessary to ensure that the system of financing the Government budget deficit is altered by an early date.

7.20 The Reserve Bank has been emphasising now for some years, that its accommodation should take the form of only Ways and Means advances to the Central Government up to an agreed level which should be cleared at the end of each year. Excessive reliance on net Reserve Bank of India credit to the Centre contributes to considerable monetary instability. To ensure that the monetised deficit does not have deleterious effects on the economy, there is a need for a law restricting the extent to which the Centre can run a deficit and moreover there should be a legal ban on the Government borrowing from all sources beyond a certain ceiling with a sub-ceiling on borrowing from the Reserve Bank of India. The upsurge in the Central Government's borrowing in the 1980s, the increase in the coupon rates on Government securities and the compression of maturities, have given rise to

a bunching of repayments and, unlike in the past, in the foreseeable future repayments could by far outstrip the fresh loan floatations. It is in this context that it is necessary to consider the re-introduction of a Consolidated Sinking Fund to redeem the public debt. It is unfortunate that this salutary system of redeeming the Government debt was dispensed with; an early introduction of this system would go a long way towards establishing long-term viability of Government borrowing.

7.21 Measures to curtail the gross fiscal deficit of the Centre have had certain unavoidable repercussions on transfer of resources from the Centre to the States which have suffered due to the rationalisation of the central taxation on structure interest rate changes have also indirectly reduced attractiveness of small savings. Excessive strain on the States' finances is translated into frequent resort to overdrafts. With the pressure on the Centre's resources, advances released to the States have been discontinued which in turn have put the finances of a number of State Governments into a bind. To avoid disruption in the States' finances as a result of the operation of the States' Overdraft Regulation Scheme, which requires the Reserve Bank to stop payments of State Governments which run an overdraft for eight consecutive working days, there is a need to undertake a fundamental reform of State finances to ensure that the States do not have structural deficits. In the case of State Governments, there is a dilemma in that they bear the burnt of agricultural and rural expenditures, as also expenditures on social and economic infrastructures. Any severe and across-the-board curtailment of such expenditures could have a direct bearing on the process of development. In the case, therefore, the focus should be on achieving improvements in the efficiency of resource use simultaneously with reduction in the size of expenditure. Also, there exists, no doubt, substantial scope for augmenting the resources base of State Governments through rationalisation of the States' taxation system including the practices of granting Sales Tax and other exemptions and tax write-offs. The minimisation of the large hidden subsidies is long overdue. It is apparent that utmost priority is required to be accorded for strengthening the tax administration and for improving tax compliance in contrast to the increase in tax rates or the introduction of new taxes. More importantly, there is greater scope for mobilising resources through non-tax revenues, particularly by improving the financial positions of the State departmental and non-departmental enterprises. During the three-year period 1989-90 to 1991-92 the estimated losses of State Electricity Boards work out to over Rs. 17,000 crore, and those of departmental commercial undertakings at Rs. 5,600 crore. In this regard, a recent initiative to strengthen the financial positions of the State Electricity Boards is an important step in the right direction. While the agreement to impose a minimum electricity tariff for agricultural consumers, who have hitherto enjoyed a significant amount of subsidy in this respect, is a welcome beginning, there are many more areas requiring similar attention. In particular, State Transport Corporations and departmentally-run irrigation projects have been incurring massive losses partly due to their inefficiencies of operation and partly due to uneconomic pricing policies. These and other fiscal issues no doubt call for systematic dialogue with State Governments in the context of the stabilisation programme. The introduction of a quarterly review of the budgetary operations of the States would facilitate such a dialogue.

7.22 With the pressure on the overall borrowing programme in 1992-93 because of the reduction in the SLR, the burden of adjustment has fallen on the Centre and Centrally-guaranteed institutions, while the State and State-guaranteed institutions' borrowing has been maintained at the previous year's level. Herein lies a dilemma the increase in coupon rates on Government securities which is a direct consequence of inflationary trends and the need to maintain a real interest rate, leads to a problem for all borrowing entities. In particular, the States, the institutions of which are running relatively inefficiently find, this a problem. Further, debt servicing at these rates requires a much more careful screening of projects which, financed with such high-cost money, can in no way expect a rate of return at a level which would enable servicing of the debt. In the first instance, it is necessary for the States to limit their recourse to high-cost borrowing to finance their revenue deficits and losses of public enterprises.

7.23 The root of the problem is the increasing revenue deficits of States which have then to finance them by borrowing at high cost. These costs in turn add to the revenue deficits leading to an explosive increase in debt. It is inevitable that given the Central Government's fiscal constraints, the States have to balance their revenue budgets with a modicum of transfers from the Centre. If this is not done, the fundamental disequilibrium in States' fiscal situation will continue. The practice of solving the problem by increased transfers from the Centre will only shift the burden of adjustment from the States to the Centre an increasingly difficult task.

Financial Sector Reform

7.24 In recent years substantial reform measures have been implemented in respect of the financial sector. The Narasimham Committee on the Financial System has provided a sharp focus on the need for more rapid reorientation of the financial sector. The Committee's far-reaching recommendations have been discussed in Section I of the Report; quite a few of the recommendations have already been implemented.

7.25 While the need for a basic policy shift from reserve requirements as a tool of monetary control to a more active open market operations policy is well accepted, the central issue is really one of the phasing of this reform. It is recognised that the statutory requirements for banks have reached such high levels that they have tended to become counter-productive and this has fostered the process of disintermediation to an extent. The pace of reduction in reserve requirements needs to be carefully worked out as too rapid a pace of adjustment could conceivably aggravate the problem of excessive liquidity creation in the economy. Thus, a reduction of the CRR to more realistic levels is possible only when there are clear signs of an enduring abatement of inflationary pressures in the economy. As the Narasimham Committee has emphasised, the Reserve Bank should have the flexibility to operate the CRR instrument to serve its monetary policy objectives. An important matter in the CRR regime is the payment of interest on cash balances. It is better to prescribe a low CRR without interest rather than a high CRR with high interest. The dilemma is that the CRR adjustment alters the assets of banks while the reduction in interest affects the income of banks. Thus, the level of CRR and interest rate on cash balances have to be finely modulated to ensure that overall bank profitability is not affected. Again, there is a trade-off between refinancing and CRR. It is probably better to move towards a system of lower CRR and lower refinancing rather than higher CRR and higher refinancing. Ideally, the normal level of CRR should be such that it leaves the banking system viable even if no interest is paid and while the CRR may be raised when monetary expansion is excessive there should be expeditious downward movements when monetary growth comes back to the desired path.

7.26 The Narasimham Committee has recommended that the SLR should be brought down to 25 per cent over a five-year period. This is a reasonable objective to work towards. The phasing of the SLR adjustment should, however, be consistent with the market borrowing programme. A substantial reduction in the SLR was effected in April 1992. The pace of adjustment in the SLR in the future would depend on the pace of fiscal adjustment, the monetary expansion and the inflation rate. The Central Government and Centrally-guaranteed institutions have, in the current year, undertaken a significant reduction in the borrowing programme but the State and State-guaranteed institutions have maintained the borrowing at the previous year's level. While moving to market-related rates on Government and other approved securities, it would be necessary to move the entire borrowing (Centre and States) to market-related rates and as such the phasing needs to be carefully worked out.

7.27 The basic thrust of the Narasimham Committee, that real interest rates should be positive and that compressive interest rates should not be the vehicle for subvention, is well accepted. A considerable extent of interest rate reform has already been undertaken in terms of money market rates, lending and deposit rates and interest rates on Government securities. While these measures need to be preserved with, there is a need for a cautious step-by-step approach rather than a rapid deregulation of all rates in the system. The experience in a number of countries has been that too rapid a

deregulation of interest rates and reserve requirements results in a loss of monetary control something which the Indian economy can ill afford at this stage.

7.28 There are a number of other recommendations of the Narasimham Committee such as reduction in priority sector lendings, the appointment of Special Tribunals for speeding up the process of loan recoveries, the establishment of an Asset Reconstruction Fund (ARF), and reorganisation of the rural credit structure, which need detailed examination and these recommendations have far-reaching implications both in terms of the structure of the financial system and also the financing required to implement these recommendations.

7.29 As regards reduction of the priority sector targeted credit, there is a need to carefully assess the credit requirements of the economically weaker sections of society. The repercussions of any change in the share of these segments on output and employment would have to be studied carefully as the economic structure in India is a highly differentiated one. There are two aspects of priority sector credit which need to be clearly delineated. First the banking system cannot be expected to bear the subvention in terms of low interest rates and to a large extent this matter has been resolved by relating the concessionality to the size of the loan. Secondly, it can be argued that in an economy at the stage of development at which India is, an equitable distribution of credit to the weaker sections can contribute not only to higher output but also help ensure social justice. Whether the banking system is the best instrument for achievement of social goal is a matter of some debate. However, it cannot be denied that the experience in a number of countries shows that some element of direction of credit is necessary in the development process.

7.30 While the Narasimham Committee has recommended the setting up of an Asset Reconstruction Fund (ARF) to take over bad and doubtful debts off the balance sheets of banks and financial institutions there are certain issues which need attention, and before implementing such a scheme, it would be necessary to be clear about the sources of funding. The impact of such a scheme on recovery climate would also need to be considered. The question of the recovery process is being considered. The Narasimham Committee recommendations on the setting up of Special Recovery Tribunals, when implemented would enable the speedy enforcement of banks' claims. The Reserve Bank has already set out certain norms on capital adequacy, income recognition and provisioning. It is recognised that the provisioning will, as a consequence, require large infusion of capital. If these large capital requirements are to be met by the Government or the Reserve Bank, it would merely imply a large monetisation with obvious deleterious effects on the economy. Thus, the strategy for raising fresh capital by banks needs to be carefully worked out.

Agricultural Credit

7.31 Institutional credit to the agricultural sector has been affected by the overdues syndrome that has, over a period of time, debilitated the process of recycling of funds. The Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, has accentuated the problem of recovery. Further, the relatively low rates of interest stipulated for agricultural advances are not only unremunerative but even do not cover the cost of funds and other expenses incurred by co-operative and other credit institutions. As a result, every rupee of deposit mobilised and lent by the co-operative institutions, for instance, means a negative spread and a consequent loss. There is a built-in disincentive to co-operative/rural credit agencies to expand their deposit mobilisation and lending activities so long as they have to lend at low interest and raise deposits at competitive rates. With co-operative credit societies not being able to mobilise adequate deposits to meet credit needs, this has implied greater recourse to refinance from NABARD/RBI.

7.32 A basic prerequisite for a successful financial sector reform is that the rural credit delivery system, which has developed serious problems in the recent period, is revamped and an enduring institutional structure put in place. While the question of imparting improved viability to the rural credit structure has engaged the attention of various Committees, a viable structure has yet to be evolved.

The Government is considering a proposed to set up a National Rural Bank of India. The question of whether all the regional rural banks (RRBs) should be merged into one national level bank or into four or five zonal banks needs urgent attention. The alternative suggested by the Narasimham Committee of merging the RRBs into rural subsidiaries of banks could also be considered. It is imperative to devise a rural credit delivery system which will not require large subvention. In this context, better alignment of interest rates and mix of target and non-target lending would need to be given attention. The problems of the RRBs is a serious one and it would require a multi-pronged approach. To the extent that the rural credit delivery system is satisfactory in an area, it may be feasible to allow existing institutions and new institutions such as rural subsidiaries of commercial banks to develop on their own strength. There are, however, vast areas where the rural delivery system is quite clearly unsatisfactory and it is imperative that early measures are taken to bring about an enduring improvement in the credit delivery system.

Lessons from the Irregularities in Securities Operations

7.33 In an earlier section, the genesis and ramifications of the recently detected irregularities in the securities operations of banking and financial institutions have been explained. The details of the action taken by the Reserve Bank and the Government, are set out in Part Two of this Report. The Bank is undertaking a fresh look at its own operations and organisational structure and staffing. In particular, the Bank is modernising its operations, strengthening its operational efficiency, establishing a regular and systematic economic intelligence apparatus and instituting a strong Supervisory Authority under its aegis which would powers of comprehensive supervision over banks, financial institutions and non-banking financial companies.

7.34 The avowed objective of the Reserve Bank and the Government of India is to restore confidence, both in India and abroad, in the country's financial system. The financial system would become stronger and much more efficient by undertaking appropriate follow-up measures in the light of the recent episode.

7.35 An important issue relates to the impact of these irregularities on the reform process in the financial sector. These irregularities are not attributable to the process of liberalisation. It is necessary to note some of the facts about the process of liberalisation. First, the policies of stabilisation and structural adjustment began towards the end of June 1991. Secondly, the liberalisation process so far has essentially been concerned with fiscal correction, industrial licensing, trade reforms, exchange rate adjustment and rectification of the balance of payments disequilibrium. Thirdly, the instruments of monetary policy were tightened in 1990-91 and the first half of 1991-92 more than ever before with the highest-ever interest rates on bank lendings and severe restrictions on bank credit so as to restrain aggregate demand in the Indian economy in general and import demand in particular; moreover, the traditional instruments of reserve requirements were used as major tools of policy during this period. It is pertinent to note that the financial sector reform is intended to enforce better financial discipline. A link between financial liberalisation and irregularities in securities dealings would thus not be tenable. Finally, it is significant to note that all types of banks and financial institutions—public, private, foreign and co-operative—have been involved in the recent episode. With the vast growth and diversification of the financial system, which has been facilitated by a series of policy initiatives taken during the past few years, the system has now entered a phase of development where further progress is possible only if its efficiency, productivity and profitability are considerably and rapidly improved. The medium-term objective is to put in place a credible and coherent system of financial sector reform. It is, therefore, important that the recent episode, though an unfortunate one, does not put back the clock of reforms. As the Narasimham Committee has emphasised, the deficiencies in the financial system are structural and a vibrant and competitive financial system is necessary to sustain the ongoing reform process to remove structural imbalances in the real economy. For this purpose a well-structured and comprehensive financial sector reform package has to be pursued vigorously so that it would ensure operational flexibility and functional autonomy for the sector.

Board for Financial Supervision

7.36 The Narasimham Committee has recommended the setting up of a Supervisory Board under the aegis of the Reserve Bank of India. The Government have decided to set up a high-powered Board for Financial Supervision under the aegis of the Reserve Bank with the Governor as Chairman. The Vice Chairman will be a Deputy Governor of the Reserve Bank of India exclusively assigned to the work relating to supervision. The Board will consist of four to five full-time members. The Board for Financial Supervision will have an Advisory Council which will consist of eminent persons with background experience in banking, economics, auditing, management, law and public policy. The Board will undertake supervision and also follow-up on compliance.

Money Market Operation and Reserve Requirements

7.37 When the call rates in the money market were freed in May 1989, it was expected that a stable and healthy money market would emerge. The past three years' experience, however, indicates that the call money rates fluctuate sharply during any single reserve requirement fortnight. The freeing of interest rates in one segment, while rates in other segments are generally regulated, does result in the former bearing the brunt of the volatility. The instability in call money rates could be traced to factors, both systemic as well as regulatory, governing the maintenance of reserve requirements. An issue in this context is whether the present system of maintenance of CRR by the banks on the basis of a daily average for a fortnight has contributed to volatility. While the present system of maintenance of CRR provides flexibility to banks both on the borrowing and lending side, the very flexibility afforded to banks has contributed to volatility in the call money rate. In contrast, the SLR is required to be maintained on a daily basis with the liability being lagged by a fortnight as compared with the CRR liability date. In this context, various options can be considered. The liability date for both CRR and SLR could be the same; given the communication system in the country the reference date would be as for SLR and as such the CRR would need to be further lagged than what it is now. If this option is adopted, the logical corollary would be that CRR should, like SLR, be required to be maintained on each day. A lagged reserve requirement attenuates the policy and therefore requires much higher levels to be prescribed. In this context, the reserve requirements could be contemporaneous; this would, however, pose a problem given the present state of communications. It should be recognised that any change in the system of reserve requirements will require a change in the law. While considering a basic change in the reserve requirements it would be best to first undertake the phased reduction in reserve requirements and then consider a fundamental change in the legislative framework. To the extent that some banks have a structural dependence on the money market, call money rates will remain erratic and the resolution of the high volatility in call money rates lies less in reserve requirement systems than in the over-extended position of some banks.

7.38 In the recent period there had been a phenomenal increase in the amount of churning in the dated securities market largely in the form of ready-forward transactions; such activity, ostensibly to adjust reserve requirements, inter alia facilitated the recent irregularities in the securities market. It was for this reason that the Reserve Bank felt it necessary to put a temporary ban on ready-forward transactions in dated securities. A legitimate question that arises is whether there are adequate facilities for inter-bank adjustments of liquidity. Ready-forward transactions in Treasury bills are, however, allowed and a market of nearly Rs. 8,000 crore should suffice for the fortnightly adjustments. There are a number of reasons for not immediately resuming ready-forwards in dated securities. First, the present reserve requirements and the interest rate regulations could provide scope for predatory activity to circumvent the regulatory framework. Secondly, the unwinding of the transactions prior to the ban needs to be completed in view of the serious problems faced by the system. Thirdly, the market borrowing programme and auctions for longer-dated Treasury bills have been proceeding very smoothly despite the disruption of the secondary market. In view of all these factors it is prudent to continue the ban on ready forward transaction in Government securities at least for some time.

7.39 A prerequisite for a well-developed financial system is close integration of various segments of the money market leading to greater stability in and narrowing of differentials among the relative interest rates. Convergence in interest rates on different money market instruments will have to wait till the rates in other segments of the financial markets are freed. A precondition for this to be achieved is that the phenomenon of a large monetisation of the Government debt would need to come down drastically.

Monetary Policy Stance

The macroeconomic state obtained earlier—the possibility of supply shortages due to reduced agricultural output and their consequences on the inflationary situation—calls for considerable vigil on the monetary front. A sharp reduction in the M3 target for 1992-93 to less than 11 per cent, as compared with 10.5 per cent in 1991-92 is considered as very crucial in such a bind, but this is predicated on a significant adjustment in the gross fiscal deficit, as also in the monetised deficit. In this regard, an aspect of fiscal and monetary developments which has been a source of concern to the Reserve Bank relates to the persistence of considerable rigidities in the levels of net RBI credit to the Centre and the budgetary deficit. During the first year and a half months of 1992-93 so far, the budget deficit has been much higher as compared with its levels in the previous year; it has also risen at a faster pace as compared with the previous year's pace of increase. The injection of RBI credit has a multiplier effect working through the system and resulting in considerable secondary expansion. In the current policy environment, the monetary system is considerably short of instruments to sterilise liquidity. The reserve requirements have reached such high levels that, as explained in the earlier paragraphs, their potency has been considerably diluted; any further increase in them would be counter-productive and would also contribute to the process of disintermediation. The interest rate weapon has to be flexibly used against the backdrop of inflation behaviour. The real rates of interest have been positive and kept consciously so to fight inflation. There is a case for persisting with the existing rates until the abatement of inflation is found to be of an enduring nature. For the interest rate policy to be effective, it is necessary that there should be a moderation of fiscal deficits. Considering the recessionary conditions obtaining in industry, we need to improve the credit delivery so that small and medium and large-scale industries alike augment their investment and output activities. A reform in the present system of determining the structure of rates will have to await the emergence of market-determined reference rates in the money market—RBI refinancing rate for short-term instruments and the long-term yield rates on Government dated securities. The process of putting in place a dynamic internal debt management policy has been initiated with a move towards market-related rates of interest on Government debt instruments. It would, however, be quite a while before open market operations become an effective instrument of monetary policy. Be that as it may, it is of utmost importance that the size of the monetised deficit is restricted to realistic levels throughout the year. In fact, in a medium-term context, it is imperative, as has been emphasised by the Reserve Bank of India in the past, that, beyond a mutually agreed quantum of Ways and Means accommodation from the Reserve Bank, it is necessary that Government aims at placing its entire debt including the short-term requirements in the market at appropriate interest rates and, moreover, there should be a ceiling on the Government's access to the Reserve Bank. Apart from the fact that this would allow for a more effective monetary management in the system with a view to achieving a sharp break in inflationary expectations, it would also facilitate the implementation of many other important financial reform measures such as the deregulation of interest rates and the lowering of reserve requirements and the introduction of level playing fields among different types of financial institutions.

7.41 With the shift in emphasis of monetary policy instruments away from reserve requirements, it is essential that interest rate policy is used actively to control monetary expansion and thereby to control inflation. The interest rate policy has played a central role along with the stable exchange rate policy in reversing the leads and lags and this has been an important factor in the sharp recovery of the country's

foreign exchange reserves. As such there is a need to persevere with the present lending rates until monetary expansion slows down and there is an enduring reduction in the inflation rate. Monetary policy during 1992-93 has the unenviable task of bringing about a drastic reduction in overall liquidity without curtailing the resources available for reviving economic activity. While there are always multiple objectives, ultimately the mission of the Reserve Bank has to be to steer monetary policy with its sights set firmly on inflation control.

PART TWO—THE WORKING AND OPERATIONS OF THE RESERVE BANK OF INDIA

VIII. INTRODUCTION

8.1 The accounting year has been one of the most eventful years in the recent history of the Reserve Bank of India. The crucial role played by the Reserve Bank in day-to-day management of external liquidity when it had reached precariously low levels, in averting the crisis and achieving a remarkable recovery in external reserves, and in initiating and/or participating in deliberations associated with stabilisation and structural adjustment measures have all been comprehensively set out in the previous Sections. Two major aspects of its operations which received pointed attention in the context of the reform measures relate to exchange control regulations and banking regulations and supervisory issues; the issues concerning industrial sickness and rehabilitation, rural credit and credit for small-scale industries, urban co-operative banking, regulations of deposit acceptance activities of non banking financial companies, and the subject of currency management, have all received fresh focus in the changing context.

8.2 Anticipating the need for reorienting the roles of different wings of the Bank in the current and prospective economic environment, the Bank had already begun as early as in February, 1991 to take a fresh look at various aspects of its operations and its own organisational structure and staffing and to prepare a Strategic Plan with an overall perspective of the decade ahead broken into suitable sub-periods. In August 1991, two private consultancy organisations were shortlisted for helping the Bank in preparing the Strategic Plan. An in-house group was set up under the Chairmanship of Shri R. Janakiraman, Deputy Governor, in September 1991. On the basis of its report submitted in December, 1991, the RBI set up a Task Force to formulate the Bank's corporate plan. After detailed discussions with the internal Task Force in January, 1992 the two consultancy organisations made preliminary presentations to the Reserve Bank. Finally, one of the consultants, M/s. A. F. Ferguson & Co. was selected in March 1992 to assist the Task Force and other officers, staff and employees of the Bank. Earlier, in November 1991 an Expert Committee under the Chairmanship of Shri S. S. Marathe, a member of the Bank's Central Board, was set up to review the existing policies relating to human resources development in the Bank.

8.3 Considering the need for sharpening the supervisory function of the Bank, a Working Group under the Chairmanship of Shri S. Padmanabhan, former Chairman, Indian Overseas Bank, was appointed in May 1991 and its report had been under the consideration of the Bank. Subsequent to the recommendations of the Narasimham Committee on the Financial System, the broader question of an appropriate supervisory system for the banks and financial institutions has come into sharp focus and it has now been decided to set up a high-powered Board of Financial Supervision under the aegis of the Reserve Bank of India. The precise details regarding its organisational structure and staffing are being worked out. With a view to providing a forum for collaborative efforts between the Bank's professional staff and the academic community, a Development Research Group (DRG) has been constituted in the Bank.

8.4 The magnitude and ramification of the irregularities in securities dealings of banks and financial institutions turned out to be much larger and deeper than what were visualised when preliminary enquiries began in January 1992. As explained in a subsequent paragraph, such co-ordinated frauds can occur in any system. That apart, the Reserve Bank and the Government have now before them the avowed objective of restoring public confidence and the confidence of the inter-

national community in the country's financial system. Towards that end, the lessons and lacunae thrown up by the episode and anticipated by the Janakiraman Committee are being sifted so that foolproof checks and balances are put in place to prevent a recurrence in future. In the meantime, a 10-member Joint Parliamentary Committee (JPC) comprising honourable members from both the Houses of Parliament has been set up in August 1992 to probe into the whole gamut of securities irregularities (Details are given in Chapter IX).

8.5 In the light of these major developments and also keeping in view the changing economic structure, information technology and business environment, the role, functions and operations of the Bank assume greater importance. Part II of the Report deals with some of these issues as also the operational aspects of the Bank during 1991-92, touching thereupon wherever necessary the policy initiatives foreseen to face the challenging situation ahead.

IX. DEVELOPMENTS CONCERNING COMMERCIAL BANKS

Branch Expansion of Commercial Banks

9.1 The previous Annual Report mentioned about some element of freedom to the scheduled commercial banks in respect of opening of Extension Counters and swapping of some unremunerative branches. With the completion of the branch expansion policy for the period 1985-1990, the objective of providing adequate banking infrastructure throughout the country, particularly in rural areas, had been broadly achieved; the opening of new branches in rural areas is being permitted on the basis of the felt need and viability. In response to the suggestions received from banks seeking greater freedom in operational matters in the context of the recent steps towards deregulation and in the light of the recommendations of the Narasimham Committee, a liberalised licensing policy has been put in place the details of which have been already set out in Section I (Paragraph 1.80).

Prudential Norms

9.2 Likewise, a number of other policy actions like capital adequacy measures, norms relating to income recognition, asset classification, provisioning of bad debts on a prudential basis and accounting standards for investments, have also been set out. With a view to bringing about greater transparency in the annual accounts of banks, beginning from the accounting year 1991-92 (April-March), banks are required to prepare their annual accounts in the revised formats which disclose their accounting policies regarding key areas of operations.

Inspection of Banks

9.3 The Reserve Bank has been carrying out two types of inspections under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 : (i) Financial Inspection (FI) at intervals of two to four years which involve visits to Head Offices, Controlling Offices and a cross-section of branches; and (ii) Annual Financial Review (AFR), so far confined to public sector banks, that covers Head Offices and a quarter of the Controlling Offices only, and relies mostly on the banks' Management Information System.

9.4 To obviate the major shortcomings in the AFR exercise, a 'Modified Scheme of Bank Inspection' for all the public sector banks has been introduced on an experimental basis from January 1, 1991. With a view to making the AFR more purposive and to make the findings more pointed, it was thought best to cover a wider cross-section of branches also under this Scheme. Accordingly, the Regional Offices have been advised to take up inspections of as many larger branches of public sector banks as possible in the half-year January to June. It is the intention to cover all the branches with advances of more than Rs. 5 crore each. The Branch Inspection notes are expected to serve as part of support system for AFRs of Head Offices. The Principal Inspecting Officer will update/supplement the findings of those notes with observations during the course of the inspection of Head Offices/Controlling Offices. However, the financial inspections of private sector banks and foreign banks are being conducted as hitherto.

9.5 In May, 1991, as referred to earlier, a Working Group (Chairman : Shri S. Padmanabhan) was set up to look into the present system of the RBI inspections of commercial banks and to make recommendations with a view to making them more purposeful and effective. The group commenced its deliberations on June 8, 1991 and submitted its report to Government on September 10, 1991.

Moratorium, Amalgamation and Liquidation

9.6 Consequent upon the appointment of a Receiver by the Regulators at Cayman Islands to look after the affairs of the Bank of Credit & Commerce International Ltd., the BCCI (Overseas) Ltd., Bombay, had suspended all payments and other transactions with effect from July 1, 1991. With a view to preventing the affairs of BCCI(O) Ltd., Bombay, being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors including the NRI depositors and other creditors of the bank, and with a view to keeping the assets and liabilities of the Bombay branch of the bank separate from the Head Office operations and to settle the claim of Indian depositors, the Reserve Bank filed a petition in the High Court of Bombay to appoint SBI as provisional liquidator of the BCCI(O) Ltd., Bombay, for winding up the operations of the bank. The High Court granted an ad interim order on July 15, 1991 appointing SBI as provisional liquidator.

9.7 Due to large scale irregularities in the securities transactions undertaken by the Bank of Karad Ltd., on behalf of certain brokers involving a very large financial liability which the bank may not be able to fulfil, the bank's continuance would have been prejudicial to the interest of the public and the bank's depositors. On a petition filed by the RBI with the High Court, Bombay, for the appointment of an official of Bank of Baroda, as the provisional liquidator for winding up the operations of the Bank of Karad Ltd., the High Court granted the prayer by passing an ad interim order on May 27, 1992.

9.8 While the above two banks were taken into liquidation during the year, 28 banks in liquidation process were treated as dissolved. The number of banks under liquidation now stands at 96.

9.9 During the period under review the Reserve Bank conducted Annual Financial Reviews in respect of 28 public sector banks and 13 Local Head Offices of State Bank of India. The financial inspections of public sector banks, fourteen private sector banks and ten foreign banks were undertaken during the year.

Irregularities in the Securities Operations of Banks and Financial Institutions

9.10 A pointed reference has been made to the recent episode of gross irregularities in the securities transactions of banks and financial institutions in Sections I and VII of this Report. Two interim reports, as also a third report, submitted by the Janakiraman Committee, which have all been released, have brought out the genesis, the modus operandi, the size and nature of these fraudulent dealings in Government securities, public sector bonds, units of the UTI, and other similar instruments.

9.11 The major findings of the Committee in the two interim reports have indicated serious deficiencies in the functioning of the banks and financial institutions involved, absence of necessary internal control in various functions, raising of funds against securities which proved to be not genuine, deployment of funds in call money market while the banks receiving the funds credited the amounts to brokers' accounts, large concentrations of transactions in securities with only a few rejected brokers (The Committee has observed that over sixty per cent of the transactions were entered into through the medium of brokers) and malva collusion between the concerned officials and the brokers involved in dealings in Government securities, public sector bonds and units, etc. The Committee has listed the devices adopted for diversion of funds from the banking system to the individual accounts of certain brokers which prima facie constitute evidence of fraudulent misrepresentation. Funds—management operations have been conducted in gross violation and with utter disregard of instructions and guidelines issued by the Reserve

Bank from time to time. The break-down of essential disclosure regarding the issue and recording of Bank Receipts (BRs), the receipt and delivery of securities, and the receipt and payment of settlement of the transactions in many of the transactions have been detailed in the Reports. The Committee has also come across instances wherein brokers have been financed by banks through the discounting of bills not supported by genuine commercial transactions. Large-scale violations of RBI guidelines on portfolio management services by certain banks have been pointedly brought out by the Committee in its Third report.

9.12 The total amount of exposure of banks/institutions involved in these transactions aggregated to Rs. 3,542.79 crore (After taking into account the value of securities seized by a bank from a broker to the extent of Rs. 350 crores).

9.13 The Committee has found that increase in the volume of transactions in securities and capital market instruments over the past year, particularly in the form of ready-forward deals, led to indiscriminate use of BRs and even CGLs and facilitated diversion of funds to selected brokers. Funds have been diverted to the broker involved in these irregular transactions and his associated concerns in a number of transaction put through particularly by NHB, State Bank of Saurashtra, SBI and SBI Cap. In several transactions the counterparties mentioned in the contracts provided by the concerned broker were only in name. Further, the facility of netting of the contracts afforded by SBI and SBI Cap. to the broker and collection and credit of bankers' cheques issued in favour of SBI in the broker's accounts and issue of bankers' cheques of SBI as per his instructions have also resulted in irregular operations. The irregularities observed by the Committee in regard to SBI's transactions with the broker indicate that the investment account in SBI's books and SBI's accounts with Public Debt Office (PDO) of RBI had been manipulated to accommodate the broker's transactions.

9.14 The Committee found that the functioning of the Public Debt Office of the Reserve Bank of India required considerable speeding up and computerisation to effectively handle the large number of transactions and to provide relevant information to the banks for reconciliation at regular intervals to detect fraudulent/irregular transactions.

9.15 The Committee has made the following recommendations in its First Interim Report :

- (i) The practice of banks entering into ready-forward and double ready-forward deals with other banks should be restricted to Government securities only and should be prohibited in other securities including PSU bonds, units and shares.
- (ii) Ready-forward and double ready-forward deals may be prohibited under portfolio management schemes.
- (iii) The RBI's prohibition regarding banks entering into buy-back deals with non-bank clients should be strictly enforced.
- (iv) Banks should be required to formulate internal exposure limits for transactions including limits in regard to brokers.
- (v) Brokers' contract notes should indicate counterparty and brokerage charged.
- (vi) When banks act as custodian of brokers' or other parties' securities, the documentation for all transactions effected for such customers should indicate the banks' status.
- (vii) The existing prohibition on banks issuing cheques drawn on their account with the RBI for third party transactions should be strictly enforced.
- (viii) Bank's transactions on behalf of their merchant banking subsidiaries should be transparent giving full details to the subsidiaries.
- (ix) Banks may be required to conduct all their transactions in PSU bonds, units and similar securities through a separate institution like the Stock Holding Corporation, which can be established to obviate the need to issue BRs.

- (x) Speeding up the work in SGL Section of Public Debt Office and furnishing of information to banks.
- (xi) Widening of scope of the RBI inspections with greater emphasis on the treasury transactions and supplementing of on-site inspection by the RBI by reporting of compliance by banks duly certified by the statutory auditors, with prudential and other guidelines.
- (xii) The RBI should review the adequacy of the Internal Audit Department of the banks.
- (xiii) Separate audit by the banks' statutory auditors for the portfolio management operations of the banks.
- (xiv) Strengthening of the RBI's organisation responsible for market intelligence.
- (xv) Institutional arrangements for inspection of National Housing Bank.

9.16 Apart from accepting these recommendations and initiating follow-up action with utmost speed and urgency, the Reserve Bank has taken a number of other steps as detailed in a subsequent paragraph.

9.17 The scrutiny of securities transactions of banks/institutions is continuing with a view to tracing the flow of funds involving various cheques drawn by banks and the brokers.

9.18 The Government and the RBI have taken serious note of gross violation of the RBI guidelines, the failure of internal control systems as also the flouting of banking norms regarding Account Payee cheques. The process for fixing responsibility for lapses and collusion and fraud has been initiated and a CBI enquiry is being undertaken. Government has initiated all steps to ensure that action is taken to recover the dues of the banking system.

9.19 Governor held a special meeting with Chairmen and Managing Directors and Chief Executives of banks and financial institutions on June 9, 1992 for a detailed discussion on the findings and recommendations of the Janakiraman Committee's First Interim Report. The meeting noted the public concern at the recent revelations in the securities transactions of banks and financial institutions and emphasised the need to restore public confidence in their functioning as quickly as possible. The Chief Executives informed the Governor that remedial action has already been initiated by them to introduce proper internal control systems, strengthen monitoring, and remove lacunae in existing systems and procedures so as to prevent the recurrence of similar lapses in future. The Chief Executives expressed their commitment to implement the further guidelines being issued by the RBI based on the Janakiraman Committee Report.

9.20 The Reserve Bank of India and the Government have taken a number of other steps as under with a view to unearthing the entire ramifications of the episode to enable appropriate remedial measures:

- (i) The entire securities transactions of all the banks and institutions for the past one year are under examination by the Inspecting Officers of the RBI.
- (ii) Appropriate action has been taken to facilitate the investigations by the Committee, as also the Central Bureau of Investigations (CBI) who has been asked by the Government of India to investigate into the matter.
- (iii) The Chairman and two Directors of the Bank of Karad Ltd., which is involved in the case, were served with show-cause notices by the Reserve Bank asking them to step down from the posts. Subsequently, with a view to protecting the interests of depositors of the bank, Bank of Karad Ltd. was put under liquidation, and a liquidator has been appointed to take care of the assets of the bank. The Bank of Karad Ltd., a private bank with an asset base of Rs. 80 crore, had an exposure to the tune of Rs. 753 crore by issuing BRs without any backing or against non-existent securities. Any option other than liquidation (i.e.,

amalgamation/merger or moratorium) was not considered feasible having regard to the circumstances of the case. The decision to place the bank in liquidation was also in the best interest of small depositors. Any amalgamation/merger with some other bank would have meant that the acquiring bank would have to be willing to take on a liability to the tune of Rs. 794.22 crore. Moratorium would have made it possible for the institutional creditors to move their preference claim against the bank's assets to the detriment of the interest of a large number of small depositors even to get their deposit insurance money released to the extent of Rs. 30,000 each. On the recommendations of the Reserve Bank of India, the DICGC has been directed to release necessary funds against their insurance liabilities.

- (iv) The operations of the Bank of Madura Ltd. are being investigated and an observer from the Reserve Bank has been appointed.
- (v) The Reserve Bank has recommended to the Government of Maharashtra for directing the State's Registrar of Co-operatives to proceed with the winding up of Metropolitan Co-operative Bank involved in the securities malpractices.
- (vi) With a view to safeguarding the banks'/institutions' interest and speeding up the process of recovery of their dues, an Ordinance has been promulgated by the Government of India attaching the properties of all those persons involved in the malpractices and placing them with the Custodian appointed for the purpose by the Government of India.
- (vii) The Reserve Bank has de-listed four brokers from the Bank's list of approved brokers.
- (viii) The Reserve Bank has directed SBI and ANZ Grindlays Bank Ltd. to make provisions for squaring up their obligations to the National Housing Bank. While SBI has since paid the amount to NHB, ANZ has also brought in the funds to provide for the claim.
- (ix) A 'special court' has been set up by the Government of India to exclusively attend to the cases relating to securities transactions of banks/institutions.
- (x) The recommendations of the Janakiraman Committee in its interim report have been accepted by the Reserve Bank of India and the same have already been implemented by the Bank. It has already taken up the work of computerising SGL Section of PDO. The Reserve Bank has already introduced a computerised system for the processing of SGL transactions in the PDO and the system has since become operational for Central Government loans at Bombay which would be extended shortly to State Government loans also and to other major PDOs. The system provides for (a) prompt and immediate processing of SGL transfer forms and (b) dispatch of certain essential statements to the individual SGL account holders. A Committee under the Chairmanship of Shri S. S. Nadkarni, Chairman of IDBI, has been appointed by the Reserve Bank to suggest modalities for the setting up of a Depository on the lines of the Stock Holding Corporation of India for trading in units and PSU bonds by banks and institutions and the Committee's Report received on August 8, 1992 is under consideration.
- (xi) The Reserve Bank has appointed experienced firms of Chartered Accountants to verify the securities transactions of a number of banks/institutions, including subsidiaries of banks, bank mutual funds and four foreign banks.
- (xii) Action is being taken to drastically overhaul and strengthen the supervisory system for banking and financial institutions and towards that end, to constitute a high-powered Banking Supervisory Board under the aegis of the Reserve Bank of India.

- (xiii) The inspection procedures of the Reserve Bank of India (RBI) are being modified commencing from the current financial year providing for detailed annual inspection of all banks with focus on financial evaluation. Treasury operations of banks will be looked into specifically and at more regular intervals.
- (xiv) The role of the Audit profession is being enlarged in the RBI's supervisory process from the current financial year.
- (xv) Issuance of special guidelines including the prohibition of intro-bank ready-forward deals in dated securities and approved/trustee securities except treasury bills of all maturities and prohibition of double ready-forward deals in Government securities including treasury bills, along with detailed guidelines on the internal control system required to be put in place and accounting standards required to be followed.

9.21 The Janakiraman Committee now proposes to confine its further work, to an examination of the findings of the scrutiny already undertaken by the RBI Inspecting Officers under the direction of the Committee and to report thereon.

JPC

9.22 A 30-member Joint Parliamentary Committee (JPC) comprising honourable members from both the Houses of Parliament has been constituted in August 1992 with the following terms of reference.

- (i) to go into the irregularities and fraudulent manipulations in all its aspects and ramifications in transactions relating to securities, shares, bonds and other financial instruments and the role of the banks, stock exchanges, financial institutions and public sector undertakings in transactions relating thereto, which have or may come to light.
- (ii) to fix responsibilities of the persons, institutions or authorities in respect of such transactions.
- (iii) in the above context, to identify the misuse, if any, of and the failures/inadequacies in the control mechanism and the supervisory mechanism.
- (iv) to make recommendations for safeguards and improvement in the system for elimination of such failures and occurrences in future.
- (v) to make appropriate recommendations regarding policies and regulations to be followed in future.

Industrial Credit and Changing Role of the Reserve Bank

9.23 With the discontinuance of the system of prior credit authorisation as also post-sanction scrutiny of credit proposals of large borrowers on cent per cent basis the role of the Reserve Bank in administering the industrial credit system has undergone a significant change. The observance of the norms has to be increasingly assessed from the view point of prudential requirements rather than that of credit regulation. Large borrowers have also begun to diversify their sources of finance with increasing reliance on funds from non-banking sources. Simultaneously, the subject of industrial sickness, overt as well as incipient, and its repercussions on credit provided by banks and financial institutions, have assumed added significance particularly in the context of structural reforms under way. In the rapidly changing structure, the Reserve Bank would have a wider role to play not only in preventing industrial sickness and minimising non-performing assets of banks but also in serving as a catalytic agent in promoting industrial credit by banks on healthier lines. The translation of these broader themes into concrete action programmes, policies and organisational preparedness in receiving increasing attention in the Bank.

Sick Industrial Undertakings

9.24 The Reserve Bank issued fresh guidelines to banks in August 1991 on industrial sickness including measures to strengthen the bank's organisational machinery for detection

of incipient sickness, taking corrective measures like augmentation of capital by promoters, better co-ordination between the banks and financial institutions, mandatory participation by banks in the rehabilitation packages, designation of Nodal Monitoring Agency (lead bank/financial institution), and devising of a time-frame for implementation of rehabilitation packages. In order to speed up implementation of the rehabilitation package, the Reserve Bank has evolved a 'Single Window Concept for Lending' under the consortium arrangement for sick/weak units for disbursement of credit (working capital/rehabilitation term loan). The banks and financial institutions have also been given the option, on a case-by-case basis, of conversion of interest/term debt into equity or quasi-equity so as to reduce the debt burden of the unit under rehabilitation.

9.25 The Reserve Bank has withdrawn the requirement of its prior approval for extension by banks of concessions/reliefs beyond the prescribed limits to sick/weak units under revival with a view to speeding up the rehabilitation process. Instead, it has introduced a system of quarterly reports to be submitted by commercial banks to monitor their performance in the area of rehabilitation of sick/weak industrial units. The Sick Industrial Co. (Special Power) Act, 1985 amended in December 1991 widening its scope and coverage so as to bring public sector and Government companies within the purview of the Act.

9.26 Between September 1989 and September 1990, the number of SSI sick units (which covers rural artisans, cottage and village industries also) increased from 1,86,441 to 2,25,324. Other larger sick/weak units increased from 2,181 to 2,284. The outstanding bank credit increased to Rs. 9,930.38 crore as against Rs. 6,501 crore in the previous period forming 9.7 per cent of the total bank credit and 17.7 per cent of total bank advances to industry.

The Reserve Bank's Assistance to Financial Institutions

9.27 The Reserve Bank was granting loans on soft terms to public financial institutions in order to augment their resources, out of its National Industrial Credit (LTO) Fund. But in accordance with the decision taken as part of the Union Budget for 1992-93, the practice of appropriating amounts from out of the profits of the Reserve Bank of India to the LTO Funds for providing assistance to industrial and agricultural financial institutions has been discontinued. Therefore, no allocation would be made to the eligible institutions out of the LTO Funds from the year 1992-93 onwards.

9.28 It was mentioned in the last year's Report that the Financial Institutions Cell set up to function as a nodal unit in the Reserve Bank for all issues pertaining to financial institutions, had introduced a quarterly information system in this respect. The data collected under this system are being analysed and used as background information for purposes of policy and monitoring of operations. So far eleven major all-India financial institutions have been brought under the monitoring of the Cell. In the context of the emerging financial sector reforms, and in view of the recommendations of the Committee on the Financial System, the Reserve Bank of India would be more closely involved with the supervision of the financial institutions. The major recommendations of the Committee, as applicable to financial institutions, can be classified under two broad categories, viz., (a) those relating to accounting practices/standards (such as, capital adequacy, income recognition, provisioning and asset classification, valuation of investments, disclosure in financial statements and taxation) and (b) those relating to treatment of bad and doubtful debt portfolios of financial institutions. While the decisions in respect of some of the recommendations of the Committee relating to capital adequacy and prudential accounting norms, as applicable to commercial banks, have already been taken, insofar as financial institutions are concerned, the Reserve Bank in consultation with the major all-India financial institutions will be introducing appropriate norms.

Housing Finance

9.29 Apart from continuing the target of 1.5 per cent of incremental deposits (computed for the period April 1991-March 1992) for housing finance allocation by each bank, it was stipulated during the year that (i) 30 per cent of the

allocation would be by way of direct lending, of which at least one-half should be in rural and semi-urban areas; (ii) 30 per cent as term loans to housing finance companies, housing boards and other public housing agencies; and (iii) the balance of 40 per cent in the form of subscription to guaranteed bonds and debentures of National Housing Bank and Housing and Urban Development Corporation. Banks may exceed their individual targets having regard to their resource position and compliance with their statutory reserve requirements.

9.30 In the case of finance to intermediary lending agencies, the lending rate is 3 percentage points below the minimum rate applicable for credit limits in the category of over Rs. 2 lakh. This concession is available only if not less than 75 per cent of the dwelling units are meant for economically weaker sections and lower income groups as defined by HUDCO and the lending rates charged to the ultimate beneficiaries are in accordance with the lending rates structure prescribed by the Reserve Bank of India for scheduled commercial banks. Loans up to Rs. 5,000/- to SC/ST beneficiaries were provided at an interest rate of 4 per cent per annum. Effective May 14, 1991, these loans may be covered under the DRI Scheme, subject to such beneficiaries fulfilling the income criterion under the Scheme.

9.31 Banks have been advised to ensure that speculative activities in land deals were not supported by the banking system and that there can be no increase in the credit outstanding for 'Real Estate' purposes. Loans provided by banks under their housing finance targets are, however, exempt from this restriction.

9.32 The National Housing Bank was notified by the Government of India on July 26, 1991 as a 'public financial institution'. This move enabled the NHB to diversify its activities towards effective mobilisation of resources. A Board of Directors of the NHB was constituted under a notification issued by the Central Government on April 3, 1992. The share capital of the NHB was raised in March 1992 by Rs. 50 crore to Rs. 250 crore. During the year under review the Reserve Bank advanced to NHB a loan of Rs. 50 crore out of the National Housing Credit (Long-term Operations) Fund raising the total loans advanced out of the Fund to Rs. 175 crore.

Service Area Approach

9.33 The Service Area Approach launched three years ago is in the process of getting stabilised. As per the recommendations of the Central Evaluation Team constituted by the Reserve Bank, the work of computerisation of data under Service Area Monitoring and Information System was awarded to various external computer agencies in different States and the work of computerisation of Lead Bank Returns has since begun.

Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990

9.34 As reported in the previous year's Report, the implementation of Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990 came to a close on June 30, 1991. Earlier figures reported by public sector banks and NABARD indicated that debt relief to the extent of about Rs. 7,917 crore has been provided by banks, of which public sector commercial banks provided Rs. 2,962 crore. Regional Rural Banks (RRBs) Rs. 808 crore and co-operative banks Rs. 4,147 crore. Against this, after carrying out verification of debt relief provided, the banks have claimed an aggregate amount of Rs. 7,800 crore, commercial banks Rs. 2,841 crore, RRBs Rs. 804 crore and co-operatives Rs. 4,155 crore (provisional). The amount of Rs. 2,925 crore released up to June 1992 by the Government of India out of budgetary allocations for the years 1990-91 and 1991-92 has been allocated for reimbursement to the three agencies—Rs. 755.04 crore to public sector commercial banks, Rs. 592 crore to RRBs and Rs. 1,577.16 crore to co-operatives. Also, loans aggregating Rs. 1,604.16 crore were arranged through NABARD for meeting the State Governments' share of 50 per cent in implementation of the Scheme for borrowers of co-operatives.

Committee on Customer Service in Banks

9.35 The Committee on Customer Service in Banks has submitted its Report to the Reserve Bank of India wherein it

has identified a number of areas of customer services which call for improvement and made a number of recommendations to improve customer service in banks. The Bank has carefully examined the various recommendations of the Committee and it has been decided that banks should speedily implement them so as to provide better banking services to the customers.

Committee on Small-Scale Industries

9.36 In December 1991 the Reserve Bank of India appointed a Committee under the Chairmanship of Shri P. R. Nayak, the then Deputy Governor of the Bank, to review the arrangements for meeting the working capital and term loan requirements of small-scale industrial units, etc. The Report is scheduled for submission by end-August 1992.

X. ISSUES RELATING TO THE CO-OPERATIVE CREDIT STRUCTURE

Committee on Licensing of New Urban Co-operative Banks

10.1 As reported in the last year's Annual Report, the Reserve Bank had set up a Committee under the Chairmanship of Shri S. S. Marathe, a member of the Bank's Board, to review the policy relating to the licensing of new urban co-operative banks and other related matters. The Committee in its Report submitted on May 20, 1992 has favoured a somewhat more liberal entry policy and recommended that organisation of new urban co-operative banks may be permitted on criteria of need for the co-operative institution and the potential in the proposed centre/area. The Committee has advocated a pro-active approach to promote the growth of the urban co-operative banking movement in the regions where it has not taken strong roots. It has suggested increased pre-registration entry point criterion relating to initial share capital and achievement of revised norms of viability within 3 to 5 years. Existing banks are also expected to achieve the same norms. It has recommended relaxations in the entry point norms and elongated time-frame schedule for achieving the viability for banks organised in the least and less developed States and Tribal Areas and also an upward revision of existing norms relating to the scheduling of urban co-operative banks in the light of various factors including the revised norms for new urban banks. The Committee favoured the urban co-operative banks in metropolitan areas to operate in the contiguous urban agglomeration areas thereto. In order to ensure the existence of a strong and viable urban banking structure, the Committee has suggested introduction of a monitoring system to generate early warning signals and timely detection of sickness, determine the revival strategies and future set-up of banks falling to respond to revival strategies. In order to remove the existing feeling of alienation of urban co-operative banks it has been recommended that State Governments/State Co-operative Banks/District Central Co-operative Banks may look into various aspects relating to facilities/servicing to be provided to urban co-operative banks.

10.2 Once the recommendations of the Marathe Committee are accepted and begun to be implemented, the main thrust of the Bank's policy initiative in the area of urban co-operative banking would relate to a controlled deregulation in the licensing of new banks, a promotional initiative for the organisation of UCBs in the less developed States based on a region-specific approach, rationalisation of the position in respect of as many as 313 unlicensed banks, weeding out of weak banks and consolidation of the system along sound and viable lines including strengthening of the regulatory as well as supervisory mechanism.

Rehabilitation of Weak Co-operative Banks

10.3 As part of its responsibility to supervise, control and develop the urban co-operative banking system, the Reserve Bank has to ensure the existence of a sound and viable urban co-operative banking structure. With this objective in view, the efforts of the Reserve Bank are directed towards rehabilitation of banks classified as weak due to heavy erosion in their owned funds, high level of overdue, non-compliance with Section 11(1) of Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) regarding minimum share capital, and non-attainment, in stipulated time, of viability norms, prescribed by the Reserve Bank. As a sequel to the adverse findings of inspection/investigation of complaints,

indicating substantial deterioration in the financial position, directions under Section 35-A of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) were issued to 3 primary urban co-operative banks placing restrictions, among others, on payment to depositors incurring expenditure beyond specified amounts and prohibiting granting/renewal of loans and advances. With this, a total of 11 banks were working under such directions.

Winding up of Metropolitan Co-operative Bank Ltd.

10.4 A reference has been made earlier to the involvement of the Metropolitan Co-operative Bank Ltd. in issuing Bank Receipts (BRs) to some banks the outstanding amount of which exceeded Rs. 1,300 crore as against the bank's total working capital of less than Rs. 8 crore. Considering the seriousness of the irregularities, the Reserve Bank in May 1992 asked the Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra in terms of Section 110-A(iii) of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 to immediately replace the Board of Directors of the Co-operative Bank by an Administrator to take charge and run its affairs. After due consideration and consultation with the concerned authorities, the Reserve Bank accorded its sanction for the winding up of the bank on June 19, 1992. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has been requested to stand ready to pay the depositors of the bank, the amount outstanding to their credit up to a maximum of Rs. 30,000 per each depositor.

Change in the Accounting Year for Co-operative Banks

10.5 The accounting period of the co-operative banks has been brought in line with that of commercial banks from the accounting period 1991-92 onwards. Section 29(i) read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 has been amended providing for the Central Government to specify the date with reference to which annual accounts are to be drawn by co-operative banks. The Central Government accordingly issued a notification on January 29, 1992 specifying March 31 of each year as the date for closing of annual accounts and March 31, 1992 as the date for closing of accounts covering the period 1st day of July 1991 to 31st day of March, 1992 by co-operative banks.

XI. DEPOSIT ACCEPTANCE BY NON-BANKING FINANCIAL AND NON-FINANCIAL COMPANIES

Chit Funds Act, 1982

11.1 The Act has so far been brought into force in 19 States/Union Territories, viz., Assam, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry. Necessary followup action is being taken with the remaining States/Union Territories.

Acceptance of Deposits by Union Corporated Bodies

11.2 During the year under review, three more Union Territories have issued notifications authorising suitable officers to take action against unincorporated bodies as envisaged in Sections 45-T and 58-F of the Reserve Bank of India Act, 1934 thereby bringing the total number of such States-Union Territories to 30. The matter is being pursued with the remaining States. Of the prosecutions against 19 unincorporated bodies initiated as reported in the last Report, 5 cases have been disposed of by the trial courts. The other cases are at various stages of trial.

Working Group in Financial Companies

11.3 In May 1992, the Reserve Bank has set up a Working Group under the Chairmanship of Dr. A. C. Shah, Chairman, Bank of Baroda to study in depth the role of non-banking financial companies and suggest regulatory and control measures to ensure health operations of these companies. The Group is expected to submit its report by the end of August 1992.

Bank's Policy and Regulations, towards Deposits Acceptance by Non-Banking Companies

11.4 It was mentioned in the earlier Report that effective July 27, 1991 the maximum rate of interest that non-banking financial companies and miscellaneous non-banking companies can offer on their deposits had been raised from 14 per cent to 15 per cent per annum. In September 1991, it was prescribed that interest could be paid or compounded at quarterly rests. From June 17, 1992, however, these companies have been allowed to pay interest or compound interest at rests not shorter than monthly rests. The requirement of maintaining liquid assets in the form of bank deposits and investments in Government and approved securities by hire-purchase and equipment leasing companies has been raised from 10 per cent to 15 per cent of the deposit liabilities which would be achieved in phases of one per cent in each quarter commencing from November 1, 1991 and reaching 15 per cent on and from November 1, 1992. Out of the 15 per cent liquid assets, a minimum of 5 per cent is required to be kept in the form of Central and State Government securities and/or Central and State Government-guaranteed bonds. The minimum and maximum period for which deposits can be accepted by loan and investment companies have been raised from 6 months and 36 months respectively to over 24 months and 60 months, respectively, as in the case with the hire-purchase and equipment-leasing companies. It has also been stipulated that if a company is engaged both in hire-purchase finance and equipment-leasing activities, its business in both these activities will be taken together in determining its principal business and classification. On a 3-year average the company should hold at least 50 per cent of its assets in hire-purchase and equipment-leasing and should have at least a third of its income from these two activities so as to be classified as a hire-purchase or leasing company.

XII. DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

12.1 Under the Deposit Insurance Scheme of the Corporation, the insurance coverage per depositor per bank and rate of insurance premium remained unaltered at Rs. 30,000 and 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. As at the end of June 1991, the fully-protected accounts constituted 96.4 per cent of the total number of deposit accounts. During the year, the Corporation paid an aggregate amount of Rs. 7.64 crore towards settlement of claims in respect of one commercial bank and four co-operative banks. Furthermore, a provision of Rs. 50.97 crore has been made for claim liabilities (inclusive of Rs. 45.43 crore in respect of the Bank of Karad Ltd.). There have been increasing demands that the existing limits of insurance cover are inadequate. Any increase in the insurance cover would, however, necessitate a stepping up of the premium rate from the existing level. The matter is under consideration.

12.2 Out of its six credit guarantee schemes, the Corporation has terminated three Schemes, viz., Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971, Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 with effect from April 1, 1992 on account of either nil or negligible guaranteed advances and persistent default in payment of guarantee fee, etc., by participating institutions. The two schemes for small borrowers, viz., Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and the one Scheme for Small-Scale Industrial sector, viz., Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 which together cover more than 99 per cent of the total guaranteed advances are, however, in operation. The guaranteed advances under these Schemes amounted to Rs. 46,543 crore as on March 31, 1991. In spite of the increase in the guarantee fee rate from 50.75 paise to Rs. 1.50 per Rs. 100 with effect from April 1, 1989, the guarantee fee receipts fell short of the guarantee claims receipts consecutively over the last two years. There is, therefore, a need for reviewing the operational viability of the existing guarantee schemes.

XIII. EXCHANGE MANAGEMENT AND EXCHANGE CONTROL

13. The year under review saw considerable reorientation in exchange management and control. The introduction of the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) effective from March 1, 1992, as explained earlier, constituted a major step forward in regard to the medium-term objective

of aiming at making the rupee convertible in a phased manner for external transactions in current account. The Reserve Bank has also liberalised many aspects of exchange control, simplified some of them, reduced their rigour and shed its powers in favour of delegating them to authorised dealers for the convenience of users of foreign exchange. The Bank has, however, been entrusted with additional responsibilities in granting automatic approval for direct foreign investment, as also for technology agreements, on high-priority industries, and in approving foreign currency loans/credits of short maturities.

Foreign Investment

13.2 Foreign investment in high priority industries requiring large investments and technology collaboration will be encouraged to obtain higher technology to increase exports and to expand the production base. In this light automatic approval is now being granted by the Reserve Bank for direct foreign investment up to 51% foreign equity in high-priority industries listed in Annexure III to the Statement on Industrial Policy. Such investment in trading companies primarily engaged in export activity is also being permitted. Simultaneously, non-resident Indian (NRI) investment up to 100 per cent equity is being allowed in such high-priority industries. To encourage NRI investment, it has been decided to allow existing or new companies engaged in the areas of specified real estate development to issue shares/convertible debentures to non-resident Indians (NRIs) and overseas corporate bodies (OCBs) owned by them, on non-repatriation basis, upto 100 per cent of the new issue.

13.3 In order to achieve technological upgradation required for improving competitiveness of the Indian Industry in the international market, automatic approval is being given by the Reserve Bank for technology agreements between Indian companies and their foreign collaborators. In order to help this process, the hiring of foreign technicians and foreign testing of indigenously developed technologies have been freed from prior clearance of Government/Reserve Bank as required hitherto.

Direct NRI Investment on Non-repatriation Basis

13.4 The Reserve Bank has granted general permission to NRIs/OCBs to take up or to subscribe to, on non-repatriation basis, the shares or convertible debentures, whether by public issue or private placement, by a company incorporated in India as also to invest by way of capital contribution in any proprietary or partnership concern in India, without prior approval, subject to certain conditions.

Investment by Non-Residents of Indian Nationality/Origin under PIS

13.5 With a view to providing further incentives to NRIs, it has been decided to permit NRIs and their OCBs to acquire both on repatriation and non-repatriation basis, subject to certain prudential limits and a general body resolution to that effect, shares/debentures of Indian companies through stock exchanges in India, under Portfolio Investment Scheme (PIS), up to 24 per cent of total paid-up equity capital of a company concerned and 24 per cent of total paid-up value of each series of convertible debentures issued by a company as against the earlier limit of 5 per cent each.

Acquisition of Immovable Property

13.6 General permission has now been granted to foreign citizens of Indian origin, whether resident in India or not, to acquire immovable properties situated in India for residential purposes against payment in foreign exchange subject to certain conditions.

13.7 It has been decided to permit on application foreign citizens of non-Indian origin, whether resident in India or not, and foreign companies, trusts, societies and associates incorporated abroad to acquire, hold, transfer or dispose of immovable property in India provided purchase consideration is made in foreign exchange out of remittances from abroad. The permission to acquire the property would, however, be subject to the condition that neither the rental income nor the sale proceeds of the property would be allowed to be remitted at any time outside India.

Import of Gold by NRIs

13.8 General permission has been granted to persons of Indian nationality or origin to bring into India as part of

their baggage, gold in any form up to 5,000 grams (i.e., 5 kilograms) provided duty payable on such gold under the Customs Act, 1962 is paid in any convertible foreign currency. The rate of duty which was initially fixed at Rs. 450 per 10 grams has been reduced to Rs. 220 per 10 grams. While in the case of non-residents the general permission is available once in six months, in the case of others the general permission is available provided their stay outside India immediately preceding their coming to India has not been less than six months.

FERA Review

13.9 Government has also announced its intention to undertake a comprehensive review of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 to simplify remove regulations which hinder free flow of foreign capital into India as also investment by Indian companies in joint ventures overseas. In the meantime, the Reserve Bank has issued various notifications under the existing provisions of FERA granting general permissions. Thus, restrictions imposed on FERA companies (i.e., companies incorporated in India in which the non-resident interest is more than 40 per cent) under Section 26(7), 28, 29 and 31 of FERA, 1973 have all been removed as indicated below thereby placing them on par with other Indian companies in regard to their operations in India. FERA Companies are now permitted,

- (a) to borrow money or accept deposits from persons resident in India;
- (b) to accept appointment as agent or technical or management advisers in India of any person or company;
- (c) to allow their trade marks to be used by any person or company;
- (d) to carry on in India any activity of a trading commercial or industrial nature except agricultural and plantation activity;
- (e) to acquire any undertaking in India carrying on any trade, commerce or industry or purchase the shares of any such company; and
- (f) to acquire, hold, transfer or dispose of by sale, mortgage, lease, gift settlement or otherwise any immovable property in India.

IDBs and the Immunities Scheme

13.10 Under the 'Remittances of Foreign Exchange and Investment in Foreign Exchange Bonds (Immunities and Exemptions) Act, 1991 which came into effect from September 18, 1991, two schemes were introduced.

13.11 In terms of Section 3(1)(a) of the Act, 'The Remittances in Foreign Exchange (Immunities) Scheme, 1991' was formulated by the Reserve Bank of India under which a one-time transfer of funds to India was permitted on a non-repatriable basis for which the recipients would not be asked about the source of funds or the purpose and nature of the remittance and would enjoy exemption from exchange control regulations and direct tax laws. The Scheme which was initially open up to November 30, 1991 was extended up to January 31, 1992.

13.12 Under Section 5(1)(a) of the Act, the State Bank of India was permitted by the Reserve Bank to issue India Development Bonds (IDBs), originally in US dollars at a rate of interest of 9.5 per cent per annum but later also in Pound Sterling at an interest rate of 13.25 per cent per annum, for a maturity period of five years from the date of allotment with full repatriation benefits for both interest and principal. Originally, the Scheme was to remain open between October 1, 1991 and November 30, 1991 but it was extended up to January 31, 1992. Eligible subscribers for the IDBs were NRIs, OCBs and banks acting in a fiduciary capacity on behalf of NRIs and OCBs. Authorised dealers have been permitted to grant rupee loans to the non-resident holders of IDBs against their security for certain specified purposes, the rupee loan not exceeding 75 per cent of the value of the security and the rate of interest at 4 per cent above the Bank Rate.

Swaps :

13.13 The Bank commenced dollar/rupee swap transactions with effect from April 29, 1991. The swaps were in the nature of the RBI buying spot US dollar and selling forward for maturities in three and six months. The main purpose behind these deals was to mop up the excess liquidity in the inter-bank market which arises when authorised dealers purchase spot dollars to cover their forward sales to customers.

13.14 The swap window was extended to 2, 4 and 5 months in September 1991 and continued up to February 19, 1992 when it was temporarily suspended. After introduction of LERMS, the Bank reintroduced the swap facility with effect from March 3, 1992 in minimum lots of US dollar 1 million for fixed date deliveries in two, three, four, five and six months. As on June 30, 1992, the outstanding under the swap deals was US \$ 2051.25 million.

Foreign Currency/External Accounts :

13.15 A few new foreign currency/external accounts have been permitted to be maintained. First, the 'Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC) Accounts' wherein all exporters of goods and services and other recipients of inward remittances in convertible currencies are allowed under LERMS to retain up to 15 per cent of their receipts. The accounts can be maintained in any form, i.e., current/savings or term deposits with the banks in India. The funds held in such accounts can be used for meeting current account payment permitted under Trade and Exchange Control Regulations. In view of this, the existing Blanket, CAFEX and BAFEX permit holders were allowed to continue to avail of the remittance facilities for all permitted purposes within the balance available against the said permits up to May 31, 1992.

13.16 Second, the opening of foreign currency accounts by Indian exporters with banks in India and abroad. Permission would be granted selectively to exporters having satisfactory track record and net foreign exchange earnings during the preceding year from exports to and imports from countries in the External Group of not less than Rs. 4 crore to maintain foreign currency accounts with designated branches of authorised dealers in India. As for maintaining foreign currency accounts with bank abroad, the Reserve Bank would consider such cases where exporters are in a position to arrange to raise foreign currency overdrafts/revolving lines of credit from banks abroad for financing their import requirements for export purposes. Normally, only one account will be allowed to be maintained by the exporter in US dollar or Pound sterling. An exporter allowed to open a foreign currency account with either a bank in India or abroad will be permitted to credit proceeds of all export shipments made by him to countries in External Group (except countries which are members of the Asian Clearing Union) to such accounts. The funds in the account will be permitted to be utilised for specified purposes.

13.17 The third is that of opening of Resident Foreign Currency (RFC) Accounts with authorised dealers in India by returning Indians. This new Scheme, replacing the existing 'Returning Indians Foreign Exchange Entitlement (RIFFE) Scheme', enables returning Indians who were residents in the External Group Countries to open and maintain RFC Accounts in US dollar with designated branches of authorised dealers in India to which they are permitted to credit the entire balances standing to the credit of their foreign currency accounts held abroad in permitted currencies which are transferred to India within three months from the date of their arrival in India.

FCNR Swap Scheme :

13.18 Deposits under the Foreign Currency (Non-resident) Deposit Scheme (FCNR) can be accepted in four currencies, viz., Pound sterling, US Dollar, Deutsche mark and Japanese yen. It has now been decided that, in case a customer with any other convertible currency, desires to place a deposit under the scheme, there will be no objection to authorised dealers undertaking a fully-covered swap in that currency against one of the FCNR currencies with an NRI depositor.

This will enable a depositor with a non-FCNR currency to participate in the FCNR Scheme. There is also no objection to such a swap being done between two FCNR currencies. Swap difference may be paid to, or received from, the customer and may also be shared between the customer and their authorised dealer. However, the transaction between the authorised dealer and the Reserve Bank will be only in one of the four FCNR currencies and will be put through in the normal course under the FCNR scheme.

Acceptance of Foreign Currency Deposits from ADs :

13.19 Authorised dealers have been advised that the interest payable on US dollar deposits with the Reserve Bank for maturities beyond one month will be the London Interbank Offered Rate (LIBOR) for the corresponding maturities. Earlier, interest payable on US dollar deposits for periods of one month and above was equal to one month's LIBOR prevailing on the day before the date of transaction.

Inter-bank Deposits :

13.20 Authorised dealers have been permitted to manage their foreign currency funds within prudential norms/guidelines to be prescribed by their top managements and subject to adequate and effective internal controls in place. They would be required to place deposits in four major designated currencies, viz., US dollar, Pound sterling, Deutsche mark and Japanese yen, with other authorised dealers within the local interbank market for amounts and periods of their choice, at market determined rates of interest. It is also not necessary that such transactions should be only for funding the Nostro accounts or for reducing overdrafts in such accounts.

Liberalisations in Exchange Control Regulations :

13.21 With a view to mitigating the rigours of control, exchange control regulations have been relaxed in various areas as indicated below :

- (i) Indian firms/companies have been permitted to engage the services of foreign technicians without the prior approval of the Reserve Bank provided the terms of engagement conform to the prescribed guidelines relating to per diem rate, duration of engagement, etc.
- (ii) The value limits for taking out gold jewellery and precious stones/non-gold jewellery by travellers going abroad have been revised upwards.
- (iii) Consequent on introduction of LERMS, the blanket/BAFEX/CAFEX permit schemes have been withdrawn. Authorised dealers have, however, been permitted to release exchange for foreign travel of residents for business, medical treatment, employment, technical training, study tours, for attending conferences, etc.
- (iv) Additional powers have been given to authorised dealers to allow remittances of export claims, commission on exports, and to permit reduction in invoice value.

XIV. ORGANISATIONAL MATTERS OF THE BANK**Currency Chests :**

14.1 There were in all 3,922 currency chests functioning in the country at the end of June 1992. Out of this, 2,809 chests were with State Bank of India and its associate banks. The nationalised banks held 671, whereas the treasuries and sub-treasuries were having 418 chests. The number of chests with the Reserve Bank and Jammu and Kashmir Bank Ltd. continued to remain unaltered at 17 and 5, respectively. Along with these chests, 492 repositories maintained with public sector banks were also functioning.

14.2 As mentioned in the previous year's Report, a few private sector banks have now been permitted to open currency chests. Fifteen private sector banks have sought permission to establish the chests of which seven have been permitted to set up one chest each in their respective area/zone of operations. Two private sector banks have already established currency chests while another had entered into an agreement with the Reserve Bank to open a chest.

Currency Management .

14.3 There has not been much improvement in the position regarding the availability of fresh notes. The volume of supplies from the existing two note printing presses at Nasik and Dewas has remained, more or less, static for quite sometime. With the increase in demand for fresh notes the gap between demand and supply has been widening and the supply constraints were acute in respect of higher denomination notes giving rise to complaints of non-availability of fresh notes. Under the circumstances, the Bank has had to necessarily advise all the currency chests to sort out notes and salvage maximum number of reissuable notes on a continuing basis and to ensure that surplus/deficit chests are identified to effect inter-and intra-circle diversions. As a sequel to this move and the recycling of soiled notes, there has been deterioration in the quality of currency notes held with the public as also the currency chests. The immediate need to augment the supply of fresh notes in higher denominations to meet the ever increasing demand continues to be of paramount importance.

Committee on Currency Management :

14.4 In keeping with the decision taken by the Committee on Long-Term Coinage Policy of the Government and reiterated by the Committee on Currency Management to coinize notes in denominations of Rupee one, Rupees two and Rupees five in a phased manner by 1995, the Standing Group of the Government of India has already implemented the decision by finalising specifications/designs of coins. The other decisions of the Group include : (i) bringing out a new family of notes of reduced sizes coinciding with the commissioning of the two new note presses at Mysore and Salboni, and (ii) utilising the existing production capacity of the Nasik Press to also print notes of higher denominations in anticipation of increasing demand for such notes. Besides, the Bank has also initiated action with a view to changing the systems and procedures involved in cash handling within the Bank as recommended by the Committee on Currency Management.

New Note Press Project :

14.5 The pace of civil construction including provision of various infrastructural facilities required at the project sites at Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) for the new note printing presses has progressed further during the year under review. The New Note Press Project had reinvited tenders for possible use of web technology for printing notes of lower denominations. On the basis of a techno-economic re-assessment, however, it has been decided to go in for sheet technology for all denominations of notes. As part of the tender processing for the main plant and equipment, the financial packages offered by the tenderers have been evaluated and the choice of successful tenderer is expected to be finalised shortly.

Surveys Conducted by the Reserve Bank :

14.6 The 'Survey of Foreign Currency (Non-Resident) and Non-Resident (External) Rupee Account' conducted earlier for the period July, 1985 to June, 1988 has been launched again in November, 1991 to cover a further three-year period from July, 1988 to June, 1991 and the results are awaited. As referred to in the previous year's Report the decennial All-India Debt and Investment Survey (AIDIS) 1991-92 was launched by the National Sample Survey Organisation (NSSO) as part of the subject programme of their 48th Round. The Bank was actively associated with the technical work of designs, schedules, tabulation formats, etc. for the survey. The field work commenced in January, 1992 and is expected to be completed by December, 1992.

Progress of Computerisation :

14.7 Internal Accounting and Chests Accounting modules are running live at the Issue Departments of Ahmedabad, Byculla, Nagpur, Madras, Hyderabad, Bangalore, New Delhi and Kanpur. The systems are going to be operationalised at Jaipur and Trivandrum shortly. Computerised payroll module is fully operational at Bangalore, Ahmedabad, Madras, and Kanpur Payroll module has been loaded on the issue Department systems at Nagpur & Hyderabad & presently is on the

parallel runs at Nagpur. The payroll software will be loaded on the Issue Department Systems at New Delhi and Trivandrum next month. As regards other offices, it would be taken up in a phased manner.

14.8 For preparation of various reports/statements relating to Weekly Statements, Profit and Loss Accounts, Balance Sheet of the RBI and reconciliation of the RBI General Accounts, etc., 3 personal computers with UNIX operating system have been installed in the Department of Government and Bank Accounts. Five additional PC ATs have been installed in the Department of Economic Analysis and Policy for computerising the activities of the department. Signature storage and retrieval systems have been installed at Nagpur and Bangalore. The system at Bangalore is fully operational. Signature capture work was completed and the system is being utilised for retrieval and verification of signatures. A similar system is delivered to Calcutta Office also. A mini-computer system was installed in the Legal Department for storage and quick retrieval of legal decisions. Software development is in progress. ALPMs (with LAN) were delivered and installed in Madras Office. Software is ported and test runs have started. ALPMs have been delivered at New Delhi; 2 ALPMs have been installed but not yet operationalised.

14.9 The process of replacement of the Present Cii-Honeywell Bull Mainframe Computer System in the Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS) by a state-of-the-art large Mainframe Computer System is in progress. The new system is expected to be installed early next year. A back-up payroll application package has been developed on the IBM computer system of National Clearing Cell so as to avoid any dislocation on processing of sensitive payroll application in the event of break-down of the existing mainframe system which has, of late, become prone to frequent failures. The software packages were developed on PCs for general accounting and pension processing, which can also be used with advantage by various departments of the Bank. Development of software for implementing certain administrative applications like advances for consumer articles, housing loan, etc., is in progress. The first phase consisting of SGI Transfers (local) in respect of Central Government loans has been operationalised since July 2, 1992 and work in respect of remaining items is in progress.

Computerisation of cheque clearance

14.10 One-way inter-city clearing was further extended to connect Trivandrum and Baroda to Bombay and Coimbatore, Salem, Trichy, Madurai and Trivandrum to Madras. The concept of 'Electronic Clearing Service' was introduced with the salary credit of the RBI employees through the Clearing House Mechanism. The scheme is now operational at Madras and one salary disbursing unit of Central Office Pension credit through clearing house mechanism has also commenced at Madras, Calcutta and Bombay. National Clearing Cell, Madras, has also been conducting electronic clearings with the monthly interest payment transactions of Madras-based financial companies.

Office Automation

14.11 Further progress has been made in respect of office aids and equipments in the Bank. In addition to the existing number of Fax machines operating in the Bank, 34 more Fax machines were installed in 8 Central Office Departments, 3 Training Colleges and 21 Offices.

Strategic Planning in the Reserve Bank

14.12 The Reserve Bank is now actively engaged in a Strategic Planning Exercise, which has an overall perspective of 10 years, broken up into smaller periods of 2, 3 and 5 years. The exercise aims at identifying those trends and changes which are likely to occur in the global and national economic environment and their implications for the Reserve Bank.

14.13 The future plan of action regarding computerisation in the Reserve Bank has to be organised in the context of sweeping reforms taking place in the financial sector, introduction of new financial instruments and widening of the financial markets. The macro-economic administration is ex-

pected to undergo considerable changes due to several measures initiated by the Government in an environment of delicensing, deregulation and market determined mechanism for transactions and pricing. In this environment, there will be greater scope for computerisation of new items of work apart from computerising items of work in existing areas. The installation of new state-of-the-art Mainframe Computer System at the Department of Statistical Analysis and Computer Services would provide considerable avenues for development of software, communication experiments for exchange of data with banks and new and quicker methods for data processing and retrieval. The expertise in systems and software areas in the Bank will need to be put to optimum use by creating congenial organisational structure. Existing computer/communication resources, such as, BANKNET and IBM Mainframe will have to be optimally used. MICR or input-based computerised clearing for local and inter-city cheque processing will have to be extended to more and more commercially important towns. It is also necessary to interconnect the four metropolitan towns for clearing settlement operations so that each member bank knows its net funds position immediately after each settlement through BANKNET.

14.14 The stage has now reached to atleast network commercially important centres so as to facilitate instant information/data transfer. There is need for real time on line access to money market indicators (stock market, money market, securities market, etc.) within the country to start with and globally in the shortest span of time. The flow of information should be at a great speed with efficiency. There should be effective use of expertise and software for creating and using the data base. BANKNET should be supplemented with FAX and Electronic Mail facilities. There is a greater need to have an 'integrated on-line payment settlement' system for identified commercially important centres on the patterns of FEDWIRE of USA. It is essential to have a system of on-line updation of SGL account of banks and others with the Reserve Bank and consequential instant payment settlement of such transactions. Even smaller town getting sizeable NRI remittances may have to be networked. This is all the more necessary for the Reserve Bank because of its crucial role as the central banking institution charged with overseeing the functioning of banks and financial institutions.

C. D. DESHMUKH MEMORIAL LECTURE

14.15 The Seventh Chintaman Deshmukh Memorial Lecture was delivered by Mr. Jacques de Larosiere, Governor, Banque de France on March 24, 1992 in Bombay on 'The World-wide Adjustment Process in the 1990s'.

SEANZA CENTRAL BANKING COURSE

14.16 The nineteenth SEANZA Council of Governors' meeting was held on November 22, 1991 in Tokyo hosted by the Bank of Japan. The Governor of the Reserve Bank of India presented the Report of the Directing Staff on the eighteenth SEANZA Central Banking Course held in Bombay in October/December 1990 as also the Report on the cost of the said Course and the principles of cost-sharing. The lectures and notes of the eighteenth SEANZA Central Banking Course have been brought together in the form of a book.

HISTORY OF THE RESERVE BANK

14.17 Work on the History of the Reserve Bank of India is on hand and the drafting of the volume covering developments from 1951 to 1967, under the guidance of the Committee of Direction, is in progress in the History Cell set up for the purpose.

TRAINING

14.18 In the recent period the Bank has been exploring the introduction of new and innovative avenues for improving the general efficiency and professional skill of its employees. As of now, there are a number of schemes in operation and in this year also the Bank came out with certain new schemes and the number of employees availing the facilities and deriving the benefit has been increasing steadily.

DEVELOPMENT RESEARCH GROUP

14.19 The economic reform measures throw up complex and varied issues that their ramifications and long-term effects would need to be discussed by a series of research studies undertaken with intellectual inputs of a high order. With a view to fulfilling this need, the Development Research Group (DRG) was constituted in the Bank's Department of Economic Analysis and Policy in November, 1991. The DRG aims at producing quick and quality papers on subjects of current policy issues and areas of interest to the Bank. The special feature of DRG studies is that it is an outcome of collaborative effort between external experts—academics, consultants and professionals—and a team of research workers within the Bank. These studies are published for wider discussion among professional economists and policy makers. During the first six months of its working, the DRG has published three studies and six studies are on hand.

IGIDR

14.20 The Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) continued its research activities and completed, during the year, studies in the areas of methods of planning and policy analysis, energy policy, agriculture and rural development, industrial sector, macro-economic and monetary policy issues, external sector and environmental studies. It also conducted various conferences and workshops on topics, such as, trade policy reforms, CNG implementation for transportation, challenges of development, economic growth and poverty alleviation, energy modelling and long-range planning for energy resources, and development and environmental sustainability. The Institute is conducting a four-year Ph.D. Programme in Development Policy since August 1990. It has enrolled the second batch in August 1991.

BANKERS TRAINING COLLEGE (BTC), BOMBAY

14.21 The new programmes introduced by the College during the year were in the areas of Mutual Funds, Credit Monitoring, Profile and Financing of Selected Industries, Monetary Management, Security and Risk Management for Security Officers, and Programme for Disciplinary Authorities. The College also arranged seminars on Financial System and Profitability of Commercial Banks.

14.22 During the year, the College conducted 94 programmes (including 9 programmes in Hindi) with 2,396 participants, bringing the total number of participants trained at the College since its inception in 1954 to 43,774.

RESERVE BANK STAFF COLLEGE (RBSC), MADRAS

14.23 The College introduced a few new programmes, such as, Office Management and Housekeeping, Development Programme for Rajbhasha Officers, Programme on 'UNIX' and 'C' Programming Language, and Programme on Structured Systems Analysis and Design.

14.24 During the year, the College conducted 76 programmes, imparting training to 1,627 participants and the total number of officers trained since its inception in 1963 rose to 28,490.

COLLEGE OF AGRICULTURAL BANKING (CAB), PUNE

14.25 During the year, the College conducted four new programmes, viz., Programme on Successful Implementation of Rural Development Schemes, Programme on Financing of Sericulture, Programme on Methods of Recovery of Agricultural Loans, Orientation Programme on Inspection for UBD officers and a Seminar on Agro-exports. Besides, an international programme on 'Management of Financing of Small-Scale Projects' was conducted on behalf of the Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA). Other programmes include four special programmes of four weeks duration each for officers of the National Savings Bank of Sri Lanka and a programme on 'Term Credit Lending' for the officers of Agricultural Development Bank of Afghanistan.

14.26 During the year, the College conducted 104 programmes (including 4 programmes exclusively in Hindi) imparting training to 2,422 officers. The total number of officers trained by the College since its inception in 1969 was 40,478.

ZONAL TRAINING CENTRES (ZTCs)

14.27 The programmes conducted by ZTCs during the year included a one week programme on computer, appreciation for Class III staff. During the year, 1,902 Class III and 295 Class IV staff received training, raising the total number of staff trained by the ZTCs to 40,002 and 2,984 respectively.

TRAINING IN COMMERCIAL BANKS

14.28 Under the scheme of training of the Bank's officers in Grade 'A', 'B' and 'C' in commercial banks, 116 officers have completed the training so far since its introduction in 1986. The scheme was reviewed and revised suitably during the year. Forty officers under have been deputed to commercial banks this year for undergoing training under the revised scheme. During the year, two senior officers completed a six-months attachment in key departments of commercial banks while one more officer is currently undergoing the same.

DEPUTATION OF OFFICERS FOR TRAINING IN INDIA AND ABROAD

14.29 During the year, the Bank deputed 314 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management/banking institutes in India. Two officers are currently attending M. Phil. Course in Applied Economics at the Centre of Development Studies, Tiruvannamalai.

14.30 Twenty six officers were deputed during the year for training/study to banking and financial institutions in the USA, UK, Switzerland, Germany, Japan, Thailand, South Korea, Iran, Philippines and Malaysia.

14.31 Under the scheme for award of scholarships to the Bank's officers for higher studies abroad for a duration not exceeding one year, introduced in 1985 as a part of the Golden Jubilee celebrations of the Banks, 4 officers are being selected every year. Until now 24 officers have had the benefit of this scheme.

TRAINING FACILITIES TO OFFICERS OF FOREIGN BANKS

14.32 During 1991-92, in all, 174 foreign officials from different countries availed the training and study facilities extended by the Bank. Of these, 127 were from Sri Lanka, 13 from Iran, 8 from Afghanistan, 7 each from Kenya and Tanzania, 4 from Uganda, 2 each from Botswana and Nepal, and one each from Ethiopia, Malawi, Kizighistan and Gambia. The total numbers of officers of foreign banks trained since 1981 was 813.

TRAINING IN COMPUTER TECHNOLOGY

14.33 Since 1987 the Bank has been providing incentives for acquiring qualification in the field of computers and in all 117 officers and 476 clerical staff have joined courses at various institutions in the country.

INCENTIVES FOR ACQUIRING PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

14.34 Under a scheme of offering incentives to the employees who successfully complete the Chartered Financial Analysts programme conducted by the Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAL), Hyderabad, 151 employees had availed of the benefit of the scheme.

SCHEME OF SPONSORSHIP FOR Ph.D.

14.35 The Bank introduced another Scheme a year ago of sponsoring officers from the Department of Economic Analysis and Policy for Ph.D. programme and two officers are presently pursuing their studies in IIT, Bombay, while another officer is prosecuting study at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay.

1317 GI/93-27

NORTH EASTERN INSTITUTE OF BANK MANAGEMENT

14.36 North Eastern Institute of Bank Management (NEIBM) was established in Guwahati in 1980 with a view to catering to the training needs of the North Eastern Region. The Institute is engaged in training, research and consultancy in the banking and management development areas. As these facilities needed to be expanded in order to cater more effectively to the banking development potential in the North Eastern States, NEIBM proposed broad-basing of its sponsorship (which was till then confined to just three banks) and requested the Bank to become one of the sponsors. Accordingly, the Bank agreed, in August 1991, to become its lead sponsor, simultaneously with the induction of three more banks including NABARD. The Bank's share in the funding of NEIBMs activities will not be more than 30 per cent, and the Deputy Governor in charge of training is the ex-officio Chairman of its Governing Board.

EMPLOYER-EMPLOYEE RELATIONS

14.37 The employer-employee relations at various centres of the Bank by and large remained cordial during the year.

14.38 A Joint Study Team comprising 6 members each from from All-India Reserve Bank Employees' Association and the Bank was set up in August 1990 to look into the question of providing promotion avenues to Class III employees consistently with organisational needs and achieving greater flexibility in the deployment of staff. The Bank has accepted the Report of the Team and implemented its agreed recommendations in respect of the Cash Department. Another Joint Study Team on similar lines has been constituted by the Bank along with the All India Reserve Bank Workers' Federation to go into the question of recruitment to base cadres, regularisation of part-time employees into full-time service, absorption of daily wage employees into regular service, etc., and its Report is awaited.

14.39 In response to requests from the Bank's Officers' Associations for a reappraisal of various policies affecting their career,—an Expert Committee was set up under the Chairmanship of Shri S. S. Marathe, to review the existing policies relating to Human Resources Development particularly those of Direct Recruitment and Promotion in the Officers' cadres. The Expert Committee has since submitted its Report and it is being processed by the Bank for phased implementation.

STAFF WELFARE

14.40 During the year under review, the Reserve Bank introduced many welfare measures for the benefit of the staff at large. A mention was made in the last year's Report about establishment of a Fund in commemoration of the birth centenary of Dr. Babasaheb Ambedkar. A new scheme entitled 'Bharat Ratna Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar Centenary Year Scholarship Scheme' was introduced for grant of scholarships from out of this Fund exclusively for the children of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Workmen employees of the Bank.

14.41 The Bank has liberalised the scope and extent of scholarships granted to the wards of employees under the 'Bank's Golden Jubilee Year Scholarship Scheme'. The liberalisations include doing away with the limit as to the number of scholarships by covering all eligible wards and granting of financial assistance for purchase of books to the wards of workmen employees who are awarded this scholarship.

14.42 In the context of increasing incidents of robberies and terrorist attacks on banks and their employees, the Reserve Bank has, as outlined by the Government of India, made available a package of compensation/rewards for its own employees injured/killed in such incidents. As per this package, the family of the deceased is eligible for receiving compensation ranging from rupees one lakh to five lakh, besides various other benefits. This Scheme along with the Bank's own scheme of compensation for injuries/death due to accidents, while on duty, adequately provides for the employees/families in case of any untoward incidents.

14.43 The Bank effected certain amendments to the RBI Pension Regulations which included an important amendment providing for grant of premature retirement pension to employees seeking voluntary retirement after rendering 20 years of qualifying service and addition upto a maximum of 5 years to qualifying service for such retirement. The employees who had earlier opted for contributory provident fund were allowed to exercise fresh options in favour of pension, in response to which the percentage of pension optees has now gone up to 45.21 per cent. A decision has also been taken to give the benefit of past service in the Public Sector banks (SBI) Central and State Governments Central autonomous bodies as qualifying service for pension broadly on the lines of similar provisions existing in the Central Government Pension Scheme.

Employment to Reserved Categories : SCs/STs.

14.44 The representation to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in different categories of recruitment in the Bank during the calendar year 1991 was as under :

Category	Total Number of Candidates Recruit-ed	of which		Percentage	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	59	16	9	27.1	15.3
Class III	186	33	26	17.7	14.0
Class IV	270	96	24	35.6	8.9
Of whom					
(a) Excluding Sweepers	226	67	20	29.6	8.8
(b) Sweepers	44	29	4	65.9	9.1

With this, the total number of SC and ST employees in the Bank as on January 1, 1992 rose to 2,362 and 704 in Class IV, 2,495 and 1,190 in Class III and 525 and 109 in Class I, respectively. During the year, the Liaison Officer for SC/ST employees conducted inspection of reservation rosters maintained at Bangalore, Bombay, Calcutta, Guwahati, Kanpur and Patna offices of the Bank. There has been a continuing dialogue between the management and the representatives of the All India Reserve Bank SC/ST and Buddhist Employees' Federation to discuss matters relating to implementation of the reservation policy by the Bank. During the year, three such meetings were held at Bombay.

Ex-Servicemen

14.45 During the calendar year 1991, out of 186 and 270 vacancies filled in Classes III and IV respectively, 27 and 66 posts were required to be reserved for ex-servicemen at the prescribed rates of reservation of 14.5 per cent for Class III and 24.5 per cent for Class IV. As against this, 26 vacancies in Class III and 54 in Class IV were filled up by appointing ex-servicemen raising their total strength in the Bank to 787 in Class III and 1,081 in Class IV as on December 31, 1991.

Physically Handicapped Persons

14.46. During the calendar year 1991, eight physically handicapped persons were recruited in each of Class III and Class IV raising the total number of physically handicapped employees in the Bank to 424.

Promotion of Hindi

14.47 The Bank has been making continuous efforts to promote Hindi in its day-to-day functions. During the year, full time functional Hindi Training Programme for senior officers and Intensive Training Programmes for middle level officers were conducted in which 232 officers participated. Similarly, 1009 employees/officers were trained in Hindi Workshops during the year. Training in Hindi typing was also imparted to 38 English Typists.

14.48 The fourth revised and enlarged edition of 'Banking Shabdavali' was published during the year. Work on 'Banking Paribhasha Kosh', an interpretative dictionary of banking terms and phrases was completed and ready for publication.

14.49 September 14, 1991 was celebrated as Hindi Day at all offices of the Bank. In order to increase the competitiveness among employees as well as officers for increasing use of Hindi, inter-office and inter-departmental competitions were held during the year and shields were awarded.

14.50 Contributions in Hindi to the in-house Journal 'Without Reserve' have increased. Similarly, the Hindi quarterly 'Banking Chintan Anuchintan' published by the Bankers Training College continued to make valuable contribution of original Hindi to banking literature.

Office Building and Residential Accommodation

14.51. During the year, 1991-92 a sum of Rs. 14.24 crore was spent on construction/acquisition of office buildings and residential quarters, additions and alterations to the existing premises and purchase of land, 15 officers' quarters and 92 staff quarters were completed at Lucknow and Bhubaneswar during the year. The work on construction of office buildings at Jammu and that of Bankers Training College complex at Hyderabad is in progress. Construction of 560 officers' quarters and 468 staff quarters are in progress at different Centres. Plans have been finalised for constructing an office building together with quarters for Class III and IV staff at New Bombay.

14.52 The Bank has laid down satisfaction norms for residential quarters at 75 per cent for officers (Transferable) and at 50 per cent each for Class III and IV staff (non-transferable). The Bank has achieved the required level of satisfaction in respect of officers' quarters at 11 centres. Similarly, in respect of Class III and IV quarters the required level of satisfaction has been achieved at more than 50 per cent of the centres and with the completion of the projects under construction/planning almost 80 per cent of the centres where the Bank's officers are located would achieve the norm.

Housing Loan

14.53 During the period July 1, 1991 to June 30, 1992, the Bank sanctioned a total amount of Rs. 14.26 crore towards housing loans to employees (societies/individuals). The details are given below :

Category	No. of Societies	No. of Employees	Amount in Rupees
1	2	3	4
A. Co-operative Housing Societies	35	141	64,98,830
(i) Fresh loans	—	—	—
(ii) Additional loans	35	141	64,98,830
B. Individual loans sanctioned by Central Office	—	322	3,43,25,189
(i) Fresh loans	—	209	3,09,07,122
(ii) Additional loans	—	113	34,18,067
C. Individual loans sanctioned by Regional Offices	—	1,264*	10,17,95,886*
(i) Fresh loans	—	709	7,83,90,513
(ii) Additional loans	—	555	2,34,05,373
Total (A+B+C)	35	1,727	14,25,19,000

*In respect of Jammu, Jaipur, Kanpur and Calcutta (Banking) Offices, the housing loans relate to sanctions up to March 31, 1992.

Central Board

14.54 Dr. C. Rangarajan, Deputy Governor of the Bank relinquished charge of his office with effect from August 20, 1991 consequent upon his appointment as a full-time Member, Planning Commission. The Board wishes to place on record its high appreciation of the services rendered by Dr. C. Rangarajan.

14.55 Shri A. Ghosh, Deputy Governor of the Bank relinquished charge of his office with effect from the close of business on January 20, 1992 on completion of his term. The Board wishes to place on record its high appreciation of the services rendered by Shri A. Ghosh.

14.56 Shri P. R. Nayak, Deputy Governor of the Bank relinquished charge of his office with effect from the close of business on March 31, 1992 on completion of his term. The Board wishes to place on record its high appreciation of the services rendered by Shri P. K. Nayak.

14.57 Shri S. S. Tarapore, former Executive Director of the Bank was appointed as Deputy Governor with effect from January 30, 1992 for a period up to September 30, 1996.

14.58 Shri S. P. Shukla ceased to be the Government nominee on the Central Board with effect from November 6, 1991 and Shri Montek Singh Ahluwalia, Secretary, Economic Affairs, Government of India, was nominated in his place from that date. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri S. P. Shukla.

14.59 The Board regrets to report the said demise on March 29, 1992 of Col. B. H. Zaidi, former director. Col. Zaidi had been on the Central Board of the Bank from September 16, 1958 to December 12, 1963. The Board wishes to place on record its deep sympathy to the members of his family in their bereavement.

14.60 The Board regrets to report the sad demise on June 5, 1992 of Shri D. C. Kothari, former Director on the Central Board of the Bank from January 15, 1969 to June 30, 1972. The Board wishes to place on record its deep sympathy to the members of his family in their bereavement.

Local Board

14.61 The Board regrets to report the sad demise on June 5, 1992 of Shri Mahboob Ahmed, member of the Eastern Area Local Board of the Bank from August 25, 1984 till his demise. The Board wishes to place on record its deep sympathy to the members of his family in their bereavement.

14.62 There was no change in the constitution of any of the Local Boards during the year.

Appointment of Executives

14.63 Shri W. S. Saraf was appointed as Executive Director with effect from February 1, 1992.

XV. THE BANK'S ACCOUNTS FOR THE YEAR 1991-92 (JULY-JUNE)

1. INCOME

15.1 During the accounting year ended June 30, 1992 the Bank's income, after making adjustments for various provisions, increased by Rs. 1,074.59 crore (or 23.2 per cent)

to Rs. 5,699.56 crore from Rs. 4,624.97 crore of the previous year. The sources of income are given below :

(Rupees crore)

Items	Year ending June 30, 1992	Year ending June 30, 1991
1	2	3
(a) Interest on securities, loans and advances to banks, financial institutions, State Governments etc., (including interest on foreign securities, deposits, etc.,)	4,527.84	3,415.56
(b) Discount on rupee and foreign treasury bills	819.65	962.01
(c) Exchange on remittances, TTs purchased, etc., (including foreign transactions).	307.91	219.79
(d) Commission on management of public debt and other miscellaneous income.	4.16	27.61
Total income :	5,699.56	4,624.97

15.2 There was an increase of Rs. 1,112.28 crore in interest earnings during 1991-92. Discount earned registered a decrease of Rs. 142.36 crore mainly on account of a fall in the discount earnings on Rupee Treasury bills.

2. EXPENDITURE

15.3 Total expenditure which was Rs. 3,279.97 crore during 1990-91 (July-June) increased by Rs. 919.59 crore to Rs. 4,199.56 crore in 1991-92 (July-June). The increase was mainly due to the amount reimbursed to the Government for changes in respect of drawals from the IMF under the Extended Fund Facility, (under which drawings were made during 1981/1984 increased cost of establishment, security printing, turnover commission paid to public sector banks for conducting Government business and payment of interest to scheduled banks on their additional eligible balances for CRR purposes. Of the interest payments of Rs. 3,311.47 crore, interest payments to scheduled banks during the year on their eligible additional balances (i.e., above the 3 per cent statutory ratio) maintained with the Reserve Bank for CRR purposes alone amounted to Rs. 2,683.68 crore and constituted 63.9 per cent of total expenditure (Table 15.1).

15.4 Establishment cost went up by Rs. 33.60 crore to Rs. 277.29 crore and formed 6.6 per cent of total expenditure mainly on account of periodic increases in pay and allowances of staff in all categories and liberalisation in the schemes for reimbursement of medical expenses, leave fare concession, etc.

15.5 Security printing and incidental costs, which constituted 5.7 per cent of total expenditure, amounted to Rs. 238.30 crore and were higher by Rs. 76.02 crore than last year, on account of increase in the rates of charges for printing of note forms and cheque forms.

15.6 The higher turnover in Government transactions handled by Agency Banks resulted in Agency charges registering a rise of Rs. 36.72 crore to Rs. 302.34 crore and formed 7.2 per cent of total expenditure.

15.7 A Major policy decision taken during the year was to discontinue the practice of appropriating large amounts from the profits of the Reserve Bank for credit to various statutory funds for advancing loans to industrial and agricultural financial institutions before transferring the surplus to Government. Accordingly, the surplus profits transferred

Table 15.1 : Reserve Bank of India : Income and Expenditure—1981-82 to 1991-92

(Rupees crore)												
Sr. No.	Particulars	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Total Income (Gross)	1185.42	1343.61	1645.13	1886.28	2209.67	2896.85	3541.23	4939.25	4426.73	4624.97	5699.56
2.	Appropriations to:											
(a)	NIC (LTO) Fund	290.00	315.00	315.00	330.00	400.00	430.00	450.00	450.00	525.00	525.00	—
(b)	NRC (LTO) Fund	180.00	225.00	275.00	300.00	350.00	300.00	330.00	330.00	375.00	400.00	—
(c)	NRC (Stabilisation) Fund	75.00	75.00	80.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	—
(d)	NHC (LTO) Fund	—	—	—	—	—	—	50.00	25.00	50.00	50.00	—
3.	Total (a + b + c + d)	545.00	615.00	670.00	675.00	760.00	740.00	840.00	815.00	960.00	995.00	—
*4.	Net Income (1—3)	640.42	728.61	975.13	1211.28	1449.67	2156.85	2701.23	3215.25	3466.73	3629.97	5699.56
5.	Expenditure:											
(a)	Interest paid to Scheduled Comm. Banks.	228.66	303.19	503.28	625.00	810.00	1042.99	1521.59	1829.82	2137.33	2431.02	2683.68
(b)	Agency Charges	70.16	82.28	93.93	132.85	150.01	163.64	173.88	259.46	261.25	265.62	302.84
(c)	Security Printing	41.53	35.94	43.42	58.28	100.03	173.05	206.81	187.02	143.71	162.27	238.30
(d)	Interest on Extended Funds Facility (EFI)	—	—	—	—	—	368.00	357.03	445.18	388.89	62.00	540.42
(e)	Other Exp. @	90.02	97.20	124.50	185.15	179.58	199.13	231.81	283.64	325.43	359.06	434.82
6.	Total Expenditure (a + b + c + d + e)	430.42	518.61	765.13	1001.28	1239.67	1946.81	2491.12	3005.12	3256.61	3279.97	4199.56
7.	Amount Transferred to Government (4—6)	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.04	210.11	210.13	210.12	350.00	1500.00

@ Includes expenditure on Establishment, interest on funds and other Expenditure. (—) means 'nil'

by the Reserve Bank to Government as announced in the Central Budget, 1992-93 stand at Rs. 1,500 crore for 1991-92 (July-June) as compared with Rs. 350 crore in 1990-91 and Rs. 210 crore in the 1980s (Table 15.1).

3. BALANCE SHEET

Banks' Deposits

15.8 The aggregate deposits of scheduled commercial banks rose by Rs. 12,658.49 crore from the previous year's level of Rs. 30,789.62 crore to Rs. 43,448.11 crore, whereas aggregate deposits of scheduled state co-operative banks, other scheduled co-operative banks, non-scheduled state co-operative banks and other banks, declined by Rs. 356.67 crore from the previous year's level of Rs. 805.04 crore to Rs. 448.37 crore during 1991-92 (July-June).

Other Deposits

15.9 The rise of Rs. 1,821.45 crore in other deposits from the previous year's level of Rs. 5,868.62 crore to Rs. 7,690.07 crore was mainly on account of an increase of Rs. 1,573 crore in the balance in IMF Account No. 1.

Foreign Exchange Assets

15.10 Foreign exchange reserves include foreign securities in the Issue Department, balances held abroad and part of 'Investments' in the Banking Department. Such assets which stood at Rs. 2,382.69 crore as on June 30, 1991 increased by Rs. 13,742.24 crore to Rs. 16,124.93 crore as on June 30, 1992.

GOI Rupee Securities and Investments

15.11 Investments in Government of India (GOI) Rupee Securities and shares of subsidiaries, which were at Rs. 96,410.11 crore as on June 30, 1991 declined by Rs. 2,381.35 crore to Rs. 94,028.76 crore on account of disinvestments of Government of India Rupee Securities during the year.

Loans and Advances

15.12 The credit extended to scheduled banks and financial institutions registered a sharp increase of Rs. 3,077.11 crore from Rs. 9,506.43 crore as at the end of June 1991 to Rs. 12,583.54 crore as at the end of June, 1992 mainly owing to higher outstandings under export refinance (Rs. 7,395 crore) to scheduled commercial banks.

Other Assets

15.13 Other assets increased by Rs. 1,834.83 crore from Rs. 2,513.35 crore as at June 30, 1991 to Rs. 4,348.18 crore mainly on account of gold holdings in Banking Department (Rs. 1,188.65 crore) and accrued income receivable.

Provisions for Exchange Cover for Foreign Currency Deposit Schemes

15.14 In recent period the profitability of the Bank is coming under severe pressure as the Bank is required to make large provisions to cover the exchange risk in respect of the foreign currencies borrowed under (i) Foreign Currency Non-Resident Accounts Scheme and foreign currencies deposited

under similar scheme by foreign banks in India, (ii) funds mobilised under the India Development Bond, and (iii) foreign currency loans obtained by financial institutions and deposited with the Reserve Bank pending utilisation. To cover the fluctuations in the exchange rate of the Rupee, further provisions will have to be made in future as well and such provisions will have to come out of the Bank's profits.

15.15 During the year ended June 30, 1992, the burden devolving on the Reserve Bank of India on account of the exchange risk borne on FCNR Account withdrawals/renewals aggregated Rs. 5,531.91 crore as against Rs. 2,513.83 crore borne in the year ended June 30, 1991. This burden has been borne by the Bank's internal reserves. It is in this context that

an endeavour is being made to restructure various foreign currency deposit schemes (referred to earlier in paragraph 7.15) to reduce the exchange risk devolving on the Bank.

Auditors

15.16 The Accounts of the Bank have been audited by M/s. Sorub S. Engineer and Co., Bombay, M/s. Brahmayya and Co. Madras M/s. N. M. Rajji & Co., Bombay, M/s. Goel Garg & Co., New Delhi, M/s. Guha Nandi and Co., Calcutta and M/s. J. N. Sharma & Co., Kanpur. While the first two auditors were reappointed by the Government of India for 1991-92, the other four auditors have been newly appointed. All the offices of the Bank divided into 6 Zones were allocated for audit by the Statutory Auditors.

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1992

(Rs. Thousands)

Liabilities	1991-92 Rs.		Issue Department 1990-91 Assets Rs.	1991-92 Rs.	1990-91 Rs.
Notes held in the Banking Department	13,45,21	11,87,86	Gold Coin and Bullion		
Notes in circulation	64550,25,75	57858,45,88	(a) Held in India	7275,91,94	7410,79,89
			(b) Held out side India	467,50,24	—
Total Notes issued	64563,70,96	57870,33,74	Foreign Securities	200,00,00	200,00,00
			Total	7943,42,18	7610,79,89
			Rupee Coin	96,01,23	91,46,03
			Government of India Rupec Securities	56524,27,55	50168,07,82
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—	—
Total Liabilities	64563,70,96	57870,33,74	Total Assets	64563,70,96	57870,33,74

BANKING DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Capital paid up	5,00,00	5,00,00	Notes	13,45,21	11,87,86
Reserve Fund	6500,00,00	6500,00,00	Rupee Coin	7,57	10,89
National Industrial Credit (LTO) Fund	5675,00,00	5675,00,00	Small Coin	11,01	6,96
National Housing Credit (L.T.) Fund	175,00,00	175,00,00	Bills Purchased and Discounted		
Deposits			(a) Internal	—	—
(a) Government			(b) External	—	—
(i) Central Government	47,30,04	105,62,06	(c) Government Treasury Bills	1827,77,18	399,20,21
(ii) State Governments	39,16,17	15,75,60	Balances Held Abroad	14690,06,84	2087,54,77
(b) Banks			Investments	38739,34,93	46337,16,59
(i) Scheduled Commercial Banks	43448,10,84	30789,61,72	Loans and Advances to		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	250,01,04	548,01,79	(i) Central Government	—	—
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	135,16,23	188,13,88	(ii) State Governments	170,73,00	16,99,00
(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	10,55,21	10,89,76	Loans and Advances to		
(v) Other Banks	52,65,07	57,98,58	(i) Scheduled Commercial Banks	7471,98,19	6104,28,23
(c) Others	7690,07,35	5868,61,65	(ii) Scheduled State Co-operative Banks	12,68,58	18,83,64
Bills Payable	126,06,92	185,22,75	(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	—	9,83
Other Liabilities	13857,74,23	15853,01,52	(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	—	—

		ASSETS	Rs.	Rs.	
		(v) NABARD	3582,27,17	3322,36,70	
		(vi) Others	1518,59,75	60,84,16	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund			
		(a) Loans and Advances to			
		(i) Industrial Development Bank of India	3576,55,41	3705,15,46	
		(ii) Export Import Bank of India	877,00,00	745,00,00	
		(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	170,00,00	130,00,00	
		(iv) Others	840,00,00	400,00,00	
		(b) Investments in bonds/debentures issued by			
		(i) Industrial Development Bank of India	--	--	
		(ii) Export Import Bank of India	--	--	
		(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	--	--	
		(iv) Others	--	--	
		Loans, Advances and Investments from National Housing Credit (Long Term Operations) Fund			
		(a) Loans and advances to National Housing Bank	175,00,00	125,00,00	
		(b) Investments in bonds/debentures issued by National Housing Bank	--	--	
		Other Assets	4348,18,26	2513,35,01	
Total Liabilities	78011,83,10	65977,89,31	Total Assets	78011,83,10	65977,89,31

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies as per Annexure.

(Rs. Thousands)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 1992

INCOME	1991-92	1090-91
	Rs.	Rs.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.	5699,56,44	4624,97,34
Total	5699,56,44	4624,97,34
EXPENDITURE		
Interest	3311,57,46	2547,69,66
Establishment	277,29,02	243,68,89
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses	8,26	5,34
Remittance of Treasure	5,59,14	4,73,59
Agency Charges	302,34,10	265,62,33
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.)	238,29,63	162,27,50
Printing and Stationery	3,00,97	2,54,43
Postage and Telecommunication charges	531,53	4,68,05
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	15,83,94	12,78,63
Auditors' Fees and Expenses	8,32	9,16
Law Charges	45,89	11,44
Depreciation and Repairs to Bank Property	20,47,81	20,28,00
Miscellaneous Expenses	19,30,37	15,40,32
Total	4199,56,44	3279,97,34

INCOME	1991-92	1991-92
	Rs.	Rs.
Available Balance	1500,00,00	1345,00,00
LESS : Contributions to:		
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		575,00,00
National Rural Credit (Long Term Operations) Fund ²		400,00,00
National Rural Credit (Stabilisation) Fund ⁴		20,00,00
National Housing Credit (Long Term Operations) Fund		50,00,00
Surplus Payable to Central Government	1500,00,00	995,00,00 350,00,00

1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

(V.G. Athavale)
Chief Accountant

(S.S. Tarapore)
Deputy Governor

(R. Janakiraman)
Deputy Governor

(S. Venkataramanan)
Governor

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet of the Bank as at 30th June 1992 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date.

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June, 1992 and the Profit and Loss Account of the year ended on that date and report that where we have called for explanations and information from the Bank, such information and explanations have been given and have been satisfactory.

In our opinion and according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of accounts of the Bank, the Balance Sheet read with Notes to Accounts and Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed there under so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs.

M/s Sorab S. Engineer & Co. M/s Brahmayya & Co. M/s Goel Garg & Co. M/s N.M. Rajji & Co. M/s Guha Nandi & Co.
Auditors Auditors Auditors Auditors Auditors

M/s J.N. Sharma & Co.
Auditors

Dated 20th August 1992.

RESERVE BANK OF INDIA

ANNEXURE

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies

1. (a) Gold holdings

Gold held in Issue and Banking Departments is valued on the basis of average London price of gold and resultant dollars are converted into rupee at the RBI buying rate for dollar prevailing as on the last business day of the year; 90 per cent of the above rate is applied for valuation of gold.

(b) Investments in Foreign Securities

Foreign Securities are valued at rates not exceeding the market rates prevailing on the last business day of the year and are converted into rupee equivalent at the exchange rates prevailing on that date. While depreciation is charged to Profit and Loss account, no credit is taken for appreciation in the value of securities.

(c) Investments in Government of India Rupee Securities

Securities are valued at rates not exceeding the market rates on the last working day of the month of June. While depreciation is charged to Profit and Loss account, no credit is taken for appreciation in the value of securities. The sale proceeds of Rupee Securities are credited to Bank's invest-

ment Account. Profit/Loss is booked only at the time of redemption of securities.

(d) Government Treasury Bills

Treasury Bills are valued at cost.

(e) Bank's investments

Bank's investments in shares of State Bank of India, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank and Discount and Finance House of India Ltd., are valued at cost.

(f) Assets and Liabilities in foreign currencies are translated into rupees at the exchange rates prevailing on the Balance Sheet date except in cases where rates have been contractually fixed. Income and Expenditure are translated into rupees at the holding rates for the month in which the transactions take place.

(g) Profit and Loss Account

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis. Accounting for accrued income and provision for outstanding expenses are made only for individual items of Rs. 1 lakh and above.

(h) Retirement benefits

Contributions to the Gratuity Fund are made on the basis of actuarial valuation every year. An actuarial valuation for the recently introduced Pension Scheme for employees is to be obtained.

(i) Depreciation

Depreciation on assets such as premises, fixtures and electrical installations is charged on written down value method and in case of computers, motor vehicles, etc., depreciation is charged on straight line method.

2. Reserve Fund

Represents initial contribution of Rs. 5 crores made by Government of India in the form of Government securities and appreciation of Rs. 6495 crores on account of revaluation of gold.

3. Deposits—Others

Include mainly deposits from Foreign Central Banks, Financial institutions, IMF balances and staff pension/provident fund contributions.

4. Other Liabilities

Include mainly reserves for exchange fluctuations, Asian Clearing Union account and other contingency accounts.

5. Other Assets

Include mainly gold (valued at Rs. 1188.65 crores which is held outside India), fixed assets, capital works in progress, Receivables, balances in inter-office accounts, staff loans and advances. Fixed assets are stated at cost less accumulated Depreciation.

6. Investments in Banking Department include Rs. 1234.87 crores (Previous year Rs. 95.14 crores) held abroad in foreign currencies.

INDEX OF APPENDIX TABLES

Table No.	Title	Page
1	2	3
I. POLICY DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES		
I.1	Interest Rate Structure for Advances of Scheduled Commercial Banks (Excluding Interest Tax)	2125-26
1.2	Scheduled Commercial Banks' Interest Rates on Deposits	2126
1.3	Interest Rates on Export Credit of Scheduled Commercial Banks (Excluding Interest Tax)	2127
1.4	Minimum Margins and Level of Credit Ceilings (Effective April 22, 1992)	2128
1.5	Foreign Collaboration Approvals	2128
II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS		
II.1	Sectoral Composition and Growth Rates of Real Gross Domestic Product	2129
II.2	Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios	2129
II.3	Agricultural Production	2130
II.4	Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains	2130
II.5	Trends in index of Industrial Production	2131
II.6	Growth in Seventeen Major Groups of Manufacturing Sector	2131-32
II.7	Growth Rate of Industrial Production : Use-based Classification	2132
II.8	Trends in Production of Infrastructure Industries	2132
III. GOVERNMENT FINANCES		
III.1	Measures of Deficit—Monetised, Budget Gross and Net Fiscal Deficits of Central Government	2133
III.2	Fortnightly Levels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government	2134
III.3	Financing of Gross Fiscal Deficit	2134-35
III.4	Total Outstanding Liabilities of Government of India	2135
III.5	Budgetary Deficit, Market Loans and RBI Support to Central Government	2136
III.6	Measures of Deficit—Monetised, Budget, Revenue, Gross and Net-Fiscal Deficit of States	2136
III.7	Financing of States' Gross Fiscal Deficit	2137
III.8	Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments	2137-38
III.9	Developmental and Non-developmental Expenditures of Centre and States	2138
III.10	Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States	2139
III.11	Market Borrowings of Central and State Governments, Local Authorities and Institutions Sponsored by Central and State Governments	2140
III.12	Coupon Rates on Central and State Government Securities	2140
IV. MONETARY AND PRICE TRENDS		
IV.1	Money Stock (M3)—Components and Sources	2141-42
IV.2	Reserve Money—Components and Sources	2142-43
IV.3	Trends in Income Velocity of Currency, Aggregate Deposits, M1 and M3	2143
IV.4	Monetary Ratios	2143-44
IV.5	Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks	2144
IV.6	Variations in Selected items of Scheduled Commercial Banks : Last Week of March	2145

1	2	3
IV.7	Scheduled Commercial Banks' Non-deposit Resources	2145-46
IV.8	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors	2146
IV.9	Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	2147
IV.10	RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks	2147
IV.11	Reserve Bank Refinance to DFHI	2148
IV.12	Cumulative Turnover of the DFHI in Money Market Instruments	2148
IV.13	Interest Rates for Reserve Bank Refinance to DFHI	2149
IV.14	Call Money Lending Rates of DFHI	2149-50
IV.15	182 Day Government of India Treasury Bills	2150
IV.16	364 Day Government of India Treasury Bills	2151
IV.17	Issue of Certificates of Deposit (CDs) by Scheduled Commercial Banks	2151-52
IV.18	Three Phases of Variation in Wholesale Price Index on Point-to-Point Basis	2152
IV.19	Variations in Index Numbers of Wholesale Prices	2153
IV.20	Weighted Contribution of Groups/Commodities to the Increase in the General Index of Wholesale Prices	2154
IV.21	Annual and Quarterly Rates of Price Increases as Reflected in WPI and CPI (Point-to-Point Basis)	2155
IV.22	Gold and Silver Prices in Domestic and International Markets	2155
IV.23	Gold and Silver Ratio in Terms of Grammes	2156
IV.24	Monthly Spread between Gold & Silver Prices	2156

V. CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS

V.1	Assistance Sanctioned and Disbursed by All Financial Institutions	2157-58
V.2	Deposits with the Non-banking Corporate Sector	2158
V.3	Consents/Acknowledgements granted by the Controller of Capital Issue to Government and Non-Government Companies for raising Capital	2159
V.4	New Capital Issue by Non-Government Public Limited Companies	2159-60
V.5	Reserve Bank of India All-India Index Number of Ordinary Share Price (Weekly)	2160

VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

VI.1	India's Overall Balance of Payments (Preliminary)	2161
VI.2	Financing Need and Sources of Financing	2162
VI.3	India's Foreign Exchange Reserves	2163
VI.4	India's Foreign Trade	2164
VI.5	India's Exports of Principal Commodities	2164-65
VI.6	India's Imports of Principal Commodities	2165-66
VI.7	India's Trade with Rupee Payment Area (RPA) and General Currency Area (GCA)	2167
VI.8	External Assistance	2168
VI.9	Deposit Liabilities under NR(E)RA and FCNRA Schemes	2169
VI.10	Interest Rates on FCNRA Deposits	2170
VI.11	India's External Debt	2171
VI.12	Rupee Exchange Rates	2172

APPENDIX TABLE 1.1 INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (EXCLUDING INTEREST TAX)

Category of Account	Rates prior to October 9, 1991	(Per cent per annum)	
		Rates Effective	
		October 9, 1991	April 22 1991
1	2	3	
I. Size of limit			
(1) Upto and inclusive of Rs. 7,500/-	10.0		
(2) Over Rs. 7,500/- and upto Rs. 15,000/-	11.5		

I	2	3	4
(3) Over Rs. 15,000/- and upto Rs. 25,000/-	12.0	13.5	13.5
(4) Over Rs. 25,000/- and upto Rs. 50,000/-	14.0	15.5	16.5
(5) Over Rs. 50,000/- and upto Rs. 2 lakh	15.0	16.5	
(6) Over Rs. 2 lakh*	18.5*	20.0	19.0
	(Minimum)	(Minimum)	(Minimum)
II. (1) DR† Advances	4.0	4.0	4.0
(2) Terms loan to agriculture, SS† and transport operators owning upto two vehicles			
Size of limit			
(i) Over Rs. 25,000 and upto Rs. 50,000/-	13.0	14.0	15.0
(ii) Over Rs. 50,000 and upto Rs. 2 lakh	14.0	15.0	
(iii) Over Rs. 2 lakh	14.0	15.0	15.0
		(Minimum)	(Minimum)
(3) (i) Loans for purchase of consumer durables			
(ii) Loans to individuals against shares and debentures/bonds	---	Banks free to determine the rate	
(iii) Other non-priority sector personal loans	---		
III. Lending rate for commodities coming within the purview of Selective Credit Control (SCC)			
Loans/Advances/Cash Credit/* Overdrafts against commodities subject to SCC	18.5*	20.0	19.0
	(Minimum)	(Minimum)	(Minimum)

NOTES : (1) The effective interest rate on bill discounting in the case of parties with cash credit/overall limits of over Rs. 2 lakh should be one percentage point lower than the rate chargeable on the cash credit/overall facility.

(2) In the case of finance granted to intermediary agencies (including those for housing) for onlending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support the rate should be a fixed rate of 3.0 percentage points below the minimum rate applicable for credit limits in the category of over Rs. 2 lakh.

(3) Where short-term loans are routed through PACS/LAMPS/FSS the rates to be charged by banks to the PACS/LAMPS/FSS shall be 2.5 percentage points lower than the rates to the ultimate borrowers indicated in item I above for the respective size of the limit.

*The changes made in this rate since September 1990 are set out below :

16.0 (minimum) effective September 9, 1990
 17.0 (minimum) effective April 13, 1991
 18.5 (minimum) effective July 4, 1991
 20.0 (minimum) effective October 9, 1991
 19.0 (minimum) effective March 2, 1992.

APPENDIX TABLE 1.2 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' INTEREST RATES ON DEPOSITS

Category of Account	(per cent per annum)		
	Rates effective		
	July 4, 1991	October 9, 1991	April 22, 1992
I	2	3	4
Current	Nil	Nil	Nil
Savings	5.0	5.0	6.0*
Term Deposits			
(a) 46 days to less than one year	9.0	11.0	
(b) One year to less than two years	10.0	12.0	Not exceeding 13.0
(c) Two years to less than three years.	11.0		
(d) Three years and over	13.0	13.0	

*Effective April 24, 1992.

APPENDIX TABLE 1.3 : INTEREST RATES ON EXPORT CREDIT OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS
(Excluding Interest Tax)

(per cent per annum)

Export Credit	Rates effective					
	April 1, 1991	April 23, 1991	August 6, 1991	October 9, 1991	January 1, 1992	March 2, 1992
1	2	3	4	5	6	7
1. Pre-shipment credit						
(a) (i) Up to 180 days	7.50	7.50	12.50	15.00	15.00	15.00
(ii) Beyond 180 days and upto to 270 days*	9.50	9.50	14.50	17.00	17.00	17.00
(b) Against cash incentives, etc., covered by ECGC guarantee up to 90 days	7.50	7.50	12.50	15.00	15.00	15.00
2. Post-shipment credit						
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	8.65	7.00	12.50	15.00	15.00	15.00
(ii) Usance bill (for period comprising usance period of export bills, transit period, as specified by FEDAI, and grace period, wherever applicable.)						
(a) Up to 45 days		7.00				
(b) Beyond 45 days up to 90 days	8.65 (Up to 90 days)	8.65—	12.50	15.00	15.00	15.00
(c) Beyond 90 days up to six months from date of shipment	16.00 (from the date of advance)	18.00 (from the date of advance)	18.00 (from the date of advance)	20.00	20.00	19.00
(b) Beyond six months from date of shipment	16.00 (plus a surcharge of 2.00 from the date of advance)	25.00 (from the date of advance)	25.00 (from the date of advance)	25.00	25.00	24.00
(iii) Cash incentives, receivable from Government, covered by ECGC Guarantee (up to 90 days)	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
(iv) Undrawn balance (up to 90 days)	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (up to 90 days)	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
3. Deferred Credit						
Deferred credit for the period beyond 180 days	8.65	8.65	12.50	15.00	15.00	15.00
4. Duty Drawback Credit Scheme, 1976						
Against duty drawback as provisionally certified by the Customs Authorities (up to 90 days)	Free of interest	Free of interest	Free of interest	Free of interest	—	—
5. Export credit not otherwise specified	16.00 (minimum)	18.00 (minimum)	18.50 (minimum)	20.00 (minimum)	20.00 (minimum)	19.00 (minimum)
6. Post-Shipment Export Credit denominated in Foreign Currency						
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)					8.5	6.5
(ii) Usance bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period, as specified by FEDAI, and grace period, wherever applicable, upto six months from date of shipment.					8.5	6.5

*Prior approval of the Reserve Bank of India is not considered necessary with effect from March 12, 1992.

APPENDIX TABLE 1.4 : MINIMUM MARGINS AND LEVEL OF CREDIT CEILINGS
(effective April 22, 1992)

Commodities	Minimum Margins			(In per cent)
	Mills/ Processing units	Others	Warehouse receipts	Level of Credit ceilings (Base year : Three years ending 1990-91) (Nov.-Oct.)
1	2	3	4	5
1. Paddy/rice	60	75	60	70
2. Wheat	60	75	60	70
3. Pulses	60	75	60	85
4. Other foodgrains	60	75	60	85
5. Oilseeds (viz., groundnut, rapeseed/ mustard, cottonseed, linseed, castorseed and all imported oilseeds)	60	75	60	85
6. Veg table oil (viz., groundnut oil, rapeseed/mustard oil, cottonseed oil, linseed oil, castor oil, vanaspathi and all imported vegetable oils)	60	75	60	85
7. Sugar				
(a) Buffer stock	nil	—	—	—
(b) Unreleased stock	20*	—	—	—
(c) Released stock	75	75	60	—
8. Gur and Khandsari	45	75	60	—
9. Cotton and Kapas	×	75	60	85

@ Applicable to registered oil mills and vanaspathi manufacturers.

— Not Applicable.

* At the rate of to 17.5 percent during the period May 9, 1991 to August 8, 1991.

× Exempt from the stipulations.

APPENDIX TABLE 1.5 : FOREIGN COLLABORATION APPROVALS

Items	1990	1991	1991-92 (August- June) (Post-Policy Period)	1990-91 (August- June)
1	2	3	4	5
1. Total No. of Foreign Collaboration Approvals by :				
(i) SIA	666	760	831	474
(ii) RBI	—	188	580	—
(iii) FIPB	—	2	19	—
TOTAL	666	950	1,430	474
2. No. of FC Approvals Involving Foreign Equity :				
(i) SIA	194	426	332	147
(ii) RBI	—	41	168	—
(iii) FIPB	—	2	19	—
TOTAL	194	289	519	147
Total Amount of Foreign Equity Involved (Rs. in million)				
(i) SIA	1,283.2	3,577.6	4,668.4	1,632.6
(ii) RBI	—	1,422.4	5,734.3	—
(iii) FIPB	—	341.1	8,465.2	—
TOTAL	1,283.2	5,341.1	18,887.9	1,632.6

NOTE : 10 million = 1 crore. SIA—Secretariat for Industrial Approvals.

RBI—Reserve Bank of India. FIPB—Foreign Investment Promotion Board.

APPENDIX TABLE II.1 : SECTORAL COMPOSITION AND GROWTH RATES OF REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

(In per cent)

Sector	Share in real GDP			Growth Rate				
	1990-91*	1980-81	1970-71	1990-91*	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Agriculture and Allied Activities	31.6	38.2	44.5	+4.2	+2.7	+16.4	+0.4	-1.7
(a) Agriculture	29.5	34.7	39.7	+4.3	+2.6	+17.6	+0.5	-1.7
2. Industry	24.6	20.8	18.6	+7.1	+7.4	+8.5	+6.8	+7.8
(a) Manufacturing	20.6	17.6	16.1	+7.3	+7.2	+8.5	+7.0	+7.0
3. Service@	43.8	41.0	36.9	+5.8	+7.8	+7.3	+5.8	+7.3
TOTAL GDP	100.0	100.0	100.0	+5.6	+6.0	+10.5	+4.2	+4.3

* Quick Estimates (February 1992), Central Statistical Organisation.

@Inclusive of Construction.

APPENDIX TABLE II.2 : ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT RATIOS

(In per cent)

Sectors/ Fiscal Year	Gross Saving and Investment as percentage of GDP at Current Market Prices			Net Saving and Investment as percentage of NDP at Current Market Prices		
	1991-92	1990-91	1989-90	1991-92	1990-91	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1. Household Sector Saving; of which : Saving in Financial Assets*	19.2	18.7	18.4	17.1	16.6	16.2
	9.5	8.9	9.5	10.6	9.8	10.6
2. Public Sector	1.2	0.9	1.6	-3.7	-4.1	-3.4
3. Domestic Private Corporate Sector	2.8	2.6	2.7	0.9	0.8	0.8
4. Total : Domestic Saving (1 + 2 + 3)	23.2	22.2	22.7	14.3	13.4	13.6
5. Net Inflow of Foreign Resources	1.3	2.8	2.5	1.4	3.1	2.8
6. Aggregate Investment (4 + 5) GDP/NDP at Current Market Prices (Rupees Crore)	24.5	25.0	25.2	15.7	16.5	16.4
	6,19,000***	5,29,537**	4,50,601@	5,57,079***	4,77,460**	4,05,055@

These are adjusted for financial liabilities. As savings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets, net ratios work out higher than gross ratios: like-wise, in net inflow of foreign resources.

** Quick Estimates.

** RBI Estimates.

) Provisional estimates.

ote : 1. The ratios for 1989-90 and 1990-91 differ from those given in the previous year's Annual Report of the Bank and those published in the CSO's Quick Estimates for 1990-91, because of the revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of fresh data.

2. Figures may not add up to the totals because of rounding off.

APPENDIX TABLE II.3 : AGRICULTURAL PRODUCTION

(In million tonnes)				
CROP	1988-89	1989-90	1990-91 (final)	1991-92 Likely achievement
1	2	3	4	5
1. ALL CROPS £	21.0	2.1	2.6	—1.0
2. FOOD GRAINS	169.9	171.0	176.2	169.0-170.5
Rice	70.5	73.6	74.6	74.0-74.5
Wheat	54.1	49.8	54.5	55.0
Coarsegrains	31.5	34.8	33.0	27.0-27.5
Pulses	13.8	12.8	14.1	13.0-13.5
(a) KHARIF	95.6	101.0	99.9	94.2
Rice	63.4	65.9	66.6	65.7
Coarsegrains	26.6	29.6	27.9	23.5
Pulses	5.6	5.5	5.4	5.0
(b) RABI	74.3	70.0	76.3	74.8-76.3
Rice	7.1	7.0	8.0	8.3-8.8
Wheat	54.1	49.8	54.5	55.0
Coarsegrains	4.9	5.2	5.1	3.5-4.0
Pulses	8.2	7.3	8.7	8.0-8.5
3. OILSEEDS	18.0	16.9	18.5	18.3
4. SUGARCANE	203.0	225.6	240.3	244.8
5. COTTON*	8.7	11.4	9.8	9.8
6. JUTE & MESTA @	7.9	8.3	9.1	10.1

* Million bales—one bale = 170 Kgs. @ Million bales—one bale = 180 Kgs. £ Growth rates.
Source : Ministry of Agriculture, Government of India.

APPENDIX TABLE II.4 : PROCUREMENT, OFF-TAKE AND STOCKS OF FOODGRAINS

(In million tonnes)									
Fiscal Year	Procurement			Off-take			Stocks*		
	Rice	Wheat	Total	Rice	Wheat	Total@	Rice	Wheat	Total@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1989-90	11.2	9.0	20.2	8.4	7.3	15.8	7.9	3.6	11.7
1990-91	12.8	11.1	23.9	7.8	8.3	16.1	11.2	5.8	17.3
1991-92 \$	10.5	7.8	18.3	9.9	9.1	19.0	9.8	2.3	12.1
First quarter (April-June)									
1991	1.3	7.7	9.0	2.5	2.1	4.6	9.9	11.0	21.1
1992 \$	1.1	6.4	7.5	2.3	1.9	4.2	8.4	6.7	15.1

* Stocks are as at end-March for fiscal year period and as at end-June for first quarter period.

@ Includes coarsegrains. \$ Provisional.

Source : Ministry of Food & Civil Supplies, Government of India.

APPENDIX TABLE 11.5 : TRENDS IN INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION
(Base : 1980-81 = 100)

Year	Sector Weight	Mining and Quarrying		Manufacturing		Electricity		General Index	
		11.46		77.11		11.43		100.00	
		Index	Growth rate (percent)	Index	Growth rate (percent)	Index	Growth rate (percent)	Index	Growth rate (percent)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1987-88		184.6	3.7	161.5	7.9	181.0	7.6	166.4	7.3
1988-89		199.1	7.9	175.6	8.7	198.2	9.5	180.9	8.7
1989-90		211.6	6.3	190.7	8.6	219.7	10.9	196.4	8.6
1990-91		221.2	4.5	208.0	9.1	236.8	7.8	212.8	8.3
Apr.-Jun.		211.0	4.7	195.2	14.6	228.1	9.8	200.7	12.6
Jul.-Sept.		196.6	1.7	196.5	12.6	229.7	7.8	200.3	10.6
Oct.-Dec.		215.1	0.4	203.4	5.9	237.6	3.7	208.6	4.9
Jan.-Mar.		262.0	10.5	237.1	5.0	251.9	10.1	241.6	6.2
1991-92		222.9	0.8	205.0	1.4	256.5	8.4	213.0	0.1
Apr.-Jun.		203.1	3.7	188.2	3.6	242.5	6.3	196.1	2.3
Jul.-Sept.		193.1	1.8	194.4	1.1	252.5	10.0	200.9	0.3
Oct.-Dec.		227.6	5.8	196.3	2.4	262.2	10.4	209.1	0.2
Jan.-Mar.		268.7	2.6	238.5	0.8	269.2	6.9	245.7	1.7

APPENDIX TABLE 11.6 : GROWTH IN SEVENTH MAJOR GROUPS OF MANUFACTURING SECTOR

Industry Group	Weight	Fiscal Year		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
I. POSITIVE				
ACCELERATION (During 1991-92)				
1. Beverages, Tobacco and Tobacco Products	1.57	103.0 (+11.8)	104.3 (+1.3)	117.8 (+12.9)
2. Non-metallic Mineral Products	3.00	189.9 (+2.9)	193.2 (+1.7)	204.9 (+6.1)
DECELERATION (During 1991-92)				
3. Basic Metal and Alloys Industries	9.80	143.7 (-0.8)	159.1 (+10.7)	167.8 (+5.5)
4. Paper and Paper Products	3.23	181.5 (+6.0)	197.9 (+9.0)	205.1 (+3.6)
5. Food and Food Products	5.33	150.9 (+1.6)	169.7 (+12.5)	175.5 (+3.4)
6. Chemicals and Chemical Products	12.51	247.6 (+6.1)	254.3 (+2.7)	260.3 (+2.4)
7. Cotton Textiles	12.31	112.3 (+4.2)	128.7 (+14.6)	129.7 (+8.0)
II. NEGATIVE (During 1991-92)				
8. Miscellaneous Manufacturing Industries	0.90	333.2 (+9.0)	323.7 (+2.9)	270.6 (-16.4)
9. Electrical Machinery	5.78	459.2 (+31.9)	562.0 (+22.4)	503.9 (-10.3)
10. Leather and Leather and Fur Products	0.49	188.3 (+6.1)	194.2 (+3.1)	180.7 (-7.0)
11. Metal Products	2.29	142.6 (+6.8)	143.2 (+0.4)	133.2 (-7.0)
12. Wood and Wood Products	0.45	176.0 (+2.5)	198.4 (+12.7)	185.2 (-6.7)

1	2	3	4	5
13. Textile Products (Including wearing apparel other than footwear)	0.82	151.7	103.2	97.3
		(+13.0)	(-32.0)	(-5.7)
14. Jute, Hemp and Mesta Textiles	2.00	97.4	101.7	97.5
		(-4.4)	(+4.4)	(-4.1)
15. Machinery and Machine Tools	6.24	171.9	187.0	179.5
		(+6.7)	(+8.8)	(-4.0)
16. Transport Equipment and Parts	6.39	181.1	192.5	187.6
		(+5.0)	(+6.3)	(-2.5)
17. Rubber, Plastic, Petroleum and Coal Products	4.00	173.5	173.4	171.4
		(+3.1)	(-0.1)	(-1.2)
MANUFACTURING SECTOR	77.11	190.7	208.0	205.0
		(+8.4)	(+9.1)	(-1.4)

Note : Figures in brackets are percentage variation over the previous year.

APPENDIX TABLE II.7 : GROWTH RATE OF INDUSTRIAL PRODUCTION : USE-BASED CLASSIFICATION

Industry Group	All Industries			Selected 155 Industries*				
	Variation in Per cent			Number of Industries	Weight	Variations in Per cent		
	Weight	Growth				1989-90	1990-91@	1991-92@
		1985-86 to 1989-90	1990-91@					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Basic Goods Industries	39.42	+7.4	+3.8	40	36.36	+5.2	+9.7	+6.2
B. Consumer Goods of which	43.65	+7.3	+10.4	47	21.76	+5.2	+9.1	+1.1
(a) Consumer Durables	2.55	+11.8	+14.8	12	2.20	+2.0	+9.1	+12.5
(b) Consumer Non-durables	21.10	+6.5	+9.4	35	19.56	+5.8	+9.1	+1.2
C. Capital Goods	16.42	+14.8	+17.4	32	11.32	+29.1	+5.4	+12.8
D. Intermediate Goods	20.51	+6.5	+6.1	36	16.10	+4.3	+9.5	+0.7
GENERAL INDEX	100.00	+8.5	+8.3	155	85.54	+9.2	+8.6	+0.5

@ Provisional.

* Data are based on 155 selected industries which account for a weight of 85.5 per cent in the General Index.

Source : Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Government of India.

APPENDIX TABLE II.8 : TRENDS IN PRODUCTION OF INFRASTRUCTURE INDUSTRIES

Industry	Weight	Unit	Fiscal Year		
			1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
Electricity	11.43	Billion Units	245.14	264.23	286.70
				(+7.8)	(+8.5)
Coal	6.61	Million Tonnes	200.90	211.70	229.30
				(+5.4)	(+8.3)
Saleable Steel	5.21	"	9.03	9.31	10.07
				(+3.1)	(+8.1)
Cement	1.60	"	45.80	48.69	53.70
				(+6.3)	(+10.3)
Petroleum Crude	2.41	"	34.09	33.03	30.34
				(-3.1)	(-8.1)
Petroleum Refinery Products	1.52	"	48.31	48.15	47.82
				(-0.3)	(-0.7)
Composite Index Of Infrastructure Industries	28.77	Number	205.2	215.0	228.0
				(+4.8)	(+6.0)

Note : Figures in brackets are percentage variation over the previous year.

Source : Ministry of Planning & Programme Implementation, Government of India.

APPENDIX TABLE III.1 : MEASURES OF DEFICIT : MONETISED, BUDGET, GROSS AND NET FISCAL DEFICITS OF CENTRAL GOVERNMENT

(Rupees crore)

Year	Gross Fiscal Deficit@	Net Fiscal Deficit@	Primary Deficit	Monetised Deficit	Conventional Deficit	Revenue Deficit	GDP at Market Price
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	8,299	5,110	7,490	3,551	2,477	2,037	1,36,013
1981-82	8,666	4,591	7,686	3,207	1,400	392	1,59,760
1982-83	10,627*	5,973*	9,541*	3,368	1,656*	1,308	1,78,137
1983-84	13,030*	8,171*	10,903*	3,949	1,417*	2,540	2,07,589
1984-85	17,416	10,972	15,405	6,055	3,745	4,225	2,31,387
1985-86	21,857*	13,543*	18,940*	6,190	5,315*	5,889	2,61,920
1986-87	26,342	17,036	22,449	7,091	8,261	7,777	2,91,974
1987-88	27,044	18,431	21,548	6,559	5,816	9,137	3,32,616
1988-89	30,923	20,770	23,626	6,503	5,642	10,515	3,94,992
1989-90	35,632	23,722	26,349	13,813	10,592	11,914	4,50,601§
1990-91	44,650	30,710	31,909	14,716	11,347	18,562	5,29,537§
1991-92 (RE)	37,792	26,126*	21,839	5,508	7,032†	17,081	6,19,000**
1992-93(BE)	34,408	23,940	15,872	5,389	5,389	13,882	7,00,000§§

As a Percentage to GDP at Market Prices

1980-81	6.10	3.76	5.51	2.61	1.82	1.50
1981-82	5.42	2.87	4.81	2.01	0.88	0.25
1982-83	5.97	3.35	5.36	1.89	0.93	0.73
1983-84	6.28	3.94	5.25	1.90	0.68	1.22
1984-85	7.53	4.74	6.66	2.62	1.62	1.83
1985-86	8.34	5.17	7.23	2.36	2.03	2.25
1986-87	9.02	5.83	7.69	2.43	2.83	2.66
1987-88	8.13	5.54	6.48	1.97	1.75	2.75
1988-89	7.83	5.6	5.98	1.65	1.43	2.66
1989-90	7.91	5.26	5.85	3.07	2.35	2.64
1990-91	8.43	5.80	6.03	2.78	2.14	3.51
1991-92	6.50†	4.22	3.53	0.89	1.14	2.76
1992-93	5.00	3.42	2.27	0.77	0.77	1.98

@ These data differ from those published earlier on account of certain adjustments of contraintries on the capital account. Excluding medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1983-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with the RBI. ** RBI Estimates.

§ Actuals as per RBI Records. § Quick Estimates. §§ Rough Estimates. As per Budget Document. The deficit according to RBI Records after closure of Government Accounts as on March 31, 1992 was Rs. 6,492 crore.

† Inclusive of OCC and others.

Note : 1. The data are based on latest Budget Documents and may differ from those published earlier.

2. For definition of deficit concepts, see Annual Report, RBI, 1989-90, pp. 84-85, also see page 183 para 7.18 of this Report
BE : Budget Estimates. RE : Revised Estimates.

Source : Central Government Budget Documents and RBI Records and National Accounts Statistics.

APPENDIX TABLE III.2 : FORTNIGHTLY LEVELS OF THE CENTRE'S BUDGET DEFICIT AND NET RBI CREDIT TO CENTRAL GOVERNMENT

(Rupees crore)

	Period	Centre's Budget Deficit				Net RBI Credit to Centre			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Estimates (Fortnight)									
	Date \$	7,337	7,206	7,719	5,389	7,337	7,206	7,719	5,389
1	5-4-91	1,170	2,679	2,271	4,774	2,001	2,712	2,427	3,847
2	19-4-91	3,497	3,204	3,716	6,115	3,772	4,050	3,269	6,52
3	3-5-91	6,045	5,754	5,500	6,604	5,461	4,994	3,962	5,219
4	17-5-91	6,176	6,638	8,409	8,928	6,392	7,058	6,764	7,218
5	31-5-91	8,565	8,228	8,925	10,414	7,675	6,907	7,534	7,985
6	14-6-91	9,508	7,698	11,029	10,854	7,784	7,463	9,607	7,192
7	28-6-91	9,824	9,107	11,503	8,886	7,858	7,703	9,168	3,912
8	12-7-91	11,378	9,996	12,747		9,500	9,883	11,165	
9	26-7-91	11,382	10,128	11,873		9,140	8,185	10,580	
10	9-8-91	13,416	10,976	12,793		10,277	9,018	10,759	
11	23-8-91	12,596	8,729	11,571		9,938	7,543	10,303	
12	6-9-91	13,265	10,290	13,442		10,664	8,209	11,029	
13	20-9-91	11,535	10,289	10,393		9,111	7,269	8,890	
14	4-10-91	12,953	11,971	12,406		11,186	9,245	10,445	
15	18-10-91	10,375	10,755	13,097		9,869	10,241	11,866	
16	1-11-91	10,934	11,830	11,409		8,901	10,438	9,564	
17	15-11-91	13,044	13,636	14,245		12,403	12,476	12,418	
18	29-11-91	13,789	13,001	15,272		12,748	12,978	13,117	
19	13-12-91	13,317	15,330	17,419		13,634	15,159	15,830	
20	27-12-91	11,789	13,097	11,503		12,611	13,029	9,812	
21	10-1-92	14,206	15,093	16,177		15,277	15,055	14,979	
22	24-1-92	14,158	15,123	14,138		15,255	14,621	13,961	
23	7-2-92	13,675	15,442	15,726		15,395	15,447	15,305	
24	21-2-92	13,790	14,627	15,024		15,804	15,107	14,454	
25	6-3-92	14,266	15,072	13,001		16,383	16,064	12,485	
26	20-3-92	10,290	11,969	10,606		14,344	14,486	10,452	
	March 31	10,624	11,430	6,492		13,813	14,746	5,508	
Quarterly Averages									
First Quarter		6,398	6,187	7,337		5,843	5,841	6,104	
Second Quarter		12,262	10,068	12,137		9,772	8,185	10,454	
Third Quarter		12,314	12,803	13,622		11,622	11,938	11,865	
Fourth Quarter		13,398	14,554	14,114		15,410	15,130	13,606	
Financial Year Average		10,947	10,818	11,508		10,635	10,336	10,209	

② Based on RBI Records.

\$ The relevant dates of fortnights for 1991-92 have been specified ; the dates for other years pertain to corresponding fortnights.

Note : As per budgetary data, Centre's deficit was Rs. 10,592 crore in 1989-90 and Rs. 11,347 crore in 1990-91.

APPENDIX TABLE III.3 : FINANCING OF GROSS FISCAL DEFICIT

(Rupees crore)

Year	External Finance	Internal Finance			Total Finance/ Gross Fiscal Deficit (2+6)
		Market Borrowings+	Other Liabilities††	Conventional Deficit\$	
		3	4	5	6
1980-81	1,281 (15.4)	2,679 (32.3)	1,862 (22.4)	2,477 (29.9)	7,018 (84.6)
1981-82	964 (11.1)	2,913 (33.6)	3,38 (39.1)	1,400 (16.2)	7,702 (88.9)
1982-83	1,258 (11.8)	3,771 (35.5)	3,942 (37.1)	1,656* (15.6)	9,369 (88.2)
1983-84	1,338 (10.3)	4,038 (31.0)	6,237 (47.8)	1,417* (10.9)	11,692 (89.7)

1	2	3	4	5	6	7
1984-85	1,452 (8.3)	4,095 (23.5)	8,124 (46.7)	3,745 (21.5)	15,964 (91.7)	17,416 (100.0)
1985-86	1,449 (6.6)	4,884 (22.4)	10,209 (46.7)	*5,315* (24.3)	40,408 (93.4)	21,857 (100.0)
1986-87	2,024 (7.7)	5,532 (21.0)	10,525 (39.9)	8,261 (31.4)	24,318 (92.3)	26,342 (100.0)
1987-88	2,893 (10.7)	5,862 (21.7)	12,473 (46.1)	5,816 (21.5)	24,151 (89.3)	27,044 (100.0)
1988-89	2,460 (8.0)	8,418 (27.2)	14,403 (46.6)	5,642 (18.2)	28,463 (92.0)	30,923 (100.0)
1989-90	2,595 (7.3)	7,404 (20.8)	15,041 (42.2)	10,592 (29.7)	33,037 (92.7)	35,632 (100.0)
1990-91	3,181 (7.1)	8,001 (17.9)	22,121 (49.5)	11,347 (25.4)	41,469 (92.9)	44,650 (100.0)
1991-92(RE)	5,063 (13.4)	7,500 (19.8)	18,197 (48.2)	7,032 (18.6)	32,729 (86.6)	37,792 (100.0)
	4,509 (13.1)	5,000 (14.5)	19,510 (56.7)	5,389 (15.7)	29,899 (86.9)	34,408 (100.0)

Note : Figures in brackets represent percentages to total finance/gross fiscal deficit.

† These may, for some years, differ from the data presented in Appendix Table III.11 based on RBI Records due to accounting leads and lags.

†† Other liabilities comprise small savings, provided funds, special deposits, reserve funds, etc.

\$ Defined as variations in 91-days Treasury bills issued net of changes in cash balances with RBI.

* Excluding medium term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with RBI.

BE : Budget Estimates. RE : Revised Estimates.

Source : Budget Documents of Government of India.

APPENDIX TABLE III.4 : TOTAL OUTSTANDING LIABILITIES OF GOVERNMENT OF INDIA

(Rupees crore)

Year	Internal Debt	Small Savings	Provident Fund & Other Accounts	Reserve Fund & Deposits	Total Internal Liabilities (2+3+4+5)	External Liabilities	Total Liabilities (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30,864 (22.7)	7,976 (5.9)	5,977 (4.4)	3,634 (2.7)	48,451 (35.7)	11,298 (8.3)	59,749 (44.0)
1981-82	35,653 (22.4)	9,375 (5.9)	7,203 (4.5)	3,627 (2.3)	55,858 (35.0)	12,328 (7.7)	68,186 (42.7)
1982-83	46,939 (26.4)	11,098 (6.2)	8,789 (5.0)	4,364 (2.5)	71,190 (40.1)	13,682 (7.7)	84,872 (47.8)
1983-84	50,263 (24.3)	13,506 (6.5)	10,368 (5.0)	6,004 (2.9)	80,141 (38.7)	15,120 (7.3)	95,261 (46.1)
1984-85	58,537 (25.4)	17,157 (7.5)	12,547 (5.4)	8,563 (3.7)	96,804 (42.0)	16,637 (7.2)	1,13,441 (49.0)
1985-86	17,039 (27.0)	21,449 (8.2)	15,410 (5.9)	11,433 (4.4)	1,19,331 (45.5)	18,153 (6.9)	1,37,484 (52.4)
1986-87	86,312 (29.4)	24,725 (8.4)	20,204 (6.9)	15,006 (5.1)	1,46,247 (49.8)	20,299 (6.9)	1,66,546 (56.7)
1987-88	98,646 (29.7)	28,358 (8.5)	26,170 (7.9)	19,164 (5.7)	1,72,338 (51.8)	23,223 (7.0)	1,95,561 (58.8)
1988-89	1,14,498 (29.0)	33,833 (8.6)	34,702 (8.8)	20,992 (5.3)	2,04,025 (51.7)	25,746 (6.5)	2,29,771 (58.2)
1989-90	1,33,193 (29.6)	41,791 (9.3)	45,273 (10.0)	19,592 (4.3)	2,39,849 (53.2)	28,343 (6.3)	2,68,192 (59.5)
1990-91	1,54,004 (29.1)	50,100 (9.4)	56,940 (10.8)	22,150 (4.2)	2,83,194 (53.3)	31,525 (5.9)	3,14,719 (59.4)
1991-92 (RE)	1,70,104 (27.5)	55,620 (9.00)	67,105 (10.8)	24,850 (4.0)	3,17,679 (51.3)	35,501 (5.7)	3,53,180 (57.1)
1992-93(BE)	1,88,019 (26.9)	61,790 (8.8)	78,663 (11.2)	27,301 (3.9)	3,55,773 (50.8)	39,565 (5.7)	3,95,338 (56.5)

Note : Figures in brackets represent percentages to GDP at current market prices.

Source : Budget Documents of Government of India.

BE : Budget Estimates

RE : Revised Estimates.

APPENDIX TABLE III.5 : BUDGETARY DEFICIT, MARKET LOANS AND RBI
SUPPORT TO CENTRAL GOVERNMENT

(Rupees crore)				
Items	1990-91 (Accounts)	1991-92 (BE)	1991-92 (RE)	1992-93 (BE)
1	2	3	4	5
1. Revenue Account				
(i) Receipts (a)	57,650	70,870	70,114	79,648
(ii) Expenditure (a)	76,212	84,724	87,195	94,530
(iii) Surplus(+)/Deficit(—)	—18,562	—13,854	—17,081	—13,882
2. Capital Account				
(i) Receipts	39,015	38,174	39,521	38,010
(ii) Disbursements	31,800	32,039	29,472	29,517
(iii) Surplus(+)/Deficit(—)	+7,215	+6,135	+10,047	+8,493
3. Total Receipts [1(i)+2(i)]	96,665	1,09,044	1,09,635	1,17,658
4. Total Expenditure [1(ii)+2(ii)]	1,08,012	1,16,763	1,16,667	1,23,047
5. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—11,347	—7,719	—7,032	—5,389
6. (5) as percent of (4)	—10.5	—6.6	—6.0	—4.4
7. Net Market Loans*	8,001 (8,988)	7,500 (8,918)	7,500 (8,918)	5,000 (6,151)
8. (7) as percent of (3)	8.3	6.9	6.8	4.2
9. Increase(+)/Decrease(—) in RBI holding of Govern- ment Rupee Securities other than Treasury Bills(b)	+3,481		—295	
10. Increase (+)/Decrease(—) in net RBI credit to Central Government (c)	+14,745	+7,717	+8,800	+5,389

(a) Include commercial departments.

(b) On book value basis, according to RBI Records. Excludes Special Securities worth Rs. 30,000 crore and Rs. 5,000 crore due to funding of ad hoc Treasury bills during 1990-91 and 1991-92, respectively.

(c) As per memorandum item given in the Union Budget.

* Figures in brackets represent gross Market loans.

BE : Budget Estimates.

RE : Revised Estimates.

APPENDIX TABLE III.6 : MEASURES OF DEFICIT : MONETISED, BUDGET , REVENUE,
GROSS AND NET FISCAL DEFICITS OF STATES

(Rupees crore)						
Year	Gross Fiscal Deficit	Net Fiscal Deficit	Monetised Deficit*	Conven- tional Deficit	Revenue Deficit	GFD as Ratio of GDP@
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3,712	1,714	487	897	+1,486	2.7
1981-82	4,062	2,209	789	1,020	+1,379	2.5
1982-83	4,986	2,830	+860	820	+888	2.8
1983-84	6,359	4,067	38	561	+211	4.1
1984-85	8,199	5,834	1,486	1,438	924	3.5
1985-86	7,520	4,799	+1,862	+1,688	+654	2.9
1986-87	9,269	6,107	516	667	+169	3.2
1987-88	11,219	7,742	+157	66	1,088	3.4
1988-89	11,672	8,884	425	+380	1,807	3.0
1989-90	15,433	11,645	255	161	3,682	3.4
1990-91	18,815	14,559	+420	70	5,335	3.6
1991-92(RE)	20,219	15,427	340	1,667	5,344	3.3
1992-93(BE)	20,968	14,997	N.A.	98	3,667	3.0

+ Indicates Surplus.

* Data pertains to 23 States having accounts with Reserve Bank of India.

BE : Budget Estimates.

RE : Revised Estimates.

GFD : Gross Fiscal Deficit.

@GDP at current market prices.

APPENDIX TABLE III.7 : FINANCING OF STATES' GROSS FISCAL DEFICIT

(Rupees crore)

Year	Loans from Central Govt. (net)	Market Borrowings (net)	Others	Gross Fiscal Deficit (2+3+4)	States' Outstanding Liabilities (end-year) Total *	Loans & Advances from Centre †	Market Loans
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,564 (42.1)	184 (5.0)	1,964 (52.9)	3,712 (100.0)	23,977	17,071	2,973
1981-82	2,000 (49.2)	339 (8.3)	1,723 (42.5)	4,062 (100.0)	27,729	19,080	3,328
1982-83	2,735 (54.9)	393 (7.9)	1,858 (37.2)	4,986 (100.0)	29,457	20,425 ^(a)	3,735
1983-84	3,031 (47.7)	563 (8.9)	2,765 (43.4)	6,359 (100.0)	38,493	27,539 ^(a)	4,408
1984-85	3,580 (43.7)	693 (8.5)	3,926 (47.8)	8,199 (100.0)	44,394	31,226	5,100
1985-86	5,757 (76.6)	1,010 (13.4)	753 (10.0)	7,520 (100.0)	52,474	38,682 ^(a)	6,014
1986-87	4,786 (51.6)	1,147 (12.4)	3,336 (36.0)	9,269 (100.0)	59,273	43,468	7,251
1987-88	5,832 (52.0)	1,523 (13.6)	3,864 (34.4)	11,219 (100.0)	68,523	49,300	8,773
1988-89	6,688 (57.3)	1,973 (16.9)	3,011 (25.8)	11,672 (100.0)	79,496	55,985	10,706
1989-90	7,917 (51.3)	2,298 (14.9)	5,218 (33.8)	15,433 (100.0)	92,300	63,903	12,913
1990-91	9,950 (52.9)	2,184 (11.6)	6,681 (35.5)	18,815 (100.0)	1,03,236	73,852	15,097
1991-92(RE)	9,709 (48.0)	2,874 (14.2)	7,636 (37.8)	20,219 (100.0)	1,24,307	83,562	17,971
1992-93(BE)	12,069 (57.6)	2,940 (14.0)	5,959 (28.4)	20,968 (100.0)	1,43,348	95,630	20,911

* Includes other internal debts, small savings, provident fund etc. reserves funds, deposits and advantages, suspense & miscellaneous including contingency fund.

† Includes medium term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given by the Centre to States to clear their overdrafts.

BE : Budget Estimates. RE : Revised Estimates.

Note : Figures in brackets are percentages to the total.

APPENDIX TABLE III.8 : COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Rupees crore)

Items	1990-91 (Accounts)	1991-92 (BE)	1991-92 (RE)	1992-93* (BE)	Percentage Variation	
					Col. 4 over Col. 2	Col. 5 over Col. 4
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	1,55,606	1,78,093	1,80,665	1,93,617	16.1	9.9
A. Revenue Receipts	1,05,752	1,27,971	1,27,078	1,44,720	20.2	13.9
of which :						
Tax Receipts (a+b)	87,561	1,03,882	1,01,929	1,16,264	16.4	14.1
(a) Direct Taxes	14,268	18,114	18,589	21,325	30.3	14.7
(b) Indirect Taxes	73,293	85,768	83,350	94,939	13.7	13.9
B. Capital Receipts	49,854	50,122	53,587	53,897	7.5	0.6
II. Total Disbursements (A+B+C)	1,66,883	1,87,005	1,89,364	2,04,104	13.5	7.8
A. Development Expenditure (a+b+c)	98,151	1,05,747	1,08,486	1,11,027	10.5	2.3
(a) Revenue	70,750	76,007	80,236	82,093	13.4	2.3
(b) Capital Outlay	16,366	17,347	16,355	17,975	-0.1	9.9
(c) Loans and Advances	11,035	11,493	11,895	10,959	7.8	-7.9

1	2	3	4	5	6	7
B. Non-Developmental Expenditure (a+b+c)	63,973	74,440	74,025	85,541	15.7	15.6
(a) Revenue	58,114	68,313	68,337	79,199	17.6	15.9
(b) Capital Outlay	5,006	5,755	5,272	5,910	5.3	12.1
(c) Loans and Advances	853	372	416	432	—51.2	3.8
C. Others	4,759	6,819	6,853	7,536	44.0	10.0
III. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—11,277	—8,913	—8,699	—5,487		

* Includes effect to Budget proposals, BE : Budget Estimates, RE : Revised Estimates.

Note : 1. Regarding State Governments, data relate to 25 States of which 9 are from Vote-on-Account Budgets.
2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in figures of repayments of loans by States to Central Government given in their respective budgets.

APPENDIX TABLE III.9 : DEVELOPMENTAL AND NON-DEVELOPMENTAL EXPENDITURES OF CENTRE AND STATES

(Rupees crore)

Year	Centre			States				Centre and States Combined			
	Developmental Expenditure	Non-Developmental Expenditure	Total@	Developmental Expenditure	Non-Developmental Expenditure	Others*	Total	Developmental Expenditure	Non-Developmental Expenditure	Others**	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)
1983-84	22,07 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,448 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.3)	61,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	1,01,602 (100.0)
1987-88	61,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,614 (2.3)	1,11,161 (100.0)
1988-89	41,536 (53.9)	35,579 (46.1)	77,055 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (23.4)	4,599 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (61.6)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,245 (100.0)
1989-90	54,204 (56.9)	41,020 (43.1)	95,224 (100.0)	53,150 (69.2)	19,253 (25.1)	4,406 (5.7)	76,809 (100.0)	89,386 (60.5)	54,300 (36.8)	3,939 (2.7)	1,47,625 (100.0)
1990-91	+58,645 (54.3)	49,367 (45.7)	1,08,012 (100.0)	62,831 (68.8)	23,162 (25.4)	5,295 (5.8)	91,288 (100.0)	98,151 (58.8)	63,973 (38.3)	4,759 (2.9)	1,66,883 (100.0)
1991-92 (RE)	+61,795 (53.0)	54,872 (47.0)	1,16,667 (100.0)	72,745 (68.6)	28,133 (26.6)	5,107 (4.8)	1,05,985 (100.0)	1,08,486 (57.3)	74,025 (39.1)	6,853 (3.6)	1,89,364 (100.0)
1992-93 (BE)	+61,138 (49.7)	61,909 (50.3)	1,23,047 (100.0)	76,706 (65.8)	33,912 (29.1)	5,944 (5.1)	1,16,562 (100.0)	1,11,027 (54.4)	85,541 (41.9)	7,536 (3.7)	2,04,104 (100.0)

@ Excludes discharge of internal and external debt.

* Comprise discharge of internal debt, repayment of loans to the Centre, appropriation for contingency fund and remittances (net) and assignments to Local Bodies and Panchayati Raj institutions.

** Comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayati Raj institutions, appropriation for contingency funds, net remittances of State Governments and are adjusted for differences in the figures of repayment of loans by the State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

+ Regarding State Governments, data relate to 25 States of which 9 are Vote-on-Account Budgets.
BE : Budget Estimates, RE : Revised Estimates.

Notes : (1) Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure.

(2) Figures for the Centre and States do not add up to the combined position due to inter-Governmental adjustments.

(3) The figures for Centre's expenditure prior to 1989-90 do not take into account capital expenditure on Railways and loans to States against small savings collections.

APPENDIX TABLE III.10: DIRECT AND INDIRECT TAX REVENUES OF THE CENTRE AND STATES

(Rupees crore)

Year	Centre (Gross)			States +			Centre & States Combined		
	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,764
(a)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(b)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(a)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
(b)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992
(a)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
(b)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412
(a)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(b)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.8
1987-88	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	48,299	57,010
(a)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(b)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1
1988-89	8,824	35,596	44,420	2,413	19,988	22,401	11,237	55,584	66,821
(a)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(b)	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	14.1	16.9
1989-90	10,003	41,578	51,581	3,006	22,989	25,995	13,009	64,567	77,576
(a)	19.4	80.6	100.0	11.6	88.4	100.0	16.8	83.2	100.0
(b)	2.2	9.2	11.4	0.7	5.1	5.8	2.9	14.3	17.2
1990-91*	11,024	46,489	57,513	3,244	26,804	30,048	14,268	73,293	87,561
(a)	19.2	80.8	100.0	10.8	89.2	100.0	16.3	83.8	100.0
(b)	2.1	8.8	10.9	0.6	5.1	5.7	2.7	13.9	16.6
1991-92 (RE)*	15,000	52,205	67,205	3,589	31,145	34,734	18,589	83,350	1,01,939
(a)	22.3	77.7	100.0	12.3	89.7	100.0	18.2	81.8	100.0
(b)	2.4	8.4	10.9	0.5	5.1	5.6	3.0	13.5	16.5
1992-93 (BE)*	18,153	59,295	76,448	4,172	35,644	39,816	21,325	94,939	1,16,264
(a)	22.4	77.6	100.0	10.5	89.5	100.0	18.3	81.7	100.0
(b)	2.5	8.5	10.9	0.6	5.1	5.7	3.0	13.6	16.6

+ Excluding States' share in Central taxes as reported in Central Budget Documents.

* Regarding State Governments, data relates to 25 States of which 9 are from Vote-on Account Budgets.

Note : (a) Represents percentages to total tax revenue.

(b) Indicates tax to GDP ratio in percentages.

BE : Budget Estimates.

RE : Revised Estimates.

**APPENDIX TABLE III.11 MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS,
LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS***

(Rupees crore)

Government/Authority	Repayments					
	Gross Market Borrowings		(Total Maturities)		Net Market Borrowings	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
	1	2	3	4	5	6
1. Central Government	8,989	8,919	988	1,418	8,001	7,501
2. State Governments	2,569	3,364	—	—	2,569	3,364
3. Institutions Sponsored by Central Government	2,442	2,702	14	14	2,429	2,688
4. Institutions Sponsored by State Governments (including Local Authorities and State Land Development Banks) ⁱ	1,194	1,203	96	104	1,098	1,099
5. Aggregate Market Borrowings	15,194	16,188	1,098	1,536	14,097	14,652

*Actuals as per Reserve Bank of India Records.

APPENDIX TABLE III.12 : COUPON RATES ON CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS SECURITIES

(per cent per annum)

Year	Maturity period in years	Central Government										State Governments			
		5	6	7	8	9 to 10	14 to 15	18	19 to 20	22 and 23	28	29 to 30	13	15	20
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1984-85		7.75	8.00			8.50			9.50		10.25	10.50		9.00	
1985-86		9.00		9.25		9.50			10.50	10.80		11.50	9.75		
1986-87		10.00		10.20		10.50		11.30	11.50					11.00	
1987-88						10.50	11.00		11.50					11.00	
1988-89		10.00			10.30	10.50	11.00		11.50						11.50
1989-90						10.50	11.00		11.50						11.50
1990-91		10.50				10.75	11.25		11.50						11.50
1991-92 (a)		10.50				10.75	11.25		11.50						11.50
(b)		10.75				11.00	11.50		12.00						12.00—
(c)							12.50								
1992-93		12.00 [@]				12.75 [@]									13.00

[@] On auction basis cut-on yield. + Coupon rate raised to 12.00 per cent on October 3 1991.

(a) I and II Tranches. (b) III, IV and V Tranches. (c) VI Tranche.

APPENDIX TABLE IV.1 : MONEY STOCK (M3)—COMPONENTS AND SOURCES

(Rupees crore)

Items	Outstanding as on March 31 1992*	Variation during**							
		1990-91		1991-92*		1992-93* (April-June)		1991-92* (April-June)	
		Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. M3 (a+b+c)	3,15,084	34,878	15.1	49,256	18.5	18,243	5.8	12,535	4.7
a. Currency with the Public	61,232	6,748	14.6	8,184	15.4	2,719	4.4	3,737	7.0
b. Aggregate Deposits with Banks (1+2) o/w External deposits (i+ii) ††	2,52,956	28,054	15.2	40,850	19.3	10,534	4.2	8,064	3.8
i. All foreign currency deposits	28,273	4,777	26.7	5,606	24.7	3,909	13.8	203	0.9
ii. NRE deposits	20,439	4,088	35.4	4,812	30.8	3,427	16.8	—35	—0.2
1. Demand Deposits	7,834	689	10.8	794	11.3	482	6.2	238	3.4
2. Time Deposits	51,983	5,008	14.7	12,813	32.7	44	0.1	1,796	4.6
c. 'Other' Deposits with RBI	2,00,973	23,046	15.4	28,037	16.2	10,490	5.2	6,268	3.6
	896	76	12.7	222	32.9	4,990	556.9	734	108.9
II. M1 (a+b(i)+c)	1,14,111	11,832	14.6	21,219	22.8	7,753	6.8	6,267	6.2
III. SOURCES OF MONEY STOCK (M3) (1+2+3+4+5)									
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	1,58,294	23,042	19.7	18,101	12.9	6,391	4.0	10,445	7.5
A. RBI's net Credit to Government (i+ii) ††	94,016	15,165	20.6	5,168	5.8	2,320	2.5	7,081	8.0
i. Net claims on Central Government (a—b)	92,266	14,745	20.5	5,508	6.3	3,913	4.2	9,170	10.6
a. Claims on Central Government	94,348	15,086	20.6	5,904	6.7	1,906	2.0	7,589	8.6
b. Deposits of Central Government	2,082	341	25.4	396	23.5	—2,007	—96.4	—1,581	—93.8
ii. Net claims on State Governments (a—b)	1,750	420	25.1	—340	—16.3	—1,593	—91.0	—2,089	—100.0
a. Claims on State Governments	1,750	420	25.1	—340	—16.3	—1,577	—90.1	—2,073	—99.2
b. Deposits of State governments	—	—	—	—	—	16	@@	16	@@
B. Other banks' credit to Government	64,278	7,877	18.1	12,933	25.2	4,071	6.3	3,364	6.6
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	1,91,065	20,065	13.2	19,296	11.2	8,493	4.4	89	0.1
A. RBI's credit to commercial sector @	7,260	7	0.1	918	14.5	93	1.3	—850	—13.4
B. Other banks' credit to commercial sector	1,83,805	20,072	13.8	18,378	11.1	8,400	4.6	939	0.6
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)\$	19,527	1,854	27.2	10,855	125.2	849	4.3	—1,225	—14.1
		(—4,694)	(—68.8)	(9,141)	(105.4)	(1,049)	(5.4)	(—1,807)	(—20.8)
A. RBI's net foreign exchange assets	18,838	1,915	31.6	10,855	136.0	849	4.5	—1,225	—15.3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. Other bank's net foreign exchange assets		689	—61	—8.1	—	—	—	—	—	—
4. Government's Currency liabilities to the Public		1,606	66	4.2	75	4.6	—		22	1.4
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)		55,498	10,149	21.9	—929	—1.6	—2,510	—4.5	—3,204	—5.7
A. Net non monetary liabilities of RBI's		27,403	9,486	54.1	381	1.4	—2,195	—8.0	257	1
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)		28,095	663	2.3	—1,310	—4.5	—315	—1.1	—3,461	—11.8

** Based on data pertaining to March 31 in respect of the Reserve Bank and the last reporting Friday on March in respect of scheduled commercial banks.

* Provisional ††Includes special securities. @@increase over zero.

@ Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

\$ Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities. Figures within brackets are net of such revaluation.

** Figures relates to scheduled commercial banks.

Note : Constituent items may not add upto totals due to rounding off.

APPENDIX TABLE IV.2 : RESERVE MONEY—COMPONENTS AND SOURCES

(Rupees crore)

Items	Outstanding as on March, 31, 1992*	Variation during \$			
		1990-91	1991-92*	1992-93*	1991-92*
1	2	3	4	5	6
RESERVE MONEY (1+2+3+4)	99,509	10,188 (13.1)	11,730 (13.4)	6,027 (6.1)	4,725 (5.4)
1. Currency with the Public	61,232	6,748 (14.6)	8,184 (15.4)	2,719 (4.4)	3,737 (7.0)
2. 'Other' Deposits with RBI	896	76 (12.7)	222 (32.9)	4,990 (556.9)	734 (108.9)
3. Cash with Banks	2,499	248 (12.5)	265 (11.9)	3.17 (12.7)	482 (21.6)
4. Bankers' Deposits with RBI	34,882	3,116 (10.9)	3,059 (9.6)	—1,999 (—5.7)	—228 (—0.7)
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3+4+5—6)					
1. Net RBI credit to Government	94,016	15,165 (20.6)	5,168 (5.8)	2,320 (2.5)	—7,081 (8.0)
2. RBI's claims on commercial and co-operative banks@	5,102	2,535 (33.9)	—4,905 (—49.0)	570 (11.2)	—46 (—0.5)
3. RBI's credit to commercial sector	7,260	—7 (—0.1)	918 (14.5)	93 (1.3)	850 (—13.4)

	1	2	3	4	5	6
4. Net foreign exchange assets of RBI	18,838	1,915** (-4,633@@ (31.6) (-76.4)	10,855** (9,141)@@ (136.0) (114.5)	849** (1,049)@@ (4.5) (5.6)	—1,225** (1,807)@ (-15.3) (-22.6)	
5. Government's currency liabilities to the public	1,696	66 (4.2)	75 (4.6)	—	22 (1.4)	
6. Net non-monetary liabilities to RBI	27,403	9,486** (54.1)	381** (1.4)	—2,195** (-8.0)	257** (1.0)	
Net Domestic Assets of RBI	80,671	8,273	875	5,178	5,950	

- * Provisional \$Based on data pertaining to March 31.
 @ Including NABARD. †Includes special securities.
 ** Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market prices effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities.
 @@ Excluding gold revaluation.
 Note : Figures in brackets indicate percentage variation.

APPENDIX TABLE IV.3 : TRENDS IN INCOME VELOCITY OF CURRENCY, AGGREGATE DEPOSITS M1 AND M3

Year	Average* (Rupees crore)				Income Velocity Ratios			
	Currency (C)	Aggregate Deposits (AD)	M1	M3	GDP/C	GDP/AD	GDP/M1	GDP/M3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	27,062	1,03,620	47,009	1,30,938	10.789	2.818	6.211	2.230
1987-88	31,490	1,21,744	53,039	1,53,546	10.563	2.732	6.155	2.166
1988-89	35,934	1,43,556	61,877	1,79,884	10.992	2.751	6.384	2.196
1989-90	42,678	1,70,544	74,370	2,13,807	10.558	2.642	6.059	2.108
1990-91	50,046	1,98,066	87,375	2,49,282	10.581	2.674	6.061	2.124
1991-92@	57,661	2,32,092	1,04,121	2,91,130	10.735	2.667	5.945	2.126

*Average of reporting Fridays of the year.

@Provisional.

APPENDIX TABLE IV.4 : MONETARY RATIOS

Items	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92@
1	2	3	4	5	6	7
Point-to-point basis (Incremental Ratios)						
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.176	0.298	0.198	0.269	0.241	0.200
(b) Currency/M3(C/M3)	0.149	0.229	0.163	0.213	0.193	0.166
(c) Aggregate Deposits/M3 (AD/M3)	0.850	0.767	0.827	0.790	0.804	0.829
(d) Broad Money Multiplier (M3/RM)	3.348	2.608	3.086	2.560	3423	4.199
(e) Narrow Money Multiplier (M1/RM)	1.117	0.811	0.869	0.975	1.161	1.809
(f) Bank Reserves Aggregate Deposits (R/AD)	0.175	0.197	0.182	0.228	0.120	0.081

1	2	3	4	5	6	7
Average basis (Incremental Ratios)						
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.178	0.244	0.204	0.250	0.268	0.224
(b) Currency/MC (C/M3)	0.151	0.196	0.169	0.199	0.208	0.182
(c) Aggregate Deposits/M3 (AD/M3)	0.848	0.802	0.828	0.796	0.776	0.813
(d) Broad Money Multiplier (M3/RM)	3.163	2.482	3.127	3.159	3.026	3.353
(e) Narrow Money Multiplier (M1/RM)	0.078	0.772	0.930	1.163	1.109	1.342
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.194	0.255	0.179	0.138	0.116	0.175

@ Provisional.

Note : (i) On a point-to-point basis, the ratios are based on March 31 data while on an average basis, the ratios have been worked out on the basis of average of reporting Fridays of the year. All ratios in this table are incremental ratios,
(ii) On point-to-point basis the ratios presented here differ from those given in the earlier Reports as the basis for them was the last reporting Friday of March.

APPENDIX TABLE IV.5 : IMPORTANT BANKING INDICATORS—SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Rupees crore)						
Items	Outstanding as on March 20, 1992	Variations during				
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93* (April-June)	1991-92
1	2	3	4	5	6	7
1. Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI/NABARD)	2,51,795	29,208	26,241	39,709	14,791	6,591
2. Aggregate Deposits (a + b)	2,30,758	26,809	25,583	38,216	10,438	6,566
(a) Demand Deposits	45,088	(19.1)	(15.3)	(19.8)	(4.5)	(3.4)
(b) Time Deposits	1,85,670	5,514	4,337	11,895	124	1,238
		(23.6)	(15.0)	(35.8)	(0.3)	(3.7)
3. Borrowings from RBI	577	21,295	21,246	26,321	10,314	5,328
		(18.2)	(15.4)	(16.5)	(5.6)	(3.3)
4. Bank Credit (a + b)	1,25,592	—1,128	1,069	—2,891	1,039	2,636
		(—32.0)	(44.6)	(—83.4)	(180.1)	(76.0)
(a) Food Credit	4,670	16,734	14,848	9,291	8,166	960
		(19.8)	(14.6)	(8.0)	(6.5)	(0.8)
(b) Non-food Credit	1,20,922	1,237	2,500	164	431	811
		(160.9)	(124.6)	(3.6)	(9.2)	(18.0)
5. Investments (a + b)	90,196	15,497	12,348	9,127	7,735	150
		(18.5)	(12.4)	(8.2)	(6.4)	(0.1)
(a) Government Securities	62,727	9,707	10,696	15,131	4,025	3,188
		(17.8)	(16.6)	(20.2)	(4.5)	(4.2)
(b) Other Approved Securities	27,469	6,477	7,706	12,729	4,020	3,388
		(18.1)	(18.2)	(25.5)	(6.4)	(6.8)
6. Cash in hand	2,008	3,230	2,990	2,402	5	—200
		(17.1)	(13.5)	(9.6)	(0.0)	(—0.8)
7. Balances with RBI	34,179	204	156	204	316	325
		(14.1)	(9.5)	(11.3)	(15.7)	(18.0)
8. Credit-Deposit Ratio (%@)	54.4	2,087	398	10,318	—2,227	6,929
		(9.8)	(1.7)	(43.2)	(—6.5)	(29.0)
9. Non-food Credit-Deposit Ratio (%@)	52.4	60.8	60.4	54.4	55.5	58.9
		59.6	58.1	52.4	53.3	56.2

* Provisional.

@ Ratios relate to outstandings as on respective last reporting Fridays.

Notes : 1. Figures in brackets are percentage variations.

2. Constituent items may not add up to the totals due to rounding off.

3. No sign is indicated for positive variations.

APPENDIX TABLE IV.6 : VARIATIONS IN SELECTED ITEMS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS :
LAST WEEK OF MARCH

(Rupees crore)

Items	Variations during last week of March, 1991						Variations during last week of March, 1992					
	March 22, 1991	March 29, 1991	March 31, 1991*	March 31, 1991*	April 5, 1991*	April 19, 1991*	March 20, 1992	March 27, 1992	March 31, 1992*	March 31, 1992*	April 3, 1992*	April 17, 1992*
	over March 23 1990	over March 22, 1991	over March 29, 1991	over March 22 1991	over March 31, 1991*	over April 5, 1991*	over March 22, 1991	over March 20, 1992	over March 27, 1992	over March 20, 1992	over March 31, 1992*	over April 3, 1992*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Aggregate Deposits (a + b)	25,583 (15.3) [33.8]	8,657 (4.5) [33.8]	3,575 (1.8) [14.0]	12,232 (6.4) [47.8]	-6,705 (-3.3)	-2,090 (-1.1)	38,216 (19.8)	6,808 (0.3) [17.8]	4,502 (1.9) [11.8]	11,310 (4.9) [29.6]	-7,824 (-3.2)	985 (0.4)
(a) Demand Deposits	4,337 (15.0) [117.8]	5,107 (15.4) [117.8]	2,222 (5.8) [51.2]	7,329 (22.1) [160.0]	-5,268 (-13.0)	-1,409 (-4.0)	11,895 (35.8)	3,805 (8.4) [32.0]	2,847 (5.8) [23.9]	6,652 (14.8) [55.9]	-6,136 (-11.9)	983 (2.2)
(b) Time Deposits	21,246 (15.4) [16.7]	3,550 (2.2) [16.7]	1,353 (0.8) [6.4]	4,903 (3.1) [23.1]	-1,437 (-0.9)	-681 (-0.4)	26,321 (16.5)	3,002 (1.6) [11.4]	1,656 (0.9) [6.3]	4,658 (2.5) [17.7]	-1,688 (-0.9)	2 (0.0)
2. Bank Credit (a + b)	14,848 (14.6) [37.5]	5,564 (4.8) [37.5]	1,570 (1.3) [10.6]	7,134 (6.1) [48.0]	-5,059 (-4.1)	19 (0.0)	9,291 (8.0)	5,928 (4.7) [63.8]	4,079 (3.1) [43.9]	10,007 (8.0) [107.7]	-6,171 (-4.6)	1,687 (1.3)
(a) Food Credit	2,500 (124.6) [2.5]	63 (1.4) [2.5]	0 (0.0) [0.0]	63 (1.4) [2.5]	-128 (-2.8)	-50 (-1.1)	164 (3.6) [37.8]	-62 (-1.3) [37.8]	236 (5.1) [143.19]	174 (3.7) [106.1]	-266 (-5.5)	-71 (-1.6)
(b) Non-Food Credit	12,348 (12.4) [44.5]	5,501 (4.9) [44.5]	1,570 (1.3) [12.7]	7,071 (6.3) [57.3]	-4,931 (-4.1)	69 (0.11)	9,127 (8.2) [65.6]	5,990 (5.0) [65.6]	3,843 (3.0) [42.1]	9,833 (8.1) [107.7]	-5,905 (-4.5)	1,758 (1.4)

*Provisional.

- NOTES : 1. Figures in parentheses indicate percentage variations.
2. Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of financial year variations.
3. No sign is indicated for positive variations.

APPENDIX TABLE IV-7 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS NON-DEPOSIT RESOURCES

(Rupees crore)

Items	Outstanding as on last Reporting Friday of March			Variations	
	1990	1991	1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1. Aggregate Deposits	1,66,959	1,92,542	2,30,758	25,583 (15.3)	38,216 (19.8)
2. Gross Demand and Time Liabilities (DTL)	1,85,845	2,12,086	2,51,795	26,241 (14.1)	39,709 (18.7)
3. Assets with the Banking System	5,444	5,582	7,927	138 (2.5)	2,345 (42.0)
4. Gross DTL excluding Inter-Bank Assets (2-3)	1,80,401	2,06,504	2,43,868	26,103 (14.5)	37,364 (18.1)
5. Differences (4-1)	13,442	13,962	13,110	520 (3.9)	-852 (-6.1)

1	2	3	4	5	6
6. Other Borrowings	1,055	470	362	—585 (—55.5)	—108 (—23.0)
7. Bills Rediscounted with Financial Institutions	3,934	3,479	3,306	—455 (—11.6)	—173 (—5.0)
8. Non-Deposit Resources (5+7)	17,376	17,441	16,416	65 (0.4)	—1,025 (—5.9)
Memorandum Item					
Call Money Borrowings from UTI, LIC, DFHI@	2,600	2,275	1,212	—325 (—12.5)	—1,063 (—46.7)

@ Includes borrowings from UTI, LIC, & DFHI only for March, 1990, March, 1991 and March, 1992 figures include borrowings from IDBI, NABARD and 'Others' also.

Note : Figures in brackets are percentage variations.

APPENDIX TABLE IV-8 : SECTORAL DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTIONS@

(Rupees crore)

Sectors	Outstanding as on			Variations during	
	March 23, 1990	March, 22 1991	March 20, 1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
(I) Gross Bank Credit (1+2)	1,02,671	1,18,019	1,26,006	15,348	7,987
1. Public Food Procurement Credit	2,006	4,506	4,670	2,500	164
2. Non-Food Gross Bank Credit	1,00,665	1,13,513	1,21,336	12,848 (100.0)	7,823 (100.0)
(A) Priority Sectors	40,383 [42.4]	42,915 [39.3]	45,469 [38.5]	2,532 (19.7)	2,554 [32.6]
(1) Agriculture	16,526 [17.4]	14,750 [15.3]	18,187 [15.4]	224 (1.7)	1,437 [18.3]
(2) Small Scale Industries	15,543	17,181	18,158	1,638 (12.8)	977 (12.5)
(3) Other Priority Sectors	8,314	8,984	9,124	670 (5.2)	140 (1.8)
(B) Industry (Medium & Large)	38,262	44,508	47,330	6,246 (48.6)	2,822 (36.1)
(C) Wholesale Trade (other than food procurement)	5,472	5,910	6,194	438 (3.4)	284 (3.6)
(i) Cotton Corporation of India	140	91	208	—49 (—0.4)	117 (1.5)
(ii) Food Corporation of India (for fertiliser distribution)	230	212	21	—18 (—0.1)	—191 (—2.4)
(iii) Jute Corporation of India	54	62	70	8 (0.1)	8 (0.1)
(iv) Other Trade	5,018	5,545	5,895	497 (3.8)	350 (4.4)
(D) Other Sectors	16,548	20,180	22,343	3,632 (28.3)	2,163 (27.7)
(II) Export Credit (included under item I[2])	8,245	9,186	20,261	941	1,075
(III) Net Bank credit (including inter-bank participations)	95,132	1,09,298	1,18,024	14,166	8,726

@ Provisional.

- Note : 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks (49 from March, 1990 and 48 from August, 1990 due to merger), which account for about 95 percent of bank credit of all scheduled commercial banks.
Gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank, other approved financial institutions and inter-bank participations.
Net bank credit data are exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved financial institutions.
2. Figures in brackets are proportions to incremental non-food gross bank credit.
3. Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter-bank participations) given in item III.

APPENDIX TABLE IV.9 : INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT @

(Rupees crore)

Industry	Outstanding as on			Variations during	
	March 23, 1990	March 22, 1991	March 20, 1992	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of small, medium and large scale)	53,805	61,689	65,488	7,884	3,799
1. Coal	178	229	247	51	18
2. Iron and Steel	2,835	3,292	3,688	457	396
3. Other Metals and Metal Products	1,838	2,227	2,341	389	114
4. All Engineering of which Electronics	12,509	13,931	14,915	1,244	984
5. Electricity	(1,290)	(1,874)	(2,089)	(584)	(215)
6. Cotton Textile	1,258	1,52	1,294	—106	142
7. Jute Textiles	3,659	4,073	4,251	414	178
8. Other Textiles	340	339	332	—1	—7
9. Sugar	3,297	3,761	3,985	464	224
10. Tea	647	639	900	—8	251
11. Food Processing	571	608	658	37	50
12. Vegetable Oils (including vanaspati)	1,056	1,216	1,252	160	36
13. Tobacco and Tobacco Products	700	865	899	165	34
14. Paper and Paper Products	379	391	552	12	161
15. Rubber and Rubber Products	1,346	1,482	1,501	136	19
16. Chemical, Dyes, Paints etc. of which	912	989	1,079	77	90
(i) Fertilisers	6,785	8,743	8,279	958	536
(ii) Petro-Chemicals	(1,075)	(1,309)	(1,340)	(234)	(31)
(iii) Drugs and Pharmaceuticals	(681)	(680)	(609)	(—1)	(—71)
17. Cement	(1,013)	(987)	(1,120)	(—26)	(133)
18. Leather and Leather Products	843	899	982	56	83
19. Gems and Jewellery	931	998	1,087	67	89
20. Construction	1,214	1,236	1,294	22	58
21. Petroleum	1,091	1,321	1,365	230	44
22. SAFAUNS*	137	54	19	—83	—35
23. Other Industries	149	87	68	—62	—19
	11,130	14,157	14,500	3,027	343

@Provisional.

*Ships acquired from abroad under new scheme.

APPENDIX TABLE IV.10 : RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS @

(Rupees crore)

As on the last Reporting Friday of	Export Credit Refinance		Standby Refinance		Discretionary Refinance		182 Day Treasury Bills Refinance		Total Refinance	
	Limit	Outst- anding	Limit	Outst- anding	Limit	Outst- anding	Limit	Outst- anding	Limit	Outst- anding
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1991										
March	4,129.08	2,812.25	—	—	3,225.97	533.97	210.93	—	7,565.98	3,346.22
April	4,575.76	4,448.34	—	—	4,987.00	4,655.00	348.03	10.00	9,910.79	9,113.34
May	5,111.06	3,167.57	—	—	3,065.76	120.00	291.38	37.50	8,468.20	3,325.0
June	5,222.10	4,467.98	—	—	2,432.02	1,546.33	555.10	—	8,209.22	6,014.31
September	4,262.28	3,250.50	—	—	1,745.46	—	1,010.03	—	7,017.77	3,250.50
December	4,747.33	292.13	—	—	—	—	—	—	4,747.33	292.13
1992										
March	5,594.31	494.87	—	—	—	—	—	—	5,594.31	494.87
April	5,746.88	3,694.07	—	—	—	—	—	—	5,746.88	3,690.07
May	6,841.93	1,619.86	—	—	—	—	—	—	6,841.93	1,610.86
June	7,163.34	1,531.83	—	—	—	—	—	—	7,613.34	1,531.83
July	7,655.61	1,561.36	—	—	—	—	—	—	7,655.61	1,562.36

@ Excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc.

APPENDIX TABLE IV.11 : RESERVE BANK REFINANCE TO DELHI

(Rupees crore)

As on the last day of the month	Refinance Against the Collaterals of 182 Day Treasury Bills				Refinance Against Short-Term Commercial Bill				Refinance Against Dated Securities of the Central Government*			
	Link	Outstanding	Peak level utilisation during the month	Limit corresponding to the peak utilisation as in Col. 4	Limit	Outstanding	Peak level utilisation during the month	Limit corresponding to the peak utilisation as in Col. 8	Limit	Outstanding	Peak level utilisation during the month	Limit corresponding to the peak utilisation as in Col. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1991												
March	200.00	126.81	23.026 (19-3-91)	300.00	700.00	700.00	700.00 (30-3-91)	700.00				
June	100.00	Nil	212.17 (20-6-91)	300.00	700.00	Nil	700.00 (24-6-91)	700.00				
September	100.00	92.52	98.77 (12-9-91)	100.00	50.00	50.00	50.00 (27-9-91)	50.00				
December	100.00	Nil	3370.4 (2-12-91)	600.00	50.00	Nil	50.00 (18-12-91)	50.00				
1992												
March	600.00	Nil	580.48 (28-2-92)	600.00	50.00	Nil	50.00 (27-3-91)	50.00				
June	100.00	26.55	87.75 (19-5-92)	100.00	200.00	151.20	200.00 (22-6-92)	200.00	100.00	28.00	100.00 (27-6-92)	100.00
July	100.00	Nil	36.90 (3-7-92)	100.00	100.00	Nil	146.70 (2-7-92)	200.00	100.00	Nil	34.20 (1-7-92)	100.00

*Effective April 2, 1992.

APPENDIX TABLE IV.12 : CUMULATIVE TURNOVER OF THE DFHI IN MONEY-MARKET INSTRUMENTS

(Rupees crore)

Instrument	fiscal year		During the year 1992-93 (up to Aug 7, 1992)	During the year 1991-92 (up to Aug 9, 1991)
	1990-91	1991-92		
1	2	3	4	5
1. Call Funds (including Notice Funds)	02,2792	2,96,864	1,67,715	1,13,03
2. Treasury Bills	32,329	23,166	9,634	11,699
3. Commercial Bills	12,675	6,872	477	4,301
4. Certificate of Deposit	8	17	6	8
5. Commercial Paper	107	42	..	42
6. Term Deposits	3,532	5,962	987	2,15
7. Dated Central Government Securities	--	--	3,582	--

APPENDIX TABLE IV.13 : INTEREST RATES FOR RESERVE BANK REFINANCE TO DFHI

(per cent per annum)						
Refinance Against Holdings of 182 day Treasury Bills		Refinance Against Commercial Bills		Refinance Against Dated Securities@		
Effective Date	Rate of Interest	Effective Date	Rate of Interest	Effective Date	Rate of Interest	
1	2	3	4	5	6	
1991		1991		1992		
July	8	10.25	July	15	16.50	April 2 12.00
	9	10.00		17	16.25	
	13	10.50		18	16.00	
	15	10.75		29	15.75	
	17	10.50	August	5	15.00	
	18	10.25		7	14.00	
	22	10.00	September	25	14.00	
October	1	10.25	1992			
	5	11.00	April	13	15.00	
	7	10.25		25	16.00	
	9	11.50		28	20.00	
	12	12.50	May	5	17.00	
	19	10.00	July	11	15.00	
November	4	10.00				
	6	10.00				
	11	10.00				
	12	10.00				
	13	10.00				
	18	10.50				
	25	10.50				
December	5	10.25				
	7	10.00				
1992						
March	13	11.00				
	21	10.00				
	24	11.00				
	25	12.50				
	27	13.00				
April	7	12.00				
	20	10.00				
	30	11.00				
May	5	10.00				

+ With effect from April 30, 1992 rate of interest relates to longer maturity treasury bills including 182 day Treasury bills.

@A separate refinance limit of Rs. 100 crore was sanctioned to DFHI against dated securities of Government of India with effect from March 30, 1992.

APPENDIX TABLE IV.14 : CALL MONEY LENDING RATES OF DFHI

					(per cent per annum)				
1990-91					1991-92				
For the fortnight ended	Lending rate			For the fortnight ended	Lending rate				
	Trough	Peak	Average* of middle rate		Trough	Peak	Average* of middle rate		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1990					1991				
July	13	8.50	13.75	11.45	July	12	10.25	38.50	23.40
	27	7.50	12.25	10.10		26	5.00	27.00	14.03
August	10	8.00	11.00	9.50	August	9	5.00	17.50	12.60
	24	6.00	11.00	9.40		23	9.00	15.00	13.40

	1	2	3	4	5	6	7	8	
September	7	6.50	15.75	12.25	September	6	3.50	15.00	10.95
	21	10.00	26.00	16.50		20	3.00	14.50	10.85
October	5	10.00	34.00	22.60	October	4	5.00	50.00	18.60
	19	16.00	60.50	37.20		18	4.00	35.25	19.65
November	2	9.00	31.00	21.00	November	1	10.00	24.50	14.90
	16	8.00	28.00	19.35		15	15.00	36.00	23.25
	30	7.50	28.00	16.60		29	3.00	36.00	20.55
December	14	4.00	14.00	10.50	December	13	2.00	21.00	9.35
	28	7.50	15.00	13.20		27	3.50	16.25	9.60
1991					1992				
January	11	7.00	15.25	13.40	January	10	3.25	16.25	9.95
	25	5.00	15.00	11.80		24	4.00	10.75	9.25
February	8	6.00	14.25	12.65	February	7	2.25	10.00	8.40
	22	8.75	15.75	12.80		21	3.00	10.00	8.30
March	8	13.75	17.75	16.10	March	6	4.50	9.75	8.75
	22	7.00	27.75	21.30		20	2.00	20.25	10.30
April	5	5.00	25.00	16.05	April	3	6.00	15.00	26.70
	19	14.25	46.00	23.75		17	4.00	36.50	18.00
May	3	24.25	45.00	37.25	May	1	20.00	86.00	42.05
	17	20.00	60.50	42.90		15	6.00	51.00	34.15
	31	4.50	45.00	39.10		29	3.50	36.00	17.05
June	14	13.50	28.00	23.40	June	12	4.50	16.50	11.45
	28	6.00	38.00	25.15		26	5.00	22.00	15.00
July	12	10.25	38.50	23.40	July	10	3.00	18.50	12.70
	26	5.00	27.00	14.05		24	1.25	16.50	8.70
August	9	5.00	17.50	12.60	August	7	3.50	12.50	9.20
	23	9.00	15.00	13.40		21	3.00	12.50	8.65

*This is a simple average of daily middle rates.

APPENDIX TABLE IV.15 : 182 DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS

Date of Auction	Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-Off price for Rs. 100 of face value	Cut-off yield (per cent per annum)	Total amount Treasury Bills outstanding (Rs. crore)	
	Number	Aggregate nominal amount (Rs. crore)	Number	Aggregate nominal amount (Rs. crore)				
1	1	3	4	5	6	7	8	
1991								
July	10	23	326.00	9	198.00	95.23	10.02	2,287.77
	24	22	444.50	14	275.50	95.23	10.02	2,500.57
August	7	25	1,0001.25	10	576.25	95.24	10.00	2,801.77
	21	18	660.35	12	623.75	95.25	9.97	3,337.52
September	4	21	188.50	5	60.50	95.26	9.95	3,359.72
	18	15	534.80	—	—	—	—	3,289.47
October	1	13	109.65	11	99.65	95.25	9.97	3,192.12
	15	16	283.50	9	238.00	95.25	9.97	2,851.12
	30	16	937.83	15	622.70	95.23	10.02	3,375.92
November	13	8	196.67	4	189.67	95.24	10.00	3,336.32
	27	6	47.30	4	46.30	95.25	9.97	3,225.82
December	11	12	57.65	11	56.65	95.23	10.02	3,194.97
	24	11	373.25	11	373.25	95.25	10.04	3,360.22

1		2	3	4	5	6	7	8
1992								
January	8	26	673.25	23	621.25	95.20	10.08	3,783.47
	22	29	1,109.25	7	582.25	95.24	10.00	4,090.22
February	5	44	1,055.35	2	100.00	95.30	9.86	3,613.97
	19	73	2,106.25	24	774.00	95.45	9.53	3,764.22
March	4	59	1,184.50	2	125.00	95.80	8.77	3,828.72
	17	16	196.80	14	156.80	95.75	8.88	3,985.52
	31	8	43.70	7	42.70	95.57	9.27	3,985.52
April	11	25	538.00	13	245.00	95.80	8.77	3,935.57
	28	-	-	-	-	-	-	3,812.87
May	13	-	-	-	-	-	-	3,123.20
	27	-	-	-	-	-	-	3,076.90
June	9	-	-	-	-	-	-	3,020.25
	24	-	-	-	-	-	-	2,647.00
July	7	-	-	-	-	-	-	2,025.25
	22	-	-	-	-	-	-	1,443.50
August	5	-	-	-	-	-	-	1,343.50
	21	-	-	-	-	-	-	569.50

Auction was not held for 182 day Treasury bills from the fortnight April 28, 1992 onwards.

APPENDIX TABLE IV.16 : 364 DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS

Date of Auction	Bids Tendered			Bids Accepted		Cut-off Price Rs. 100 of face value	Cut off Yield (per cent per annum)	Total Amount of Treasury Bills outstanding (Rs. crore)
	Number	Aggregate nominal amount (Rs. crore)	Number	Aggregate nominal amount (Rs. crore)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1992								
April	28	75	1,128.65	53	666.15	89.75	11.42	666.15
May	13	57	1,396.48	44	961.48	89.75	11.42	1,627.63
	27	60	1,087.23	41	797.75	89.75	11.42	2,425.38
June	9	42	537.64	33	412.64	89.75	11.42	2,838.02
	24	85	1,756.16	66	1,474.16	89.75	11.42	4,312.18
July	7	26	589.00	10	387.00	89.80	11.36	4,699.18
	22	56	1,979.65	16	854.60	89.87	11.27	5,553.78
August	5	67	1,623.35	21	795.85	89.93	11.20	6,349.63
	19	55	997.80	35	810.00	89.95	11.17	7,159.63

APPENDIX TABLE IV.17 : ISSUE OF CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs) BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

Fortnight ended		Number of banks which issued CDs*	Total out- standing (Rs. crore)	Effective interest rate (range) of CDs** (per cent per annum)
1	2			
1991				
July	12	52	4,846	9.00-17.00
	26	52	4,683	10.50-17.00
August	9	53	4,805	11.00-17.00
	23	53	5,121	10.00-21.00

**Issued during the fortnight for all maturities.

(In per cent)

Items	Phase I			Phase II			Phase III		
	End-March to End-August			End-August to End-December			End-December to End-March		
	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
All Commodities	6.5	5.6	9.6	-0.4	3.7	1.9	2.8	2.3	1.7
Primary Articles	6.8	10.4	13.9	-3.5	2.9	2.6	3.3	3.1	-1.3
Fuel, Power, Light & Lubricants	0.5	1.5	4.7	0.8	11.1	5.2	4.9	1.4	2.8
Manufactured Products	7.5	3.7	8.0	1.2	2.9	0.9	2.1	2.1	3.3

APPENDIX TABLE IV.19: VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES
(BASE : 1981-82=100)

Major Groups/Groups/Sub-groups/ Commodities	Weight	Financial year		(In per cent)			
		Point-to-point basis		Average basis		First quarter	
		Point-to-point basis		Average basis		Point-to-point basis	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
ALL COMMODITIES	100.000	12.1	13.6	10.3	13.7	4.3	2.3
I. PRIMARY ARTICLES	32.295	17.1	15.3	13.1	18.2	7.4	3.3
1. Food articles	17.386	18.9	20.9	12.0	20.2	10.0	5.8
a. Cereals	6.824	25.3	26.9	7.9	23.2	2.6	0.9
(i) Rice	3.685	13.4	30.7	5.7	21.7	4.4	2.2
(ii) Wheat	2.248	48.9	12.3	16.2	18.3	15.5	3.8
b. Pulses	1.093	10.8	9.4	10.7	9.3	5.7	1.9
c. Fruits and vegetables	4.089	22.7	19.0	19.8	24.1	28.2	14.2
d. Milk	1.961	8.9	13.7	4.2	12.9	6.0	0.8
e. Eggs, fish & meat	1.783	10.5	16.3	9.1	14.6	11.4	3.4
f. Condiments & spices	0.947	32.3	41.3	25.9	46.7	18.8	11.5
g. Other food articles	0.689	-2.0	-5.0	13.3	-8.9	14.4	17.2
(i) Tea	0.564	-12.6	0.4	6.1	-9.6	25.1	22.3
(ii) Coffee	0.125	61.3	-22.2	60.6	-5.5	-19.9	-4.2
2. Non-food articles	10.081	19.3	8.1	17.2	17.8	3.8	-0.7
a. Fibres	1.791	24.5	14.4	5.2	38.8	14.9	0.3
(i) Raw cotton	1.335	44.3	24.7	-0.7	63.4	21.1	2.8
b. Oilseeds	3.861	26.6	4.7	28.9	20.3	2.8	2.1
3. Minerals	4.828	-0.5	5.2	6.7	4.1	3.2	0.0
(i) Petroleum & natural gas	4.274	-0.4	1.9	8.5	1.4	1.9	0.0
II. FUEL, POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	10.663	14.4	13.2	12.3	13.1	0.5	0.3
a. Cooking coal	0.353	0.0	26.1	0.0	7.0	0.0	0.0
b. Mineral oils	6.666	20.6	9.2	19.3	16.1	0.0	0.1
c. Electricity	2.741	11.4	13.7	7.1	10.8	1.5	0.9
III. MANUFACTURED PRODUCTS	57.040	8.9	12.6	8.4	11.3	3.3	2.1
a. Sugar, khandsari & gur	4.059	0.1	5.5	0.3	5.3	11.1	12.0
(i) Sugar	2.013	0.4	18.9	0.0	10.6	3.9	2.9
(ii) Khandsari	0.300	-2.8	-6.9	-1.9	3.1	16.0	14.2
(iii) Gur	1.746	0.1	-6.9	0.8	0.4	17.9	24.1
b. Edible oils	2.445	32.7	1.9	26.0	19.1	2.0	5.2
c. Cotton textiles	6.093	6.5	16.0	8.0	14.4	4.9	-0.0
d. Chemicals & chemical products	7.355	7.3	15.5	5.6	13.9	2.9	1.3
e. Cement	0.860	14.1	17.4	17.2	13.9	7.5	-1.8
f. Iron & steel	2.441	6.0	4.5	6.7	5.5	0.7	2.0

P Provisional.

**APPENDIX TABLE IV.20 : WEIGHTED CONTRIBUTION OF GROUPS/COMMODITIES TO THE INCREASE IN THE
GENERAL INDEX OF WHOLESALE PRICES
(BASE : 1981-82 = 100)**

Major Groups/Groups/Sub-groups/ Commodities	Weight	Financial year				First quarter	
		Point-to-point basis		Average basis		Point-to-point basis	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1991-92	1992-93P
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ALL COMMODITIES	100.000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
I. PRIMARY ARTICLES	32.295	44.6	37.1	40.4	43.2	36.7	48.4
1. Food articles	17.386	28.1	29.4	21.9	28.1	44.7	51.8
a. Cereals	6.824	12.7	13.4	5.0	10.8	4.1	27.9
(i) Rice	3.685	3.9	8.2	2.1	5.7	3.7	4.1
(ii) Wheat	2.248	7.3	2.2	3.2	2.8	8.7	4.0
b. Pulses	1.093	1.2	0.9	1.4	0.9	1.7	1.0
c. Fruits and vegetables	4.089	7.5	6.1	8.1	8.0	28.9	28.5
d. Milk	1.961	1.7	2.3	1.0	2.1	3.1	0.8
e. Eggs, fish & meat	1.783	1.6	2.2	1.7	2.0	5.0	2.9
f. Condiments & spices	0.947	3.6	4.8	3.2	5.0	6.9	9.8
g. Other food articles	0.689	2.2	-0.3	1.4	-0.7	3.2	6.0
(i) Tea	0.564	-1.0	0.0	0.6	-0.6	4.3	6.2
(ii) Coffee	0.125	0.8	-0.4	0.9	-0.1	-1.0	-0.3
2. Non-food articles	10.081	16.6	6.6	16.8	13.9	9.8	-3.0
a. Fibres	1.791	3.4	2.0	0.9	4.8	6.6	0.2
Raw cotton	1.335	3.7	2.4	-0.1	4.9	6.4	1.7
b. Oilseeds	3.861	8.3	1.5	9.9	6.1	2.8	3.6
3. Minerals	4.828	-0.1	1.1	1.9	0.9	2.1	0.0
Petroleum crude & natural gas	4.274	-0.1	0.3	1.9	0.2	1.0	0.0
II. FUEL, POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	10.663	12.2	10.2	12.0	9.8	1.2	1.3
a. Coking coal	0.353	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0
b. Mineral oils	6.666	9.3	4.0	9.7	6.6	0.0	0.1
c. Electricity	2.741	2.9	3.1	2.1	2.4	1.1	1.2
III. MANUFACTURED PRODUCTS	57.042	43.0	52.7	47.4	47.0	43.1	50.2
a. Sugar, khandsari & gur	4.059	0.0	1.3	0.1	1.3	3.1	15.2
i) Sugar	2.013	0.1	2.1	0.0	1.2	1.4	4.0
ii) Khandsari	0.300	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	0.8	1.1
iii) Gur	1.746	0.0	-0.7	0.1	0.0	5.9	12.0
b. Edible oils	2.445	1.3	0.5	6.6	4.1	1.5	6.6
c. Cotton textiles	6.093	3.3	6.8	4.6	6.0	6.6	-0.1
d. Chemicals & chemical products	7.355	3.7	6.7	3.4	6.0	4.0	3.4
e. Cement	0.860	0.9	1.1	1.3	0.8	1.5	-0.7
f. Iron & steel	2.441	1.4	0.9	1.8	1.1	0.4	2.1

P : provisional.

APPENDIX TABLE IV. 21 : ANNUAL AND QUARTERLY RATES OF PRICE INCREASES
AS REFLECTED IN WPI AND CPI
(POINT-TO-POINT BASIS)

Items	1990-91					1991-92				1992-93	
	Quarters				Annual Vari- ation	Quarters				Annual Vari- ation	Quarter Apr. June
	April- June	July- Sept.	Oct.- Dec.	Jan.- March		April- June	July- Sept.	Oct.- Dec.	Jan.- March.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wholesale Price Index@	4.1	1.7	3.4	2.3	12.1	4.3	5.0	2.0	1.7	13.6	2.3
CPI for Industrial Workers†	4.5	3.2	4.2	1.0	3.6	4.0	5.7	1.8	1.8	13.9	3.1
CPI for Urban Non-manual Employees‡	4.0	2.6	3.8	2.4	13.4	3.0	5.7	1.6	2.7	13.6	1.6+
CPI for Agricultural Labourers*	3.1	4.3	4.5	3.6	16.6	2.1	1.3	3.4	3.8	21.19	1.1+

@ Base : 1981-82 = 100

† Base : 1982- = 100

‡ Base : 1984-85 = 100

*Base : 1960-61 = 100

+ Upto May, 1992

APPENDIX TABLE IV.22 : GOLD AND SILVER PRICES IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKETS

Year	Gold		Silver		Spread between Bombay and London Prices (Average in percentages)	Spread between Bombay and New York prices (Average in percentages)
	Bombay Market (Rs. per 10 grammes for standard gold)		Bombay Market (Rs. per Kg. for 0.999 fineness)			
	Year-end	Average	Year-end	Average		
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	2.5	—34.9
1981-82	1,645 (—3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (—1.5)	2,636 (0.7)	42.1	0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	37.8	—1.1
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	38.5	—0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	53.3	27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	64.8	63.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	47.3	19.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	61.2	83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	62.0	114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (—4.3)	6,842 (7.5)	56.5	140.4
1990-91	3,466 (8.3)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (—1.2)	59.5	162.1
1991-92	4,334 (25.0)	4,298 (24.5)	8,040 (21.0)	7,332 (8.5)	51.3	124.2

* Till February, 1992, the spread has been worked out after converting the quotations in dollars per troy ounce in London market into rupees per 10 grammes, at the cross rates based on daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling. For March, 1992, the quotations have been converted at the daily average of FEDAI's spot buying and selling rate of U.S. dollars in Bombay.

** Till February, 1992, the spread has been worked out after converting the quotations in cents per troy ounce in New York market into rupees per Kg., at the cross rates based on the daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling. For March, 1992, the quotations have been converted at the daily average of FEDAI's spot buying and selling rate of U.S. dollars in Bombay.

Note : Figures in brackets are percentage variations over the previous year.

APPENDIX TABLE IV. 23 : GOLD AND SILVER RATIO IN TERMS OF GRAMMES†

Year	In Bombay Market*		In International Market‡	
	On average Price basis	On Year-end Price basis	On average Price basis	On Year-end Price basis
1	2	3	4	5
1980-81	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	68
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
1990-91	51	53	83	92
1991-92	59	54	87	83

† Grammes of silver available per one gramme gold.

* Based on quotations of Bombay Bullion Association.

‡ Based on quotations received from Press Trust of India for London and New York Markets.

APPENDIX TABLE IV.24 : MONTHLY SPREAD BETWEEN GOLD AND SILVER PRICES

Month/Year	Gold Bombay—London		Silver Bombay—New York	
	Absolute *	Percentage	Absolute @	Percentage
1	2	3	4	5
1991				
April	1,288.79	56.2	4,164.24	163.6
May	1,371.21	58.0	4,233.39	158.2
June	1,256.62	50.7	3,869.99	130.4
July	1,038.22	34.3	3,484.69	98.6
August	1,229.79	41.6	3,602.88	110.4
September	1,348.25	46.5	3,646.05	108.4
October	1,503.72	50.3	3,821.95	112.0
November	1,716.32	57.3	3,898.29	115.4
December	1,782.46	62.2	4,440.45	136.6
1992				
January	1,977.70	67.0	4,927.09	143.6
February	1,789.50	60.7	4,691.24	136.1
March	1,069.17	33.6	3,970.00	99.8
April	1,131.48	33.6	4,396.74	110.0
May	889.34	27.1	3,996.78	100.5
June	796.89	24.1	3,313.47	84.0
July	708.55	20.7	3,694.59	96.2

* Rupees per 10 grammes.

@ Rupees per Kilogram.

APPENDIX TABLE V.1 : ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY ALL FINANCIAL INSTITUTIONS

(Rupees crore)											
		1989-90		1990-91		1991-92		Variations in sanctions		Variations in disbursements	
Institutions		S	D	S	D	S	D	1990-91 over 1989-90	1991-92 over 1990-91	1990-91 over 1989-90	1991-92 over 1990-91
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. All India Development Banks (1 to 9)	@	13,043.7	7,574.1	16,172.3	9,778.1	18,053.6	11,693.2	3,128.6 (24.0)	1,881.3 (11.6)	2,204.0 (29.1)	1,915.1 (19.6)
	@@	11,272.1	6,468.4	14,165.9	8,550.1	15,879.6	10,384.1	2,893.8 (25.7)	1,713.7 (12.1)	2,018.7 (32.2)	1,834.0 (21.5)
1. IDBI		7,742.2	5,084.8	6,827.4	4,459.4	7,639.6	5,762.8	1,215.4* (21.6)*	812.2 (11.9)	945.6* (26.9)*	1,303.4 (29.2)
	●	7,354.7	4,701.0	6,381.2	4,017.4	7,155.8	5,279.0	1,561.7* (22.1)*	774.6 (12.1)	887.4* (28.4)*	1,261.6 (31.4)
	●●	5,583.1	3,595.3	5,569.7	3,533.2	6,506.2	4,816.4	2,116.8* (61.3)*	936.5 (16.8)	1,508.9* (74.5*)	1,283.2 (36.3)
2. IFCI		2,294.9	1,121.8	2,965.1	1,574.8	2,869.2	1,605.2	670.2 (29.2)	-95.9 (-3.2)	453.0 (40.4)	30.4 (1.9)
3. ICICI		2,850.6	1,357.1	3,744.0	1,967.6	4,305.9	2,351.3	893.4 (31.3)	561.9 (15.0)	610.5 (45.0)	383.7 (19.5)
4. SIDBI	—	2,408.8	1,838.5	2,898.1	2,027.4	—	489.3 (20.3)	—	188.9 (10.3)
	—	1,213.9	1,094.7	1,373.7	1,180.9	—	159.8 (13.2)	—	86.2 (7.9)
5. IRBI		146.6	141.2	234.7	153.9	277.7	185.2	88.1 (60.1)	43.0 (18.3)	12.7 (9.0)	31.3 (20.3)
6. RCTC		8.8	5.0	10.5	7.3	14.5	7.4	1.7 (19.3)	4.0 (38.1)	2.3 (46.0)	0.1 (1.4)
7. TDICI		14.1	9.5	11.4	12.4	19.9	18.5	-2.7 (-19.1)	8.5 (74.6)	2.9 (30.5)	6.1 (49.2)
8. SCICI		321.2	225.7	331.6	167.0	409.0	170.9	10.4 (3.2)	77.4 (23.3)	-58.7 (-26.0)	3.9 (2.3)
9. TFCI		52.8	12.8	85.0	39.2	103.5	48.3	32.2 (61.1)	18.5 (21.8)	26.4 (206.3)	(9.1) (32.2)
B. INVESTMENT INSTITUTIONS		2,086.0	1,715.3	3,078.2	2,156.5	6,005.0	4,174.7	992.2	2,926.8	441.2	2,018.2
(10 + 11 + 12)								(47.6)	(95.1)	(25.7)	(93.6)
	●	1,956.0	1,500.3	2,568.2	1,631.5	4,955.0	3,624.7	612.2 (31.3)	2,386.8 (92.9)	131.2 (8.7)	1,993.2 (122.2)
10. UTI		1,296.6	1,080.5	2,077.2	1,582.7	3,832.5	2,910.4	780.6 (60.2)	1,755.3 (84.5)	502.2 (46.5)	1,327.7 (83.9)
	●	1,166.6	865.5	1,567.2	1,057.7	3,182.5	2,410.4	400.6 (43.3)	1,615.3 (103.1)	192.2 (22.2)	1,352.7 (127.9)
11. LIC		578.2	455.2	688.1	427.4	1,515.3	1,022.5	109.9 (19.0)	827.2 (120.2)	-27.8 (-6.1)	595.1 (139.2)
	●	578.2	455.2	688.1	427.4	1,115.3	972.5	109.9 (19.0)	427.2 (62.1)	-27.8 (-6.1)	545.1 (127.5)
12. GIC		211.2	179.6	312.9	146.4	657.2	241.8	101.7 (48.2)	344.3 (110.0)	-33.2 (-18.5)	95.4 (65.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. Total Assistance by All-India Financial Institutions (A@ + B@)	@14,999.7	9,074.4	18,740.5	11,409.6	23,008.6	15,317.9	3,740.8 (24.9)	4,268.1 (22.8)	2,335.2 (25.7)	3,908.3 (34.3)
D. State-level Institutions (13 and 14)	2,177.0	1,692.1	2,663.0	1,857.7	2,970.5	2,063.2	486.0 (22.3)	307.5 (11.5)	165.6 (9.8)	205.5 (11.1)
13. SFCs	1,511.0	1,154.6	1,848.0	1,267.3	2,065.0	1,393.2	337.0 (22.3)	217.0 (11.7)	112.7 (9.8)	125.9 (9.9)
14. SIDCs	666.0	537.5	815.0	590.4	905.5	670.0	149.0 (22.4)	90.5 (11.1)	52.9 (9.8)	79.6 (13.5)
E. Total Assistance by All Financial Institutions (A@@ + B @ + D)	15,405.1	9,660.8	19,397.1	12,039.3	23,805.1	16,072.0	3,992.0 (25.9)	4,408.0 (22.7)	3,378.5 (24.6)	4,032.7 (33.5)

S = Sanctions

D = Disbursements

@ Data are adjusted for inter-institutional (all-India) flows.

@@ Data are adjusted for inter-institutional (all-India and State level) flows.

.. Not applicable *Indicates increase excluding small sector.

Note : 1. Data for 1991-92 are provisional for all institutions and estimated for SFCs and SIDCs.

2. Data have been adjusted for inter-institutional flows. This involves adjustment in regard to loans to and investments in shares and bonds of financial institutions by IDBI, IDBI/SIDBI's refinance assistance to SFCs and SIDCs and seed capital assistance, term loans given by LIC to IFCI and ICICI, and special deposits by UTI to IDBI, IFCI and ICICI.

3. Figures in brackets are percentage variation over the corresponding figure of the previous year.

4. IDBI figures for 1989-90 include assistance to small sector (S-Rs. 2,130.2 crore. D-Rs. 1,571.0 crore).

5. SIDBI commenced its operations from April 2, 1990.

SOURCE : IDBI and Respective Financial Institutions.

APPENDIX TABLE V.2 : DEPOSITS WITH THE NON-BANKING CORPORATE SECTOR
(as at the end of March)

Category	(Rupees crore)								
	1989-90				1990-91 (Provisional)				
	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aggregate Deposits of which :	10,140	6,758	26,773	33,531	9,901	8,003	36,060	44,063	
(i) Non-financial companies	2,438 (24.0)	4,044 (59.8)	16,759 (62.6)	20,803 (62.0)	2,365 (23.9)	4,610 (57.6)	21,671 (60.1)	26,281 (59.6)	
(ii) Financial companies	6,538 (64.5)	1,825 (27.0)	9,139 (34.1)	10,964 (32.7)	6,416 (64.8)	2,184 (27.3)	13,450 (37.3)	15,634 (35.5)	
(iii) Miscellaneous Non-Banking Companies and Residuary Non-Banking Companies.	1,164 (11.5)	889 (13.2)	875 (3.3)	1,764 (5.3)	1,120 (11.3)	1,209 (155.1)	939 (2.6)	2,148 (4.9)	

Note : Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies/regulated/exempted/aggregate deposits as the case may be.

**APPENDIX TABLE V.3 : CONSENTS/ACKNOWLEDGEMENTS GRANTED BY THE CONTROLLER OF
CAPITAL ISSUES TO GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT
COMPANIES FOR RAISING CAPITAL**

Type of Issue	(Rupees crore)			
	1990-91		1991-92	
	Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5
A. Non-Government Companies				
1. Share (a + b)	499	2,552	799	3,939
(a) Initial	231	1,252	361	2,025
(b) Further*	268	1,300	438	1,914
2. Debenture (a + b)	233	3,570	375	8,050
(a) Convertible	137	2,588	231	5,858
(b) Non-Convertible	96	982	144	2,192
3. Sub-Total (1 + 2)	732	6,122	1,174	11,989
4. Bonus Shares	342	301	69	352
5. Total (3 + 4)	1,074	6,423	1,243	12,341
B. Government Companies				
1. Shares (a + b)	4	61	2	56
(a) Initial	2	30	—	—
(b) Further	2	31**	2	56
2. Public Sector Bonds	17	6,007	17	6,985
3. Sub-Total (1 + 2)	21	6,068	19	7,041
4. Bonus Shares	10	140	1	20
5. Total (3 + 4)	31	6,208	20	7,061
C. Grand Total (A3 + B3) (i.e. Excluding Bonus)	753	12,190	1,193	19,030
Of Which				
1. Shares	503	2,613	801	3,995
2. Debentures & Bonds	250	9,577	392	15,035
D. Total Bonus Shares (A4 + B4)	352	441	70	372
E. Grand Total (C + D) Non-Government & Government Companies	1,105	12,631	1,263	19,402

* Including premium of Rs. 274 crore in 1990-91, and Rs. 402 crore in 1991-92.

** Including premium of Rs. 0.19 crore.

Source : Controller of Capital Issues.

**APPENDIX TABLE V. 4 : NEW CAPITAL ISSUES BY NON-GOVERNMENT
PUBLIC LIMITED COMPANIES@**

Sr. No.	Type of Issues	(Rupees crore)					
		1989-90		1990-91		1991-92	
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Equityshare * (a + b)	268	1,218.8	246	1,285.7	367	1,792.5
		(57)	(272.0)	(41)	(128.1)	(56)	(227.5)
	(a) Prospectus	13	734.1	105	993.8	158	1,043.1
		(17)	(30.0)	(15)	(73.9)	(16)	(26.7)
	(b) Rights	125	484.7	141	219.9	209	686.4
		(40)	(242.0)	(26)	(54.2)	(40)	(200.8)
2.	Preference Shares (a + b)	4	7.9	3	13.1	3	1.5
	(Including CCPS)						
	(a) Prospectus	3	5.4	2	13.0	2	0.5
	(b) Rights	1	2.5	1	0.1	1	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Debentures (a + b)		136	5,246.4	114	2,931.4	146	43,19.8
(a) Prospectus		44	2,400.7	45	1,037.9	50	860.1
(b) Rights		92	2,845.7	69	1,893.5	96	3,159.7
Of which :							
(i) Convertible (a + b)**		109	4,762.2	94	2,355.2	133	3,489.2
(a) Prospectus		37	2,240.4	38	874.7	47	848.4
(b) Rights		72	2,512.8	56	1,480.5	86	2,640.8
(ii) Non-Convertible (a + b)		27	484.2	20	576.2	13	530.6
(a) Prospectus		7	160.3	7	163.2	3	11.7
(b) Rights		20	323.9	13	413.0	10	518.9
4. Total (1 + 2 + 3)		408	6,473.1	363	4,230.2	516	5,750.8
(a) Prospectus		190	3,140.2	152	2,044.7	210	1,903.7
(b) Rights		218	3,332.9	211	2,185.5	306	3,847.1

@ Provisional

* Exclude bonus issues

** Convertible debentures include partly convertible debentures.

Notes : (1) Figures in brackets indicate data in respect of premium on capital issues which are included in respective totals.

(2) Data exclude issues privately placed with financial institutions etc.

(3) Data include amount of over-subscription retained and under subscription in case where specific information was available.

Source : Prospectus/Circulars/Advertisements issued by companies, replies given by the companies to the Reserve Bank's questionnaires; information received from Ministry of Finance and Stock Exchanges, Press reports, handouts, etc.

APPENDIX TABLE V. 5 : RESERVE BANK OF INDIA ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF ORDINARY SHARE PRICES (WEEKLY)

(Base : 1080-81 = 100)

Year/Month	Average+	High	Low	Last week-end of the month/year		
1	2	3	4	5		
1990-91	500.3	654.2	395.6	527.9		
(April-March)	(+39.2)			(+32.0)		
1991-92	776.2	1,485.4	536.9	1,485.4		
(April-March)	(+55.1)			(+181.4)		
April 1991	554.9	568.0	536.9	568.0		
May	563.8	570.2	558.9	570.2		
June	571.3	579.6	563.8	568.6		
July	607.8	644.3	569.3	644.3		
August	715.1	752.2	693.4	752.2		
September	771.8	792.3	751.8	779.9		
October	761.2	781.2	750.9	756.7		
November	801.3	821.4	781.8	813.4		
December	805.4	821.0	788.5	808.7		
January 1992	840.7	868.8	822.1	868.8		
February	990.3	1,095.3	923.3	1,095.3		
March	1,337.3	1,485.4	1,271.5	1,485.4		
April	1,620.2	1,656.9	1,597.3	1,622.0		
May	1,345.5	1,519.3	1,206.8	1,206.8		
June*	1,164.9	1,183.4	1,139.3	1,162.1		
Memorandum Items	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	Average for the five years (1987-88 to 1991-92)
(A) Co-efficient of Variation (in percentage)+	4.82	16.36	5.90	14.66	27.04	13.76
(B) Dispersion (The Range)	40.0	121.1	93.7	258.6	948.5	292.4

+ Based on weekly indices.

* Provisional.

Note * Figures in brackets are percentage variation over the previous year.

APPENDIX TABLE VI. 1 : INDIA'S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS (PRELIMINARY)

Item	Rupees crore					US \$ million				
	1991-92 (QE)	1990-91 (PE)	1990-91 (Q)	1989-90	1988-89	1991-92 (QE)	1990-91 (PE)	1990-91 (QE)	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Current Account										
1. Exports, f.o.b.	44,607.4	33,177.5	33,178.0	28,229.0	20,646.7	18,135.0	18,490.7	18,490.9	16,955.2	14,257.1
2. Imports, c.i.f.	51,522.4	47,083.4	48,320.0	40,642.4	34,202.3	21,213.0	26,240.8	26,930.0	24,411.0	26,617.6
3. Trade Balance	-6,915.0	-13,905.9	-15,142.0	-12,413.4	-13,555.6	-3,078.0	-7,750.1	-8,439.1	-7,455.8	-9,360.5
4. Non-Monetary Gold Movement	493.8	-	-	6.4	-	191.0	-	-	3.8	-
5. Official Transfers, net	1,116.8	819.1	854.0	896.8	724.2	451.0	456.5	476.0	538.6	500.1
6. Other Invisibles, net	-946.6	-778.6	1,200.0	128.0	1,251.3	-399.0	-434.0	668.8	76.9	864.0
7. Current Account Balance	-6,251.0	-13,865.4	-13,088.0	-11,382.2	11,580.1	-2,835.0	-7,727.6	-7,294.3	-6,836.5	-7,996.4
B. Capital Account										
1. External Assistance, net*	6,792.1	4,070.1	3,241.0	3,089.9	3,209.7	2,803.0	2,268.4	1,806.3	1,855.9	2,216.4
Disbursements	10,428.8	6,189.6	5,578.0	4,998.4	4,859.6	4,253.0	3,449.6	3,080.9	3,002.2	3,335.7
Amortisation †	-3,636.7	-2,119.5	-2,287.0	-1,908.5	-1,649.9	-1,450.0	-1,181.2	-1,274.6	-1,146.3	-1,139.3
2. Commercial Borrowings, net*	9,672.9@	1,308.6	1,244.0	2,958.4	2,742.9	1,805.0@	@792.3	699.3	1,776.9	1,894.1
Disbursements	7,620.6-@	3,679.9	3,507.0	4,823.3	4,265.0	2,995.0@	2,050.9	1,954.5	2,897.0	2,945.1
Amortisation	-2,947.7	-2,237.3	-2,263.0	-1,864.9	-1,522.1	-1,190.0	-1,321.6	1,261.2	-1,120.1	-1,051.0
3. NRI Deposits, net	-1,562.1	2,259.9	209.0	4,000.2	3,635.5	-747.0	1,259.5	116.5	2,402.6	2,510.4
4. Other Capital (net)	4,110.1	3,004.2	3,923.0	2,280.9	1,886.6	1,767.0	1,674.6	2,186.4	1,370.0	1,302.7
5. Total Capital Account	14,013.0	10,642.8	8,617.0	12,329.4	11,474.7	5,628.0	5,931.8	4,802.5	7,405.4	7,923.6
C. IMF (Net)	2,079.4	2,177.9	2,178.0	-1,459.6	-1,547.3	781.0	1,213.8	1,213.9	-876.7	-1,068.5
D. SDR Allocation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Total Capital Account, I.M.F. and SDR Allocation	16,092.4	12,820.7	10,795.0	10,869.8	9,927.4	6,409.0	7,145.6	6,016.4	6,528.7	6,855.1
F. Total Current Account, Capital Account, I.M.F. and SDR Allocation	9,841.4	-1,044.7	-2,293.0	-512.4	-1,652.7	3574.0	-582.0	-1,277.9	-307.8	-1,141.8
G. Errors & Omissions	-	-1,248.4	-	-720.0	203.4	-	-696.0	-	-432.4	140.5
H. Reserves and Monetary Gold (Increase—Decrease +)	-9,841.4	2,293.1	2,293.0	1,232.4	1,449.3	-3,574.0	1,278.0	1,277.9	740.2	1,000.8

@Include India Development Bonds.

*Excluding refinancing credits.

QE : Quick Estimates.

PE : Provisional Estimate.

Note : Interest Payments forming part of gross withdrawals under FCNRA deposits have now been segregated under invisible payments. Similarly interest accrued during the year and credited to NRI deposits has been treated as notional outflow under invisible payments and added as reinvestment in NRI deposits in Capital Account. For this reason other invisibles (net), current account and inflow under NRI deposits may not tally with those published elsewhere.

APPENDIX TABLE VI.2 : FINANCE NEED AND SOURCES OF FINANCING

Item	Rupees crore				US dollar million			
	1989-90@	Total		1990-91@ (PE)	1991-92@ (QE)	1989-90@	Total	
		Seventh Five-Year Plan*					Seventh Five-Year Plan*	1990-91@ (PE)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Current Account Deficit including Errors & Omissions	15,0544	39,285	15,114	6,251	7,269.1	27,998.9	8,423.6	2,835.0
2. Repayment to IMF	1,460	5,153	1,156	1,127	876.7	3,610.3	644.0	459.0
3. Financing Need (1+2) Financed by	12,004	44,438	16,270	7,378	8,145.8	31,609.2	9,067.6	3,294.0
4. External Assistance	3,090 (25.7)	12,728 (28.6)	4,070 (25.0)	6,792 (92.1)	1,855.9 (22.8)	9,115.5 (28.8)	2,268.4 (25.0)	2,803.0 (85.1)
5. Commercial Borrowings	2,958 (24.7)	10,647 (24.0)	1,309 (8.0)	4,673 (63.3)	1,776.9 (21.8)	7,547.5 (23.9)	729.3 (8.0)	1,805.0 (54.8)
6. Non-Resident Deposits	2,442 (20.3)	10,164 (22.9)	2,260 (13.9)	—1,562 (21.2)	2,402.6 (29.5)	7,323.5 (23.2)	1,259.5 (13.9)	—74.07 (—22.7)
7. Drawals from IMF	—	—	3,004 (18.5)	32,06 (43.5)	1857.8 (20.5)	1,240.0 (37.6)
8. Other Capital	2,281 (19.0)	5,823 (13.1)	3,334 (20.5)	4,110 (55.7)	1,370.2 (16.8)	3,995.3 (12.6)	2,186.4 (18.5)	1,767.0 (53.6)
9. Use of Reserves	1,223 (10.3)	5,076 (11.4)	2,293 (14.1)	—9,841 (—133.4)	740.2 (9.1)	3,627.4 (11.5)	1,278.0 (14.1)	—3,574 (—108.5)

Note : 1. Figures in brackets indicate proportions to financing need (item 3). Conversions to US \$ has been made at respective annual average rates (Except transactions with the IMF in 1991-92).

2. Figures of commercial borrowing for 1991-92 include India Development Bonds of Rs. 4,212 crore (US \$ 1,627 million QE Quick Estimate. PE Provisional Estimate.

@ Please see note under Appendix Table VI-1

* Excludes accrued interest on NRI deposits.

APPENDIX TABLE VL3—INDIA'S FOREIGN EXCHANGE RESERVES

End of Month	Foreign Exchange Reserves (Rupees crore)				Foreign Exchange Reserves (US \$ Million)				Total Foreign Exchange Reserve@	Movement in Foreign Reserves	Reserve Position	Transaction with the IMF (In SDR million)				Movement in Foreign Exchange Reserves
	SDRs†	Gold@	Foreign Currency (2+3+4)	Total Assets	SDRs	Gold	Foreign Currency (6+7+8)	Total	(In SDR million)	(In SDR million)*	(In SDR million)	Gross Drawings	Cumulative Repurchases	Out-standing Net drawing (13-14)	Net Drawals (+)/Re-payments (-) of IMF Credit*	(net of IMF credit and drawal of Reserve Tranche)* (In SDR million) (11-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
March 1990	183	281	5,787	6,251	107	487	3,368	3,962	3,045	-670	487	3,900	2,752	1,148	-681	11
June 1990	206	281	5,356	5,843	118	495	3,072	3,685	2,784	-261	487	3,900	2,863	1,037	-111	-150
March 1991	200	6,828	4,388	11,416	102	3,496	2,236	5,834	4,329	1,284	..	5,169	3,221	1,948	800	-3@@ (-2,221)
June 1991	133	7,411	2,382	9,926	63	3,524	1,124	4,711	3,564	-765	..	5,169	3,300	1,869	-79	-686 (-754)
September 1991	476	8,658	4,442	13,576	184	3,353	1,722	5,259	3,838	-491	..	5,804	3,396	2,408	460	-951 (-805)
December 1991	120	9,489	9,287	18,896	46	3,675	3,580	7,301	5,095	766	..	5,889	3,463	2,426	478	288 3 1)
March 1992	233	9,039	14,578	23,850	90	3,499	5,631	9,220	6,716	2,387	..	6,074	3,558	2,516	568	18,19 (1887)
June 1992	297	8,932	16,125	25,354	115	3,459	6,221	9,795	6,838	122	..	6,074	3,612	2,462	-54	176 (310)

†At Rupee-SDR exchange rate at the end of the respective month.

* Variations over the previous March.

@ Gold has been valued at Rs. 84.39 per cent grammes in col. 3 and at SDR 35 per troy ounce as in the IFS of IMF in col. 7 till October, 16, 1990 and close to international market price thereafter.

@@ Cover drawal of Reserve Position in the Fund (col. 12).

Notes : 1. Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF relate to transactions in respect of Extended Fund Facility, Stand-by Credit Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility and exclude those relating to Trust Fund Loans.

2. Conversion of foreign currency assets and SDRs into U.S. dollar is done at exchange rates supplied by the IMF.

3. Figures in brackets represent reserves adjusted for gold revaluation.

APPENDIX TABLE VI.4 : INDIA'S FOREIGN TRADE

	Rupees crore			US \$ million			SDR million		
	1991-92 (P)	1990-91	1989-90 (P)	1991-92 (P)	1990-91	1989-90 (P)	1991-92 (P)	1990-91	1989-90 (P)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Exports	43,978 (35.1)	32,553 (17.6)	27,681 (36.8)	17,840 (—1.7)	18,143 (9.1)	16,626 (19.0)	13,134 (0.4)	13,110 (1.1)	12,954 (23.3)
Crude oil
POL	1,022 (9.0)	938 (34.6)	697 (38.0)	415 (—20.7)	523 (24.9)	418 (20.0)	306 (—19.0)	377 (15.8)	326 (24.4)
Non-oil	42,956 (35.9)	31,615 (17.2)	26,958 (36.8)	17,425 (—1.1)	17,620 (8.7)	16,208 (19.0)	12,848 (1.0)	12,723 (0.7)	12,628 (23.3)
II. Imports	47,813 (10.7)	43,193 (22.0)	35,416 (23.4)	19,396 (—19.4)	24,073 (13.2)	21,272 (9.1)	14,301 (—17.7)	17,382 (4.9)	16,574 (13.1)
Oil & POL	13,129 (21.4)	10,816 (72.4)	6,274 (44.0)	5,365 (—11.0)	6,028 (60.0)	3,768 (25.2)	3,927 (—9.8)	4,353 (48.2)	2,936 (29.8)
Non-Oil	34,684 (7.1)	32,377 (11.1)	29,142 (22.0)	14,031 (—22.2)	18,045 (3.1)	17,504 (6.2)	10,374 (—20.4)	13,029 (—4.5)	13,638 (10.0)
III. Trade Balance	—3,835	—10,640	—7,735	—1,556	—5,930	—4,646	—1,147	—4,232	—3,620
Oil Balance	—12,107	—9,878	—5,577	—4,950	—5,505	—3,350	—3,621	—3,975	—2,610
Non-oil Balance	+8,272	—762	—2,157	+3,394	—425	—1,296	+2474	—307	—1,010

Note : (1) Final data for the year 1989-90 are not available from D.G.C.I. & S.

(2) Figures in brackets relate to percentage variation over the previous year.

(3) P—Provisional.

(4) Data for imports of oil & POL in US dollar terms during 1991-92 are converted by using official-average exchange rate, whereas, composite average exchange rate (40 per cent of official and 60 per cent of market exchange rate) for March 1992, has been used for converting other data in US dollar terms.

Source : D.G.C.I. & S.

APPENDIX TABLE VI.5 : INDIA'S EXPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES

Commodity Group	Rupees crore			Percentage variation		US \$ million			Percentage variation	
	1989-90 (P)	1990-91	1991-92 (P)	(3)/(2)	(4)/(3)	1989-90 (P)	1990-91	1991-92 (P)	(8)/(7)	(9)/(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Primary Products	5,951 (21.5)	7,759 (23.8)	9,919 (22.6)	30.4	27.8	3,574 (21.5)	4,324 (23.8)	4,024 (22.6)	21.0	—7.0
of which :										
Agriculture and allied products	4,571 (16.5)	6,019 (18.5)	7,638 (17.4)	31.7	26.9	2,745 (16.5)	3,355 (18.5)	3,098 (17.4)	22.2	—7.6
Ores and Minerals	1,380 (5.0)	1,740 (5.3)	2,281 (5.2)	26.1	31.1	829 (5.0)	970 (5.3)	945 (5.2)	17.0	—4.6

Manufactured Goods	20,310 (73.4)	23,319 (71.6)	32,384 (73.9)	14.8	38.9	12,199 (73.4)	12,996 (71.6)	13,137 (73.9)	6.5	1.
of which :										
Leather and leather Manufactures	1,951 (7.0)	2,566 (7.9)	3,076 (7.0)	31.5	19.9	1,172 (7.0)	1,430 (7.9)	1,248 (7.0)	22.0	-12.7
Chemical and related products	1,981 (7.2)	2,345 (7.2)	3,677 (8.4)	18.4	56.8	1,190 (7.2)	1,307 (7.2)	1,491 (8.4)	9.8	14.1
Engineering goods	3,321 (12.0)	3,809 (11.7)	5,107 (11.7)	14.7	34.1	1,995 (12.0)	2,123 (11.7)	2,072 (11.7)	6.4	-2.4
Textile Fabrics and manufactures	5,246 (19.0)	6,775 (20.8)	9,964 (22.7)	29.1	47.1	3,151 (19.0)	3,776 (20.8)	4,042 (22.7)	19.8	7.0
of which :										
Cotton yarn, Fabrics, made-ups	1,480 (5.3)	2,100 (6.5)	3,209 (7.3)	41.9	52.8	889 (5.3)	1,170 (6.5)	1,302 (7.3)	31.7	11.2
Readymade Garments	3,224 (11.6)	4,012 (12.3)	5,411 (12.3)	24.4	34.9	1,936 (11.6)	2,236 (12.3)	2,195 (12.3)	15.5	-1.8
Handicrafts	6,285 (22.7)	6,167 (18.9)	8,346 (19.0)	-1.9	35.3	3,775 (22.4)	3,437 (18.9)	3,386 (19.0)	-9.0	-1.
of which :										
Gems and Jewellery	5,296 (19.1)	5,247 (16.1)	6,750 (15.4)	-0.9	28.6	3,181 (19.1)	2,924 (16.1)	2,738 (15.4)	-8.1	-6.
Minerals and Lubricants*	697 (2.5)	938 (2.9)	1,022 (2.3)	34.6	9.0	419 (2.5)	523 (2.9)	415 (2.3)	-4.9	-20.7
Others	723 (2.6)	537 (1.6)	653 (1.5)	-25.7	21.6	434 (2.6)	299 (1.6)	265 (1.6)	-31.1	-11.5
Total Exports	27,681	32,553	43,978	17.6	35.1	16,626	18,143	17,840	9.1	-1.7

Note : (1) Final data for the year 1989-90 are not available from D.G.C.I.&S.

(2) Figures in brackets represent percentage to total exports.

(3) P—Provisional

* Relates to petroleum crude and petroleum products.

Source : D.G.C.I. & S.

APPENDIX TABLE VI.6. INDIA'S IMPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES

Commodity Group	Rupees crore			Percentage variation		US \$ Million			Percentage variation	
	1989-90 (P)	1990-91	1991-92 (P)	(3)/(2)	(4)/(3)	1989-90 (P)	1990-91	1991-92 (P)	(8)/(7)	(9)/(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Bulk Imports	14,440 (40.8)	19,454 (45.0)	21,002 (44.0)	34.7	8.0	8,673 (40.8)	10,842 (45.0)	8,559 (44.1)	25.0	-21.1
of which :										
(A) Petroleum, Petroleum products & related material	6,274 (17.7)	10,816 (25.0)	13,129 (27.5)	72.4	21.4	3,768 (17.7)	6,028 (25.0)	5,365 (27.7)	60.0	-11.8
(B) Bulk consumption goods	914	989	636	8.2	-35.7	549	551	258	0.4	-53.2
of which :	(2.6)	(2.3)	(1.3)			(2.6)	(2.3)	(1.3)		
(a) Cereals & cereal preparations	378	182	141	-51.9	-22.5	227	101	57	-55.3	-43.6
(b) Edible Oils	211	326	240	54.5	-26.4	127	182	97	43.4	-46.4
(c) Pulses	228	481	254	111.0	-47.2	137	268	103	95.8	-61.6
(d) Sugar	97	9	1	-90.7	-88.9	58	5	0	-91.4	-91.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(C) Other bulk items	7,252	7,649	7,237	5.5	—5.4	4,356	4,263	2,936	—2.1	—31.1
of which :	(20.5)	(17.7)	(15.2)			(20.5)	(17.7)	(15.2)		
(a) Fertilizers	1,776	1,766	2,259	—0.6	27.9	1,067	984	916	—7.7	—6.9
of which :										
(i) Crude	253	347	440	37.2	26.8	152	193	178	27.3	—7.7
(ii) Sulphur & unroasted iron pyrite	295	278	299	—5.8	7.6	177	155	121	—12.6	—21.7
(iii) Manufactured	1,228	1,141	1,520	—7.1	33.2	738	636	617	—13.8	—3.0
(b) Non-ferrous metals	1,253	1,102	840	—12.1	—23.8	753	614	341	—18.4	—44.5
(c) Paper, paperboard & manufactures thereof (incl. newsprint)	358	456	488	27.4	7.0	215	254	198	18.2	—22.1
(d) Crude rubber	172	226	182	31.4	—19.5	103	126	74	21.9	—41.4
(e) Pulp & waste paper	304	458	299	50.7	—34.7	183	255	121	39.8	—52.5
(f) Metalliferous ores & metal scrap	1,084	1,528	1,015	41.0	—33.6	651	852	412	30.8	—51.7
(g) Iron & Steel	2,305	2,113	2,154	—8.3	—1.9	1,384	1,178	874	—14.9	—25.8
II. Non-bulk Imports	20,972	23,739	26,811	13.2	12.9	12,596	13,230	10,837	5.6	—18.1
of which :	(59.2)	(55.0)	(56.1)			(59.2)	(55.0)	(55.9)		
(A) Capital goods	8,831	10,465	10,394	18.5	—0.7	5,304	5,832	4,216	10.0	—27.7
	(24.9)	(24.2)	(21.7)			(24.9)	(24.2)	(21.7)		
(B) Mainly export related items	6,803	6,604	8,954	—2.9	35.6	4,086	3,681	3,632	—9.9	—1.3
	(19.2)	(15.3)	(18.7)			(19.2)	(15.3)	(18.7)		
of which :										
(a) Pearls, precious & semi-precious stone	4,242	3,738	4,822	—11.9	29.0	2,548	—2,083	1,956	—18.2	—6.1
(b) Chemicals, organic & inorganic	2,135	2,289	3,523	7.2	53.9	1,282	1,276	1,429	—0.5	12.0
(c) Textile yarn, fabrics, etc.	349	443	343	26.9	—22.6	210	247	139	17.8	—43.6
(d) Cashew nuts, raw	77	134	266	74.0	98.5	46	75	108	61.5	44.5
(C) Others	5,338	6,670	7,463	25.0	11.9	3,206	3,717	2,998	15.9	—19.3
	(15.1)	(15.4)	(15.6)			(15.1)	(15.4)	(15.5)		
of which :										
(a) Artificial resins & plastic materials	996	1,095	1,403	9.9	28.1	598	610	569	2.0	—6.7
(b) Professional, scientific & optical goods, etc.	886	1,060	1,041	19.6	—1.8	532	591	422	11.0	—28.5
(c) Coal, coke & briquettes, etc.	562	789	1,036	40.4	31.3	338	440	420	30.3	—4.4
(d) Medicinal & pharmaceutical products	272	468	456	72.1	—2.6	163	261	185	59.7	—29.1
(e) Chemical material & products	222	286	321	28.8	12.2	133	159	130	19.5	—18.3
(f) Non-metallic mineral manufactures	168	203	228	20.8	12.3	101	113	92	12.1	—18.3
Total imports (I+II)	35,416	43,193	47,813	22.0	10.7	21,272	24,073	19,396	13.2	—19.4

Note : (1) Final data for the year 1989-90 are not available from D.G.C.I. & S.

(2) Figures in brackets represent percentage to total imports.

(3) P. Provisional.

(4) @ Converted in US dollar terms by using official average exchange rate.

For other commodities composite average exchange rate is used for March, 1992.

Source : D.G.C.I. & S.

ANNEX TABLE A-1A TRADE WITH FREE PAYMENT AREA (RPA) AND GENERAL CURRENCY AREA (GCA)

Year (April-March)	RPA			GCA			Total		
	Exports	Imports	Trade bal.	Exports	Imports	Trade bal.	Exports	Imports	Trade bal.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rupees crore									
1985-86	2,310	2,071	+239	8,585	17,587	-9,002	10,895	19,958	-8,763
1986-87	2,231 (-3.4)	1,359 (-34.4)	+872	10,221 (19.1)	18,737 (6.5)	-8,516	12,452 (14.3)	20,096 (2.2)	-7,644
1987-88	2,444 (9.5)	1,885 (38.7)	+559	13,230 (29.4)	20,359 (8.7)	-7,129	15,674 (25.9)	2,244 (10.7)	-6,570
1988-89	3,162 (29.4)	1,655 (-12.2)	+1,407	17,070 (29.0)	26,580 (30.6)	-9,510	20,232 (29.1)	28,235 (26.9)	-8,003
1989-90 (F)	5,173 (63.6)	2,059 (61.9)	+2,454	22,508 (31.9)	32,737 (23.2)	-10,229	27,681 (36.8)	35,416 (25.4)	-7,73
1990-91	5,507 (6.5)	2,869 (7.1)	+2,638	27,046 (20.2)	40,324 (23.2)	-13,278	32,553 (17.6)	43,193 (22.0)	-10,640
1991-92 (P)	4,351 (-21.0)	1,955 (-31.9)	+2,396	39,627 (46.5)	45,858 (13.7)	-6,231	43,978 (35.1)	47,813 (10.7)	-3,835
US \$ million									
1985-86	1,888	1,693	+195	7,017	14,374	-7,358	8,905	16,067	-7,162
1986-87	1,746 (-7.5)	1,064 (-37.2)	+682	7,999 (14.0)	14,663 (2.0)	-6,664	9,745 (9.4)	15,727 (2.1)	-5,982
1987-88	1,885 (8.0)	1,454 (36.7)	+431	10,204 (27.6)	15,702 (7.1)	-5,498	12,089 (24.1)	17,156 (9.1)	-5,067
1988-89	2,183 (15.8)	1,143 (21.4)	+1,041	11,787 (15.5)	18,354 (16.9)	-6,567	13,971 (15.6)	19,497 (13.6)	-5,526
1989-90 (P)	3,107 (42.3)	1,609 (40.8)	+1,498	13,519 (14.7)	19,663 (7.1)	-6,144	16,626 (19.0)	21,272 (9.1)	-4,646
1990-91	3,069 (-1.2)	1,599 (-0.6)	+1,470	15,073 (11.5)	22,474 (14.3)	-7,400	18,143 (9.1)	24,073 (13.2)	-5,930
1991-92 (P)	1,765 (-42.5)	793 (-50.4)	+972	16,075 (6.6)	18,603 (-17.2)	-2,528	14,840 (-1.7)	19,396 (-19.4)	-1,556

Note : (1) Final data for the year 1989-90 are not available from D.G.C.I. & S.

(2) Figures in brackets represent percentage variation over the previous year.

(3) Till 1989-90 five countries are included in RPA countries, namely, USSR, Romania, Czechoslovakia, GDR and Poland. Since 1990-91, only first three of the countries mentioned above are included.

(4) P—Provisional.

Source—D.G.C.I. & S.

APPENDIX TABLE VI.8 : EXTERNAL ASSISTANCE

Item	Rupees crores							US \$ million						
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91R	1991-92P	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91R	1991-92P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Loans	2,493	3,176	4,574	4,738	4,138	6,170	10,215	2,038	2,485	3,528	3,272	3,086	3,439	4,174
2. Grants	443	429	478	566	665	534	863	362	336	368	391	399	297	353
3. Gross Utilisation	2,936	3,605	5,052	5,304	5,803	6,704	11,078	2,400	2,821	3,896	3,663	3,485	3,736	4,527
4. Repayments	776	1,176	1,581	1,646	1,987	2,329	3,559	634	920	1,219	1,137	1,193	1,298	1,455
5. Net (3-4)	2,160	2,429	3,471	3,658	3,816	4,375	7,519	1,766	1,901	2,677	2,526	2,292	2,438	3,072

Note : 1. Loans are inclusive of non-government loans but exclusive of suppliers' credits and commercial borrowings.

2. Grants are exclusive of PL-480 II grants.

3. R—Revised.

4. P—Provisional.

5. Figures in U.S. dollar are converted at annual average rates.

Source : Controller of Aid, Accounts & Audit, Government of India.

APPENDIX TABLE VI.9 : DEPOSIT LIABILITIES UNDER NR(E)RA AND FCNRA SCHEMES

As at end-March	Non-Resident (External) Rupee Account						Foreign Currency Non-Resident Account@@						Total			
	Inflow during the year@		Total* Outstanding		Inflow during the year @		Outstanding						Inflow		Outstanding	
	Rupees crore	US \$ mn.	Rupees crore	US \$ mn.	Rupees crore	US \$ mn.	US Dollar	Pound Sterling	DM	Yen	Total (8 to 11)		Rupees crore (2+6)	US \$ mn. (3+7)	Rupees crore (4+12)	US \$ mn. (5+13)
											Rupees crore	US \$ mn.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1987	477	373	4,336	3,354	1,173	918	3,047 (2,360)	464 (224)	3,511	2,720	1,650	1,291	7,847	6,074
1988	477	368	5,107	3,942	1,363	1,051	4,406 (3,410)	541 (222)	4,947	3,827	1,840	1,419	10,054	7,769
1989	235	162	5,899	3,774	2,230	1,540	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	5,275	2,465	1,702	14,1	9,049
1990	277	166	6,507	3,777	2,165	1,309	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,327)	11,324	6,586	2,442	1,475	17,831	10,363
1991	156	84	7,349	3,746	255	168	11,270 (5,754)	305 (89)	1,005 (874)	825 (59,403)	13,405	6,836	411	252	20,754	10,584
1992	—44	—27	8,071	2,591	—3,641	—1,627	10,300 (3,978)	2,002 (445)	447 (284)	859 (44,028)	13,608	5,256	—3,685	—1,654	21,679	7,747

@ Excluding the estimated accrued interest.

* Inclusive of accrued interest.

@@ Do not include accrued interest.

Note : 1. Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in million.

2. Conversion to US dollar has been done at annual average rate in the case of inflows and at year-end rate in the case of outstanding balances.

APPENDIX TABLE VI.10 : INTEREST RATES ON FCNRA DEPOSITS

(per cent per annum)

Effective Dates	US \$				Pound Sterling				DM				Yen			
	months				months				months				months			
	6 and above to less than 1 years	1 year and above to less than 2 years	2 years and above to less than 3 years	3 years only	6 and above to less than 1 year	1 year and above to less than 2 years	2 year and above to less than 3 years	3 years	6 and above only to less than 1 year	1 year and above to less than 2 years	2 years and above to less than 3 years	3 years only	6 and above to less than 1 year	1 year and above to less than 2 years	2 years and above to less than 3 years	3 years only
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
May 30, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
July 19, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25
August 13, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50
September 3, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	9.00	9.25	9.25	9.25
September 25, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.25	9.50	9.75	9.75
December 4, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.50	9.75	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00
January 14, 1991	8.25	8.50	9.00	9.25	11.50	11.75	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
February 8, 1991	7.50	8.00	8.50	9.00	13.25	13.25	13.25	13.25	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
December 12, 1991	6.50	6.75	7.25	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	7.50	7.50	7.50	7.50
January 27, 1992	5.50	5.75	6.75	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	10.25	10.25	10.50	10.50	7.00	7.00	7.00	7.00
March 27, 1992	5.75	6.25	7.50	8.25	12.00	12.00	12.00	12.00	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	6.00	6.50	7.00

APPENDIX TABLE VI. 11 : INDIA'S EXTERNAL DEBT

(Rupees crore)

Item	As at end-March						
	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992(P)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Medium and Long Term							
1. External Assistance—	24,004 19,311	32,312 (24,711)	36,578 (29,182)	46,838 (29,872)	54,101 (32,145)	66,314 (34,281)	109,981 (38,101)
2. IMF	4,888 (3,932)	5,548 (4,291)	4,732 (3,356)	3,696 (3,364)	2,573 (1,494)	5,145 (2,623)	8,935 (3,451)
3. External Commercial Borrowings*	6,908 (5,558)	11,243 (8,697)	13,543 (10,455)	19,147 (12,249)	23,661 (13,735)	29,007 (14,782)	52,389 (16,080)
4. Total (1 + 2 + 3)	35,800 (28,801)	49,103 (37,699)	54,853 (42,993)	69,681 (44,485)	80,335 (47,374)	100,466 (51,686)	171,305 (57,632)
B. NRI Deposits	3,819 (3,075)	7,847 (6,073)	10,054 (7,770)	14,154 (9,049)	17,831 (10,363)	20,754 (10,584)	21,679 (7,847)
C. Total (A + B)	39,619 (31,876)	56,950 (43,772)	64,907 (50,763)	83,835 (53,534)	98,166 (57,737)	121,220 (62,270)	192,984 (65,479)
D. Short term	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9,418 (4,800)	8,687 (3,191)
E. Grand Total (C + D)						130,638 (67,070)	201,671 (68,670)
Memorandum Items :							
1. Debt Stock (Long & Medium term and NRI deposits) Export Ratio @ (in per cent)	201	270	258	272	247	259	303
2. Debt Service Ratio ** (For respective fiscal year) (in per cent)	N.A.	N.A.	N.A.	28.3	24.9	25.2	26.2

+ Exclude non-Government loans.

* Include non-Government loans under External Assistance Programme and suppliers' credits from East-European countries repayable in rupees.

** Includes accrued interest on NRI deposits.

@ Exports cover export of merchandise goods plus gross invisible receipts excluding official transfers.

P : Provisional.

Notes : 1. Figures in brackets indicate U.S. dollar in million.

2. Under the figures for 1992 external assistance, external commercial borrowings, NR(E)R deposits and short term debt other than BAF are converted at market rate. IMF, ID Bonds and BAF under short term are converted at official rate.

3. Commercial borrowings for 1992 include India Development Bonds of Rs. 4,212 crore (U.S. \$ 1,627 million).

4. Under NRI deposits, FCNR deposits do not include accrued interest.

5. Above data include NRI deposits and short term debt. But they are not according to the definition and classification as recommended in the recent Reports on External Debt Statistics.

6. Debt Stock-Export ratio is worked out on the basis of the rupee figures.

APPENDIX TABLE VI. 12 : RUPEE EXCHANGE RATES

(Rupees per unit of SDR/Foreign currency)

Period	SDR	US Dollar	Pound Sterling	Deutsche Mark	Japanese Yen
1	2	3	4	5	6
A. Annual Average Rates* (April-March)					
1987-88	17.1208	12.9658	22.0872	7.4004	0.0941
1988-89	19.2619 (-11.1)	14.4817 (-10.5)	25.5959 (-13.7)	8.0494 (-8.1)	0.113 (-16.7)
1989-90	21.3684 (-9.9)	16.6492 (-13.0)	26.9179 (-4.9)	9.0922 (-11.5)	0.1166 (-3.1)
1990-91	24.8491 (-14.0)	17.9428 (-7.2)	33.193 (18.9)	11.4351 (-20.5)	0.1279 (-8.8)
1991-92	33.4325 (-25.7)	24.4737 (-26.7)	42.5152 (-21.9)	14.6248 (-21.8)	0.1845 (-30.7)
B. Monthly Average Rates					
March 1991*	26.6358	19.2009	35.0742	11.9658	0.14
March 1992*	35.3472	25.8901	44.6775	15.6033	0.1949
March 1992 (FEDAI)**	—	29.4551	51.9588	18.1709	0.227
% Appreciation(+)/ Depreciation(—)					
of March 1992 over March 1991*	(24.64)	(-25.84)	(-21.49)	(-23.31)	(-28.17)
June 1991*	27.7722	21.0055	34.6572	11.7874	0.1504
June 1992**	36.5507	25.8900	47.7889	16.4646	0.2043
June 1992 (FEDAI)**	—	30.2361	55.9065	19.1931	0.2383
% Appreciation(+)/ Depreciation(—)					
of June 1992 over June 1991	(-24.02)	(-18.87)	(-27.48)	(-28.41)	(-26.38)
C. Exchange Rates as on :					
March 29, 1991*	26.3457†	19.6429	34.1	11.4784	0.1391
March 31, 1992*	35.5143	25.8900	44.949	15.7294	0.1948
March 31, 1992 (FEDAI)**	—	31.2256	53.6913	18.8501	0.2328
June 28, 1991	27.855	21.0410	34.36	11.739	0.1523
June 30, 1992	37.053	25.8900	49.2789	17.0182	0.2061
June 30, 1992 (FEDAI)**	—	30.6607	58.4795	20.2429	0.2460

* Represents RBI official rate.

** Represents Foreign Exchange Dealers Association of India, indicative rates.

† As on 28-3-91

Note : Figures in brackets indicate % appreciation(./)/depreciation(+). of Rupee.

[F. No. 19/19/92—B.O.I.]

Sd/-

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.